



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की
सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट
मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
2026 की प्रतिवेदन संख्या 21
(अनुपालन लेखापरीक्षा)

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की
सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट**

मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए

**संघ सरकार (वाणिज्यिक)
2026 की प्रतिवेदन संख्या 21
(अनुपालन लेखापरीक्षा)**

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	vii
	कार्यकारी सारांश	ix
अध्याय I	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश	
	1.1 परिचय	1
	1.2 सरकारी कंपनियों एवं निगमों में निवेश	4
	1.3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त प्रतिफल	15
	1.4 सरकारी कंपनियों एवं निगमों की परिचालन दक्षता	23
अध्याय II	सीएजी की पर्यवेक्षण भूमिका	
	2.1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा	31
	2.2 सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	31
	2.3 सीपीएसई द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण	31
	2.4 सीएजी का पर्यवेक्षण- वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा	34
	2.5 सीएजी की पर्यवेक्षी भूमिका का परिणाम	37
	2.6 लेखांकन मानकों/इंड एस के प्रावधानों का अनुपालन न करना	76
	2.7 प्रबंधन पत्र	83
अध्याय III	कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रणाली	
	3.1 परिचय	87
	भाग-क: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जिनके अंश/अंश तथा बांड दोनों 31 मार्च 2024 तक शेयर बाजारों में सूचीबद्ध थे।	
	3.2 निदेशक मंडल	89
	3.3 निदेशक मंडल एवं समितियों की बैठकें	94
	3.4 रिक्त पदों को भरने में अंतराल	97
	3.5 विविध	98
	3.6 लेखापरीक्षा समिति	100
	3.7 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष की वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	103
	3.8 सतर्कता तंत्र	103

अध्याय	विषय		पृष्ठ सं.	
	3.9	सम्बद्ध पक्ष से लेनदेन	103	
	3.10	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	104	
	3.11	हितधारक संबंध समिति	107	
	3.12	सहायक कंपनियाँ	108	
	3.13	जोखिम प्रबंधन समिति	108	
	3.14	अनुपालन प्रमाणपत्र	109	
	3.15	निष्कर्ष	110	
	भाग-ख : वे सीपीएसई/सांविधिक निगम जिनके बांड/ऋणपत्र शेयर बाजारों में सूचीबद्ध थे			
	3.16	परिचय	112	
	3.17	स्टॉक एक्सचेंज को सूचना	113	
	3.18	वित्तीय परिणाम	113	
	3.19	स्टॉक एक्सचेंज को सूचनाएं/अन्य प्रस्तुतियाँ	114	
	3.20	गैर-परिवर्तनीय (ऋण) प्रतिभूतियों और गैर-परिवर्तनीय वरीयता शेयरों के धारकों के लिए दस्तौवेज और सूचना	115	
	3.21	निदेशक मंडल	115	
	3.22	लेखापरीक्षा समिति	117	
	3.23	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	118	
	3.24	अनुपालन प्रमाणपत्र	119	
	3.25	विविध	119	
	3.26	निष्कर्ष	120	
	अध्याय IV	सीपीएसई द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर व्यय		
		4.1	परिचय	125
		4.2	लेखापरीक्षा का दायरा	126
		4.3	लेखापरीक्षा का उद्देश्य	127
		4.4	लेखापरीक्षा के मानदंड	127
		4.5	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	128
		4.6	निष्कर्ष	153
अध्याय V	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व			
	5.1	परिचय	157	

अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
	5.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं आच्छादन	158
	5.3 नियोजन	158
	5.4 वित्तीय घटक	161
	5.5 परियोजना कार्यान्वयन	170
	5.6 निगरानी ढांचा	173
	5.7 रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण	173
	5.8 सीएसआर व्यय की रिपोर्टिंग में विसंगतियाँ	176
	5.9 निष्कर्ष	176
अध्याय VI	प्रशासनिक मंत्रालयों एवं नवरत्न सीपीएसई के मध्य हुए समझौता ज्ञापनों का विश्लेषण	
	6.1 परिचय	181
	6.2 समझौता ज्ञापन हेतु संस्थागत तंत्र	181
	6.3 समझौता ज्ञापन मूल्यांकन	184
	6.4 विश्लेषण का आच्छादन	184
	6.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष	185
अध्याय VII	विनिवेश प्रक्रिया	
	7.1 भारत सरकार की विनिवेश नीति	207
	7.2 विनिवेश के तरीके	208
	7.3 विनिवेश की प्रक्रिया	209
	7.4 सीपीएसई के विनिवेश के लिए लक्ष्य और उपलब्धि	212
	7.5 विनिवेश से माध्यम-वार प्राप्तियाँ	213
	7.6 अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री - प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव और बिक्री के लिए प्रस्ताव	213
	7.7 अन्य विषय	220
अध्याय VIII	सततता की स्थिति की समीक्षा	
	8.1 परिचय	227
	8.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य	228
	8.3 लेखापरीक्षा का दायरा और आच्छादन	228
	8.4 लेखापरीक्षा के मानदंड	228
	8.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष	228
	8.6 निष्कर्ष	266

अध्याय	विषय		पृष्ठ सं.
अनुलग्नक	I	31 मार्च 2024 के अनुसार सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों/सांविधिक निगमों की सूची	271
	II	सीपीएसई जो 2023-24 के दौरान सीएजी लेखापरीक्षा के दायरे में आए/बाहर गए	296
	III क	बकाया लेखे, अदेय लेखे अथवा परिसमापनाधीन कंपनियों का विवरण - सरकारी कंपनियां	299
	III ख	बकाया लेखे, अदेय लेखे अथवा परिसमापनाधीन कंपनियों का विवरण - सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां	303
	IV	उन सरकारी कंपनियों की सूची जिनकी योग परिसंपत्तियों का मूल्य 31 मार्च 2024 को बकाया दीर्घकालिक ऋणों से कम था	305
	V	66 सूचीबद्ध सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि एवं कमी	306
	VI	2023-24 के दौरान लाभ कमाने वाली सरकारी कंपनियों एवं निगमों की सूची, जिन्हें 2022-23 में घाटे में रहने वाली कंपनियों की तुलना में लाभ कमाने वाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया	309
	VII	2023-24 में लाभ कमाने वाली कंपनियों की सूची से बाहर रखी गई सरकारी कंपनियों की सूची	311
	VIII	31 मार्च 2024 तक शून्य या ऋणात्मक निवल संपत्ति वाली सरकारी कंपनियों की सूची	312
	IX	31 मार्च 2024 तक शून्य या ऋणात्मक निवल मूल्य वाली सरकार-नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची	316
	X	सरकारी कंपनियों एवं निगमों द्वारा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	317
	XI	सरकारी कंपनियों एवं निगमों की इक्विटी पर प्रतिफल	353
	XII	उन सीपीएसई की सूची जिन पर सीएजी द्वारा टिप्पणियाँ जारी की गईं	388
	XIII	उन सीपीएसई का विवरण जिनमें सांविधिक लेखापरीक्षकों ने लेखांकन मानकों/इंड एस के अनुपालन न होने की रिपोर्ट दी।	392
	XIV	उन सीपीएसई का विवरण जहां सीएजी द्वारा प्रबंधन पत्र जारी किए गए	394
	XV	उन सीपीएसई का विवरण जिनमें सीएजी द्वारा जारी प्रबंधन पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण सुधार किए गए	404
	XVI	चुनिंदा सीपीएसई की सूची जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे	412
	XVII	चुने हुए सीपीएसई/ सांविधिक निगमों की सूची, जिनके बांड/डिबेंचर/ गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थीं	415
XVIII	सीपीएसई की सूची जिनके शेयर एवं डिबेंचर दोनों स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे	417	

अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
	XIX वे सीपीएसई जहां अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं	418
	XX चयनित सीपीएसई के नाम	426
	XXI क सीपीएसई की सूची	428
	XXI ख चयनित सीपीएसई की सूची	443
	XXII सीएसआर नीति तैयार करना	447
	XXIII कुल सीएसआर व्यय	450
	XXIII क कुल सीएसआर व्यय (दायित्व से अधिक)	455
	XXIII ख 2023-24 के लिए कोई दायित्व नहीं	458
	XXIII ग कुल सीएसआर व्यय दायित्व से कम	459
	XXIII घ कुल सीएसआर व्यय दायित्व के बराबर	461
	XXIV रत्न श्रेणी-वार सीएसआर व्यय	463
	XXV मंत्रालय-वार/विभाग-वार सीएसआर व्यय	469
	XXVI श्रेणी-वार सीएसआर व्यय	474
	XXVII अव्ययित राशि	477
	XXVIII सीएसआर पर प्रशासनिक उपरिव्यय एवं प्रभाव आकलन	482
	XXIX सामान्य विषय पर व्यय	486
	XXIX क आकांक्षी जिला-वार सीएसआर व्यय	491
	XXX आवश्यकता आकलन के आधार पर सीएसआर परियोजनाओं/ गतिविधियों का चयन	572
	XXXI सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका	576
	XXXI क सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका	581
	XXXI ख सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका	582
	XXXI ग सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका	583
	XXXI घ सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका	586
	XXXI इ सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका	587
	XXXII अनुसूची VII के अनुसार फोकस क्षेत्र	588
	XXXIII स्थानीय क्षेत्र	596
	XXXIV वेबसाइट पर सीएसआर आँकड़ों का प्रकटीकरण	600
	XXXV सीएसआर रिपोर्टिंग प्रारूप	603

अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
	XXXVI सृजित/अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्तियाँ	606
	XXXVII प्रभाव आकलन	609
	XXXVIII वर्ष 2022-23 तथा उसके बाद के लिए समझौता जापन के मापदंड एवं उनका संबंधित भारांक	612
	XXXIX वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए समझौता जापन के मापदंडों के संबंध में मानक लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ	613
	XL रणनीतिक विनिवेश की स्थिति	619
	XLI पीएसई की सहायक कंपनियों/ इकाइयों के बंद होने/ विनिवेश का विवरण	621
	XLII समीक्षा के लिए चयनित सीपीएसई की सूची	623
	XLIII खंड-क के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण	625
	XLIV खंड-ख के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण	627
	XLV खंड-ग के सिद्धांत1 के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण	629
	XLVI खंड-ग के सिद्धांत2 के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण	631
	XLVII खंड-ग के सिद्धांत3 के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण	633
	XLVIII खंड-ग के सिद्धांत4 के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण	636
	XLIX खंड-ग के सिद्धांत 5 के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण	637
	L खंड-ग के सिद्धांत 6 के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण	640
	LI खंड-ग के सिद्धांत 7 के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण	643
	LII खंड-ग के सिद्धांत 8 के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण	644
	LIII खंड-ग के सिद्धांत 9 के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण	646

प्राक्कथन

कंपनी अधिनियम, के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) द्वारा प्रमाणित लेखाओं की सीएजी के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सीएजी अपनी टिप्पणियाँ देता है अथवा सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदनों का अनुपूरण करता है। इसके अतिरिक्त, ये कंपनियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(7) के प्रावधानों के अंतर्गत सीएजी द्वारा नमूना लेखापरीक्षा के अधीन भी होती हैं।

कुछ निगमों एवं प्राधिकरणों को शासित करने वाले अधिनियमों में यह प्रावधान है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाएगी। ऐसे छः निगमों, अर्थात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम, दामोदर घाटी निगम तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के संबंध में संबंधित अधिनियमों में सीएजी को उनका एकमात्र लेखापरीक्षक नामित किया गया है। एक निगम, अर्थात् केंद्रीय भंडारण निगम के संबंध में, उसके लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की नियुक्ति सरकार द्वारा सीएजी की सलाह पर की जाती है। सीएजी को आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है।

सरकारी कंपनी या निगम के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन, सीएजी द्वारा सरकार को संसद में प्रस्तुत करने हेतु, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदनों में आठ अध्याय अर्थात् केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश, सीएजी की पर्यवेक्षणात्मक भूमिका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सीपीएसई द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर व्यय, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रशासनिक मंत्रालयों और नवरत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापनों का विश्लेषण, सीपीएसई में विनिवेश तथा सततता की स्थिति की समीक्षा शामिल हैं। जिन सीपीएसई के संबंध में किसी विशेष वर्ष के लेखे 31 दिसंबर, 2024 से पहले प्राप्त नहीं हुए थे, उनके लिए अंतिम लेखापरीक्षित लेखाओं के आंकड़े अपनाए गए हैं। अध्याय-1 के कुछ सीपीएसई के संबंध में पिछले वर्ष के आंकड़े, 2025 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 23, में दर्शाए गए संबंधित आंकड़ों से मेल नहीं खा सकते, क्योंकि अनंतिम आंकड़ों को लेखापरीक्षित/संशोधित आंकड़ों से प्रतिस्थापित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 'कंपनियों/निगमों' या 'सीपीएसई' के सभी संदर्भों को, जब तक संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो, 'केंद्रीय सरकारी कंपनियों/निगमों' के रूप में समझा जाए।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सीपीएसई के प्रबंधन तथा उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है।

कार्यकारी सारांश

I. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

प्रस्तावना

31 मार्च, 2024 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 757 केंद्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) थे। इनमें 521 सरकारी कंपनियाँ, 229 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ तथा सात सांविधिक निगम शामिल थे। यह प्रतिवेदन 684 सीपीएसई के वित्तीय निष्पादन को प्रस्तुत करता है, जिनमें 479 सरकारी कंपनियाँ एवं निगम (सात सांविधिक निगमों सहित) तथा 205 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ शामिल हैं। 73 सीपीएसई (जिनमें 24 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ शामिल हैं), जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या जो परिसमापनाधीन थे अथवा जिनके प्रथम लेखे देय नहीं थे/प्राप्त नहीं हुए थे, इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं हैं।

(पैरा 1.1.3)

केंद्रीय सरकार का निवेश

479 सरकारी कंपनियों एवं निगमों के लेखाओं के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक केंद्रीय सरकार का अंश पूंजी में ₹11,93,439 करोड़ का इक्विटी निवेश था। 31 मार्च, 2024 को ऐसे सीपीएसई को दिए गए दीर्घकालिक ऋणों की बकाया राशि ₹2,87,678 करोड़ थी। पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 2023-24 के दौरान ऐसे सीपीएसई की इक्विटी में केंद्रीय सरकार की हिस्सेदारी में ₹2,68,767 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई तथा दीर्घकालिक ऋणों की बकाया राशि में ₹1,63,332 करोड़ की वृद्धि हुई।

(पैरा 1.2, 1.2.1 एवं 1.2.2.1)

बाजार पूंजीकरण

वर्ष 2023-24 के दौरान, 66 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (जिनमें नौ सहायक कंपनियाँ शामिल हैं तथा वर्ष के दौरान नव-सूचीबद्ध तीन सीपीएसई को छोड़कर), जिनके शेयरों का कारोबार हुआ, का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च, 2024 का ₹37,92,736 करोड़ था। इन 66 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (नौ सहायक कंपनियों सहित) में केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाले शेयरों का बाजार मूल्य 31 मार्च, 2024 को ₹23,51,459 करोड़ था।

(पैरा 1.2.4)

सरकारी कंपनियों एवं निगमों से प्राप्त प्रतिफल

वर्ष 2023-24 के दौरान 282 सरकारी कंपनियों एवं निगमों ने ₹3,58,385 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जिसमें से 70.46 प्रतिशत (₹2,52,535 करोड़) का योगदान तीन क्षेत्रों अर्थात् पेट्रोलियम, विद्युत तथा कोयला एवं लिग्नाइट की 79 सीपीएसई द्वारा किया गया। वर्ष 2023-24 में इन 282 सीपीएसई का इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) 16.28 प्रतिशत रहा, जबकि वर्ष 2022-23 में 259 सीपीएसई का यह 13.75 प्रतिशत था।

(पैरा 1.3.1)

134 सरकारी कंपनियों एवं निगमों ने वर्ष 2023-24 के लिए ₹1,38,138 करोड़ का लाभांश घोषित किया। इसमें से केंद्र सरकार को प्राप्त/प्राप्य लाभांश ₹65,071 करोड़ था, जो सभी 479 सरकारी कंपनियों एवं निगमों की अंश पूंजी में केंद्र सरकार के कुल निवेश (₹11,93,439 करोड़) पर 5.45 प्रतिशत प्रतिफल को दर्शाता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाली 11 सरकारी कंपनियों ने ₹50,469 करोड़ का योगदान दिया, जो सभी सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 36.54 प्रतिशत है।

(पैरा 1.3.4)

हानियाँ/संचित हानियाँ

वर्ष 2023-24 के दौरान 182 सरकारी कंपनियों को ₹34,908 करोड़ की हानि हुई। 31 मार्च, 2024 तक 214 सरकारी कंपनियों में ₹2,47,181 करोड़ की संचित हानियाँ थीं। इनमें से 91 कंपनियों की निवल मुल्य उनकी संचित हानियों के कारण पूर्णतः समाप्त हो गई थी। परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2024 तक इन कंपनियों का समग्र निवल मुल्य ₹58,175 करोड़ तक श्रणात्मक हो गया। इन 91 सीपीएसई में से 21 ने वर्ष 2023-24 के दौरान ₹961 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

(पैरा 1.3.2 एवं 1.3.3.1)

बिक्री एवं विपणन

479 सरकारी कंपनियों एवं निगमों की कुल बिक्री ₹36,44,513 करोड़ थी। इनमें से 117 सीपीएसई ने सरकारी क्षेत्र को ₹3,94,081 करोड़ मूल्य के माल/सेवाओं की बिक्री/सेवाएँ प्रदान कीं, जो उनकी कुल बिक्री का 22.46 प्रतिशत थी।

(पैरा 1.4.3.1)

II. सीएजी की पर्यवेक्षणात्मक भूमिका

31 मार्च, 2024 की स्थिति में सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 757 सीपीएसई (सात सांविधिक निगमों सहित) थे। इनमें से 607 सीपीएसई के 2023-24 के वित्तीय विवरण 30 सितंबर, 2024 तक प्राप्त हुए। सीएजी ने 327 सीपीएसई (सात सांविधिक निगमों सहित) के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की।

चयनित सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर सीएजी द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों का लाभप्रदता तथा परिसंपत्तियों/देयताओं पर वित्तीय प्रभाव क्रमशः ₹3,563.37 करोड़ तथा ₹61,949.59 करोड़ था। कुछ कंपनियों, अर्थात् ट्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अतीत में उनके वित्तीय विवरणों पर सीएजी द्वारा जारी टिप्पणियों पर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

(पैरा 2.5.1)

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखांकन मानकों/इंड एस के प्रावधानों से विचलन 21 सीपीएसई में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा पाए गए। सीएजी ने भी 27 सीपीएसई में ऐसे विचलन को इंगित किया।

(पैरा 2.6)

सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सीएजी द्वारा टिप्पणियों के रूप में रिपोर्ट की गईं। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय रिपोर्टों या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में देखी गई अनियमितताओं एवं कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु 304 सीपीएसई के प्रबंधन को 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से सूचित किया गया। वर्ष के दौरान जारी प्रबंधन पत्रों के आधार पर सीपीएसई के प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण सुधार किए गए।

(पैरा 2.7)

III. कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रणाली

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की समीक्षा में 65 ऐसे सूचीबद्ध सीपीएसई शामिल थे, जिनके अंश शेयर बाजारों में सूचीबद्ध थे (जिनमें 22 सीपीएसई ऐसे थे जिनके शेयर एवं बांड/ऋणपत्र दोनों सूचीबद्ध थे) तथा 36 ऐसे सीपीएसई/सांविधिक निगम शामिल थे (जिनमें चार सांविधिक निगम, अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम शामिल थे), जिनके केवल बांड/ऋणपत्र 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में शेयर बाजारों में सूचीबद्ध थे। यह पाया गया कि कुछ सीपीएसई/सांविधिक निगमों द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के विनियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

(पैरा 3.1.2)

वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि 65 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 58 में गैर-कार्यकारी निदेशकों की आवश्यक संख्या (कुल बोर्ड संख्या का कम से कम 50 प्रतिशत) उपलब्ध थी, जबकि सात सीपीएसई इस आवश्यकता का पालन 2 माह से 12 माह की अवधि तक नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त, 49 सीपीएसई (75 प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या बोर्ड में उपलब्ध नहीं थी, जिसकी अवधि 1 माह से 12 माह तक रही (कमी का प्रतिशत 13 से 100 प्रतिशत के बीच था)।

(पैरा 3.2.1 एवं 3.2.2)

65 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 58 के बोर्ड में महिला निदेशक उपलब्ध थीं, जबकि सात सीपीएसई (11 प्रतिशत) में वर्ष 2023-24 के दौरान 2 से 12 माह की अवधि तक बोर्ड में महिला निदेशक नहीं थीं। इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(a) के अनुसार शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध इकाइयों के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होना अनिवार्य है। तथापि, शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध इकाइयों का हिस्सा रहे 60 सीपीएसई में से 16 सीपीएसई में वर्ष 2023-24 के दौरान 2 से 12 माह की अवधि तक बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थीं।

(पैरा 3.2.3)

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध इकाइयों के निदेशक मंडल में कम से कम छः निदेशक होने चाहिए। निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा से यह पाया गया कि 62 सीपीएसई (जो शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध इकाइयों का हिस्सा थे) में से पाँच सीपीएसई में यह मानदंड पूरा नहीं किया गया था।

(पैरा 3.2.4)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की सभी बैठकों, जिन बोर्ड समितियों के वे सदस्य हैं उनकी बैठकों तथा कंपनी की आम बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 65 सूचीबद्ध सीपीएसई में से दो सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों ने वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड एवं उसकी समितियों की कम से कम 80 प्रतिशत बैठकों में भाग नहीं लिया। इसके अतिरिक्त, छः सीपीएसई (नौ प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों ने सीपीएसई की आम बैठकों में भाग नहीं लिया।

(पैरा 3.3.1 एवं 3.3.2)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(4) के अनुसार, यदि किसी पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पद रिक्त हो जाता है, तो उस रिक्ति को बोर्ड द्वारा उस रिक्ति की तिथि से छः माह के भीतर भरा जाना चाहिए। तथापि, 65 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 12 सीपीएसई (18 प्रतिशत) में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की रिक्ति छः माह की निर्धारित अवधि के भीतर नहीं भरी गई। विलंब निर्धारित समय-सीमा से आगे 5 माह से 37 माह तक रहा।

(पैरा 3.4)

एक सीपीएसई (दो प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था; चार सीपीएसई (छः प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे; दो सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने एजीएम में भाग नहीं लिया। पाँच सीपीएसई (आठ प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति की कोरम आवश्यकता अपर्याप्त था।

(पैरा 3.6.1.1, 3.6.1.2, 3.7 एवं 3.6.3)

अनुशंसा:

प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करें कि सूचीबद्ध सीपीएसई/सांविधिक निगमों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी विनियमों तथा डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए। ऐसे सूचीबद्ध उपक्रमों के निदेशक मंडल/प्रबंधन भी अपने कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।

IV. सीपीएसई द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

यह अध्याय 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान 26 चयनित रत्न श्रेणी सीपीएसई द्वारा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर किए गए व्यय को आच्छादित करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि सरकारी दिशानिर्देशों के अभाव में सीपीएसई अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को अपनाने हेतु समर्पित एवं एकरूप नीति बनाने के लिए बाध्य नहीं थे।

लेखापरीक्षा हेतु चयनित 26 सीपीएसई में से आधे से अधिक के पास समर्पित नीति नहीं थी तथा उन्होंने इसके स्थान पर गुणवत्ता नीति/कार्य योजना/अन्य संबंधित दिशानिर्देश/ढाँचा दस्तावेज आदि का पालन किया।

(पैरा 4.5.1)

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान, 9-13 सीपीएसई (महानवरत्न, नवरत्न एवं मिनीरत्न) ने अनुसंधान एवं विकास पर कर-पूर्व लाभ के 2 प्रतिशत से कम व्यय किया, जबकि तीन सीपीएसई (एक नवरत्न तथा दो मिनीरत्न) ने इस अवधि में अनुसंधान एवं विकास पर कोई व्यय नहीं किया।

(पैरा 4.5.2.2)

यद्यपि चयनित अधिकांश रत्न सीपीएसई में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सुव्यवस्थित तंत्र उपलब्ध था, तथापि अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के प्रभावी अनुवीक्षण का अभाव पाया गया। 26 सीपीएसई में से केवल 13 में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के आवधिक अनुवीक्षण हेतु शीर्ष/समीक्षा/उप-समिति उपलब्ध थी।

(पैरा 4.5.4)

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के पूर्ण होने में 1 से 69 माह तक के महत्वपूर्ण विलंब पाए गए। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान 22 सीपीएसई द्वारा लिए गए 6,783 परियोजनाओं में से 5,816 परियोजनाएँ पूर्ण की गईं, जिनमें 1,652 परियोजनाएँ निर्धारित पूर्णता तिथि के बाद पूर्ण हुईं तथा 172 परियोजनाएँ चल रही थीं, किन्तु उनमें भी विलंब था।

(पैरा 4.5.3.1)

चयनित 26 सीपीएसई में से 12 सीपीएसई ने अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के व्यावसायीकरण के माध्यम से ₹33,977.35 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। 16 सीपीएसई द्वारा 1,670 शोध पत्र प्रकाशित किए गए तथा 10 सीपीएसई ने कोई भी शोध पत्र प्रकाशित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, 17 सीपीएसई द्वारा पंजीकरण हेतु दाखिल 2,436 पेटेंट में से 952 पेटेंट प्रदान किए गए, 1,466 पेटेंट आवेदन प्रक्रियाधीन थे तथा 18 अस्वीकृत किए गए।

(पैरा 4.5.6.1, 4.5.6.2 एवं 4.5.7)

अनुशंसा:

- सीपीएसई के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर समर्पित नीति/दिशानिर्देश विकसित करने पर सरकार विचार करे।
- अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के समयबद्ध पूर्णता तथा अपेक्षित प्रभाव प्राप्त करने के लिए बेहतर अनुवीक्षण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करने हेतु तंत्रस्थापित किए जाने चाहिए।
- नवाचार को बढ़ावा देने, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने तथा दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता में योगदान देने के लिए नियमित कार्यशालाओं, वेबिनारों एवं प्रोत्साहनों के माध्यम से सीपीएसई को अनुसंधान एवं विकास के रणनीतिक महत्व को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

V. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

समीक्षा में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 58 सीपीएसई (10 महा-रत्न, 12 नवरत्न, 18 मिनीरत्न एवं 18 अन्य) को शामिल किया गया। समीक्षा के अंतर्गत 58 सीपीएसई के संबंध में मार्च 2024 को समाप्त एक वर्ष की अवधि को कवर किया गया।

समीक्षा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अवलोकन किए गए:

पाँच सीपीएसई (एनएफडीसीएल, एसडीसीएल, जेकेडीएफसीएल, आईएल, नेरामैक) ने सीएसआर समिति का

गठन नहीं किया। एनएफडीसीएल और एसडीसीएल को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं थी। जबकि जेकेडीएफसीएल, आईएल और नेरामैक का शुद्ध लाभ पाँच करोड़ की सीमा से कम होने के कारण उन पर सीएसआर लागू नहीं था। कॉनकोर के मामले में सीएसआर समिति में केवल दो निदेशक थे। आठ सीपीएसई ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित सीएसआर नीति तैयार नहीं की थी। अठारह सीपीएसई ने वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की थी।

(पैरा 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3)

वित्त वर्ष 2023-24 में 58 सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर कुल व्यय ₹3,339.80 करोड़ था। 15 सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय में कमी की सूचना दी। कुल सीएसआर व्यय में पेट्रोलियम एवं विद्युत क्षेत्र का व्यय 69 प्रतिशत था। तीन सीपीएसई, ओएनजीसी, आईओसीएल और पीजीसीआईएल में कुल सीएसआर व्यय का 42.60 प्रतिशत हिस्सा था।

(पैरा 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3)

58 सीपीएसई में से 18 सीपीएसई के पास वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में ₹517.48 करोड़ की अव्ययित राशि थी। इन अठारह सीपीएसई ने शेष अव्ययित सीएसआर बजट को या तो अव्ययित सीएसआर लेखे में या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी कोष में निर्धारित समय सीमा के भीतर हस्तांतरित कर दिया। इन 18 सीपीएसई में से चार सीपीएसई ने अव्ययित राशि को अव्ययित सीएसआर लेखे तथा अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट कोष—दोनों में स्थानांतरित किया।

(पैरा 5.4.4)

वर्ष 2023-24 के दौरान 29 सीपीएसई ने प्रशासनिक उपरिव्यय पर ₹112.03 करोड़ व्यय किया तथा 20 सीपीएसई ने प्रभाव आकलन पर ₹7.47 करोड़ व्यय किया। वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर व्यय मुख्यतः स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित गतिविधियों पर केंद्रित रहा। 58 सीपीएसई में से 26 सीपीएसई सामान्य विषय “स्वास्थ्य एवं पोषण” पर 60 प्रतिशत व्यय के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। 37 सीपीएसई ने आकांक्षी जिलों में सामान्य विषय पर सीएसआर व्यय किया (₹277.20 करोड़), जो कुल सीएसआर व्यय का 8.30 प्रतिशत है।

(पैरा 5.4.5 एवं 5.4.6)

आठ सीपीएसई ने 198 परियोजनाओं/गतिविधियों के संबंध में आधारभूत सर्वेक्षण/आवश्यकता आकलन अध्ययन नहीं किया।

(पैरा 5.5.1)

58 सीपीएसई में से चार सीपीएसई ने केवल आंतरिक परियोजनाएँ ही संचालित कीं, छः सीपीएसई ने सभी सीएसआर परियोजनाएँ बाह्य एजेंसियों को आउटसोर्स कीं, तथा बत्तीस सीपीएसई ने आंतरिक परियोजनाओं के साथ-साथ बाह्य एजेंसियों को आउटसोर्स की गई सीएसआर परियोजनाएँ दोनों प्रकार से संचालित कीं।

(पैरा 5.5.2)

तेरह सीपीएसई ने अपनी सीएसआर नीति में स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया तथा आठ सीपीएसई ने स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी।

(पैरा 5.5.4)

पाँच सीपीएसई ने सीएसआर गतिविधियों का प्रकटीकरण अपनी वेबसाइट पर नहीं किया। सात सीपीएसई ने कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2022 (नियम 5-अनुलग्नक II) द्वारा निर्धारित वार्षिक प्रतिवेदन में सीएसआर गतिविधियों की रिपोर्टिंग हेतु निर्धारित प्रकटीकरण प्रारूप का अनुपालन नहीं किया।

(पैरा 5.7.1 एवं 5.7.2)

VI. प्रशासनिक मंत्रालयों और नवरत्न सीपीएसई के बीच समझौता जापन का विश्लेषण

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए छः नवरत्न सीपीएसई तथा उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच हुए समझौता जापनों का विश्लेषण किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

डीपीई द्वारा जारी समझौता जापन दिशानिर्देशों में समझौता जापन मापदंडों को अंतिम रूप देने हेतु अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक आयोजित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। आईएमसी बैठक आयोजित होने से लेकर समझौता जापन पर हस्ताक्षर होने तक का समय वर्ष 2022-23 में चयनित छः में से पाँच सीपीएसई के मामले में 27 से 75 दिनों के बीच रहा तथा वर्ष 2023-24 में छः में से पाँच चयनित सीपीएसई के मामले में यह अवधि 24 से 56 दिनों के बीच रही।

(पैरा 6.5.1.1)

छः चयनित सीपीएसई में से पाँच के संबंध में, मंत्रालयों ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए समझौता जापन लक्ष्यों के अंतिम निर्धारण हेतु समझौता जापन डैशबोर्ड पर क्षेत्रीय विजन प्लान तैयार कर अपलोड नहीं किया।

(पैरा 6.5.1.2)

डीपीई दिशानिर्देशों में समझौता जापन के अंतिम रूप देने और अपलोड करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी; परिणामस्वरूप, वर्ष 2022-23 के लिए ईआईएल और एनएमडीसी के संबंध में समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने में विलंब हुआ।

(पैरा 6.5.1.3)

ईआईएल के मामले में, वर्ष 2023-24 के लिए इसकी सहायक कंपनी सीईआईएल के साथ समझौता जापन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लगभग अंत में हस्ताक्षरित किया गया, जिससे सहायक कंपनी के पास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत कम समय उपलब्ध रहा। इसके अतिरिक्त, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के मामले में, इसकी सहायक कंपनी इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड को वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए समझौता जापन पर हस्ताक्षर से छूट प्रदान करने में क्रमशः नौ माह और दो माह का विलंब हुआ।

(पैरा 6.5.1.4)

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी (एलओडीआर) विनियमों के प्रावधानों, जैसे कि स्वतंत्र निदेशकों/स्वतंत्र महिला निदेशकों की न्यूनतम संख्या, का अनुपालन न किए जाने के बावजूद, प्रशासनिक मंत्रालयों तथा डीपीई ने समझौता जापन दिशानिर्देशों के अनुसार सीपीएसई के समझौता जापन अंकों में आवश्यक कटौती नहीं की।

(पैरा 6.5.2.1)

ईआईएल और एससीआई के मामले में, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों ने 2022-23 और 2023-24 के लिए समझौता ज्ञापन अनुपालन मापदंड 'सीपीएसई' में मानव संसाधनों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। हालाँकि, डीपीई ने इस मापदंड के अनुपालन का उल्लेख किया और 2022-23 और 2023-24 की समझौता ज्ञापन मूल्यांकन रिपोर्ट में कोई अंक नहीं काटा।

(पैरा 6.5.2.3)

अनुपालन मापदंड "संपत्ति मुद्रीकरण माइलस्टोन पर नीति आयोग द्वारा दिए गए लक्ष्य" को समझौता ज्ञापन मूल्यांकन के दौरान डीपीई पोर्टल/डैशबोर्ड से हटा दिया गया, जबकि यह मापदंड हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का हिस्सा था।

(पैरा 6.5.2.4)

सीपीएसई को समझौता ज्ञापन वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए क्रमशः 31 दिसंबर, 2021 और 31 दिसंबर, 2022 तक कुछ वित्तीय एवं भौतिक विशेषताओं के अनुमानित आंकड़े समझौता ज्ञापन डैशबोर्ड पर अपलोड करने की आवश्यकता थी। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि छः चयनित सीपीएसई द्वारा अनुमानित आंकड़े वर्ष 2022-23 के लिए 87 से 104 दिनों के विलंब से तथा वर्ष 2023-24 के लिए 55 से 76 दिनों के विलंब से अपलोड किए गए।

(पैरा 6.5.3.1)

वर्ष 2022-23 के लिए डीपीई ने छः चयनित सीपीएसई के संबंध में अंतिम रैंकिंग/अंक प्रदान करने में 55 से 100 दिनों तथा वर्ष 2023-24 के लिए 68 से 92 दिनों तक का काफी समय लिया।

(पैरा 6.5.3.2)

VII. विनिवेश प्रक्रिया

वर्ष 2023-24 के दौरान निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने विनिवेश के माध्यम से ₹16,507.29 करोड़ की राशि प्राप्त की (प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम, बिक्री हेतु प्रस्ताव, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम से प्राप्त धनराशि तथा खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से)।

(पैरा 7.5)

विनिवेश हेतु लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष 2023-24 के लिए विनिवेश से प्राप्तियों का बजट अनुमान आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा ₹51,000 करोड़ निर्धारित किया गया था। तथापि, वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों में विनिवेश के लिए कोई विशिष्ट अनुमान निर्धारित नहीं किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान वास्तविक विनिवेश प्राप्तियाँ ₹16,507.29 करोड़ रही।

(पैरा 7.4)

लाभांश आय को विनिवेश प्राप्ति के रूप में माना गया

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम (एसयूटीआई) ने (मार्च 2024) ₹1,770 करोड़ की लाभांश आय दीपम को प्रेषित की (मार्च 2024), जिसे दीपम द्वारा वर्ष 2023-24 की विनिवेश प्राप्तियों के भाग के रूप में रिपोर्ट

किया गया (वार्षिक प्रतिवेदन)। चूँकि लाभांश आय सरकारी शेयरधारिता की बिक्री से प्राप्त प्रेषण का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे विनिवेश प्राप्तियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

{पैरा 7.6.5 (क)}

एक्सिस बैंक लिमिटेड में सरकार की शेयरधारिता की बिक्री

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम (एसयूटीआई) द्वारा एक्सिस बैंक लिमिटेड के शेयरों की बिक्री से प्राप्त ₹40.32 करोड़ की विनिवेश प्राप्तियाँ दीपम को प्रेषित की गईं (3 अप्रैल, 2023), जिन्हें 'सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों के विनिवेश' शीर्ष के स्थान पर 'सरकारी लेखे में अन्य प्राप्तियाँ' शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित किया गया। इसके परिणामस्वरूप एक्सिस बैंक लिमिटेड के शेयरों की बिक्री से प्राप्त विनिवेश प्राप्तियों का गलत लेखांकन हुआ।

{पैरा 7.6.5 (ख)}

VIII. सततता की स्थिति की समीक्षा

सेबी (जुलाई 2023) ने सूचीबद्ध इकाइयों के लिए पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन प्रकटीकरण आवश्यकताओं को सुदृढ़ करने तथा आश्वासन बढ़ाने हेतु बीआरएसआर कोर रूपरेखा प्रस्तुत की। विनियमों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 31 मार्च, 2024 तक बाजार पूंजीकरण के आधार पर भारत की शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बीआरएसआर प्रकटीकरण शामिल करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, शीर्ष 150 इकाइयों को बीआरएसआर कोर प्रकटीकरणों के लिए यथोचित आश्वासन प्राप्त करना अनिवार्य है ताकि उनकी सटीकता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। लेखापरीक्षा ने वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2024 के लिए बाजार पूंजीकरण के आधार पर 30 सीपीएसई द्वारा किए गए प्रकटीकरणों की समीक्षा की।

सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर रूपरेखा तीन खंडों में विभाजित है, जिसमें कुल 145 संकेतक शामिल हैं।

- खंड क: सामान्य प्रकटीकरण (26 संकेतक): इकाई से संबंधित मूलभूत जानकारी को शामिल करता है।
- खंड ख: प्रबंधन एवं प्रक्रिया प्रकटीकरण (12 संकेतक)।
- खंड ग: सिद्धांत-वार निष्पादन प्रकटीकरण।

खंड ग को नौ सिद्धांतों में विभाजित किया गया है, जो इकाई के निष्पादन पर प्रकटीकरण की मांग करते हैं। नौ सिद्धांतों को 68 आवश्यक संकेतकों तथा 39 नेतृत्व संकेतकों में विभाजित किया गया है। आवश्यक संकेतकों पर अनिवार्य रूप से रिपोर्टिंग करनी आवश्यक थी, जबकि नेतृत्व संकेतक स्वैच्छिक थे।

लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए प्रमुख अवलोकन निम्नलिखित हैं:

- इकाइयों को अपने प्रदत्त पूँजी का प्रकटीकरण करना आवश्यक था। रिपोर्टिंग के दौरान, एक इकाई द्वारा वर्ष 2023-24 के स्थान पर वर्ष 2022-23 की प्रदत्त पूँजी का प्रकटीकरण किया गया।

{पैरा 8.5.1}

- इकाइयों को रिपोर्टिंग सीमा का प्रकटीकरण करना आवश्यक था, अर्थात् यह बताना कि रिपोर्टिंग एकल आधार पर की गई है या समेकित आधार पर। यद्यपि रिपोर्टिंग सीमा "समेकित आधार" थी, फिर भी सभी सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों एवं सहयोगी संस्थाओं आदि का विवरण शामिल नहीं किया गया।

{पैरा 8.5.1}

- इकाइयों को अपने कुल कर्मचारियों एवं श्रमिकों का लिंग-वार विभाजित विवरण, स्थायी एवं अस्थायी श्रेणी के अंतर्गत, तथा प्रत्येक श्रेणी में दिव्यांग व्यक्तियों सहित, प्रकटीकरण करना आवश्यक था। तथापि प्रकटीकरण में असंगतियाँ पाई गईं, जैसे लिंग-वार विभाजन का अभाव, दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित विवरण का अभाव आदि।

(पैरा 8.5.1)

- इकाइयों के लिए आवश्यक था कि वे अपनाए गए राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय कोड/प्रमाणनों की मैपिंग करें। तथापि, सीपीएसई द्वारा यह प्रकटीकरण किया गया कि कोड/मानक आदि अपनाए गए हैं, परंतु ऐसे कोड/मानक इकाई के पास उपलब्ध नहीं थे। सीपीएसई द्वारा इन कोड/मानकों की मैपिंग भी नहीं की गई।

(पैरा 8.5.2)

- इकाइयों को परिभाषित समय-सीमा सहित विशिष्ट प्रतिबद्धता/लक्ष्य तथा उसके विरुद्ध प्राप्त उपलब्धियों का प्रकटीकरण करना आवश्यक था। तथापि, प्रकट किए गए लक्ष्य मापनीयता एवं निर्धारित समय-सीमा से रहित थे तथा रिपोर्ट की गई उपलब्धियाँ विशिष्ट न होकर सामान्य प्रकृति की थीं।

(पैरा 8.5.2)

- इकाइयों को संबंधित पक्षों के साथ की गई खरीद, बिक्री, ऋण तथा निवेश का विवरण प्रकटीकृत करना आवश्यक था। तथापि, संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन होने के बावजूद सूचना को 'शून्य' के रूप में प्रकटीकृत किया गया।

(पैरा 8.5.3.1)

- स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा आच्छादन, मातृत्व/पितृत्व लाभ तथा सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर्गत आच्छादन के संबंध में गलत/त्रुटिपूर्ण प्रकटीकरण के मामले पाए गए।

(पैरा 8.5.3.3)

- विभिन्न मामलों में वेब लिंक्स जैसे, हितधारकों हेतु शिकायत निवारण नीति, समान अवसर नीति तथा साइबर सुरक्षा नीतिका प्रकटीकरण नहीं किया गया।

(पैरा 8.5.1, 8.5.3.3 एवं 8.5.3.9)

- आच्छादन संबंधी मुद्दों, जैसे प्रशिक्षण आच्छादन तथा यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के संबंध में गलत/अपूर्ण प्रकटीकरण के उदाहरण पाए गए।

(पैरा 8.5.3.5)

- ऊर्जा एवं जल खपत, वायु उत्सर्जन तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संबंध में खपत एवं उत्सर्जन विवरण का प्रकटीकरण न किए जाने, सभी इकाइयों/संयंत्रों को शामिल न किए जाने तथा इकाइयों एवं स्वतंत्र आकलन का प्रकटीकरण न किए जाने के मामले पाए गए।

(पैरा 8.5.3.6)

- एक सीपीएसई ने सेबी द्वारा जुलाई 2023 में निर्धारित संशोधित प्रारूप के अनुसार अपना बीआरएसआर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप सेबी की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं हुआ।

(पैरा 8.5.4.2)

अध्याय I

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

अध्याय I

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

1.1 परिचय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में सरकारी कंपनी को ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत चुकता शेयर पूंजी केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित होती है, और इसमें ऐसी कंपनी भी सम्मिलित है जो किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

सरकारी कंपनी

कोई भी कंपनी जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत चुकता शेयर पूंजी केंद्र सरकार या एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा धारित हो और इसमें सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त, कोई अन्य कंपनी¹ केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित कंपनियों को इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

प्रतिवेदन के इस अध्याय में सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय निष्पादन का सारांश प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन में, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) शब्द से अभिप्राय उन सरकारी कंपनियों से है जिनमें केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है और ऐसी सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियां भी सम्मिलित हैं। संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगमों और केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व या नियंत्रण वाली अन्य कंपनियों को भी सीपीएसई की श्रेणी में रखा गया है।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने लोक उद्यम सर्वेक्षण 2023-24 में कहा (दिसंबर 2024) कि सांविधिक निगमों के अलावा सीपीएसई का अर्थ उन सरकारी कंपनियों से है जिनमें केंद्र सरकार की 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी हिस्सेदारी है।

इन कंपनियों की सहायक कंपनियां, यदि भारत में पंजीकृत हैं, तो उन्हें भी सीपीएसई की श्रेणी में रखा गया है। इसमें विभागीय रूप से संचालित लोक उद्यम, बैंकिंग संस्थान और बीमा कंपनियां सम्मिलित नहीं हैं।

¹ कंपनियों (कठिनाइयों का निवारण) सातवां आदेश, 2014, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 04 सितंबर, 2014 के माध्यम से जारी किया गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) और डीपीई द्वारा अपनाई गई परिभाषा में अंतर के कारण, सीएजी और डीपीई द्वारा सीपीएसई के रूप में मानी जाने वाली कंपनियों की संख्या में अंतर था। परिणामस्वरूप, डीपीई के लोक उद्यम सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सीपीएसई की संख्या 448 थी, जबकि इस प्रतिवेदन के अनुसार सीपीएसई की संख्या 757 थी (528 सरकारी कंपनियां और सांविधिक निगम तथा 229 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां)।

1.1.1 अधिदेश

सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के साथ-साथ, सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सीएजी सनदी लेखाकारों को सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं और इन कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के तरीके पर निर्देश देते हैं। इसके अतिरिक्त, सीएजी को पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को नियंत्रित करने वाली विधियों के अनुसार, उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल सीएजी द्वारा ही किए जाने का प्रावधान है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों में ऐसे प्रावधान हैं जिनके अंतर्गत केंद्र सरकार किसी भी समय सीएजी को इन संस्थानों के लेखाओं की जांच और रिपोर्ट करने के लिए लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। 2023-24 तक ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

1.1.2 इस प्रतिवेदन में निहित विषय

यह प्रतिवेदन सीपीएसई के लेखाओं से परिलक्षित उनके वित्तीय निष्पादन का समग्र चित्रण प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में सीएजी द्वारा वर्ष 2023-24 (और पिछले वर्षों के लिए, जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया था) के लिए किए गए सीपीएसई के वित्तीय विवरणों के पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी किए गए वित्तीय विवरणों के संशोधन के प्रभाव के साथ-साथ महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण दिया गया है। इस प्रतिवेदन में सीएजी द्वारा उन सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर जारी की गई टिप्पणियों का प्रभाव भी सम्मिलित है, जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है।

यह प्रतिवेदन सीपीएसई द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 के निगमित शासन, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, समझौता ज्ञापनों के विश्लेषण और सूचीबद्ध सीपीएसई में स्थिरता की स्थिति की समीक्षा (व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग) के साथ-साथ सीपीएसई में विनिवेश और सीपीएसई द्वारा अनुसंधान और विकास में किए गए व्यय की समीक्षा की स्थिति का समग्र चित्र भी प्रस्तुत करती है।

1.1.3 सीपीएसई की संख्या

31 मार्च, 2024 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 757 सीपीएसई (अनुलग्नक-I) थे। इनमें 521 सरकारी कंपनियाँ², सात सांविधिक निगम³ एवं 229 सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियाँ सम्मिलित हैं। इनमें से, 684 सीपीएसई के वित्तीय निष्पादन का सारांश इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है और इन सीपीएसई की प्रकृति नीचे तालिका 1.1 में दर्शाई गई है:

सरकारी कंपनियाँ	521
सांविधिक निगम	7
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	229
कुल सीपीएसई	757

तालिका 1.1: इस प्रतिवेदन में सम्मिलित सीपीएसई का दायरा और प्रकृति

सीपीएसई की प्रकृति	सीपीएसई की योग संख्या	प्रतिवेदन में सम्मिलित सीपीएसई की संख्या				प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किए गए सीपीएसई की संख्या
		तक के लेखे			योग	
		2023-24	2022-23	2021-22		
सरकारी कंपनियाँ	521	444	18	10	472*	49
सांविधिक निगम	7	7	0	0	7	0
योग कंपनियां/निगम (क)	528	451	18	10	479	49
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां (ख)	229	200	4	1	205	24
योग (क+ख)	757	651	22	11	684	73

*472 सरकारी कंपनियों में से 208 सीपीएसई में केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी है। शेष 264 सरकारी कंपनियाँ या तो सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियाँ/संयुक्त उद्यम (जेवी) हैं या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत निगमित ऐसी गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनियाँ हैं, जिनकी कोई अंश पूंजी नहीं है।

वर्ष 2023-24 के दौरान सीएजी के लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली/ उससे बाहर जाने वाली सरकारी कंपनियों/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

इस प्रतिवेदन में 73 सीपीएसई (जिनमें 24 सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियाँ सम्मिलित हैं) को सम्मिलित नहीं किया गया है, जिनके वित्तीय विवरण तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे, या जो परिसमापन की प्रक्रिया में थीं, या जिनके प्रथम लेखे बकाया नहीं थे/प्राप्त नहीं हुए थे। इन सीपीएसई को अनुलग्नक-III ए और अनुलग्नक-III बी में दो तारांकित चिह्नों (**) से दर्शाया गया है।

² 521 सरकारी कंपनियों में 226 स्टैंडअलोन/होल्टिंग सरकारी कंपनियाँ और 295 सरकारी कंपनियों की सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियाँ शामिल हैं।

³ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्रीय भंडारण निगम, दामोदर घाटी निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम।

⁴ क्रिएटिव म्यूजियम डिज़ाइनर्स, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

सीपीएसई की संख्या	528
सम्मिलित सीपीएसई	479
प्रदत्त पूंजी (479 सीपीएसई)	₹14,40,927 करोड़
निवल संपत्ति (479 सीपीएसई)	₹31,23,174 करोड़
दीर्घकालिक ऋण (196 सीपीएसई)	₹28,85,802 करोड़
31 मार्च, 2024 तक का बाजार पूंजीकरण (69 कारोबार वाली सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां)	₹38,32,107 करोड़
निवल लाभ (282 सीपीएसई)	₹3,58,385 करोड़
निवल घाटा (182 सीपीएसई) ⁵	₹34,908 करोड़
शून्य लाभ/हानि 13 सीपीएसई	
घोषित लाभांश (134 सीपीएसई)	₹1,38,138 करोड़

1.2 सरकारी कंपनियों एवं निगमों में निवेश

31 मार्च, 2024 की समाप्ति पर 479 सरकारी कंपनियों और निगमों⁶ में प्रदत्त पूंजी और दीर्घकालिक ऋणों की राशि को तालिका 1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.2: सरकारी कंपनियों और निगमों में प्रदत्त पूंजी और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31.03.2024 तक			31.03.2023 तक		
	प्रदत्त ⁷ पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	योग	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	योग
केंद्र सरकार	11,93,439	2,87,678	14,81,117	9,24,672	2,70,335	11,95,007

⁵ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के घाटे को उसकी अचल संपत्तियों में शुद्ध स्थापना व्यय के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के घाटे को उसके आईडब्ल्यूएआई फंड में समायोजित कर दिया गया।

⁶ 528 सीपीएसई - 49 सीपीएसई जिनके खाते तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या परिसमापन के अधीन थे या जिनके पहले खाते देय नहीं थे/प्राप्त नहीं हुए थे।

⁷ प्रदत्त पूंजी में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में ₹2,12,856 करोड़ का किया गया निवेश शामिल है। इसके अलावा, रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई 49 सरकारी कंपनियों में से 18 सीपीएसई की सूचना उपलब्ध थी, जिनकी प्रदत्त पूंजी ₹1,939 करोड़ थी।

निवेश के स्रोत	31.03.2024 तक			31.03.2023 तक		
	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	योग	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	योग
केंद्र सरकार की कंपनियां/ निगम	1,33,611	66,889	2,00,500	1,18,377	51,519	1,69,896
राज्य सरकारें/ राज्य सरकारी कंपनियां/ निगम	50,996	25,904	76,900	46,719	35,198	81,917
वित्तीय संस्थान और अन्य	62,881	25,05,331	25,68,212	51,636	23,65,418	24,17,054
योग	14,40,927	28,85,802	43,26,729	11,41,404	27,22,470	38,63,874
योग निवेश में केंद्र सरकार के निवेश का प्रतिशत	82.82	9.97	34.23	81.01	9.93	30.93

स्रोत: वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए सीपीएसई के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण।

यह देखा गया कि सरकारी कंपनियों और निगमों में निवेश की गई योग धनराशि 2023-24 के दौरान 2022-23 की तुलना में ₹4,62,855 करोड़ (11.98 प्रतिशत) बढ़ गई, जिसमें प्रदत्त पूंजी में ₹2,99,523 करोड़ की वृद्धि और दीर्घकालिक ऋणों में ₹1,63,332 करोड़ की वृद्धि सम्मिलित है।

1.2.1 अंशधारिता

2023-24 के दौरान, इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 479 सीपीएसई की प्रदत्त पूंजी में ₹2,99,523 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई। 2023-24 के दौरान सीपीएसई में केंद्र सरकार की अंशधारिता में ₹2,68,767 करोड़⁸ की वृद्धि हुई है। 31 सीपीएसई में ₹2,70,406 करोड़ के शेयरों के निर्गमन और 11 सीपीएसई में ₹1,639 करोड़ के शेयरों के विनिवेश/ पुनर्खरीद आदि के परिणामस्वरूप ₹2,68,767 करोड़ की अंतिम वृद्धि हुई।

वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा ₹2,70,406 करोड़ की नई अंशधारिता में से, ₹2,68,354 करोड़ की अंशधारिता 25 सीपीएसई में नई इक्विटी के रूप में थी, जिससे संबंधित सीपीएसई में नकदी प्रवाह हुआ, और ₹2,052 करोड़ छः सीपीएसई⁹ में बोनस शेयर जारी करने के रूप में थी।

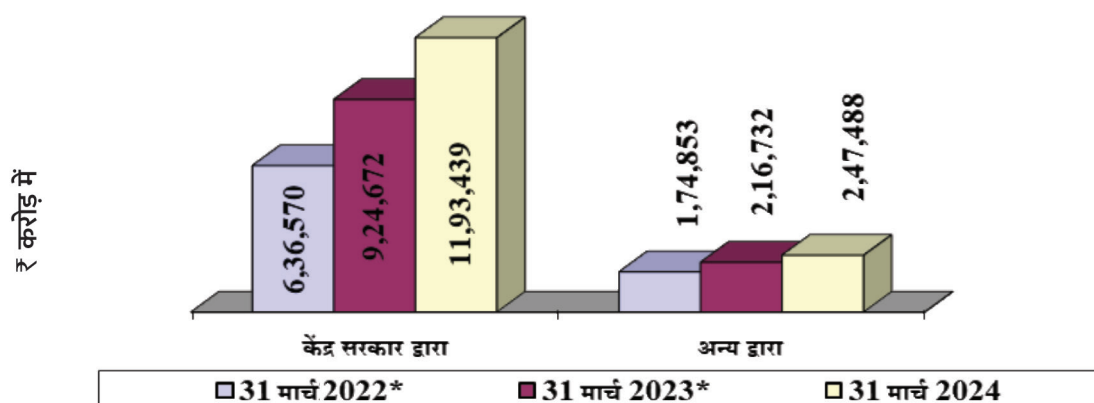
पिछले तीन वर्षों 2021-22 से 2023-24 तक के दौरान सरकारी कंपनियों और निगमों में केंद्र सरकार और अन्य¹⁰ की अंशधारिता की स्थिति को चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

⁸ इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 28 सरकारी कंपनियों के अनंतिम आंकड़े उनके अंतिम लेखापरीक्षित खातों के आंकड़ों के आधार पर शामिल किए गए हैं, क्योंकि वर्ष 2023-24 के खाते रिपोर्ट तैयार करने की अंतिम तिथि (31.12.2024) से पहले प्राप्त नहीं हुए थे।

⁹ आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड, आईटीआई लिमिटेड, एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड

¹⁰ अन्य में केंद्र सरकार की कंपनियां/निगम, राज्य सरकारें, राज्य सरकार की कंपनियां/निगम और वित्तीय संस्थान आदि शामिल हैं।

चार्ट 1.1: सरकारी कंपनियों और निगमों में अंशधारिता



* वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त लेखाओं के अनुसार अद्यतन किए गए पूर्व वर्षों के अंतिम आँकड़े।

वर्ष 2023-24 के दौरान सीपीएसई की प्रदत्त पूंजी में केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए ₹1,000 करोड़ से अधिक के निवेश का विवरण नीचे तालिका 1.3 में दिया गया है:

तालिका 1.3: वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा ₹1,000 करोड़ से अधिक का निवेश
(₹ करोड़ में)

सीपीएसई का नाम	मंत्रालय का नाम	राशि
सांविधिक निगम		
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	सड़क परिवहन और राजमार्ग	2,12,856
सरकारी कंपनियाँ		
भारत संचार निगम लिमिटेड	संचार	46,380
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परमाणु ऊर्जा विभाग	3,942
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	विद्युत	1,194

1.2.2 सरकारी कंपनियों एवं निगमों को दिए गए ऋण

1.2.2.1 31 मार्च 2024 तक बकाया दीर्घकालिक ऋणों की गणना

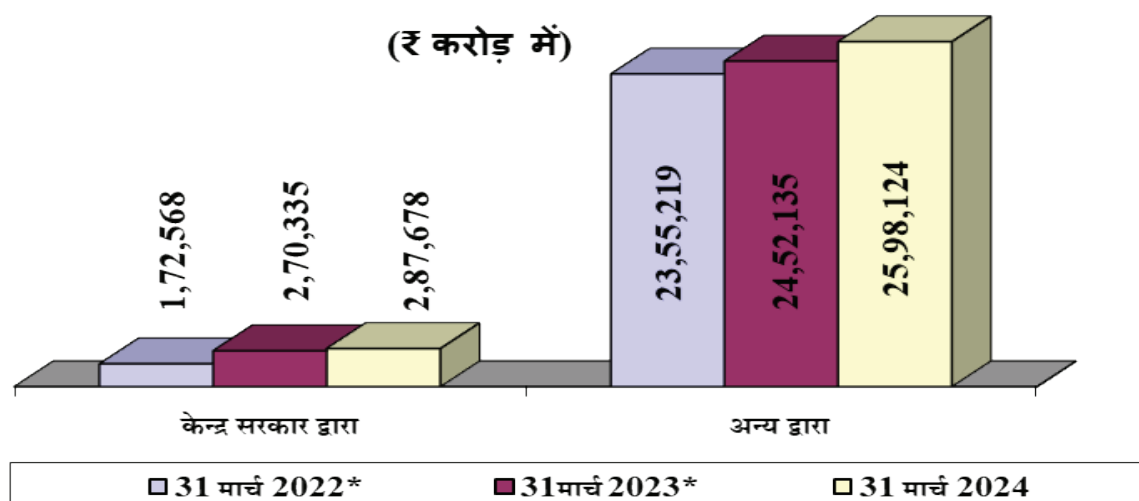
31 मार्च, 2024 तक सभी स्रोतों से प्राप्त 479 सरकारी कंपनियों और निगमों में से 196 सीपीएसई के योग दीर्घकालिक ऋण ₹28,85,802 करोड़ थे। 2023-24 के दौरान, सरकारी कंपनियों और निगमों के दीर्घकालिक ऋणों में ₹1,63,332 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। 31 मार्च, 2024 तक 196 सीपीएसई के योग दीर्घकालिक ऋणों में से केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण ₹2,87,678 करोड़ था।¹¹ पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान 52 सीपीएसई में से, 20 सीपीएसई में, केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए ऋण में ₹23,358 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि 19 सीपीएसई में केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए ऋण में ₹6,015 करोड़ की कमी आई।

¹¹ इसमें विश्व बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) आदि जैसी बाहरी एजेंसियों से लिए गए ऋण भी शामिल हैं।

20 सीपीएसई में से 14 सीपीएसई¹² में चल रही परियोजनाओं/संचालनों के कार्यान्वयन के वित्तपोषण के लिए ऋण दिया गया था और शेष छः सीपीएसई के मामले में, ऋण में वृद्धि पहले के ऋणों पर बकाया ब्याज के कारण हुई थी।

2021-22 से 2023-24 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी कंपनियों और निगमों (केंद्र सरकार और अन्य¹³ द्वारा) के बकाया दीर्घकालिक ऋणों का वर्षवार विवरण को चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: सरकारी कंपनियों और निगमों में बकाया दीर्घकालिक ऋण



*पिछले वर्षों के अंतिम आंकड़ों को 2023-24 के दौरान उस वर्ष के लेखाओं की प्राप्ति के साथ अद्यतन किया गया।

अन्य संस्थाओं द्वारा सरकारी कंपनियों और निगमों को दिए गए दीर्घकालिक ऋणों में 2023-24 के दौरान अंतिम ₹1,45,989 करोड़ की वृद्धि हुई है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों में अंतिम ₹17,343 करोड़ की वृद्धि हुई।

479 सरकारी कंपनियों और निगमों में से 283 सीपीएसई (जिसमें एक सांविधिक निगम यानी केंद्रीय भंडारण निगम भी सम्मिलित है) के पास 31 मार्च 2024 तक कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं था।

1.2.2.2 ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

योग ऋण और योग परिसंपत्तियों का अनुपात किसी कंपनी की वित्तीय स्थिरता निर्धारित करने के तरीकों में से एक है। वित्तीय रूप से सक्षम माने जाने के लिए, किसी संस्था की परिसंपत्तियों का मूल्य उसके ऋणों/कर्जों के योग से अधिक होना चाहिए। 31 मार्च 2024 तक बकाया ऋणों वाली 196 सीपीएसई

¹² कोलकाता मेट्रो रेल निगम लिमिटेड चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न हंडीक्राफ्ट्स एंड हंडलम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

¹³ अन्य में केंद्र सरकार की कंपनियां/निगम, राज्य सरकारें, राज्य सरकार की कंपनियां/निगम और वित्तीय संस्थान आदि शामिल हैं।

में योग परिसंपत्तियों के मूल्य के आधार पर दीर्घकालिक ऋणों का आच्छादन नीचे तालिका 1.4 में दिया गया है:

तालिका 1.4: योग परिसंपत्तियों के साथ दीर्घकालिक ऋणों का आच्छादन

	सकारात्मक आच्छादन				नकारात्मक आच्छादन			
	सीपीएसई की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	परिसंपत्तियाँ	ऋणों के सापेक्ष परिसंपत्तियों का प्रतिशत	सीपीएसई की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	परिसंपत्तियाँ	ऋणों के सापेक्ष परिसंपत्तियों का प्रतिशत
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम	6	3,93,812	13,39,802	340.21				
सूचीबद्ध कंपनियाँ	39	18,69,357	41,89,733	224.13	1	25,795	9,248	35.85
असूचीबद्ध कंपनियाँ	132	5,70,039	13,50,883	236.98	18	26,799	12,635	47.15
योग	177	28,33,208	68,80,418		19	52,594	21,883	

196 सीपीएसई में से 19 सीपीएसई के संबंध में, योग परिसंपत्तियों का मूल्य बकाया दीर्घकालिक ऋणों से कम था (अनुलग्नक-IV)।

1.2.2.3 ब्याज आच्छादन अनुपात

ब्याज आच्छादन अनुपात (आईसीआर) का उपयोग किसी कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज चुकाने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना कंपनी के ब्याज और कर से पूर्व आय (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। उच्च आईसीआर यह दर्शाता है कि कंपनी अपने ब्याज दायित्वों को आसानी से पूरा कर सकती है, जो वित्तीय स्थिरता का संकेत है, जबकि कम अनुपात वित्तीय संकट के उच्च जोखिम और ऋण चुकाने में संभावित कठिनाई को दर्शाता है। 2021-22 से 2023-24 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान बकाया ऋण वाली सीपीएसई के सकारात्मक और नकारात्मक ब्याज आच्छादन अनुपात का विवरण नीचे तालिका 1.5 में दिया गया है:

तालिका 1.5: ब्याज आच्छादन अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	कर से पूर्व आय एवं ब्याज (₹ करोड़ में)	सीपीएसई की संख्या	शून्य ब्याज दर वाले सीपीएसई की संख्या	आईसीआर ≥ 1 वाले सीपीएसई की संख्या	आईसीआर < 1 वाले सीपीएसई की संख्या
सांविधिक निगम						
2021-22	5,773	5,698	5	1	3	1
2022-23	5,776	10,209	6	2	3	1
2023-24	5,697	12,423	6	2	3	1

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	कर से पूर्व आय एवं ब्याज (₹ करोड़ में)	सीपीएसई की संख्या	शून्य ब्याज दर वाले सीपीएसई की संख्या	आईसीआर >= 1 वाले सीपीएसई की संख्या	आईसीआर < 1 वाले सीपीएसई की संख्या
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां						
2021-22	90,756	3,18,056	40	1	33	6
2022-23	1,00,483	2,67,385	41	1	32	8
2023-24	1,28,030	4,15,637	40	1	30	9
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां						
2021-22	22,053	33,653	132	41	41	50
2022-23	24,608	35,505	131	25	54	52
2023-24	34,071	54,292	150	23	63	64

आईसीआर स्थिति वाली सीपीएसई की कुल संख्या

वर्ष	एक या एक से अधिक आईसीआर वाले सीपीएसई	एक से कम आईसीआर वाले सीपीएसई
2022-23	89	61
2023-24	96	74

1.2.2.4 केंद्र सरकार के ऋणों पर अवधिवार ब्याज बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2024 तक, केंद्र सरकार द्वारा 24 सीपीएसई को दिए गए दीर्घकालिक ऋणों पर ₹13,240.27 करोड़ का ब्याज बकाया था। केंद्रीय सरकार द्वारा सीपीएसई को दिए गए ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधिवार विश्लेषण तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर बकाया ब्याज	केंद्र सरकार द्वारा दिए गए उन ऋणों पर ब्याज जो 1 वर्ष से कम समय से बकाया हैं	केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर 1-3 वर्षों से बकाया ब्याज	केंद्र सरकार द्वारा दिए गए उन ऋणों पर ब्याज जो 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं
1	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	1,142.07	38.87	38.87	1,064.33
2	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड	52.70	0.00	0.00	52.70

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर बकाया ब्याज	केंद्र सरकार द्वारा दिए गए उन ऋणों पर ब्याज जो 1 वर्ष से कम समय से बकाया हैं	केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर 1-3 वर्षों से बकाया ब्याज	केंद्र सरकार द्वारा दिए गए उन ऋणों पर ब्याज जो 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं
3	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	78.56	3.89	11.62	63.05
4	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	123.85	0.00	0.00	123.85
5	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.39	0.41	0.98	0.00
6	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	15.50	0.00	0.00	15.50
7	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6,328.78	1,666.98	2,218.58	2,443.22
8	दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	427.91	12.68	415.23	0.00
9	भारतीय खाद्य निगम	230.55	230.55	0.00	0.00
10	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	91.19	10.77	21.53	58.89
11	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	119.85	26.16	58.19	35.50
12	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	448.61	50.00	100.98	297.63
13	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	26.55	18.72	7.83	0.00
14	आईटीआई लिमिटेड	28.56	3.00	6.00	19.56
15	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	875.56	54.58	93.61	727.37
16	नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	646.21	0.00	62.83	583.38
17	एनईपीए लिमिटेड	314.86	52.01	126.53	136.32
18	एनएचपीसी लिमिटेड	69.58	69.58	0.00	0.00
19	एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड	8.95	0.00	8.95	0.00

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर बकाया ब्याज	केंद्र सरकार द्वारा दिए गए उन ऋणों पर ब्याज जो 1 वर्ष से कम समय से बकाया हैं	केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर 1-3 वर्षों से बकाया ब्याज	केंद्र सरकार द्वारा दिए गए उन ऋणों पर ब्याज जो 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं
20.	पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	24.47	0.00	0.00	24.47
21.	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	169.68	169.68	0.00	0.00
22.	आरईसी लिमिटेड	325.12	325.12	0.00	0.00
23.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	16.66	5.54	5.54	5.58
24.	द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	1,673.11	239.02	478.03	956.06
	योग	13,240.27	2,977.56	3,655.30	6,607.41

यह देखा गया कि केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज 2022-23 में ₹11,608.52 करोड़ (19 सीपीएसई) से बढ़कर 2023-24 में ₹13,240.27 करोड़ (24 सीपीएसई) हो गया। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि 49.90 प्रतिशत ब्याज तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया था।

1.2.3 सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियों में निवेश एवं ऋण

वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र/राज्य सरकार की कंपनियों/निगमों द्वारा 205 सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियों¹⁴ में निवेश की गई पूंजी की स्थिति को तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियों में शेयर पूंजी और ऋणों की संरचना

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31.03.2024 तक			31.03.2023 तक		
	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	योग	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	योग
केंद्र सरकार	321	5,502	5,823	321	5,080	5,401
केंद्र सरकार की कंपनियां/निगम	41,836	1,591	43,427	37,789	6,784	44,573
राज्य सरकारें/ राज्य सरकारी कंपनियां/ निगम	6,758	0	6,758	6,472	0	6,472

¹⁴ 205 = 229- 24 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या परिसमापन या पहले खाते देय नहीं थे/प्राप्त नहीं हुए थे।

निवेश के स्रोत	31.03.2024 तक			31.03.2023 तक		
	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	योग	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	योग
वित्तीय संस्थान और अन्य	25,475	1,34,956	1,60,431	22,020	1,16,911	1,38,931
योग	74,390	1,42,049	2,16,439	66,602	1,28,775	1,95,377
योग निवेश में केंद्र सरकार के निवेश का प्रतिशत	0.43	3.87	2.69	0.48	3.94	2.76

31 मार्च 2024 तक, सरकार के नियंत्रण वाली 205 अन्य कंपनियों की प्रदत्त पूंजी ₹74,390 करोड़ थी। पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कंपनियों की प्रदत्त पूंजी में ₹7,788 करोड़ (11.69 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

1.2.4 सरकारी कंपनियों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

बाजार पूंजीकरण उन कंपनियों के शेयरों के बाजार मूल्य को दर्शाता है जिनके शेयर सूचीबद्ध होते हैं। 31 मार्च 2024 को 79 सीपीएसई के शेयर विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे, जिनमें 60 सरकारी कंपनियाँ, सरकारी कंपनियों की 11 सहायक¹⁵ कंपनियाँ तथा आठ सरकार-नियंत्रित अन्य कंपनियाँ¹⁶ सम्मिलित थीं। इनमें से तीन सीपीएसई (बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड तथा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड) वर्ष 2023-24 के दौरान सूचीबद्ध हुईं। इसके अतिरिक्त, सरकारी कंपनियों की 11 सहायक कंपनियों में से दो सहायक कंपनियों के शेयर कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज¹⁷ में सूचीबद्ध थे।

2023-24 के दौरान 60 सरकारी कंपनियों और सरकारी कंपनियों की नौ सहायक कंपनियों के (कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध दो कंपनियों को छोड़कर) शेयरों का बीएसई पर कारोबार हुआ।

31 मार्च 2024 को सूचीबद्ध 66 सरकारी कंपनियों (**अनुलग्नक V**) (नौ सहायक कंपनियों सहित और वर्ष के दौरान सूचीबद्ध तीन नई सरकारी कंपनियों को छोड़कर) के शेयरों का योग बाजार मूल्य ₹37,92,736 करोड़ (इक्विटी निवेश ₹1,23,962 करोड़) था, जबकि 31 मार्च 2023 को 66 सरकारी कंपनियों का बाजार मूल्य ₹17,28,066 करोड़ (इक्विटी निवेश ₹1,17,689 करोड़) था। इस प्रकार, सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों के शेयरों के योग बाजार मूल्य में 31 मार्च 2024 को ₹20,64,670 करोड़ (119.48 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

¹⁵ बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, द ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, द बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड।

¹⁶ ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड, तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड तथा द ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड।

¹⁷ ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड तथा द बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड।

इन 66 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (नौ सहायक कंपनियों सहित) में भारत सरकार के शेयरों का बाजार मूल्य 31 मार्च 2024 को ₹23,51,459 करोड़ था, जबकि 31 मार्च 2023 को 66 सीपीएसई में यह ₹10,50,225 करोड़ था। इस प्रकार, सीपीएसई में भारत सरकार के शेयरों के बाजार मूल्य में 31 मार्च 2024 को ₹13,01,234 करोड़ (123.90 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

सेबी द्वारा निर्धारित लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की परिभाषा¹⁸ को ध्यान में रखते हुए और बीएसई के अनुसार शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण मूल्य के आधार पर, कारोबार करने वाली 69 सूचीबद्ध सीपीएसई को तालिका 1.8 में दिए गए अनुसार लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में वर्गीकृत किया गया है।

तालिका 1.8: 69 सूचीबद्ध सीपीएसई का वर्गीकरण

विवरण	2023-24	2022-23	सामान्य सीपीएसई
लार्ज कैप सीपीएसई	14	9	9
मिड कैप सीपीएसई	20	14	9
स्मॉल कैप सीपीएसई	35	43	33
योग	69	66	

यह देखा गया कि 2022-23 में 43 स्मॉल कैप सीपीएसई में से दस कंपनियां¹⁹ 2023-24 में मिड कैप कंपनी बन गईं। 2022-23 में 14 मिड कैप सीपीएसई में से पांच कंपनियां 2023-24 में लार्ज कैप कंपनी²⁰ बन गईं।

बाजार पूंजीकरण के मामले में शीर्ष तीन क्षेत्र पेट्रोलियम (₹10,08,009 करोड़ - 26.56 प्रतिशत), विद्युत (₹7,21,174 करोड़ - 19.01 प्रतिशत) और वित्तीय सेवाएं (₹5,19,820 करोड़ - 12.71 प्रतिशत) थे। शेयरों के बाजार मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि पेट्रोलियम क्षेत्र (₹4,90,511 करोड़ - 94.79 प्रतिशत) में देखी गई, इसके बाद वित्तीय सेवाएं क्षेत्र (₹3,65,460 करोड़ - 312.76 प्रतिशत) और विद्युत क्षेत्र (₹3,40,356 करोड़ - 89.38 प्रतिशत) का स्थान रहा।

इस अवधि के दौरान, एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स²¹ एसएंडपी बीएसई-सीपीएसई सूचकांक²² 31 मार्च 2023 को 58,991.52 से बढ़कर 31 मार्च 2024 को 73,651.35 हो गया, जिसमें 24.85 प्रतिशत की वृद्धि

¹⁸ एसईबीआई के दिनांक 6 अक्टूबर, 2017 के परिपत्र के अनुसार, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

लार्ज कैप: कुल बाजार पूंजीकरण के आधार पर पहली से सौवीं कंपनी

मिड कैप: कुल बाजार पूंजीकरण के आधार पर 101वीं से 250वीं कंपनी

स्मॉल कैप: कुल बाजार पूंजीकरण के आधार पर 251वीं कंपनी से आगे।

¹⁹ रेल विकास निगम लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और आईटीआई लिमिटेड।

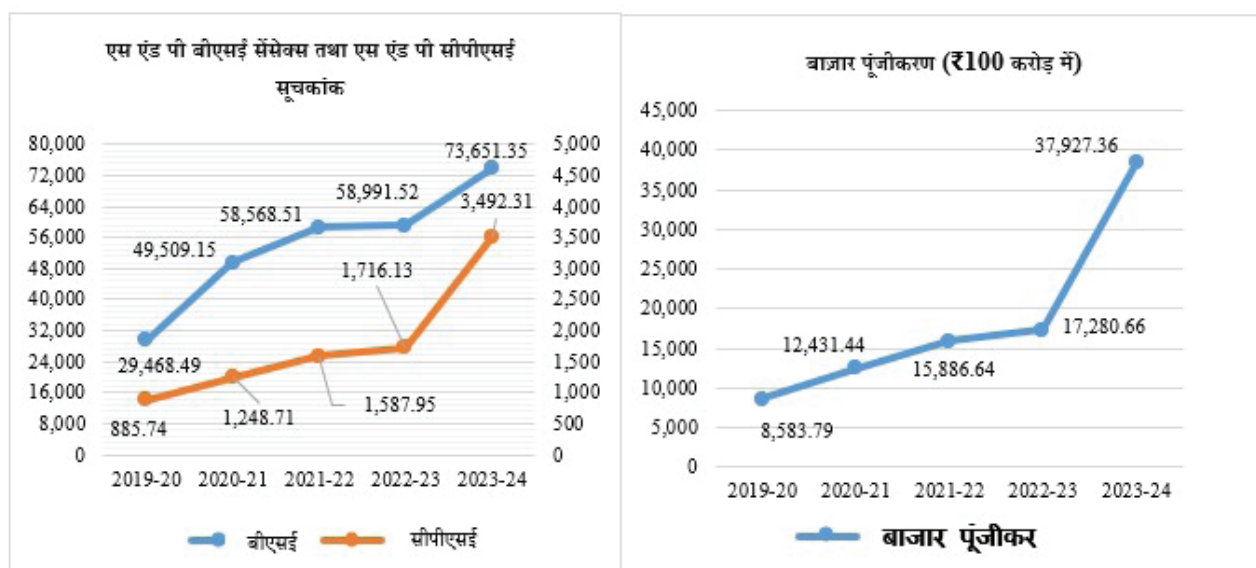
²⁰ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड।

²¹ एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स एक बेंचमार्क इंडेक्स है जो 30 घटक शेयरों का एक समूह है, जो बड़ी, तरल और प्रतिनिधि कंपनियों का एक नमूना प्रस्तुत करता है।

²² एस एंड पी बीएसई सीपीएसई सूचकांक, बीएसई में सूचीबद्ध सीपीएसई के निष्पादन को मापता है।

हुई। इसकी तुलना में, एस एंड पी बीएसई-सीपीएसई सूचकांक में 103.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 31 मार्च 2023 को 1,716.13 से बढ़कर 31 मार्च 2024 को 3,492.31 पर पहुंच गया। पिछले पांच वर्षों में सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों के बाजार पूंजीकरण का एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और एसएंडपी बीएसई-सीपीएसई सूचकांक के सापेक्ष रुझान चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।:

चार्ट 1.3: एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और सीपीएसई सूचकांक के सापेक्ष कारोबार करने वाली सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों के बाजार पूंजीकरण का रुझान



यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान जहाँ एसएंडपी बीएसई सूचकांक के बाजार पूंजीकरण में 24.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर एसएंडपी सीपीएसई सूचकांक में 103.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान बाजार पूंजीकरण में 119.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

यह देखा गया कि 2019-20 से 2023-24 के दौरान कारोबार करने वाली सूचीबद्ध सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण का रुझान एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और एसएंडपी बीएसई सीपीएसई सूचकांक के रुझान के अनुरूप था।

सरकारी कंपनियों की सात सहायक कंपनियों (दो नई सूचीबद्ध सहायक कंपनियों को छोड़कर) के शेयरों का बाजार मूल्य, जिनका कारोबार 2023-24 के दौरान हुआ, 31 मार्च, 2024 को ₹2,45,693 करोड़ था। इन सात सहायक सरकारी कंपनियों के शेयरों का योग बाजार मूल्य 31 मार्च, 2023 की तुलना में 31 मार्च, 2024 को ₹1,65,606 करोड़ बढ़ गया।

31 मार्च 2024 को सर्वाधिक बाजार पूंजीकरण वाली शीर्ष 10 व्यापारित सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ तालिका 1.9 में दी गई हैं।

तालिका 1.9: उच्चतम बाजार पूंजीकरण वाली सरकारी कंपनियां

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	बाजार पूंजीकरण		
		31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	वृद्धि (प्रतिशत में)
1	ऑयल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	3,36,963	1,89,962	77.38
2	एनटीपीसी लिमिटेड	3,25,760	1,69,934	91.70
3	कोल इंडिया लिमिटेड	2,67,308	1,31,667	103.02
4	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2,57,673	1,57,436	63.67
5	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,36,884	1,10,061	115.23
6	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	2,22,518	91,296	143.73
7	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	1,86,096	34,762	435.34
8	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1,47,255	71,307	106.51
9	भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	1,30,654	74,633	75.06
10	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,28,770	40,063	221.42

1.3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त प्रतिफल

1.3.1 सीपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

लाभ अर्जित करने वाली सरकारी कंपनियों और निगमों की संख्या 2023-24 में 282 थी, जबकि 2022-23 में यह संख्या 259 थी {38 सीपीएसई (अनुलग्नक-VI) जुड़े और 15 सीपीएसई (अनुलग्नक-VII) हटे}।

इन 38 सीपीएसई में से, दो सीपीएसई नए थे और उन्होंने अपने परिचालन के पहले वर्ष में लाभ दर्ज किया, जबकि 36 सीपीएसई ने पिछले वर्ष घाटा उठाने के बाद लाभ दर्ज किया। 36 सीपीएसई में से 20 ने परिचालन लाभ के कारण लाभ दर्ज किया।²³ पिछले वर्ष लाभ अर्जित करने के बाद घाटे में चल रही 15 सीपीएसई में से आठ सीपीएसई को मुख्य रूप से परिचालन घाटे के कारण नुकसान हुआ।

पिछले दो वर्षों यानी 2022-23 और 2023-24 के लिए लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई का वर्गीकरण निम्नलिखित मानदंडों को अपनाते हुए तालिका 1.10 में दिया गया है:

- ₹10,000 करोड़ से अधिक का लाभ कमाने वाली सीपीएसई को उच्च लाभ अर्जित करने वाली सीपीएसई माना गया है।
- ₹1,000 करोड़ से ₹10,000 करोड़ के बीच लाभ कमाने वाली सीपीएसई को मध्यम लाभ अर्जित करने वाली सीपीएसई माना गया है।

²³ व्यय घटाने के बाद कुल परिचालन आय।

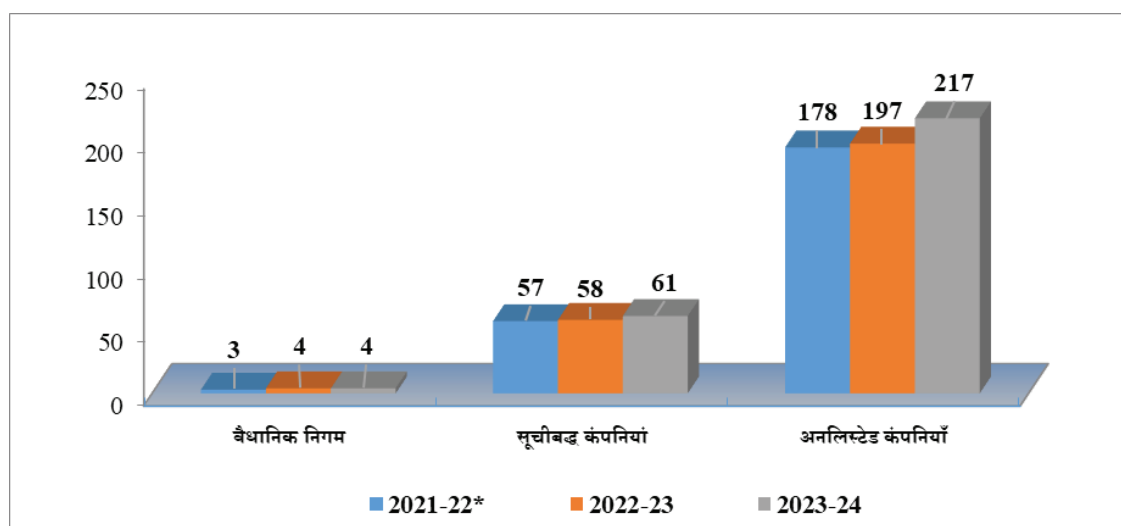
- ₹1,000 करोड़ से कम लाभ कमाने वाले सीपीएसई को कम लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई माना गया है।

तालिका 1.10: लाभ कमाने वाले सीपीएसई का वर्गीकरण

सीपीएसई की श्रेणी	2023-24	2022-23	सामान्य सीपीएसई
₹10,000 करोड़ से अधिक का लाभ	10	7	7
₹1,000 करोड़ से ₹10,000 करोड़ के बीच लाभ	34	34	28
₹1,000 करोड़ से कम लाभ	238	218	199
योग	282	259	234

सरकारी कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ 2023-24 के दौरान ₹1,03,732 करोड़ (40.73 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ 2022-23 के ₹2,54,653 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹3,58,385 करोड़ हो गया। तदनुसार, 282 सीपीएसई का इक्विटी²⁴ पर प्रतिफल (आरओई) वर्ष 2023-24 में 16.28 प्रतिशत रहा, जबकि 2022-23 में 259 सीपीएसई का आरओई 13.75 प्रतिशत था। 477 सरकारी कंपनियों एवं निगमों²⁵ (जिसमें 182 हानि में चल रही और 13 शून्य लाभ/हानि वाली कंपनियाँ सम्मिलित हैं) का आरओई वर्ष 2023-24 में 13.50 प्रतिशत रहा। 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की संख्या चार्ट 1.4 में दर्शाई गई है। इससे पता चलता है कि इस अवधि के दौरान योग मिलाकर लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या में वृद्धि हुई है।

चार्ट 1.4: लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की संख्या



*पिछले वर्षों के आंकड़े 2023-24 के दौरान उस वर्ष के लेखाओं प्राप्त होने पर अद्यतन किए गए थे।

²⁴ इक्विटी पर प्रतिफल = (कर और अधिमान्य लाभांश के बाद शुद्ध लाभ / इक्विटी) * 100 जहाँ इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त भंडार - संचित हानि - स्थगित राजस्व व्यय।

²⁵ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, क्योंकि उनके नुकसान को फुटनोट 5 में दिए गए अनुसार समायोजित किया गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान अधिकतम लाभ में योगदान देने वाले शीर्ष तीन क्षेत्रों का विवरण नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1.11: वर्ष 2023-24 के दौरान अधिकतम लाभ में योगदान देने वाले शीर्ष तीन क्षेत्र

क्षेत्र	लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	योग लाभ के अनुपात में लाभ का प्रतिशत
पेट्रोलियम			
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां	8	1,42,208	39.68
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां	6	4,604	1.28
उप-योग (क)	14	1,46,812	40.96
कोयला और लिग्नाइट			
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां	2	17,613	4.91
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां	9	35,984	10.04
उप-योग (ख)	11	53,597	14.96
विद्युत			
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां	4	38,206	10.66
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां	49	13,109	3.66
सांविधिक निगम	1	811	0.23
उप-योग (ग)	54	52,126	14.54
योग (क+ख+ग)	79	2,52,535	70.46

2023-24 में सरकारी कंपनियों और निगमों के योग लाभ का 70.46 प्रतिशत यानी ₹2,52,535 करोड़ का निवल लाभ 79 सीपीएसई द्वारा अर्जित किया गया, जबकि 2022-23 में इन्हीं क्षेत्रों में 69 सीपीएसई द्वारा अर्जित निवल लाभ 65.97 प्रतिशत था।

वर्ष 2023-24 के दौरान ₹10,000 करोड़ से अधिक का अर्जित निवल लाभ करने वाली सरकारी कंपनियों की सूची नीचे दी गई है:

तालिका 1.12: सीपीएसई जिनका निवल लाभ ₹10,000 करोड़ से अधिक रहा

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
1.	ऑयल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	40,526	13.25
2.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	39,619	22.44
3.	भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	26,674	35.71
4.	एनटीपीसी लिमिटेड	18,079	12.33

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
5.	कोल इंडिया लिमिटेड	15,767	91.00
6.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	15,475	18.43
7.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	14,694	36.37
8.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	14,367	18.14
9.	आरईसी लिमिटेड	14,019	20.55
10.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	11,845	73.55
	योग	2,11,065	20.92

यह देखा जा सकता है कि इन 10 सरकारी कंपनियों ने 2023-24 के दौरान 282 सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा अर्जित योग ₹3,58,385 करोड़ के लाभ में 58.89 प्रतिशत का योगदान दिया। इन 10 सरकारी कंपनियों का आरओई 20.92 प्रतिशत था और शेष 272 सरकारी कंपनियों का आरओई 12.36 प्रतिशत रहा।

205 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में से 163 सीपीएसई ने वर्ष 2023-24 के दौरान ₹23,475 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जो वर्ष 2022-23 में 148 सीपीएसई द्वारा अर्जित ₹19,965 करोड़ के लाभ की तुलना में ₹3,510 करोड़ (17.58 प्रतिशत) अधिक था। इसके अलावा, 163 सीपीएसई का आरओई वर्ष 2023-24 में 4.33 प्रतिशत रहा, जबकि वर्ष 2022-23 में 148 सीपीएसई का आरओई 4.66 प्रतिशत था। 205 सरकारी नियंत्रित अन्य सभी कंपनियों का आरओई वर्ष 2023-24 में 4.01 प्रतिशत रहा, जबकि वर्ष 2022-23 में 197 ऐसी कंपनियों का आरओई 4.19 प्रतिशत था।

1.3.2 सीपीएसई द्वारा वहन की गई हानि

वर्ष 2023-24 के दौरान 182 सीपीएसई²⁶ ने हानि वहन की। इन 182 हानि में चल रही सीपीएसई में से 65 ने पिछले पाँच वर्षों में दो से चार वर्षों तक हानि वहन की, जबकि 75 सीपीएसई ने पिछले पाँच वर्षों से लगातार हानि वहन की है। सीपीएसई द्वारा वहन की गई हानि वर्ष 2023-24 में घटकर ₹34,908 करोड़ रह गई, जो वर्ष 2022-23 में ₹49,552 करोड़ थी, जैसा कि तालिका 1.13 में दिया गया है।

²⁶ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, क्योंकि उनके नुकसान को फुटनोट 5 में दिए गए अनुसार समायोजित किया गया है।

तालिका 1.13: वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान हानि वहन करने वाली सीपीएसई की संख्या
(₹ करोड़ में)

वर्ष	हानि वहन करने वाली सीपीएसई की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध घाटा	संचित हानि	निवल मूल्य ²⁷
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां				
2021-22	141	27,056	1,18,876	1,13,002
2022-23	159	36,823	1,32,274	1,18,544
2023-24	172	29,212	93,412	1,90,147
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां				
2021-22	14	4,999	21,314	-17,369
2022-23	12	12,729	23,252	10,525
2023-24	10	5,696	24,495	-4,778
योग				
2021-22	155	32,055	1,40,190	95,633
2022-23	171	49,552	1,55,526	1,29,069
2023-24	182	34,908	1,17,907	1,85,369

तालिका 1.14 में सूचीबद्ध सीपीएसई को वर्ष 2023-24 के दौरान ₹1,000 करोड़ से अधिक का घाटा हुआ।

तालिका 1.14: सीपीएसई जिन्होंने वर्ष 2023-24 के दौरान ₹1,000 करोड़ से अधिक का घाटा उठाया

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	शुद्ध घाटा
1.	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड	2,065
2.	भारत संचार निगम लिमिटेड	5,371
3.	दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	4,913
4.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	3,302
5.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	1,560
6.	ओएनजीसी पेट्रो एडिशनल्स लिमिटेड	3,456

²⁷ निवल मूल्य का अर्थ प्रदत्त अंश पूंजी तथा मुक्त आरक्षित निधि एवं अधिशेष का कुल योग, जिसमें से संचित हानि तथा स्थगित राजस्व व्यय घटा दिया जाता है। मुक्त आरक्षित निधि का अर्थ उन सभी आरक्षित निधियों से है जो लाभ तथा अंश प्रीमियम खाते से बनाई गई हों, परंतु इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से बनाई गई आरक्षित निधियाँ तथा मूल्यहास प्रावधान की वापसी से बनाई गई आरक्षित निधियाँ शामिल नहीं होती।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	शुद्ध घाटा
7.	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड	2,581
8.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	4,849
	योग	28,097

यह देखा जा सकता है कि इन आठ सीपीएसई ने 2023-24 के दौरान 182 सीपीएसई द्वारा हुए योग नुकसान में 80.49 प्रतिशत का योगदान दिया।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा नियंत्रित 205 अन्य कंपनियों में से 41 कंपनियों को वर्ष 2023-24 के दौरान ₹858 करोड़ का घाटा हुआ, जबकि 2022-23 में ऐसी 197 कंपनियों में से 48 सीपीएसई को ₹929 करोड़ का घाटा हुआ था, जो ₹71 करोड़ (7.64 प्रतिशत) की कमी दर्शाता है।

1.3.3 सीपीएसई में पूंजी का क्षरण

1.3.3.1 सरकारी कंपनियों में पूंजी का क्षरण

31 मार्च 2024 तक 214 सरकारी कंपनियों²⁸ में ₹2,47,181 करोड़ की संचित हानि थी। इन 214 सीपीएसई में से 152 सीपीएसई ने वर्ष 2023-24 में ₹25,972 करोड़ की हानि वहन की तथा 62 सीपीएसई (जिसमें शून्य लाभ/हानि वाली कंपनियाँ भी सम्मिलित हैं) ने वर्ष 2023-24 में कोई हानि नहीं वहन की, जबकि इन पर ₹1,29,274 करोड़ की संचित हानि पहले से थी। 214 सीपीएसई में से 19 सीपीएसई 31 मार्च 2024 तक बंदी की प्रक्रिया में थे, जिन पर ₹5,690 करोड़ की संचित हानि थी।

कुल मिलाकर, सभी 479 सरकारी कंपनियों और निगमों की निवल मूल्य ₹31,23,174 करोड़ थी, जबकि उनकी प्रदत्त पूंजी ₹14,40,927 करोड़ थी। 214 सीपीएसई में से 91 कंपनियों की निवल मूल्य संचित घाटे के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और उनकी निवल मूल्य शून्य या ऋणात्मक थी। 31 मार्च 2024 को इन 91 सीपीएसई की निवल संपत्ति (-) ₹58,175 करोड़ थी, जबकि इक्विटी निवेश ₹25,103 करोड़ था (अनुलग्नक-VIII)। इसमें सात सूचीबद्ध कंपनियाँ सम्मिलित थीं जिनकी निवल मूल्य (-) ₹24,172 करोड़ थी, जबकि इक्विटी निवेश ₹1,047 करोड़ था। जिन 91 सीपीएसई की पूंजी समाप्त हो गई थी (यानी जिनकी निवल मूल्य शून्य या ऋणात्मक थी), उनमें से 21 सीपीएसई ने 2023-24 के दौरान ₹961 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। इसके अतिरिक्त, 91 सीपीएसई में से 37 को पिछले पांच वर्षों के दौरान लगातार घाटा हुआ था और 31 मार्च 2024 तक संचित घाटा और नकारात्मक निवल मूल्य क्रमशः ₹62,801 करोड़ और ₹44,330 करोड़ था।

जिन 91 सीपीएसई की पूंजी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, उनमें से 16 में 31 मार्च 2024 तक सरकार द्वारा बकाया ऋण की राशि ₹7,336 करोड़ थी। इनमें दो सूचीबद्ध कंपनियाँ (मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड) भी सम्मिलित थीं, जिन पर सरकार द्वारा बकाया ऋण ₹1,487 करोड़ था।

²⁸ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, क्योंकि उनके नुकसान को फुटनोट 5 में दिए गए अनुसार समायोजित किया गया है।

31 मार्च, 2024 के अंत में 386 सीपीएसई में से 36 सीपीएसई की निवल मूल्य उनकी प्रदत्त पूंजी के आधे से भी कम थी। इन 36 सीपीएसई में से आठ सीपीएसई जिनकी निवल मूल्य ₹13,914 करोड़ थी, पिछले पांच वर्षों से लगातार घाटे में चल रही थीं और 19 सीपीएसई जिनकी निवल संपत्ति ₹4,799 करोड़ थी, पिछले पांच वर्षों में दो से चार वर्षों तक घाटे में चल रही थीं, जो उनके संभावित वित्तीय संकट का संकेत है।

1.3.3.2 सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों में पूंजी का क्षरण

31 मार्च, 2024 तक, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की संख्या 49 थी, जिन पर योग ₹5,250 करोड़ का संचित घाटा था। 49 सीपीएसई में से 29 सीपीएसई को वर्ष 2023-24 में ₹635 करोड़ का घाटा हुआ, जबकि 20 सीपीएसई ने ₹2,326 करोड़ के संचित घाटे के बावजूद लाभ अर्जित किया।

कुल मिलाकर, सरकार द्वारा नियंत्रित सभी 205 अन्य कंपनियों की योग संपत्ति ₹5,63,610 करोड़ थी, जबकि उनकी प्रदत्त पूंजी ₹74,390 करोड़ थी। 205 सीपीएसई में से 13 सीपीएसई की निवल मूल्य संचित घाटे के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और उनका निवल मूल्य शून्य या ऋणात्मक था। 31 मार्च, 2024 को इन 13 सीपीएसई की योग संपत्ति (-) ₹940 करोड़ थी, जबकि इनमें इक्विटी निवेश ₹417 करोड़ था (*अनुलग्नक IX*)। इसमें दो सूचीबद्ध कंपनियां भी सम्मिलित थीं जिनका निवल मूल्य (-) ₹284 करोड़ था, जबकि इनमें इक्विटी निवेश ₹56 करोड़ था। जिन 13 सीपीएसई की पूंजी समाप्त हो गई थी (यानी जिनकी योग संपत्ति शून्य या ऋणात्मक थी), उनमें से दो सीपीएसई ने 2023-24 के दौरान ₹0.88 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। इसके अतिरिक्त, 13 सीपीएसई में से पांच को पिछले पांच वर्षों के दौरान लगातार घाटा हुआ था और 31 मार्च, 2024 तक संचित घाटा और नकारात्मक निवल मूल्य क्रमशः ₹785 करोड़ और ₹531 करोड़ था।

जिन 13 सीपीएसई की पूंजी में गिरावट आई है, उनमें से केवल एक कंपनी (बिएको लॉरी लिमिटेड) ही ऐसी है जो सूचीबद्ध नहीं है और जिसमें 31 मार्च, 2024 तक सरकार द्वारा बकाया ऋण की राशि ₹126 करोड़ थी।

205 सीपीएसई में से जिनका निवल मूल्य 31 मार्च 2024 को धनात्मक था, उनमें से छः सीपीएसई का निवल मूल्य उनकी प्रदत्त पूंजी के आधे से कम था। इन छः सीपीएसई में से एक सीपीएसई, जिसकी निवल मूल्य ₹71 करोड़ था, पिछले पाँच वर्षों से लगातार हानि वहन कर रही थी तथा तीन सीपीएसई, जिनका निवल मूल्य ₹57 करोड़ था, पिछले पाँच वर्षों में दो से चार वर्षों तक हानि वहन कर रही थीं, जो उनके संभावित वित्तीय संकट का संकेत है।

1.3.4 सीपीएसई द्वारा लाभांश भुगतान

सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा अर्जित लाभ और घोषित लाभांश का विवरण तालिका 1.15 में दिया गया है।

तालिका 1.15: अर्जित लाभ और घोषित लाभांश

(₹ करोड़ में)

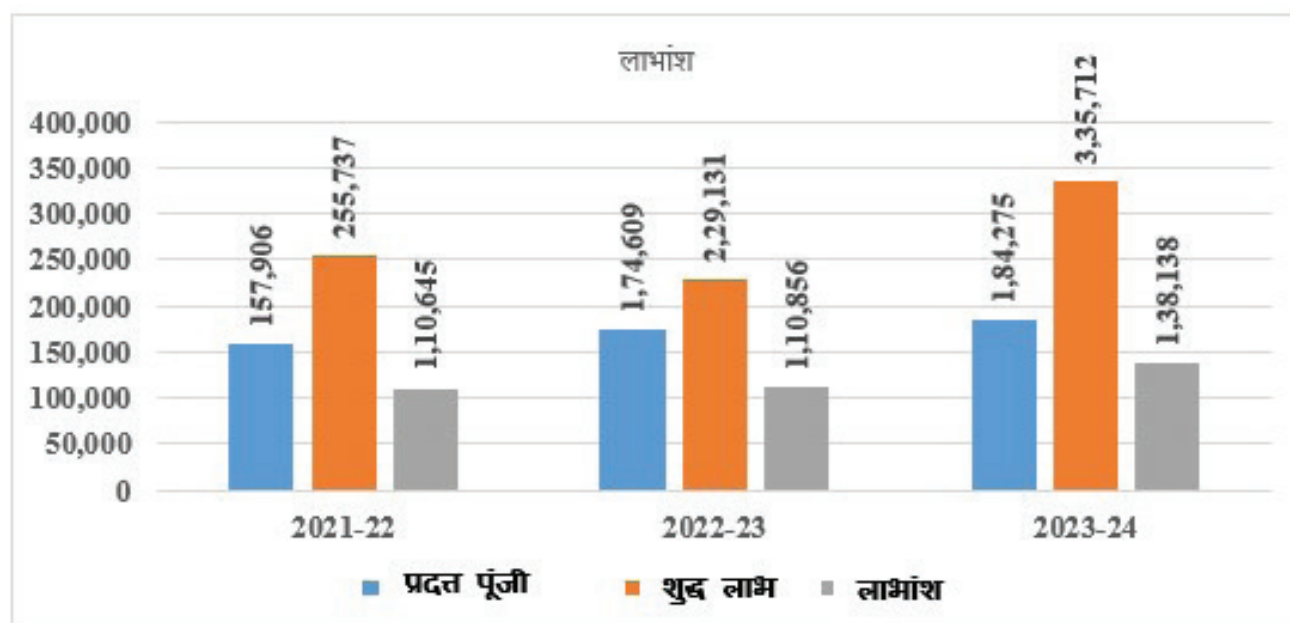
वर्ग	सीपीएसई की संख्या	प्रदत्त पूंजी	निवल लाभ	घोषित किया गया लाभांश
सांविधिक निगम	2	725	5,111	1,563
सूचीबद्ध कंपनियां	51	1,11,785	2,77,161	1,12,302
असूचीबद्ध कंपनियाँ	81	71,765	53,440	24,273
योग	134	1,84,275	3,35,712	1,38,138

479 सरकारी कंपनियों और निगमों में से 134 सीपीएसई ने वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश घोषित किया। इन 134 लाभ कमाने वाली सीपीएसई के शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में घोषित लाभांश 2022-23 में 48.38 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 41.15 प्रतिशत हो गया।

सीपीएसई द्वारा 2023-24 में घोषित लाभांश पिछले वर्ष की तुलना में ₹27,282 करोड़ अधिक रहा। चार्ट 1.5 में 2021-22 से 2023-24 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभांश घोषित करने वाली सीपीएसई के अर्जित निवल लाभ और प्रदत्त पूंजी के मुकाबले घोषित लाभांश को दर्शाया गया है।

चार्ट 1.5: घोषित लाभांश बनाम प्रदत्त पूंजी और अर्जित निवल लाभ

(₹ करोड़ में)



वर्ष 2023-24 के लिए 134 सीपीएसई द्वारा घोषित ₹1,38,138 करोड़ के कुल लाभांश (उनके निवल मूल्य का 6.90 प्रतिशत) में से, केंद्र सरकार को 85 सीपीएसई में ₹65,071 करोड़ (उनके ₹1,08,354 करोड़ के कुल लाभांश का 60.05 प्रतिशत) का लाभांश प्राप्त हुआ/प्राप्त होना बाकी था। उन²⁹ द्वारा

²⁹ 85 सीपीएसई वो सरकारी कंपनियां और सांविधिक निगम हैं, जिनमें केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी है।

घोषित, जिनमें केंद्र सरकार का ₹94,138 करोड़ का इक्विटी निवेश है। केंद्र सरकार द्वारा 479 सीपीएसई की इक्विटी पूंजी में किए गए ₹11,93,439 करोड़ के योग निवेश पर प्राप्त/प्राप्त होने योग्य लाभांश के रूप में प्रतिफल 5.45 प्रतिशत रहा, जबकि वर्ष 2022-23 में यह 3.21 प्रतिशत था। 64 सीपीएसई के मामले में, अन्य सीपीएसई में उनके ₹50,672 करोड़ के इक्विटी निवेश पर इन सीपीएसई को प्राप्त/प्राप्त होने योग्य लाभांश वर्ष 2023-24 में ₹32,996 करोड़ था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र के अंतर्गत 11 सीपीएसई ने ₹50,469 करोड़ का लाभांश घोषित किया, जो वर्ष 2023-24 में 134 सीपीएसई द्वारा घोषित ₹1,38,138 करोड़ के योग लाभांश का 36.54 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 में 51 सूचीबद्ध सीपीएसई द्वारा घोषित ₹1,12,302 करोड़ का योग लाभांश इन सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण (₹36,89,639 करोड़) का 3.04 प्रतिशत था।

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान ₹23,475 करोड़ का लाभ अर्जित करने वाली 163 सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियों में से 60 कंपनियों ने ₹5,441 करोड़ का लाभांश घोषित किया, जो उनकी ₹22,203 करोड़ की प्रदत्त पूंजी का 24.51 प्रतिशत था। वर्ष 2023-24 के दौरान लाभांश घोषित करने वाली इन 60 सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियों का क्षेत्रवार वर्गीकरण तालिका 1.16 में दिया गया है।

तालिका 1.16: सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश

(₹ करोड़ में)

सेक्टर	कंपनियों की संख्या	प्रदत्त पूंजी	निवल लाभ	घोषित लाभांश
कृषि आधारित उद्योग	1	20	3	2
वित्तीय सेवाएं	30	5,465	9,110	2,198
औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्श	3	1	6	1
बीमा	4	2,491	3,057	347
पेट्रोलियम	7	1,170	2,709	685
विद्युत	9	11,141	2,428	1,782
दूरसंचार सेवाएं	1	58	132	3
परिवहन सेवाएं	5	1,857	737	423
योग	60	22,203	18,182	5,441

1.4 सरकारी कंपनियों और निगमों की परिचालन क्षमता

1.4.1 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई)

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उसकी पूंजी के कुशल उपयोग को मापता है। आरओसीई की गणना कंपनी की ब्याज और कर से पूर्व आय (ईबीआईटी) को नियोजित³⁰ पूंजी से विभाजित करके की जाती है। सीपीएसई के अनुसार आरओसीई का

³⁰ नियोजित पूंजी = चुकता शेयर पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानि - स्थगित राजस्व व्यय।

विवरण **अनुलग्नक X** में दिया गया है। सभी सीपीएसई³¹ का पिछले तीन वर्षों के दौरान का समेकित आरओसीई 2021-22 से 2023-24 तक तालिका 1.17 में दिया गया है।

तालिका 1.17: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सीपीएसई की संख्या	ईबीआईटी	प्रयुक्त पूंजी	आरओसीई (प्रतिशत में)
2022	410	4,15,289	39,98,160	10.39
2023	441	3,98,115	43,72,330	9.11
2024	477	5,98,037	49,45,868	12.09

यह देखा गया कि 2022-23 में सीपीएसई का आरओसीई 9.11 प्रतिशत से बढ़कर 12.09 प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण ईबीआईटी में वृद्धि था।

1.4.2 इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)

इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)³² कंपनियों के वित्तीय निष्पादन की एक माप है, जिसकी गणना निवल आय को शेयरधारकों की इक्विटी से विभाजित करके की जाती है। सीपीएसई-वार आरओई का विवरण **अनुलग्नक XI** में दिया गया है। 2021-22 से 2023-24 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान का सभी सीपीएसई³³ का समेकित आरओई तालिका 1.18 में दिया गया है।

तालिका 1.18: इक्विटी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सीपीएसई की संख्या	कर एवं अधिमान्य लाभांश के बाद निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (प्रतिशत में)
2021-22	410	2,35,905	18,20,280	12.96
2022-23	441	2,05,100	19,93,974	10.29
2023-24	477	3,23,477	23,96,439	13.50

यह देखा गया कि मुख्य रूप से निवल लाभ में वृद्धि के कारण सीपीएसई का आरओई 2023-24 में 10.29 प्रतिशत से बढ़कर 13.50 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान जिन सरकारी कंपनियों एवं निगमों का क्षेत्रवार आरओई योग इक्विटी ₹10,000 करोड़ से अधिक थी उन्हें तालिका 1.19 में दर्शाया गया है।

³¹ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, क्योंकि उनके नुकसान को फुटनोट 5 में दिए गए अनुसार समायोजित किया गया है।

³² इक्विटी पर प्रतिफल = (कर और अधिमान्य लाभांश के बाद शुद्ध लाभ / इक्विटी) * 100, जहाँ इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष - संचित हानि - अप्राप्त राजस्व व्यय।

³³ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, क्योंकि उनके नुकसान को फुटनोट 5 में दिए गए अनुसार समायोजित किया गया है।

तालिका 1.19: ₹10,000 करोड़ एवं उससे अधिक योग इक्विटी वाले क्षेत्रों का आरओई

(प्रतिशत में)

क्रम संख्या	क्षेत्र	2023-24	2022-23	2021-22
1.	कोयला और लिग्नाइट	47.58	50.72	41.30
2.	अनुबंध एवं निर्माण सेवाएं	16.74	16.67	14.80
3.	वित्तीय सेवाएं	15.53	15.17	13.24
4.	भारी उद्योग	0.50	1.15	0.85
5.	औद्योगिक विकास	12.87	7.79	7.79
6.	बीमा	3.02	-2.27	-2.48
7.	खनिज और धातु	18.24	18.46	25.68
8.	पेट्रोलियम	17.05	9.31	16.91
9.	विद्युत	12.51	12.25	13.83
10.	इस्पात	-5.24	-1.34	23.13
11.	परिवहन उपकरण	26.03	20.41	24.07
12.	परिवहन सेवाएं	1.37	2.02	-2.67

1.4.3 सीपीएसई की बिक्री और विपणन

2022-23 के मुकाबले अनुबंध एवं निर्माण सेवाएँ, वित्तीय सेवाएँ, औद्योगिक विकास, बीमा, पेट्रोलियम, विद्युत तथा परिवहन उपकरण क्षेत्रों में आरओई में वृद्धि हुई, जबकि अन्य क्षेत्रों में 2023-24 में आरओई में कमी दर्ज की गई।

1.4.3.1 सरकारी कंपनियों और निगमों की बिक्री और विपणन

2023-24 के दौरान 479 सरकारी कंपनियों और निगमों की कुल बिक्री ₹36,44,513 करोड़ थी। 479 सीपीएसई में से 117 सरकारी कंपनियों ने ₹17,54,728 करोड़ की कुल बिक्री में से ₹3,94,081 करोड़ मूल्य की वस्तुएं/सेवाएं सरकारी क्षेत्र को बेचीं/प्रदान कीं। इन 117 सरकारी कंपनियों द्वारा सरकारी क्षेत्र को की गई कुल बिक्री का प्रतिशत 22.46 प्रतिशत रहा। 479 सीपीएसई में से 64 कंपनियों ने ₹1,20,904 करोड़ मूल्य की वस्तुएं/सेवाएं निर्यात कीं (जो उनकी कुल बिक्री ₹27,89,392 करोड़ का 4.33 प्रतिशत है), जबकि 43 कंपनियों ने ₹6,99,146 करोड़ मूल्य की वस्तुएं/सेवाएं आयात कीं, जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध आयात ₹5,78,242 करोड़ रहा।

तालिका 1.20 में सीपीएसई की कुल बिक्री, सरकारी क्षेत्र को बिक्री और निर्यात का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.20: सीपीएसई का बिक्री विवरण

(₹ करोड़ में)

प्रकार/वर्ष	सीपीएसई की संख्या	कुल बिक्री	सरकारी क्षेत्र को बिक्री	निर्यात बिक्री
2021-22	412	30,74,439	3,93,674	1,38,361
2022-23	443	37,24,158	4,24,037	1,41,051
2023-24	479	36,44,513	3,94,081	1,20,904

वर्ष 2023-24 में 479 सीपीएसई की योग ₹36,44,513 करोड़ बिक्री के मुकाबले, 64 सीपीएसई की निर्यात बिक्री 3.32 प्रतिशत (₹1,20,904 करोड़) रही। वर्ष 2023-24 के दौरान ₹5,000 करोड़ से अधिक निर्यात बिक्री करने वाले सीपीएसई का विवरण तालिका 1.21 में दिया गया है।

तालिका 1.21 : वर्ष 2023-24 के दौरान ₹5,000 करोड़ से अधिक निर्यात बिक्री वाले सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	निर्यात बिक्री
1.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	34,664
2.	मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	32,229
3.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8,926
4.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	7,343
5.	ऑयल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	5,965
6.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,934
7.	भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	5,595
	योग	1,00,656

इन सात सीपीएसई की निर्यात बिक्री सभी 64 सीपीएसई के योग निर्यात का 83.25 प्रतिशत थी।

1.4.3.2 सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियों की बिक्री और विपणन

वर्ष 2023-24 के दौरान 205 सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों की कुल बिक्री ₹2,24,225 करोड़ थी। इन 205 सीपीएसई में से 29 सीपीएसई ने अपनी कुल बिक्री ₹34,644 करोड़ में से ₹21,392 करोड़ मूल्य की वस्तुओं/सेवाओं सरकारी क्षेत्र को बेचीं/प्रदान कीं। इन 29 सीपीएसई की कुल बिक्री के संदर्भ में सरकारी क्षेत्र को की गई बिक्री का समग्र प्रतिशत 61.75 प्रतिशत रहा। 205 सीपीएसई की योग ₹2,24,225 करोड़ बिक्री के मुकाबले, सात सीपीएसई ने ₹803 करोड़ मूल्य की वस्तुओं/सेवाओं का निर्यात किया (₹20,438 करोड़ की उनकी कुल बिक्री का 3.93 प्रतिशत), जबकि पांच सीपीएसई ने ₹1,991 करोड़ मूल्य की वस्तुओं/सेवाओं का आयात किया, जिसके परिणामस्वरूप इन सीपीएसई द्वारा ₹1,188 करोड़ का शुद्ध आयात हुआ।

तालिका 1.22 में सीपीएसई की कुल बिक्री, सरकारी क्षेत्र को बिक्री और निर्यात का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.22: सीपीएसई का बिक्री विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सीपीएसई की संख्या	कुल बिक्री	सरकारी क्षेत्र को बिक्री	निर्यात बिक्री
2021-22	191	1,48,646	5,466	539
2022-23	197	1,89,519	10,186	65
2023-24	205	2,24,225	21,392	803

वर्ष 2023-24 में 205 सीपीएसई की योग ₹2,24,225 करोड़ बिक्री के मुकाबले, सात सीपीएसई की निर्यात बिक्री 0.36 प्रतिशत (₹803 करोड़) रही। वर्ष 2023-24 के दौरान निर्यात बिक्री करने वाली सात सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों का विवरण तालिका 1.23 में दिया गया है।

तालिका 1.23: वर्ष 2023-24 के दौरान निर्यात बिक्री वाली सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	निर्यात बिक्री
1.	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड	746.52
2.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	41.31
3.	कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	8.77
4.	यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	4.17
5.	बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड	1.53
6.	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड	0.75
7.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	0.17
	योग	803.22

अध्याय II

सीएजी की पर्यवेक्षण भूमिका

अध्याय II

सीएजी की पर्यवेक्षण भूमिका

2.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के अंतर्गत सरकारी कंपनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। सीएजी को पूरक लेखापरीक्षा करने और सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणी जारी करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार है। कुछ निगमों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार, उनके वित्तीय विवरणों का सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा करना और संसद को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2.2 सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसार, सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर की जानी है। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए वर्ष 2023-24 के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा सितंबर 2023 में की गई थी।

वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सितंबर 2023 में हुई थी।

2.3 सीपीएसई द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण

2.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और गतिविधियों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के तीन माह के भीतर तैयार की जानी चाहिए। प्रतिवेदन तैयार होने के बाद यथाशीघ्र, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सीएजी की टिप्पणियों या उसके पूरक के रूप में दी गई टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जानी चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में भी लगभग समान प्रावधान हैं। यह व्यवस्था संसद को उन सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक निगरानी प्रदान करती है, जो भारत की संचित निधि से इन कंपनियों/सांविधिक निगमों में निवेश किए जाते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करना अनिवार्य है। इसमें यह भी कहा गया है कि पहली एजीएम की तिथि और अगली एजीएम की तिथि के बीच 15 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। धारा में यह भी प्रावधान है कि पहली वार्षिक आम बैठक कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि से नौ माह की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी और अन्य मामलों में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि से छः माह की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी। धारा में यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्रार किसी विशेष कारण से, पहली वार्षिक आम बैठक के अतिरिक्त किसी भी वार्षिक आम बैठक के आयोजन की अवधि को अधिकतम तीन माह तक बढ़ा सकता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में यह प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। यह धारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में कंपनी के निदेशकों सहित उत्तरदायी व्यक्तियों पर जुर्माना तथा कारावास जैसी दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान करती है।

उपरोक्त सांविधिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय विवरणों की तैयारी में समयबद्धता से संबंधित विवरण निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए गए हैं:

2.3.2 सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों (सीपीएसई) द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2024 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा के दायरे में 521 सरकारी कंपनियां और 229 सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियां (सीपीएसई) थीं। इनमें से, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (40) और 2 (41) के अनुसार, पंद्रह सरकारी कंपनियों और तीन सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियों, जिनका हाल ही में निगमन हुआ था, के वित्तीय विवरण देय नहीं थे।

750 में से 88 सीपीएसई के वित्तीय विवरण 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बकाया थे।

सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में लंबित मामलों का विवरण नीचे तालिका 2.1 में दिया गया है:

तालिका 2.1: वित्तीय विवरणों के बकाया का विवरण

विवरण	सरकारी कंपनियां/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां					
	सरकारी कंपनियाँ		सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ		योग	
31 मार्च 2024 तक सीएजी के लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाले सीपीएसई की योग संख्या	521		229		750	
	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध
सूचीबद्ध/असूचीबद्ध	72	449	8	221	80	670

विवरण	सरकारी कंपनियाँ/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ					
	सरकारी कंपनियाँ	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ		योग		
घटाएँ:- वे सीपीएसई जिनके 2023-24 के वित्तीय विवरण जमा करने की समय सीमा नहीं थी	0	15	0	3	0	18
उन सीपीएसई की संख्या जिनके वित्तीय विवरण 2023-24 के लिए प्रस्तुत किए जाने थे	72	434	8	218	80	652
उन सीपीएसई की संख्या जिन्होंने 30 सितंबर 2024 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए।	67	351	8	174	75	525
उन सीपीएसई की संख्या जिन्होंने 31 दिसंबर 2024 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए।	70	374	8	192	78	566
उन सीपीएसई की संख्या जिनके वित्तीय विवरण 2023-24 के लिए बकाया थे	2	60	0	26	2	86
उन सीपीएसई के बकाया का विवरण जिनके वित्तीय विवरण 2023-24 के लिए बकाया थे	(i) परिसमापन के अधीन	1	22	0	16	38
	(ii) निष्क्रिय	0	0	0	0	0
	(iii) अन्य	1	38	0	10	48
अन्य श्रेणियों के बकाया का अवधिवार विश्लेषण	एक वर्ष (2023-24)	1	18	0	4	22
	दो वर्ष (2022-23 और 2023-2024)	0	10	0	2	12
	2023-24 सहित तीन वर्ष और उससे अधिक	0	10	0	4	14

उन सीपीएसई के नाम, जिनके वित्तीय विवरण देय नहीं थे या परिसमापन या अन्य किसी कारण से बकाया थे, अनुलग्नक III क³⁴ और अनुलग्नक III ख³⁵ में दर्शाए गए हैं।

2.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी में समयबद्धता

केंद्रीय अधिनियमों के अंतर्गत गठित सात सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा किया जाती है। छः सांविधिक निगमों में, जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक हैं, उन सभी निगमों के वित्तीय विवरण, अर्थात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम, भारतीय खाद्य निगम,

³⁴ इसमें वे सरकारी कंपनियाँ भी शामिल हैं जिनके वित्तीय विवरण केवल 2023-24 के लिए बकाया थे, जैसे कि लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत इन्फ्रान्फ्रास्ट्रक्चर्स एंड बायोलाजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड, रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जिबिशन सेंटर लिमिटेड, केरल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड, खवड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड, चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वाष्कोस लिमिटेड।

³⁵ इसमें सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियाँ भी शामिल हैं जिनके वित्तीय विवरण केवल 2023-24 के लिए बकाया थे, जैसे कि अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे कंपनी लिमिटेड, एआईसी-आरआरयू इनक्यूबेशन फाउंडेशन, एनआईसीडीसी पंजाब औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड और यूपी औद्योगिक और तकनीकी सलाहकार लिमिटेड।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वर्ष 2023-24 के लिए 30 सितंबर 2024 से पहले लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए थे। केंद्रीय भंडारण निगम के मामले में, सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा आयोजित की गई, केंद्रीय भंडारण निगम के 2023-24 के वित्तीय विवरण 30 सितंबर 2024 से पहले प्राप्त हुए थे।

2.4 सीएजी का पर्यवेक्षण- वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा

2.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में, और केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों का पालन करते हुए वित्तीय विवरण तैयार करने होते हैं। सांविधिक निगमों को सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों और/या ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में लेखा संबंधी किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में अपने वित्तीय विवरण तैयार करने होते हैं।

2.4.2 वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के प्रावधानों के अनुसार उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी करके एक पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है, जिसका समग्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सांविधिक लेखापरीक्षक अपने सौंपे गए कार्यों को उचित और प्रभावी ढंग से पूरा करें। यह कार्य निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करके पूरा किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर पूरक या टिप्पणी करना।

2.4.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य संबंधित अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी किसी संस्था के प्रबंधन की होती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय देने का दायित्व सौंपा गया है। यह राय भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (आईसीएआई) की मानक लेखापरीक्षा पद्धतियों और

सीएजी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित होती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रमाणित वित्तीय विवरणों और सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा करके की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर, यदि कोई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां हों, तो उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट किया जाता है।

2.4.4 सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा संबंधी प्रावधान

सांविधिक निगमों द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी और उनके लेखापरीक्षा से संबंधित प्रावधानों का विवरण नीचे तालिका 2.2 में दिया गया है:

तालिका 2.2: सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा संबंधी प्रावधान

क्रम संख्या	सांविधिक निगम का नाम	लागू संविधि	वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित प्रावधान	वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा संबंधी प्रावधान
1	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम	प्राधिकरण समुचित लेखाओं तथा अन्य संबंधित अभिलेखों का संधारण करेगा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श करके केंद्र सरकार द्वारा विहित प्रारूप में लाभ-हानि लेखा तथा तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखा-विवरण तैयार करेगा।	प्राधिकरण के लेखाओं की वार्षिक लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी।
2	केंद्रीय भंडारण निगम	भंडारण निगम अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम	प्रत्येक भंडारण निगम उचित लेखाओं और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रखरखाव करेगा तथा लाभ-हानि खातों और तुलन पत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा, जो निर्धारित प्रारूप में होगा: बशर्ते कि केंद्रीय भंडारण निगम के मामले में, भंडारण निधि और सामान्य निधि से संबंधित लेखाएं अलग-अलग रखी जाएंगी।	भंडारण निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे लेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम के अधीन लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत अर्हित हो। उक्त लेखापरीक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर उपयुक्त सरकार द्वारा की जाएगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक चाहे स्वयं निर्णय लेकर या संबंधित सरकार के अनुरोध पर, किसी वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का जब भी आवश्यक समझें, ऑडिट (लेखापरीक्षा) कर सकते हैं।

क्रम संख्या	सांविधिक निगम का नाम	लागू संविधि	वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित प्रावधान	वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा संबंधी प्रावधान
3	दामोदर घाटी निगम	दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम	निगम के लेखाओं का रखरखाव और लेखापरीक्षा उस तरीके से की जाएगी, जैसा कि भारत के महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित किया गया हो।	
4	भारतीय खाद्य निगम	खाद्य निगम अधिनियम, 1964 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम	खाद्य निगम उचित लेखाओं और अन्य प्रासंगिक अभिलेख रखेगा तथा लाभ-हानि खातों और तुलन पत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में होगा।	खाद्य निगम के लेखाओं का वार्षिक लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाएगा।
5	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम	प्राधिकरण के लेखाओं का रखरखाव और लेखापरीक्षा उस तरीके से की जाएगी, जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित किया गया हो	
6	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962	निगम उचित लेखा-जोखा और अन्य प्रासंगिक अभिलेख रखेगा तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित प्रारूप में वार्षिक लेखा-विवरण तैयार करेगा।	निगम के लेखाओं का वार्षिक लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाएगा।
7	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम	प्राधिकरण के लेखाओं का रखरखाव और लेखापरीक्षा उस तरीके से की जाएगी, जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित किया गया हो।	

2.5 सीएजी की पर्यवेक्षी भूमिका का परिणाम

2.5.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सीपीएसई के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा और संबंधित अधिनियमों के अनुसार सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा।

वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरण 30 सितंबर 2024 तक 418 सरकारी कंपनियों (जिनमें 67 सूचीबद्ध कंपनियां सम्मिलित हैं), 182 सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियों (जिनमें आठ सूचीबद्ध कंपनियां सम्मिलित हैं) और सात सांविधिक निगमों से प्राप्त हुए थे। इनमें से 235 सरकारी कंपनियों, 85 सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियों और सात सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में की गई थी।

30 सितंबर 2024 तक प्राप्त वित्तीय विवरणों में से सीएजी ने योग मिलाकर, सरकारी कंपनियों के 56.22 प्रतिशत और सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियों के 46.70 प्रतिशत वित्तीय विवरणों की समीक्षा की। समीक्षा के परिणाम नीचे विस्तार से दिए गए हैं:

सीएजी ने वर्ष 2023-24 के लिए 320 सीपीएसई और सात सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की।

सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के बाद, सीएजी ने चयनित सीपीएसई के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की। **अनुलग्नक XII** में उन 107 सीपीएसई की सूची दी गई है जिनके संबंध में टिप्पणियां जारी की गई थीं। सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों का सारांश, जिनका लाभप्रदता पर वित्तीय प्रभाव ₹3,563.37 करोड़ और परिसंपत्तियों/देनदारियों पर ₹61,949.59 करोड़ था, नीचे दिए गए हैं।

क. सूचीबद्ध सरकारी सीपीएसई

क. i. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1	कोल इंडिया लिमिटेड	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 2022-23 और 2023-24 के दौरान पूरी हुई 14 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए सीएमपीडीआईएल को अग्रिम के रूप में ₹57.42 करोड़ दिए थे। इंड एस 38 के पैराग्राफ 54 के अनुसार, अनुसंधान व्यय को खर्च होने पर ही व्यय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए; हालांकि, सीआईएल ने अग्रिम राशि को अनुसंधान एवं विकास व्यय के साथ समायोजित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप अन्य व्ययों में कमी और लाभ में ₹57.42 करोड़ की अधिकता हुई, साथ ही अन्य चालू परिसंपत्तियों में भी इसी अनुपात में अधिकता हुई।
2	आईएफसीआई लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मूल्यहास हानि भत्ता कम दर्शाया गया है और लाभ को योग ₹249.97 करोड़ अधिक दर्शाया गया है। आईएफसीआई के कई संपीड़ित ऋण लेखाओं में अपेक्षित प्रावधान से कम प्रावधान किया गया था।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		ग्रेन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, ₹135.81 करोड़ के बकाया मूलधन के मुकाबले केवल ₹97.24 करोड़ का प्रावधान बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹38.57 करोड़ की कमी आई। इसी तरह, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार वसूली योग्य बकाया ₹74.71 करोड़ तक सीमित था, जिसके लिए ₹307.02 करोड़ के प्रावधान की आवश्यकता थी, जिसके मुकाबले केवल ₹219.83 करोड़ का प्रावधान बनाया गया, जिससे ₹87.19 करोड़ की कमी आई। इसके अतिरिक्त, अन्य प्रमुख लेखाओं में भी अपेक्षित प्रावधान से कम प्रावधान किया जाना पाया गया जिनमें पायनियर गैस पावर लिमिटेड (₹56.12 करोड़ की कमी), लिज़ ट्रेडर्स एंड एजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (₹22 करोड़ की कमी), आर्कोटेक लिमिटेड (₹4.99 करोड़ की कमी), सी एंड सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (₹8.58 करोड़ की कमी), मधुकोन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (₹28.54 करोड़ की कमी) और एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड (₹3.98 करोड़ की कमी) सम्मिलित हैं। इन सभी लेखाओं में प्रावधान की उक्त कमियों के परिणामस्वरूप लाभ को समान राशि से अधिक दर्शाया गया तथा क्षीणन हानि हेतु प्रावधान को उतनी ही राशि से कम दर्शाया गया। यह उल्लेखनीय है कि इन मुद्दों की ओर वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 (जहाँ कहीं लागू हो) के दौरान बार-बार ध्यान आकृष्ट कराया गया था, तथापि कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। परिणामस्वरूप, वित्तीय परिणामों का त्रुटिपूर्ण उल्लेख जारी रहा।
3	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	एनएमडीसी लिमिटेड से 12 फरवरी 2024 को हुए 99 वर्षीय समझौता ज्ञापन के अंतर्गत परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए प्राप्त राशि को वर्ष 2023-24 के लिए आय के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, चूंकि यह व्यवस्था उपयोग के अधिकार प्रदान करने के स्वरूप की है और इसका लेखा-जोखा इंड एस अधिनियम 116 के अनुसार किया जाना चाहिए, इसलिए इस राशि को अप्राप्त राजस्व के रूप में माना जाना चाहिए था। पूरी राशि को आय के रूप में मानने से इंड एस अधिनियम 116 का अनुपालन नहीं हुआ है और तथा हानि को ₹74.68 करोड़ की राशि से कम दर्शाया गया है।
4	एनटीपीसी लिमिटेड	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5), कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 के नियम 7(3) और आईसीएआई के सीएसआर लेखांकन पर तकनीकी मार्गदर्शन के अनुसार, अतिरिक्त सीएसआर व्यय राशि को आगामी वर्षों में तभी समायोजित किया जा सकता है जब उसे परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी गई हो; अन्यथा, इसे व्यय के रूप में प्रभारित किया जाना चाहिए। वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹337.98 करोड़ के अपेक्षित सीएसआर व्यय के मुकाबले, कंपनी ने ₹200.57 करोड़ खर्च किए और पूर्व अतिरिक्त व्यय से ₹137.41 करोड़ समायोजित किए, जिससे अपेक्षित परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, नियमों का पालन नहीं हुआ और ₹137.41 करोड़ की कमी दर्ज की गई। फलस्वरूप, 'अन्य व्यय' और 'चालू देनदारियां - अन्य चालू देनदारियां' प्रत्येक में ₹137.41 करोड़ कम दर्शाई गई।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
5	एसजेवीएन लिमिटेड	एसजेवीएन लिमिटेड ने वर्ष 2014-15 में हिमाचल प्रदेश सरकार को रामपुर जलविद्युत स्टेशन की वन भूमि के पट्टे के किराए के रूप में ₹11.44 करोड़ का भुगतान किया था, जिसका विरोध किया गया और प्राधिकरण से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया गया। पिछले नौ वर्षों से लगातार संपर्क करने के बावजूद, हिमाचल प्रदेश सरकार से वापसी के समर्थन में कोई प्रतिक्रिया या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। वसूली की उचित निश्चितता के अभाव में, इस राशि को अन्य व्ययों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए था। प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अन्य व्ययों में कमी और अन्य चालू परिसंपत्तियों (सरकारी विभागों को दिए गए अग्रिम - असुरक्षित, जिन्हें अच्छा माना जाता है) तथा लाभ में ₹11.44 करोड़ की अधिकता हुई है।
6	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	- कर्मचारी लाभ व्यय (टिप्पण 39) में 26 नवंबर 2008 से 4 अक्टूबर 2009 तक अधिकारियों को देय भत्तों और सुविधाओं के लिए ₹309.34 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं है। कर्मचारियों के पक्ष में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के 2016 के आदेश और सेल की रिट याचिका को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2023 में खारिज किए जाने के बावजूद, कंपनी ने इस राशि को एक निश्चित देयता के रूप में मान्यता देने के बजाय, प्रशासनिक निर्णय लंबित होने तक एक आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया है। मान्यता न देने के कारण वर्तमान देयताओं और कर्मचारी व्ययों का कम आकलन और लाभ का ₹309.34 करोड़ का अधिक आकलन हुआ है। - अन्य व्यय (टिप्पण 41) में मेसर्स शापूरजी पल्लोनजी एंड कंपनी लिमिटेड (एसपीसीपीएल) और हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को राउरकेला स्टील प्लांट में अयस्क बिछाने और मिश्रण संयंत्र पर किए गए कार्य के लिए देय ₹28.18 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं, जो मार्च 2015 में पूरा हुआ था। यद्यपि विवाद के निपटारे के लिए गठित दो स्तरीय समापन समिति ने भुगतान की अनुशंसा की थी और सेल ने एसपीसीपीएल और एचईसी के साथ अनुलग्नक समाप्त करने के लिए मार्च 2024 में दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे। सेल ने इस बकाया राशि को प्रावधानित राशि के बजाय आकस्मिक देयता के रूप में गलत तरीके से दर्शाया है। परिणामस्वरूप, अन्य व्ययों का कम आकलन और लाभ तथा आकस्मिक देयताओं का ₹28.18 करोड़ का अधिक आकलन हुआ है। - अन्य व्यय (टिप्पण 41) में रौघाट खदानों में विश्वास निर्माण उपायों के अंतर्गत कल्याणकारी गतिविधियों पर खर्च किए गए ₹37.39 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं, जैसे कि स्कूल चलाना और कार्यक्रम आयोजित करना, जो कि इंड एस 16 के अंतर्गत परिसंपत्ति निर्माण से संबंधित नहीं हैं। इसलिए, इन्हें लाभ और हानि विवरण में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्ययों का कम आकलन और पूंजीगत कार्य प्रगति तथा लाभ का ₹37.39 करोड़ का अधिक आकलन हुआ है। - इंड एस 12 के अनुसार, “वर्तमान कर और अप्राप्तकर को लाभ या हानि से बाहर तब मान्यता दी जाएगी जब कर उन मदों से संबंधित हो जिन्हें उसी या किसी भिन्न अवधि में लाभ या हानि से बाहर मान्यता दी जाती है।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		इसलिए, वर्तमान कर और अप्राप्तकर जो उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें उसी या किसी भिन्न अवधि में अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है, उन्हें अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाएगी।” इसलिए, परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन पर कर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में 25.168 प्रतिशत (वर्तमान + अप्राप्तकर) की पूरी लागू दर पर दर्ज किया जाएगा। कंपनी ने ओसीआई के अंतर्गत मान्यता प्राप्त ₹196.621 करोड़ पर ₹49.48 करोड़ के कर का हिसाब देने के बजाय केवल ₹17.45 करोड़ का हिसाब दिया, जिससे ₹32.03 करोड़ का हिसाब नहीं हो पाया। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्यापक हानि और अन्य इक्विटी का कम आकलन हुआ है, जबकि अप्राप्तकर देनदारियों का ₹32.03 करोड़ अधिक आकलन हुआ है।
7	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	मौजूदा देनदारियों में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के खर्चों के लिए ₹17.90 करोड़ का एक तदर्थ प्रावधान सम्मिलित है। चूंकि यह प्रावधान किसी खास देनदारी की पहचान किए बिना बनाया गया था, इसलिए यह कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कमियों को दिखाता है। इसके परिणामस्वरूप, देनदारियां (खर्चों के लिए प्रविजन) ज्यादा दिखाई गईं और वर्ष का मुनाफ़ा ₹17.90 करोड़ कम दिखाया गया।

क. ii. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	वायरलेस सेवा देनदारों के 180 दिनों से अधिक समय से बकाया होने के कारण व्यापार प्राप्य राशि को ₹15.27 करोड़ से अधिक दर्शाया गया, जो कंपनी की नीति का उल्लंघन था और परिणामस्वरूप नुकसान को कम करके दर्शाया गया
2	एनएमडीसी लिमिटेड	प्रावधानों (टिप्पण 2.17.1) में चिगारगुंटा-बिसनाथम स्वर्ण ब्लॉक को सरेंडर करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को देय ₹12.39 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं है। हालांकि एनएमडीसी ने ₹12.39 करोड़ की परफॉर्मेंस गारंटी प्रस्तुत की थी और ₹2.48 करोड़ का अग्रिम शुल्क (जिसे बाद में विविध व्यय में स्थानांतरित कर दिया गया) का भुगतान किया था, फिर भी बोर्ड ने सितंबर 2023 में खदान को सरेंडर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी, जिसके परिणामस्वरूप योग ₹14.87 करोड़ का नुकसान हुआ। हालांकि, परफॉर्मेंस गारंटी के विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं बनाया गया, जिससे प्रावधानों और अन्य व्ययों में ₹12.39 करोड़ की कमी और लाभ में इतनी ही राशि की अधिकता दर्ज हुई।
3	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (बीईसी) से कोक ओवन पैकेज को एलपीजी की आपूर्ति को कम करने के लिए वसूली योग्य दिखाए गए ₹35.14 करोड़ सम्मिलित हैं। चूंकि यह राशि बीईसी की सहमति के बिना दर्ज की गई थी और चालू बिलों से वसूली की गई थी, इसलिए चालू परिसंपत्तियों को ₹35.14 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है।

क. iii. नकदी प्रवाह विवरण/नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	- कंपनी ने ₹5,442.81 करोड़ के ब्याज और ₹1,083.96 करोड़ के लाभांश (योग ₹6,526.77 करोड़) को परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह के अंतर्गत सम्मिलित किया है, जबकि एएस-3 और आईआरडीएआई मुख्य परिपत्र के अनुसार इन्हें निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, इन नकदी प्रवाहों का अलग से प्रकटीकरण नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन नकदी प्रवाह में ₹6,526.77 करोड़ की अधिकता और निवेश नकदी प्रवाह में ₹6,526.77 करोड़ की कमी दर्ज की गई। - कंपनी ने ₹5,791.96 करोड़ की बैंकों में रखी गई सावधि जमाओं को, जिनकी परिपक्वता अवधि तीन माह से अधिक है, नकद और नकद समतुल्य के अंतर्गत सम्मिलित किया है, जबकि एएस-3 में नकद समतुल्य की परिभाषा तीन माह या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाले निवेशों तक सीमित है। इसके परिणामस्वरूप नकद और नकद समतुल्य का अधिक आकलन हुआ है और निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकद प्रवाह का ₹5,791.96 करोड़ का कम आकलन हुआ है।
2	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्वचलित प्राप्तियों और भुगतानों खातों में, कंपनी ने ₹7,722.60 करोड़ की योग सावधि जमा (₹671 करोड़ 12 माह के भीतर परिपक्व होने वाली और ₹7,051.60 करोड़ अन्य) को नकद और नकद समतुल्य के अंतर्गत सम्मिलित किया है, जबकि एएस-3 के अनुसार तीन माह से कम परिपक्वता वाली जमाओं को अलग नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, तीन माह से अधिक परिपक्वता वाली सावधि जमाओं को भी नकद समतुल्य माना गया है, जिससे एएस-3 का अनुपालन नहीं हुआ है; हालांकि, विवरणों के अभाव में, इस प्रकार के गलत वर्गीकरण की सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सका।

क. iv. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1	कोल इंडिया लिमिटेड	- ओएनजीसी के साथ एक गैर-निगमित संयुक्त उद्यम सीबीएम परियोजना में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 23/04/2013 से 28/05/2017 की अवधि के लिए ओएनजीसी के ₹17.18 करोड़ के दावे को मान्यता नहीं दी और ₹51.13 करोड़ (29/05/2021 से 31/03/2024) को पूंजीगत कार्य प्रगति के अंतर्गत गलत तरीके से दर्शाया, जबकि इसे व्यय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। यह सब तब हुआ जब बोर्ड ने विकास चरण की तिथियों पर डीजीएच के स्पष्टीकरण को अंतिम मान लिया था। वित्तीय विवरणों में इन मामलों का प्रकटीकरण न करना इंड एएस 1 के अनुरूप नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई। - कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने टिप्पण 3.4: अमूर्त परिसंपत्तियों के अंतर्गत ₹140.33 करोड़ (शुद्ध ₹93.90 करोड़) मूल्य के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रकटीकरण किया, लेकिन इंड एएस 38 के पैराग्राफ 118 के अनुसार, अनुसार यह नहीं बताया कि उनकी उपयोगी अवधि अनिश्चित थी या निश्चित, अमॉर्टाइज़ेशन की दरें क्या थीं,

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		या कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए थे। महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 2.11 और टिप्पण 3.4 में इस चूक के परिणामस्वरूप अमूर्त परिसंपत्तियों और परिशोधन के बारे में अधूरी जानकारी दी गई। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 01.04.2022 से प्रभावी स्ट्रिपिंग गतिविधि पर अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। इसके अंतर्गत, अतिरिक्त ओवरबर्डन हटाने को अनुपात भिन्नता आरक्षित निधि के माध्यम से समायोजित करने की पूर्व प्रथा को बदलकर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत मान्यता दी गई है, जिनका परिशोधन खदान के समयावधि में किया जाता है। यह परिवर्तन, जो पूर्वव्यापी रूप से लागू हुआ है, नीति में “स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति का परिशोधन खदान के समयावधि में किया जाता है” कथन को भी सम्मिलित करता है। हालांकि, पट्टे पर दी गई भूमि और अमूर्त परिसंपत्तियों के विपरीत, जहां परिशोधन उसी वर्ष में प्रभारित किया जाता है, सीआईएल ने स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों के परिशोधन को अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया, यह कहते हुए कि अग्रिम स्ट्रिपिंग से लाभ केवल अगले वर्ष में प्राप्त होते हैं। हालांकि, इस विचलन के साथ-साथ यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि परिशोधन खदान के ‘संपूर्ण’ समयावधि पर आधारित है या ‘शेष’ समयावधि पर। चूंकि खनन कार्यों में स्ट्रिपिंग गतिविधि अभिन्न अंग है, इसलिए इंड एस 8 और इंड एस 1 के अंतर्गत स्वैच्छिक नीति परिवर्तन की प्रकृति और कारणों के साथ-साथ परिशोधन के आधार और विधि का प्रकटीकरण करना आवश्यक है, ताकि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता सूचित निर्णय ले सकें। महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.19 में इन विवरणों के अभाव के कारण प्रकटीकरण में महत्वपूर्ण खामी आई है।
2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	- कंपनी ने लगभग ₹450 करोड़ के मध्यस्थता अधिनिर्णय के विरुद्ध ₹1,258.259 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों के स्वामित्व अभिलेख दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा करने हेतु किए गए आवेदन, जो कि तुलन-पत्र तिथि के पश्चात घटित एक महत्वपूर्ण घटना थी, का प्रकटीकरण नहीं किया। यह इंड एस 10 के प्रावधानों के अनुरूप भी नहीं है। - कंपनी के नाम पर दर्ज न की गई अचल संपत्ति के स्वामित्व दस्तावेजों के संबंध में भी जानकारी का प्रकटीकरण अपर्याप्त है।
3	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	कंपनी ने चालू वर्ष में प्रोजेक्ट XXX के उत्पादन मूल्य (वीओपी) को बिलिंग डेटा के अनुरूप करने के लिए ₹20.81 करोड़ घटा दिया, और इस समायोजन का कारण पिछले वर्षों में दर्ज किए गए अतिरिक्त वीओपी को बताया। हालांकि, यह उलटफेर, जो पिछली अवधियों से संबंधित सुधार है, 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों में इंड एस 8 के पैरा 49 के अंतर्गत अपेक्षित रूप से प्रकट नहीं किया गया, जिससे जानकारी अधूरी रह गई।
4	एनएमडीसी लिमिटेड	एनएमडीसी लिमिटेड, जिसकी 52 प्रतिशत हिस्सेदारी है, ने बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल) में ₹152.67 करोड़ का निवेश किया था। बीआरपीएल, सेल और आईआरसीओएन के साथ मिलकर मई 2015 में जगदलपुर से रौघाट तक 140 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन के निर्माण के लिए गठित एक संयुक्त उद्यम था।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		चूंकि संयुक्त उद्यम भागीदारों के पास विशेषज्ञता की कमी थी और वे आवश्यक इक्विटी निवेश नहीं कर सके, और आईआरसीओएन परियोजना को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए बीआरपीएल के बोर्ड ने सितंबर 2022 में परियोजना को रेल मंत्रालय को सौंपने की स्वीकृति दी, जिसे फरवरी 2023 में रेलवे बोर्ड से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई। बीआरपीएल ने बस्तर जिले में ₹188.82 करोड़ की लागत से 140.233 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण भी किया था; हालांकि, पल्ली गांव में मुआवजे में अनियमितताओं के संबंध में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें कथित तौर पर ₹85.87 करोड़ के अधिक भुगतान का आरोप है, जो सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ये तथ्य एनएमडीसी के वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किए गए।
5	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	31 मार्च 2024 तक, सेल ने (टिप्पण संख्या 49.10) झारखंड (32.92 मिलियन टन, मूल्य ₹3,189.02 करोड़), उड़ीसा (6.34 मिलियन टन, मूल्य ₹554.02 करोड़) और छत्तीसगढ़ (1.62 मिलियन टन, मूल्य ₹189.31 करोड़) में स्थित सेल की कैप्टिव खदानों में मौजूद ₹3,932.35 करोड़ (40.88 मिलियन टन) के निम्न श्रेणी के लौह अयस्क का प्रकटीकरण किया, जिसका शुद्ध वसूली योग्य मूल्य 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष से वित्तीय विवरणों में एक अलग मद के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि, भारत सरकार ने (सितंबर 2019 में) निम्न श्रेणी के अयस्क की बिक्री की अनुमति दे दी थी, लेकिन झारखंड सरकार की स्वीकृति अभी लंबित थी, जिसके परिणामस्वरूप 2023-24 के दौरान इसकी खदानों से कोई बिक्री नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा से बिक्री सीमित थी (0.50 मिलियन टन) और छत्तीसगढ़ से आंतरिक उपयोग के लिए ही माल आया (0.11 मिलियन टन)। इस मामले में प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी अपर्याप्त है। - आकस्मिक देयता (टिप्पण संख्या 47.1) में भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सेंटर प्लांट II पैकेज से संबंधित लागत वृद्धि, लागत विस्तार, भुगतान में विलंब और ब्याज के लिए दावा किए गए ₹160.55 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं। नवंबर 2022 में एक बाहरी विशेषज्ञ समिति को संदर्भित यह मामला विवादित है और इसे आकस्मिक देयता के रूप में घोषित किया जाना चाहिए था। उपरोक्त को सम्मिलित न करने के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं में ₹160.55 करोड़ की कमी दर्ज की गई है। - सारंडा के संभागीय वन अधिकारी ने 30 अक्टूबर 2023 को 38,710 वृक्षों के वृक्षारोपण के लिए ₹19.50 करोड़ और 8,520 वृक्षों के वृक्षारोपण के लिए ₹4.29 करोड़ की मांग रखी। प्रबंधन ने रांची उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका के माध्यम से इन मांगों को चुनौती दी है। चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए इसे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। - संभावित देनदारी में ₹759.55 करोड़ की वह राशि सम्मिलित नहीं है, जिसका दावा जापान की मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन (लीडर) और कोलकाता की लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के कंसोर्टियम ने राउरकेला स्टील प्लांट में हॉट स्ट्रिप मिल-II के निर्माण में विलंब के कारण अतिरिक्त लागत के रूप में किया है। कंसोर्टियम ने नवंबर 2020 में सुलह प्रक्रिया शुरू की थी और मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा रहा है। इस जानकारी को गुप्त रखने के कारण संभावित देनदारियों में ₹759.55 करोड़ की कमी दर्ज की गई है।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
6	न्यू इंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड	- आकस्मिक देनदारियों में आयकर विभाग द्वारा अपील के अंतर्गत विवादित आयकर देनदारियों के रूप में ₹839.28 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए ₹323.38 करोड़, वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ₹214.29 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए ₹301.61 करोड़) को सम्मिलित नहीं किया गया है। एस-29 के अनुसार, ऐसी विवादित राशियों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में घोषित किया जाना चाहिए; घोषणा न करने के कारण आकस्मिक देनदारियों में ₹839.28 करोड़ की कमी दर्ज की गई है। - अचल संपत्तियों के लिए प्रतिबद्धताओं में मुंबई में आवासीय फ्लैटों के स्वामित्व हस्तांतरण से संबंधित संभावित स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क ₹10.50 करोड़ (जिसमें ₹0.50 करोड़ का जीएसटी सम्मिलित है) सम्मिलित हैं। आईसीएआई के दिशानिर्देश (1983) के अनुसार, पूंजी प्रतिबद्धता केवल बाध्यकारी अनुबंधों से उत्पन्न होती है; चूंकि राजस्व/स्थानीय प्राधिकरणों के पास कोई आवेदन नहीं किया गया है, इसलिए ऐसा कोई अनुलग्नक मौजूद नहीं है। इसके परिणामस्वरूप पूंजी प्रतिबद्धता में ₹10.50 करोड़ की अधिकता दर्ज की गई है।

क. v. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारत सरकार से पोत निर्माण वित्तीय सहायता (एसबीएफए) के रूप में ₹41.46 करोड़ की राशि दर्ज की, जिसका उपयोग पोतों के निर्माण में हुई लागत की भरपाई के लिए किया गया था। कंपनी ने पोतों की डिलीवरी की संशोधित तिथियों के कारण ₹10.72 करोड़ की राशि वापस कर दी और इस प्रकार ₹30.74 करोड़ की शुद्ध एसबीएफए राशि दर्ज की, जिसमें से कंपनी को ₹10.50 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सीएजी के निर्देशों के भाग-I, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के अनुलग्नक 'ए' में एसबीएफए का उल्लेख नहीं किया गया था, जिससे प्रतिवेदन उस हद तक अपूर्ण हो गई है।
2	आईएफसीआई लिमिटेड	सीएआरओ 2020 के खंड 3(vii)(बी) के अनुसार विवादित सांविधिक देय राशियों का प्रकटीकरण करना और उन मामलों के न्यायालय का विवरण देना अनिवार्य है जहां विवाद लंबित हैं। कंपनी के आयकर आयुक्त (ए), आईटीएटी और उच्च न्यायालय के समक्ष 11 आयकर अपीलें लंबित हैं, साथ ही वर्ष 2009-10 और 2013-14 से 2016-17 के लिए विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत ₹8.15 करोड़ की बकाया मांगें भी लंबित हैं। हालांकि, 30 अप्रैल 2024 की स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में केवल तीन मामलों (दो सीआईटी (ए) के समक्ष और एक ट्रेस पोर्टल के अनुसार) का ही उल्लेख किया गया है, शेष आठ मामलों और बकाया मांगों को छोड़ दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवेदन अपूर्ण है और सीएआरओ 2020 का अनुपालन नहीं करती है।
3	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	सीएआरओ 2020 के अनुलग्नक-I (vii)(बी) के अंतर्गत, सांविधिक लेखापरीक्षक ने रिपोर्ट दी थी कि मकान संबंधी भत्तों पर देय ₹43.62 करोड़ की टीडीएस (2001-02 से 2009-10) कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण जमा नहीं की गई थी। हालांकि, न्यायालय ने 18 फरवरी 2015 को इस मामले को खारिज कर दिया, जिससे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट गलत साबित हो गई। अनुलग्नक-I (vii)(बी) और अनुलग्नक-I (vii)(ए) के अंतर्गत टिप्पणियों में संशोधन की आवश्यकता है।

ख. असूचीबद्ध सरकारी सीपीएसई

ख. i. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1	बैंगलोर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	₹320.02 करोड़ के प्रावधानों (टिप्पण 21) में मेसर्स कर्नाटक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (केसीआईसी) के पक्ष में दिए गए मध्यस्थता निर्णय से संबंधित ₹17.07 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं है, यह राशि मेट्रो परियोजना के चरण 1 के रीच 3 और 3ए अनुलग्नक के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए थी। यद्यपि मध्यस्थ (मार्च 2020) ने 10 प्रतिशत ब्याज सहित ₹12.13 करोड़ के भुगतान का निर्देश दिया था, और वाणिज्यिक न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय में बीएमआरसीएल द्वारा दायर की गई याचिकाएं (जुलाई 2022 और फरवरी 2024) खारिज कर दी गईं, केवल एक समीक्षा याचिका लंबित है, फिर भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। चूंकि यह देयता सांविधिक मजदूरी दायित्वों से संबंधित है और कंपनी को पहले ही कई चरणों में नुकसान हो चुका है, इसलिए प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप व्यय और हानि को ₹17.07 करोड़ (₹4.94 करोड़ ब्याज सहित) कम करके दर्शाया गया है।
2	भारत संचार निगम लिमिटेड	- अन्य व्यय (टिप्पण 36) में ₹420.98 करोड़ की कमी दर्ज की गई है, जिसका कारण आयकर विभाग के टर्म सेल द्वारा सीएएफ और ईएमएफ पर लगाए गए जुर्माने को सम्मिलित न करना है, जिसके परिणामस्वरूप हानि में भी उतनी ही कमी दर्ज की गई है। इस मुद्दे को पिछले वर्ष भी उठाया गया था। - एलडब्ल्यूई परियोजना के लिए ₹69.11 करोड़ का राजस्व 30-04-2023 के बाद गलत तरीके से दर्ज किया गया था, जो बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय के निर्देशों (14-03-2024) का उल्लंघन था, जिसके परिणामस्वरूप अन्य परिचालन राजस्व का अधिक आकलन और नुकसान का समान राशि से कम आकलन हुआ।
3	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	अन्य व्यय (टिप्पण 13.8) में 2016-17 से 2021-22 तक ईसीएल के राजमहल क्षेत्र से कोयले में सतही नमी की अधिकता के कारण एनटीपीसी के प्रतिदाय दावे के लिए ₹214.52 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया था। योग ₹258.72 करोड़ के दावे के मुकाबले पिछले वर्ष केवल ₹44.20 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इंड एस 37 के पैरा 14 और लेखांकन नीति 2.21 के अनुसार, यह राशि मान्यता के मानदंडों को पूरा करती थी, और इसके छूट जाने के परिणामस्वरूप प्रावधानों का कम आकलन और लाभ तथा व्यापार प्राप्य का ₹214.52 करोड़ का अधिक आकलन हुआ है। 2022-23 में इस मुद्दे को उजागर किए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
4	गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस	जीईएम ने छ: विक्रेताओं से प्राप्त सेवाओं के लिए व्यापार देयताओं के अंतर्गत ₹57.82 करोड़ का प्रावधान किया, जबकि खातों की स्वीकृति से पहले ₹72.24 करोड़ (जिसमें ₹11.03 करोड़ जीएसटी सम्मिलित है) के बिल प्राप्त हो चुके थे। इसके अतिरिक्त, जीईएम ने ₹0.09 करोड़ की वास्तविक देयता के मुकाबले ₹0.22 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.13 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान हुआ। इसके परिणामस्वरूप व्यापार देयताओं में ₹14.29 करोड़ की कमी और इनपुट टैक्स क्रेडिट में ₹11.03 करोड़ की कमी हुई, जबकि अधिशेष में ₹3.26 करोड़ की वृद्धि हुई।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
5	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	अन्य व्यय (टिप्पण 27) में जीएचएमसी हैदराबाद को संपत्ति कर के रूप में देय ₹32.67 करोड़ (कारखाना ₹25.93 करोड़ और टाउनशिप ₹6.74 करोड़) सम्मिलित नहीं हैं। जबकि 2022-23 में की गई ₹23.71 करोड़ की मांग को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया था और यह 2023-24 में भी जारी रही, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹8.96 करोड़ के बकाया पर विचार नहीं किया गया और कोई देयता उत्पन्न नहीं हुई। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अन्य व्यय, चालू देयताओं और हानि में ₹32.67 करोड़ की कमी दर्ज की गई है।
6	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	कंपनी ने अपनी 435वीं बोर्ड बैठक (11 अगस्त 2023) में सह-बीमा प्राप्तियों और देयताओं को कुछ शर्तों के अधीन बड़े खातों में डालने/वापस लेने की नीति को स्वीकृति दी थी, जिसमें सह-बीमाकर्ता की लिखित अस्वीकृति भी सम्मिलित थी। इस नीति के विपरीत, कंपनी ने सभी निर्धारित मानदंडों को पूरा किए बिना ₹50.37 करोड़ की राशि को “लिखित रूप में स्पष्ट रूप से अस्वीकृत” बताकर वापस ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप अस्वीकार्य विविध आय की मान्यता हो गई। इससे अन्य आय का अधिक आकलन और चालू देनदारियों का कम आकलन हुआ और ₹50.37 करोड़ का नुकसान हुआ।
7	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	- लेखांकन नीति के अनुसार, सकल दावा भंडार के सापेक्ष सकल आईबीएनआर/आईबीएनईआर के प्रतिशत के रूप में शुद्ध आईबीएनआर/आईबीएनईआर की गणना की जानी चाहिए। समीक्षा से पता चला कि मोटर टीपी (गैर-पूल) व्यवसाय के लिए, कंपनी ने ₹6,478.99 करोड़ के बजाय ₹6,667.35 करोड़ का शुद्ध आईबीएनआर/आईबीएनईआर दर्ज किया, और फसल व्यवसाय के लिए, ₹270.85 करोड़ के बजाय ₹304.35 करोड़ दर्ज किया, जिससे ₹221.86 करोड़ (₹188.36 करोड़ + ₹33.50 करोड़) की अतिरिक्त बुकिंग हुई। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और दावों (शुद्ध) का अधिक आकलन और लाभ का समान राशि का कम आकलन हुआ। पिछले वर्षों में इस मुद्दे को उठाए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। - प्रावधानों में ₹458.65 करोड़ का अनर्जित प्रीमियम रिजर्व (यूपीआर) सम्मिलित है, जो 2022-23 तक जारी की गई उन पॉलिसियों के प्रीमियम के लिए बनाया गया था, जिनका जोखिम 2023-24 के दौरान समाप्त हो चुका था। आईआरडीए के परिपत्रों (जुलाई-2013 और अप्रैल-2016) और कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, अनर्जित जोखिम रिजर्व/अनर्जित जोखिम के लिए रिजर्व केवल आगामी अवधियों से संबंधित प्रीमियम को ही दर्शाना चाहिए; इसलिए, समाप्त हो चुकी पॉलिसियों के लिए कोई यूपीआर नहीं बनाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप रिजर्व का अधिक आकलन और लाभ का ₹458.65 करोड़ का कम आकलन हुआ। - कंपनी की लेखांकन नीति और आईआरडीए के परिपत्रों के अनुसार, प्रीमियम को जोखिम वाले वर्ष में ही दर्ज किया जाना चाहिए और बाद के वर्षों से संबंधित हिस्से के लिए आरयूआर बनाया जाना चाहिए। रबी 2023-24 के लिए डॉ. वाईएसआर मुफ्त फसल बीमा (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत, कंपनी को राज्य सरकार से तीन समूहों के अंतर्गत 12 जिलों के लिए ₹140.96 करोड़ के सकल प्रीमियम की पुष्टि प्राप्त हुई, लेकिन उसने केवल दो समूहों के लिए ₹41.86 करोड़ दर्ज किए, जिसके परिणामस्वरूप सकल प्रीमियम में ₹99.10 करोड़ और शुद्ध प्रीमियम में ₹95.14 करोड़ (4 प्रतिशत कटौती के बाद) की कमी दर्ज हुई।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		फलस्वरूप, संबंधित आरयूआर नहीं बनाया गया, जिससे अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) में ₹95.14 करोड़, आरयूआर में ₹47.57 करोड़ और लाभ में ₹47.57 करोड़ की कमी आई। 2023-24 में प्रत्यक्ष कारोबार से प्राप्त प्रीमियम में 2022-23 में लिए गए जोखिम सम्मिलित हैं, जो लेखांकन नीति का उल्लंघन है, क्योंकि नीति के अनुसार प्रीमियम को जोखिम वाले वर्ष के आधार पर दर्ज किया जाना चाहिए। वास्तविक प्राप्ति के आधार पर बुकिंग करने से भी उपार्जन लेखांकन नीति का उल्लंघन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लाभ में ₹525 करोड़ की अधिकता दर्ज हुई।

ख. ii. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1	अपोलो डिजाइन अपैरल पार्क्स लिमिटेड (वित्तीय वर्ष 2021-22)	सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ₹36.03 करोड़ की वह राशि सम्मिलित नहीं है जिसे वर्ष के घाटे के मुकाबले समायोजित किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार, सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग केवल निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है, इसलिए यह समायोजन अनुचित है। परिणामस्वरूप, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कम करके दर्शाया गया है और संचित आय को ₹36.03 करोड़ अधिक दर्शाया गया है, जबकि अन्यथा संचित घाटा भी इसी राशि का होता।
2	आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड	अन्य गैर-चालू देनदारियों (टिप्पण 19) में भारत सरकार को जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों से संबंधित ₹156.86 करोड़ सम्मिलित हैं, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अन्य इक्विटी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप अन्य गैर-चालू देनदारियों का ₹156.86 करोड़ का अधिक आकलन और अन्य इक्विटी (टिप्पण 12(ख)) का ₹156.86 करोड़ का कम आकलन हुआ है।
3	बैंगलोर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	₹25,914.69 करोड़ की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (टिप्पण 1) में ₹142.13 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं है, जो कि इब्बलुरु में चरण 2ए मेट्रो के लिए अधिग्रहित 13,503.261 वर्ग मीटर रक्षा भूमि का मूल्य है। यद्यपि समतुल्य अवसंरचना के निर्माण की शर्त पर रक्षा मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी और भूमि का कब्जा भी ले लिया गया था, कंपनी ने न तो भूमि को पूंजीकृत किया और न ही संबंधित देयता को मान्यता दी। इसके परिणामस्वरूप, भूमि और अन्य चालू देयताओं में ₹142.13 करोड़ की कमी दर्ज की गई, जो कंपनी की लेखांकन नीति 3.1, पीपीई की मान्यता संबंधी इंड एस 16 और देयताओं की मान्यता संबंधी इंड एस 37 का उल्लंघन है।
4	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड	अनुसूची III (डिवीजन II) के अनुसार, 12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमाओं को अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए। हालांकि, 15 जनवरी 2026 को परिपक्व होने वाली ₹12.00 करोड़ की सावधि जमा को गलती से 'नकदी और नकद समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष' के अंतर्गत वर्गीकृत कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप इस मद में ₹12.00 करोड़ की अधिकता और 'अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों' में ₹12.00 करोड़ की कमी दर्ज की गई।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
5	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	पूँजीगत कार्य प्रगति (टिप्पण 4) में कार्बन स्टील पाइप, एमडीपीई, जीआई पाइप, रेगुलेटर, वाल्व, एमआरएस और डीआरएस, तथा पीएनजी और सीएनजी स्पेयर पार्ट्स जैसी अचल इन्वेंट्री वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिनकी योग कीमत ₹19.88 करोड़ है और जो 4 से 10 वर्षों से निष्क्रिय पड़ी हैं। पिछले वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान इन वस्तुओं के क्षीणन का आकलन किए जाने के बावजूद, कंपनी ने क्षीणन मूल्यांकन नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप इंड एस 36 के पैराग्राफ 30-32 का अनुपालन नहीं हुआ है, और इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास कार्य प्रगति के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं के क्षीणन मूल्यांकन के लिए कोई स्पष्ट लेखांकन नीति भी नहीं है।
6	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	पूँजीगत कार्य प्रगति (टिप्पण 11) में ₹240.17 करोड़ की कमी दर्ज की गई है क्योंकि भारतनेट चरण-II के अंतर्गत टीएएनएफआईनेट के लिए 13.03.2024 को बीबीएनएल द्वारा स्वीकृत पूँजीगत व्यय को सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी और वर्तमान देनदारियों में कमी और पूँजी प्रतिबद्धताओं में समान राशि की अधिकता दर्ज की गई है।
7	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	अन्य चालू देनदारियों में ₹43.79 करोड़ की कमी दर्ज की गई है, जिसका कारण कर्नाटक सरकार को देय पर्यावरण संरक्षण शुल्क (ईपीएफ) को सम्मिलित न करना है। यह शुल्क मार्च 2009 में सरकारी आदेश संख्या एफईई 25 ईएनजी 2008 के अंतर्गत खनन के लिए उपयोग की जाने वाली गैर-वन/राजस्व भूमि के लिए ₹84,000 प्रति हेक्टेयर की दर से मांगा गया था। बार-बार याद दिलाने और सांविधिक दायित्व होने के बावजूद, बीजीएमएल ने प्रावधान बनाए बिना इसे आकस्मिक देनदारी के रूप में दर्शाना जारी रखा है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों और संचित हानियों में ₹43.79 करोड़ की कमी दर्ज की गई है।
8	ब्रेथवेट एनएसीओएफ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड।	अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (टिप्पण 10) ₹25 करोड़ की हैं, जो विद्युत खरीद समझौते की पूर्व शर्त के रूप में एमएसईडीसीएल को दी गई बैंक गारंटी के लिए मार्जिन राशि हैं। इस गारंटी को परियोजना के रद्द होने के बाद 15.07.2024 को भुना लिया गया था, क्योंकि परियोजना 31.03.2024 तक शुरू नहीं हो पाई थी। एस-4 के पैरा 13 के अनुसार, यह भुनाई, तुलन पत्र की तिथि पर मौजूद स्थितियों से संबंधित घटना होने के कारण, समायोजित की जानी चाहिए थी। समायोजन न होने के कारण गैर-चालू परिसंपत्तियों का अधिक आकलन और अवधि के लिए हानि का ₹25 करोड़ का कम आकलन हुआ है।
9	गोल्डमोहर डिजाइन एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड (वित्तीय वर्ष 2021-22)	सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ₹44.73 करोड़ की वह राशि सम्मिलित नहीं है जिसे वर्ष के घाटे के विपरीत समायोजित किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार, सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग केवल निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है और इस प्रकार का समायोजन अनुमेष नहीं है। इसके परिणामस्वरूप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कम आकलन और संचित आय का ₹44.73 करोड़ का अधिक आकलन हुआ है, जिससे अन्यथा संचित आय ₹44.73 करोड़ के संचित घाटे में परिवर्तित हो जाती।
10	आईएफसीआई वित्तीय सेवा लिमिटेड	नकद और नकद समतुल्य (टिप्पण-9) में एक वर्ष से अधिक परिपक्वता वाली ₹4.37 करोड़ की सावधि जमा और एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई ₹12.60 करोड़ की सावधि जमा सम्मिलित हैं, जो कि इंड एस अनुसूची III के अंतर्गत नकद और नकद समतुल्य की परिभाषा को पूरा नहीं करती हैं। इसके परिणामस्वरूप नकद और नकद समतुल्य का अधिक आकलन और नकद और नकद समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष का ₹16.97 करोड़ का कम आकलन हुआ।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
11	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड	• एक वर्ष से अधिक समय तक प्राप्य राशियों के विरुद्ध प्रावधान का समायोजन न होने के कारण अन्य परिसंपत्तियों (अनुसूची 11) को ₹26.89 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है। • ₹152.43 करोड़ की अप्राप्तकर परिसंपत्तियों (शुद्ध) की गणना में ग्रेच्युटी और डूबंत ऋण प्रावधानों को सम्मिलित न करने के कारण ₹10.94 करोड़ की कमी दर्ज की गई है, जिसके परिणामस्वरूप निवल लाभ में भी उतनी ही कमी दर्ज की गई है। • अन्य परिसंपत्तियों (अनुसूची 14) को ₹23.62 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है, क्योंकि ग्राहकों से आरबीआई द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर एसएमएस शुल्क लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप देनदारियों और प्रावधानों में समानुपातिक कमी हुई है।
12	कोलकाता मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	• पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) में संविदकरो/परामर्शदाताओं को भुगतान किए गए एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए ₹11.41 करोड़ सम्मिलित हैं, जिसे लेखांकन नीति संख्या 3.7 के अनुसार गैर-चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत 'एसजीएसटी प्राप्य' के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था और सीडब्ल्यूआईपी में तदनुसार कमी की जानी चाहिए थी। परिणामस्वरूप, सीडब्ल्यूआईपी में ₹11.41 करोड़ की अधिकता दर्शाई गई है और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त होने वाला एसजीएसटी - इसी राशि से कम दर्शाया गया है। • अन्य प्रशासनिक व्यय (टिप्पण 21.2) में कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मध्यस्थता निर्णय को चुनौती देने के लिए जमा की गई ₹31.43 करोड़ राशि सम्मिलित है, जिसे 'पूर्व-परिचालन व्यय' के बजाय 'पूंजीगत अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'पूर्व-परिचालन व्यय (आवंटन लंबित)' का मूल्य अधिक आंका गया है और 'अन्य परिसंपत्तियां (गैर-चालू)' का मूल्य ₹31.43 करोड़ कम आंका गया है। • पूंजीगत कार्य प्रगति (टिप्पण 5 - विद्युत आपूर्ति) में वाणिज्यिक संचालन के लिए बिजली प्रभार हेतु मेट्रो रेलवे पर लगाए गए ऊर्जा बिलों के लिए ₹14.75 करोड़ सम्मिलित हैं, जिसे 'प्रगतिशील कार्य प्रगति' के बजाय 'मेट्रो रेलवे से प्राप्य' के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, कार्यशील कार्य प्रगति का अधिक आकलन और 'कोलकाता मेट्रो रेलवे से प्राप्य' का ₹14.75 करोड़ का कम आकलन हुआ है।
13	मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और एमएमआरसीएल के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार, मुंबई मेट्रो परियोजना के वित्तपोषण स्रोतों में से एक एमएमआरडीए से प्राप्त ₹679 करोड़ का अनुदान था, जिसमें से ₹150 करोड़ वर्ष के दौरान प्राप्त हुए थे। हालांकि, एमएमआरसीएल ने इस अनुदान को अन्य गैर-चालू देनदारियों के बजाय अन्य इक्विटी के रूप में दर्ज किया है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य इक्विटी का अधिक आकलन और अन्य गैर-चालू देनदारियों का कम आकलन ₹150 करोड़ है।
14	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	आरआईएनएल ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार 12 दिसंबर 2023 के एक परिपत्र के माध्यम से अपनी विदाई योजना (स्वर्ण सिक्के) और दीर्घ सेवा पुरस्कार योजना (चांदी के पदक) को स्थगित रखने के बावजूद, 2023-24 के दौरान ₹51.73 करोड़ (गैर-चालू प्रावधानों के अंतर्गत ₹38.98 करोड़ और चालू प्रावधानों के अंतर्गत ₹12.75 करोड़) की देनदारी को मान्यता दी, जिसके परिणामस्वरूप देनदारियों और व्यय का अधिक आकलन और परिणामस्वरूप नुकसान का भी उतनी ही राशि से अधिक आकलन हुआ।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
15	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी पर एनटीपीसी लिमिटेड का ₹219.72 करोड़ का इंटर कॉर्पोरेट लोन-2 (आईसीएल-2) बकाया था, जिसका भुगतान वित्त वर्ष 2034-35 से या आईसीएल-1 के पूर्ण भुगतान के बाद, जो भी पहले हो, किया जाना था। वर्ष के दौरान आईसीएल-1 के लिए ₹400 करोड़ के पूर्व भुगतान के साथ, इसका पूर्ण भुगतान अब जून 2029 तक पूरा हो जाएगा, जिससे आईसीएल-2 की भुगतान तिथि जून 2029 तक आगे बढ़ जाएगी। हालांकि, कंपनी ने इंड एस 109 के पैरा बी5.4.6 के अंतर्गत आवश्यक आईसीएल-2 के वर्तमान मूल्य की पुनर्गणना नहीं की। संशोधित वर्तमान मूल्य ₹345.71 करोड़ बनता है, जिसके परिणामस्वरूप उधार का कम आकलन और अन्य इक्विटी का ₹125.99 करोड़ का अधिक आकलन हुआ है, साथ ही वित्तीय विवरणों के टिप्पण संख्या 17 में अपर्याप्त जानकारी दी गई है।
16	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	- वर्ष के अंत में बकाया दावों की राशि ₹14,727.95 करोड़ और आईबीएनआर/आईबीएनईआर की राशि ₹9,124.60 करोड़ थी, प्रत्यक्ष कारोबार के लिए योग राशि ₹23,852.55 करोड़ थी। हालांकि, कंपनी ने पुनर्बीमा समायोजन को घटाने के बाद चालू देनदारियों में केवल ₹19,672 करोड़ दर्ज किए, जबकि आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 के अंतर्गत पुनर्बीमा वसूली को अलग से दिखाना आवश्यक था। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और अग्रिमों एवं अन्य परिसंपत्तियों दोनों में ₹4,180.55 करोड़ की कमी दर्ज की गई। - बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 और आईआरडीएआई परिपत्र (अप्रैल 2016) के अनुसार, बीमाकर्ताओं को शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के लिए अलग-अलग निधियां रखनी चाहिए और निवेश और उचित मूल्य परिवर्तनों को तदनुसार विभाजित करना चाहिए। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, नकारात्मक निवल मूल्य के कारण, कंपनी ने शेयरधारकों की निधि ₹3,831.18 करोड़ और पॉलिसीधारकों की निधि ₹24,875.31 करोड़ बताई, जिसके परिणामस्वरूप विभाजन अनुपात क्रमशः (-)18.21 प्रतिशत और 118.21 प्रतिशत रहा। फलस्वरूप, ₹28,801.15 करोड़ के योग निवेश को शेयरधारकों (नकारात्मक निवेश) के लिए ₹5,244.69 करोड़ और पॉलिसीधारकों के लिए ₹34,045.84 करोड़ में विभाजित किया गया, जिससे अनुसूची 8 और 8ए के निवेशों में क्रमशः ₹5,244.69 करोड़ की कमी और अधिकता हुई। इसी प्रकार, शेयरधारकों के लिए उचित मूल्य परिवर्तन लेखाओं को कम करके दर्शाया गया और पॉलिसीधारकों के लिए इसे ₹1,615.65 करोड़ अधिक करके दर्शाया गया, जिसके परिणामस्वरूप पॉलिसीधारकों का अप्राप्त लाभ कंपनी के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो के योग अप्राप्त लाभ से अधिक हो गया। पिछले वर्षों में इस मुद्दे को उठाए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। - बैंक बैलेंस के अंतर्गत अल्पकालिक जमा खातों में विदेशी कार्यालयों की ₹358.11 करोड़ की सावधि जमा सम्मिलित थी, जिसमें से ₹57.47 करोड़ (नेपाल कार्यालय) की परिपक्वता अवधि 12 माह से अधिक थी और इसे अनुसूची 8 और 8ए के अंतर्गत दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके कारण भारत के बाहर अल्पकालिक जमा खातों और नकद एवं बैंक बैलेंस में ₹57.47 करोड़ की अधिकता दर्ज की गई।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
17	यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	- कंपनी के लेखा समापन दिशानिर्देशों और लेखा मानक 29 के विपरीत, 25 लंबित दावों के लिए ₹38.40 करोड़ का कम प्रावधान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों (प्रावधानों) और वर्ष के लिए हानि को ₹38.40 करोड़ कम करके दर्शाया गया है। - कंपनी ने तुलन पत्र में अनुसूची 8 के अंतर्गत निवेशों को सामूहिक रूप से दर्शाया है, जो 4 जुलाई 2016 के आईआरडीएआई विनियमों का उल्लंघन है। इन विनियमों में निवेशों को शेयरधारकों के निवेश (अनुसूची 8) और पॉलिसीधारकों के निवेश (अनुसूची 8ए) में विभाजित करने का प्रावधान है। इसके परिणामस्वरूप नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं हुआ है। - चालू परिसंपत्तियों (अनुसूची 12) में ₹580 करोड़ विवादित आयकर भुगतान के रूप में सम्मिलित थे, जो आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण से कोई प्रतिदाय आदेश न मिलने के बावजूद 2023-24 में अदा किया गया था। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों का अधिक आकलन और कर व्यय एवं हानि का ₹580 करोड़ का कम आकलन हुआ। - अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 12) में अंतर समूह संधि सदस्यों से अस्वीकृत पॉलिसी के लिए वसूली योग्य ₹44.06 करोड़ सम्मिलित थे, जिसकी वसूली असंभव है और जिसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, द्वितीय अंतरिम दावा भुगतान के लेखांकन में हुई त्रुटि के कारण कंपनी के दावे में ₹17.38 करोड़ की कमी हुई। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप अन्य बीमा कंपनियों से प्राप्त होने वाली शेष राशि को ₹61.44 करोड़ की राशि से अधिक तथा वर्ष की हानि को उतनी ही राशि से कम दर्शाया गया है।

ख. iii. नकदी प्रवाह विवरण/नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	कंपनी ने एएस-3 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में अपना नकदी प्रवाह विवरण तैयार नहीं किया है, क्योंकि परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अलग-अलग नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप लेखा मानक और नकदी प्रवाह विवरणों पर अपनी स्वयं की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 4 दोनों का अनुपालन नहीं हुआ है।
2	भारत संचार निगम लिमिटेड	कंपनी ने गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों में हुए परिवर्तनों को निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह के बजाय कार्यशील पूंजी के अंतर्गत गलत तरीके से सम्मिलित किया, जो कि इंड एएस 7 के विपरीत है, जिससे नकदी प्रवाह विवरण अपूर्ण हो गया। यह मुद्दा पिछले वर्ष भी उठाया गया था।
3	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड	- नकदी प्रवाह विवरण में खामियां हैं क्योंकि आईपीपीबी ने एएस 3 के पैरा 42 के अंतर्गत आवश्यक नकदी और नकदी समकक्षों का मिलान प्रस्तुत नहीं किया है। - आईपीपीबी ने परिचालन से नकदी प्रवाह में उपार्जित ब्याज, जो कि एक गैर-नकदी मद है, को गलत तरीके से सम्मिलित किया, जिसके परिणामस्वरूप एएस 3 का अनुपालन नहीं हुआ।
4	मसाकानी पारादीप रोड विकास लिमिटेड	इंड एएस-7 के पैरा 21 के अनुसार, 'अन्य बैंक शेष' में ₹24.25 करोड़ की वृद्धि को 'परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह' के अंतर्गत दिखाने के बजाय 'निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह' के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए था।

ख. iv. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1	एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय की 24 मार्च 2021 की अधिसूचना द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(1) का अनुपालन नहीं हुआ, जो यह अनिवार्य करता है कि वित्तीय विवरण अधिनियम की अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएं।
2	आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड	निगम लिमिटेड द्वारा 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा 24 मार्च 2021 की अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(1) का अनुपालन नहीं हुआ, जो यह अनिवार्य करता है कि वित्तीय विवरण अधिनियम की अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत किए जाएं।
3	बास्टर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी अधिनियम, 2013 में 24 मार्च 2021 को हुए संशोधन के अनुसार, कंपनियों को लेखा-पत्रों में विश्लेषणात्मक अनुपातों में 25 प्रतिशत से अधिक के परिवर्तनों के लिए स्पष्टीकरण देना आवश्यक है; हालांकि, कंपनी ने लागू अनुपातों का प्रकटीकरण तो किया, लेकिन चालू अनुपात के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसमें 99 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।
4	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने 31 मार्च 2024 को ₹1,531.62 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्य की सूचना दी। यह राशि पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण जीएसटी की प्रतिलोम संरचना है—कोयले की बिक्री पर आउटपुट जीएसटी 5 प्रतिशत है, जबकि इनपुट पर 5 प्रतिशत से 28 प्रतिशत तक की उच्च दरें लागू होती हैं। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 09/2022 - केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13 जुलाई 2022 ने स्थिति को और जटिल बना दिया है, जिसमें आईटीसी पर जमा की वापसी बंद कर दी गई, जिससे इनपुट पर भुगतान किए गए जीएसटी का उपयोग केवल आउटपुट पर जीएसटी के विरुद्ध ही सीमित हो गया। परिणामस्वरूप, आईटीसी का वार्षिक उपयोग वर्ष के दौरान क्रेडिट किए गए आईटीसी से लगातार कम रहा, जिससे पूर्व वर्षों से अग्रेषित शेष राशियों में वृद्धि हुई है और इसकी भावी वसूली के संबंध में पर्याप्त अनिश्चितता उत्पन्न हो गई। इंड एस 1 के अनुसार, ऐसी परिस्थितियाँ, जो परिसंपत्तियों के वहन मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकने वाली अनुमानगत अनिश्चितता का प्रमुख स्रोत हों, उनके संबंध में आधारभूत तथ्यों, मान्यताओं तथा जोखिमों का विस्तृत प्रकटीकरण आवश्यक है, ताकि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता सूचित निर्णय ले सकें। तथापि, न तो कंपनी ने लेखों पर टिप्पणियों में और न ही सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकटीकरण किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण कमी पाई गई।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		- सीआईएल की 01.04.2022 से प्रभावी संशोधित नीति के अनुरूप, बीसीसीएल ने पूर्व में प्रचलित अनुपात भिन्नता आरक्षित पद्धति को पीपीई के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों की मान्यता से प्रतिस्थापित कर दिया, जिसका परिशोधन खदान के समयावधि में किया जाना था, लेकिन अग्रिम स्ट्रिपिंग से प्राप्त लाभों के बाद में मिलने के आधार पर परिशोधन को अगले वर्ष के लिए स्थगित करने का विकल्प चुना। परिशोधन की सामान्य प्रक्रिया से यह विचलन, साथ ही इस बात की स्पष्टता का अभाव कि परिशोधन खदान के संपूर्ण समयावधि में किया जाएगा या शेष समयावधि में, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.19 में प्रकट नहीं किया गया था। चूंकि स्ट्रिपिंग गतिविधि खनन कार्यों का अभिन्न अंग है, इसलिए इंड एस 8 और इंड एस 1 के अनुसार इस महत्वपूर्ण लेखांकन नीति परिवर्तन की प्रकृति, तर्क और आधार का प्रकटीकरण आवश्यक है, जो अनुपस्थित था, जिसके परिणामस्वरूप प्रकटीकरण में कमी आई। 31 मार्च 2024 तक, बीसीसीएल ने स्थल पुनर्स्थापन/खदान बंद करने के लिए 49 “तीसरे पक्ष के पास सुरक्षित संपत्ति” करार में से 18 को कोयला मंत्रालय के मई 2020 के दिशानिर्देशों के अनुरूप संशोधित किया था, जिसमें खुली और भूमिगत खदानों के लिए खदान बंद करने की दरें बढ़ाई गई थीं, और इसके बाद सितंबर 2022 में कोयला नियंत्रक संगठन के खदान-वार बंद करने की लागत अनुसूचियों को अद्यतन करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, 31 समझौते अपरिवर्तित रहे, और इस स्थिति का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया। इन तथ्यों का प्रकटीकरण न करने से, जो उपयोगकर्ताओं के लिए कंपनी के दायित्वों को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं, इंड एस 1 के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कमी आई है।
5	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में 24 मार्च 2021 को अधिसूचित और 01 अप्रैल 2021 से प्रभावी संशोधनों के अनुसार, कंपनियों को चालू अनुपात, ऋण-इक्विटी अनुपात, ऋण सेवा आच्छादन अनुपात और इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात जैसे अनुपातों को अतिरिक्त नियामक जानकारी के भाग के रूप में प्रकट करना आवश्यक है; हालांकि, कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरणों में इन अनुपातों को प्रकट नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूची III की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं हुआ है।
6	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) ग्राहकों से संचित पूंजी (सीयूएफ) वसूल कर रही है और इसे ₹765.37 करोड़ (31 मार्च 2024 तक) की अन्य वित्तीय देनदारी (चालू) के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि ट्रांसपोर्टों द्वारा दायर याचिका के कारण सीयूएफ वसूलने का मामला झारखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, सीसीएल बैंक खातों में जमा इस संचित राशि पर ब्याज अर्जित कर रही है। सीसीएल ने उपरोक्त सीयूएफ पर मार्च 2024 तक अर्जित ₹78.14 करोड़ के ब्याज के प्रति कोई देनदारी नहीं बनाई और इसे अपनी आय के रूप में मान रही है। ये तथ्य वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किए गए हैं, जो इंड एस 01 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		- कंपनी ने 01.04.2022 से प्रभावी अपनी संशोधित नीति के अनुसार, पूर्व में प्रचलित अनुपात भिन्नता आरक्षित पद्धति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों (एसएए) की मान्यता से प्रतिस्थापित कर दिया है, जिनका परिशोधन खदान की समयावधि में किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि और अमूर्त परिसंपत्तियों के विपरीत, जहां परिशोधन उसी वर्ष में किया जाता है, कंपनी ने एसएए के परिशोधन को अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया, यह कहते हुए कि अग्रिम स्ट्रिपिंग से प्राप्त लाभ बाद में मिलते हैं। यह विचलन, साथ ही इस बात की स्पष्टता का अभाव कि परिशोधन खदान के संपूर्ण समयावधि में किया जाएगा या शेष समयावधि में, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.20 में प्रकट नहीं किया गया था। चूंकि स्ट्रिपिंग गतिविधि खनन कार्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इंड एस 8 और इंड एस 1 के अनुसार इस महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन की प्रकृति, तर्क और आधार का खुलासा करना आवश्यक है, जो प्रदान नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रकटीकरण में कमी आई। - कंपनी ने कोयला उत्पादक क्षेत्र अधिनियम, 1957 के अंतर्गत सरकारी अधिसूचनाओं के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया, जिसके अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति मिलने पर प्रभावित पक्षों को मुआवजा देय था। 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए पिछले पांच वर्षों के दौरान, भूमि/मकान मुआवजे के लिए ₹2724.78 करोड़ स्वीकृत किए गए, जिसमें से ₹2634.82 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, जिससे ₹89.96 करोड़ का भुगतान नहीं हो पाया है, जबकि अधिग्रहण प्रक्रिया अधिसूचित हो चुकी थी और अंतिम मुआवजा स्वीकृत भी हो चुका था। कंपनी द्वारा 2021 में अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त विशेषज्ञ राय में यह सुझाव दिया गया था कि प्रक्रियात्मक शर्तों की पूर्ति या भुगतान के समय की परवाह किए बिना, अधिग्रहण की तिथि पर सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर ऐसे दायित्वों को प्रावधानों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने न तो एक समान लेखांकन नीति अपनाई है और न ही इस बारे में सुसंगत खुलासे किए हैं कि “भूमि अधिग्रहण” क्या है और संबंधित देनदारियों को कब मान्यता दी जानी चाहिए और भूमि को कब पूंजीकृत किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप सहायक कंपनियों में लेखांकन प्रक्रियाओं में भिन्नता आई है और सीसीएल के वित्तीय विवरणों से ₹89.96 करोड़ की देनदारी को हटा दिया गया है। इस प्रकार ऐसी देनदारी को दर्ज न करना और उसकी जानकारी न देना, इंड एस 1 और इंड एस 37 के अनुरूप नहीं है, जिसके कारण लेखांकन नीति और पारदर्शिता दोनों में कमियां हैं। - सीसीएल ने 31 मार्च 2024 तक, अपने लेखाओं में पतरातु थर्मल पावर स्टेशन (पीटीपीएस)/झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) से ₹21.58 करोड़ की व्यापार प्राप्य राशि दर्शाना जारी रखा है, जबकि पीटीपीएस का परिचालन अप्रैल 2016 में पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल) को हस्तांतरित कर दिया गया था और जनवरी 2017 में बंद कर दिया गया था। जेवीसी करार में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हस्तांतरण तिथि से पहले उत्पन्न देनदारियों का भार न तो पीवीयूएनएल और न ही एनटीपीसी पर होगा।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		चूंकि पीटीपीएस/जेएसईबी अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए छः वर्षों से अधिक समय से कोई वसूली कार्रवाई या बातचीत नहीं हुई, जिससे इन बकाया राशि की वसूली अत्यधिक अनिश्चित हो गई है। हालांकि सीसीएल का दावा है कि राशि 2024-25 में वसूल कर ली जाएगी, लेकिन डूबंत ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, और न ही अनिश्चितता और संबंधित जोखिम का खुलासा किया गया है, जैसा कि इंड एस 1 के अंतर्गत आवश्यक है, जो महत्वपूर्ण अनुमान अनिश्चितताओं की प्रकृति, वहन राशि और संभावित परिणामों के खुलासे को अनिवार्य बनाता है। यह चूक प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन में कमी को दर्शाती है। इंड एस 1 के अनुसार, संस्थाओं को वित्तीय विवरणों का सही और निष्पक्ष विवरण सुनिश्चित करने के लिए अन्यत्र प्रस्तुत न की गई प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करना आवश्यक है। कोयला मंत्रालय के मई 2020 के दिशानिर्देशों ने 1 अप्रैल 2019 से खान बंद करने की दरों (खुली खदानें: ₹6.00 लाख से ₹9.00 लाख/हेक्टेयर; भूमिगत खदानें: ₹1.00 लाख से ₹1.50 लाख/हेक्टेयर) में वृद्धि की, और सितंबर 2022 में, कोयला नियंत्रक संगठन ने सभी सीआईएल सहायक कंपनियों को खदान-वार बंद करने की लागत अनुसूचियों को संशोधित करने और एस्करो करार को अद्यतन करने का निर्देश दिया। 31 मार्च 2024 तक, सीसीएल ने अपने 67 एस्करो करार में से 33 को संशोधित कर लिया था, जबकि 34 लंबित थे। ये लंबित संशोधन, जो देयता अनुमानों को प्रभावित करते हैं, वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन में कमी आई।
7	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	- इंड एस 1 के अनुसार, संस्थाओं को उन महत्वपूर्ण मान्यताओं और अनिश्चितताओं का खुलासा करना आवश्यक है जो परिसंपत्ति और देनदारी मूल्यों को काफी हद तक प्रभावित कर सकती हैं। 31 मार्च 2024 तक ईसीएल के पास ₹526.14 करोड़ का संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त था, जो उल्टी कर संरचना (कोयले की बिक्री पर 5 प्रतिशत जीएसटी, जबकि इनपुट पर 5-28 प्रतिशत कर) और 13 जुलाई 2022 से आईटीसी प्रतिदाय बंद होने के कारण सालाना बढ़ रहा है। उपयोग लगातार वार्षिक क्रेडिट और आगे ले जाए गए शेषों से कम होने के कारण, भविष्य के समायोजन की संभावना और समय अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि, इन तथ्यों और ऐसे आईटीसी को आगे ले जाने के औचित्य का खुलासा वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्रकटीकरण में कमी आई। - कंपनी की स्ट्रिपिंग गतिविधि संबंधी महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पण 2.19) को कोल इंडिया लिमिटेड के निर्देशों के अनुरूप 1 अप्रैल 2022 से संशोधित किया गया था। इसमें पूर्व में प्रयुक्त अनुपात भिन्नता विधि को प्रतिस्थापित करते हुए स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत मान्यता दी गई और यह जोड़ा गया कि ऐसी परिसंपत्तियों का परिशोधन खदान के समयावधि में किया जाएगा। हालांकि, अन्य परिसंपत्तियों के विपरीत, जिनका परिशोधन उसी वर्ष में किया जाता है, ईसीएल ने स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों के परिशोधन को अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया, यह कहते हुए कि लाभ बाद में प्राप्त होंगे। हालांकि, इस विचलन का खुलासा नहीं किया गया और न ही यह स्पष्ट किया गया कि परिशोधन खदान के संपूर्ण समयावधि में होगा या शेष समयावधि में। चूंकि स्ट्रिपिंग कोयला खनन का अभिन्न अंग है, और इंड एस 1 और इंड एस 8 के अनुसार महत्वपूर्ण नीतियों और परिवर्तनों के कारणों का खुलासा करना आवश्यक है, इसलिए इन विवरणों का अभाव उल्लिखित लेखांकन नीति में कमी का कारण बनता है।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
8	गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस	जीईएम ने दो संस्थाओं के साथ हुए करार के लिए ₹103.12 करोड़ की वास्तविक प्रतिबद्ध देनदारियों के बजाय केवल ₹70.33 करोड़ की प्रतिबद्धताओं का खुलासा किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिबद्धताओं को ₹32.79 करोड़ कम करके दर्शाया गया
9	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	(क) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में केरल सरकार द्वारा 251.40 एकड़ भूमि की वापसी से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले का खुलासा नहीं किया, जिससे नोट्स अपूर्ण रह गए। (ख) इसके अतिरिक्त, एयरपोर्ट-सीपोर्ट हाईवे फेज-II के लिए ₹16.34 करोड़ मूल्य की 1.6352 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण की स्थिति का खुलासा नहीं किया गया। (ग) यद्यपि विश्लेषणात्मक अनुपातों की रिपोर्ट की गई थी, लेकिन शुद्ध पूंजी कारोबार, निवल लाभ और नियोजित पूंजी/निवेश पर प्रतिफल अनुपातों में 25 प्रतिशत से अधिक के परिवर्तनों के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया था, जिसके कारण कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुपालन नहीं हुआ। (घ) इसके अतिरिक्त, कंपनी परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित जोखिमों का खुलासा करने में विफल रही, जैसा कि इंड एस-19 के पैरा 139 (बी) के अंतर्गत आवश्यक है, (ड) कंपनी ने निर्धारित अनुसूची III प्रारूप के अनुसार व्यापार प्राप्य का अवधिवार विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया, केवल “अच्छी स्थिति वाले” और “संदिग्ध” का खुलासा किया। (च) 1 सितंबर 2023 की बोर्ड एजेंडा नोट्स के अनुसार, लंबित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में एक, उच्च न्यायालयों में 24 और वाणिज्यिक एवं अन्य मामलों से संबंधित 9 मामले सम्मिलित थे; हालाँकि, एमटीके इकाई ने अपने लंबित मामलों का विवरण प्रदान नहीं किया, और ऐसे आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा इकाई पर वित्तीय प्रभाव का सत्यापन नहीं कर सकी।
10	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड ने अपने 62 ऋण/फैक्टरिंग/निवेश लेखाओं (एनपीए) में से 57 को ₹13.21 करोड़ के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कंपनियों को सौंप दिया, जिससे परिचालन में उल्लेखनीय कमी आई। इसके बोर्ड ने शेष पांच वित्तीय परिसंपत्तियों को होल्डिंग कंपनी, आईएफसीआई लिमिटेड को मुद्रिकृत या हस्तांतरित करने के बाद एनबीएफसी लाइसेंस के सैद्धांतिक समर्पण को स्वीकृति दे दी और वर्ष के दौरान कोई नया ऋण जारी नहीं किया गया। इन घटनाओं ने कंपनी के निरंतर परिचालन की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा किया; हालाँकि, कंपनी वित्त वर्ष 2023-24 के अपने वित्तीय विवरणों में इन महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं (लाइसेंस का समर्पण, परिचालन बंद करना, परिसंपत्ति बिक्री) का खुलासा करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप इंड एस 1 के खंड 25 का अनुपालन नहीं हुआ।
11	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	सीबीआई ने नवंबर 2018 में श्री शिवेंद्र तोमर (पूर्व प्रबंध निदेशक, आईआईडीएल), श्री पी. श्रीनिवास (पूर्व प्रबंध निदेशक, आईआईडीएल), मेसर्स होलिस्टिक अर्बन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड (एचयूआईपीएल) और अन्य के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और एचयूआईपीएल को अधिक भुगतान के आरोप में एफआईआर दर्ज की। इसके अतिरिक्त, आईएफसीआई ने अप्रैल 2022 में सीबीआई के उस अनुरोध को स्वीकृति दी जिसमें श्री तोमर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और आईपीसी के अंतर्गत जांच करने की बात कही गई थी।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		इस महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया, जिससे वे अपूर्ण रह गए, और वित्त वर्ष 2022-23 में इस ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
12	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड	मेसर्स ईआईटी सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष दायर किए गए दावे का खुलासा न करने के कारण आकस्मिक देनदारियों को ₹263.03 करोड़ कम करके दर्शाया गया है।
13	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	इस वर्ष के दौरान, कंपनी ने केरल सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों पर हड़को को ₹30.07 करोड़ (₹18.07 करोड़ मूलधन और ₹12 करोड़ ब्याज) की तिमाही किस्त का भुगतान करने में चूक की, और भुगतान 22 दिनों के विलंब से किया गया। इसके बाद, हड़को ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह एक तिमाही की किस्त के बराबर राशि को ऋण सेवा आरक्षित के रूप में अलग लेखाओं में रखे। कंपनी ने वित्तीय विवरणों के नोट्स में इस चूक या हड़को के निर्देश का खुलासा नहीं किया, जिससे उसने इंड एस 107 के पैरा 18(ए) और (सी) का उल्लंघन किया।
14	कोलकाता मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	- लेखांकन नीतियों पर टिप्पण 2.1 में कहा गया है कि रेल मंत्रालय के दिशानिर्देशों के आधार पर प्रबंधन की नीति के अनुसार, पूंजीगत निर्माणाधीन परियोजनाओं को अचल संपत्तियों में तभी स्थानांतरित किया जाता है जब परियोजना पूरी तरह से संपन्न हो जाती है। हालांकि, मंत्रालय के 2018 के संचार में केवल यह उल्लेख किया गया था कि मेट्रो रेलवे, कोलकाता पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण गलियारों का संचालन एकीकृत नियंत्रण के अंतर्गत करेगी और ऐसे स्थानांतरणों के लिए कोई लेखांकन प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी। अतः, टिप्पण 2.1 रेल मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है। - कंपनी ने मध्यस्थता के फैसले के संबंध में ₹62.87 करोड़ की संभावित देनदारी का खुलासा नहीं किया, जिसे कंपनी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
15	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	- कंपनी द्वारा घोषित आकस्मिक देनदारियों (टिप्पण 16) में माननीय दावा आयोग द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के अंतर्गत तुमूलिया और झुपुंरंगा के ग्रामीणों को दिए गए ₹1,282.86 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं है, जिस पर एमसीएल ने विवाद किया है और अदालत में चुनौती दी है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को उच्च न्यायालय को भेज दिया है, जहां यह अभी भी विचाराधीन है, लेकिन इंड एस 37 के अनुसार, इस प्रकार की विवादित देनदारियां आकस्मिक देनदारियों की परिभाषा में आती हैं। इस राशि को सम्मिलित न करने के कारण रिपोर्ट की गई आकस्मिक देनदारियों में ₹1,282.86 करोड़ की कमी आई है। 31 मार्च 2024 तक एमसीएल के पास ₹2,036.68 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) बकाया है, जो जीएसटी की प्रतिलोम संरचना (कोयले की बिक्री पर 5 प्रतिशत जीएसटी बनाम इनपुट पर 5 प्रतिशत-28 प्रतिशत) और सरकार द्वारा 13 जुलाई 2022 से आईटीसी प्रतिदाय बंद करने के कारण हर वर्ष बढ़ रहा है। उपयोग लगातार वार्षिक क्रेडिट और कैरी-फॉरवर्ड बैलेंस से कम होने के कारण, भविष्य में इसकी प्राप्ति अनिश्चित बनी हुई है। इसके बावजूद, न तो एमसीएल और न ही उसके लेखापरीक्षकों ने इंड एस 01 के अंतर्गत अपेक्षित रूप से इतने बड़े आईटीसी बैलेंस को कैरी-फॉरवर्ड करने के कारणों का खुलासा किया है, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त खुलासे हुए हैं। यह मुद्दा 2022-23 में भी उठाया गया था, लेकिन प्रबंधन द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		- कोल इंडिया लिमिटेड की नीति में बदलाव के बाद, कंपनी की स्ट्रिपिंग गतिविधि संबंधी महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पण 2.20) को 1 अप्रैल 2022 से संशोधित किया गया था। इसके अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि की लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है और खदान के समयावधि में उनका परिशोधन किया जाता है। हालांकि, पट्टे पर ली गई भूमि और अमूर्त संपत्तियों जैसी अन्य परिसंपत्तियों के विपरीत, एमसीएल इन परिसंपत्तियों का परिशोधन अगले वर्ष से करता है, यह कहते हुए कि लाभ बाद में प्राप्त होते हैं, जबकि नीति में इस विचलन का खुलासा नहीं किया गया है। नीति में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि परिशोधन खदान के पूरे समयावधि में होगा या शेष समयावधि में। इंड एस 8 और इंड एस 1 के अनुसार, ऐसे परिवर्तनों और विधियों की प्रकृति, आधार और कारणों का खुलासा किया जाना चाहिए था ताकि सूचित निर्णय लेने में सहायता मिल सके, जिससे वर्तमान खुलासा अधूरा हो जाता है। - महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और उड़ीसा सरकार भूमि बंदोबस्त अधिनियम, 1962 के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण करती है। सीबीए के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के लिए, एमसीएल परिसंपत्ति को पूंजीकृत करती है और स्वामित्व हस्तांतरण संबंधी सरकारी अधिसूचना के आधार पर मुआवजे की देनदारी को मान्यता देती है, जो एक विश्वसनीय अनुमान/मुआवजा सूची द्वारा समर्थित होती है, और स्वीकृत आदेश के बाद अंतिम समायोजन किए जाते हैं। इसके विपरीत, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की कुछ अन्य सहायक कंपनियां भूमि को पूंजीकृत करती हैं और मुआवजे के वास्तविक भुगतान पर ही देनदारी बनाती हैं, यह कहते हुए कि अधिग्रहण प्रक्रिया तभी पूरी होती है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि सीआईएल ने 2021 में अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों (मेसर्स रे एंड रे) से एक विशेषज्ञ राय प्राप्त की थी, जिसने विभिन्न शर्तों की पूर्ति की परवाह किए बिना, व्यय के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर, भूमि अधिग्रहण की तिथि पर मुआवजे की देनदारी को मान्यता देने की अनुशंसा की थी। सीआईएल की सहायक कंपनियों में “भूमि अधिग्रहण” की परिभाषा और पूंजीकरण एवं देयता मान्यता के समय को लेकर एकसमान लेखांकन नीति या मानक प्रकटीकरण का अभाव समूह के भीतर विभिन्न लेखांकन पद्धतियों का परिणाम है। यह असंगति न केवल वित्तीय विवरणों की तुलनात्मकता को प्रभावित करती है, बल्कि मुआवजे से संबंधित दायित्वों के प्रकटीकरण में कमी को भी दर्शाती है, जो इंड एस 1 और इंड एस 37 की आवश्यकताओं के विपरीत है।
16	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) ने पूर्व तट रेलवे (पूतरे) के साथ अपने संयुक्त उद्यम से ₹20.93 करोड़ उपयोगकर्ता शुल्क राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त की, जिसमें जुलाई 2023-मार्च 2024 के लिए रैक आवागमन और पिछले औसत के आधार पर अनुमानित ₹11.57 करोड़ सम्मिलित हैं, हालांकि पू.त.रे से इसकी कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई। जबकि इंड एस 115 के अनुसार राजस्व उलटफेर के जोखिम से बचने के लिए परिवर्तनीय प्रतिफल का अनुमान लगाने में प्रयुक्त निर्णयों और विधियों का खुलासा करना आवश्यक है, एमसीआरएल की लेखांकन नीति और नोट्स में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि राजस्व अंतिम रूप दिए गए ‘अंतर रेलवे वित्तीय समायोजन नियमों’ पर आधारित था या अनुमानों पर, और न ही वास्तविक प्राप्तियों और अनुमानों के बीच विभाजन का खुलासा किया गया।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		सीईआरएल जैसी अन्य सीआईएल सहायक कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथा के विपरीत, यह अप्रकटीकरण इंड एस 115 के अनुरूप नहीं है और राजस्व मान्यता नीति को त्रुटिपूर्ण बनाता है।
17	मसाकानी पारादीप रोड विकास लिमिटेड	महत्वपूर्ण लेखांकन नीति और लेखा संबंधी टिप्पणियों में निम्नलिखित कमियां थीं: (i) कंपनी ने मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त नहीं किया था, और वित्तीय विवरणों पर मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव के हस्ताक्षर नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(1) और 134 का अनुपालन नहीं हुआ; (ii) अक्टूबर 2023 में एचएएम मोड पर चंदीखोले-पारादीप एनएच-53 परियोजना (योग लागत ₹808.48 करोड़) के लिए किए गए सेवा रियायत करार का खुलासा इंड एस 115 के अनुलग्नक डी के पैरा 6 के अंतर्गत आवश्यक रूप से नहीं किया गया था; (iii) उपरोक्त रियायत करार के बावजूद टिप्पण 14 में पूंजी प्रतिबद्धताओं को गलत तरीके से शून्य बताया गया था, जिससे अनुसूची III का अनुपालन नहीं हुआ। और (iv) एमसीए की दिनांक 24/03/2021 की अधिसूचना के अंतर्गत अनिवार्य विश्लेषणात्मक अनुपातों का खुलासा नहीं किया गया, जिसमें अंश, हर और पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक के महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए स्पष्टीकरण सम्मिलित हैं।
18	मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	31 मार्च 2024 तक, जिन अनुबंधों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया और जिनके लिए प्रावधान नहीं किए गए, उनकी राशि ₹6,846.07 करोड़ थी, जिसमें मेसर्स वास्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड और मेसर्स मोंटेकार्लो लिमिटेड को दिए गए अनुबंधों के लिए ₹454.15 करोड़ की पूंजीगत प्रतिबद्धताएं सम्मिलित थीं। अन्य अनुबंधों के लिए प्रतिबद्धताओं की गणना में जीएसटी सम्मिलित किया गया था, जबकि इन दोनों अनुबंधों के लिए इसे सम्मिलित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत प्रतिबद्धताओं का ₹81.75 करोड़ का कम आकलन हुआ। यह कंपनी द्वारा पूंजीगत प्रतिबद्धताओं के अनुमान लगाने की प्रक्रिया में असंगति को दर्शाता है।
19	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	- शनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) ने "अन्य परिसंपत्तियों" के अंतर्गत "प्राप्तव्य" तथा "चालू देयताओं" के अंतर्गत "देय" शीर्ष प्रदर्शित किए हैं, जिनमें सह-बीमा तथा पुनर्बीमा दोनों से संबंधित शेष राशियाँ सम्मिलित हैं। सह-बीमा की शेष राशि को एक ही पक्ष के प्राप्य और देय राशियों को घटाए बिना प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनआईसीएल की इस प्रकार की घटाव संबंधी कोई निर्धारित नीति नहीं है और इस संबंध में आईआरडीआई द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं, जिसके कारण प्रस्तुति में असंगति है। - आईआरडीआई (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 की अनुसूची बी के भाग I के पैरा 2 के अनुसार, प्रीमियम को अनुलग्नक अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, के दौरान आय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि, एनआईसीएल की राजस्व मान्यता नीति में कहा गया है कि किशतों में भुगतान वाली पॉलिसियों के लिए, राजस्व को किशतों की प्राप्ति पर मान्यता दी जाती है, जो उक्त विनियम के अनुरूप नहीं है।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
20	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	- नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने कोयला युक्त क्षेत्र अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिग्रहित 477.42 हेक्टेयर भूमि के लिए स्वीकृत योग राशि ₹1202.41 करोड़ में से 318.03 हेक्टेयर भूमि के लिए भुगतान किए गए ₹843.27 करोड़ के भूमि मुआवजे को वित्तीय विवरणों में दर्शाया। 159.39 हेक्टेयर भूमि के लिए शेष ₹359.14 करोड़ की देनदारी, हालांकि बोर्ड द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित थी, को वित्तीय विवरणों में न तो दर्शाया गया और न ही खुलासा किया गया। एनसीएल द्वारा केवल वास्तविक भुगतान के आधार पर लेखांकन इंड एस 1 और इंड एस 37 की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। - नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने कोल इंडिया लिमिटेड के समान दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्ट्रिपिंग गतिविधि पर अपनी लेखांकन नीति में संशोधन किया है। एनसीएल ने स्ट्रिपिंग गतिविधि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी है और इसे खदान के समयावधि में परिशोधित किया है। हालांकि, अन्य परिसंपत्तियों के विपरीत, जिनका परिशोधन उसी वर्ष में किया जाता है, एनसीएल ने स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों के परिशोधन को अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है, और इस विचलन को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में प्रकट नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, नीति में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि परिशोधन खदान के संपूर्ण समयावधि में किया जाएगा या शेष समयावधि में। खनन कार्यों में स्ट्रिपिंग गतिविधि के महत्व को देखते हुए, इस प्रकार के प्रकटीकरण का अभाव इंड एस 1 और इंड एस 8 के अनुरूप नहीं है, जिससे लेखांकन नीति उस हद तक अपूर्ण हो जाती है।
21	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	- अन्य चालू परिसंपत्तियाँ (टिप्पण 14): परिचालन गतिविधियों के लिए धन जुटाने हेतु बोर्ड ने ₹476.18 करोड़ मूल्य की बाहरी संपत्तियों की बिक्री को स्वीकृति दी (22 मई 2024)। इंड एस 10 के पैरा 19 - रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं के अनुसार, इसका वित्तीय विवरणों में खुलासा करना आवश्यक था; हालाँकि, ऐसा कोई खुलासा नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इंड एस 10 का अनुपालन नहीं हुआ। - पट्टे (टिप्पण 48): कंपनी ने खुलासा किया कि मुंबई में 1.00 एकड़ भूमि सिडको से 60 वर्षों के लिए स्टॉकयार्ड के परिचालन हेतु पट्टे पर ली गई थी। वास्तव में, जनवरी 1988 में 16.34 एकड़ (66,145.50 वर्ग मीटर) भूमि पट्टे पर ली गई थी। अतः, किया गया खुलासा गलत था। - मूल्यहास विधियाँ और उपयोगी अवधि (टिप्पण 3डी): केंद्रीय प्रेषण यार्ड और वैगन मरम्मत कार्यशाला विस्तार में ₹92.22 करोड़ की लागत से किए गए सिविल और संबंधित कार्यों को 30 अप्रैल 2021 को 'भवन' मद के अंतर्गत 15 वर्ष की उपयोगी अवधि के साथ पूंजीकृत किया गया था, जबकि कंपनी की लेखांकन नीति ऐसे भवनों के लिए 60 वर्ष निर्धारित करती है। नीति से किसी भी विचलन को तकनीकी मूल्यांकन द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए और पर्याप्त रूप से प्रकट किया जाना चाहिए, जिससे वर्तमान प्रकटीकरण अपर्याप्त हो जाता है।
22	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड (2022-23)	कंपनी मामलों के मंत्रालय ने पारदर्शिता बढ़ाने और अतिरिक्त खुलासे अनिवार्य करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में 1 अप्रैल 2021 से संशोधन किया। वर्ष 2022-23 के लिए, कंपनी का इक्विटी में परिवर्तन का विवरण निर्धारित प्रारूप में नहीं था, और कुछ आवश्यक खुलासे—जैसे कि कंपनी के नाम पर न होने वाली अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख, निवेश संपत्ति के उचित मूल्यांकन का आधार और बेनामी संपत्ति का विवरण—प्रदान नहीं किए गए थे, जिसके कारण वित्तीय विवरणों के नोट्स अपूर्ण हो गए।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
23	ओरिएंटल इंडोरेस कंपनी लिमिटेड	टिप्पण 24 में कहा गया था कि वर्ष के अंत में या उससे पहले समाप्त हो चुके जोखिमों के लिए प्रीमियम को आय के रूप में मान्यता दी गई थी; हालांकि, ₹917.30 करोड़ के शुद्ध प्रीमियम (₹458.65 करोड़ के आरयूआर प्रभाव सहित) के लिए, “अर्जित न की गई प्रीमियम आरक्षित राशि” के निर्माण के कारण पूर्ण प्रीमियम को आय के रूप में मान्यता नहीं दी गई, जिससे टिप्पण अपूर्ण रह गया।
24	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	- साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने हालडीबारी भूमिगत खदान और अमगांव ओसीपी के अधूरे अनुबंधात्मक कार्यों से संबंधित ₹1104.95 करोड़ की राशि को राजस्व प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत प्रकट नहीं किया, जबकि इंड एस 1 के पैराग्राफ 114(डी) के अंतर्गत ऐसा प्रकटीकरण अनिवार्य है। इन प्रतिबद्धताओं के प्रकटीकरण न होने के कारण वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने में कमी आई है। - साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने कोल इंडिया लिमिटेड की संशोधित नीति के अनुरूप, 1 अप्रैल 2022 से पूर्वव्यापी प्रभाव से स्ट्रिपिंग गतिविधि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी और खदान के समयावधि में इसके परिशोधन का प्रावधान किया। हालांकि, अन्य परिसंपत्तियों के विपरीत, एसईसीएल ने स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों के परिशोधन को अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया, और इस विचलन को अपनी लेखांकन नीति में प्रकट नहीं किया। इसके अतिरिक्त, नीति में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि परिशोधन खदान के पूरे समयावधि में होगा या शेष समयावधि में। खनन कार्यों में स्ट्रिपिंग गतिविधि के महत्व को देखते हुए, इस प्रकार के खुलासे का अभाव इंड एस 1 और इंड एस 8 के अनुरूप नहीं है, जिससे नीति त्रुटिपूर्ण हो जाती है। - साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति मिलते ही संपत्ति क्षतिपूर्ति और पुनर्वास लाभ सहित भूमि क्षतिपूर्ति देनदारियों को मान्यता दी और सीआईएल द्वारा प्राप्त विशेषज्ञ राय के अनुरूप 2023-24 के दौरान ₹864.50 करोड़ का पूंजीकरण किया। हालांकि, अन्य सहायक कंपनियों ने अधिग्रहण प्रक्रिया के पूरा होने को पूंजीकरण का कारण बताते हुए, क्षतिपूर्ति का लेखा-जोखा केवल वास्तविक भुगतान के आधार पर किया। विशेषज्ञ राय होने के बावजूद, सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों ने “भूमि अधिग्रहण” क्या है और संबंधित देनदारियों को कब मान्यता दी जानी चाहिए, इस संबंध में कोई एकसमान लेखांकन नीति या प्रकटीकरण तैयार नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप सहायक कंपनियों में असंगत प्रथाएं और क्षतिपूर्ति दायित्वों के प्रकटीकरण में कमी आई है।
25	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) ने कोयला युक्त क्षेत्र अधिनियम, 1957 के अंतर्गत 3,842.31 हेक्टेयर भूमि के लिए स्वीकृत योग राशि ₹740.41 करोड़ में से 3,646.99 हेक्टेयर भूमि के लिए ₹705.34 करोड़ का भूमि मुआवजा दर्ज किया। 195.32 हेक्टेयर भूमि के लिए ₹35.07 करोड़ की शेष देनदारी, हालांकि स्वीकृत और अनुमोदित थी, को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी गई और न ही खुलासा किया गया, क्योंकि डब्ल्यूसीएल ने केवल वास्तविक भुगतानों को दर्ज करने की प्रथा का पालन किया।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		2021 में सीआईएल द्वारा प्राप्त विशेषज्ञ राय में भूमि अधिग्रहण के समय प्रावधान को मान्यता देने की अनुशंसा के बावजूद, सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों ने एक समान नीति या खुलासा नहीं अपनाया है, जिससे भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की देनदारियों के लेखांकन में विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं, जो इंड एस 1 और इंड एस 37 से भिन्न हैं। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) ने कोल इंडिया लिमिटेड की संशोधित नीति के अनुरूप, 1 अप्रैल 2022 से पूर्वव्यापी प्रभाव से स्ट्रिपिंग गतिविधि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी और खदान के समयावधि में इसके परिशोधन का प्रावधान किया। हालांकि, अन्य परिसंपत्तियों के विपरीत, डब्ल्यूसीएल ने स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्तियों के परिशोधन को अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया, और इस विचलन को अपनी लेखांकन नीति में प्रकट नहीं किया। इसके अतिरिक्त, नीति में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि परिशोधन खदान के संपूर्ण समयावधि में होगा या शेष समयावधि में। खनन कार्यों में स्ट्रिपिंग गतिविधि के महत्व को देखते हुए, इस प्रकार के प्रकटीकरण का अभाव इंड एस 1 और इंड एस 8 के अनुरूप नहीं है, जिससे नीति त्रुटिपूर्ण हो जाती है।

ख. v. लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुलग्नक ए के पैरा i(सी) में कमी है, क्योंकि कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण निर्धारित सीएआरओ 2020 प्रारूप में प्रकट नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अनुपालन नहीं हुआ।
2	ब्रेथवेट एनएसीओएफ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड	सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के “महत्वपूर्ण विषय” खंड में कहा गया है कि कंपनी द्वारा मेसर्स पाइनवुड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए ऋण करार में 18 माह की ऋण स्थगन अवधि का प्रावधान था, जिसके दौरान कोई ब्याज देय नहीं था। हालांकि, 15.02.2023 को दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में ब्याज भुगतान या मोहलत से संबंधित ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अतः, लेखापरीक्षक की “महत्वपूर्ण विषय” खंड में की गई टिप्पणी सही नहीं थी।
3	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	वित्त वर्ष 2023-24 में, आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड ने ₹13.21 करोड़ के 62 ऋण खातों में से 57 खाते सौंप दिए, अपने एनबीएफसी लाइसेंस को सरेंडर करने की स्वीकृति दी और शेष परिसंपत्तियों के लिए आईएफसीआई लिमिटेड से प्रस्ताव मांगा, जबकि वर्ष के दौरान कोई नया ऋण जारी नहीं किया गया। इन घटनाक्रमों ने कंपनी की निरंतर संचालन स्थिति पर गंभीर संदेह पैदा किया, लेकिन वित्तीय विवरणों में इनका अपर्याप्त रूप से खुलासा किया गया, और लेखापरीक्षकों ने इसे एसए 570 (संशोधित) और एसए 705 के अंतर्गत अपेक्षित योग्य/प्रतिकूल राय जारी करने के बजाय केवल “महत्वपूर्ण मुद्दे” के रूप में दर्ज किया, जिसके परिणामस्वरूप अनुपालन नहीं हुआ।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		सीएआरओ 2020 के अनुसार, लेखापरीक्षकों को सभी ऋणों, जिनमें एनपीए भी सम्मिलित हैं, के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची और बकाया राशि की रिपोर्ट देनी अनिवार्य है। हालांकि, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में केवल मानक ऋण परिसंपत्तियों के लिए पुनर्भुगतान नियमितता और बकाया स्थिति का खुलासा किया गया है, जिसमें निम्न-मानक, संदिग्ध और एनपीए ऋणों का विवरण सम्मिलित नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप सीएआरओ 2020 के पैरा 3(iii)(सी) और 3(iii)(डी) के अंतर्गत अपूर्ण रिपोर्टिंग हुई है।
4	पवन हंस लिमिटेड (2022-23)	- इंड एस 36 के अनुसार, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संस्था को यह आकलन करना होगा कि क्या किसी परिसंपत्ति के मूल्यहास का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है, तो संस्था को परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना होगा। हालांकि, कंपनी ने ऐसा मूल्यहास परीक्षण नहीं किया। सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपनी प्रतिवेदन में इस कमी को इंगित किया। सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपनी संशोधित प्रतिवेदन के “प्रतिकूल राय का आधार” शीर्षक के पैराग्राफ 1-ए में कहा है कि “51 प्रतिशत हिस्सेदारी के ₹199.92 करोड़ के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, कंपनी का योग मूल्यांकन ₹399.84 करोड़ है। 31 मार्च 2023 तक वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी की शुद्ध संपत्ति ₹902.55 करोड़ है। वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के मूल्यांकन की तुलना में शुद्ध संपत्ति में अंतर के कारण हानि ₹502.71 करोड़ है।” सांविधिक लेखापरीक्षक ने पवन हंस लिमिटेड में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के मूल्यांकन के आधार पर हानि की गणना की है। हालांकि, सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के मूल्यांकन पर की गई टिप्पणी को हानि की गणना का आधार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि निम्नलिखित कारण हैं: 1. कंपनी का मूल्यांकन संपूर्ण कंपनी के लिए किया गया है और इसका उद्देश्य कंपनी का विनिवेश करना है, जबकि परिसंपत्तियों का मूल्यहास केवल कुछ विशेष श्रेणियों पर किया जा रहा है, न कि संपूर्ण कंपनी पर। इंड एस 36 (परिसंपत्तियों के मूल्यहास से संबंधित) भंडार, निर्माण अनुबंधों से उत्पन्न परिसंपत्तियों, अप्राप्त कर परिसंपत्तियों, वित्तीय परिसंपत्तियों और बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों पर लागू नहीं होता है। 2. कंपनी के विनिवेश हेतु किए गए मूल्यांकन और वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरणों की स्वीकृति के बीच काफी समय का अंतर है, क्योंकि विनिवेश दिसंबर 2020 से पहले किया गया था। इसके अतिरिक्त, चूंकि विनिवेश की प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी, इसलिए किया गया मूल्यांकन अब प्रासंगिक नहीं है। उपरोक्त को देखते हुए, कंपनी के विनिवेश हेतु किए गए इस मूल्यांकन को रिपोर्टिंग अवधि, यानी 2022-23 के अंत में अचल परिसंपत्ति के मूल्यहास की गणना का आधार नहीं माना जा सकता है। साथ ही, यह इंड एस 36 के पैरा संख्या 9 का अनुपालन नहीं करता है, जिसमें कहा गया है कि “प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में एक इकाई को यह आकलन करना होगा कि क्या किसी परिसंपत्ति के मूल्यहास का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो इकाई को परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना होगा।”

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		3. इंड एस 36 के अनुसार हानि की गणना के लिए एक निर्दिष्ट कार्यप्रणाली है जिसमें वसूली योग्य राशि का निर्धारण सम्मिलित है, हालांकि, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के अभाव में, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि परिसंपत्ति का मूल्यांकन इंड एस 36 के अनुसार किया गया है या नहीं। उपरोक्त को देखते हुए, सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रतिकूल राय का आधार बनने वाली हानि की गणना अपर्याप्त है। - स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की प्रतिकूल राय के आधार के पैरा 10 (सी) (iii) में कहा गया है कि “उत्तरी क्षेत्र में, वित्तीय विवरणों में ₹ 6,676.55 लाख की अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) व्यवस्था दर्ज की गई है, जबकि सलाहकार द्वारा दिनांक 13-10-2023 को जारी ईसीएल प्रमाणपत्र के अनुसार, ₹ 6,695.94 लाख की ईसीएल व्यवस्था दर्ज की जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के “अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन” के पैरा 2 (बी) के अंतर्गत यह बताया गया है कि उत्तरी क्षेत्र के लेखाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा किया गया था। - उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, सांविधिक लेखापरीक्षक को उत्तरी क्षेत्र के लेखाओं के टिप्पण संख्या 32 (प्रावधान संचलन) में सम्मिलित खुलासे पर विचार करना चाहिए था, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड से संबंधित ईसीएल के ₹ 19.39 लाख की राशि लेखाओं में समायोजित की गई थी। उपरोक्त पर विचार न करने के कारण सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन उस हद तक अपूर्ण है।
5	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड (2022-23)	“अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन” में, पैरा 2(एच) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अंतर्गत तैयार किया गया था; हालांकि, सांविधिक लेखापरीक्षक ने कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2021 द्वारा 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी खंड (एफ) पर राय देना छोड़ दिया, जिससे स्वतंत्र लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन उस हद तक अपूर्ण हो गया। - स्वतंत्र लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन का अनुलग्नक ए, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के अनुरूप नहीं है, क्योंकि इसमें अमूर्त संपत्तियों [खंड 3(i)(बी)], कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल संपत्तियों के पूर्ण विवरण वाले स्वामित्व विलेख [खंड 3(i)(सी)], और विसलब्लोअर शिकायतों [खंड 3(xi)(सी)] पर आवश्यक विवरण सम्मिलित नहीं हैं, जिससे यह उस हद तक अपूर्ण हो जाता है।
6	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में, ‘संदर्भित राय का आधार’ अनुभाग में इक्विटी शेयरों के मूल्यहास पर लेखांकन नीति ए-10.6 में एक कमी का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसके वित्तीय प्रभाव का परिमाणीकरण नहीं दिया गया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात शेयरों के मूल्यहास के कारण उचित मूल्य परिवर्तन लेखाओं में लगातार कम आकलन और लाभ में ₹ 48.04 करोड़ की अधिकता के बावजूद, 27 मई 2024 की लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इस बात को उजागर नहीं किया गया। वित्तीय प्रभाव का परिमाणीकरण न देने के परिणामस्वरूप एसए 705 के पैरा 21 का अनुपालन नहीं हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण त्रुटियों का विवरण और परिमाणीकरण देना आवश्यक है, जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
7	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सीएजी के निर्देशों के उत्तरों में कमियां पाई गईं। लेखांकन लेनदेन को आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित करने के निर्देश के मामले में, उत्तर में यह खुलासा नहीं किया गया कि पीएमएफबीवाई के अंतर्गत पुनर्बीमा कार्यों के लिए जीसी कोर एप्लिकेशन पूरी तरह से स्वचालित नहीं है, जिसके लिए बॉर्डरॉक्स में प्राप्त कोटा शेयर प्रीमियम को भौतिक रूप से सम्मिलित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों के निर्देश के संबंध में, उत्तर में गलत तरीके से यह संकेत दिया गया कि पीएमएफबीवाई और आरएसबीवाई के अंतर्गत सब्सिडी कंपनी द्वारा प्राप्त की जाती है, जबकि ये लाभार्थियों को प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार, रिपोर्ट इन सीमाओं तक अपूर्ण है।

ग. सूचीबद्ध सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियाँ

ग. i. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1	ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, ट्रेजर की उपयोगी अवधि 25 वर्ष है; हालांकि, ट्रेजर VIII, XI, XII और XIV (1976-1991 के बीच निर्मित) अपना उपयोगी अवधि पूरा कर चुके थे और 1 अप्रैल 2023 से पहले ही उनका पूर्ण मूल्यहास हो चुका था। इसके बावजूद, कंपनी ने फरवरी 2022 और मार्च 2024 के बीच हुए ₹77.02 करोड़ के ड्राई डॉक मरम्मत खर्च (पुर्जो सहित) को पूंजीकृत किया और 2022-23 में ₹9.21 करोड़ और 2023-24 में ₹10.42 करोड़ का मूल्यहास लगाया, जबकि नीति और आईसीएआई की राय के अनुसार इस व्यय को अन्य व्ययों के अंतर्गत मरम्मत और रखरखाव के रूप में माना जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (शुद्ध) का मूल्य ₹57.39 करोड़ अधिक और अन्य व्ययों के अंतर्गत मरम्मत एवं रखरखाव (जहाजों) का मूल्य ₹67.81 करोड़ कम दर्शाया गया है, जिससे 2023-24 के लिए मूल्यहास और कर पूर्व लाभ का मूल्य क्रमशः ₹10.42 करोड़ और ₹57.39 करोड़ अधिक दर्शाया गया है। गौरतलब है कि 2021-22 और 2022-23 में इसी तरह की टिप्पणियां किए जाने के बावजूद, 2023-24 में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ग. ii. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	आकस्मिक देनदारियों (टिप्पण सी1) और लंबित मुकदमे (टिप्पण सी2) में ₹3,093.31 करोड़ की आयकर मांग और ₹78.09 करोड़ की जीएसटी मांग, योग मिलाकर ₹3,171.40 करोड़, का खुलासा सम्मिलित नहीं है। इस चूक के परिणामस्वरूप एएस-29 और आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 के अंतर्गत अपेक्षित आकस्मिक देनदारियों का खुलासा नहीं किया गया है।

घ. असूचीबद्ध सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कंपनियाँ

घ. i. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1	एचपी ऑयल गैस प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) को अंबाला-कुरुक्षेत्र और कोल्हापुर भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) के लिए प्रस्तुत निष्पादन बैंक गारंटी (बीजी) के लिए भुगतान किए गए ₹13.44 करोड़ (2023-24 के लिए ₹2.36 करोड़ और शेष 2018-19 से 2022-23 के लिए) के बैंक गारंटी (बीजी) कमीशन को पूंजीकृत किया, जो इंड एस 23 के पैरा 8 का उल्लंघन है, जिसके अनुसार ऐसे खर्चों को व्यय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, न कि पूंजीकृत। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2024 तक गैर-चालू परिसंपत्तियों (पीपीई, सीडब्ल्यूआईपी, अमूर्त परिसंपत्तियाँ और विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ) और अन्य इक्विटी का ₹13.44 करोड़ का अधिक मूल्यांकन, वित्त लागत का कम मूल्यांकन और 2023-24 के लाभ का ₹2.36 करोड़ का अधिक मूल्यांकन हुआ। इसके अतिरिक्त, चूंकि यह एक महत्वपूर्ण पूर्व अवधि की त्रुटि को दर्शाता है, इसलिए इंड एस 8 के अंतर्गत पिछले वर्षों के वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन भी आवश्यक है।
2	कामराजर पोर्ट लिमिटेड	31 मार्च 2024 तक, कंपनी ने कामराजर पोर्ट पर पूंजीगत ड्रेजिंग चरण-III के लिए कंपनी के प्रति मध्यस्थता निर्णय हेतु ₹36.39 करोड़ (₹21.08 करोड़ (निर्णय), ₹12.10 करोड़ (ब्याज) और ₹3.21 करोड़ (लागत)) की आकस्मिक देयता का खुलासा किया। हालांकि, तुलन पत्र की तिथि पर ₹36.39 करोड़ की देयता मौजूद होने के कारण, इसे इंड एस 37 के अनुसार प्रावधानित किया जाना चाहिए था। अतः, प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप देनदारियों में ₹36.39 करोड़ की कमी, पीपीई (पोर्ट बेसिन और प्रवेश चैनल) में ₹24.29 करोड़ की कमी, व्यय में ₹12.10 करोड़ की कमी और लाभ में ₹12.10 करोड़ की अधिकता दर्ज की गई।
3	कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड	'पुनर्निर्माण/प्रतिस्थापन लागत' संबंधी टिप्पण 49 में खामी है क्योंकि कंपनी ने अक्टूबर 2022 और मई 2023 के दौरान ₹376.87 करोड़ के पूर्ण ट्रैक नवीनीकरण (सीटीआर) लागत अनुमान और ₹136.86 करोड़ के अतिरिक्त संचालन एवं रखरखाव संबंधी कार्यों के लिए ₹376.87 करोड़ की लागत प्राप्त करने और सहमति देने के बावजूद, इंड एस 115 और इंड एस 37 के अंतर्गत अनुबंधात्मक बहाली दायित्वों के लिए ₹513.73 करोड़ का प्रावधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, इस अवधि के लिए प्रावधानों का कम आकलन और लाभ का समान राशि से अधिक आकलन हुआ है।
4	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	मुख्य पाइपलाइन बिछाने के अनुलग्नक को लेकर पुंज लॉयड लिमिटेड के साथ कंपनी का विवाद, विवाद से विश्वास योजना II के अंतर्गत सुलझा लिया गया। बोर्ड ने 27 मार्च 2024 को ₹33.12 करोड़ (ब्याज सहित) के पूर्ण और अंतिम निपटान को भी स्वीकृति दी। चूंकि यह 31 मार्च 2024 तक एक स्पष्ट देनदारी थी, इसलिए वित्तीय विवरणों में इसका प्रावधान किया जाना चाहिए था। हालांकि, कंपनी ने इसे आकस्मिक देनदारी के रूप में दर्शाया। परिणामस्वरूप, प्रावधान न करने से प्रावधानों में ₹33.12 करोड़, अचल संपत्तियों में ₹14.76 करोड़ और ब्याज व्यय में ₹18.36 करोड़ की कमी आई, जिससे लाभ में ₹18.36 करोड़ की अधिकता हुई।

घ. ii. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1	एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	31 मार्च 2024 तक, एआईसीआईएल ने बैंकों/वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों को देय कमीशन पर जीएसटी के लिए ₹21.11 करोड़ का प्रावधान नहीं किया, जबकि ₹117.28 करोड़ का कमीशन बुक किया गया था। पीएमएफबीवाई के परिचालन दिशानिर्देशों और एस-29 के पैरा 14 के अनुसार, इस जीएसटी देयता को मान्यता दी जानी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप विविध लेनदारों का मूल्य कम दर्शाया गया और लाभ का मूल्य ₹21.11 करोड़ अधिक दर्शाया गया
2	हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड	वर्तमान देनदारियों में गोरखपुर संयंत्र के लिए आयातित उपकरणों और सामग्रियों पर सीमा शुल्क के कम भुगतान के लिए आवश्यक ₹71.64 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित नहीं है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि रियायती पांच प्रतिशत शुल्क दर का लाभ गलत तरीके से उठाया गया था क्योंकि स्पेयर पार्ट्स के मूल्य संबंधी शर्त पूरी नहीं हुई थी। परिणामस्वरूप, कंपनी को ₹71.64 करोड़ के अंतर शुल्क के लिए प्रावधान करना चाहिए था, जो नहीं किया गया, जिसके कारण प्रावधानों में कमी और लाभ में समान राशि की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, आकस्मिक देनदारी भी अधिक बताई गई है।
3	झाबुआ पावर लिमिटेड	मध्य प्रदेश विद्युत प्रबंधन निगम लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) से 31.03.2025 के बाद देय आठ किस्तों के लिए प्राप्त होने वाली ₹37.61 करोड़ की राशि को गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के बजाय चालू वित्तीय परिसंपत्तियों - व्यापार प्राप्त के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप चालू वित्तीय परिसंपत्तियों - व्यापार प्राप्त का अधिक आकलन और गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों - व्यापार प्राप्त का ₹37.61 करोड़ का कम आकलन हुआ है।
4	नेशनल हाइवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड	कंपनी ने भारत की समेकित निधि (सीएफआई) को देय ₹21.22 करोड़ की राशि को अन्य चालू देनदारियों में सम्मिलित नहीं किया, जो कि एमओआरटीएच और एनएचएआई द्वारा अनिवार्य किए गए फास्टैग रहित वाहनों से फरवरी 2021 से मार्च 2024 के बीच वसूले गए जुर्माने का 50 प्रतिशत है। कंपनी ने इसके बजाय ₹19.81 करोड़ को परिचालन आय के रूप में दर्ज किया और गलती से सीएफआई के बजाय एनएचएआई को ₹1.41 करोड़ का भुगतान कर दिया। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष की आय में अधिकता दर्ज हुई, जिससे लाभ में ₹5.28 करोड़, संचित आय में ₹14.53 करोड़ की अधिकता हुई और चालू परिसंपत्तियों में ₹1.41 करोड़ तथा चालू देनदारियों में ₹21.22 करोड़ की कमी हुई। 2022-23 में भी इसी तरह की गड़बड़ी पाई गई थी।

घ. iii. नकदी प्रवाह विवरण/नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1	नबसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड	परिचालन और वित्तपोषण गतिविधियों के अंतर्गत ₹82.46 करोड़ (उपार्जित राशि ₹0.48 करोड़ सहित) की वित्त लागत का समायोजन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन नकदी प्रवाह में ₹82.46 करोड़ की कमी और निवेश नकदी प्रवाह में ₹81.98 करोड़ की अधिकता दर्ज की गई। इंड एस 7 के पैरा 21 के अनुसार निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से प्राप्त प्रमुख नकदी प्राप्तियों और भुगतानों की अलग-अलग रिपोर्टिंग आवश्यक है, इसलिए वित्तपोषण गतिविधियों के अंतर्गत इस राशि का खुलासा न करने से नकदी प्रवाह विवरण अपूर्ण हो गया है।

घ. iv. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1	एपीआईटीसीओ फाउंडेशन	लेखा संबंधी टिप्पणियाँ (टिप्पणी 16): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत पूरक लेखापरीक्षा के बाद, कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को सम्मिलित करने के लिए वित्तीय विवरणों को संशोधित किया गया और 7 अक्टूबर 2024 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। हालाँकि, संशोधन और इसके वित्तीय प्रभाव का खुलासा नहीं किया गया, जिसके कारण लेखा संबंधी टिप्पणियाँ अपूर्ण हो गईं।
2	भोर सागर पोर्ट लिमिटेड	कंपनी ने (टिप्पण 11.1: कॉर्पोरेट सूचना) प्रकटीकरण किया कि निदेशक मंडल ने 22 मार्च 2024 के प्रस्ताव के माध्यम से 'सतत् उपक्रम' के रूप में परिचालन जारी रखने का निर्णय लिया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पिछली बोर्ड बैठक (14 दिसंबर 2023) में पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि के सुझाव पर केवल चर्चा हुई थी, कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। इसलिए, प्रकटीकरण अपर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, ताजपुर में गहरे समुद्र बंदरगाह परियोजना स्थापित करने का प्राथमिक उद्देश्य अव्यवहार्यता के कारण संकल्पना स्तर पर ही छोड़ दिया गया था, इसलिए कंपनी का भविष्य का परिचालन अनिश्चित कारकों पर निर्भर है, जैसे कि राज्य सरकार के संभावित नए संयुक्त उद्यम और उनमें संभावित भागीदारी। तदनुसार, कंपनी की 'सतत् उपक्रम' के रूप में परिचालन जारी रखने की क्षमता पर गंभीर अनिश्चितता बनी हुई है।
3	ग्रीन गैस लिमिटेड	इंड एस 33 के अनुसार, ईपीएस की गणना इक्विटी धारकों को देय लाभ को अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जानी चाहिए। वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹4.48 करोड़ के अधिकार निर्गम के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी किए, लेकिन बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस की गणना करते समय, कंपनी ने शेयरों की भारित औसत संख्या पर विचार नहीं किया। परिणामस्वरूप, टिप्पण संख्या एम और लाभ-हानि विवरण दोनों में ईपीएस को सही आंकड़े ₹9.07 के बजाय गलत तरीके से ₹8.61 के रूप में दर्शाया गया।
4	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(1) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की बोर्ड की स्वीकृति अपूर्ण है, क्योंकि इसमें केवल तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता, लेखांकन नीतियां और नोट्स सम्मिलित हैं, जबकि इंड एस और अधिनियम की धारा 2(40) के अंतर्गत आवश्यक नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण सम्मिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण संशोधित एमसीए प्रारूप (24 मार्च 2021 की अधिसूचना) में तैयार नहीं किया गया है, और 25 प्रतिशत से अधिक अनुपात परिवर्तनों (टिप्पण-26) के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जो अधिनियम की अनुसूची III में दिए गए सामान्य निर्देशों के विपरीत है।
5	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों (केएमपी) के पारिश्रमिक संबंधी दिशानिर्देश (जून 2023) के अनुसार, बीमा कंपनियों को वर्ष के अंत में निर्धारित प्रारूप में एमडी/सीईओ/डब्ल्यूटीडी के बकाया अप्राप्त पारिश्रमिक का खुलासा करना अनिवार्य है। 31 मार्च 2024 तक, कंपनी के एमडी और सीईओ के चार पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित बकाया अप्राप्त पारिश्रमिक था, जिसमें दीर्घकालिक प्रोत्साहन, स्टॉक मूल्यवृद्धि अधिकार और कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजनाएं सम्मिलित थीं। हालांकि, इसका खुलासा लेखाओं के नोट्स में नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्रबंधकीय पारिश्रमिक संबंधी आईआरडीएआई के प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं हुआ।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
6	महाराष्ट्र प्राकृतिक गैस लिमिटेड	आकस्मिक देनदारियों (टिप्पण-34) को ₹26.70 करोड़ से कम करके दर्शाया गया था, क्योंकि वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 के अंतर्गत दिनांक 31.08.2018 के आदेश के माध्यम से आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी, पुणे-II द्वारा मांगे गए ₹26.70 करोड़ के विवादित सेवा कर पर ब्याज का खुलासा नहीं किया गया था।
7	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	कंपनी के 2023-24 के वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित कमियां हैं: (i) रेल मंत्रालय (आश्वासन प्राप्त ऑफ-टेक करार) और मेसर्स गेटेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बॉक्स एन एच एल वैगन) के साथ अनुबंधों के लिए गुणात्मक और परिमाणीकरण का खुलासा न करना, जैसा कि इंड एस 115 के पैरा 110 के अंतर्गत आवश्यक है; (ii) राजस्व पहचान पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 3.2 में इंड एस 115 के अनुसार अद्यतन होने के बजाय पूर्ववर्ती इंड एस 18 को दर्शाया गया है; और (iii) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और उनके पारिश्रमिक का खुलासा न करना, जो सम्बद्ध पक्ष प्रकटीकरण पर इंड एस 24 के पैरा 17 का उल्लंघन है।

घ. v. लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	एपीआईटीसीओ फाउंडेशन	सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एसए 560 के पैराग्राफ 12 के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में संशोधन किया; हालांकि, पैराग्राफ 12(बी) के अंतर्गत आवश्यक संशोधन के अनुसार, उन्होंने इसमें किसी विशेष मामले या अन्य मामले का उल्लेख नहीं किया जिसमें यह बताया गया हो कि उनकी अनुवर्ती कार्यवाही केवल वित्तीय विवरणों के संशोधन तक ही सीमित थी। अतः, संशोधित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस हद तक अपूर्ण है।
2.	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में कई कमियां हैं: (i) राय अनुभाग में लाभ और हानि विवरण के अनुसार “लाभ” के स्थान पर गलत तरीके से “लाभ/हानि” लिखा गया है, जो एसए-700 के विपरीत है; (ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 और उसके बाद के लिए लागू सीएआरओ 2020 के बजाय सीएआरओ 2016 के अंतर्गत रिपोर्टिंग की गई है; (iii) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के अंतर्गत रिपोर्टिंग 24 मार्च 2021 को अधिसूचित संशोधित नियमों का अनुपालन नहीं करती है; (iv) धारा 143(3) के अंतर्गत रिपोर्ट में धारा 143(3)(i) के अंतर्गत आवश्यक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्टिंग का उल्लेख नहीं है; और (v) सीएआरओ 2020 पर आईसीएआई के मार्गदर्शन टिप्पण द्वारा आवश्यक होने के बावजूद, धारा 143(5) के अंतर्गत सीएजी निर्देशों के अनुपालन पर रिपोर्टिंग का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
3.	आईएचबी प्राइवेट लिमिटेड	सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में 31.03.2024 तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रभावित भूस्वामियों द्वारा दायर 64 लंबित मुकदमों का खुलासा नहीं किया गया, जिनमें बढ़ी हुई भूमि क्षतिपूर्ति के रूप में ₹50.91 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सम्मिलित है। कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखापरीक्षक को “अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” में कंपनी की वित्तीय स्थिति पर ऐसे लंबित मुकदमों के प्रभाव की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण तथ्य की रिपोर्ट न करने के कारण लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में अपूर्ण खुलासा हुआ है।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
4.	कामराजर पोर्ट लिमिटेड	कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2021 के नियम 11(जी) के अनुसार, सांविधिक लेखापरीक्षकों को लेखा सॉफ्टवेयर में लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा के संचालन और अखंडता पर रिपोर्ट देनी होती है। यद्यपि स्वतंत्र लेखापरीक्षकों ने कहा कि कंपनी लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है, उन्होंने यह पुष्टि नहीं की कि इसका उपयोग पूरे वर्ष सभी लेन-देनों के लिए किया गया था और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। अतः प्रतिवेदन इस हद तक अपूर्ण है।

उपरोक्त तालिकाओं से यह स्पष्ट है कि पूर्व में उल्लेख किए जाने के बावजूद, कुछ सीपीएसई जैसे कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (बी.ि.3), द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (बी.1.7), ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सी.ि.1) और नेशनल हाइवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (डी.ii.4), इत्यादि ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

2.5.2 सांविधिक निगम जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है

सीएजी द्वारा सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, नीचे विस्तार से दी गई हैं:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (2022-23)

- 31 मार्च 2023 तक पूर्ण हो चुके कार्यों को पूंजीगत परिसंपत्तियों में पूंजीकृत करने के स्थान पर पूंजीगत कार्य प्रगति पर के अंतर्गत दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य प्रगति में ₹17.64 करोड़ की अधिकता, अचल संपत्तियों में ₹16.39 करोड़ की कमी और मूल्यहास में ₹1.25 करोड़ की कमी दर्ज हुई है, जिसके फलस्वरूप वर्ष का लाभ भी ₹1.25 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (2023-24)

- अन्य चालू देनदारियों में ₹30.37 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं है, जो सीसीटीवी कार्य, भवन निर्माण और मार्च 2024 तक निष्पादित अन्य संबंधित कार्यों के लिए ₹27.66 करोड़ की देनदारी न होने और ₹2.71 करोड़ के अन्य उपार्जित भुगतानों के लिए देनदारी न होने के कारण है। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) में ₹29.10 करोड़ की कमी, व्यय में ₹1.27 करोड़ की कमी और फलस्वरूप लाभ में ₹1.27 करोड़ की अधिकता दर्ज की गई है।
- मूर्त अचल संपत्तियों में त्रिची और चेन्नई में टर्मिनल भवन के उद्घाटन से संबंधित ₹11.52 करोड़ का व्यय और रांची के बिरसा मुंद्रा हवाई अड्डे पर मौजूदा शहर की सड़क के पुनर्निर्माण पर ₹0.79 करोड़ का व्यय सम्मिलित है, जिसे राजस्व व्यय के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों का ₹12.31 करोड़ का अधिक मूल्यांकन और व्यय का ₹12.31 करोड़ का कम मूल्यांकन हुआ है।
- अचल संपत्तियों में सूरत हवाई अड्डे पर कैनोपी के निर्माण की लागत ₹19.93 करोड़ और भूमि लागत के मुआवजे के रूप में ₹0.22 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं, जिन्हें राजस्व व्यय के रूप में बढ़े

खातों में डाल दिया गया। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों में ₹20.15 करोड़ की कमी, अन्य चालू देनदारियों में ₹0.22 करोड़ की कमी और व्यय में ₹19.93 करोड़ की अधिकता दर्ज की गई है। फलस्वरूप वर्ष का लाभ ₹19.93 करोड़ कम दर्शाया गया।

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और गुजरात सरकार के बीच हीरासर में नए हवाई अड्डे के विकास के लिए हुए समझौता ज्ञापन में यह शर्त रखी गई थी कि हीरासर में नए हवाई अड्डे के चालू होने के बाद मौजूदा राजकोट हवाई अड्डे को बंद कर उसकी भूमि का मुद्रीकरण किया जाएगा, जिससे नए विमानपत्तन की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तथापि, इस व्यवस्था का खुलासा लेखा-टिप्पणियों में नहीं किया गया।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) (2023-24)

- अन्य चालू देनदारियों में खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 34(2) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को देय ₹64.10 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर) लेखापरीक्षा शुल्क सम्मिलित नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों में ₹64.10 करोड़, लेखापरीक्षा शुल्क और चालू वर्ष के घाटे में ₹9.70 करोड़ और पूर्व अवधि के व्यय में ₹54.40 करोड़ की कमी दर्ज की गई है। “अन्य व्यय” के अंतर्गत दिया गया टिप्पण तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि लेखापरीक्षा शुल्क निर्विवाद है और वित्त मंत्रालय (अप्रैल 2023) द्वारा एक सांविधिक दायित्व के रूप में पुष्टि की गई है। पूर्व में की गई अभ्युक्तियों के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
- एफसीआई की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 9 के अनुसार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के अंतर्गत किए गए भुगतान, भुगतान की गई राशि के एक-पांचवें हिस्से को छोड़कर, अप्राप्त राजस्व व्यय के रूप में माने जाते हैं और अगले चार वर्षों में व्यय के रूप में दावा किए जाते हैं। यह एएस-15 (पैरा 146) का उल्लंघन है, जिसमें सेवा समाप्ति लाभों को तुरंत व्यय के रूप में दर्ज करने की आवश्यकता है। इसका अनुपालन न होने के कारण अप्राप्त राजस्व व्यय में ₹124.47 करोड़ की अधिकता दर्ज की गई है, जिसके परिणामस्वरूप प्रबंधन व्यय (विभागीय श्रमिकों का वेतन) में ₹113.63 करोड़ और पिछले वर्ष के व्यय में ₹10.84 करोड़ की कमी दर्ज की गई है।
- अन्य प्राप्तियों में दालों की मूल्य समर्थन योजना (टिप्पण सी2) पर प्राप्त ₹14.79 करोड़ का शुद्ध ब्याज सम्मिलित है, जिसे दिशानिर्देशों में इस प्रकार के प्रावधान के अभाव के बावजूद आय के रूप में मान्यता दी गई है। यह लेखा मानक के विपरीत है, जिसके अनुसार राजस्व की मान्यता तभी दी जानी चाहिए जब उसके अंतिम संग्रह के संबंध में कोई अनिश्चितता न हो। इसके परिणामस्वरूप आय और प्राप्य दोनों में ₹14.79 करोड़ की अधिकता दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, एफसीआई द्वारा पिछले वर्षों में इस मुद्दे को उठाए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
- निगम ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का लेखा-जोखा नकद आधार पर करता है, जो एएस-15 के पैरा 61 के विपरीत है, जिसमें सेवानिवृत्ति लाभ लागतों को लाभ और हानि विवरण में मान्यता देने की आवश्यकता होती है।

- निगम ने वित्तीय वर्ष 2013-14 से कम्प्यूटरीकृत वित्तीय लेखांकन पैकेज (एफएपी) अपनाया। भौतिक लेखांकन से एफएपी में परिवर्तन के समय, प्रबंधन ने सभी मौजूदा परिसंपत्तियों की अधिग्रहण तिथि 01.04.2013 मानने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, 01.04.2013 से पहले अधिग्रहित/उपयोग में लाई गई परिसंपत्तियों की अधिग्रहण/उपयोग में लाने की तिथि भी परिसंपत्ति बही में 01.04.2013 ही दिखाई गई है। फलस्वरूप, इन मौजूदा परिसंपत्तियों की शेष अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सका और परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में मूल्यहास की कम वसूली का परिमाण निर्धारित नहीं किया जा सका। चूंकि अधिग्रहण की वास्तविक तिथि भौतिक अभिलेखों में उपलब्ध है, इसलिए अधिग्रहण की तिथि में इस परिवर्तन के प्रभाव को लेखाओं में प्रकट किया जाना चाहिए था।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (2022-23)

- अनुसूची-2 के टिप्पण 12 के अनुसार, आईडब्ल्यूआई को कलादान परियोजना के लिए 31 मार्च 2023 तक विदेश मंत्रालय (एमईए) से ₹33.88 करोड़ प्राप्त हुए, जिसमें पीडीसी शुल्क के रूप में ₹29.05 करोड़, सेवा कर के रूप में ₹2.11 करोड़, जीएसटी के रूप में ₹1.72 करोड़ और जलवैज्ञानिक सर्वेक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में ₹1 करोड़ सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, परियोजना पर मुख्य रूप से बैंक ब्याज से ₹2.95 करोड़ की आंतरिक प्राप्तियां भी प्राप्त हुईं। उपरोक्त के मुकाबले, 31 मार्च 2023 तक ₹30.25 करोड़ का व्यय हुआ है। हालांकि, आईडब्ल्यूआई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कलादान परियोजना के लिए अलग बहीखाते रखे हैं, और आंतरिक प्राप्तियों को छोड़कर, इन लेन-देन का कोई भी प्रभाव आईडब्ल्यूआई के मुख्य लेखाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए आंकड़ों की लेखापरीक्षा द्वारा पूर्ण रूप से सत्यापन नहीं किया जा सका। इस मुद्दे को 2016-17 से बार-बार उठाया गया है, लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (2023-24)

- 2023-24 में, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) को अंतर्देशीय जल परिवहन और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ₹1,010.50 करोड़ तथा आईडब्ल्यूआई के अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/बांडों पर ब्याज देयता के निर्वहन हेतु राजस्व अनुदान के रूप में ₹76.50 करोड़ प्राप्त हुए; हालांकि, एएस-12 के अनुसार वित्तीय विवरणों में इन अनुदानों की प्रकृति का खुलासा नहीं किया गया, जिससे टिप्पण संख्या 17 अपूर्ण हो गया।
- आईडब्ल्यूआई ने मंत्रालय से इस उद्देश्य के लिए राजस्व अनुदान मांगने के बजाय, परिचालन एवं रखरखाव व्यय तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक व्यय के लिए ₹228.65 करोड़ के पूंजी अनुदान का उपयोग किया। यह मुद्दा 2016-17 से उठाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (2023-24)

- निगम द्वारा गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के लिए किया गया प्रावधान उसकी स्वयं की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति से भिन्न था, जिसमें परिसंपत्ति वर्गीकरण के आधार पर विशिष्ट न्यूनतम

प्रावधान दरें निर्धारित हैं—जो निम्न-स्तरीय परिसंपत्तियों के लिए 15 प्रतिशत से लेकर हानि वाली परिसंपत्तियों के लिए 100 प्रतिशत तक हैं। इसके विपरीत, निगम ने सभी एनपीए श्रेणियों में 100 प्रतिशत प्रावधान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹142.86 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। इस अतिरिक्त प्रावधान के कारण चालू देनदारियों और डूबंत ऋणों के लिए प्रावधानों का अधिक आकलन हुआ, जिससे अधिशेष (आय और व्यय के बीच का अंतर) ₹142.86 करोड़ कम दर्शाया गया

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (2022-23)

- वर्ष 2022-23 में, एनएचआई ने राजमार्ग रखरखाव और टोल संग्रह व्यय (अनुदान और प्राप्तियों के बाद शुद्ध ₹2,689.38 करोड़) के ₹4,650.84 करोड़ को लाभ और हानि खातों के बजाय पूंजी खातों में गलत तरीके से समायोजित किया, जिससे वर्ष की हानि और पूंजी दोनों में ₹2,689.38 करोड़ की कमी दर्ज हुई। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह अवसंरचना के निर्माण के लिए टोल राजस्व के पुनर्निवेश से कटौती की गई ₹62.50 करोड़ की राशि - जो पूंजीगत व्यय थी - को पूंजीकृत नहीं किया गया, जिसके कारण भारत सरकार की ओर से रखी गई पूंजी और परिसंपत्तियों में कमी दर्ज हुई। संबंधित लेखांकन नीति त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह ऐसी पूंजीगत परिसंपत्तियों को व्यय के रूप में माना गया है। यह मुद्दा लेखापरीक्षा में बार-बार उठाया गया है लेकिन इसका समाधान नहीं किया गया है।
- ₹9,221.93 करोड़ की पूंजी आरक्षित राशि को “भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों” में कटौती के रूप में गलत तरीके से दर्शाया गया, जबकि इसे आरक्षित और अधिशेष के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए था। यह लेखांकन सिद्धांतों के विपरीत है, जिनके अनुसार पूंजी आरक्षित (पूंजीगत लाभ से उत्पन्न) को आरक्षित निधि के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए। इससे आरक्षित और अधिशेष तथा भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों दोनों में ₹9,221.93 करोड़ की कमी आई है। इस मुद्दे को लेखापरीक्षा द्वारा बार-बार उठाया गया, लेकिन प्रबंधन द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया।
- भारत सरकार की ओर से रखी गई संपत्तियों में 2022-23 के दौरान पूर्ण और चालू परियोजनाओं पर पूंजीकृत ₹25,581.70 करोड़ की उधार लागत सम्मिलित है, जो एस 16 के विपरीत है, जिसके अनुसार परियोजनाओं के उपयोग के लिए तैयार होने पर पूंजीकरण बंद कर दिया जाना चाहिए। परियोजना-वार विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा आवंटन का सत्यापन नहीं कर सकी। योग मिलाकर, 31 मार्च 2023 तक ₹1,18,545.67 करोड़ की उधार लागत पूंजीकृत की जा चुकी है।
- परिसंपत्तियों में ₹23,197.79 करोड़ का “अप्रयुक्त पूंजी पर ब्याज” सम्मिलित है, जिसमें संविदाकारों/ परामर्शदाताओं को दिए गए अप्रयुक्त अनुदान और अग्रिमों पर ब्याज सम्मिलित है। जीएफआर 2017 नियम 230(8) के अनुसार, ऐसे ब्याज को भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाना चाहिए और भविष्य के अनुदानों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाना चाहिए। एनएचआई ने 2022-23 में ₹2,350.64 करोड़ का ब्याज अर्जित किया, लेकिन इसे सीएफआई में जमा नहीं किया, जिससे भारत सरकार को देय वर्तमान देनदारियों और भारत सरकार की ओर से धारित

परिसंपत्तियों दोनों को कम करके दर्शाया गया संबंधित लेखांकन नीति त्रुटिपूर्ण है और जीएफआर के अनुरूप नहीं है।

- एनएचएआई द्वारा विभिन्न कंपनियों/एसपीवी में किए गए ₹6,572.80 करोड़ के निवेश को लागत मूल्य पर दर्ज किया गया है, लेकिन एस 13 के अंतर्गत आवश्यक मूल्य में अस्थायी गिरावट के अलावा किसी अन्य गिरावट का आकलन करने के लिए हाल ही में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। घाटे में चल रही सहायक कंपनियों का अंतिम मूल्यांकन 2016-17 में किया गया था, जिसके बाद प्रावधान किए गए थे। हालांकि, शेष एसपीवी के लिए अद्यतन मूल्यांकन के अभाव में, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन किए गए निवेश मूल्य की सत्यता को सत्यापित नहीं कर सकी। इस मुद्दे को बार-बार उठाया गया है, लेकिन प्रबंधन द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।
- 31 मार्च 2023 तक विभिन्न रियायतकर्ताओं, संविदाकारों और सरकारी एजेंसियों से वसूल की जाने वाली ₹85.60 करोड़ की राशि चालू परिसंपत्तियों में सम्मिलित नहीं है, इसके परिणामस्वरूप 'वसूल किए जाने योग्य दावे' तथा 'भारत सरकार को देय देयता' दोनों ₹85.60 करोड़ कम दर्शाए गए।
- 31 मार्च 2023 तक भूमि मुआवजे, संविदाकारों/रियायतधारकों/उपभोक्ता विभागों को देय राशि तथा अन्य मदों के संबंध में देयताओं के लिए प्रावधान न किए जाने अथवा अपर्याप्त प्रावधान किए जाने के कारण चालू देयताएँ एवं प्रावधान ₹792.68 करोड़ कम दर्शाए गए, इसके अतिरिक्त, 'भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियाँ (पूर्ण/प्रगतिरत)' ₹788.85 करोड़ तथा 'राजमार्गों के अनुरक्षण पर व्यय' ₹3.83 करोड़ कम दर्शाए गए।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (2023-24)

- एनएचएआई अधिनियम, 1988 की धारा 23 के अनुसार, एनएचएआई के वार्षिक लेखा विवरण को भारत सरकार (जीओआई) द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के परामर्श से निर्धारित प्रारूप में तैयार किए जाने चाहिए।
 - i. एनएचएआई ने अपने तुलन पत्र में ₹10,07,532.92 करोड़ की राशि "भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियाँ (पूर्ण एवं प्रगतिरत)" को एक अलग मद के रूप में दर्शाया है, जो स्वीकृत प्रारूप और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएपी) के अनुरूप नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों का स्वामित्व भारत सरकार के पास है और एनएचएआई केवल एक कार्यकारी अभिकरण है, जैसा कि भारत के सॉलिसिटर जनरल ने (जनवरी 2015 में) पुष्टि की थी। आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने भी यह राय दी थी कि चूंकि एनएचएआई इन राजमार्गों को नियंत्रित नहीं करता है और न ही भविष्य में इनसे कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करता है, इसलिए इन्हें एनएचएआई की परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। अतः, एनएचएआई अधिनियम या लेखा के स्वीकृत प्रारूप (1992) में संशोधन किए बिना इन्हें परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाना गलत है।
 - ii. एनएचएआई ने स्वीकृत प्रारूप के अनुसार लाभ/हानि खाता तैयार करने के बजाय, 'शुद्ध स्थापना व्यय' (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹800.79 करोड़) की गणना की और इसे अचल परिसंपत्तियों के अंतर्गत "भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियाँ" में स्थानांतरित कर दिया, जिससे पूरी राशि का पूंजीकरण हो गया। यह प्रक्रिया जीएपी का उल्लंघन करती है, क्योंकि राजस्व व्यय को पूर्ण परियोजनाओं में दर्ज नहीं किया जा सकता है और इसे लाभ-

हानि खातों के माध्यम से दर्ज किया जाना चाहिए। परियोजना-वार विवरण उपलब्ध नहीं थे, जिससे लेखापरीक्षा के लिए इसके प्रभाव का आकलन करना संभव नहीं हो सका। इस संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 6 अपूर्ण है।

- iii. वित्त वर्ष 2023-24 में ₹25,900.33 करोड़ की उधारी लागत को पूंजीकृत किया गया है और इसे भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों (पूर्ण और निर्माणाधीन) में सम्मिलित किया गया है, जिनका योग मूल्य ₹10,07,532.92 करोड़ है। एएस 16 के अनुसार, पात्र परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए तैयार हो जाने पर पूंजीकरण बंद कर देना चाहिए; पूर्ण परियोजनाओं से संबंधित लागतों को लाभ और हानि खातों में प्रभारित किया जाना चाहिए। एनएचएआई परियोजना-वार विवरण नहीं रखता है, जिससे लेखापरीक्षा योग उधारी लागत (31 मार्च 2024 तक ₹1,44,446 करोड़) के आवंटन का सत्यापन करने में असमर्थ है।
 - iv. 2023-24 के दौरान, एनएचएआई ने राजमार्ग रखरखाव पर ₹5,812.21 करोड़ खर्च किए, जबकि एमओआरटीएच ने अनुदान के रूप में ₹1,174.07 करोड़ जारी किए और एनएचएआई ने अन्य प्राप्तियों से ₹128.99 करोड़ अर्जित किए। शुद्ध व्यय (₹4,509.15 करोड़) को लाभ-हानि खातों में दर्ज करने के बजाय, एनएचएआई ने इसे शेयरधारक निधि में समायोजित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप व्यय और शेयरधारक निधि दोनों में ₹4,509.15 करोड़ की कमी दर्ज हुई। लेखापरीक्षा में बार-बार उठाए गए इस विचलन का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है।
 - v. पूंजी (अनुसूची 1) में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) और टोल प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) पर खर्च किए गए ₹67.29 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं, जिसे एनएचएआई ने “टोल राजस्व की वापसी” से घटाया था। चूंकि यह पूंजीगत व्यय है, इसलिए इसे पूंजीकृत किया जाना चाहिए था, जिसके परिणामस्वरूप पूंजी (अनुसूची 1) और भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों (अनुसूची 5) में ₹67.29 करोड़ की कमी दिखाई गई है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (अनुसूची-18, पैरा 8) भी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे व्यय को पूंजीकृत करने के बजाय टोल भुगतान के विरुद्ध समायोजित करती है। पहले की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
- ₹9,414.73 करोड़ के पूंजीगत भंडार को “भंडार और अधिशेष” के अंतर्गत घोषित करने के बजाय “भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों” से कटौती के रूप में दर्शाया गया है, जबकि यह पूंजीगत लाभ से निर्मित होने के कारण आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप, “भंडार और अधिशेष” और “भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों” दोनों में ₹9,414.73 करोड़ की कमी दर्ज की गई है।
 - भारत सरकार की ओर से धारित संपत्तियों में ‘अप्रयुक्त पूंजी पर ब्याज’ के अंतर्गत ₹27,350.33 करोड़ सम्मिलित हैं, जो अप्रयुक्त पूंजी और संविदाकारों एवं परामर्शदाताओं को दिए गए ऋणों/अग्रिमों पर अर्जित संचयी ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 230(8) के अनुसार, ऐसे ब्याज को भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाना चाहिए और भविष्य में जारी की जाने वाली निधियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाना चाहिए। एनएचएआई ने वर्ष 2023-24 के दौरान ₹4,152.54 करोड़ ब्याज अर्जित किया, लेकिन इसे सीएफआई में जमा नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों (भारत सरकार को देय) और भारत सरकार की ओर से धारित संपत्तियों का कम आकलन हुआ। पिछले वर्षों

(2017-18 से 2022-23) में अर्जित ब्याज का भी मिलान और जमा करना आवश्यक है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 3, जो ऐसे ब्याज को “अप्रयुक्त पूंजी पर ब्याज” में जमा करती है, त्रुटिपूर्ण है और जीएफआर 2017 का उल्लंघन करती है।

- 31 मार्च 2024 तक भूमि मुआवजे के संबंध में संविदाकारों/रियायतकर्ताओं/उपभोक्ता विभागों और अन्य को देय राशि तथा अन्य मदों के संबंध में देयता के अपर्याप्त/कम प्रावधान के कारण चालू देनदारियों और प्रावधानों को ₹854.72 करोड़, कम दर्शाए गए। इसके अतिरिक्त, “भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियाँ (पूर्ण/प्रगतिरत)” ₹853.30 करोड़ तथा “वसूल किए जाने योग्य दावे” ₹1.42 करोड़ कम दर्शाए गए।

2.6 लेखांकन मानकों/इंड एस के प्रावधानों का अनुपालन न करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ धारा 129 (1), धारा 132 और धारा 133 के अंतर्गत प्रदत्त विद्युत्यों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार लेखा मानक निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के माध्यम से भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) अधिसूचित करती है, जिनमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने रिपोर्ट दी कि **अनुलग्नक XIII** में विस्तृत रूप से उल्लिखित 21 सीपीएसई अनिवार्य लेखा मानकों/इंड एस का अनुपालन नहीं करते हैं।

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान, सीएजी ने यह भी पाया कि कुछ सीपीएसई ने लेखांकन मानकों/इंड एस का अनुपालन नहीं किया था, जिसकी जानकारी उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा तालिका 2.3 में दिए गए अनुसार नहीं दी गई थी।

तालिका 2.3: लेखांकन मानकों/इंड एस का अनुपालन न करना

लेखांकन मानक/ इंड एस	विवरण	सीपीएसई का नाम	विचलन
एस 3	नकदी प्रवाह विवरण	ईसीजीसी लिमिटेड	कंपनी ने ₹1165 करोड़ की राशि के नकद और नकद समकक्षों में फिक्स्ड डिपॉजिट (जो तीन माह बाद परिपक्व होने वाले हैं) को सम्मिलित किया है, जो एस-3 की शर्तों के अनुसार नहीं है।
		जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कंपनी ने ₹6,526.77 करोड़ के ब्याज और लाभांश आय को निवेश गतिविधियों के बजाय परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत करके और तीन माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले ₹5,791.96 करोड़ की सावधि जमा को नकद और नकद समतुल्य में सम्मिलित करके एस-3 (नकदी प्रवाह विवरण) से विचलन किया है। इससे परिचालन नकदी प्रवाह और नकद और नकद समतुल्य को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया है, जबकि निवेश नकदी प्रवाह को कम करके दर्शाया गया है।

लेखांकन मानक/ इंड एस	विवरण	सीपीएसई का नाम	विचलन
		इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड	एस 3 के पैरा 42 का अनुपालन न करना। कंपनी ने उपार्जित ब्याज को भी, जो कि एक गैर-नकद मद है, नकदी प्रवाह विवरण में सम्मिलित किया है।
		एसबीआई फाउंडेशन	कंपनी ने ₹34370 करोड़ की पूरी नकदी और बैंक बैलेंस को नकदी और नकदी समतुल्य के रूप में मानकर एस-3 (नकदी प्रवाह विवरण) से विचलन किया है, जबकि इसके लिए आवश्यक मिलान (पैरा 42) तैयार नहीं किया गया और न ही इनकी संरचना निर्धारित करने की नीति का खुलासा किया गया (पैरा 43)। इसके अतिरिक्त, तीन माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली ₹258.70 करोड़ की सावधि जमा को निवेश गतिविधियों के अंतर्गत दर्शाने के बजाय गलती से नकदी और नकदी समतुल्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप नकदी और नकदी समतुल्य का अधिक आकलन और निवेश बहिर्वाह का कम आकलन हुआ।
		न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टैंडअलोन प्राप्तियों और भुगतानों लेखाओं में ₹7,722.60 करोड़ की संपूर्ण सावधि जमाओं (जिनमें तीन माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमा राशियाँ भी सम्मिलित हैं) को नकद और नकद समतुल्य में सम्मिलित करके एस-3 (नकदी प्रवाह विवरण) से विचलन किया है। विवरणों के अभाव में, लेखापरीक्षा तीन माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमाओं से संबंधित हिस्से का परिमाण निर्धारित नहीं कर सकी, जिसके परिणामस्वरूप एस-3 का अनुपालन नहीं हुआ।
एस 12	सरकारी अनुदानों का लेखा-जोखा	एसबीआई फाउंडेशन	कंपनी ने वर्ष के दौरान प्राप्त संपूर्ण अनुदान (₹322.38 करोड़) को परिचालन आय के रूप में दर्ज किया और इसे वर्ष के दौरान परियोजना व्यय (₹217.12 करोड़) के विरुद्ध समायोजित किया। एसबीआई और उसके समूह की कंपनियों से वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान ₹321.20 करोड़ था। इसमें से कंपनी ने केवल ₹213.91 करोड़ खर्च किए। इसके परिणामस्वरूप वर्ष की परिचालन आय में ₹107.29 करोड़ की अधिकता दर्ज हुई है, जो एसबीआई और उसकी सहायक कंपनियों से उनकी और से सीएसआर गतिविधियों को संचालित करने के लिए प्राप्त अनुदान की अव्यवस्थित राशि है, और इसी अनुपात में वर्ष के अधिशेष में भी अधिकता दर्ज हुई है।
एस 15	कर्मचारी लाभ	एसबीआई फाउंडेशन	कंपनी के पास एसबीआई लाइफ इश्योरेंस के साथ पॉलिसी के माध्यम से ग्रेच्युटी के लिए एक परिभाषित लाभ योजना होने के बावजूद, उसने कर्मचारी लाभ देनदारियों का एक्युअरियल मूल्यांकन नहीं किया है और न ही एस 15 के पैराग्राफ 120 (1) के अंतर्गत आवश्यक खुलासे किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप मानक का अनुपालन नहीं हुआ है।

लेखांकन मानक/ इंड एस	विवरण	सीपीएसई का नाम	विचलन
एस -20	प्रति शेयर आय (ईपीएस)	ईसीजीसी लिमिटेड	कंपनी ने एस 20 के पैरा 8 के अंतर्गत अपेक्षित लाभ और हानि लेखाओं में प्रति शेयर मूल और पतला आय प्रस्तुत नहीं की है।
इंड एस-1	वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति	सीएससी वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	कंपनी ने नियत समय के लिए निर्धारित सावधि जमाओं को गैर-चालू संपत्तियों के बजाय चालू संपत्तियों के रूप में सम्मिलित किया।
		नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	कंपनी ने लेखांकन शीर्षों के प्रस्तुतीकरण/वर्गीकरण में परिवर्तन किया है, लेकिन आवश्यकतानुसार ऐसे पुनर्वर्गीकरण की प्रकृति और कारण का खुलासा नहीं किया है।
		एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड	टिप्पण (1(ii)(ए) के अंतर्गत कंपनी का बयान, जिसमें इंड एस के साथ पूर्ण अनुपालन का दावा किया गया है, गलत है, क्योंकि यह क्रेडिट-खराब परिसंपत्तियों से ब्याज आय की मान्यता के संबंध में इंड एस 109 के पैरा 5.4.1(बी) का पालन नहीं करता है, जिससे इंड एस 1 के खंड 16 से विचलन होता है।
		स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएसएफ लिमिटेड	कंपनी ने वित्तीय विवरणों के नोटों में इंड एस 1 के पैरा 134 के अनुपालन का खुलासा नहीं किया है और न ही अपनी लेखांकन नीतियों में यह बताने में विफल रही है कि क्या वित्तीय विवरण इंड एस 1 के पैरा 25 के अंतर्गत आवश्यक रूप से निरंतर संचालन के आधार पर तैयार किए गए हैं।
इंड एस 7	नकद प्रवाह विवरण	गोल्डमोहर डिजाइन एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड (2021-22)	₹3.96 करोड़ की जमा राशि, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह से अधिक है, को निवेश गतिविधियों के अंतर्गत अन्य चालू संपत्तियों के अंतर्गत दिखाने के बजाय नकद और नकद समकक्षों के रूप में दर्शाया गया है।
		अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	इंड एस 7 के पैरा 18 का अनुपालन न करते हुए, ठेकेदार की (एफजीडी इंस्टॉलेशन के लिए) भुनाई गई बैंक गारंटी पर उत्पन्न ₹18.59 करोड़ की ब्याज देयता को “परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह” में गैर-नकदी मद के रूप में समायोजित किए जाने के बजाय “निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह” के अंतर्गत गलत तरीके से सम्मिलित कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप निवेश नकदी प्रवाह में ₹18.59 करोड़ की अधिकता और परिचालन नकदी प्रवाह में ₹18.59 करोड़ की कमी दर्ज की गई।
		एसआरआईसी (भारत) लिमिटेड	एसएआरएफआईएसआई के अंतर्गत ऋण पोर्टफोलियो और एनपीए के अधिग्रहण में लगी कंपनी ने सुरक्षा रसीदों और सीधे अधिग्रहीत ऋण लेखाओं में निवेश को निवेश गतिविधियों के बजाय परिचालन गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया है, जो इंड एस 7 के पैरा 6 के अनुरूप नहीं है।

लेखांकन मानक/ इंड एस	विवरण	सीपीएसई का नाम	विचलन
		ग्रीन गैस लिमिटेड	इंड एस 7 के पैरा 7 का उल्लंघन करते हुए, कंपनी ने तीन माह से अधिक (लेकिन बारह माह से कम) परिपक्वता अवधि वाले ₹1.99 करोड़ के सावधि जमा को 'नकदी और नकद समतुल्य' के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया, जबकि इसे 'नकदी और नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'नकदी और नकद समतुल्य' का ₹1.99 करोड़ का अधिक मूल्यांकन और 'नकदी और नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष' का ₹1.99 करोड़ का कम मूल्यांकन हुआ, और परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह विवरण में गलत विवरण दिया गया।
		आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2023-24 के नकदी प्रवाह विवरण में म्यूचुअल फंड यूनिटों की बिक्री पर लाभ को निवेश गतिविधियों के अंतर्गत गलत तरीके से दर्शाया गया है, जो कि इंड एस के विपरीत है।
		झाबुआ पावर लिमिटेड	इंड एस 7 के पैरा 43 का उल्लंघन करते हुए, 2023-24 के दौरान योग ₹46.92 करोड़ की ब्याज आय में से, नकदी प्रवाह विवरण में "प्राप्त ब्याज" के अंतर्गत केवल ₹31.05 करोड़ की नकद राशि ही दिखाई जानी चाहिए थी, जबकि गैर-नकद भाग को गलत तरीके से सम्मिलित कर लिया गया। इसके परिणामस्वरूप निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह का ₹15.87 करोड़ अधिक और परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह का ₹15.87 करोड़ कम दर्शाया गया, जिससे नकदी प्रवाह विवरण में कमी आई।
		नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	इंड एस 7 के पैरा 16 (ए) और (ई) के अनुसार, निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी में वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ₹44.04 करोड़ के पूंजीगत अग्रिमों को सम्मिलित न करने के कारण, निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी का कम आकलन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी का भी इसी राशि से कम आकलन हुआ है।
			निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी में उपयोग के अधिकार परिसंपत्तियों में ₹35.99 करोड़ की वृद्धि को सम्मिलित करने से, जो कि इंड एस 7 के पैरा 43 और 44 के अनुसार गैर-नकदी लेनदेन था, निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी का अधिक आकलन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी का भी अधिक आकलन हुआ है।

लेखांकन मानक/ इंड एस	विवरण	सीपीएसई का नाम	विचलन
			निवेश नकदी प्रवाह में ₹44.04 करोड़ के पूंजीगत अग्रिमों को सम्मिलित न करने से निवेश बहिर्वाह और परिचालन अंतर्वाह दोनों कम करके आंका गया, जबकि उपयोग के अधिकार परिसंपत्तियों में ₹35.99 करोड़ की गैर-नकद वृद्धि को सम्मिलित करने से निवेश और परिचालन नकदी प्रवाह दोनों को बढ़ा-चढ़ाकर आंका गया, जिससे इंड एस 7 का अनुपालन नहीं हुआ।
		एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	इंड एस 7 के पैरा 6 और आईसीएआई विशेषज्ञ सलाहकार समिति (04 जनवरी 2018) की राय के विपरीत, जिसमें कहा गया है कि परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों को निवेश गतिविधियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए, कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से प्राप्त ₹460.59 करोड़ के पूंजी अनुदान को 'निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह' के बजाय 'वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह' के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया, जिसके परिणामस्वरूप इंड एस 7 का अनुपालन नहीं हुआ और नकदी प्रवाह का वर्गीकरण भी उतनी ही राशि से गलत हुआ।
		पवन हंस लिमिटेड (2022-23)	कंपनी ने ₹3.40 करोड़ की ब्याज आय दर्ज की, जिसमें ₹1.36 करोड़ की राशि सावधि जमा पर अर्जित ब्याज के रूप में सम्मिलित थी। परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की गणना करते समय इसे 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी' में गलत तरीके से सम्मिलित कर लिया गया था, जबकि इंड एस 7 के अनुसार केवल प्राप्त नकद ब्याज को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए था। इस गलत वर्गीकरण के कारण निवेश नकदी प्रवाह ₹1.36 करोड़ अधिक और परिचालन नकदी प्रवाह ₹1.36 करोड़ कम दर्शाया गया
		रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	इंड एस 7 के पैरा 6 के विपरीत, 31 मार्च 2024 को एसबीआई मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम (एमओडीएस) के अंतर्गत जमा ₹171.21 करोड़ की राशि को 'नकद और नकद समतुल्य' के बजाय 'नकद और नकद समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जबकि एमओडीएस पूर्ण तरलता प्रदान करता है। इसके परिणामस्वरूप 'नकद और नकद समतुल्य' का कम आकलन और 'नकद और नकद समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष' का ₹171.21 करोड़ का अधिक आकलन हुआ।
			इंड एस 7 के पैरा 17 के उल्लंघन में, कार्यशील पूंजी के लिए एनटीपीसी से लिए गए ₹100 करोड़ के अल्पकालिक ऋण को "वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह" के बजाय "परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह" के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन नकदी प्रवाह का ₹100 करोड़ से अधिक और वित्तपोषण नकदी प्रवाह का ₹100 करोड़ से कम मूल्यांकन हुआ।

लेखांकन मानक/ इंड एस	विवरण	सीपीएसई का नाम	विचलन
		सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	एफडीआर पर अर्जित ₹19.90 करोड़ के ब्याज को निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था।
इंड एस 12	आयकर	बास्टर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	इंड एस 12 के पैरा 34 के अनुसार भविष्य के कर योग्य लाभों का अनुमान लगाने वाले पूर्वानुमान विवरणों का रखरखाव न करना।
इंड एस 16	सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	इंड एस 16 के पैरा 51 के अनुसार, किसी परिसंपत्ति के अवशिष्ट मूल्य और उपयोगी अवधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जानी चाहिए। लेखांकन नीति 1.6 में भी ऐसी समीक्षा की आवश्यकता सम्मिलित है, और इसके अतिरिक्त मूल्यहास की विधि की समीक्षा भी अनिवार्य है। सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई। इंड एस 16 से विचलन करते हुए, पाइलिंग के कारण बेकार सामग्री को सम्मिलित करने के कारण, अन्य इक्विटी के अनुरूप ₹9.23 करोड़ की अधिकता के साथ पूंजीगत कार्य प्रगति को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है, जो पिछले वर्षों में निरर्थक/निष्क्रिय साबित हुई थी।
		स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	स्कूलों के संचालन, रामकृष्ण मिशन आश्रम के संचालन, खेल मेले के आयोजन आदि पर किया गया व्यय रौघाट खान क्षेत्र में अयस्क निष्कर्षण से संबंधित नहीं था। ये केवल कल्याणकारी उपाय हैं और इन्हें इंड एस 16 के पैरा 16 के अनुसार लाभ और हानि विवरण में सम्मिलित किया जाना चाहिए था।
इंड एस 19	कर्मचारी लाभ	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत संस्था को होने वाले जोखिमों के विवरण का खुलासा न करना, जो कि इंड एस 19 के पैरा 139(बी) के अंतर्गत आता है।
		महाराष्ट्र मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	कंपनी ने परिभाषित अंशदान योजना के अंतर्गत भविष्य निधि में किए गए अंशदान का खुलासा नहीं किया है, जिसे इंड एस 19 के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए "परिभाषित अंशदान योजना" के अंतर्गत अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
		एनएमडीसी लिमिटेड	अवकाश नकदीकरण योजना के प्रति दायित्व का प्रावधान न करना।
इंड एस 20	सरकारी अनुदान और सरकारी सहायता	मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	अन्य वित्तीय देनदारियों में महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त ₹1,104.88 करोड़ की अनुदान सहायता सम्मिलित है, जिसे कंपनी ने इंड एस 20 के अनुसार आय या संबंधित व्यय में कमी के रूप में दर्ज करने के बजाय वित्तीय देनदारियों के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया है। इस गलत वर्गीकरण के कारण डब्ल्यू आईपी ₹772.07 करोड़, चालू वित्तीय देनदारियां ₹1,104.88 करोड़ अधिक, आय ₹200.69 करोड़ कम और अन्य चालू देनदारियां ₹132.12 करोड़ कम दिखाई गईं।

लेखांकन मानक/ इंड एस	विवरण	सीपीएसई का नाम	विचलन
		मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	इंड एस 20 के पैरा 39 के अनुसार, सरकारी अनुदानों के लिए अपनाई गई लेखांकन नीति, जिसमें वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत करने की विधियाँ भी सम्मिलित हैं, का खुलासा किया जाना आवश्यक है। अनुदान सहायता संबंधी मौजूदा लेखांकन नीति संख्या 1.20, ऋण चुकोती के लिए प्राप्त अनुदान सहायता के संबंध में निरुत्तर है।
इंड एस 23	उधार लागत	बैंगलोर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत की राशि और उपयोग की गई पूंजीकरण दर का खुलासा न करना।
इंड एस 24	सम्बद्ध पक्ष प्रकटीकरण	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	इंड एस 24 के पैरा 18 के अंतर्गत सम्बद्ध पक्ष की जानकारी का खुलासा न करना।
		आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	टिप्पण बी-31 में सम्बद्ध पक्ष प्रकटीकरण इंड एस 24 का अनुपालन नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड, एलआईसी और एनएसडीएल (पैरा 18) के साथ संबंधों की प्रकृति निर्दिष्ट नहीं की गई है और पैरा 17 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के मुआवजे का खुलासा करने में विफल रहे हैं।
		नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	कंपनी ने केवल प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ योग लेनदेन का खुलासा किया है, जिसमें इंड एस 24 के पैरा 17 के अंतर्गत आवश्यक मुआवजे का विस्तृत विवरण सम्मिलित नहीं है, और परिवर्तनीय वेतन घटक के लंबित अंतिम रूप देने का पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप अननुपालन और वित्तीय विवरणों के टिप्पण में कमी आई है।
इंड एस 37	प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्तियां	औरंगाबाद टेक्सटाइल्स एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	अतिक्रमण और मुकदमेबाजी के अधीन भूमि के लिए देय संपत्ति और अन्य करों से संबंधित देनदारियों का खुलासा न करना।
		भारतीय शिपिंग निगम लिमिटेड	आकस्मिक संपत्तियों के विवरण, प्रकृति आदि का खुलासा न करना।
इंड एस 38	अमूर्त संपत्ति	बीपीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड	कंपनी ने आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया है, और इसलिए अवशिष्ट मूल्य घटाने के बाद अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन इंड एस 38 के अनुसार नहीं है।
		केआईओसीएल लिमिटेड	खनन अधिकारों के लिए किए गए व्यय को अमूर्त संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया गया था; हालाँकि, इंड एस 38 के पैरा 8-17 और 21-23 में निर्धारित मान्यता मानदंड पूरे नहीं किए गए थे, जिससे ऐसा पूंजीकरण अनुपयुक्त हो गया।

लेखांकन मानक/ इंड एस	विवरण	सीपीएसई का नाम	विचलन
इंड एस 40	निवेश संपत्ति	मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	विधान भवन में स्थित फ्रीहोल्ड भूमि, जिसका भविष्य में अनिश्चित उपयोग के लिए स्वामित्व था, को इंड एस 40 के अनुसार निवेश संपत्ति के बजाय पीपीई के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उचित मूल्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं हुआ।
इंड एस 110	समेकित वित्तीय विवरण	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	समेकित वित्तीय विवरणों में परिचालन राजस्व मद के अंतर्गत ₹4.30 करोड़ की लाभांश आय को सम्मिलित न करना।
इंड एस 113	उचित मूल्य माप	महाराष्ट्र मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	कंपनी ने ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋणों का उचित मूल्यांकन नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप उचित मूल्य मापन पर अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीति और इंड एस 113 का अनुपालन नहीं हुआ है, जिसके अनुसार वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।
इंड एस 116	पट्टे	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	पट्टे की राशि को अप्राप्त राजस्व के रूप में दिखाने के बजाय अन्य आय के रूप में दर्ज किया गया।

2.7 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक यह है कि वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से प्राप्त लेखापरीक्षा मामलों पर लेखापरीक्षक और निगमित इकाई के शासन की जिम्मेदारी संभालने वालों के बीच संचार स्थापित किया जाए।

सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत टिप्पणियों के रूप में दर्ज की गईं। इन टिप्पणियों के अलावा, सीएजी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में पाई गई अनियमितताओं या कमियों के बारे में भी प्रबंधन को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से सूचित किया गया। ये कमियां आम तौर पर निम्नलिखित से संबंधित थीं:

- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का अनुप्रयोग और व्याख्या,
- लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से उत्पन्न समायोजन जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और
- कुछ अपर्याप्त जानकारीयां या अप्रकटीकरण, जिनके संबंध में संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वित्तीय विवरणों की समीक्षा के दौरान, सीएजी ने 304 सीपीएसई को 'प्रबंधन पत्र' जारी किए **अनुलग्नक XIV**

जारी किए गए प्रबंधन पत्रों के आधार पर, सीपीएसई के प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों को **अनुलग्नक XV** में उजागर किया गया है।

अध्याय III

कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रणाली

अध्याय III

कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रणाली

3.1 परिचय

कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं का अनुप्रकुल, कानूनों का अक्षरशः और मूल भावना के अनुरूप अनुपालन और सभी हितधारकों के सतत विकास के लिए धन के प्रभावी प्रबंधन और वितरण तथा सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए नैतिक मानकों का पालन है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (भारत के सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत कई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) और सांविधिक निगम आते हैं, जिनके शेयर और/या बांड/डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। सीपीएसई को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की सरकार की नीति के संदर्भ में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का महत्व बढ़ गया है। महारत्न योजना के अंतर्गत, सीपीएसई से अपने परिचालन का विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर दिग्गज बनने की अपेक्षा की जाती है, जिसके लिए प्रभावी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनिवार्य हो गया है।

3.1.1 कॉर्पोरेट गवर्नेंस को नियंत्रित करने वाले प्रावधान

भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी पहलों के लिए कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) प्रमुख नियामक संस्थाएं हैं। सेबी भारत में सूचीबद्ध कंपनियों/सांविधिक निगमों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निगरानी और विनियम करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित नियामक प्रावधान मुख्य रूप से निम्नलिखित के अंतर्गत आते हैं: कंपनी अधिनियम 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और विनियम सेबी (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीबद्धता) 2021 और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित। जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

3.1.1.1 कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान

कंपनी अधिनियम, 2013, 29 अगस्त 2013 को लागू किया गया, जिसने कंपनी अधिनियम, 1956 का स्थान लिया। इसके अतिरिक्त, कंपनी मामलों के मंत्रालय ने प्रबंधन और प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता, बोर्ड की बैठकों और उसकी शक्तियों से संबंधित कंपनी नियम, 2014 को अधिसूचित (31 मार्च 2014) भी किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी नियम मिलकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं। इन नियमों में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यताएं, साथ ही पेशेवर आचरण के लिए कर्तव्य और दिशानिर्देश (धारा 149 (6) और (8) और अनुसूची IV) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाए।
- सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति {धारा 149(1)}।
- लेखापरीक्षा समिति {धारा 177(1)}, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति {धारा 178(1)}, तथा हितधारक संबंध समिति {धारा 178(5)} जैसी कुछ समितियों का अनिवार्य गठन।
- निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें प्रति वर्ष इस प्रकार आयोजित की जानी चाहिए कि दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो {धारा 173(1)}।

3.1.1.2 भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015

सेबी ने (2 सितंबर 2015 को) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 अधिसूचित किया, जो 1 दिसंबर 2015 से प्रभावी हुआ। मार्च 2024 तक, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (संशोधन) विनियम, 2021 (अंतिम संशोधन सितंबर 2023 में) अधिसूचित किया गया था, जिसे इस रिपोर्ट के लिए लिया गया है।

सेबी के दिशानिर्देश, विनियम 16 से 27 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार, शेयर और गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ दोनों के लिए सीपीएसई में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रथाओं को संस्थागत रूप देने में सहायक हैं और विनियम 50 से 62 में निर्दिष्ट अन्य प्रासंगिक तथा संशोधित प्रावधान केवल गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों³⁶ पर लागू होते हैं।

3.1.1.3 सेबी (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गमन एवं सूचीबद्धता) विनियम, 2021

यह विनियम 16 अगस्त, 2021 से प्रभावी है और यह किसी संस्था को गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के लिए निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार सीपीएसई में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थापित करने में सक्षम बनाता है।

3.1.1.4 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने नवंबर 1992 में निदेशक मंडल में गैर- आधिकारिक निदेशकों को सम्मिलित करने के संबंध में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश जारी किए। डीपीई ने नवंबर 2001 में निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों को सम्मिलित करने के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए। सीपीएसई के संचालन में अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए, केंद्र सरकार ने (जून 2007 में) सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश प्रस्तुत किए, जिन्हें मई 2010 में संशोधित और

³⁶ परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का अर्थ है ऋण प्रतिभूतियाँ, परिवर्तनीय प्रतिदेय अधिमन्य शेयर, स्थायी गैर-संचयी अधिमन्य शेयर, स्थायी ऋण साधन और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य प्रतिभूतियाँ। इसके अतिरिक्त, विनियम 16 से 27 31 मार्च, 2024 तक 'अनुपालन करें या स्पष्टीकरण दें' के आधार पर लागू हैं और उसके बाद उच्च मूल्य वाले ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए अनिवार्य हैं। अतः, चूंकि विनियम 16 से 27 उच्च मूल्य वाले ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए अनिवार्य नहीं हैं, इसलिए परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए विनियम 16 से 27 के अनुपालन पर विचार नहीं किया गया है।

पुनः जारी किया गया और सभी सीपीएसई पर अनिवार्य रूप से लागू किया गया। डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निदेशक मंडल की संरचना, लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति जैसी बोर्ड समितियों की संरचना और कार्य, सहायक कंपनियों का विवरण, खुलासे, रिपोर्ट और कार्यान्वयन की समय-सारणी जैसे क्षेत्र सम्मिलित थे। इस अध्याय में डीपीई दिशानिर्देशों के सभी संदर्भ मई 2010 में जारी डीपीई दिशानिर्देशों को संदर्भित करते हैं, जो सभी सीपीएसई के लिए अनिवार्य हैं। डीपीई ने सभी सीपीएसई के समझौता ज्ञापन (एमओयू) में 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस' को एक निष्पादन मानदंड के रूप में सम्मिलित किया है।

इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के साथ मिलकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक सक्षम ढांचा प्रदान करता है।

3.1.2. स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयरों, बांडों और डिबेंचरों वाली सूचीबद्ध सीपीएसई और सांविधिक निगमों द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा।

31 मार्च 2024 तक, विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कुल 757 सीपीएसई (सात सांविधिक निगमों सहित) जो भारत के सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत थे, जिनमें से 66 सीपीएसई³⁷, जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं (*अनुलग्नक XVI*) और 36 सीपीएसई/सांविधिक निगम³⁸ जिन बांडों/डिबेंचरों को 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया गया था (*अनुलग्नक XVII*), उनकी लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त में से, 22 सीपीएसई जिनके शेयर और बांड/डिबेंचर दोनों स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, जैसा कि *अनुलग्नक XVIII* में दिया गया है।

31 मार्च, 2024 तक विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध शेयरों (शेयर और बॉन्ड दोनों) वाले सीपीएसई द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के अनुपालन में पाई गई समस्याओं को मूल्यांकन रूपरेखा के भाग क में दर्शाया गया है और 31 मार्च, 2024 तक विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध बॉन्ड/डिबेंचर वाले सीपीएसई/सांविधिक निगमों को मूल्यांकन रूपरेखा के भाग ख में दर्शाया गया है।

भाग क

सीपीएसई जिनके शेयर/शेयर और बॉन्ड दोनों 31 मार्च 2024 तक स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं।

3.2 निदेशक मंडल

3.2.1 बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक

बोर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (ए) में यह निर्धारित किया गया है कि सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए,

³⁷ 66 सूचीबद्ध सीपीएसई में से एक कंपनी (भारत इन्स्यूलोलाजिकल्स एंड बायोलाजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंधन ने आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है।

³⁸ इसमें एनएचएआई, आईडब्ल्यूआई, एफसीआई और एनसीडीसी नामक चार सांविधिक निगम शामिल हैं, जिनके बांड स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

जिसमें निदेशक मंडल के कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य गैर-कार्यकारी निदेशक हों। निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.1 में सूचीबद्ध सीपीएसई में गैर-कार्यकारी निदेशकों की अपेक्षित संख्या (बोर्ड की कुल संख्या का कम से कम 50 प्रतिशत) नहीं थी।

तालिका 3.1: सीपीएसई जहाँ गैर-कार्यकारी निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं है

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	बोर्ड में निदेशकों की संख्या	बोर्ड में कार्यकारी निदेशकों की संख्या	गैर-कार्यकारी निदेशकों की न्यूनतम संख्या	गैर-कार्यकारी निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	कमी की अवधि दौरान वर्ष 2023-24
1.	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	7	5	5	2	3 (60)	जून से अक्टूबर तक
		8	5	5	3	2 (40)	नवंबर से मार्च तक
2.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	5	3	3	2	1 (33)	अप्रैल, मई, फरवरी और मार्च
		6	4	4	2	2 (50)	जून से जनवरी तक
3.	ऑयल इंडिया लिमिटेड	8	5	5	3	2 (40)	जून से मार्च तक
4.	एमएमटीसी लिमिटेड	7	4	4	3	1 (25)	अप्रैल और मई
5.	रेल विकास निगम लिमिटेड	8	5	5	3	2 (40)	अप्रैल से सितंबर, नवंबर, फरवरी और मार्च
		9	5	5	4	1 (20)	अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी
6.	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	7	4	4	3	1 (25)	मई से जून तक
7.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	7	4	4	3	1 (25)	जुलाई से मार्च तक

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा जा सकता है, सूचीबद्ध 65 सीपीएसई में से सात (11 प्रतिशत) में गैर-कार्यकारी निदेशकों की अपेक्षित संख्या बोर्ड में नहीं थी। यह कमी 20 से 60 प्रतिशत के बीच थी।

3.2.2 स्वतंत्र निदेशक

प्रबंधन के निर्णयों पर स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने में सक्षम स्वतंत्र प्रतिनिधियों की बोर्ड में उपस्थिति को शेयरधारकों के हितों की रक्षा का एक साधन माना जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4), कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (ख) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के अनुसार, यदि बोर्ड का अध्यक्ष गैर-कार्यकारी निदेशक है, तो बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और यदि अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक है, तो बोर्ड के कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। बशर्ते कि यदि नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई का प्रवर्तक है या किसी प्रवर्तक से संबंधित है या निदेशक मंडल स्तर पर या उससे एक स्तर नीचे प्रबंधन पद पर आसीन व्यक्ति है, तो सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल के कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 16(1)(ख) के अनुसार, 'स्वतंत्र निदेशक' से तात्पर्य सूचीबद्ध इकाई के नामित निदेशक के अलावा किसी गैर-कार्यकारी निदेशक से है।

निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा से पता चला कि सूचीबद्ध 65 सीपीएसई में से 49 (75 प्रतिशत) (**अनुलग्नक XIX**) में वर्ष 2023-24 की पूरी/आंशिक अवधि के दौरान निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक मौजूद नहीं थे। यह कमी 13 से 100 प्रतिशत के बीच थी। इसके अतिरिक्त, यह कमी एक से बारह माह तक की अवधि तक रही।

3.2.3 महिला निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 149 (1), कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के अध्याय 11 के नियम 3 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (क) के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए। सेबी विनियम, 2015 में यह भी प्रावधान है कि शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए। निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.2 और 3.3 में सूचीबद्ध सीपीएसई के निदेशक मंडल में कोई महिला निदेशक नहीं थी।

तालिका 3.2: वर्ष 2023-24 के दौरान सूचीबद्ध सीपीएसई जिनके बोर्ड में महिला निदेशक नहीं थीं

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	अनुपालन न करने की अवधि
1.	आईएफसीआई लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
2.	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
3.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	अनुपालन न करने की अवधि
4.	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	फरवरी से मार्च तक
5.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
6.	बीईएमएल लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
7.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, 65 सीपीएसई में से सात (11 प्रतिशत) में 2023-24 के दौरान बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।

तालिका 3.3: शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध सीपीएसई जिनमें उनके बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	अनुपालन न करने की अवधि
1.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
2.	कोल इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
3.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
4.	एचएमटी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
5.	एनएमडीसी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
6.	आईएफसीआई लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
7.	एमएमटीसी लिमिटेड	अप्रैल से मई तक
8.	रेल विकास निगम लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
9.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
10.	भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
11.	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	जुलाई से मार्च तक
12.	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	फरवरी से मार्च तक
13.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
14.	बीईएमएल लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
15.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
16.	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध संस्थाओं में से 60 सीपीएसई में से 16 (25 प्रतिशत) में, 2023-24 के दौरान बोर्ड में कोई महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी।

3.2.4 बोर्ड में निदेशकों की न्यूनतम संख्या

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1)(सी) के अनुसार, शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल में कम से कम छः निदेशक होने चाहिए। निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.4 में सूचीबद्ध सीपीएसई के निदेशक मंडल में वर्ष 2023-24 की पूरी/आंशिक अवधि के दौरान अपेक्षित संख्या में निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.4: शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध संस्थाओं में सम्मिलित सीपीएसई, जिनके बोर्ड में छः से कम निदेशक थे

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	अनुपालन न करने की अवधि
1.	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
2.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	अप्रैल से मई और फरवरी से मार्च
3.	एचएमटी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
4.	भारत पर्यटन विकास निगम	जुलाई से सितंबर तक
5.	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	नवंबर से जनवरी तक

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध संस्थाओं में सम्मिलित 62 सीपीएसई में से पांच (आठ प्रतिशत) में बोर्ड में छः से कम निदेशक थे।

3.2.5 निदेशक मंडल की बैठकों में कोरम

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियम 17 (2) (2ए) के अनुसार, शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में कोरम की आवश्यकता उसकी कुल संख्या का एक तिहाई या तीन निदेशक, जो भी अधिक हो, होनी चाहिए, जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित होना चाहिए। हालांकि, तालिका 3.5 में दर्शाई गई सीपीएसई के संबंध में बोर्ड की बैठकों में अपर्याप्त कोरम पाया गया।

तालिका 3.5: शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध संस्थाओं में सम्मिलित सीपीएसई जिनके बोर्ड की बैठकों में अपर्याप्त कोरम था।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें स्वतंत्र निदेशक अनुपस्थित थे	कमी (प्रतिशत)
1.	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	4	4	100
2.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	5	5	100
3.	एचएमटी लिमिटेड	6	6	100
4.	आईएफसीआई लिमिटेड	6	1	17

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा जा सकता है, 62 सीपीएसई में से चार (छ: प्रतिशत) में बोर्ड की बैठक के लिए आवश्यक कोरम पूरा नहीं हुआ। कोरम की कमी का प्रतिशत 17 से 100 प्रतिशत के बीच था।

3.2.6 स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के नियम 25 (7) के अनुसार, कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी/उद्योग की गतिविधियों, उनकी भूमिकाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों तथा अन्य प्रासंगिक जानकारी से परिचित कराना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 की अनुसूची V सी(2) (जी) में यह प्रावधान है कि वार्षिक रिपोर्ट में एक वेब लिंक उपलब्ध कराया जाए, जिसमें स्वतंत्र निदेशकों के लिए आयोजित परिचयात्मक कार्यक्रम का विवरण दिया गया हो।

हालांकि, एक सीपीएसई (ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) के संबंध में, जहां स्वतंत्र निदेशकों के लिए ऐसा कोई परिचय कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था और एक सीपीएसई (भारत पर्यटन विकास निगम) के संबंध में, स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम का विवरण उसकी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट नहीं किया गया था।

3.3 निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें

3.3.1 निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों की बैठक में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (III) (3) में कहा गया है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल और उस समिति की सभी बैठकों में उपस्थित रहने का प्रयास करना चाहिए जिसके वे सदस्य हैं। हालांकि, कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने इनमें से कुछ बैठकों में भाग नहीं लिया। तालिका 3.6 ऐसे स्वतंत्र निदेशकों की संख्या दर्शाती है जिन्होंने निदेशक मंडल और समिति की कम से कम 80 प्रतिशत बैठकों में भाग नहीं लिया, जिनके वे सदस्य थे।

तालिका 3.6: सीपीएसई जहां एक या अधिक स्वतंत्र निदेशकों ने बोर्ड/समिति की बैठकों में कम से कम 80 प्रतिशत में भाग नहीं लिया।

क्रम संख्या	सीपीएसई के नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
1.	भारतीय साधारण बीमा निगम	2
2.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, 65 सीपीएसई में से दो (तीन प्रतिशत) में, स्वतंत्र निदेशकों ने बोर्ड और समितियों की कम से कम 80 प्रतिशत बैठकों में भाग नहीं लिया, जिनमें वे सदस्य थे।

3.3.2 कंपनी की आम बैठकों में भाग लेना

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (III) (5) में कहा गया है कि स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी की सभी आम बैठकों में उपस्थित रहने का प्रयास करना चाहिए। तालिका 3.7 में उन सूचीबद्ध सीपीएसई (कंपनी विकास उपक्रम) को दर्शाया गया है जिनके एक या अधिक स्वतंत्र निदेशक आम बैठकों में उपस्थित नहीं हुए।

तालिका 3.7: वे सीपीएसई जहां एक या अधिक स्वतंत्र निदेशकों ने आम बैठकों में भाग नहीं लिया

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड
3.	एचएमटी लिमिटेड
4.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5.	एमएमटीसी लिमिटेड
6.	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, 65 सीपीएसई में से छः (नौ प्रतिशत) में, एक या अधिक स्वतंत्र निदेशक आम बैठक में उपस्थित नहीं थे।

3.3.3 कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियम 25 (3) के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई के स्वतंत्र निदेशकों को वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बैठक गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की अनुपस्थिति में आयोजित करनी होगी और सभी स्वतंत्र निदेशकों को ऐसी बैठक में उपस्थित रहने का प्रयास करना होगा। तालिका 3.8 उन सीपीएसई को दर्शाती है जिनके स्वतंत्र निदेशकों ने वर्ष 2023-24 के दौरान ऐसी कम से कम एक बैठक आयोजित नहीं की है। इसके अतिरिक्त, तालिका 3.9 उन सीपीएसई को दर्शाती है जहां सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठकों में उपस्थित नहीं थे।

तालिका 3.8: सीपीएसई जिनके स्वतंत्र निदेशकों ने वर्ष 2023-24 के दौरान गैर-स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति के बिना कम-से-कम एक बैठक आयोजित नहीं की।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1.	मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
2.	आईएफसीआई लिमिटेड

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, 65 सीपीएसई में से दो (तीन प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों ने कम से कम एक बैठक नहीं की।

तालिका 3.9: सीपीएसई जहां गैर-स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में बैठकों में सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित नहीं थे।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1.	हेमीस्फीयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
2.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, 65 सीपीएसई में से दो (तीन प्रतिशत) में, सभी स्वतंत्र निदेशक उस बैठक में उपस्थित नहीं थे जिसमें विशेष रूप से केवल स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति अनिवार्य थी।

3.3.4 निदेशक मंडल की बैठकें

3.3.4.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(3) में यह प्रावधान है कि निदेशक मंडल की बैठकें कम से कम सात दिन पहले लिखित सूचना देकर बुलाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, अत्यावश्यक कार्य निपटाने के लिए कम समय की सूचना पर भी निदेशक मंडल की बैठक बुलाई जा सकती है, बशर्ते कि बैठक में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक (यदि कोई हो) उपस्थित हो। इसके अतिरिक्त, यदि निदेशक मंडल की ऐसी बैठक में स्वतंत्र निदेशक अनुपस्थित हों, तो बैठक में लिए गए निर्णय सभी निदेशकों को सूचित किए जाएंगे और कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक (यदि कोई हो) द्वारा पुष्टि किए जाने पर ही अंतिम माने जाएंगे। तालिका 3.10 में उन बैठकों की संख्या दर्शाई गई है जिनमें कम से कम सात दिन पहले सूचना नहीं दी गई थी।

तालिका: 3.10: सीपीएसई जहां कम से कम सात दिन का नोटिस दिए बिना बोर्ड की बैठक बुलाई गई

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	बोर्ड की बैठकों की कुल संख्या	कम से कम 7 दिन का नोटिस दिए बिना बुलाई गई बैठकों की संख्या।	बैठक बुलाने के लिए 7 दिन से कम का नोटिस देने पर होने वाली कमी का प्रतिशत।
1.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	5	1	20
2.	एचएमटी लिमिटेड	6	1	17
3.	एमओआईएल लिमिटेड	7	2	29

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, 65 सीपीएसई में से तीन (पांच प्रतिशत) में निदेशक मंडल की बैठकों (एक या अधिक) के लिए कम से कम सात दिनों की अवधि के लिए नोटिस नहीं दिए गए थे और अन्य शर्तें पूरी नहीं की गई थीं।

3.3.4.2 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 17(7) की अनुसूची II के भाग क में यह प्रावधान है कि संस्था के संचालन की समीक्षा के लिए निदेशक मंडल द्वारा आवश्यक जानकारी का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। उपरोक्त विनियम के अनुसार, तालिका 3.11 में दर्शाई गई सीपीएसई के संबंध में निदेशक मंडल को जानकारी प्रदान नहीं की गई थी।

तालिका 3.11: वे सीपीएसई जिनके बारे में निदेशक मंडल को विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं की गई थी

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	बोर्ड को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई
1.	ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नियामक, सांविधिक या सूचीबद्धता संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन न करना और शेयरधारकों को दी जाने वाली सेवाओं का उल्लंघन करना, जैसे लाभांश का भुगतान न करना, शेयर हस्तांतरण में विलंब आदि।
2.	भारत पर्यटन विकास निगम	जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक का कार्यवृत्त
3.	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	वार्षिक परिचालन योजनाएँ और बजट तथा अन्य घटित होने वाली अद्यतन घटनाएँ विदेशी मुद्रा के जोखिम का त्रैमासिक विवरण और विनिमय दर में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम, यदि महत्वपूर्ण हों।

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, 65 सीपीएसई में से तीन (पांच प्रतिशत) में निदेशक मंडल को विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं की गई थी।

3.3.4.3 विनियम 46 2(सी) में यह प्रावधान है कि सूचीबद्ध कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की संरचना का खुलासा करना होगा। हालांकि, एक सीपीएसई (एनएमडीसी स्टील लिमिटेड) के संबंध में, निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की संरचना का खुलासा वेबसाइट पर नहीं किया गया है।

3.4 रिक्त पदों को भरने में अंतराल

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 (4) के अनुसार, यदि किसी पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पद रिक्त हो जाता है, तो उस रिक्ति को रिक्ति की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर बोर्ड द्वारा भरा जाना अनिवार्य है। हालांकि, तालिका 3.12 में सूचीबद्ध सीपीएसई में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की रिक्ति को रिक्ति की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर बोर्ड द्वारा नहीं भरा गया है।

तालिका 3.12: वे सीपीएसई जहां बोर्ड द्वारा छः माह के भीतर पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के रिक्त पद नहीं भरे गए।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	छः माह से अधिक के विलंब की अवधि (माह में)
1.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	12
2.	केआईओसीएल लिमिटेड	9
3.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	6
4.	एनएमडीसी लिमिटेड	37
5.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	5

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	छः माह से अधिक के विलंब की अवधि (माह में)
6.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6
7.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5
8.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	21
9.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	7
10.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	6
11.	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	8
12.	एचएमटी लिमिटेड	26

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा जा सकता है, 65 सीपीएसई में से 12 (18 प्रतिशत) में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय पदों की रिक्ति रिक्ति की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर नहीं भरी गई। यह विलंब निर्धारित समय सीमा से पांच माह से लेकर 37 माह तक का था।

3.5 विविध

3.5.1 अनुसूची V के भाग सी (6) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) के अनुसार, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित की जाने वाली कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट में निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में निम्नलिखित खुलासे सम्मिलित होने चाहिए: (i) सूचीबद्ध इकाई के संबंध में गैर-कार्यकारी निदेशकों के सभी वित्तीय लेनदेन, (ii) गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड, (iii) व्यक्तिगत निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज के सभी तत्व, जैसे वेतन, लाभ, बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन आदि, (iv) निश्चित घटक और निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों का विवरण, साथ ही निष्पादन मानदंड, (v) सेवा अनुलग्नक, नोटिस अवधि, सेवा समाप्ति शुल्क, और (vi) स्टॉक विकल्प विवरण - छूट, अवधि आदि। हालांकि, एक सीपीएसई (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया

3.5.2 डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 8.3 में यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। हालांकि, तालिका 3.13 में विस्तृत विवरण के अनुसार, 65 सीपीएसई में से दो (तीन प्रतिशत) ने इसका अनुपालन नहीं किया।

तालिका 3.13: वे सीपीएसई जिन्होंने 15 दिनों के भीतर प्रशासनिक मंत्रालय को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1.	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2.	हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड

3.5.3 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V के भाग सी (2) (एच) में यह निर्धारित किया गया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में एक चार्ट या मैट्रिक्स होना चाहिए जो निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता को निर्दिष्ट करे, जैसा कि उसके व्यवसाय (व्यवसायों) और क्षेत्र (क्षेत्रों) के संदर्भ में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक है। हालांकि, जैसा कि नीचे दी गई तालिका 3.14 में विस्तार से बताया गया है, सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया था।

तालिका 3.14: वे सीपीएसई जिनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की सूची निर्दिष्ट करने वाला चार्ट/मैट्रिक्स सम्मिलित नहीं था।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1.	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
2.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
3.	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
4.	भारत पर्यटन विकास निगम
5.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
7.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
8.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, 65 सीपीएसई में से आठ (12 प्रतिशत) में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता को दर्शाने वाला चार्ट/मैट्रिक्स सम्मिलित नहीं था, जैसा कि अपेक्षित था।

3.5.4 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची v के भाग सी (2) (जे) में यह प्रावधान है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में स्वतंत्र निदेशक द्वारा अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा देने के विस्तृत कारण और साथ ही निदेशक द्वारा इस बात की पुष्टि सम्मिलित होनी चाहिए कि बताए गए कारणों के अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण कारण नहीं हैं। हालांकि, तालिका 3.15 में विस्तृत रूप से दर्शाए गए अनुसार, सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

तालिका 3.15: वे सीपीएसई जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में स्वतंत्र निदेशक के इस्तीफे के कारणों का उल्लेख नहीं है

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	इस्तीफा देने वाले निदेशकों की संख्या
1.	एमएमटीसी लिमिटेड	1
2.	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	1

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, 65 सीपीएसई में से दो (तीन प्रतिशत) में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में स्वतंत्र निदेशक के इस्तीफे के कारणों का उल्लेख नहीं था।

3.6 लेखापरीक्षा समिति

3.6.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और सेबी (दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 18 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

3.6.1.1 प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई को एक योग्य और स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति का गठन करना होगा। हालांकि, एक सीपीएसई (एनएमडीसी स्टील लिमिटेड) के संबंध में लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था।

3.6.1.2 लेखापरीक्षा समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। हालांकि, तालिका 3.16 में विस्तृत रूप से वर्णित सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया था।

तालिका 3.16: वे सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की कुल संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)
1.	एचएमटी लिमिटेड	3	2	0	2 (100)
2.	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	3	2	0	2 (100)
3.	आईएफसीआई लिमिटेड	4	3	1	2 (67)
4.	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	3	2	1	1 (50)

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा जा सकता है, 65 सीपीएसई में से चार (छ: प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। यह कमी 50 से 100 प्रतिशत तक थी।

3.6.1.3 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे। हालांकि, तालिका 3.17 में विस्तृत रूप से वर्णित सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया था।

तालिका 3.17: वे सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1.	एचएमटी लिमिटेड
2.	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, 65 सीपीएसई में से दो (तीन प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

3.6.2 लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की वित्तीय साक्षरता:

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18 (1) (सी) एस में यह निर्धारित किया गया है कि लेखापरीक्षा समिति के सभी सदस्य वित्तीय रूप से साक्षर होने चाहिए और कम से कम एक सदस्य के पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता होनी चाहिए। हालांकि, तालिका 3.18 में विस्तृत रूप से दर्शाए गए अनुसार, सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया था।

तालिका 3.18: वे सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति की वित्तीय साक्षरता से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1.	राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
2.	बाल्मर लॉरी और कंपनी लिमिटेड
3.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, 65 सीपीएसई में से तीन (पांच प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति की वित्तीय साक्षरता से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं किया गया था।

3.6.3 लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए आवश्यक कोरम

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18(2)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.4 में लेखापरीक्षा कमेटी की बैठकों के लिए कोरम की आवश्यकता निर्धारित की गई है (अर्थात्, कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों के साथ लेखापरीक्षा कमेटी के दो सदस्य या एक तिहाई सदस्य, जो भी अधिक हो)। तालिका 3.19 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा कमेटी की बैठकों में अपर्याप्त कोरम था।

तालिका 3.19: लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए अपूर्ण कोरम वाले सीपीएसई

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	अपूर्ण कोरम वाली बैठकों की संख्या	अपूर्ण कोरम वाली बैठकों का प्रतिशत
1.	एचएमटी लिमिटेड	6	6	100
2.	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	4	4	100
3.	आईएफसीआई लिमिटेड	6	6	100
4.	एमएमटीसी लिमिटेड	4	1	25
5.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	5	2	40

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, 65 सीपीएसई में से पांच (आठ प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कोरम अपर्याप्त था।

3.6.4. लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचनाओं/दस्तावेजों की समीक्षा:

3.6.4.1 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियम 18(3) और अनुसूची II के भाग सी (ए) में यह निर्धारित है कि लेखापरीक्षा कमेटी को इन विनियमों में बताए गए कुछ मामलों की समीक्षा करनी होगी। हालांकि, लेखापरीक्षा कमेटी ने सीपीएसई के संबंध में इनमें से एक या अधिक मामलों की समीक्षा नहीं की, जैसा कि तालिका 3.20 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.20: वे सीपीएसई जहां आवश्यक जानकारी लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा नहीं की गई

क्रम संख्या	सेबी विनियमन	समीक्षा की जाने वाली जानकारी	सीपीएसई का नाम
1.	विनियम 18(3) की अनुसूची II के भाग सी(ए) (4बी)	कंपनी की लेखांकन नीतियों में यदि कोई परिवर्तन प्रस्तावित हो तो उसकी समीक्षा करें।	1. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
2.	विनियम 18(3) की अनुसूची II के भाग सी (ए) (7)	लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और निष्पादन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।	1. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
3.	विनियम 18(3) की अनुसूची II के भाग सी(ए) (10)	सूचीबद्ध इकाई के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करें।	1. केआईओसीएल लिमिटेड 2. एचएमटी लिमिटेड
4.	विनियम 18(3) की अनुसूची II के भाग सी(ए) (11)	आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन	1. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
5.	विनियम 18(3) की अनुसूची II के भाग सी(ए) (12)	प्रबंधन के साथ मिलकर सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करें।	1. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
6.	विनियम 18(3) की अनुसूची II के भाग सी(ए) (16)	लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में चर्चा करें।	1. एचएमटी लिमिटेड 2. हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड 3. कोल इंडिया लिमिटेड 4. भारतीय पर्यटन विकास निगम
7.	विनियम 18(3) की अनुसूची II के भाग सी(ए) (17)	जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न होने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में भारी चूक के कारणों की जांच करें।	1. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, एक से लेकर चार तक की संख्या वाले सीपीएसई में लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवश्यक जानकारी की समीक्षा नहीं की गई थी।

3.6.4.2 सेबी (दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 18 (3) की अनुसूची II के भाग सी (ए) (9) में यह प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जांच करनी होगी। हालांकि, एक सीपीएसई (द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड) के संबंध में लेखापरीक्षा समिति ने अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जांच नहीं की थी।

3.6.4.3 सेबी (दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग सी(ए) (19) में यह प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति को स्वीकृति देगी। हालांकि, दो सीपीएसई (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड) के मामले में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

3.7 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष की वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18(1)(डी) में यह प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा और वह शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक आम बैठक में उपस्थित रहेगा। हालांकि, दो सीपीएसई (हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एमएमटीसी लिमिटेड) के मामले में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

3.8 सतर्कता तंत्र

सेबी (दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के 18(3) विनियम और अनुसूची II के भाग सी(ए)(18)(3) विनियमों में यह निर्धारित है कि लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में अन्य बातों के अलावा व्हिसलब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना भी सम्मिलित होगा। हालांकि, दो सीपीएसई (हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एमएमटीसी लिमिटेड) के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

3.9 सम्बद्ध पक्ष से लेनदेन

3.9.1 सेबी (दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 23(1) में यह प्रावधान है कि सूचीबद्ध इकाई को सम्बद्ध पक्ष लेनदेन की प्रासंगिकता और उनसे निपटने के संबंध में एक नीति बनानी होगी, जिसमें निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित स्पष्ट सीमाएं सम्मिलित होंगी। ऐसी नीति की समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा कम से कम तीन वर्ष में एक बार की जाएगी और उसे आवश्यकतानुसार अद्यतन किया जाएगा। हालांकि, एक सीपीएसई (केआईओसीएल लिमिटेड) के मामले में, इकाई ने सम्बद्ध पक्ष लेनदेन संबंधी नीति की समीक्षा नहीं की।

3.9.2 सेबी (दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 23(2) में यह निर्धारित किया गया है कि सभी सम्बद्ध पक्ष लेनदेन और बाद के महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए लेखापरीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। हालांकि, तालिका 3.21 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में, सम्बद्ध पक्ष लेनदेन के लिए लेखापरीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी।

**तालिका 3.21: वे सीपीएसई जहां सम्बद्ध पक्ष लेनदेन के लिए
लेखापरीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति नहीं थी**

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1.	एमओआईएल लिमिटेड
2.	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, 65 सीपीएसई में से दो (तीन प्रतिशत) में, सम्बद्ध पक्ष लेनदेन को लेखापरीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं थी।

3.9.3 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 23(9) में यह प्रावधान है कि सूचीबद्ध इकाई को अपने छमाही के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर, सम्बद्ध पक्ष लेनदेन का समेकित आधार पर प्रकटीकरण, वार्षिक परिणामों के लिए प्रासंगिक लेखा मानकों में निर्दिष्ट प्रारूप में, स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करना होगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा। हालांकि, तालिका 3.22 में विस्तृत सीपीएसई के संबंध में, स्टॉक एक्सचेंज को प्रकटीकरण किया गया था, लेकिन इसे वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया था।

तालिका 3.22: वे सीपीएसई जिन्होंने अपने पृथक तथा समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए गए प्रकटीकरण को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
2.	ट्रेजिंग कंपनीकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, 65 सीपीएसई में से दो (तीन प्रतिशत) में, स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत की गई जानकारी वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं की गई थी।

3.10 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

3.10.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1), कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 का नियम 6 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 19 (1) और (2) में यह प्रावधान है कि सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल को कम से कम तीन निदेशकों वाली एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करना होगा, जिनमें से सभी गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए और कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए तथा समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे। हालांकि, एक सीपीएसई (एनएमडीसी स्टील लिमिटेड) के संबंध में, 2023-24 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, यद्यपि नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था, लेकिन तालिका 3.23 में दर्शाए अनुसार सीपीएसई में तीन गैर-कार्यकारी निदेशकों और उनमें से आधे स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी।

तालिका 3.23: नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की अनुपयुक्त संरचना वाले सीपीएसई

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	अनुपालन न करने की अवधि
1.	एचएमटी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
2.	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
3.	आईएफसीआईलिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
4.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	नवंबर से मार्च तक
5.	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, 65 सीपीएसई में से पांच (आठ प्रतिशत) में नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना उपयुक्त नहीं थी।

3.10.2 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 19(2) और सीपीएसई पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के पैरा 5.1 में यह निर्धारित है कि नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे। हालांकि, तालिका 3.24 में विस्तृत सीपीएसई के संबंध में, 2023-24 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.24: वे सीपीएसई जहां नामांकन और पारिश्रमिक के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	अनुपालन न करने की अवधि
1.	एचएमटी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
2.	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
3.	आईएफसीआईलिमिटेड	अप्रैल से जुलाई तक

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, 65 सीपीएसई में से तीन (पांच प्रतिशत) में नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

3.10.3 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 19 (3) में यह प्रावधान है कि नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थित हो सकते हैं। हालांकि, दो सीपीएसई (एमएमटीसी लिमिटेड और बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड) के संबंध में अध्यक्ष वार्षिक आम बैठक में उपस्थित नहीं थे।

3.10.4 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियम 19 (4) और अनुसूची II के भाग डी (I) में यह प्रावधान है कि नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति निदेशकों, प्रमुख

प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की अनुशंसा निदेशक मंडल को करेगी। हालांकि, तालिका 3.25 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

तालिका 3.25: ऐसे सीपीएसई जहां वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति निदेशक मंडल को अनुशंसित नहीं किया गया।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1.	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
2.	भारत हेवीइलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, 65 सीपीएसई में से दो (तीन प्रतिशत) में, वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति को नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा निदेशक मंडल को अनुशंसित नहीं किया गया था।

3.10.5 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 19 (2ए) में यह निर्धारित किया गया है कि नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक के लिए कोरम में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति सहित, समिति के दो सदस्य या एक तिहाई सदस्य, जो भी अधिक हो, सम्मिलित होंगे। तालिका 3.26 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में अपर्याप्त कोरम था।

तालिका 3.26: नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों के लिए अपूर्ण कोरम वाले सीपीएसई

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1.	एचएमटी लिमिटेड
2.	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा गया है, 65 सीपीएसई में से दो (तीन प्रतिशत) में नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों के लिए कोरम अपर्याप्त था।

3.10.6 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) रेगुलेशन, 2015 के अनुसूची II भाग डी, ए (3) में यह निर्धारित किया गया है कि निदेशक मंडल में विविधता सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार की जाएगी। हालांकि, तालिका 3.27 में सूचीबद्ध 65 सीपीएसई में से 11 (17 प्रतिशत) के संबंध में निदेशक मंडल में विविधता सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार नहीं की गई थी।

तालिका 3.27: वे सीपीएसई जहां निदेशक मंडल में विविधता सुनिश्चित करने की नीति तैयार नहीं की गई

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1.	मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
2.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
3.	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
4.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड
5.	एचएमटी लिमिटेड
6.	एनएमडीसी लिमिटेड
7.	कोल इंडिया लिमिटेड
8.	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
9.	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
10.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड

3.11 हितधारक संबंध समिति

3.11.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (5) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 20 (1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को एक हितधारक संबंध समिति का गठन करना होगा। हालांकि, एक सीपीएसई (एनएमडीसी स्टील लिमिटेड) के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

3.11.2 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 20(2ए) में यह निर्धारित किया गया है कि हितधारक संबंध समिति में कम से कम तीन निदेशक होने चाहिए, जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक हो। हालांकि, 2023-24 के दौरान 65 सीपीएसई में से तीन (पांच प्रतिशत) के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया, जैसा कि तालिका 3.28 में विस्तार से बताया गया है।

तालिका 3.28: वे सीपीएसई जहां समिति की संरचना विनियम के अनुसार नहीं है

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	अनुपालन न करने की अवधि
1.	आईएफसीआई लिमिटेड	अप्रैल से जुलाई तक
2.	एचएमटी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
3.	बाल्मर लॉरीइन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक

3.11.3 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 20(3ए) में यह निर्धारित है कि समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होनी चाहिए। हालांकि, एक सीपीएसई (एमएमटीसी लिमिटेड) के मामले में इसका अनुपालन नहीं किया गया, जहां हितधारक संबंध समिति की बैठक एक बार भी नहीं हुई।

3.12 सहायक कंपनियाँ

3.12.1 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24(1) में यह प्रावधान है कि सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में भी निदेशक होना चाहिए। हालांकि, तालिका 3.29 में विस्तृत रूप से दर्शाए गए पांच सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया था।

तालिका 3.29: ऐसे सीपीएसई जहां सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक, असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में नहीं थे।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
2.	एचएमटी लिमिटेड
3.	कोल इंडिया लिमिटेड
4.	ऑयल इंडिया लिमिटेड
5.	आईएफसीआई लिमिटेड

3.12.2 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 46 (2) (एच) और अनुसूची V (सी) (10) (ई) में यह निर्धारित किया गया है कि सूचीबद्ध इकाई को महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए एक नीति तैयार करनी होगी। हालांकि, सीपीएसई (एमएमटीसी लिमिटेड) के मामले में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

3.13 जोखिम प्रबंधन समिति

3.13.1 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 21(1) के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य है। हालांकि, वर्ष 2023-24 के दौरान एकमात्र सीपीएसई (एनएमडीसी स्टील लिमिटेड) के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

3.13.2 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 21(2) में यह निर्धारित किया गया है कि जोखिम प्रबंधन समिति में कम से कम तीन सदस्य होंगे, जिनमें से अधिकांश निदेशक मंडल के सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित होगा। हालांकि, 2023-24 के दौरान 65 सीपीएसई में से दो (तीन प्रतिशत) के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया, जैसा कि तालिका 3.30 में विस्तार से बताया गया है।

तालिका 3.30: जोखिम प्रबंधन समिति की अनुपयुक्त संरचना वाले सीपीएसई

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	अनुपालन न करने की अवधि
1.	एचएमटी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक
2.	आईएफसीआई लिमिटेड	अप्रैल से जुलाई तक

3.13.3 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (9) (ए) और (बी) में यह प्रावधान है कि सूचीबद्ध इकाई को निदेशक मंडल के सदस्यों को जोखिम मूल्यांकन और जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करनी होंगी और निदेशक मंडल सूचीबद्ध इकाई के लिए जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करने, उसे लागू करने और उसकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि, एक सीपीएसई (हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड) के मामले में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

3.14 अनुपालन प्रमाण पत्र

3.14.1 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V(सी) (10)(के) में यह प्रावधान है कि सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक को समेकित आधार पर भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रकट किया जाना आवश्यक है। हालांकि, एक सीपीएसई (एमएमटीसी लिमिटेड) के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

3.14.2 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V(सी) (10) (I) में यह प्रावधान है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 से संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या, निपटाए गए शिकायतों की संख्या और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या का प्रकटीकरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में किया जाना आवश्यक है। हालांकि, एक सीपीएसई (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) के मामले में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

3.14.3 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V (ई) में यह प्रावधान है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षकों या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण पत्र वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। हालांकि, एक सीपीएसई (द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड) के मामले में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

3.14.4 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 38 में यह निर्धारित है कि सूचीबद्ध इकाई को प्रतिभूति अनुलग्नक (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19 (2) और नियम 19 (ए) में निर्दिष्ट न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। नियम 19 (ए) (3) में यह निर्धारित है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी

को कम से कम 10 प्रतिशत की सार्वजनिक शेयरधारिता बनाए रखनी होगी। हालांकि, एक सीपीएसई (केआईओसीएल लिमिटेड) के मामले में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

3.14.5 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 43(ए) के पैराग्राफ (I) में यह प्रावधान है कि बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध संस्थाओं को लाभांश वितरण नीति बनानी होगी, जिसका प्रकाशन सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट पर किया जाएगा और उनकी वार्षिक रिपोर्ट में एक वेब-लिंक भी प्रदान किया जाएगा। हालांकि, एक सीपीएसई (ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) के मामले में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

3.15 निष्कर्ष

इस अध्याय में सम्मिलित 65 सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में, यह पाया गया कि केवल छः सीपीएसई (9 प्रतिशत) यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इरेडा), पीएनबी गिल्ट लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने डीपीई/सेबी दिशानिर्देशों/विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी प्रासंगिक प्रावधानों में निर्धारित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया, जिनका लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण किया गया था। 65 सूचीबद्ध सीपीएसई में से, प्रमुख अननुपालन के मामले नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

- i. सात सीपीएसई (11 प्रतिशत) में गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या बोर्ड की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से कम थी और यह कमी 20 से 60 प्रतिशत के बीच थी;
- ii. 2023-24 के दौरान 49 सीपीएसई (75 प्रतिशत) में बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक मौजूद नहीं थे। कमी का प्रतिशत 13 से 100 प्रतिशत के बीच था।
- iii. सात सीपीएसई (11 प्रतिशत) के बोर्ड में महिला निदेशक नहीं थीं। इसके अतिरिक्त, शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध संस्थाओं में सम्मिलित 60 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 16 सीपीएसई (25 प्रतिशत) के बोर्ड में 2023-24 के दौरान महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थीं।
- iv. शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध संस्थाओं में सम्मिलित 62 सीपीएसई में से पांच (आठ प्रतिशत) में न्यूनतम छः निदेशकों का मानदंड पूरा नहीं किया गया था;
- v. शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध संस्थाओं में सम्मिलित 62 सीपीएसई में से चार (छः प्रतिशत) की बोर्ड बैठक में कोरम अपर्याप्त था;
- vi. एक सीपीएसई (दो प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था; एक सीपीएसई (दो प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम का विवरण उसकी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट नहीं किया गया था।
- vii. दो सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों ने बोर्ड और समितियों की कम से कम 80 प्रतिशत बैठकों में भाग नहीं लिया, जिनमें वे सदस्य थे; छः सीपीएसई (नौ प्रतिशत) में एक

या अधिक स्वतंत्र निदेशक आम बैठक में उपस्थित नहीं थे; दो सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों ने गैर-स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में कम से कम एक बैठक आयोजित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, दो सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में गैर-स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में आयोजित स्वतंत्र निदेशकों की बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित नहीं थे।

- viii. तीन सीपीएसई (पांच प्रतिशत) में, निदेशक मंडल की बैठकों के लिए सूचनासात दिनों से कम की अवधि के लिए दी गई थी।
- ix. तीन सीपीएसई (पांच प्रतिशत) में, निदेशक मंडल को विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं की गई थी।
- x. 12 सीपीएसई (18 प्रतिशत) में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के पद रिक्त होने की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर नहीं भरे गए;
- xi. दो सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में प्रत्येक तिमाही के अंत से 15 दिनों के भीतर त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं की गई थी;
- xii. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में आठ सीपीएसई (12 प्रतिशत) में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता को दर्शाने वाला कोई अपेक्षित चार्ट या मैट्रिक्स सम्मिलित नहीं था; कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दो सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में एक स्वतंत्र निदेशक के इस्तीफे के कारणों का उल्लेख नहीं था।
- xiii. एक सीपीएसई (दो प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था; चार सीपीएसई (छः प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे; दो सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे; तीन सीपीएसई (पांच प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति की वित्तीय साक्षरता से संबंधित विनियम का अनुपालन नहीं किया गया था; पांच सीपीएसई (आठ प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति की बैठक के लिए आवश्यक कोरम अपर्याप्त था।
- xiv. दो सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति ने मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति को स्वीकृति नहीं दी थी; चार सीपीएसई (आठ प्रतिशत) में लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले लेखापरीक्षा समिति ने सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे पर चर्चा नहीं की थी; एक सीपीएसई में लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन प्रणाली के मूल्यांकन की समीक्षा नहीं की थी।
- xv. दो सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने वार्षिक आम बैठक में भाग नहीं लिया; दो सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति द्वारा व्हिसल ब्लोअर तंत्र की समीक्षा नहीं की गई;
- xvi. दो सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में सम्बद्ध पक्ष लेनदेन के लिए लेखापरीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति नहीं थी; दो सीपीएसई (तीन प्रतिशत) के संबंध में, सम्बद्ध पक्ष लेनदेन का

प्रकटीकरण स्टॉक एक्सचेंज को उसके स्वतंत्र और समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर नहीं भेजा गया था;

- xvii. एक सीपीएसई (दो प्रतिशत) में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया; पांच सीपीएसई (आठ प्रतिशत) में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना उपयुक्त नहीं थी; तीन सीपीएसई (पांच प्रतिशत) में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे; दो सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष वार्षिक आम बैठक में उपस्थित नहीं थे; दो सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति निदेशक मंडल को अनुशंसित नहीं की गई थी; दो सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों के लिए कोरम पूरा नहीं था।
- xviii. 11 सीपीएसई (17 प्रतिशत) में निदेशक मंडल की विविधता सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार नहीं की गई थी;
- xix. एक सीपीएसई (दो प्रतिशत) में हितधारक संबंध समिति का गठन नहीं किया गया था; तीन सीपीएसई (पांच प्रतिशत) में हितधारक संबंध समिति की संरचना विनियम के अनुसार नहीं थी;
- xx. पांच सीपीएसई (आठ प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशक सहायक कंपनी के बोर्ड में निदेशक नहीं थे; एक सीपीएसई में अपनी वेबसाइट पर एक अलग अनुभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों को निर्धारित करने की नीति का प्रकटीकरण नहीं किया गया था।
- xxi. दो सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना उपयुक्त नहीं थी; एक सीपीएसई (दो प्रतिशत) में जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण प्रक्रियाएं और जोखिम प्रबंधन योजना निर्धारित नहीं की गई थी;
- xxii. एक सीपीएसई (दो प्रतिशत) में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षक को भुगतान की गई फीस से संबंधित विवरण का प्रकटीकरण नहीं किया गया था; एक सीपीएसई (दो प्रतिशत) में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण नहीं किया गया था।

भाग ख

सीपीएसई/ सांविधिक निगम जिनके बांड/ डिबेंचर 31 मार्च, 2024 को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं

3.16 परिचय

36 सीपीएसई³⁹ और भारत के सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सांविधिक निगम, जिनके बांड/डिबेंचर 31 मार्च, 2024 को भारत के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे। स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध बांड/डिबेंचर वाले सीपीएसई/सांविधिक निगमों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को नियंत्रित करने वाले प्रावधान मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देश, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और

³⁹ इसमें एनएचएआई, आईडब्ल्यूएआई, एनसीडीसी और एफसीआई सहित चार सांविधिक निगम शामिल हैं, जिनके बांड स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। निदेशक मंडल, समितियों आदि से संबंधित मुद्दों पर सांविधिक निगमों के लिए विचार नहीं किया जाता है।

प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सेबी (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीबद्धता) विनियम, 2021 के अंतर्गत आते हैं।

भारत के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध बॉन्ड/डिबेंचर वाली सीपीएसई और सांविधिक निगमों द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा से निम्नलिखित अननुपालन का पता चला।

3.17 स्टॉक एक्सचेंज को सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियम 50 (1) के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को बोर्ड की बैठकों के लिए स्टॉक एक्सचेंज को कम से कम दो कार्यदिवसों (सूचना और बैठक की तारीख को छोड़कर) की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है, जहां वित्तीय परिणामों जैसे कि त्रैमासिक या वार्षिक, गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के निर्गमन द्वारा धन जुटाने जैसे प्रस्तावों पर विचार किया जाना है।

तालिका 3.31 में सूचीबद्ध 36 सीपीएसई/सांविधिक निगमों में से दो (छ: प्रतिशत) ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 50 (1) में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को बैठकों के बारे में सूचित नहीं किया।

तालिका 3.31: निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को बैठकों की सूचना न देने वाले सीपीएसई/सांविधिक निगम

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1.	ओएनजीसीपेट्रो एडिशनल्स लिमिटेड
2.	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

3.18 वित्तीय परिणाम

3.18.1 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, विनियम 52(1) में यह निर्धारित किया गया है कि सूचीबद्ध इकाई को तिमाही आधार पर, बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में, अंतिम तिमाही को छोड़कर, तिमाही की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर, बिना लेखापरीक्षित या लेखापरीक्षित तिमाही और वर्ष-दर-वर्ष के स्वतंत्र वित्तीय परिणाम तैयार करके मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(ओं) को प्रस्तुत करने होंगे।

एक सांविधिक निगम (भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण) ने उपरोक्त नियम के अनुसार निर्धारित समय के भीतर वित्तीय परिणाम प्रस्तुत नहीं किए थे।

3.18.2 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 52(2) (डी) में यह निर्धारित किया गया है कि वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखापरीक्षित स्वतंत्र और समेकित वित्तीय परिणाम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ वित्तीय वर्ष की समाप्ति से साठ दिनों के भीतर

स्टॉक एक्सचेंज(ओं) को प्रस्तुत किए जाएंगे। बशर्ते कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए जा रहे जारीकर्ता वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के प्रकटीकरण के लिए निम्नलिखित दो-चरणीय प्रक्रिया अपनाएंगे:

(i) प्रथम स्तर की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी, जो सूचीबद्ध इकाई के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करेगा और ऐसे वित्तीय परिणाम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से साठ दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ii) सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा पूरा होने के बाद, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ माह के भीतर वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रस्तुत किए जाएंगे।

तालिका 3.32 में सूचीबद्ध 36 सीपीएसई/सांविधिक निगमों में से दो (छ: प्रतिशत) ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति से साठ दिनों के भीतर लेखापरीक्षित स्वतंत्र और समेकित वित्तीय परिणाम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत नहीं किए।

तालिका 3.32: वे सीपीएसई जिन्होंने साठ दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत नहीं किए।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	विलंब (माह में)
1.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	22
2.	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण	7.5

3.18.3 सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 52 (8) में यह निर्धारित किया गया है कि सूचीबद्ध इकाई निदेशक मंडल की बैठक के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर भारत के संपूर्ण या लगभग संपूर्ण भाग में प्रसारित होने वाले कम से कम एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में वित्तीय परिणाम प्रकाशित करेगी।

एक सांविधिक निगम (भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण) ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 52 (8) में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर कम से कम एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में वित्तीय परिणाम और विवरण प्रकाशित नहीं किया।

3.19 स्टॉक एक्सचेंज को सूचनाएं/अन्य प्रस्तुतियाँ

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2021 के विनियम 60 (2) में यह प्रावधान है कि सूचीबद्ध इकाई को अभिलेखित तिथि की सूचना मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को कम से कम सात कार्यदिवसों (सूचना की तिथि और अभिलेखित तिथि को छोड़कर) से पहले देनी होगी (ब्याज, लाभांश और मोचन या पुनर्भुगतान राशि के भुगतान के लिए या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए) या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सहमत या आवश्यक दिनों की संख्या तक, जिसमें अभिलेखित तिथि का उद्देश्य स्पष्ट किया गया हो। हालांकि, एक सीपीएसई

(हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के मामले में, अभिलेखित तिथि की सूचना निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को नहीं दी गई थी।

3.20 गैर परिवर्तनीय (ऋण) प्रतिभूतियों और गैर परिवर्तनीय वरीयता शेयरों के धारकों के लिए दस्तावेज और सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 विनियम 58(1)(ए), (बी), (सी), (2) और (3) यह निर्धारित करता है कि सूचीबद्ध इकाई निम्नलिखित दस्तावेज भेजेगी: (क) गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के सभी धारकों को, जिन्होंने सूचीबद्ध इकाई या किसी डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत कराया है, पूर्ण वार्षिक प्रतिवेदन की सॉफ्ट कॉपी; (ख) गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के उन धारकों को, जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों की मुख्य विशेषताओं वाले विवरण की हार्ड कॉपी; (ग) ऐसे गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के धारकों को, जो इसकी मांग करें, वार्षिक प्रतिवेदन की संपूर्ण मुद्रित प्रति उपलब्ध कराई जाएगी

(2) सूचीबद्ध इकाई गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के धारकों और गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयरों के धारकों की सभी बैठकों की सूचना भेजेगी जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 में उल्लिखित प्रॉक्सी की नियुक्ति के प्रावधान ऐसी बैठक के लिए लागू होंगे।

(3) सूचीबद्ध इकाई गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों और गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयरों के धारकों को प्रॉक्सी प्रपत्र भेजेगी, जिन्हें इस प्रकार से तैयार किया जाएगा कि इन प्रतिभूतियों के धारक प्रत्येक प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मतदान कर सकें।

हालांकि, 36 सीपीएसई/सांविधिक निगमों में से तीन (नौ प्रतिशत) के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया, जिनमें सम्मिलित हैं: (क) राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड (ख) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और (ग) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.21 निदेशक मंडल

3.21.1 स्वतंत्र निदेशक

प्रबंधन के निर्णयों पर स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने में सक्षम स्वतंत्र प्रतिनिधियों की बोर्ड में उपस्थिति को शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के अनुसार, यदि बोर्ड का अध्यक्ष गैर-कार्यकारी निदेशक है, तो बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और यदि वह कार्यकारी निदेशक है, तो बोर्ड के कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.33 में सूचीबद्ध सीपीएसई के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.33: सूचीबद्ध बांड वाले सीपीएसई जिनके पास वर्ष 2023-24 के दौरान अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

क्रम संख्या	सीपीएसई/सांविधिक निगम का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	कमी की अवधि
1.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	4	गैर कार्यकारी	2	0	2 (100)	अप्रैल से मार्च तक
2.	राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	2	3 (60)	अप्रैल
		4		4	2	2 (50)	मई से अगस्त तक
		3		3	2	1 (33)	सितंबर से नवंबर तक
3.	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	9	कार्यकारी	9	4	5(55)	अप्रैल से मई
		8		8	4	4(50)	जून
		9		9	5	4(45)	जुलाई
		9		9	8	1(11)	अगस्त से सितंबर और जनवरी से फरवरी
		9		9	7	2(22)	अक्टूबर
4.	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	0	7 (100)	अप्रैल
		7		7	1	6 (86)	मई से मार्च तक
5.	टीएचडीसी लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	3	3(50)	अप्रैल और मई
		8		8	3	5(62)	जून
		8		8	2	6(75)	जुलाई से नवंबर तक
		6		6	2	4(67)	दिसंबर से मार्च तक
6.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	5	1 (17)	अप्रैल से मार्च तक
7.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	2	2 (50)	अप्रैल से अक्टूबर तक
		3		3	2	1 (33)	नवंबर से मार्च तक

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा जा सकता है, 32 में से सात (22 प्रतिशत) सीपीएसई में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में मौजूद नहीं थे। यह कमी 11 से 100 प्रतिशत के बीच थी।

3.21.2 महिला निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 में यह प्रावधान है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए। निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.34 में सूचीबद्ध 32 सूचीबद्ध सीपीएसई में से तीन (नौ प्रतिशत) में 2023-24 के दौरान कोई भी महिला निदेशक नहीं थी।

तालिका 3.34: सूचीबद्ध बांड वाली सीपीएसई जिनके बोर्ड में महिला निदेशक नहीं हैं

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	अनुपालन न करने की अवधि
1.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	दिसंबर से मार्च तक
2.	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से जून तक
3.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च तक

3.21.3 लोक उद्यम विभाग(डीपीई) के दिशानिर्देश 2010 के पैरा 3.1.3 में निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में यह प्रावधान है कि 'सरकार/अन्य निगमों द्वारा नियुक्त मनोनीत निदेशकों की संख्या अधिकतम दो तक सीमित होगी'। हालांकि, एक सांविधिक निगम (भारतीय खाद्य निगम) के मामले में इसका अनुपालन नहीं किया गया है।

3.21.4 कंपनी की आम बैठकों में भाग लेना।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (III) (5) में कहा गया है कि स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी की सभी आम बैठकों में उपस्थित रहने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि, एक सीपीएसई (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड) के मामले में, स्वतंत्र निदेशकों ने आम बैठकों में भाग नहीं लिया।

3.22 लेखापरीक्षा समिति

3.22.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (2) में यह प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक होंगे, जिनमें स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा। हालांकि, तालिका 3.35 में सूचीबद्ध दो सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (2) के अनुसार नहीं थी।

तालिका 3.35: ऐसे सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति के अधिकांश सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की कुल संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)
1.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	3	2	0	2 (100)
2.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	6	4	1	3 (75)

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में देखा जा सकता है, 32 सीपीएसई में से दो (छ: प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति के अधिकांश सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। यह कमी 75 से 100 प्रतिशत के बीच थी।

3.22.2 डीपीई दिशानिर्देश 2010 के पैरा 4.1.2 में यह प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। हालांकि, एक सीपीएसई (एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड) के मामले में लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

3.22.3 लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए आवश्यक कोरम:

डीपीई दिशानिर्देशों का पैरा 4.4 लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कोरम की आवश्यकता निर्धारित की गई है (अर्थात्, लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य या एक तिहाई सदस्य, जो भी अधिक हो, कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों के साथ)। वर्ष 2023-24 के दौरान तालिका 3.36 में उल्लिखित 32 सीपीएसई में से चार (13 प्रतिशत) के लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों में आवश्यक कोरम उपलब्ध नहीं था।

तालिका 3.36: लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए अपूर्ण कोरम वाले सीपीएसई

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	अपर्याप्त कोरम वाली बैठकों की संख्या	टिप्पणी
1.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	6	6	बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। इसलिए, कोरम पूरा नहीं हुआ।
2.	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8	2	बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक थे। इसलिए, कोरम पूरा नहीं हुआ।
3.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	9	9	बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक थे। इसलिए, कोरम पूरा नहीं हुआ।
4.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5	1	बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक थे। इसलिए, कोरम पूरा नहीं हुआ।

3.23 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

3.23.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई को कम से कम तीन निदेशकों की एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करना होगा, जिनमें से सभी गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए और कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। तथापि, वर्ष 2023-24 के दौरान 32 सीपीएसई में से दो (एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड तथा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) (छ: प्रतिशत) में समिति की संरचना उपर्युक्त प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाई गई।

3.23.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष

इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 5.1 में यह निर्धारित किया गया है कि नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे। हालांकि, एक सीपीएसई

(एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड) के मामले में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

3.24 अनुपालन प्रमाण पत्र

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V(सी) (10) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

क्रम संख्या	सेबी विनियम संख्या	विशिष्ट	सीपीएसई/एस का नाम
1.	अनुसूची V(सी) (10) (i)	कंपनी गवर्नेंस रिपोर्ट में एक कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र का प्रकटीकरण किया जाना चाहिए, जिसमें यह प्रमाणित हो कि कंपनी के निदेशक मंडल में सम्मिलित किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2.	अनुसूची V(सी) (10) (के)	सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक को समेकित आधार पर भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रकट किया जाना आवश्यक है।	
3.	अनुसूची V(सी) (10) (I)	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में वित्तीय वर्ष के अंत तक दर्ज शिकायतों की संख्या, निपटाए गए शिकायतों की संख्या और लंबित शिकायतों की संख्या का प्रकटीकरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में करना आवश्यक है।	

2023-24 के दौरान एक सीपीएसई (द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) के संबंध में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं किया गया था।

3.25 विविध

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V का भाग सी (2) (एच) के अनुसार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में एक चार्ट या मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें निदेशक मंडल द्वारा अपने व्यवसाय(यों) और क्षेत्र(त्रों) के संदर्भ में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक माने गए मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/योग्यताएँ निर्दिष्ट हों और साथ ही वे कौशल/विशेषज्ञता/योग्यताएँ भी निर्दिष्ट हों जो वास्तव में बोर्ड के पास उपलब्ध हों, और उन निदेशकों के नाम भी सम्मिलित हों जिनके पास ये कौशल/विशेषज्ञता/योग्यताएँ हैं। हालांकि, एक सीपीएसई (द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) के मामले में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

3.26 निष्कर्ष

इस अध्याय में सम्मिलित 36 सूचीबद्ध सीपीएसई/सांविधिक निगमों (बांड द्वारा सूचीबद्ध) के संबंध में, यह पाया गया कि 36 में से चार सीपीएसई/सांविधिक निगमों (11 प्रतिशत), भारत संचार निगम लिमिटेड, आईआरडीडीए, डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने डीपीई/सेबी दिशानिर्देशों/विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी प्रासंगिक प्रावधानों में निर्धारित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया था, जिनका विश्लेषण लेखापरीक्षा द्वारा किया गया था।

शेष 32 सूचीबद्ध सीपीएसई/सांविधिक निगमों (बांड द्वारा सूचीबद्ध) के संबंध में प्रमुख गैर-अनुपालनों के मामलों का सारांश नीचे दिया गया है:

- i) 36 सांविधिक निगमों/संसांविधिक निगमों में से दो (छः प्रतिशत) ने निर्धारित समय के भीतर वित्तीय परिणामों पर विचार करने के लिए आयोजित होने वाली बोर्ड बैठक के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को सूचित नहीं किया।
- ii) 36 सीपीएसई/सांविधिक निगमों में से एक सांविधिक निगम (तीन प्रतिशत) ने तिमाही की समाप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर वित्तीय परिणाम प्रस्तुत नहीं किए।
- iii) 36 सांविधिक निगमों/कंपनियों में से दो (छः प्रतिशत) ने निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक लेखापरीक्षित स्वतंत्र और समेकित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत नहीं किए।
- iv) 36 सीपीएसई/सांविधिक निगमों में से एक सांविधिक निगम (तीन प्रतिशत) ने कम से कम एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में वित्तीय परिणाम और विवरण प्रकाशित नहीं किए।
- v) 36 सांविधिक निगमों/सीपीएसई में से एक सीपीएसई (तीन प्रतिशत) ने अभिलेखित तिथि की सात दिन पहले की सूचना मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को नहीं भेजी थी।
- vi) 36 सांविधिक निगमों/कानूनी निगमों में से तीन (आठ प्रतिशत) ने गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के धारकों को पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट/हार्ड कॉपी नहीं भेजी।
- vii) 32 सीपीएसई में से सात सीपीएसई (22 प्रतिशत) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी; कमी का प्रतिशत 11 से 100 प्रतिशत के बीच था।
- viii) 32 सीपीएसई में से तीन सीपीएसई (नौ प्रतिशत) के बोर्ड में कोई भी महिला निदेशक नहीं थी।
- ix) 32 सीपीएसई में से एक सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों ने आम बैठकों में भाग नहीं लिया।
- x) 32 सीपीएसई में से, दो सीपीएसई (छः प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति की संरचना अनुपयुक्त थी; एक सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे; चार सीपीएसई (12 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में कोरम अपूर्ण था।

- xi) 32 सीपीएसई में से, दो सीपीएसई (छः प्रतिशत) में नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना अपर्याप्त थी; एक सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक नहीं थे;
- xii) 32 सीपीएसई में से एक सीपीएसई (तीन प्रतिशत) की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में कुछ नियमों का अनुपालन नहीं किया गया था।

अनुशंसा:

प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सूचीबद्ध सीपीएसई/सांविधिक निगमों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डीपीई दिशानिर्देशों, सेबी विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें। ऐसे सूचीबद्ध निगमों के निदेशक मंडल/प्रबंधन भी अपने कामकाज में बेहतर पारदर्शिता और उत्तरदेही लाने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।

संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रतिक्रिया के लिए अध्याय (17 अक्टूबर 2025) जारी किया गया था, हालांकि 19 मंत्रालयों में से 12 मंत्रालयों के उत्तर (सात मंत्रालयों के पूर्ण उत्तर और पांच मंत्रालयों के आंशिक उत्तर) प्राप्त हो चुके हैं और सात मंत्रालयों के उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त जवाबों पर इस अध्याय में (13 फरवरी 2026 तक) उचित रूप से विचार किया गया है।

अध्याय IV

सीपीएसई द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय

अध्याय IV

सीपीएसई द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय

4.1 परिचय

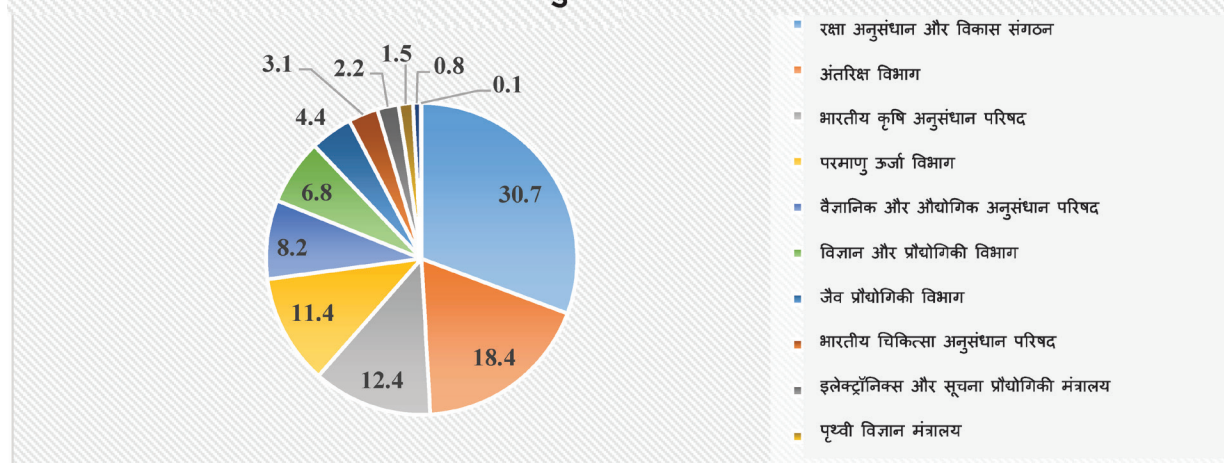
तकनीकी उन्नयन के लिए अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं और इनके परिणामस्वरूप बाजार में नए उत्पाद और सेवाएं आती हैं तथा अधिक कुशल और लागत प्रभावी प्रक्रियाएं विकसित होती हैं।

केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत की प्रगति में नवाचार, अनुसंधान और विकास के प्रमुख योगदानकर्ताओं के रूप में इन पर जोर दिया गया, जो अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना, निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान में निवेश, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार और कृषि एवं परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में प्रगति जैसी वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा देने वाली पहलों से स्पष्ट था। सरकार ने विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए बजट आवंटन और छः प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसियों/विभागों⁴⁰ को आवंटित राशि में लगातार वृद्धि की तथा 2025-26 के बजट में पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनएसटीएमआईएस) द्वारा किए गए सर्वेक्षण (2022-23) के अनुसार, अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय (जीईआरडी) 2010-11 से 2020-21 के दशक में ₹60,196.75 करोड़ से बढ़कर ₹1,27,380.96 करोड़ हो गया, जो दोगुने से भी अधिक है। अध्ययन से पता चला कि जीईआरडी मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र द्वारा संचालित था, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 43.70 प्रतिशत, राज्य सरकारों का 6.70 प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का 4.40 प्रतिशत और उच्च शिक्षा संस्थानों का 8.8 प्रतिशत था, जबकि शेष 36.40 प्रतिशत निजी उद्योग का था। 2020-21 के दौरान यह बात सामने आई कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास व्यय बारह प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसियों से आए थे, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है।

⁴⁰ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग/वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।

चार्ट 1 : 12 प्रमुख केंद्रीय सरकारी वैज्ञानिक अभिकरणों द्वारा किया गया अनुसंधान एवं विकास व्यय



स्रोत: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 में प्रकाशित अनुसंधान एवं विकास सांख्यिकी।

सर्वेक्षण में यह भी बताया गया कि भारत में अनुसंधान एवं विकास में निवेश सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.64 प्रतिशत है। भारत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” जैसी पहलों के माध्यम से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। वित्त वर्ष 2025 के अंतरिम बजट में सरकार ने ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान’ के नारे के साथ देश में अनुसंधान और नवाचार के लिए एक लाख करोड़ के कोष की घोषणा की।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्य हमारे देश की तकनीकी क्षमता को मजबूत कर सकते हैं और देश में रोजगार सृजन और विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही, ये गतिविधियां सीपीएसई को तेजी से वैश्विक हो रही दुनिया में नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करने में सक्षम बनाती हैं। लोक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में कार्यरत 272 सीपीएसई में से 79 सीपीएसई का अनुसंधान एवं विकास व्यय ₹10,813 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह ₹7,233 करोड़ था, जो 49.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

4.2 लेखापरीक्षा का दायरा

इस अध्याय में वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान चयनित 26 रत्न श्रेणी के सीपीएसई (अनुलग्नक XX) द्वारा अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर किए गए व्यय को सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा में 100 रत्न सीपीएसई⁴¹ में से 26 सीपीएसई के नमूने का चयन करने के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण विधि का प्रयोग किया गया था। 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए योग अनुसंधान एवं विकास व्यय ₹8,165 करोड़ के आधार पर (14 महारत्न, 24 नवरत्न, 51 मिनीरत्न (श्रेणी 1) और 11 मिनीरत्न (श्रेणी 2) सीपीएसई)। इन 26 सीपीएसई में से, 14 ने ₹100 करोड़ से अधिक का व्यय किया, पांच सीपीएसई ने ₹20 करोड़ और ₹100 करोड़ के बीच व्यय किया,

⁴¹ फरवरी 2025 में डीपीई द्वारा प्रकाशित रत्न श्रेणी के सीपीएसई की सूची के अनुसार।

चार सीपीएसई ने ₹20 करोड़ तक का व्यय किया और तीन सीपीएसई ने शून्य व्यय किया (हालांकि उनका कर पूर्व लाभ ₹100 करोड़ से अधिक था) 2019-20 से 2023-24 के दौरान किसी भी वर्ष में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर। यह पैराग्राफ जुलाई-अगस्त 2025 के दौरान 26 सीपीएसई को और संबंधित मंत्रालयों को सितंबर 2025 में जारी किया गया था। प्रबंधन और मंत्रालयों से 14.01.2026 तक प्राप्त उत्तरों को इस अध्याय में सम्मिलित कर लिया गया है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के संबंध में रक्षा मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित था (14 जनवरी 2026)।

4.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

- सीपीएसई के पास अनुसंधान एवं विकास नीति/नियमावली और भविष्य की योजना के लिए एक रोडमैप है;
- अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अंतिम परिणामों की निगरानी, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए प्रभावी प्रक्रियाएं और कार्यप्रणालियां मौजूद हैं;
- डीपीई के समझौता ज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार अनुसंधान और विकास पर धनराशि खर्च की जा रही थी;

अनुसंधान और विकास पर किए गए व्यय के परिणामस्वरूप उत्पादों/सेवाओं का व्यावसायीकरण हुआ और अंततः इससे कंपनी को जमीनी स्तर पर लाभ प्राप्त हुआ।

सीएजी का प्रतिवेदन संख्या 18, वर्ष 2019 में डीपीई के दिशानिर्देशों (सितंबर 2011) के आधार पर 'सीपीएसई द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय' से संबंधित एक लेखापरीक्षा अध्याय सम्मिलित किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी होने के तुरंत बाद ही दिशानिर्देश वापस ले लिए गए (जुलाई 2019)। सीपीएसई द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय की निगरानी के लिए वर्तमान में कोई विशिष्ट दिशानिर्देश मौजूद नहीं हैं। समेकित समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों (मार्च 2022) के अंतर्गत अनुसंधान और विकास/नवाचारों और पहलों पर व्यय को निष्पादन मापदंडों में से एक (100 में से दो अंक) के रूप में निर्धारित किया गया है, लेकिन पेटेंट प्राप्ति, सामग्री लागत में बचत, विकसित और व्यावसायीकृत प्रौद्योगिकी आदि जैसे निष्पादन पर विशेष जोर नहीं दिया गया है।

4.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया गया था:

- निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति और योजनाएँ तथा प्रशासनिक मंत्रालय की विजन योजना/रोडमैप।
- अनुसंधान एवं विकास निष्पादन मापदंड को डीपीई द्वारा जारी समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

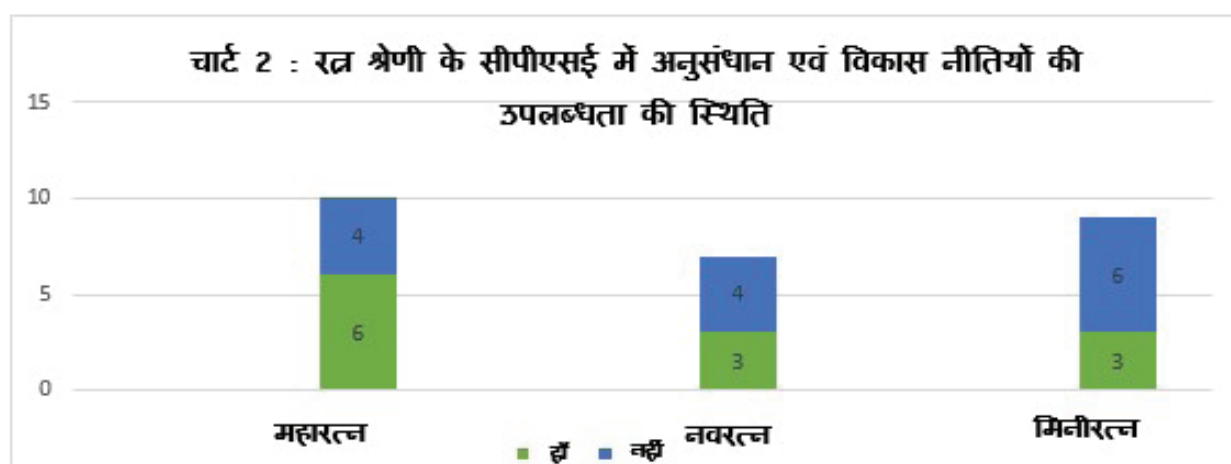
- कंपनियों के बोर्ड की बैठकों का एजेंडा और कार्यवृत्त।
- आयकर अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास व्यय से संबंधित आयकर लाभ लागू होता है।

4.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.5.1 अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के संचालन हेतु नीति एवं योजना

सीपीएसई द्वारा अनुसंधान और विकास नीति संबंधी गतिविधियों को निर्देशित और संचालित करने के लिए स्पष्ट, संरचित नीति और निर्धारित प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। यह नीति कंपनी के समग्र दृष्टिकोण और मिशन के अनुरूप होनी चाहिए, और योजना में विशिष्ट परियोजनाओं, समय-सीमा, बजट और अपेक्षित परिणामों का विस्तृत विवरण होना चाहिए।

वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान चयनित रत्ना सीपीएसई में समर्पित अनुसंधान और विकास नीति की उपलब्धता की स्थिति नीचे चार्ट 2 में दर्शाई गई है:



स्रोत: कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 26 सीपीएसई में से 12 सीपीएसई की अपनी अनुसंधान एवं विकास नीति है, इन नीतियों को 2018 से 2025 के दौरान संशोधित/अद्यतन किया गया था। जबकि, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और माझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने 2013 के बाद से अपनी अनुसंधान एवं विकास नीति को संशोधित नहीं किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1983 में तैयार की गई अनुसंधान एवं विकास नीति का पालन कर रही है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शेष 14 सीपीएसई के पास विशिष्ट अनुसंधान और विकास नीति नहीं थी और इसके बजाय वे गुणवत्ता नीति/कार्य योजना/अन्य संबंधित दिशा-निर्देश/ढांचागत दस्तावेज आदि का पालन करते थे, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

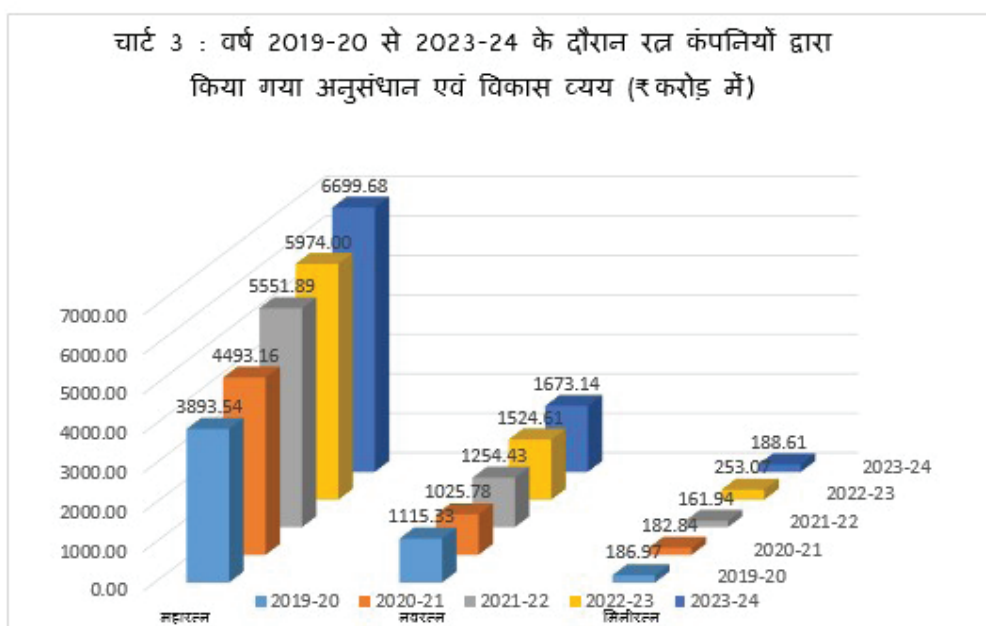
- **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड:** रांची स्थित लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केंद्र (आरडीसीआईएस) की एक गुणवत्ता नीति थी जिसमें गुणवत्ता संबंधी निर्धारित उद्देश्य सम्मिलित थे। इस्पात मंत्रालय ने (नवंबर 2025 में) उत्तर दिया कि आरडीसीआईएस द्वारा एक अनुसंधान एवं विकास नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है।
- **भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड (एलिम्को):** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीओईपीडब्ल्यूडी) ने (नवंबर 2025 में) उत्तर दिया कि शीर्ष समूह द्वारा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की आवधिक निगरानी को सम्मिलित करते हुए अनुसंधान एवं विकास नीति तैयार की जाएगी। प्रस्तावित नीति को अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत कर दिया गया है।
- **ऑयल इंडिया लिमिटेड:** अनुसंधान एवं विकास विभाग की स्थापना (1985) हुई और अनुसंधान एवं विकास नीति तैयार की गई। (2012-2013), जिसे हालांकि अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर डीपीई दिशानिर्देशों को वापस लेने के बाद (जून 2019) लागू नहीं किया गया था।
- **कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल):** कंपनियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के दिशानिर्देश का पालन करती हैं। सीआईएल ने समिति का गठन किया (जनवरी 2025) और अनुसंधान एवं विकास नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार किया। बीसीसीएल ने अपने सीएमडी की अध्यक्षता में एक अनुसंधान एवं विकास समिति का गठन किया। कोयला मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2025) कि चूंकि बीसीसीएल एक सहायक कंपनी है, इसलिए अलग से अनुसंधान एवं विकास नीति की आवश्यकता नहीं है।
- **ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी):** बोर्ड स्तर की बैठकों में अनुसंधान एवं विकास नीति पर चर्चा की गई थी और कंपनी अनुसंधान एवं विकास तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने की प्रक्रिया में थी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने (नवंबर 2025) कहा कि ओएनजीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ओएनजीसी की स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करती है और अपने मूल संगठन के माध्यम से उपलब्ध व्यापक तकनीकी एवं अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना से लाभान्वित होती है। इसलिए, ओएनजीसी (विदेश) की अपनी कोई अलग अनुसंधान एवं विकास नीति नहीं है।
- **राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (एनएमडीसी):** कंपनी ने अनुसंधान और विकास के लिए एक एकीकृत प्रबंधन प्रणाली मैनुअल (आईएमएस) और एपेक्स फ्रेमवर्क दस्तावेज़ विकसित किया था।
- **मेकॉन लिमिटेड:** कंपनी के पास अनुसंधान एवं विकास प्रभाग के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और गुणवत्ता नियमावली थी।
- **मिश्र धातु निगम लिमिटेड (एमडीएनएल):** एमडीएनएल के विजन 2047 दस्तावेजों में भविष्य की योजना का रोडमैप सम्मिलित है। वार्षिक अनुसंधान और विकास योजनाएं तैयार की गई हैं और विजन दस्तावेजों में सम्मिलित की गई हैं।

- **केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी):** उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (एमओसीएफपीडी) ने (नवंबर 2025 में) उत्तर दिया कि केंद्रीय भंडारण निगम के पास अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को करने के लिए एक दस्तावेजी प्रक्रिया है, और ऐसे सभी कार्य स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किए जाते हैं।
- **नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएसआईसी):** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) ने (नवंबर 2025 में) कहा कि एनएसआईसी एक वित्तीय संस्थान होने के नाते एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) है, इसलिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां संगठन के मूल अधिदेश के अनुरूप नहीं हैं।
- **भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा):** कंपनी ने यह स्पष्ट किया कि वित्तीय संस्थान होने के कारण उसकी कोई अनुसंधान एवं विकास नीति नहीं है।
- **टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल):** दूरसंचार विभाग ने (अक्टूबर 2025 में) उत्तर दिया कि टीसीआईएल सीमित उत्पाद नवाचार के साथ सेवा-उन्मुख ईपीसी व्यवसाय मॉडल पर काम कर रही थी और इसकी कोई अनुसंधान एवं विकास नीति नहीं थी।

सरकार की ओर से किसी भी प्रकार के दिशा-निर्देशों के अभाव में, सीपीएसई केंद्रीय सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अनुरूप अपनी गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों को शुरू करने हेतु समर्पित और एकसमान नीति बनाने के लिए बाध्य नहीं थे।

4.5.2 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर व्यय

4.5.2.1 वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान 26 रत्ना सीपीएसई द्वारा अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर कुल व्यय ₹34,178.99 करोड़ था, जैसा कि नीचे चार्ट 3 में विस्तार से बताया गया है:



स्रोत: कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट

उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि 2019-20 के दौरान 10 महारत्न सीपीएसई द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय ₹3,893.54 करोड़ था, जो 2023-24 में 72.07 प्रतिशत बढ़कर ₹6,699.68 करोड़ हो गया। सात नवरत्न सीपीएसई के मामले में, 2019-20 के दौरान व्यय ₹1,115.33 करोड़ था, जो 2023-24 में बढ़कर ₹1,673.14 करोड़ हो गया (50 प्रतिशत से अधिक)। हालांकि, 2019-20 से 2023-24 के दौरान नौ मिनीरत्न (I और II) सीपीएसई द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय लगभग स्थिर रहा।

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान कुल अनुसंधान और विकास व्यय में से, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ₹10,206.84 करोड़ (कुल अनुसंधान और विकास व्यय का 29.86 प्रतिशत) के साथ शीर्ष व्ययकर्ता रहा, जिसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्थान रहा।

4.5.2.2 डीपीई (मार्च 2022) द्वारा जारी वर्ष 2021-22 और उसके बाद के लिए समेकित समझौता जापन दिशानिर्देशों के समझौता जापन (एमओयू) पैरामीटर के अनुसार, “प्रत्येक सीपीएसई को अनुसंधान और विकास/नवाचार और पहल पर कर-पूर्व लाभ का दो प्रतिशत व्यय करना आवश्यक था” ताकि समझौता जापन पैरामीटर के अंतर्गत दो अंक प्राप्त किए जा सकें।

चयनित सीपीएसई द्वारा वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान कर पूर्व लाभ के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास व्यय का विवरण तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका 4.1: वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान चयनित रत्ना सीपीएसई द्वारा कर पूर्व लाभ के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास व्यय।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सीपीएसई की श्रेणी	2021-22 पीबीटी का प्रतिशत	2022-23 पीबीटी का प्रतिशत	2023-24 पीबीटी का प्रतिशत	श्रेणीवार उप-योग
1.	बीएचईएल	महारत्न	160.2	100.76	316.8	3,582.01
2.	कोल इंडिया		0.27	0.84	0	194.65
3.	गेल		1.79	2.74	2.17	761.14
4.	एचपीसीएल		4.43	-- ⁴²	1.84	1,588.97
5.	आईओसीएल		1.82	7.2	1.81	3,157.89
6.	एनटीपीसी		1.15	1.18	2.05	1,358.66
7.	ओएनजीसी		1.3	1.09	1.3	2,947.21
8.	सेल		5.08	16.33	8.33	2,208.48
9.	ओआईएल		2.02	2.02	2.21	606.42

⁴² कंपनी को 2022-23 में घाटा हुआ और इसलिए इसे उन सीपीएसई के अंतर्गत नहीं माना जाता है जिनका व्यय पीबीटी के 2 प्रतिशत से कम है।

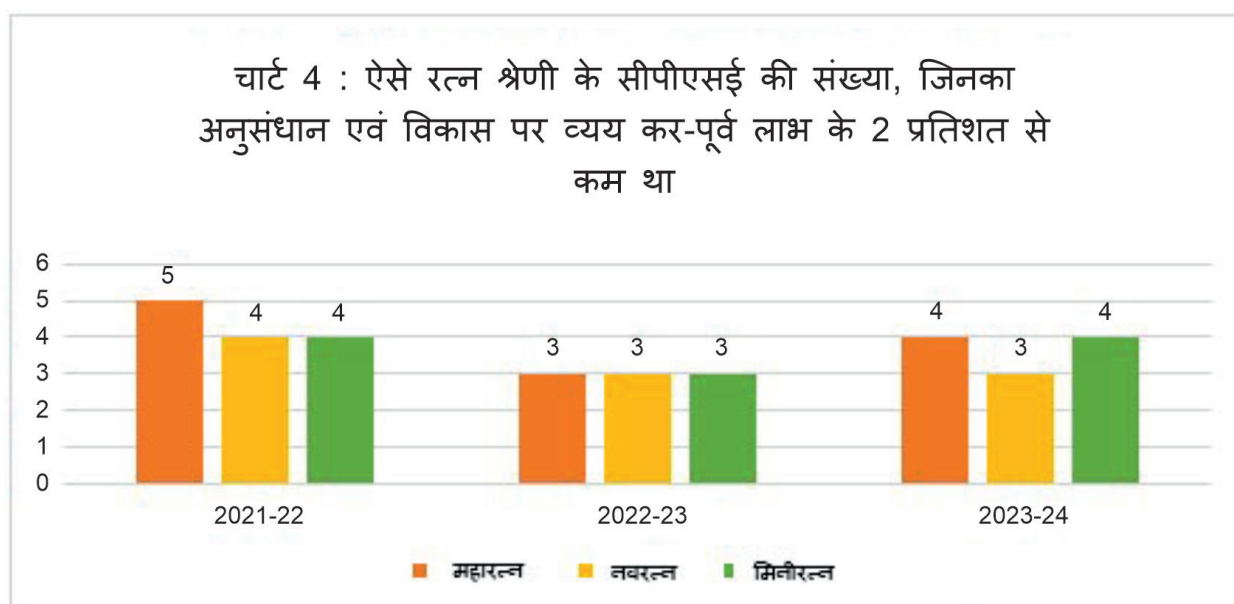
क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	सीपीएसई की श्रेणी	2021-22 पीबीटी का प्रतिशत	2022-23 पीबीटी का प्रतिशत	2023-24 पीबीटी का प्रतिशत	श्रेणीवार उप-योग
10.	एचएएल		37.60	38.42	27.71	10,206.84
		योग				26,612.27
11.	बेल	नवरत्न	33.86	26.99	22.57	5,214.27
12.	सीडब्ल्यूसी		2.28	4.63	2.27	47.55
13.	इरेडा		0.00	0.00	0.00	0
14.	एमडीएसएल		9.56	14.80	12.89	778.19
15.	नालको		1.65	8.26	3.82	359.33
16.	एनएमडीसी		0.23	0.40	0.30	145.89
17.	ओवीएल		0.00	1.17	1.47	48.06
		योग				6,593.29
18.	एएआई	मिनीरत्न-I	0.183	0.002	0.00	0.12
19.	बीसीसीएल ⁴³		0.00	0.00	0.00	0
20.	बीडीएल		6.78	31.55	9.10	392.36
21.	बीईएमएल		49.90	26.84	22.72	500.11
22.	एमडीएनएल		2.85	9.36	14.02	59.15
23.	एनएसआईसी		1.43	2.29	1.43	8.82
24.	टी सी आई एल		0.00	0.00	0.00	0
25.	एलिम्को	मिनीरत्न-II	2.25	2.42	4.26	7.27
26.	मेकॉन ⁴⁴		3.74	2.73	3.71	5.6
		योग				973.43
						34,178.99

स्रोत: कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट

⁴³ बीसीसीएल ने कोयला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुदान और कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास अनुदान के तहत एक उप-कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया, लेकिन इस व्यय को बीसीसीएल के बही-खातों में शामिल नहीं किया गया।

⁴⁴ मेकॉन द्वारा किया गया व्यय केवल वेतन और अन्य खर्चों से संबंधित था।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान कर-पूर्व लाभ के दो प्रतिशत से कम अनुसंधान एवं विकास व्यय वाली महारत्न/नवरत्न/मिनीरत्न श्रेणी में वर्गीकृत सीपीएसई की संख्या नीचे चार्ट 4 में दर्शाई गई है:



स्रोत: कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट

2021-22 के दौरान, 26 सीपीएसई में से 13 सीपीएसई (पांच महारत्न, चार नवरत्न और चार मिनीरत्न) ने कर-पूर्व लाभ के दो प्रतिशत से कम अनुसंधान एवं विकास व्यय किया। 2022-23 में यह संख्या घटकर नौ सीपीएसई (तीन महारत्न, तीन नवरत्न और तीन मिनीरत्न) रह गई, लेकिन 2023-24 में बढ़कर 11 (चार महारत्न, तीन नवरत्न और चार मिनीरत्न) हो गई। उपरोक्त में तीन सीपीएसई (एक नवरत्न और दो मिनीरत्न-1) सम्मिलित हैं जिन्होंने 2021-22 से 2023-24 के दौरान कोई अनुसंधान एवं विकास व्यय नहीं किया।

कोयला मंत्रालय ने (अक्टूबर 2025) बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सहायक स्तर की परियोजनाओं के लिए प्रति वर्ष एक करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन बीसीसीएल ने किसी भी आंतरिक अनुसंधान एवं विकास परियोजना को वित्त पोषित नहीं किया था क्योंकि उसकी आवश्यकताएं कोल इंडिया लिमिटेड/कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित चल रही परियोजनाओं के माध्यम से पूरी हो रही थीं। खान मंत्रालय ने (अक्टूबर 2025) बताया कि कोविड-19 महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण वर्ष 2021-22 के दौरान एनएएलसीओ का अनुसंधान एवं विकास व्यय कर-पूर्व लाभ के दो प्रतिशत से कम था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने (नवंबर 2025) बताया कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एक गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते, नवाचार गतिविधियों के अंतर्गत व्यय कंपनी द्वारा किया गया अनुसंधान एवं विकास व्यय था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वित्तपोषित एनबीएफसी के पास अनुसंधान एवं विकास व्यय नहीं हो सकता है, इसे वित्त वर्ष 2025-26 से समझौता जापन के मापदंडों से हटा दिया गया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने (नवंबर 2025) कहा कि ओवीएल की अपनी कोई अलग अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) नीति नहीं है और वह मुख्य रूप से विदेशी संपत्तियों पर अनुसंधान एवं विकास व्यय करती है, इसलिए इसे लेखापरीक्षा के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने (दिसंबर

2025) कहा कि इरेडा एक गैर-नववित्तीय वित्तीय कंपनी होने के नाते, एमएनआई के निर्देशों, सेबी और आरबीआई के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है और वर्तमान में उसके पास अनुसंधान एवं विकास करने का कोई दायित्व नहीं है।

इन उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों में निर्धारित न्यूनतम मापदंड को पूरा करने के लिए सीपीएसई द्वारा अनुसंधान और विकास पर किए जाने वाले व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है।

4.5.3 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की व्यवस्था

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, सीपीएसई (संचारी शिक्षा उद्यम) परियोजनाओं की शुरुआत में ही कार्यान्वयन के लिए एक संरचित तंत्र स्थापित कर सकते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि रत्ना सीपीएसई के अधिकांश संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सुव्यवस्थित तंत्र मौजूद है, जैसा कि नीचे⁴⁵ चर्चा की गई है।:

- (i) **एस. ए. आई. एल.:** रांची स्थित आरडीसीआईएस (सेल की कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास इकाई) संयंत्र निष्पादन सुधार, उत्पाद विकास, वैज्ञानिक जांच एवं विकास, मौलिक अनुसंधान और तकनीकी सेवाओं की श्रेणियों के अंतर्गत लौह एवं इस्पात प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं संचालित करती है।
- (ii) **भारतीय विमानपतन प्राधिकरण लिमिटेड :** भारतीय विमानपतन प्राधिकरण लिमिटेड परियोजना निगरानी/समीक्षा के लिए एक सर्वोच्च समिति है जो समय-समय पर परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करती है और परिणामों का आकलन करती है। एएआई ने परियोजना निगरानी/समीक्षा के लिए सर्वोच्च समिति को परियोजना समाप्त करने का अधिकार दिया है।
- (iii) **कोल इंडिया लिमिटेड:** कोल इंडिया लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का नेतृत्व कंपनी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में अनुसंधान एवं विकास बोर्ड करता है। कुशल निर्णय लेने के लिए, अनुसंधान एवं विकास बोर्ड के अधीन एक सर्वोच्च समिति कार्यरत है। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई), जो सीआईएल की परामर्श शाखा है, अनुसंधान एवं विकास पहलों के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। कोयला मंत्रालय ने (अक्टूबर 2025 में) कहा कि बीसीसीएल में शुरू की गई सभी परियोजनाएं या तो कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास अनुदान या कोयला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुदान द्वारा वित्त पोषित हैं, जिसमें बीसीसीएल उप-कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- (iv) **नालको:** नालको के मामले में, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (एनआरटीसी) को अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की योजना बनाने, उन्हें लागू करने, समय-समय पर समीक्षा करने और बोर्ड से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में स्थानीय सलाहकार बोर्ड (अनुसंधान सलाहकार समिति) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

⁴⁵ इसमें बीसीसीएल को शामिल नहीं किया गया है, जो सीआईएल की एक सहायक एजेंसी थी, और इरेडा, टीसीआईएल और एनएसआईसी को भी शामिल नहीं किया गया है, जिनमें कोई अनुसंधान एवं विकास कार्य नहीं किया गया था।

- (v) **एनटीपीसी:** एनटीपीसी में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का मार्गदर्शन और संचालन अनुसंधान सलाहकार परिषद (आरएसी) द्वारा किया जाता है, जिसमें भारत और विदेश के प्रख्यात वैज्ञानिक और विशेषज्ञ सम्मिलित हैं। आरएसी, एनटीपीसी ऊर्जा प्रौद्योगिकी अनुसंधान गठबंधन (नेट्रा) के अंतर्गत कार्य करती है। नेट्रा की स्थापना 2009 में एनटीपीसी के अनुसंधान एवं विकास विभाग के रूप में की गई थी।
- (vi) **एचएएल:** हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) मुख्य रूप से दो श्रेणियों के अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का संचालन करती है: ग्राहक वित्तपोषित परियोजनाएं एवं एचएएल वित्तपोषित परियोजनाएं। ग्राहक वित्तपोषित परियोजनाएं रक्षा बलों की आवश्यकताओं के आधार पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा अनुमोदित स्वीकृतियों के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती हैं। एचएएल द्वारा शुरू की गई डिजाइन और विकास परियोजनाएं आंतरिक संसाधनों और एचएएल द्वारा आंतरिक अनुसंधान और विकास के लिए बनाए गए कोष के माध्यम से स्वदेशी क्षमता निर्माण के लिए शुरू की जाती हैं। एचएएल अपने परिचालन लाभ का 10 प्रतिशत कर-पश्चात वार्षिक रूप से इस कोष में योगदान करती है।
- (vii) **मेकॉन:** कंपनी किसी भी अनुसंधान एवं विकास परियोजना को शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और गुणवत्ता नियमावली की कार्यप्रणाली का पालन करती है।
- (viii) **बीएचईएल:** कंपनी ने 14 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं और साथ ही हैदराबाद स्थित कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास प्रभाग और अपनी विनिर्माण इकाइयों में स्थित अनुसंधान एवं उत्पाद विकास (आरपीडी) केंद्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां भी संचालित करती है।
- (ix) **गेल:** गेल कंपनी के व्यवसाय/संचालन के क्षेत्रों जैसे प्राकृतिक गैस पारेषण और वितरण, पेट्रोकेमिकल्स, शहरी गैस वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑयल और गैस अन्वेषण में सीमित रूप से अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां कर रही है।
- (x) **एचपीसीएल:** एचपीसीएल ने नवोन्मेषी और अभूतपूर्व प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को विकसित करने के लिए बेंगलुरु में (2016 में) 'एचपी ग्रीन आर एंड डी सेंटर' की स्थापना की है। यह अनुसंधान एवं विकास केंद्र वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा मान्यता प्राप्त है और भारत और विदेश के अनुसंधान संस्थानों के साथ इसका सहयोग है।
- (xi) **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड:** कंपनी ने (1972 में) हरियाणा के फरीदाबाद में अपना अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया। स्नेहक उत्पादों के अपने ब्रांड को स्थापित करने और विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों में स्नेहक उत्पादों की आपूर्ति की क्षमता विकसित करने के बाद, इंडियन ऑयल ने पेट्रोलियम शोधन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों और उत्प्रेरकों पर ध्यान केंद्रित किया।
- (xii) **ओएनजीसी:** हाइड्रोकार्बन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के अन्वेषण और उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए, ओएनजीसी ने सात आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों) के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर (2015) किए।

- (xiii) **ऑयल इंडिया लिमिटेड:** ऑयल इंडिया लिमिटेड ने दुलियाजान, असम, भारत में अपने क्षेत्रीय मुख्यालय में अनुसंधान एवं विकास विभाग (आरएंडडी), और गुवाहाटी, असम, भारत में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनर्जी स्टडीज, दो ज्ञान-आधारित अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किए।
- (xiv) **बीईएल:** इसकी एक बहु-स्तरीय अनुसंधान एवं विकास संरचना है और बीईएल के सभी आर एंड डी केंद्र वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के साथ पंजीकृत हैं तथा पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं। बीईएल के बेंगलूर स्थित सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केंद्र, हैदराबाद इकाई और सीआरएल-गाजियाबाद को कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन लेवल 5 रेटिंग से प्रमाणित किया गया है।
- (xv) **एनएमडीसी:** हैदराबाद स्थित एनएमडीसी का अनुसंधान एवं विकास केंद्र, एनएमडीसी की आंतरिक परियोजनाओं और भारत में अन्य संगठनों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- (xvi) **एमडीएनएल:** एमडीएनएल का अनुसंधान एवं विकास कार्य परीक्षण आदेश (ट्रायल ऑर्डर) या विकास आदेश के तहत होता है, और नए ग्रेड/उत्पादों के लिए लिए गए 'हीट्स' को अनुसंधान एवं विकास व्यय माना जाता है। परीक्षण आदेश के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, ग्राहक द्वारा एमडीएनएल को उत्पादन के आदेश दिए जाते हैं।
- (xvii) **ओएनजीसी विदेश लिमिटेड:** ओवीएल, ओएनजीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, ओएनजीसी की स्थापित अनुसंधान एवं विकास प्रक्रियाओं का पालन करती है।
- (xviii) **बीडीएल:** कंपनी ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए उत्पाद विकास और मौजूदा उत्पादों के उन्नयन में सतत संलग्न रही। बीडीएल का डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रभाग विभिन्न परियोजनाओं के विकास पर कार्य करता है।
- (xix) **बीईएमएल:** बीईएमएल के अनुसंधान एवं विकास प्रभाग ने कंपनी को विकास के लिए एक तकनीकी आधार प्रदान किया और स्वदेशीकरण के साथ मिलकर यह बीईएमएल के व्यवसाय का प्रमुख हिस्सा रहा है। खनन और निर्माण, रक्षा और एयरोस्पेस, तथा रेल और मेट्रो के सभी तीन प्रमुख व्यावसायिक खंडों (वर्टिकल्स) में अनुसंधान और विकास कार्य उनके डिजाइन विकास, इंजीनियरिंग, विनिर्माण और परीक्षण के लिए समर्पित विभिन्न परिसरों में किए गए।
- (xx) **सीडब्ल्यूसी:** अनुसंधान एवं विकास प्रभाग ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से खाद्यान्न और अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण के क्षेत्र में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, मौजूदा विधियों/प्रणालियों में सुधार और नए क्षेत्रों की खोज के लिए अध्ययन करता है।
- (xxi) **एलिम्को:** निगम के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए, इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर, और आईआईटी-एम जैसे अग्रणी शीर्ष अनुसंधान निकायों के साथ समझौता ज्ञापन किए गए थे। निगम ने एलिम्को मुख्यालय, कानपुर में एक हाई-एंड प्रोस्थेसिस (उच्च-स्तरीय कृत्रिम अंग) शॉप की स्थापना की थी, जिसमें उच्च परिशुद्धता वाली मशीनें (सीएनसी सहित) स्थापित और कमीशन की गई थीं।

(xxii) **एमडीएसएल:** एमडीएसएल ने न केवल मुख्य रक्षा क्षेत्र में, बल्कि अंडरवाटर ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी (पानी के भीतर स्वायत्त प्रौद्योगिकी), टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन समाधान आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी शैक्षणिक संस्थानों, स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई के साथ सहयोग के माध्यम से केंद्रित अनुसंधान एवं विकास पहल की थी।

4.5.3.1 शुरू की गई अनुसंधान और विकास परियोजनाएं

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 26 रत्न सीपीएसई के प्रतिदर्श (नमूने) में से केवल 22 सीपीएसई ने ही वर्ष 2019-2024 के दौरान अनुसंधान और विकास परियोजनाएं हाथ में ली थीं। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान सीपीएसई द्वारा हाथ में ली गई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है।

तालिका 4.2 - वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान रत्न सीपीएसई द्वारा शुरू की गई अनुसंधान और विकास परियोजनाएं।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	शुरू की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण की गई परियोजनाएँ (कॉलम 3 के प्रोजेक्ट में से)	विलंबित परियोजनाओं की संख्या		परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब (माह में)	एक वर्ष से ज़्यादा विलंब वाली परियोजनाओं की संख्या
				पूर्ण	कार्यरत		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ओएनजीसी	2334	2322	37	11	51-1	7
2.	बीईएल	2323	1978	964	--		360
3.	बीएचईएल	952	800	401	--	69-2	119
4.	कोल इंडिया	29	27	23	--	44-3	8
5.	गेल	27	11	10	12	48-3	13
6.	एचपीसीएल	278	120	47	125	67-1	108
7.	आईओसीएल	133	123	25	17	-3	1
8.	एनटीपीसी	47	34	30	--	--	12
9.	सेल	296	223	64	--	12-1	--
10.	ओआईएल	10	10	2	--	3-1	
11.	एचएएल	78	31	19	--	36-1	6
12.	सीडब्ल्यूसी	2	1	1	1	26-2	1
13.	एमडीएसएल	3	1	1	--	46	1
14.	नाल्को	17	17	09	--	18-2	3
15.	एनएमडीसी	56	56	0	0	0	

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	शुरु की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण की गई परियोजनाएँ (कालम 3 के प्रोजेक्ट में से)	विलंबित परियोजनाओं की संख्या		परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब (माह में)	एक वर्ष से ज़्यादा विलंब वाली परियोजनाओं की संख्या
16.	ओवीएल	आर एंड डी प्रोजेक्ट्स अपने-अपने प्रोजेक्ट्स के वर्क प्रोग्राम में सम्मिलित होते हैं और उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया जाता है।					
17.	ए ए आई	25	25	2	--	27-17	2
18.	बीसीसीएल	8	8	7	--	5-3	
19.	बीडीएल	27	10	5	4	12-2	0
20.	बीईएमएल	8	3	0	0		
21.	एमडीएनएल	113	अनियत				
22.	एलिम्को	17	16	5	2	31-2	1
योग		6783	5816	1652	172		642

स्रोत : प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी।

उपरोक्त तालिका सीपीएसई द्वारा शुरू की गई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का विवरण दर्शाती है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान 22 सीपीएसई द्वारा शुरू की गई 6,783 परियोजनाओं में से, 5,816 परियोजनाएं पूरी की गईं, जिसमें 1,652 परियोजनाएं सम्मिलित हैं जो अपनी निर्धारित पूर्णता तिथि के बाद पूरी हुईं, और 172 जारी परियोजनाओं में विलंब हुआ। विलंबित 1,824 परियोजनाओं में से, 642 परियोजनाएं एक वर्ष से अधिक समय के लिए विलंबित थीं।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभ्युक्तियाँ पाई गईं:

- **ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड** ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान 2,334 अनुसंधान और विकास परियोजनाएं निष्पादित कीं। इनमें से 48 परियोजनाएं 1 से 51 माह की अवधि तक विलंबित रहीं। सात परियोजनाएं एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विलंबित थीं।
- **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड** ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान 2,323 अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शुरू कीं। पूरी की गई 1,978 परियोजनाओं में से, 964 परियोजनाएं विलंबित रहीं, जिनमें 360 परियोजनाएं एक वर्ष से अधिक समय तक विलंबित थीं।
- **भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड** ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान 800 परियोजनाएं पूरी कीं। इनमें से 401 परियोजनाएं विलंबित रहीं, जिनमें 119 परियोजनाएं एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए विलंबित थीं।
- **एमडीएनएल** के मामले में, कंपनी का अनुसंधान और विकास कार्य ट्रायल ऑर्डर या डेवलपमेंट ऑर्डर के विरुद्ध हुआ ग्राहकों ने विकास कार्यों को पूरा करने के लिए किसी विशिष्ट समय-सीमा का आग्रह नहीं किया था।

- **ओवीएल** के मामले में, अनुसंधान और विकास/नवाचार एवं पहल संयुक्त उद्यमों की संबंधित परियोजनाओं के कार्य कार्यक्रम और बजट में अंतर्निहित थे और इन्हें कंपनी की बही/ लेखे में व्यवस्थित रूप से दर्ज नहीं किया गया था।

भारी उद्योग मंत्रालय ने उल्लेख किया (अक्टूबर 2025) कि वर्ष 2021-22 के बाद से एक वर्ष से अधिक की विलंब वाले परियोजनाओं के प्रतिशत में कमी आई है। कोयला मंत्रालय ने उत्तर दिया कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान 24 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उल्लेख किया (नवंबर 2025) कि एनएसआईसी एक विनिर्माण संगठन नहीं था, इसलिए अनुसंधान एवं विकास के तहत व्यय लागू नहीं था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने उल्लेख किया (दिसंबर 2025) कि इरेडा एक वित्तीय संस्थान होने के कारण, अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के लिए अधिदेशित नहीं था। अन्य मंत्रालयों के उत्तरों ने रेखांकित किया कि परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब मुख्य रूप से खरीद और वैधानिक स्वीकृति ; कोविड-19 महामारी के प्रकोप व देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हुई थी तथा परियोजनाएं जटिल प्रकृति की थीं और उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।

4.5.3.2 विश्वविद्यालयों/संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

वर्ष 2019-2024 की अवधि के दौरान 19 सीपीएसई ने 216 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के संबंध में विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ सहयोग किया था। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान विश्वविद्यालयों/संस्थानों के सहयोग से शीर्ष पांच सीपीएसई और नमूने में सम्मिलित अन्य 14 सीपीएसई द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का विवरण नीचे तालिका 4.3 में दिया गया है।

तालिका 4.3: 2019-2024 की अवधि के दौरान शीर्ष पांच सीपीएसई द्वारा विश्वविद्यालयों/संस्थानों के सहयोग से शुरू की गई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का विवरण।

सीपीएसई का नाम	अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	व्यय (₹ करोड़ में)	पूर्ण की गई परियोजनाएँ		चल रही परियोजनाएँ
				समय-सीमा में	अनुसूची से परे	
बीएचईएल	32	14.66	13.26	8	18	6
गेल	27	30.13	28.00	0	11	16
कोल इंडिया	27	195.26	163.88	4	21	2
एचपीसीएल	23	12.93	10.72	14	3	6
नाल्को	17	10.73	10.73	8	9	0
अन्य	90*	172.45	101.26	44	32	14
योग	216	436.16	327.85	78	94	44

* बीईएल से जुड़े 44 परियोजनाओं को हटा दिया गया है क्योंकि पूर्ण हो चुके या प्रगतिरत परियोजनाओं की जानकारी नहीं दी गई थी।

उपरोक्त तालिका 2019-20 से 2023-24 के दौरान विश्वविद्यालयों/संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) परियोजनाओं पर 18 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र⁴⁶ के उद्यमों (बीईएल को छोड़कर) द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या और किए गए व्यय को दर्शाती है। शीर्ष पांच सीपीएसई में चार महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (बीएचईएल, गेल, सीआईएल, एचपीसीएल) और एक नवरत्न कंपनी (नाल्को) सम्मिलित थीं। इन 18 कंपनियों द्वारा शुरू की गई 216 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में से 94 परियोजनाएं (लगभग 43.52 प्रतिशत) विलंब से पूरी हुईं। 78 परियोजनाएं निर्धारित समय के भीतर पूरी हो चुकी थीं और 44 परियोजनाएं अभी भी चल रही थीं।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विश्वविद्यालयों/संस्थानों के सहयोग से इन 18 सीपीएसई द्वारा किया गया ₹327.85 करोड़ का व्यय, चयनित 26 सीपीएसई में से 23 सीपीएसई द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर किए गए योग ₹34,178.99 करोड़ के व्यय का (लगभग एक प्रतिशत) था।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभ्यक्तियाँ पाई गई:

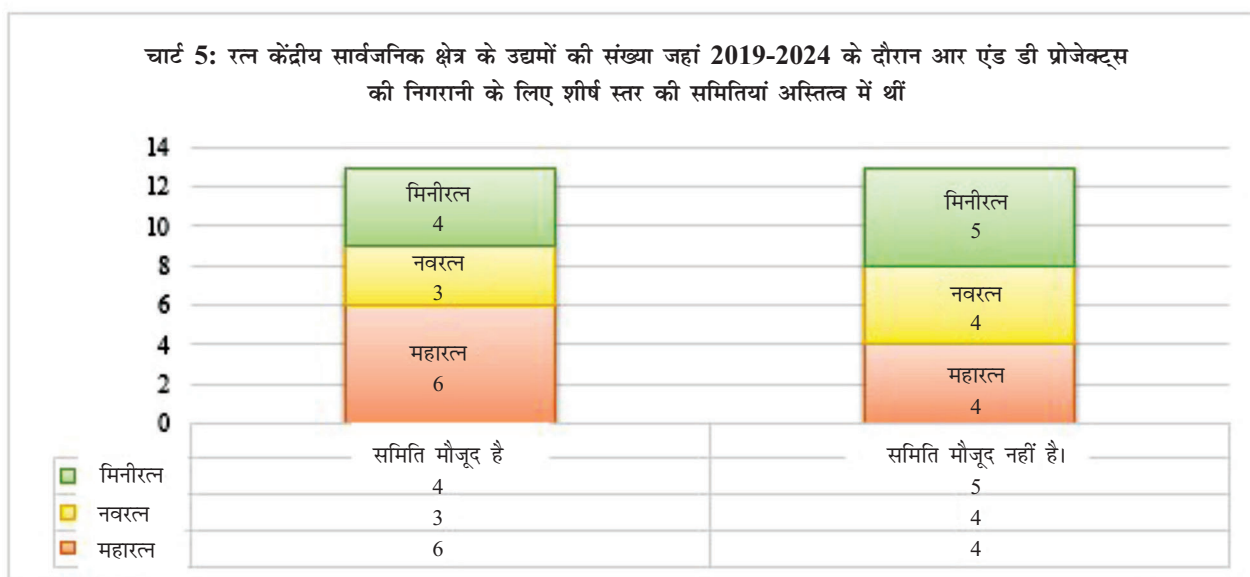
- भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा हाथ में ली गई 32 परियोजनाओं में से 18 परियोजनाएं दो माह से अधिक के विलंब से पूरी हुईं, आठ परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी हुईं और छः परियोजनाओं का पूरा होना अभी (जून 2025 तक) शेष था।
- गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू की गई 27 परियोजनाओं में से 11 परियोजनाएं निर्धारित समय के बाद पूरी हुईं, जिनमें 10 से 29 माह तक का विलंब हुआ। शेष 16 परियोजनाओं का पूरा होना अभी (मार्च 2025 तक) शेष था।
- कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू की गई योग 27 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में से केवल चार परियोजनाएं समय पर पूरी हुईं। 21 परियोजनाएं तीन से 44 माह के विलंब से पूरी हुईं। शेष दो परियोजनाओं का पूरा होना अभी (जून 2025 तक) शेष था।
- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा शुरू की गई 23 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाएं निर्धारित समय के भीतर पूरी हुईं और 3 परियोजनाएं निर्धारित समय के बाद पूरी हुईं। शेष छः परियोजनाओं का पूरा होना अभी (जून 2025 तक) शेष था।
- अन्य सीपीएसई द्वारा शुरू की गई 90 परियोजनाओं (बीईएल को छोड़कर) में से 44 परियोजनाएं समय पर पूरी हुईं, 32 परियोजनाएं निर्धारित समय के बाद एक से 67 माह के विलंब से पूरी हुईं। शेष 14 परियोजनाओं का पूरा होना भी अभी (जून 2025 तक) शेष था। मंत्रालयों के उत्तरों में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि परियोजनाओं को पूरा करने में हुए विलंब का मुख्य कारण खरीद (प्रोक्योरमेंट) और सांविधिक स्वीकृतियां (स्टैच्यूटरी क्लीयरेंस); कोविड-19 महामारी का प्रकोप तथा देशव्यापी लॉकडाउन था तथा परियोजनाएं जटिल प्रकृति की थीं और उनके सामने विभिन्न चुनौतियां आईं।

⁴⁶ महारत्न- सीआईएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, बीएचईएल, सेल, एचपीसीएल, ओआईएल, गेल, आईओसीएल और एचएएल; नवरत्न- नाल्को, एनएमडीसी, अलिमको; मिनीरत्न- बीडीएल, बीसीसीएल, एमडीएनएल, बीईएमएल और एएआई।

4.5.4 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की निगरानी

हालाँकि अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं किसी भी कंपनी के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए लक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए भौतिक और वित्तीय दोनों संदर्भों में, शीर्ष स्तर पर परियोजना के माइलस्टोन्स की कड़ी निगरानी आवश्यक है।

अवधि 2019-2024 के दौरान उन रत्न सीपीएसई की संख्या, जहां अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए शीर्ष स्तर की समितियां अस्तित्व में थीं/अस्तित्व में नहीं थीं, चार्ट 5 में दी गई है:



स्रोत: प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी।

उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि 26 सीपीएसई में से 13 सीपीएसई में शीर्ष/समीक्षा/उप-समिति थी। कुछ सीपीएसई की शीर्ष/समीक्षा/उप-समिति का विवरण नीचे दिया गया है:

- **कोल इंडिया लिमिटेड:** अनुसंधान एवं विकास बोर्ड और शीर्ष समिति में प्रतिष्ठित संस्थानों के स्वतंत्र विशेषज्ञ सम्मिलित हैं। बैठकों का निर्धारण प्रस्तावों की संख्या, वित्तीय परिव्यय और सदस्यों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।
- **हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड:** अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी), अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की समय-समय पर निगरानी के लिए शीर्ष निकाय है। आरएसी की बैठकें हर छः माह में आयोजित की जाती थीं।
- **गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड:** गेल ने आर एंड डी गतिविधियों की उचित और समय-समय पर निगरानी के लिए एक उपयुक्त शीर्ष समूह का गठन किया है, जिसे अनुसंधान सलाहकार परिषद (आरएसी) के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रमुख संस्थानों/प्रयोगशालाओं के पांच बाहरी सदस्य सम्मिलित हैं।

- **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड:** कार्यकारी निदेशकों (ईडी) की एक परियोजना निगरानी समिति अस्तित्व में थी, जो निदेशक (आर एंड डी) को प्रतिवेदन करती थी।
- **भारत कोकिंग कोल लिमिटेड:** बीसीसीएल में एक आर एंड डी समिति का गठन किया गया था जो हर माह चल रही आर एंड डी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है। कोयला मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की निगरानी स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति द्वारा की जाती थी।
- **भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (अलिमको):** विभाग की कार्य योजना से संबंधित गतिविधियों के समन्वय के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया गया था।
- **नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड:** अनुसंधान सलाहकार समिति, आर एंड डी और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रमों की दिशा तय करने में सहायता करती है।
- **ओएनजीसी:** ओएनजीसी के पास एक अनुसंधान एवं विकास समिति है, जिसके अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक हैं।
- **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड:** रक्षा मंत्रालय ने उल्लेख किया (दिसंबर 2025) कि एक बोर्ड स्तर की आर एंड डी समिति थी जिसमें स्वतंत्र और कार्यात्मक निदेशक सम्मिलित थे। इस समिति ने ₹10 करोड़ से अधिक की उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं की निगरानी की। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी योजना विभाग ने समग्र आर एंड डी परियोजनाओं की निगरानी की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शेष 13 सीपीएसई में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की समय-समय पर निगरानी के लिए बोर्ड या शीर्ष समूह की कोई उप-समिति नहीं थी, बल्कि इसके बजाय आर एंड डी प्रमुखों के स्तर पर निगरानी की जा रही थी या कोई निगरानी समिति नहीं थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- उन चार महारत्न सीपीएसई का विवरण जहां समितियां अस्तित्व में नहीं थीं, इस प्रकार है:
 - **भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड:** भारी उद्योग मंत्रालय ने उल्लेख किया (अक्टूबर 2025) कि प्रमुख आर एंड डी परियोजनाओं की समय-समय पर समीक्षा निदेशक (इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास) और निदेशक (औद्योगिक प्रणाली और उत्पाद) द्वारा की जाती थी। इसके अतिरिक्त, शीर्ष स्तर की उत्पाद विकास समिति परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करती है।
 - **नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड:** विद्युत मंत्रालय ने उल्लेख किया (अक्टूबर 2025) कि आर एंड डी परियोजनाओं के लिए डोमेन विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, इसलिए एनटीपीसी शीर्ष/समीक्षा/उप-समिति द्वारा आर एंड डी परियोजनाओं की समीक्षा प्रासंगिक नहीं है।
 - **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड:** इस्पात मंत्रालय ने उल्लेख किया (नवंबर 2025) कि निदेशक (तकनीकी, परियोजनाएं और कच्चा माल) समय-समय पर आर एंड डी गतिविधियों की

समीक्षा करते थे। इसके अतिरिक्त, सीएमडी (सेल) की मासिक समन्वय बैठक के दौरान, सेल के संयंत्रों और इकाइयों की आर एंड डी आवश्यकताओं पर चर्चा की जाती थी और आवश्यकतानुसार आरडीसीआईएस को उपयुक्त कार्य सौंपे जाते थे। इसके अलावा, आरडीसीआईएस के पास आंतरिक और संयंत्र स्तर दोनों पर आर एंड डी परियोजनाओं और कार्यों की समीक्षा के लिए मानक प्रक्रियाएं थीं।

- **ऑयल इंडिया लिमिटेड:** कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की समय-समय पर निगरानी के लिए बोर्ड या शीर्ष समूह की किसी उप-समिति की नियुक्ति नहीं की थी।

➤ उन चार नवरत्न सीपीएसई का विवरण जहां समितियां अस्तित्व में नहीं थीं, इस प्रकार हैं:

- **केंद्रीय भंडारण निगम:** उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उल्लेख किया (नवंबर 2025) कि कॉर्पोरेट कार्यालय में तकनीकी प्रभाग द्वारा आर एंड डी कार्यों की नियमित रूप से निगरानी की जाती थी आर एंड डी कार्यों पर विस्तृत प्रतिवेदन समीक्षा और रिकॉर्ड के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती थी।
- **भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा):** कोई भी आर एंड डी परियोजना निष्पादित नहीं की गई थी और इसलिए कोई आर एंड डी समिति अस्तित्व में नहीं थी।
- **एनएमडीसी:** आर एंड डी गतिविधियों की मासिक समीक्षा कार्यात्मक निदेशक द्वारा की जाती थी और कंपनियों द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा के लिए बोर्ड की उप-समिति को प्रतिवेदन की जाती थी।
- **ओवीएल (ओएनजीसी विदेश लिमिटेड):** प्रबंधन ने उल्लेख किया (जुलाई 2025) कि ओवीएल की प्रत्येक परियोजना इसके संयुक्त संचालन समझौते द्वारा शासित थी, जिसमें एक संचालन समिति (ऑपरेटिंग कमेटी) के गठन का प्रावधान था, जो नवाचारों और पहलों से संबंधित गतिविधियों सहित सभी गतिविधियों के प्रभाव को स्वीकृति, निगरानी और मूल्यांकन करती थी।

➤ उन पांच मिनीरत्न सीपीएसई का विवरण जहां समितियां अस्तित्व में नहीं थीं, इस प्रकार हैं:

- **मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी):** प्रबंधन ने उल्लेख किया (अगस्त 2025) कि विकास/परीक्षण (ट्रायल) आदेशों के विरुद्ध आर एंड डी गतिविधियां शुरू की गई थीं और पूरा होने की कोई विशिष्ट निर्धारित तिथि नहीं थी। कार्यान्वयन, मूल्यांकन, निगरानी परिणामों और तौर-तरीकों के लिए प्रभावी कार्यप्रणाली तय नहीं की गई थी। रक्षा मंत्रालय ने उल्लेख किया (दिसंबर 2025) कि एमडीएनएल (मिधानी) बोर्ड की एक उप-समिति नियुक्त कर रहा है या आवश्यकता के आधार पर आर एंड डी संस्थान/प्रयोगशाला से सहायता ले रहा है।
- **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उल्लेख किया (नवंबर 2025) कि हालांकि एनएसआईसी एक वित्तपोषक (फाइनेंसिंग) संस्थान है, इसलिए

आर एंड डी गतिविधियों में निवेश की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि आर एंड डी में किसी अनिवार्य निवेश की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए बोर्ड स्तर की समिति या किसी शीर्ष समूह द्वारा निगरानी की कोई आवश्यकता नहीं थी।

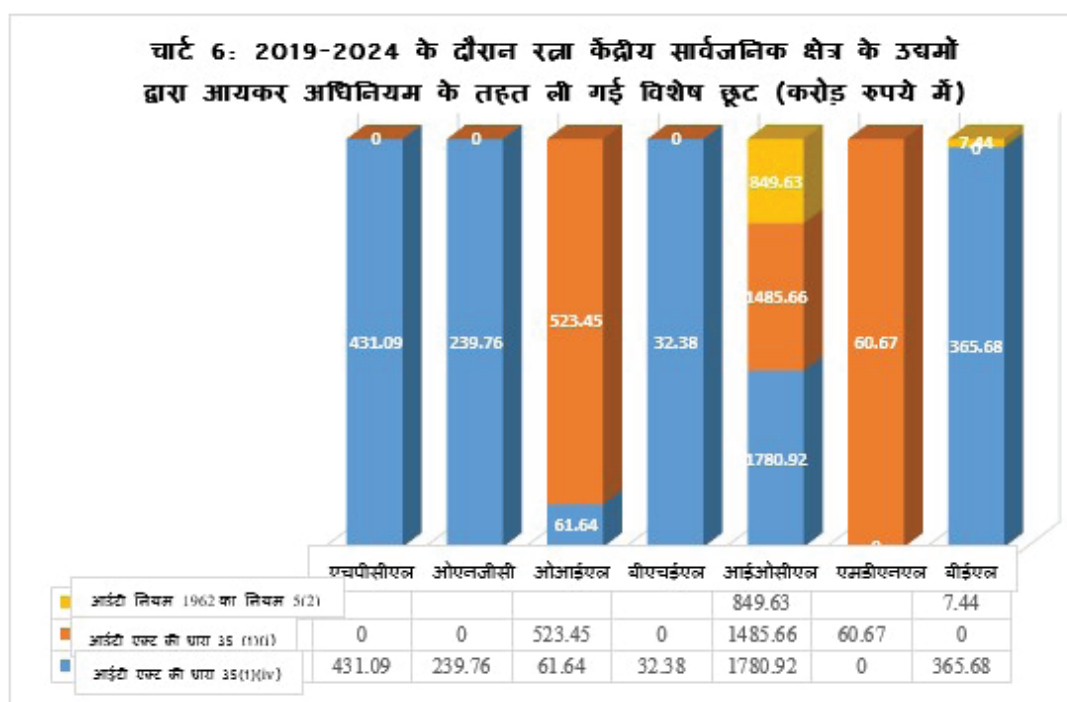
- **टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड:** दूरसंचार विभाग ने उल्लेख किया (अक्टूबर 2025) कि टीसीआईएल ने सीमित उत्पाद नवाचार क्षमता के साथ सेवा-उन्मुख ईपीसी बिजनेस मॉडल पर काम किया और अनुसंधान एवं विकास प्रतिस्पर्धात्मकता का मुख्य चालक नहीं था। इसलिए, कोई आर एंड डी कार्य शुरू नहीं किया गया था और कोई समिति स्थापित नहीं की गई थी।
- **मेकॉन:** कंपनी द्वारा आर एंड डी गतिविधियां शुरू नहीं की गई थीं और कोई समिति स्थापित नहीं की गई थी।
- **भारत डायनेमिक्स लिमिटेड:** बीडीएल की अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) परियोजनाओं की निगरानी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और निदेशक (तकनीकी) द्वारा समय-समय पर की जाती है। आंतरिक समीक्षा समिति (आईआरसी), जिसकी अध्यक्षता मुख्य प्रबंध निदेशक करते हैं और जिसमें सभी कार्यात्मक निदेशक सम्मिलित होते हैं, आर एंड डी योजना और उसके बाद के संशोधनों को अनुमोदन देती है।

4.5.5 अनुसंधान एवं विकास व्यय पर सीपीएसई द्वारा कर लाभ प्राप्त करना

आयकर अधिनियम की धारा 35/आयकर नियमावली के नियम 5(2) के तहत उपलब्ध विशिष्ट छूटें इस प्रकार हैं:

- व्यवसाय से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए राजस्व व्यय पर 100 प्रतिशत की कटौती (आयकर अधिनियम की धारा 35(1) (i))।
- व्यवसाय से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान पर हुए पूंजीगत व्यय पर, जिस वर्ष व्यय किया गया है उसी वर्ष 100 प्रतिशत की कटौती (आयकर अधिनियम की धारा 35(1) (iv))।
- अनुमोदित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और आईआईटी या किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को किए गए भुगतानों के लिए (प्रायोजक को) 150 प्रतिशत की दर से कटौती, बशर्ते यह विशिष्ट निर्देश हो कि उक्त राशि का उपयोग किसी कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा (आयकर अधिनियम की धारा 35 (2क क))।
- स्वदेशी तकनीक के आधार पर संयंत्र और मशीनरी (प्लांट एंड मशीनरी) पर किए गए निवेश के लिए त्वरित मूल्यहास भत्ता (आयकर नियमावली, 1962 का नियम 5(2) (क)(ख))।

सीपीएसई द्वारा आयकर अधिनियम के तहत प्राप्त की गई विशिष्ट छूटों का विवरण चार्ट 6 में दिया गया है:



स्रोत: प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि:

- आयकर अधिनियम के तहत छूट: सीपीएसई द्वारा धारा 35(1)(iv) के अंतर्गत प्राप्त की गई विशिष्ट छूट ₹2,911.47 करोड़ है, जिसमें से सर्वाधिक 61.17 प्रतिशत का लाभ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹1,780.92 करोड़) द्वारा प्राप्त किया गया, जिसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्थान रहा जिसने 14.81 प्रतिशत (₹431.09 करोड़) का लाभ प्राप्त किया।
- ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने आयकर अधिनियम की धारा 35(1)(i) के तहत ₹2,069.78 करोड़ की छूट प्राप्त की थी।
- स्वदेशी तकनीक के आधार पर संयंत्र और मशीनरी (प्लांट एंड मशीनरी) पर किए गए निवेश के लिए त्वरित मूल्यहास भत्ता (आयकर नियमावली, 1962 का नियम 5(2)(क)(ख)) के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्रमशः ₹849.63 करोड़ और ₹7.44 करोड़ का लाभ प्राप्त किया था।

इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मौजूदा हवाई यातायात प्रवाह प्रबंधन (एटीएफएम) प्रणालियों के निष्पादन में सुधार करने और भविष्य के ट्रेजेक्टरी आधारित एटीएफएम को विकसित करने के उद्देश्य से "सिस्टम वाइड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करके 4-डी ट्रेजेक्टरी आधारित हवाई यातायात प्रवाह प्रबंधन प्रणाली" नामक एक अनुसंधान परियोजना के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 35(1)(iv) के तहत ₹11.5 लाख की कर छूट प्राप्त करने में विफल रहा। रक्षा मंत्रालय ने उल्लेख किया (दिसंबर 2025) कि बीडीएल ने आयकर अधिनियम की धारा 115बीए के तहत रियायती कर व्यवस्था का विकल्प चुना था, जो बीडीएल के लिए फायदेमंद

था और वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान आयकर अधिनियम की धारा 35 या नियम 5(2) के तहत छूट या लाभ प्राप्त नहीं किया गया था। शेष 17 सीपीएसई में से, ओएनजीसी (जिसने वर्ष 2019-20 के दौरान कर छूट का दावा किया था) को छोड़कर, पांच⁴⁷ सीपीएसई ने कर छूट के संबंध में 'शून्य' और 12 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों⁴⁸ ने 'लागू नहीं' बताया था।

(ख) अनुसंधान और विकास के लिए आवश्यक पूंजीगत उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों के लिए अस्पताल के अलावा कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा स्थापित इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास इकाइयों के लिए सीमा शुल्क से छूट दी गई है। (अधिसूचना संख्या 24/2007-सीमा शुल्क, दिनांक 01 मार्च 2007, समय-समय पर यथा संशोधित)।

इसके अलावा, उद्योग में सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए किए गए आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। (अधिसूचना संख्या 50/96-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई 1996)।

- 26 सीपीएसई में से, केवल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने क्रमशः ₹270.21 लाख और ₹41.59 लाख की सीमा शुल्क छूट का लाभ उठाया।
- वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान नेत्र (एनटीपीसी की आर एंड डी शाखा) द्वारा ₹9.98 करोड़ मूल्य के विदेशी निर्मित वैज्ञानिक उपकरणों, सहायक उपकरणों, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और उपभोग्य सामग्रियों की, सीधे विदेशी विक्रेता से या भारत में स्थित तीसरे पक्ष के विक्रेता से खरीद में कोई सीमा शुल्क छूट प्राप्त नहीं की गई थी।

नेत्र ने उल्लेख किया कि 2019-2024 के दौरान खरीदे गए योग ₹9.98 करोड़ के विदेशी उपकरणों में से केवल ₹5.70 लाख (0.57 प्रतिशत) मूल्य का एक उपकरण उनके द्वारा सीधे आयात किया गया था। इसलिए, नेत्र द्वारा किसी अन्य आयातक से खरीदे गए आर एंड डी उपकरणों के संबंध में पांच प्रतिशत की रियायती सीमा शुल्क दर लागू नहीं थी। हालांकि, यह आश्वासन दिया गया कि लेखापरीक्षा अवलोकनों को टिप्पण कर लिया गया है और भविष्य में जहां भी संभव होगा, इस पर ध्यान दिया जाएगा।

- बीईएल के प्रबंधन ने उल्लेख किया (नवंबर 2025) कि कंपनी डीएसआईआर के साथ पंजीकृत थी और अधिसूचना संख्या 51/1996 के तहत बुनियादी सीमा शुल्क की रियायती दर का लाभ उठा रही थी।
- ओएनजीसी ने 2019-20 के दौरान सीमा शुल्क के लिए दावा किया था। शेष 21 कंपनियों ने 2019-20 से 2023-24 के दौरान सीमा शुल्क छूट प्राप्त करने के संबंध में 'शून्य या लागू नहीं' सूचित किया।

⁴⁷ एमडीएसएल, बीईएमएल, नाल्को, सीआईएल और एचएएल

⁴⁸ अलिमको, इरेडा, गेल, ओवीएल, टीसीआईएल, एनएसआईसी, एनएमडीसी, मेकॉन, सीडब्ल्यूसी, एनटीपीसी, बीसीसीएल और सेल

4.5.6 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर पेटेंट का पंजीकरण तथा शोध पत्र का प्रकाशन

4.5.6.1 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर पेटेंट का पंजीकरण

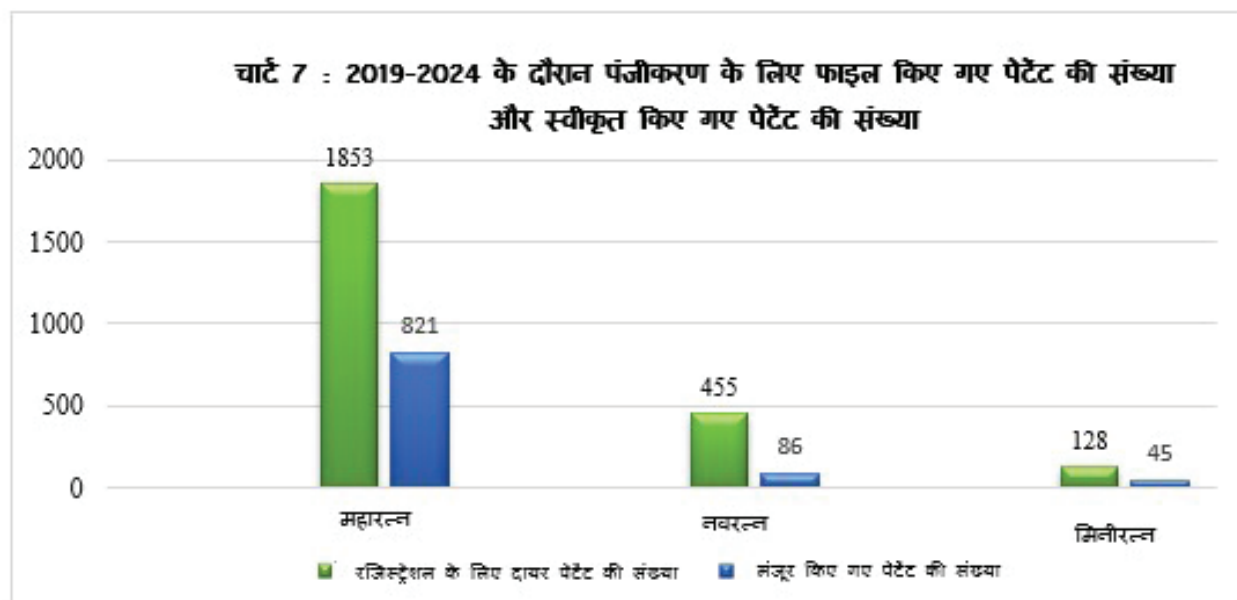
किसी तकनीक, उत्पाद या आविष्कार का पेटेंट किसी कंपनी को दूसरों को इसके निर्माण, उपयोग या बिक्री से बाहर रखने (प्रतिबंधित करने) का अधिकार सुरक्षित करता है। इससे विकास लागत की वसूली करने और निवेश पर प्रतिफल (रिटर्न) प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। पेटेंट दाखिल करने से इस जोखिम को सीमित करने में मदद मिलती है कि उसी विचार पर विकसित तकनीक, उत्पाद या आविष्कार किसी अन्य कंपनी द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान पंजीकरण के लिए दाखिल किए गए पेटेंट की तुलना में स्वीकृत किए गए पेटेंट का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों-वार विवरण तालिका 4.4 और चार्ट 7 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.4: सीपीएसई के हिसाब से रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल किए गए पेटेंट की संख्या और वर्ष 2019 से 2024 के दौरान स्वीकृत किए गए पेटेंट की संख्या

क्रम संख्या	सीपीएसई के नाम	पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल किए गए पेटेंट तालिका इन्वेंशन की संख्या					योग	दिए गए पेटेंट की संख्या	प्रतिशत
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24			
1.	बीएचईएल	133	108	99	76	70	486	251	51.6
2.	कोल इंडिया लिमिटेड	0	1	0	1	1	3	0	0
3.	गेल	3	3	2	6	2	16	6	37.5
4.	एचपीसीएल	51	34	69	89	112	355	165	46.48
5.	एनटीपीसी						25	8	32
6.	ओएनजीसी	10	6	13	11	9	49	15	30.61
7.	सेल	15	14	14	13	17	73	7	9.59
8.	ओआईएल	0	0	0	0	5	5	0	0
9.	एचएएल	6	0	0	34	69	109	1	1
10.	बीईएल	100	86	73	79	108	446	80	17.94
11.	एमडीएसएल	0	0	3	0	0	3	3	100
12.	नाल्को	2	0	0	0	0	2	2	100
13.	एनएमडीसी	2	2	0	0	0	04	1	25
14.	बीडीएल	0	1	1	20	0	22	1	4.55
15.	बीईएमएल	31	10	3	54	6	104	42	40.38
16.	एलिम्को	1	0	1	0	0	02	2	100
17.	आईओसीएल	137	158	221	126	90	732	368	50
	योग						2,436	952	

स्रोत: प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी।

- उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान 17 सीपीएसई द्वारा पंजीकरण के लिए दाखिल किए गए 2436 पेटेंटों में से केवल 952 पेटेंट (39.08 प्रतिशत) ही स्वीकृत किए गए थे। योग 2436 पेटेंट आवेदनों में से 952 स्वीकृत किए गए थे तथा बीएचईएल के 18 आवेदनों, जिन्हें खारिज कर दिया गया था, को छोड़कर शेष आवेदन प्रक्रियाधीन थे।



स्रोत: प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी।

उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि:

- महाराष्ट्र सीपीएसई ने पंजीकरण के लिए 1853 पेटेंट दाखिल किए हैं, जिनमें से 821 पेटेंट (44.31 प्रतिशत) स्वीकृत किए गए।
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पंजीकरण के लिए सबसे अधिक जो कि 732 पेटेंट दाखिल किए, जिनमें से 368 पेटेंट (50.27 प्रतिशत) स्वीकृत किए गए।
- बीएचईएल ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान दूसरा सबसे अधिक जो कि 486 पेटेंट दाखिल किए। हालांकि, 251 पेटेंट स्वीकृत किए गए, जो पंजीकरण के लिए दाखिल किए गए पेटेंटों का लगभग 51.65 प्रतिशत है।
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान तीसरा सबसे अधिक जो कि 446 पेटेंट दाखिल किए, जिसमें से पंजीकरण के लिए दाखिल पेटेंटों के मुकाबले 80 पेटेंट (लगभग 18 प्रतिशत) स्वीकृत किए गए।
- मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड और आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने क्रमशः तीन, दो और दो पेटेंट दाखिल किए और ये सभी पेटेंट स्वीकृत कर दिए गए। इसी प्रकार, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 49 पेटेंट दाखिल किए, जिनमें से 15 पेटेंट (30.61 प्रतिशत) स्वीकृत किए गए।

- दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, अर्थात् कोल इंडिया लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड के मामले में, पंजीकरण के लिए योग 8 पेटेंट दाखिल किए गए थे, लेकिन कोई भी पेटेंट स्वीकृत नहीं हुआ।

इस्पात मंत्रालय ने उल्लेख किया (नवंबर 2025) कि पेटेंट की स्वीकृति एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आमतौर पर इसे दाखिल करने के बाद 5 वर्ष से अधिक का समय लगता है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान स्वीकृत किए गए योग 210 पेटेंट, वर्ष 2019 से पहले के पिछले वर्षों में दाखिल किए गए पेटेंटों का संचयी प्रभाव था। वर्ष 2019-20 और उसके बाद दाखिल किए गए पेटेंट स्वीकृत होने की प्रक्रिया में थे। हालांकि, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान दाखिल किए गए 210 आवेदनों के मुकाबले सात पेटेंट स्वीकृत किए गए थे।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उल्लेख किया (नवंबर 2025) कि हालांकि सीडब्ल्यूसी के कार्य का उद्देश्य आंतरिक प्रक्रिया में सुधार करना था, इसलिए किसी पेटेंट आवेदन की परिकल्पना नहीं की गई थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उल्लेख किया (नवंबर 2025) कि एनबीएफसी होने के नाते, एनएसआईसी किसी भी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का संचालन नहीं कर रहा था, इसलिए इस पैरा में उल्लिखित पेटेंट दाखिल करना लागू नहीं होता है। कोयला मंत्रालय ने उल्लेख किया (अक्टूबर 2025) कि बीसीसीएल 2025 में चार पेटेंट आवेदन दाखिल किए थे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने उल्लेख किया (दिसंबर 2025) कि इरेडा द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय, एमएनआरई के साथ हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता ज्ञापनों के अनुसार, इरेडा के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए 100 अंकों के कुल समझौता ज्ञापन स्कोर में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए कोई विशिष्ट पैरामीटर और कोई विशिष्ट अंक नहीं थे। इसलिए इरेडा ने अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कोई गतिविधि नहीं की थी और न ही शोध पत्र प्रकाशित किए थे और न ही अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कोई पेटेंट दाखिल किए थे। रक्षा मंत्रालय ने उल्लेख किया (दिसंबर 2025) कि मिथानी (एमडीएनएल) ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान 34 पेटेंट दाखिल किए थे, लेकिन वे अनुसंधान एवं विकास से संबंधित नहीं थे। शेष चार सीपीएसई ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान पेटेंट की स्वीकृति के संबंध में 'शून्य' या 'लागू नहीं' होने का उल्लेख किया था।

4.5.6.2 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर शोध पत्रों का प्रकाशन

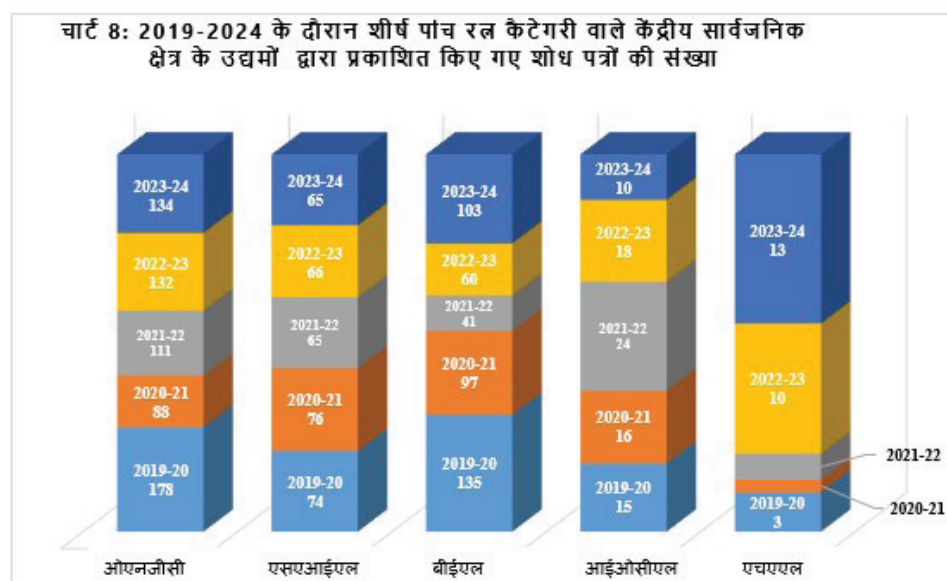
अनुसंधान एवं विकास से प्राप्त उपलब्धियों को शोध पत्रों के रूप में प्रकाशित किया जाता है जो भविष्य के मार्गदर्शन के साथ-साथ ज्ञान साझा करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप लेखक की अनुमति से अन्य इकाई/संगठन द्वारा अनुसंधान का अनुप्रयोग किया जा सकता है और अनुसंधान आउटपुट से रॉयल्टी अर्जित की जा सकती है। हालांकि, यह पाया गया कि अनुसंधान एवं विकास पर महत्वपूर्ण व्यय के बावजूद, शोध पत्रों के प्रकाशन में सीपीएसई का योगदान बहुत उत्साहजनक नहीं था। वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान शोध पत्रों का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों-वार प्रकाशन तालिका 4.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.5: 2019-2024 के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों-वार प्रकाशित हुए शोध पत्रों की संख्या

क्रम संख्या	सीपीएसई के नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	प्रकाशनों की संख्या
1.	बीएचईएल	4	2	2	8	8	24
2.	कोल इंडिया लिमिटेड	0	2	1	0	5	8
3.	गेल	0	0	3	1	5	9
4.	एचपीसीएल	7	7	2	4	2	22
5.	आईओसीएल	15	16	24	18	10	83
6.	एनटीपीसी	1	2	3	8	9	23
7.	ओएनजीसी	178	88	111	132	134	643
8.	सेल	74	76	65	66	65	346
9.	ओआईएल	6	4	1	2	2	15
10.	एचएएल	3	1	2	10	13	29
11.	बीईएल	135	97	41	60	103	436
12.	एमडीएसएल	1	1	0	0	1	3
13.	नाल्को	3	0	1	2	3	9
14.	एनएमडीसी	2	0	3	5	4	14
15.	बीईएमएल	0	0	0	0	4	4
16.	एलिम्को	1	0	1	0	0	2
योग							1,670

स्रोत: प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी।

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान शीर्ष पांच सीपीएसई द्वारा शोध पत्र का प्रकाशन चार्ट 8 में दिखाया गया है:



स्रोत: प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि योग 1,670 प्रकाशित शोध पत्रों में से 1,537 (92.04 प्रतिशत) शोध पत्र इन शीर्ष पांच सीपीएसई द्वारा प्रकाशित किए गए थे। इन पांच सीपीएसई में से, अकेले ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (643) तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (436) का प्रकाशनों में 64.61 प्रतिशत का योगदान था। शेष 11 सीपीएसई ने केवल 02 से 24 शोध पत्र ही प्रकाशित किए। यह भी पाया गया कि समीक्षाधीन 26 सीपीएसई में से 10 सीपीएसई ने कोई भी शोध पत्र प्रकाशित नहीं किया था।

भारी उद्योग मंत्रालय ने उल्लेख किया (अक्टूबर 2025) कि बीएचईएल रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए परियोजनाएं लेता रहा है जो ग्राहकों के साथ गैर-प्रकटीकरण समझौतों द्वारा शासित होती हैं, जो सूचनाओं को साझा करने को प्रतिबंधित करती हैं। मंत्रालय ने आगे उल्लेख किया कि बीएचईएल ने शोध परिणामों के प्रसार के लिए सार्वजनिक डोमेन में कॉपीराइट दाखिल किए हैं।

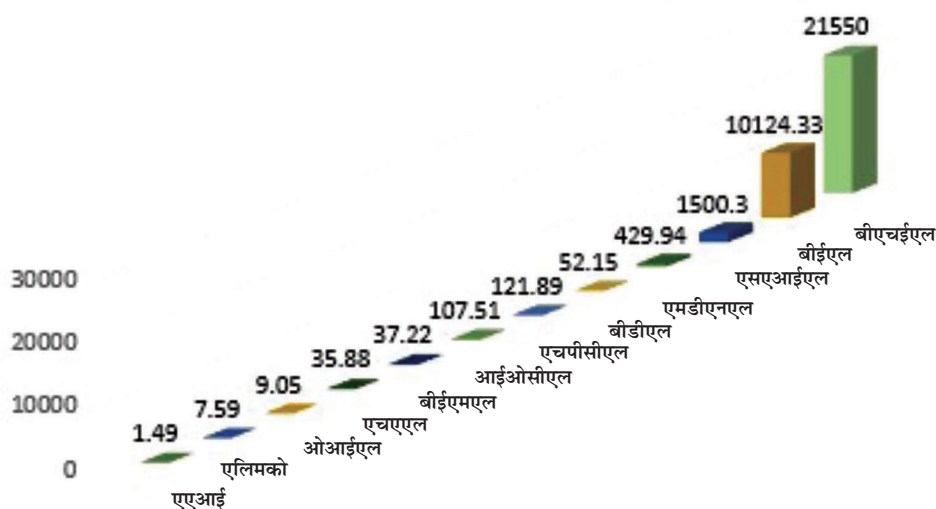
खनन मंत्रालय ने उल्लेख किया (अक्टूबर 2025) कि कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण 2020-22 के दौरान सभी गतिविधियां बाधित रहीं। वर्ष 2022-23 के बाद से प्रकाशनों में सुधार हुआ। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उल्लेख किया (नवंबर 2025) कि सीडब्ल्यूसी के कार्य का उद्देश्य आंतरिक शिक्षण और मौजूदा पद्धति तथा परिचालन प्रथाओं में सुधार करना था, अतः कोई शोध पत्र प्रकाशित नहीं किया गया था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उल्लेख किया (नवंबर 2025) कि एक वित्तपोषक संस्थान होने के नाते, एनएसआईसी कोई अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियां संचालित नहीं कर रहा था, इसलिए इस पैरा में उल्लिखित शोध पत्रों का प्रकाशन उस पर लागू नहीं था। कोयला मंत्रालय ने उल्लेख किया (अक्टूबर 2025) कि सीआईएल द्वारा वित्त पोषित आरएंडडी परियोजनाओं के तीन शोध पत्र वर्ष 2024-25 के दौरान बीसीसीएल द्वारा प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित किए गए थे। रक्षा मंत्रालय ने उल्लेख किया (दिसंबर 2025) कि बीडीएल के मामले में शोध पत्रों के अधिक प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने उल्लेख किया (दिसंबर 2025) कि इरेडा द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय, एमएनआरई के साथ हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता ज्ञापनों के अनुसार, इरेडा के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए 100 अंकों के योग स्कोर में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए कोई विशिष्ट पैरामीटर/अंक निर्दिष्ट नहीं किए गए थे। इसलिए, इरेडा ने अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कोई गतिविधियां संचालित नहीं की थीं और न ही कोई शोध पत्र प्रकाशित किया था या अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कोई पेटेंट दाखिल किया था।

4.5.7 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम नए उत्पादों या काम करने के तरीकों को विकसित करने या पहले से मौजूद उत्पादों या प्रक्रियाओं को बढ़ाने की दिशा में काम करने में मदद करने वाली खोज को करने के प्रयास में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर काफी संसाधन खर्च कर रहे हैं।

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के व्यवसायीकरण से उत्पन्न राजस्व का विवरण चार्ट 9 में दिया गया है।

चार्ट 9-2019-2024 के दौरान रत्न सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्यों के व्यवसायीकरण से मिला राजस्व (₹ करोड़ में)



स्रोत: प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी।

उपर्युक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि चयनित 26 सीपीएसई में से 12 सीपीएसई द्वारा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के व्यवसायीकरण से ₹33,977.35 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया था। इसमें से 93.22 प्रतिशत राजस्व अकेले भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (₹21,550 करोड़) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (₹10,124.33 करोड़) द्वारा उत्पन्न किया गया था।

विद्युत मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2025) कि नेत्रा की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप थीं तथा रणनीतिक प्रकृति की थीं। इसलिए, इस समय उनका व्यवसायीकरण न करना ही उचित समझा गया है। खनन मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2025) कि नाल्को के मामले में, अधिकांश परियोजनाएं प्रयोगशाला स्तर की हैं जो राजस्व अर्जित नहीं करती हैं। उद्यमियों को आमंत्रित करने के लिए नाल्को की वेबसाइट पर नियमित रूप से रुचि की अभिव्यक्ति जारी की गई थी। कोयला मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2025) कि राष्ट्रीय कोयला एवं ऊर्जा केंद्र-चरण 1 की स्थापना की गई है, जिससे भविष्य में व्यवसायीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवंबर 2025) कि हालांकि पॉली पैलेट्स पर होने वाले व्यय से प्रत्यक्ष राजस्व अर्जित नहीं होता है, फिर भी यह लागत से बचने, संपत्तियों के संरक्षण और खाद्यान्न भंडारण के लिए अनिवार्य गुणवत्ता एवं स्वच्छता मानकों के अनुपालन में योगदान देता है। शेष 10 सीपीएसई ने अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के व्यवसायीकरण से प्राप्त राजस्व के संबंध में 'शून्य या लागू नहीं' की सूचना दी।

यह पाया गया कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित 26 'रत्न' सीपीएसई में से 22 सीपीएसई ने कुल ₹34,178.99 करोड़ का अनुसंधान एवं विकास व्यय किया था। इनमें से, बारह सीपीएसई (जिन्होंने

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के व्यवसायीकरण के माध्यम से राजस्व अर्जित किया) ने ₹27,523.89 करोड़ (80.53 प्रतिशत) खर्च किए थे और ऐसी गतिविधियों के व्यवसायीकरण के माध्यम से योग ₹33,977.35 करोड़ का राजस्व अर्जित किया था। शेष 10 सीपीएसई ने अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर ₹6,655.1 करोड़ (19.47 प्रतिशत) खर्च किए थे, लेकिन वे व्यवसायीकरण के माध्यम से राजस्व अर्जित करने में असमर्थ रहे।

4.6 निष्कर्ष

सरकारी दिशानिर्देशों के अभाव में, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम केंद्र सरकार के "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाने के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को शुरू करने हेतु एक विशिष्ट और एक-समान नीति तैयार करने के लिए बाध्य नहीं थे। लेखापरीक्षा के लिए चयनित 26 सीपीएसई में से आधे से अधिक के पास विशिष्ट नीति नहीं थी और इसके बजाय वे गुणवत्ता नीति/ कार्य योजनाओं/ अन्य संबंधित दिशानिर्देशों/ रूपरेखा दस्तावेजों आदि का पालन करते थे। इस क्षेत्र में प्रतिबद्ध फोकस की कमी के कारण चयनित सीपीएसई द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर किए जा रहे व्यय के संबंध में विभिन्न अंतराल सामने आए।

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान, 9 से 13 सीपीएसई (महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न) ने अनुसंधान एवं विकास पर कर-पूर्व लाभ का 2 प्रतिशत से कम खर्च किया, जबकि तीन सीपीएसई (एक नवरत्न और दो मिनीरत्न) ने इस अवधि के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर कोई व्यय नहीं किया। हालांकि चयनित अधिकांश 'रत्न' सीपीएसई के पास अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अच्छी तरह से परिभाषित तंत्र मौजूद था, फिर भी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी की कमी थी। 26 सीपीएसई में से केवल 13 के पास अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की समय-समय पर निगरानी के लिए शीर्ष/समीक्षा/उप-समिति थी। परिणामस्वरूप, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को पूरा करने में 1 से 69 माह तक का अत्यधिक विलंब हुआ। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान 22 सीपीएसई द्वारा शुरू की गई 6,783 परियोजनाओं में से 5,816 परियोजनाएं पूरी की गईं, जिनमें निर्धारित पूर्ण होने की तिथि के बाद पूरी हुई 1,652 परियोजनाएं और 172 ऐसी परियोजनाएं सम्मिलित थीं जो जारी एवं विलंबित थीं।

चयनित 26 सीपीएसई में से 23 सीपीएसई द्वारा किए गए ₹34,178.99 करोड़ के अनुसंधान एवं विकास व्यय का प्रभाव ग्यारह सीपीएसई द्वारा व्यावसायीकरण के माध्यम से उत्पन्न ₹33,977.35 करोड़ के राजस्व में देखा जा सकता है। 16 सीपीएसई द्वारा 1,670 शोध पत्र प्रकाशित करवाए गए और 10 सीपीएसई ने कोई भी शोध पत्र प्रकाशित नहीं किया था। इसके अलावा, 17 सीपीएसई द्वारा पंजीकरण के लिए दायर किए गए 2,436 पेटेंटों में से 952 पेटेंट स्वीकृत किए गए, 1,466 पेटेंट आवेदन प्रक्रियाधीन थे जबकि 18 खारिज कर दिए गए थे।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ देश की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा ऐसी गतिविधियों पर खर्च को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि विकास, रोजगार का सृजन सुनिश्चित किया जा सके और सीपीएसई को वैश्विक स्तर पर चुनौतियों और अवसरों का सामना करने में सक्षम बनाया जा सके।

अनुशंसा:

सरकार सीपीएसई के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर एक विशिष्ट नीति/दिशानिर्देश विकसित करने पर विचार करे।

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और परिकल्पित प्रभाव को प्राप्त करने के लिए उनकी बेहतर निगरानी, निष्पादन और मूल्यांकन सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए।

नवाचार को बढ़ावा देने, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने और दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता में योगदान देने के लिए नियमित कार्यशालाओं, वेबिनार और प्रोत्साहनों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अनुसंधान एवं विकास के रणनीतिक महत्व को पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अध्याय V

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

अध्याय V

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

5.1 परिचय

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यावसायिक जगत की वह सतत प्रतिबद्धता है जिसके तहत वे नैतिक रूप से व्यवहार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान देते हैं और साथ ही स्थानीय समुदाय एवं बड़े पैमाने पर समाज के जीवन स्तर में सुधार लाते हैं। यह सततता, सामाजिक प्रभाव और नैतिकता को समाहित करते हुए अपने हितधारकों और आम जनता के हितों को मान्यता देता है। सीएसआर की अवधारणा 'आपसी समझौता' की विचारधारा पर आधारित है। कंपनियां समाज से कच्चे माल, आदि के रूप में संसाधन लेती हैं। सीएसआर गतिविधियों के कार्य का निष्पादन करके कंपनियां समाज को बदले में कुछ वापस देती हैं।

कानूनी ढांचा: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के माध्यम से भारत में सीएसआर फंडिंग को अनिवार्य बना दिया गया है। यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक कंपनी जिसका निवल मूल्य पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, या टर्नओवर एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, या तुरंत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निवल लाभ पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, वह सीएसआर गतिविधियां संचालित करने के लिए पात्र होगी। अधिनियम ऐसी किसी भी कंपनी के लिए सीएसआर गतिविधियों पर तुरंत पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अनुसार गणना की गई) का कम से कम दो प्रतिशत सालाना खर्च करना अनिवार्य है। जिन गतिविधियों को कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर नीतियों में सम्मिलित किया जा सकता है, उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में सूचीबद्ध किया गया है। अधिनियम के तहत सीएसआर के प्रावधानों का अनुपालन, अर्थात् सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति तैयार करना और सीएसआर गतिविधियों पर निर्धारित राशि खर्च करना, अप्रैल 2014 से लागू हुआ।

फरवरी 2014 में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 (जनवरी 2021 में संशोधित) जारी किए। सीएसआर नीति नियम 1 अप्रैल 2014 से सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू किए गए थे। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने भी अगस्त 2016 में सीपीएसई द्वारा सीएसआर के तहत गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन में पारदर्शिता और यथोचित तत्परता अननुपालन के संबंध में अधिसूचना जारी की थी। दिसंबर 2018 में, डीपीई ने प्रत्येक वर्ष एक विषय-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की दिशा में केंद्रित तरीके से सीएसआर निधि के उपयोग से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए।

5.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं आच्छादन

लेखापरीक्षा ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 212 सीपीएसई में से 59 सीपीएसई का चयन किया था, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 में निवल लाभ अर्जित किया था (डीपीई की सर्वेक्षण प्रतिवेदन में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार), जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई तालिका में है। सर्वेक्षण प्रतिवेदन में प्रकाशित वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ कमाने वाले सभी सीपीएसई का विवरण, जिसमें विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित सीपीएसई की नमूना सूची **अनुलग्नक XXI क** और **XXI ख** में दिया गया है।

तालिका 5.1: चयनित और समीक्षा किए गए सीपीएसई

सीपीएसई का निवल लाभ (₹ करोड़ में)	सीपीएसई की संख्या	चयनित और समीक्षा किए गए सीपीएसई की संख्या	चयनित और समीक्षा किए गए सीपीएसई का प्रतिशत
10500 से अधिक	7	7	100.00
500-10500	45	31*	68.89
500-100	38	08	21.05
100-50	18	04	22.22
50-10	40	04	10.00
10-5	18	02	11.11
5 से कम	46	03	06.52
योग	212	59	35.54 ⁴⁹

*ओवीएल सम्मिलित है।

उपरोक्त 59 सीपीएसई में से एक सीपीएसई अर्थात् ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को सीएसआर नियमों के तहत सीएसआर पर खर्च करने से छूट दी गई थी क्योंकि यह विदेशों में परिचालन कर रही है। इसलिए, लेखापरीक्षा ने 58 सीपीएसई के लिए सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा की थी।

5.3 नियोजन

5.3.1. सीएसआर समिति का गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के अनुसार, अधिनियम की धारा 135 में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करने वाली प्रत्येक कंपनी को बोर्ड की एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

⁴⁹ वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संबंधित ग्रुप के हिसाब से लाभ कमाने वाली सीपीएसई की कुल संख्या 212 थी। हालाँकि, इन 212 सीपीएसई में से, "5 से कम" वाले ग्रुप की 46 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, कंपनीज़ एक्ट 2013 के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में सीएसआर खर्च के लिए योग्य नहीं थीं, क्योंकि या तो वित्त वर्ष 2022-23 में उनका नेट प्रॉफिट ₹5 करोड़ से कम था या वे नुकसान में चल रही थीं। सीएसआर के लिए योग्य इन 166 सीपीएसई में से, लेखापरीक्षा के लिए 56 सीपीएसई को चुना गया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा के दायरे को और व्यापक बनाने के लिए, सीपीएसई के नेट प्रॉफिट की "5 से कम" वाली रेंज से तीन सीपीएसई को चुना गया। इस प्रकार, सीएसआर खर्च के लिए योग्य 166 सीपीएसई में से कुल 59 सीपीएसई को चुना गया, जिसमें सैंपल सिलेक्शन का प्रतिशत 35.54 था।

का गठन करना होगा, जिसमें तीन या अधिक निदेशक सम्मिलित होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होना अनिवार्य है। इसके अलावा, सीएसआर नियम 2014 के नियम 5(1)(i) के अनुसार, धारा 135(1) के अंतर्गत आने वाली एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को अधिनियम की धारा 149(4) के अनुसरण में एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है और कंपनी निदेशक के बिना अपनी सीएसआर समिति रख सकती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित 58 सीपीएसई में से 53 सीपीएसई ने अधिनियम के तहत आवश्यकतानुसार सीएसआर समिति का गठन किया था। पांच⁵⁰ सीपीएसई ने सीएसआर समिति का गठन नहीं किया था।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसीएल) और सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल) को सीएसआर समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (9) के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान उप-धारा (5) के तहत कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि ₹50 लाख से अधिक नहीं थी। इसके अलावा, तीन सीपीएसई अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेडीएफसीएल), नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक) और इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड पांच करोड़ की स्लैब (निवल लाभ) से नीचे थे, इसलिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर व्यय लागू नहीं था।

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने अपने उत्तर (नवंबर 2025) में इस अभ्युक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं दी है।

58 सीपीएसई में से 52 सीपीएसई की समिति में अधिनियम की धारा 135(1) के अनुसार न्यूनतम तीन निदेशक थे। पांच सीपीएसई (एनएफडीसीएल, एसडीसीएल, आईओएल, जेकेडीएफसीएल और नेरामैक के संबंध में यह मानदंड लागू नहीं था। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकॉर) के मामले में समिति में केवल दो स्वतंत्र निदेशक थे।

इसके अलावा, 58 सीपीएसई में से 28 सूचीबद्ध सीपीएसई की सीएसआर समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक था। राइट्स लिमिटेड एक सूचीबद्ध सीपीएसई होने के बावजूद, अपनी सीएसआर समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं रखता था। इसके अलावा, कॉनकॉर, सूचीबद्ध सीपीएसई होने के बावजूद, न तो सीएसआर समिति में न्यूनतम तीन निदेशक होने के मानदंड को पूरा करता था और न ही इसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक था। शेष 28 सीपीएसई असूचीबद्ध होने के कारण इन मानदंडों के अंतर्गत नहीं आते थे।

5.3.2 सीपीएसई द्वारा सीएसआर नीति का प्रारूपण और अनुमोदन

अधिनियम की धारा 135(3) के अनुसार सीएसआर समिति को कंपनी के लिए एक सीएसआर नीति तैयार करनी होगी और बोर्ड को इसकी अनुशंसा करनी होगी, जो धारा 135(4) के अनुसार समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने के बाद इसे स्वीकृति देगा।

⁵⁰ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जम्मू एवं कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी, इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड और नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 58 में से 50 सीपीएसई ने सीएसआर नीति तैयार की थी, जिसे उनके संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित किया गया था **(अनुलग्नक XXII)**।

पांच असूचीबद्ध सीपीएसई –राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सिनियोरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिनियोरिटी इंटररेस्ट ऑफ़ इंडिया, एमएमटीसी लिमिटेड और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के मामले में बोर्ड ने स्वयं सीएसआर नीति तैयार और स्वीकृत की थी। दो असूचीबद्ध सीपीएसई, अर्थात् इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड और नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन ने सीएसआर नीति तैयार नहीं की थी। एक असूचीबद्ध सीपीएसई, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के मामले में, सीएसआर समिति ने एक नीति की अनुशंसा की थी; हालांकि, इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

डीपीई अपने उत्तर (नवंबर 2025) में इस अभ्युक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं दी है।

5.3.3 वार्षिक सीएसआर योजना और बजट

संशोधित सीएसआर नियम 2021 के नियम 5(2) के अनुसार, सीएसआर समिति बोर्ड को एक वार्षिक कार्य योजना तैयार और अनुशंसित करेगी, जिसमें अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों में की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों और कार्यक्रमों के लिए निधि के उपयोग की सूची, निष्पादन के तरीके और तौर-तरीके सम्मिलित होंगे और सीएसआर समिति की अनुशंसा पर वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसी योजना में बदलाव किया जा सकता है।

58 सीपीएसई में से 40 ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर वार्षिक कार्य योजना तैयार की थी, जबकि 18 सीपीएसई ने ऐसी योजना तैयार नहीं की थी। इन सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित पाया गया:

- आठ⁵¹ सीपीएसई पर सीएसआर वार्षिक कार्य योजना लागू नहीं थी। इसके लागू न होने के स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं:

बीसीपीएल के मामले में वर्ष 2023-24 के लिए दायित्व ₹18.77 लाख था और इसे स्वच्छ गंगा और स्वच्छ भारत कोष में स्थानांतरित कर दिया गया था। एनएमडीएफसी का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹132 लाख का दायित्व था। हालांकि, सीपीएसई ने इस राशि को खर्च नहीं किया और पूरी ₹132 लाख की राशि को बिना खर्च किए खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। सीईआरएसए के मामले में चालू वित्त वर्ष के ₹179 लाख के दायित्व को ₹255 लाख (पिछले वर्षों में किए गए अतिरिक्त सीएसआर व्यय) के साथ समायोजित किया गया था, जिसे 2023-24 में समायोजित किया जाना आवश्यक था। इसलिए बीसीपीएल, एनएमडीएफसी और सीईआरएसएआई नामक सीपीएसई ने 2023-24 के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की। इसके अतिरिक्त, चार सीपीएसई अर्थात् एनएफडीसी, बीएचईएल, एमएमटीसी और एनईआरएमएसी के मामले में वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर दायित्व शून्य था। इसलिए, इन चारों सीपीएसई ने वार्षिक कार्य

⁵¹ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, नेशनल माइनोंरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सिनियोरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिनियोरिटी इंटररेस्ट ऑफ़ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड और नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

योजना तैयार नहीं की। इसके अलावा, आईआरडीडी के मामले में, प्रबंधन ने कहा कि सीएसआर वार्षिक कार्य योजना लागू नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में मौजूद आईआरडीडी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII की विभिन्न गतिविधियों के तहत सीएसआर बजट का निर्धारण सम्मिलित था।

- दस⁵² सीपीएसई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की थी।

वार्षिक कार्य योजना बुनियादी ढांचा प्रदान करती है जो लागू सीएसआर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। इस प्रकार, यह पाया गया कि दस कंपनियों ने 2023-24 के लिए सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने में कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के नियम 5 का अनुपालन नहीं किया।

डीपीई ने अपने उत्तर (नवंबर 2025) में इस अभ्युक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं दी है।

5.4 वित्तीय घटक

सीएसआर परिदृश्य में व्यापक बदलाव आए हैं, जो मुख्य रूप से सीएसआर नियम 2014 को लागू करने से प्रेरित हैं। यह निर्देश कंपनियों को सामाजिक विकास के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत आवंटित करने का आदेश देता है और इस आदेश ने विकास पहलों की ओर निर्देशित संसाधनों में भारी वृद्धि की है। परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप सामाजिक चुनौतियों के समाधान पर बढ़ते जोर के साथ सीएसआर गतिविधियों के दायरे और प्रभाव में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। इस संबंध में लेखापरीक्षा के अवलोकनों पर आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है।

5.4.1 निधि का उपयोग

अधिनियम की धारा 135(5) में कहा गया है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करे। डीपीई ने भी सलाह दी (अगस्त 2016) कि सीपीएसई द्वारा वर्ष के लिए आवंटित सीएसआर निधि का पूर्ण उपयोग करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि योग सीएसआर व्यय के दो प्रतिशत की निर्धारित आवश्यकता की तुलना में, जो ₹3,845.90 करोड़ थी और ₹489.30 करोड़ की राशि को समायोजित करने के बाद पिछले वर्ष के ₹1.50 करोड़ के अधिशेष को जोड़ने पर, चयनित सीपीएसई के लिए वास्तविक दायित्व ₹3,366.20 करोड़ था। ₹3,366.20 करोड़ के वास्तविक दायित्व की तुलना में, चयनित सीपीएसई द्वारा 2023-24 की अवधि के लिए किया गया सीएसआर व्यय ₹3,339.80 करोड़ था। (अनुलग्नक XXIII)

⁵² एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, नेशनल हाईवेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड और जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

इस प्रकार, वर्ष के लिए निर्धारित न्यूनतम दायित्व की तुलना में व्यय में ₹26.40 करोड़ की कमी रही। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें देखीं:

- i. 58 सीपीएसई में से 27 सीपीएसई⁵³ ने आवश्यक दायित्व से ₹352.27 करोड़ अधिक खर्च किए, जो 0.00329 प्रतिशत से 771.88 प्रतिशत के बीच था (अनुलग्नक XXIIIक)।
- ii. 58 सीपीएसई में से पांच सीपीएसई⁵⁴ का वर्ष के दौरान सीएसआर दायित्व 'शून्य' था। इन पांच सीपीएसई में से चार सीपीएसई अर्थात् एनएफडीसी, बीएचईएल, एमएमटीसी और नेरामैक का पिछले तीन वर्षों का औसत निवल लाभ ₹5 करोड़ से कम था। सीईआरएसआई के मामले में चालू वर्ष के ₹179 लाख के दायित्व को पिछले वर्षों में किए गए ₹255 लाख के अतिरिक्त सीएसआर व्यय के विरुद्ध समायोजित किया गया था, जिसे 2023-24 में समायोजित किया जाना आवश्यक था। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर व्यय लागू नहीं था (अनुलग्नक XXIIIख)।
- iii. 15 सीपीएसई⁵⁵ द्वारा ₹378.66 करोड़ की कमी की सूचना दी गई थी, जो 1-100 प्रतिशत के बीच थी (अनुलग्नक XXIIIग)।
- iv. 58 सीपीएसई में से 11 सीपीएसई⁵⁶ ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर निधि का निर्धारित न्यूनतम व्यय किया (अनुलग्नक XXIIIघ)।

लेखापरीक्षा ने इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जयपुर के संबंध में औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत की गणना में गलती भी पाई। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जयपुर ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹22.48 लाख निर्धारित किए थे, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 (ठीक पिछला वित्तीय वर्ष) के बजाय 2019-20 के आंकड़ों को ध्यान में रखकर निकाले गए थे। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर निधि के निर्धारण में ₹0.95 लाख का कम आकलन हुआ।

⁵³ नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट्स लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

⁵⁴ नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सिक्यूरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्यूरिटी इंटरैस्ट ऑफ़ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड और नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

⁵⁵ नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनंस कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनंस कंपनी लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड।

⁵⁶ इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड कंट्रोल ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, पावरग्रिड एन एम ट्रांसमिशन लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड ने कहा (मई 2025) कि ठीक पिछले वित्तीय वर्ष (जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर देयता की गणना के लिए आवश्यक है) के लिए लाभ का सही अनुमान लगाने में तकनीकी कठिनाइयों के कारण, आंकड़े नवंबर 2023 तक भी उपलब्ध नहीं थे। नतीजतन, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रावधान के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 तक के उपलब्ध लाभ के आंकड़ों के बैक-वर्किंग पर भरोसा किया, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के शुरुआत में आसानी से उपलब्ध थे। कंपनी ने आगे कहा कि स्थायी जनशक्ति पर प्रतिबंधों ने अनुपालन में बाधा डाली थी, हालांकि तब से एक पूर्णकालिक कंपनी सचिव की भर्ती की जा चुकी है। प्रबंधन ने दोहराया (जून 2025) कि पेशेवर कर्मचारियों की कमी के कारण खातों को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण लाभ के अनुमान उपलब्ध नहीं हो सके। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि अनंतिम खातों के आधार पर अनुमान तैयार किए जा सकते थे।

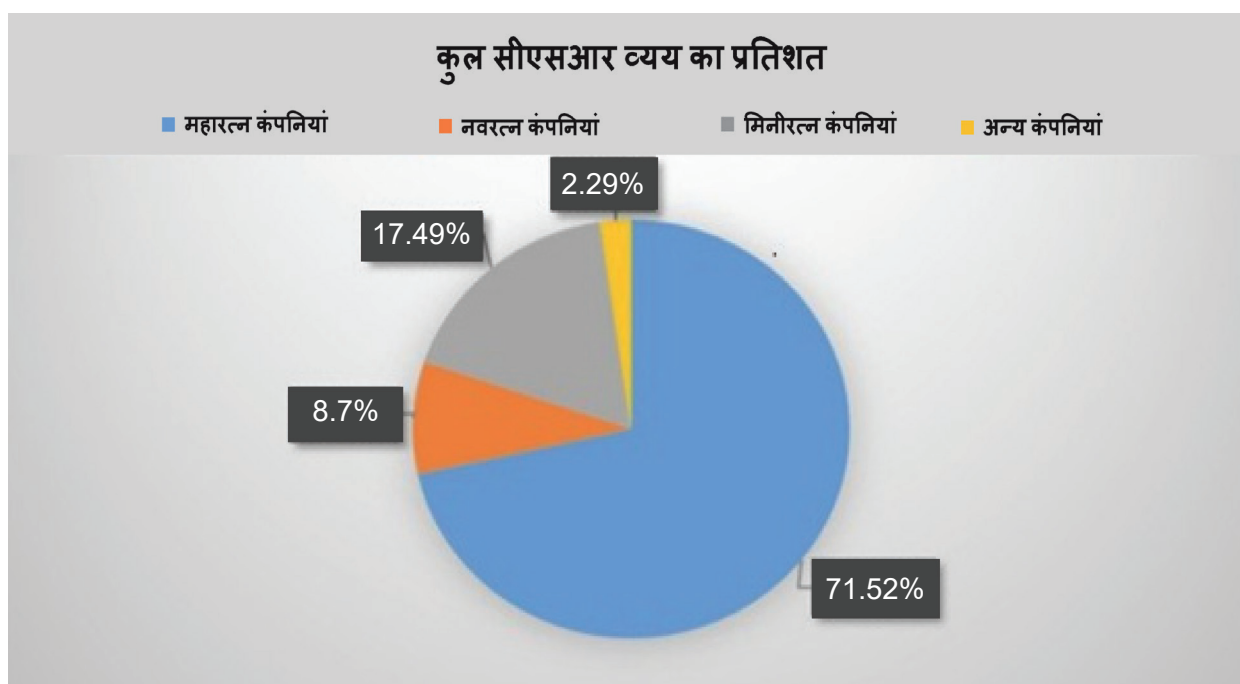
डीपीई ने अपने उत्तर (नवंबर 2025) में इस टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं दी है।

5.4.2 श्रेणीवार और मंत्रालयवार सीएसआर व्यय

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 58 सीपीएसई के श्रेणीवार सीएसआर व्यय का सारांश नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। कंपनीवार व्यय का विवरण *अनुलग्नक XXIV* में प्रदान किया गया है।

तालिका 5.2: श्रेणीवार सीएसआर व्यय

श्रेणी	सीपीएसई की संख्या	सीएसआर व्यय (₹ करोड़ में)	योग सीएसआर व्यय का प्रतिशत (% में)
महारत्न कंपनियां	10	2,388.69	71.52
नवरत्न कंपनियां	12	290.56	8.70
मिनीरत्न कंपनियां	18	584.22	17.49
अन्य कंपनियां	18	76.33	2.29
योग	58	3,339.80	100



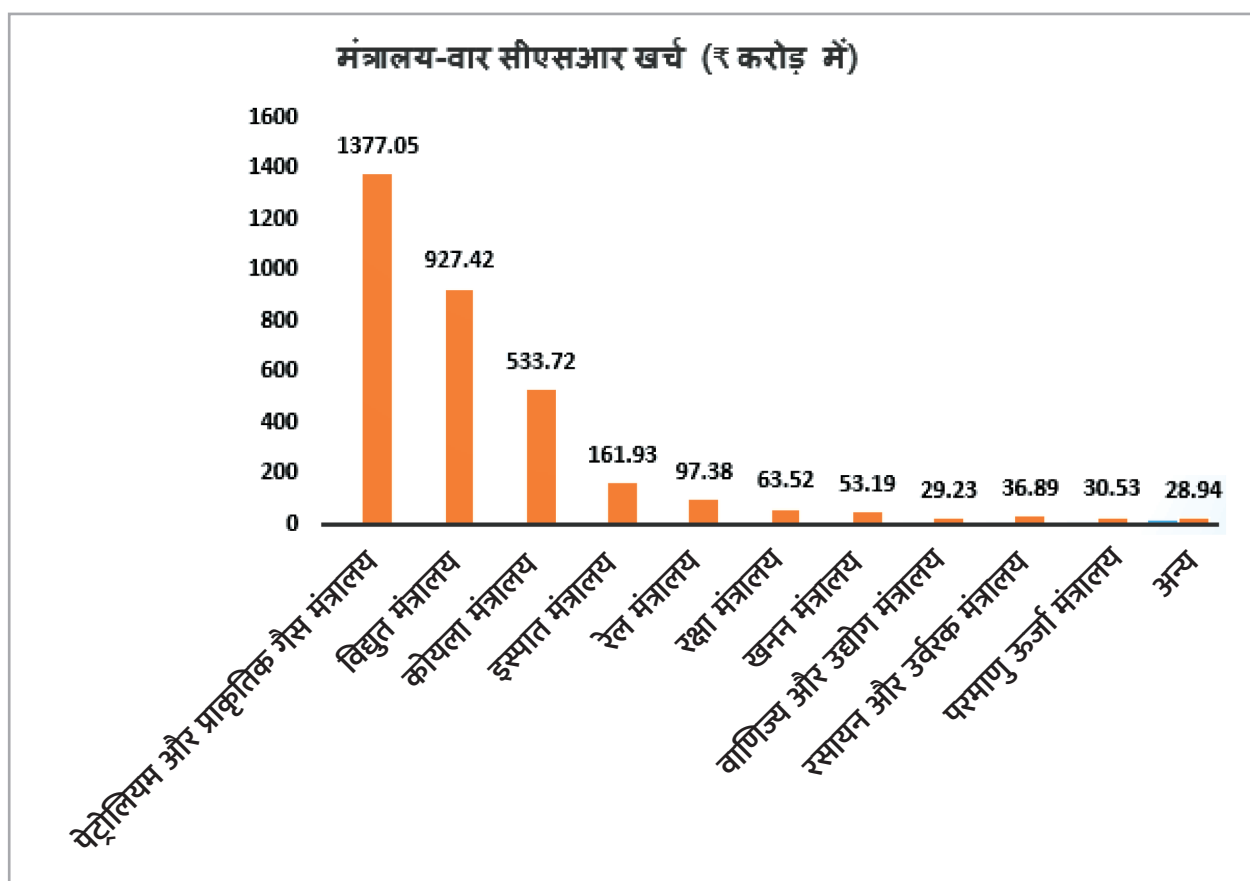
विभिन्न मंत्रालयों के तहत चुने गए 58 सीपीएसई में से, सीएसआर पर सबसे अधिक व्यय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत सीपीएसई (छः सीपीएसई, ₹1377.05 करोड़) द्वारा किया गया, इसके बाद विद्युत मंत्रालय (आठ सीपीएसई, ₹927.42 करोड़) और कोयला मंत्रालय (छः सीपीएसई, ₹533.72 करोड़) का स्थान रहा।

सबसे कम सीएसआर खर्च भारी उद्योग मंत्रालय (दो सीपीएसई, ₹0.20 करोड़) द्वारा किया गया। मंत्रालय-वार सीएसआर खर्च तालिका 5.3 में दिया गया है (*अनुलग्नक XXV*)।

तालिका 5.3: मंत्रालयवार/विभागवार सीएसआर व्यय

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सीपीएसई की संख्या	सीएसआर व्यय (₹ करोड़ में)
1.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	6	1,377.05
2.	विद्युत मंत्रालय	8	927.42
3.	कोयला मंत्रालय	6	533.72
4.	इस्पात मंत्रालय	1	161.93
5.	रेल मंत्रालय	6	97.38
6.	रक्षा मंत्रालय	5	63.52
7.	खनन मंत्रालय	2	53.19
8.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	3	29.23
9.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	3	36.89

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग	सीपीएसई की संख्या	सीएसआर व्यय (₹ करोड़ में)
10.	परमाणु ऊर्जा मंत्रालय	3	30.53
11.	अन्य ⁵⁷	15	28.94
	योग	58	3,339.80



डीपीई ने अपने उत्तर (नवंबर 2025) में इस अभ्युक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं दी है।

5.4.3 सर्वाधिक व्यय करने वाले सीपीएसई

2023-2024 में 58 सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर योग व्यय ₹3,339.80 करोड़ था। ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड (ओएनजीसी) ने ₹634.57 करोड़ का सबसे अधिक सीएसआर व्यय किया (योग सीएसआर व्यय का 19 प्रतिशत)। इसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ₹457.71 करोड़ (13.70 प्रतिशत) और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ₹330.48 करोड़ (9.90 प्रतिशत) के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। ₹3,339.80 करोड़ के योग सीएसआर व्यय के मुकाबले, इन तीन सीपीएसई का योग ₹1,422.76 करोड़ के साथ 42.60 प्रतिशत हिस्सा था (अनुलग्नक XXVI)।

⁵⁷ बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा; आयुष; वित्त; भारी उद्योग; अल्पसंख्यक मामले; सड़क और परिवहन; जनजातीय मामले; पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास; सूचना और प्रसारण; तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय (कुल 11 मंत्रालय); इसके अलावा, सूचना और प्रसारण, अल्पसंख्यक मामलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाली सीपीएसई ने सीएसआर पर 'शून्य' खर्च किया।

डीपीई ने अपने उत्तर (नवंबर 2025) में इस टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं दी है।

5.4.4 व्यय न की जाने वाली राशि का अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के अनुसार, किसी कंपनी द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में शुरू की गई किसी चल रही परियोजना के तहत उप-धारा (5) के अंतर्गत अप्रयुक्त रह गई कोई भी राशि, जो निर्धारित शर्तों को पूरा करती है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर कंपनी द्वारा किसी भी अनुसूचित बैंक में उस वित्तीय वर्ष के लिए इस निमित्त खोले जाने वाले एक विशेष खाते में स्थानांतरित की जाएगी, जिसे 'अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाता' कहा जाएगा। धारा 135(5) के अनुसार जब तक कि बिना खर्च की गई राशि उप-धारा (6) में संदर्भित किसी चल रही परियोजना से संबंधित न हो, ऐसी अप्रयुक्त राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकन किया।

- i. 58 सीपीएसई में से 18 सीपीएसई⁵⁸ के पास वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में ₹517.48 करोड़ की अप्रयुक्त राशि थी। इन 18 सीपीएसई ने निर्धारित समय के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार शेष अप्रयुक्त सीएसआर बजट को या तो अप्रयुक्त सीएसआर खाते में या अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट कोष में स्थानांतरित कर दिया।
- ii. इन 18 सीपीएसई में से चार सीपीएसई⁵⁹ ने अप्रयुक्त राशि को अप्रयुक्त सीएसआर खाते और अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट कोष दोनों में स्थानांतरित किया (अनुलग्नक XXVII)।

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के नियम 4 (5) के अनुसार, "कंपनी का बोर्ड खुद को संतुष्ट करेगा कि इस प्रकार संवितरित धन का उपयोग उसी उद्देश्य और तरीके से किया गया है जैसा कि उसके द्वारा अनुमोदित किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय का प्रमाण पत्र देगा।"

लेखापरीक्षा ने हालांकि जम्मू-कश्मीर वित्तीय विकास निगम लिमिटेड (जेकेएफडीसीएल) के मामले में पाया कि बोर्ड को संतुष्ट करने के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए संवितरित निधि के उपयोग का सीएफओ प्रमाण पत्र बोर्ड की स्वीकृति के लिए सीएसआर पर वार्षिक प्रतिवेदन रखते समय बोर्ड की बैठक में नहीं रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त नियमों का उल्लंघन हुआ।

जेकेएफडीसीएल ने उत्तर में इस अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (जून 2025) कि सीएफओ प्रमाण पत्र की प्रस्तुति, जो बोर्ड के अनुमोदन के लिए थी, अनजाने में छूट गई थी और तत्काल

⁵⁸ नेशनल माइनोंरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड।

⁵⁹ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

अनुपालन का आश्वासन दिया।

इसके अलावा, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने के लिए ₹22.47 लाख की राशि निर्धारित की गई थी, जिसमें से प्रबंधन ने सीएसआर गतिविधियों पर ₹9.45 लाख खर्च किए। शेष राशि ₹13.02 लाख प्रबंधन द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में बैंक में जमा की गई थी।

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ने कहा कि उपयुक्त परियोजनाएं नहीं मिलीं, जिसके परिणामस्वरूप कम व्यय हुआ। हालांकि, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर निधि के लिए समर्पित खाता नहीं खोला। इस प्रकार, कंपनी ने अप्रयुक्त राशि के प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) और 135(6) के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ने कहा कि कंपनी का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि सीएसआर निधि विशेष रूप से सीएसआर उद्देश्यों के लिए समर्पित हों। बैंक स्टेटमेंट पुष्टि करते हैं कि उपयोग किए जाने तक धन फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा गया था, और ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रकटीकरण (टिप्पण नंबर 32.6) इसका समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त, अर्जित ब्याज का उपयोग सीएसआर उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा, जो विधि के अनुरूप है और जिम्मेदार निधि प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। प्रबंधन ने आगे कहा (जून 2025) कि कंपनी ने बैंक से फिक्स्ड डिपॉजिट पर ग्रहणाधिकार बनाने का अनुरोध किया है, यह हवाला देते हुए कि इसका उपयोग केवल सीएसआर उद्देश्य के लिए किया जाएगा। एक बार लियन बन जाने के बाद, बैंक द्वारा एफडी केवल कंपनी द्वारा प्रमाणित लियन उद्देश्य की संतुष्टि पर ही जारी की जाएगी।

प्रबंधन ने दावा किया कि बिना खर्च की गई सीएसआर राशि को भविष्य के व्यय के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा गया था, जिसका बैलेंस शीट में उचित प्रकटीकरण किया गया था।

हालांकि, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर निधि को एक समर्पित अप्रयुक्त सीएसआर खाते में जमा करना आवश्यक है।

डीपीई ने अपने उत्तर (नवंबर 2025) में कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 और सीएसआर नियमों के तहत अप्रयुक्त सीएसआर राशि से निपटने के लिए केवल दो तरीके निर्धारित हैं। पहला यह है कि यदि राशि किसी सीएसआर परियोजना को आवंटित की गई है, तो 30 दिनों के भीतर राशि को अप्रयुक्त सीएसआर खाते में जमा किया जाए और दूसरा यह है कि यदि वित्तीय वर्ष के अंत में राशि किसी सीएसआर परियोजना को आवंटित नहीं की गई है, तो 180 दिनों के भीतर अनुसूची VII में उल्लिखित किसी भी कोष में राशि जमा की जाए।

उपरोक्त सीपीएसई द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) और (6) के अननुपालन पर डीपीई का उत्तर मौन है।

5.4.5 प्रशासनिक उपरि व्यय

सीएसआर नियम 2021 के नियम 7(1) के अनुसार, प्रशासनिक उपरिशीर्ष व्यय वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के योग सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ष 2020-21 के बाद से प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के लिए उस वित्तीय वर्ष के योग सीएसआर व्यय का अतिरिक्त पाँच

प्रतिशत या ₹50 लाख, जो भी कम हो, खर्च करने की अनुमति दी गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2023-24 के दौरान 29 सीपीएसई⁶⁰ ने प्रशासनिक उपरिशीर्ष पर ₹112.03 करोड़ और 20 सीपीएसई⁶¹ ने प्रभाव मूल्यांकन पर ₹7.47 करोड़ खर्च किए (*अनुलग्नक XXVIII*)। इसके अलावा, 17 सीपीएसई ने प्रशासनिक उपरिशीर्ष के साथ-साथ प्रभाव मूल्यांकन दोनों पर खर्च किया था।

लेखापरीक्षा ने एनटीपीसी द्वारा किट और प्रशासनिक ओवरहेड्स पर अतिरिक्त व्यय देखा। पूरक समझौते की शर्तों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय तीरंदाजी टीमों को किट प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष ₹25 लाख (तीन वर्षों में योग ₹75 लाख) आवंटित किए जाने थे। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि किट के लिए ₹129.02 लाख संवितरित किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्वीकृत सीमा से ₹54.02 लाख अधिक व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त, नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट (एनआरएटी) और नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप (एनएसी) के आयोजन की लागत के ऊपर और अतिरिक्त आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएआई) द्वारा दावा किए गए प्रशासनिक खर्चों के लिए ₹123.80 लाख की राशि का भुगतान किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2020-21 के दौरान किए गए ₹30.14 लाख अनजाने में किट व्यय के रूप में वर्गीकृत किए गए थे, जबकि यह वास्तव में प्रशासनिक लागतों से संबंधित है। एएआई ने गलती स्वीकार कर ली है और आगामी यूसी में इसे सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। किटिंग पर वास्तविक व्यय ₹99.86 लाख है।

डीपीई ने उत्तर (नवंबर 2025) में स्वीकार किया कि प्रशासनिक उपरिशीर्ष की गणना अनुदान देने वाले द्वारा किए गए व्यय से की जानी चाहिए और स्वीकृत परियोजनाओं से कोई भी राशि इस गणना में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए।

5.4.6 सामान्य विषय पर डीपीई दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

डीपीई ने हर वर्ष विषय-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की ओर केंद्रित तरीके से सीएसआर निधि के उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए (दिसंबर 2018) और दिशानिर्देशों में सामान्य विषय पर वार्षिक सीएसआर व्यय का लगभग 60 प्रतिशत परिकल्पित किया गया था और आकांक्षी जिलों में व्यय करने को प्राथमिकता दी जानी थी। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

⁶⁰ नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आई आर ई अल (इंडिया) लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

⁶¹ राइट्स लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

i. वर्ष 2023-24 के लिए, डीपीई द्वारा जारी दिनांक 24 अप्रैल 2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों के लिए चुनी गई सामान्य विषय 'स्वास्थ्य और पोषण' थी। 58 सीपीएसई में से, 32 सीपीएसई⁶² सामान्य विषय पर निर्धारित 60 प्रतिशत सीएसआर व्यय का लक्ष्य हासिल करने में सक्षम रहे। हालांकि, इन 32 सीपीएसई में से आठ ने खर्च किए गए वास्तविक प्रतिशत को निर्दिष्ट नहीं किया।

ii. अठारह सीपीएसई⁶³ ने लक्ष्य से कम सीएसआर व्यय किया। हालांकि, इन 18 सीपीएसई में से दो ने वास्तविक प्रतिशत निर्दिष्ट नहीं किया।

iii. तीन सीपीएसई (इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड, एआईईएसएल और सीटीयूआईएल) ने पूरी राशि अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट कोष में स्थानांतरित कर दी और पांच सीपीएसई⁶⁴ के संबंध में यह मानदंड लागू नहीं था। एनएफडीसी, एमएमटीसी, नेरामैक और बीएचईएल के मामले में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर दायित्व शून्य था और सीईआरएसएआई के मामले में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹179 लाख के सीएसआर दायित्व को वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹255 लाख द्वारा समायोजित कर दिया गया था। इसलिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कोई सीएसआर व्यय नहीं हुआ (अनुलग्नक XXIX)।

डीपीई ने उत्तर (नवंबर 2025) में कहा कि हालांकि डीपीई के कार्यालय ज्ञापन में "लगभग 60 प्रतिशत" का उल्लेख है, इसलिए इस संबंध में उचित विचलन पर विचार किया जा सकता है।

यद्यपि "उचित विचलन" शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेखापरीक्षा ने पहले ही इस प्रावधान पर ध्यान दिया है तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का आकलन करते समय पांच प्रतिशत का उचित विचलन लागू किया है।

नीति आयोग ने पांच विभिन्न क्षेत्रों में 49 प्रमुख निष्पादन संकेतकों के आधार पर उनके सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार करने के लिए विभिन्न राज्यों में 112 सबसे कम विकसित जिलों (आकांक्षी जिलों) की पहचान की। आकांक्षी जिलों में सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार था:

⁶² नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल हाईवेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनंस कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड, नेशनल माइनोंरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनंस कॉर्पोरेशन, जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूरैनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

⁶³ इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईआरआईएल (इंडिया) लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।

⁶⁴ नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सिक्युरिटाइज़ेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्युरिटी इंटररेस्ट ऑफ़ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड।

- सैंतीस सीपीएसई ने एक सामान्य विषय पर आकांक्षी जिलों में सीएसआर व्यय (₹277.20 करोड़) किया जो योग सीएसआर व्यय (₹3,339.80 करोड़) का 8.30 प्रतिशत है।
- सामान्य विषय पर आकांक्षी जिलों में अधिकतम सीएसआर व्यय ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड (₹80.96 करोड़) द्वारा किया गया, इसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹47.26 करोड़) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹30.93 करोड़) का स्थान रहा।

झारखंड के आकांक्षी जिलों को ₹42.18 करोड़ के सीएसआर व्यय का अधिकतम ध्यान मिला। इस राज्य में अधिकतम व्यय ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड (₹14.97 करोड़) द्वारा किया गया, इसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹12.43 करोड़) का स्थान रहा (अनुलग्नक XXIXक)।

5.5 परियोजना कार्यान्वयन

5.5.1 आवश्यकता आकलन के संचालन के आधार पर सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों का चयन

डीपीई ने अगस्त 2016 के अपने कार्यालय जापन में कहा था कि हितधारकों को चुनने का आधार और उनकी भागीदारी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इस स्पष्टता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि चयनित सीएसआर गतिविधियां/परियोजनाएं उन प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं। इस संबंध में, यह पाया गया कि:

- 58 सीपीएसई में से 19 सीपीएसई⁶⁵ ने सभी 3,208 परियोजनाओं के संबंध में सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों की पहचान के लिए आधारभूत सर्वेक्षण /आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन किए थे (अनुलग्नक XXX)।
- आठ सीपीएसई⁶⁶ ने 198 परियोजनाओं/गतिविधियों के संबंध में आधारभूत सर्वेक्षण/आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन नहीं किए (अनुलग्नक XXX)।
- नौ सीपीएसई⁶⁷ ने आधारभूत सर्वेक्षण के साथ 562 परियोजनाएं और बिना आधारभूत सर्वेक्षण के 307 परियोजनाएं शुरू कीं (अनुलग्नक XXX)।

⁶⁵ पावरग्रिड एन एम ट्रांसमिशन लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, आई आर ई एल (इंडिया) लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एन अल सी इंडिया लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, आर ई सी लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एन टी पी सी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

⁶⁶ बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल माइनोंरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनंस कॉर्पोरेशन, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ईसीजीसी लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

⁶⁷ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

- iv. ग्यारह सीपीएसई⁶⁸ ने कोई परियोजना शुरू नहीं की **(अनुलग्नक XXX)**।
- v. शेष 11 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों⁶⁹ में से, नौ सीपीएसई पर आधारभूत सर्वेक्षण लागू नहीं था, एक सीपीएसई ने 'सेल की नीति के अनुसार' उल्लेख किया और एक सीपीएसई अर्थात् इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने डेटा प्रस्तुत नहीं किया **(अनुलग्नक XXX)**।

5.5.2 सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन की विधि

कंपनी (सीएसआर) नियम 2014 का नियम 4 विशेष रूप से उस तरीके से संबंधित है जिससे अधिनियम की धारा 135 के तहत सीएसआर गतिविधि की जानी है। बोर्ड सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित अपनी सीएसआर गतिविधियों को एक पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी या अधिनियम की धारा 8 के तहत कंपनियों के माध्यम से या अन्यथा करने का निर्णय ले सकता है।

58 सीपीएसई के लिए उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1,806 परियोजनाओं के कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्षतः/इन-हाउस था और 4,063 परियोजनाओं को सरकारी/बाहरी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, सोसाइटी के माध्यम से निष्पादित किया गया था **(अनुलग्नक XXXI)**।

- चार सीपीएसई ने इन-हाउस परियोजनाएं शुरू कीं; **(अनुलग्नक XXXIक)**
- छः सीपीएसई ने सीएसआर परियोजनाओं को बाहरी एजेंसियों को आउटसोर्स किया; **(अनुलग्नक XXXIख)**
- बत्तीस सीपीएसई ने इन-हाउस परियोजनाओं के साथ-साथ बाहरी एजेंसियों को आउटसोर्स की गई सीएसआर परियोजनाएं दोनों शुरू की हैं **(अनुलग्नक XXXIग)** और
- नौ सीपीएसई ने कोई परियोजना नहीं की **(अनुलग्नक XXXIघ)**
- शेष सात सीपीएसई में से, छः सीपीएसई पर मानदंड लागू नहीं थे और सेल के लिए यह कंपनी की नीति के अनुसार था **(अनुलग्नक XXXIड)**।

बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित 4,124 परियोजनाओं में से, सीपीएसई ने 944 परियोजनाओं के संबंध में निविदा का सहारा लिया था; नामांकन आधार पर 2,361 परियोजनाएं और 806 परियोजनाएं या तो सरकारी एजेंसियों/संस्थानों, स्थानीय निकायों/समुदाय-आधारित संगठनों के माध्यम से या एनजीओ/कार्यान्वयन एजेंसियों आदि से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर शुरू की गई थीं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच⁷⁰ सीपीएसई ने बाहरी एजेंसियों द्वारा की गई योग परियोजनाओं/गतिविधियों की अलग संख्या (4063) और उसका प्रदान किया गया विवरण (4124) प्रस्तुत किया है।

⁶⁸ सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूरिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्युरिटी इंजिनेरिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्युरिटी इंटररेस्ट ऑफ इंडिया, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड।

⁶⁹ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, नेशनल हाईवेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।

⁷⁰ राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

इसलिए, पांच सीपीएसई की 61 परियोजनाओं/गतिविधियों का मिलान होना बाकी है।

योग 55 सीपीएसई ने नामांकन आधार पर 2,361 परियोजनाएं प्रदान कीं जो एक विवेकपूर्ण प्रथा नहीं है क्योंकि नामांकन के आधार पर अनुलग्नक देना केवल असाधारण और अपरिहार्य परिस्थितियों में ही होना चाहिए, जैसे कि आपातकाल के दौरान, जब केवल एक ही स्रोत से खरीद संभव हो, या जब किसी आपूर्तिकर्ता के पास विशेष अधिकार हों, जैसा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों में विस्तृत है। इस पद्धति को एक प्रतिबंधात्मक प्रथा माना जाता है जो प्रतिस्पर्धा को समाप्त करती है।

5.5.3 फोकस क्षेत्र: अधिकतम और न्यूनतम सीएसआर खर्च वाले फोकस क्षेत्र

स्वास्थ्य देखभाल को ₹1,550.09 करोड़ के खर्च के साथ अधिकतम ध्यान मिला जो योग व्यय जो कि ₹3,489.81 करोड़⁷¹ का 44.42 प्रतिशत है। अगला सबसे अधिक व्यय (₹823.63 करोड़) शिक्षा पर था जो योग व्यय का 23.60 प्रतिशत है। सबसे कम ध्यान वाले क्षेत्र आपदा प्रबंधन के लिए योगदान/कोष (₹11.99 करोड़) और विज्ञान आदि में इनक्यूबेटर या अनुसंधान और विकास परियोजना (₹14.54 करोड़) थे (अनुलग्नक XXXII)।

अनुसूची VII के अनुसार शीर्ष चार मदों जो कि स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना (₹1550.09 करोड़), शिक्षा को बढ़ावा देना (₹823.63 करोड़), ग्रामीण विकास (₹285.04 करोड़) और पर्यावरण (₹242.13 करोड़) में से:

- i. आईओसीएल स्वास्थ्य देखभाल पर सबसे अधिक खर्च करने वाला (₹290.01 करोड़) था,
- ii. ओएनजीसी शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला (₹253.10 करोड़) था,
- iii. एनसीएल ग्रामीण विकास के मामले में सबसे अधिक खर्च करने वाला (₹80.75 करोड़) था और
- iv. ओएनजीसी पर्यावरण के मामले में सबसे अधिक खर्च करने वाला (₹60.16 करोड़) था।

डीपीई (नवंबर 2025) ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि सीएसआर व्यय का बड़ा हिस्सा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डीपीई द्वारा निर्धारित सामान्य विषय जो कि स्वास्थ्य और पोषण पर होना चाहिए।

5.5.4 स्थानीय क्षेत्र

अधिनियम की धारा 135(5) में प्रावधान है कि सीपीएसई सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि खर्च करने के लिए उस स्थानीय क्षेत्र और उसके आस-पास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगे जहां वे काम करते हैं। 58 सीपीएसई के संबंध में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 41 सीपीएसई ने अपनी सीएसआर नीति में स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित किया, 13 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों⁷² ने अपनी सीएसआर नीति में स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया और चार सीपीएसई के लिए यह लागू नहीं

⁷¹ इसमें पिछले वर्षों की आगे लाई गई राशि में से खर्च की गई राशि भी शामिल है।

⁷² नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सिक्युरिटाइज़ेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्युरिटी इंटरैक्ट ऑफ़ इंडिया, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

था क्योंकि उन्हें खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी।

इसके अलावा, 40 सीपीएसई ने स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी, आठ सीपीएसई ने स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी और 10 सीपीएसई के लिए प्राथमिकता देना लागू नहीं था (अनुलग्नक XXXIII)।

5.6 निगरानी ढांचा

सीएसआर नियम 2014 के नियम 5(2) के अनुसार, सीएसआर समिति सीपीएसई द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करेगी। डीपीई ने 1 अगस्त 2016 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीपीएसई को सीएसआर की निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के लिए एक संस्थागत तंत्र रखने का निर्देश दिया था।

सीएसआर गतिविधियों की निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के लिए संस्थागत तंत्र के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 58 सीपीएसई में से:

- ग्यारह सीपीएसई ने मासिक समीक्षा की,
- पंद्रह सीपीएसई ने त्रैमासिक समीक्षा की।
- दो सीपीएसई ने अर्धवार्षिक समीक्षा की।
- दो सीपीएसई ने वार्षिक निगरानी की,
- पांच सीपीएसई ने आवश्यकता के अनुसार संचालन किया,
- दो सीपीएसई ने समझौता ज्ञापन के अनुसार समीक्षा की,
- दस सीपीएसई ने नीति/जारी किए गए एलओए/समिति की बैठकों/लक्ष्य आधारित/वर्ष में तीन बार/समझौते के अनुसार/समय-समय पर समीक्षा की,
- दो सीपीएसई ने आवधिकता शून्य घोषित की है।
- दो सीपीएसई ने सीएसआर कार्य की निगरानी नहीं की।
- चार सीपीएसई पर लागू नहीं और तीन सीपीएसई ने सीएसआर नीति में आवधिकता को परिभाषित नहीं किया।

डीपीई (नवंबर 2025) ने अपनी प्रतिक्रिया में ऊपर बताए गए बिंदुओं से सहमति व्यक्त की।

5.7 रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण

2014 के सीएसआर नियमों के नियम 8 के अनुसार, एक कंपनी को अपने निदेशक मंडल की प्रतिवेदन में सीएसआर पर एक वार्षिक प्रतिवेदन सम्मिलित करना आवश्यक है। सीएसआर नियम 2022 के अनुलग्नक II के अनुसार, कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित जानकारी साझा करनी चाहिए:

- i. सीएसआर नीति की सामग्री और उसका वेब लिंक, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं, औसत निवल लाभ, सीएसआर समिति की संरचना, प्रशासनिक ओवरहेड्स, निर्धारित राशि, अप्रयुक्त राशि, राशि न खर्च होने के कारण।
- ii. अधिग्रहित की गई पूंजीगत संपत्ति (पूंजीगत संपत्तियों के पूर्ण पते और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें।

5.7.1 वेबसाइट पर सीएसआर गतिविधियों का प्रदर्शित न होना

58 सीपीएसई में से, 51 सीपीएसई ने सार्वजनिक पहुंच के लिए वेबसाइट पर सीएसआर गतिविधियों की जानकारी नहीं दी और पांच⁷³ सीपीएसई ने इसकी जानकारी साझा नहीं की। जबकि एक सीपीएसई नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (नेरामैक) के लिए सीपीएसई के पिछले तीन वर्षों का औसत निवल लाभ नकारात्मक होने के कारण यह लागू नहीं था और एक सीपीएसई (एआईईएसएल) ने कहा कि बोर्ड प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जा रहा है (अनुलग्नक XXXIV)।

5.7.2 रिपोर्टिंग प्रारूप

58 सीपीएसई में से, 49 सीपीएसई ने प्रकटीकरण प्रारूप का अनुपालन किया और सात⁷⁴ सीपीएसई ने अपनी वार्षिक प्रतिवेदन में सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करते समय कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2022 (नियम 5-अनुलग्नक II) द्वारा निर्धारित प्रकटीकरण प्रारूप का अनुपालन नहीं किया। एक सीपीएसई नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक) के संबंध में यह लागू नहीं था और एक सीपीएसई एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) ने अपनी बोर्ड प्रतिवेदन को अंतिम रूप नहीं दिया है (अनुलग्नक XXXV)। इस प्रकार, 84.48 प्रतिशत सीपीएसई ने रिपोर्टिंग प्रारूप का अनुपालन किया था।

5.7.3 परिसंपत्ति निर्माण

58 सीपीएसई में से 18 सीपीएसई (अनुलग्नक XXXVI) ने वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण/अधिग्रहण किया था और वार्षिक प्रतिवेदन में इसका खुलासा किया था। उन सीपीएसई की संख्या जिन्होंने पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण/अधिग्रहण नहीं किया और अननुप्रयुक्तता का उल्लेख नीचे किया गया है:

क्र. सं.	सीपीएसई की संख्या	अनुपालन
1.	34	पूंजीगत संपत्तियों का निर्माण/अधिग्रहण नहीं किया
2.	06	लागू नहीं
3.	18	वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण/अधिग्रहण किया

⁷³ इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड।

⁷⁴ बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड।

5.7.4 व्यवसाय के सामान्य क्रम के अनुसरण में की जाने वाली सीएसआर गतिविधियां

एमसीए सीएसआर नियम 2014 के पैरा 6 के अनुसार 'सीएसआर गतिविधियों में वे गतिविधियां सम्मिलित नहीं हैं जो किसी कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम के अनुसरण में की जाती हैं'। उक्त सीएसआर नियम, जून 2014 के पैरा (viii) में यह भी कहा गया है कि किसी ट्रस्ट/सोसाइटी/धारा 8 की कंपनियों आदि के कॉर्पस (पूंजी) में योगदान सीएसआर व्यय के रूप में तब तक योग्य माना जाएगा जब तक कि (क) ट्रस्ट/सोसाइटी/धारा 8 की कंपनियां आदि विशेष रूप से सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए बनाई गई हों या (ख) जहां कॉर्पस विशेष रूप से अधिनियम की अनुसूची VII में सम्मिलित विषय से सीधे संबंधित उद्देश्य के लिए बनाया गया हो।

जनवरी 2019 में, आईओसीएल ने अन्य ऑयल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ मिलकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बॉम्बे के साथ ऑयल, गैस और ऊर्जा में एक उत्कृष्टता केंद्र (सीईओजीई) बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, ताकि भारत के ऑयल और गैस उद्योग को एक प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान किया जा सके। इस प्रकार, कंपनी द्वारा सीईओजीई की स्थापना और संचालन के लिए 2023-24 के दौरान किया गया ₹6.35 करोड़ का व्यय एक पात्र सीएसआर गतिविधि नहीं था।

आईओसीएल ने उत्तर दिया (मई 2025) कि केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर काम करने, सतत विकास के उद्देश्य का समर्थन करने और शिक्षाविदों के साथ उद्योग की एक स्वस्थ बातचीत के माध्यम से प्रणाली में ज्ञान के अंतर को पाटने के लिए की गई थी, जिससे पूरे समाज को लाभ हो और ऑयल एवं गैस क्षेत्र में क्षमता निर्माण के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्य का समर्थन किया जा सके। इसके अलावा, सीईओजीई द्वारा काम करने के लिए जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है, वे मुख्य रूप से सतत विकास पर शिक्षा और कौशल बढ़ाने, आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से आत्मनिर्भरता और बायोमास, गैस हाइड्रेट उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा वाहक के रूप में हाइड्रोजन, ऊर्जा प्रबंधन और कम कार्बन भविष्य आदि के रूप में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों के साथ संरेखित हैं।

आईओसीएल के उत्तर को इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि ऑयल विपणन कंपनियों और बॉम्बे सीईओजीई के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, इस परियोजना का उद्देश्य ऑयल और गैस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करना था। हालांकि सीईओजीई उद्योग-विशिष्ट है और इसकी गतिविधियां बड़े पैमाने पर समाज के बजाय इस क्षेत्र के व्यावसायिक/व्यापारिक हितों की सेवा करती हैं, इसलिए इसे सीएसआर गतिविधि के रूप में प्रस्तुत करना सीएसआर नियम 2014 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

डीपीई (नवंबर 2025) ने अपनी प्रतिक्रिया में उल्लिखित अवलोकन से सहमति व्यक्त की।

5.7.5 प्रभाव मूल्यांकन

सीएसआर संशोधित नियम, 2021 के नियम 8 (3) (क) के अनुसार, अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसरण में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में ₹10 करोड़ या उससे अधिक का औसत सीएसआर दायित्व रखने वाली प्रत्येक कंपनी एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से अपनी उन सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन कराएगी जिनका परिव्यय ₹ एक करोड़ या उससे अधिक है और

जो प्रभाव मूल्यांकन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी हैं। 58 सीपीएसई में से 22 सीपीएसई ने एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन कराया। आठ सीपीएसई ने प्रभाव मूल्यांकन नहीं कराया है और शेष 28 सीपीएसई के लिए मानदंड लागू नहीं हैं और उन्होंने अपनी सीएसआर प्रतिवेदन में इसकी सूचना दी है (अनुलग्नक XXXVII)।

5.8 सीएसआर व्यय की रिपोर्टिंग में विसंगतियां

लेखापरीक्षा ने पाया कि 58 में से तीन सीपीएसई में राज्यवार और फोकस क्षेत्र के व्यय की रिपोर्टिंग में विसंगति थी। लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए रिकॉर्ड और उनके वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए संबंधित आंकड़ों में विसंगति ₹5.12 लाख से ₹299.10 लाख तक थी, जो विवरणों की रिपोर्टिंग में विसंगतियों को दर्शाती है जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	अनुपालन
1.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्यवार योग व्यय ₹2,016.63 लाख था, जबकि वार्षिक प्रतिवेदन में योग सीएसआर व्यय का आंकड़ा ₹2,011.51 लाख था जो कि ₹5.12 लाख का अंतर था।
2.	इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार, फोकस क्षेत्रों पर व्यय ₹1,963.90 लाख के रूप में दर्शाया गया था, जो कि ₹299.1 लाख का अंतर था।
3.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार, फोकस क्षेत्रों पर व्यय ₹4,730.56 लाख दर्शाया गया था, जबकि वार्षिक प्रतिवेदन में योग सीएसआर व्यय का आंकड़ा ₹4,736.25 लाख था जो कि ₹5.69 लाख का अंतर था।

5.9 निष्कर्ष

जमीनी स्तर पर, सीएसआर कार्यक्रम आवश्यक प्रावधानों और आजीविका के अवसरों तक पहुंच को सुगम बनाकर हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बना सकते हैं। जमीनी स्तर पर काम करके और वंचित समुदायों को सहायता प्रदान करने वाली सेवाओं में सुधार का लक्ष्य रखकर, सीएसआर पहलों में सार्थक और सतत परिवर्तन लाने की क्षमता है, जिससे देश के समग्र विकास लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।

सीपीएसई के बीच सीएसआर निगरानी ढांचे और कार्यान्वयन प्रथाओं की समीक्षा से महत्वपूर्ण विसंगतियां और सुधार के क्षेत्र सामने आए हैं। सीएसआर नियम 2014 के नियम 5(2) के अनुसार एक पारदर्शी निगरानी तंत्र के आदेश और डीपीई तथा एमसीए के बाद के दिशानिर्देशों के बावजूद, बड़ी संख्या में सीपीएसई में प्रभावी निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को स्थापित करने की आवश्यकता

थी। लेखापरीक्षा के अवलोकन सीएसआर परियोजना समीक्षाओं की आवृत्ति में अनियमितताओं, उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कमियों और सीएसआर व्यय की अनुचित रिपोर्टिंग जैसे मुद्दों को उजागर करते हैं। इसके अलावा, निर्धारित रिपोर्टिंग प्रारूपों का अननुपालन, कंपनी की वेबसाइटों पर सीएसआर गतिविधियों का अपर्याप्त प्रकटीकरण, और संपत्ति निर्माण तथा प्रभाव मूल्यांकन आवश्यकताओं के पालन की कमी सीएसआर दायित्वों के निष्पादन में एक प्रणालीगत कमजोरी को दर्शाती है। ये निष्कर्ष उत्तरदेही, पारदर्शिता और वैधानिक तथा नियामक दिशानिर्देशों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए सीपीएसई को अपने सीएसआर गवर्नेंस ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हैं, जिससे उनकी सीएसआर पहलों की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता बढ़ेगी।

अध्याय VI

प्रशासनिक मंत्रालयों और नवरत्न सीपीएसई के
बीच समझौता ज्ञापनों का विश्लेषण

अध्याय VI

प्रशासनिक मंत्रालयों और नवरत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापनों का विश्लेषण

6.1 परिचय

समझौता ज्ञापन (एमओयू) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के प्रबंधन और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के बीच सीपीएसई के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक पारस्परिक रूप से बातचीत के जरिए किया गया समझौता है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले चयनित मापदंडों के संबंध में लक्ष्य तय करने और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लक्ष्यों के मुकाबले निष्पादन को मापने के लिए परिणामों के मूल्यांकन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। समझौता ज्ञापन की प्रणाली सूचीबद्ध और असूचीबद्ध दोनों सीपीएसई के लिए उनके लेखापरीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों के अनुसार सीपीएसई के निष्पादन का आकलन करने के एक तंत्र के रूप में कार्य करती है।

सभी सीपीएसई (होल्टिंग के साथ-साथ सहायक कंपनियों) को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है; होल्टिंग कंपनियां अपने प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करती हैं और सहायक कंपनियां अपनी संबंधित होल्टिंग कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती हैं। हालांकि, होल्टिंग सीपीएसई अपनी सहायक कंपनियों को समझौता ज्ञापन से छूट दे सकती है।

6.2 समझौता ज्ञापन के लिए संस्थागत तंत्र

6.2.1 सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई)

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) सीपीएसई और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करता है। डीपीई, अपने समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों के माध्यम से, समझौता ज्ञापन मापदंडों, मूल्यांकन प्रणाली के विवरण, प्रमुख जिम्मेदारियों और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की समयसीमा को निर्दिष्ट करता है। यह एक डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से समझौता ज्ञापन लक्ष्य निर्धारण के साथ-साथ निष्पादन मापदंडों के मूल्यांकन की प्रणाली प्रदान करके सीपीएसई के प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करने का एक तंत्र भी प्रदान करता है। इस डैशबोर्ड का उपयोग सीपीएसई/मंत्रालयों/विभागों द्वारा डेटा दर्ज करने, हस्ताक्षर करने, निगरानी करने और समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

6.2.2 अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी)

अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) को संबंधित सीपीएसई, मंत्रालय/विभाग और आईएमसी के सदस्य होने के नाते अन्य प्रमुख एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के आधार पर हर वर्ष सीपीएसई-वार समझौता जापन मापदंडों को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें अध्यक्ष के रूप में सचिव (डीपीई), मुख्य आर्थिक सलाहकार (आर्थिक कार्य विभाग), व्यय विभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) के प्रतिनिधि और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव/प्रतिनिधि और आवश्यकता के आधार पर सम्मिलित किए गए कोई अन्य विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं।

आईएमसी समझौता जापन मूल्यांकन के उद्देश्य से सेक्टर-वार टेम्पलेट/सीपीएसई-वार समझौता जापन मापदंडों को अंतिम रूप देती है। आईएमसी को विभिन्न मापदंडों के लिए बेंचमार्क निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, सीपीएसई को समझौता जापन वर्ष से पिछले वित्तीय वर्ष (आधार वर्ष के रूप में संदर्भित) के 31 दिसंबर तक डैशबोर्ड पर कुछ वित्तीय और भौतिक विशेषताओं के अनुमानित आंकड़े अपलोड करने होते हैं। इन आंकड़ों को सीपीएसई द्वारा समझौता जापन वर्ष के 31 अक्टूबर तक डीपीई के सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण पोर्टल के माध्यम से डैशबोर्ड पर आधार वर्ष के वास्तविक परिणामों के अनुसार अद्यतन किया जाता है। इसी तरह, आधार वर्ष के 31 दिसंबर तक, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को आईएमसी द्वारा बेंचमार्किंग के समय विचार के लिए डैशबोर्ड पर वार्षिक मील के पथर के साथ तीन वर्षों के लिए क्षेत्रीय विज्ञान प्लान अपलोड करना आवश्यक है।

क्षेत्रीय टेम्पलेट्स का उद्देश्य उस क्षेत्र और/या सीपीएसई में मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से प्रासंगिक मापदंडों और भारांकों का चयन और पहचान करना है। आईएमसी बेंचमार्क किए गए लक्ष्यों के रूप में तय किए गए प्रत्येक मापदंड के मुकाबले निष्पादन के अपेक्षित स्तर भी निर्धारित करेगी।

6.2.3 उच्चाधिकार प्राप्त समिति

समझौता जापन प्रणाली के तहत संस्थागत व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर, उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) आईएमसी की अनुशंसाओं के अनुसार नीतिगत दिशानिर्देश देती है। एचपीसी में समिति के अध्यक्ष के रूप में कैबिनेट सचिव और सदस्यों के रूप में सीईओ (नीति आयोग), वित्त सचिव, सचिव (व्यय), सचिव (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन), अध्यक्ष (लोक उद्यम चयन बोर्ड), मुख्य आर्थिक सलाहकार (आर्थिक कार्य विभाग) और सचिव (सार्वजनिक उद्यम) सम्मिलित होते हैं। एचपीसी सामान्य टेम्पलेट (समझौता जापन मापदंडों) को स्वीकृति देती है।

6.2.4 समझौता जापन मापदंडों और लक्ष्यों का निर्धारण

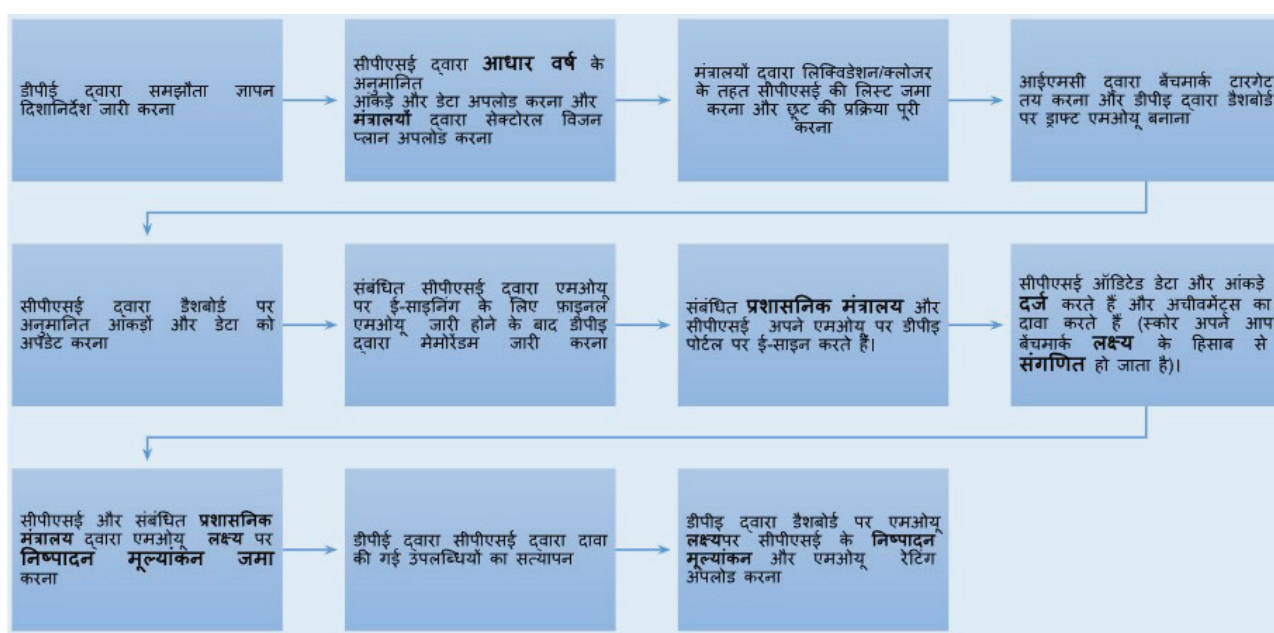
समझौता जापन प्रक्रिया में सम्मिलित मापदंडों का उद्देश्य सीपीएसई के लेखापरीक्षा किए गए खातों की पुस्तकों के अनुसार उनकी लाभप्रदता/निवेशित पूंजी पर रिटर्न के आर्थिक निष्पादन को प्रतिबिंबित करना है। इन मापदंडों को किसी दिए गए व्यावसायिक वातावरण में केवल उनके 'प्रयासों' का मूल्यांकन करने के बजाय दिए गए व्यावसायिक क्षेत्र में सीपीएसई की प्रतिस्पर्धात्मकता/उपयोगिता का मूल्यांकन करना माना जाता है। ये मापदंड परिचालन से राजस्व, भौतिक उत्पादन, निवल संपत्ति पर रिटर्न,

एसेट टर्नओवर अनुपात, प्रति शेयर आय को कवर करके सीपीएसई के भौतिक और वित्तीय निष्पादन को हासिल करने का प्रयास करते हैं, इसके अलावा सीपीएसई द्वारा सीएसआर पर डीपीई दिशानिर्देशों, और सेबी (एलओडीआर) विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद और उन्हें पुनर्भुगतान की समयसीमा से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन को भी सम्मिलित करते हैं। बेंचमार्क किया गया लक्ष्य "उत्कृष्ट" स्तर होता है।

समझौता ज्ञापन मापदंडों को समूहों में विभाजित किया गया है ताकि किसी क्षेत्र सीपीएसई के लिए गैर-लागू मापदंड (यदि कोई हो) के भारांक को उसी समूह के अन्य मापदंडों में पुनर्वितरित किया जा सके। इसके अलावा, सरकार के कुछ कार्यक्रम जैसे सीएसआर, जीईएम/एमएसई से खरीद आदि भी सीपीएसई द्वारा अनुपालन के लिए सम्मिलित किए गए हैं, जिनका अनुपालन न करने पर पूरे अंक काट लिए जाते हैं अर्थात्, कोई आंशिक कटौती नहीं होती है। समझौता ज्ञापन मापदंडों और अंकन प्रणाली का उल्लेख **अनलग्नक-XXXVIII** में किया गया है।

6.2.5 समझौता ज्ञापन स्कोर और रेटिंग:

डीपीई द्वारा निर्धारित समझौता ज्ञापन लक्ष्य निर्धारण और मल्यांकन की प्रक्रिया नीचे दी गई है:



समझौता ज़ापन दिशानिर्देशों में निर्धारित सीपीएसई द्वारा प्राप्त समझौता ज़ापन स्कोर के आधार पर समझौता ज़ापन रेटिंग नीचे दिखाई गई है:

समझौता ज्ञापन स्कोर समझौता ज्ञापन रेटिंग

स्कोर >= 90	उत्कृष्ट
स्कोर >= 70	बहुत अच्छा
स्कोर >= 50	अच्छा
स्कोर >= 33	ठीक
स्कोर < 33	खराब

6.3 समझौता ज़ापन मूल्यांकन

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, एक बार डैशबोर्ड पर सीपीएसई के लेखापरीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों का डेटा उपलब्ध हो जाने के बाद, बेंचमार्क लक्ष्यों के मुकाबले स्कोर स्वचालित रूप से गणना की जाएगी। विनिमय दर में बदलाव, कच्चे माल या तैयार माल की कीमत के कारण या किसी अन्य कारण से ऑफसेट के कारण समझौता ज़ापन स्कोर में कोई समायोजन नहीं होगा क्योंकि इन्हें सामान्य व्यावसायिक गतिविधि माना जाता है और खातों के घोषित लेखापरीक्षा किए गए विवरण मान्य होंगे। सीपीएसई को प्रत्येक मापदंड के लिए लक्ष्य आंकड़े के 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की उपलब्धि के लिए आनुपातिक रूप से अंक दिए जाते हैं (नुकसान करने वाली सीपीएसई के संबंध में नुकसान/ खर्चों में कमी के मापदंडों को छोड़कर)। हालांकि, लक्ष्य के 50 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाले मापदंडों के लिए कोई अंक नहीं दिए जाते हैं (शेयरधारकों को कुल रिटर्न के मापदंड को छोड़कर)। एक समग्र स्कोर तक पहुँचने के लिए सभी मापदंडों के स्कोर जोड़े जाते हैं।

6.4 विश्लेषण का आच्छादन

चयनित नवरत्न⁷⁵ केंद्रीय सीपीएसई में 2022-23 और 2023-24 के लिए समझौता ज़ापन मापदंडों के मुकाबले वास्तविक उपलब्धि की समीक्षा की गई। डीपीई की सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों के तहत 2022-23 और 2023-24 के दौरान क्रमशः 12 और 16 नवरत्न सीपीएसई थे। इनमें से 11 नवरत्न सीपीएसई दोनों वर्षों के दौरान समान थे, जिनमें से दो सीपीएसई⁷⁶ को वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए समझौता ज़ापन पर हस्ताक्षर करने से छूट दी गई थी। शेष नौ नवरत्न सीपीएसई में से छः को 2022-23 और 2023-24 के लिए समझौता ज़ापन के विश्लेषण के लिए चुना गया था।

संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय और वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए उनकी समझौता ज़ापन रेटिंग के साथ चयनित सीपीएसई का विवरण नीचे तालिका 6.1 में दिया गया है:

तालिका 6.1: चयनित नवरत्न सीपीएसई की समझौता ज़ापन रेटिंग

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	समझौता ज़ापन रेटिंग		
			2021-22	2022-23	2023-24
1.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)	रक्षा मंत्रालय	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
2.	एनएमडीसी लिमिटेड (एनएमडीसी)	इस्पात मंत्रालय	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा
3.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसी)	कोयला मंत्रालय	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा
4.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	खनन मंत्रालय	उत्कृष्ट	अच्छा	बहुत अच्छा

⁷⁵ मिनीरत्न कैटेगरी-1 और अनुसूची 'क' वाली सीपीएसई, जिन्हें पिछले पांच वर्षों में से तीन वर्षों में 'उत्कृष्ट' या बहुत अच्छा समझौता ज़ापन रेटिंग मिली हो और जिनका छह चुने हुए परफॉर्मंस पैरामीटर्स में कुल स्कोर 60 या उससे ज़्यादा हो, उन्हें नवरत्न का दर्जा दिया जाता है।

⁷⁶ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	समझौता जापन रेटिंग		
			2021-22	2022-23	2023-24
5.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआई)	पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा
6.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा

2022-23 और 2023-24 के लिए समझौता जापन के संबंध में सीपीएसई के बेंचमार्क लक्ष्यों और उपलब्धियों को **अनुलग्नक-XXXIX** में दर्शाया गया है।

6.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने चयनित छः नवरत्न सीपीएसई द्वारा अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ हस्ताक्षरित समझौता जापन और वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की जांच की। समझौता जापन को अंतिम रूप देने और मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न पहलुओं की भी समीक्षा की गई। इस तरह की समीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

6.5.1 आईएमसी बैठकें और समझौता जापन को अंतिम रूप देना/हस्ताक्षर करना

6.5.1.1 डीपीई द्वारा आईएमसी बैठकें आयोजित करने और समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने में लिया गया समय

जैसा कि वर्ष 2022-23 और उसके बाद के डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित है, आईएमसी क्षेत्रीय टेम्पलेट/सीपीएसई-वार समझौता जापन मापदंडों को अंतिम रूप देती है। क्षेत्रीय टेम्पलेट्स का उद्देश्य उस क्षेत्र और/या सीपीएसई में मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से प्रासंगिक मापदंडों और भारांकों का चयन और पहचान करना है। आईएमसी ने तय किए गए प्रत्येक समझौता जापन मापदंड के मुकाबले निष्पादन के अपेक्षित स्तरों को बेंचमार्क लक्ष्यों के रूप में निर्धारित किया। डीपीई द्वारा जारी समझौता जापन दिशानिर्देशों में, समझौता जापन मापदंडों को अंतिम रूप देने के लिए आईएमसी बैठक आयोजित करने की कोई समयसीमा नहीं बताई गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समझौता जापन वर्ष 2022-23 के लिए आईएमसी बैठकें सभी छः चयनित सीपीएसई के संबंध में अक्टूबर 2022 के दौरान आयोजित की गई थीं और उनके समझौता जापनों पर नवंबर 2022 से जनवरी 2023 के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। इसी तरह, समझौता जापन वर्ष 2023-24 के लिए आईएमसी बैठकें जुलाई से सितंबर 2023 तक आयोजित की गई थीं और उनके समझौता जापनों पर जुलाई से अक्टूबर 2023 के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। उल्लिखित आईएमसी बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष 2022-23 के लिए

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम	आईएमसी बैठक की तारीख	आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त जारी करने की तारीख	डीपीई द्वारा समझौता ज्ञापन पोर्टल पर अपलोड करने की तारीख	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तिथि	आईएमसी बैठक से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होने में लगने वाला समय (दिनों में)
1.	एनएमडीसी लिमिटेड	19.10.2022	21.10.2022	01.12.2022	12.12.2022	54 दिन
2.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	21.10.2022	28.10.2022	22.12.2022	04.01.2023	75 दिन
3.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	17.10.2022	21.10.2022	14.11.2022	28.11.2022	42 दिन
4.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	21.10.2022	28.10.2022	01.12.2022	21.12.2022	61 दिन
5.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	31.10.2022	03.11.2022	07.11.2022	16.11.2022	16 दिन
6.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	19.10.2022	21.10.2022	25.10.2022	15.11.2022	27 दिन

जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, एचएएल को छोड़कर, चयनित सीपीएसई में आईएमसी बैठक आयोजित करने से लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में लिया गया समय 27 से 75 दिनों के बीच रहा। इसके अलावा, आईएमसी बैठक आयोजित करने के बाद पोर्टल पर डीपीई द्वारा समझौता ज्ञापन अपलोड करने में 62 दिनों तक का काफी समय लिया गया। हालांकि डीपीई ने पोर्टल पर समझौता ज्ञापन के ई-हस्ताक्षर के लिए 21 दिनों की अवधि निर्धारित की थी (नवंबर 2022), आईएमसी बैठक के बाद समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए ऐसी कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई थी। आईएमसी बैठकों और उसके बाद समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष 2023-24 के लिए

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आईएमसी बैठक की तारीख	आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त जारी करने की तारीख	डीपीई द्वारा समझौता ज्ञापन पोर्टल पर अपलोड करने की तारीख	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तिथि	आईएमसी बैठक से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होने में लगने वाला समय (दिनों में)
1.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	25.08.2023	06.09.2023	09.10.2023	20.10.2023	56 दिन
2.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	02.08.2023	08.08.2023	25.08.2023	06.09.2023	35 दिन
3.	एनएमडीसी लिमिटेड	02.08.2023	16.08.2023	16.08.2023	30.08.2023	28 दिन
4.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	03.07.2023	19.07.2023	19.07.2023	27.07.2023	24 दिन
5.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	02.08.2023	08.08.2023	08.08.2023	22.08.2023	20 दिन
6.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	04.09.2023	19.09.2023	20.09.2023	04.10.2023	30 दिन

इसी तरह, वर्ष 2023-24 के समझौता ज़ापन के संबंध में, नालको को छोड़कर, जहाँ लिया गया समय 20 दिन था, आईएमसी बैठक आयोजित करने से लेकर समझौता ज़ापन पर हस्ताक्षर करने में लिया गया समय 24 से 56 दिनों के बीच रहा।

इस प्रकार, सीपीएसई को अंतिम समझौता ज़ापन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए क्रमशः लगभग 3-4 माह और 6-7 माह की कम अवधि मिल सकी। इस संबंध में निर्धारित समयसीमा की अनुपस्थिति डीपीई में पर्याप्त तंत्र की कमी को दर्शाती है जिससे समझौता ज़ापन को समय पर अंतिम रूप देना और हस्ताक्षर करना सुनिश्चित किया जा सके ताकि सीपीएसई को समझौता ज़ापन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

डीपीई ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि पिछले वर्षों की तुलना में समझौता ज़ापन पर हस्ताक्षर करने की समयसीमा में महत्वपूर्ण सुधार हुआ था। आईएमसी ने सैद्धांतिक और गैर लेखापरीक्षित उपलब्धियों के अनुमानों के आधार पर 2022-23 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे, जिसके लिए 2021-22 के लेखापरीक्षित आंकड़े उपलब्ध होने के बाद अपडेट करने की आवश्यकता थी। वर्ष 2023-24 के लिए समझौता ज़ापनों को समयसीमा में और सुधार के साथ अंतिम रूप दिया गया था और 2024-25 के लिए समझौता ज़ापनों को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से काफी पहले अंतिम रूप दिया गया था (हालांकि आधार वर्ष के लिए सीपीएसई के निष्पादन की उपलब्धता के बाद समीक्षा के अधीन)।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि समझौता ज़ापन लक्ष्यों के समक्ष सीपीएसई के नियमित और प्रभावी निष्पादन मूल्यांकन के लिए समझौता ज़ापन प्रक्रिया को समय पर पूरा करना आवश्यक था। इसलिए, डीपीई समझौता ज़ापनों को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने के लिए समयसीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकता है।

6.5.1.2 मंत्रालयों के क्षेत्रीय विज्ञान योजना के बिना समझौता ज़ापन को अंतिम रूप देना

समझौता ज़ापन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि समझौता ज़ापन में मापदंडों को सीपीएसई के पिछले निष्पादन, प्रशासनिक मंत्रालय के दृष्टिकोण, क्षेत्रीय बेंचमार्किंग और सहकर्मी तुलना, यदि कोई हो, से अनुक्रमित किया जाता है। इसके अलावा, ये दिशानिर्देश यह भी बताते हैं कि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग आधार वर्ष के 31 दिसंबर तक वार्षिक मील के पत्थर के साथ तीन वर्षों के लिए क्षेत्रीय विज्ञान योजना का विवरण डैशबोर्ड पर अपलोड करेगा ताकि आईएमसी द्वारा बेंचमार्किंग के समय इस पर विचार किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छः चयनित सीपीएसई में से पांच⁷⁷ के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालयों ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए समझौता ज़ापन लक्ष्यों को अंतिम रूप देने के लिए समझौता ज़ापन डैशबोर्ड पर अपना क्षेत्रीय विज्ञान योजना तैयार और अपलोड नहीं किया। इस प्रकार, इन सीपीएसई के संबंध में समझौता ज़ापन डैशबोर्ड पर क्षेत्रीय विज्ञान प्लान के बिना समझौता ज़ापन को अंतिम रूप दिया गया और हस्ताक्षर किए गए जो समझौता ज़ापन दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था। सम्मिलित संबंधित संस्थाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करने वाले समझौता ज़ापन तंत्र को देखते हुए और ऐसे विज्ञान योजना के महत्व को देखते हुए, ये महत्वपूर्ण इनपुट समझौता ज़ापन की

⁷⁷ एनएमडीसी, एससीआई, नालको, एनएलसी और ईआईएल।

लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिससे विज्ञान योजना के बिना समझौता ज्ञापन मूल्यांकन अपूर्ण रह जाता है।

इस्पात मंत्रालय (एमओएस) ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि एनएमडीसी के लिए विज्ञान योजना एनएमडीसी द्वारा तैयार किया गया था और इसके बाद, एनएमडीसी से विज्ञान योजना को समझौता ज्ञापन डैशबोर्ड पर अपलोड करने का अनुरोध किया गया था।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडबल्यू) ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि उसके पास पहले से ही विज्ञान दस्तावेज़ मैरीटाइम इंडिया विज्ञान (एमआईवी), 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विज्ञान (एमकेवी) 2047 था और उपरोक्त विज्ञान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के दो अधिकारी सरकारी नामित निदेशकों के रूप में एससीआई के बोर्ड में थे।

खनन मंत्रालय (एमओएम) ने कहा कि नालको ने अनुमानित लक्ष्यों के साथ अपना विज्ञान योजना अपलोड किया था और मंत्रालय द्वारा इसका समर्थन किया गया था। समझौता ज्ञापन के लक्ष्य, जो नालको की क्षमता के अनुसार थे, पर भी मंत्रालय द्वारा आईएमसी में विचार-विमर्श किया गया था। 2022-23 और 2023-24 के लिए कोई अलग विज्ञान योजना अपलोड नहीं किया गया था। मंत्रालय ने अवलोकन को स्वीकार किया और भविष्य में डैशबोर्ड पर अलग विज्ञान प्लान अपलोड करने का आश्वासन दिया ।

कोयला मंत्रालय (एमओसी) ने उत्तर दिया (अगस्त 2025) कि मंत्रालय हर वर्ष एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करता है जिसमें उत्पादन लक्ष्य और मंत्रालय का दृष्टिकोण सम्मिलित होता है, और इसे सार्वजनिक डोमेन में जारी किया जाता है। इस कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए, कोयला मंत्रालय ने डीपीई पोर्टल पर समझौता ज्ञापन मापदंडों की अनुशंसा की, जिन पर फिर कोयला मंत्रालय द्वारा विचार किया गया और सहकर्मी तुलनाओं के साथ आईएमसी बैठकों में विचार-विमर्श किया गया और इन्हें डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने में सम्मिलित किया गया।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2025) कि क्षेत्रीय विज्ञान योजना के मुद्दे पर डीपीई दिशानिर्देश अनिवार्य प्रकृति के नहीं थे।

उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों के अनुसार, आईएमसी द्वारा बेंचमार्किंग के समय क्षेत्रीय विज्ञान योजना पर विचार किया जाना एक आवश्यक तत्व था।

6.5.1.3 समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने में लिया गया समय

डीपीई द्वारा जारी समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों में, डीपीई द्वारा पोर्टल पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने और अपलोड करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई थी। हालांकि, डीपीई ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया (11 नवंबर 2022) जिसने डैशबोर्ड पर समझौता ज्ञापन को ई-हस्ताक्षर करने के लिए 21 दिनों की अवधि निर्धारित की थी। समझौता ज्ञापन के ई-हस्ताक्षर में विलंब के मामले में, समझौता ज्ञापन स्कोर से अंक काटे⁷⁸ जाने थे।

⁷⁸ एक हफ्ते तक के विलंब पर: 2.5 अंक, दो हफ्ते तक: 5.0 अंक और तीन हफ्ते तक: 7.5 अंक। तीन हफ्ते से ज्यादा की देरी के बाद साइन करने पर, स्कोर चाहे जो भी हो, सीपीएसई को 'खराब' रेटिंग दी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छः चयनित सीपीएसई में से वर्ष 2022-23 के लिए दो सीपीएसई अर्थात् ईआईएल और एनएमडीसी के संबंध में समझौता जापन पर हस्ताक्षर⁷⁹ करने में विलंब हुआ। डीपीई ने ईआईएल और एमओपीएंडएनजी (09 सितंबर 2022) तथा एनएमडीसी और इस्पात मंत्रालय (23 सितंबर 2022) से 21 दिनों के भीतर वर्ष 2022-23 के लिए समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया था। हालांकि, ईआईएल और एनएमडीसी के मामले में क्रमशः 21 दिसंबर 2022 और 12 दिसंबर 2022 को समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए गए थे अर्थात्, ईआईएल के मामले में ढाई माह से अधिक और एनएमडीसी के मामले में दो माह की विलंब के बाद। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विलंब नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एनएमडीसी/एमओएस और ईआईएल/एमओपीएंडएनजी के अनुरोध के आधार पर समझौता जापन मापदंडों के संशोधन के कारण हुआ था:

सीपीएसई का नाम	समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने के लिए डीपीई द्वारा सीपीएसई को पत्र भेजने की तिथि	समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख (21 दिनों के अंदर)	सीपीएसई द्वारा प्रतिनिधित्व की तिथि	ई-हस्ताक्षर के लिए सीपीएसई को संशोधित समझौता जापन भेजने की तिथि	समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि
ईआईएल	09.09.2022	30.09.2022	14.09.2022	01.12.2022	21.12.2022
एनएमडीसी	23.09.2022	14.10.2022	06.10.2022 (पहला)	25.10.2022	27.11.2022
	25.10.2022	जल्द से जल्द	15.11.2022 (दूसरा)	01.12.2022	12.12.2022

इस प्रकार, समझौता जापन में संशोधन के बाद भी वर्ष 2022-23 के लिए समझौता जापन के ई-हस्ताक्षर में विलंब हुआ लेकिन मूल्यांकन के दौरान डीपीई द्वारा कोई अंक नहीं काटा गया जो कि डीपीई के दिनांक 11 नवंबर 2022 के कार्यालय जापन के अनुरूप नहीं था।

ईआईएल ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि उसने लक्ष्यों के संशोधन के लिए एमओपीएंडएनजी को मापदंड-वार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसकी अनुशंसा एमओपीएंडएनजी द्वारा डीपीई से की गई थी। डीपीई ने ई-हस्ताक्षर के लिए 2022-23 के लिए संशोधित समझौता जापन जारी किया जिसे 21 दिसंबर 2022 को ई-हस्ताक्षरित किया गया था।

एमओपीएंडएनजी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2025) कि डीपीई समझौता जापन को अंतिम रूप देने के लिए नोडल एजेंसी थी और ईआईएल ने बिना किसी विलंब के डीपीई द्वारा निर्धारित समयसीमा का पालन किया। ईआईएल ने डीपीई द्वारा प्रदान की गई समयसीमा के भीतर दोनों वर्षों के लिए समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए थे और ईआईएल की ओर से कोई विलंब नहीं हुआ।

एनएमडीसी ने उत्तर दिया (जून 2025) कि ऊपर उल्लिखित लक्ष्यों का संशोधन लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान हुआ था। एमओएस ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि 21 दिनों के भीतर समझौता जापन को ई-हस्ताक्षर करने के निर्देशों (11 नवंबर 2022) के बाद, मंत्रालय ने समझौता जापन मापदंडों में संशोधन का अनुरोध (23 नवंबर 2022) किया। चूंकि डीपीई ने विलंब के लिए संभावित नकारात्मक अंकन का हवाला देते हुए मंत्रालय से बिना किसी विलंब के समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने का

⁷⁹ एससीआई के संबंध में एमओयू पर ई-साइन करने में हुई विलंब को तकनीकी खराबी के कारण नज़रअंदाज़ कर दिया गया और मंत्रालय ने एससीआई के हस्ताक्षर के बिना ही समय पर एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए।

आग्रह किया, मंत्रालय ने एक अंतरिम उपाय के रूप में 27 नवंबर 2022 को समझौता जापन पर ई-हस्ताक्षर किए और 12 दिसंबर 2022 को संशोधित समझौता जापन पर ई-हस्ताक्षर किए। लक्ष्यों का संशोधन लक्ष्य निर्धारण के दौरान हुआ था।

उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि लक्ष्य निर्धारण पूरी समझौता जापन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था क्योंकि निष्पादन को इन मापदंडों के खिलाफ मापा गया था। इसके अलावा, प्रशासनिक मंत्रालय आईएमसी बैठक में भाग लेता है जिसमें एचपीसी को इसकी स्वीकृति की अनुशंसा के लिए लक्ष्यों पर विचार-विमर्श किया गया था। इसके अलावा, मापदंडों/लक्ष्यों के संशोधन के लिए प्रतिवेदन समय पर किया जाना चाहिए था।

6.5.1.4 होल्डिंग सीपीएसई द्वारा सहायक कंपनी के साथ समझौता जापन पर हस्ताक्षर करना

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी सीपीएसई (होल्डिंग और सहायक कंपनियों) को समझौता जापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था। होल्डिंग कंपनियां अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समझौता जापन पर हस्ताक्षर करेंगी और सहायक सीपीएसई अपनी संबंधित होल्डिंग कंपनियों के साथ समझौता जापन पर हस्ताक्षर करेंगी। इसके अलावा, होल्डिंग कंपनियां अपनी सहायक कंपनियों को समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने से छूट देने के लिए स्वतंत्र थीं, लेकिन छूट की प्रक्रिया आमतौर पर आधार वर्ष के 31 मार्च तक पूरी की जानी थी (, अर्थात्, समझौता जापन वित्तीय वर्ष से पिछला वित्तीय वर्ष)। इस प्रकार, 2022-23 और 2023-24 के लिए समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने से छूट की प्रक्रिया क्रमशः 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 तक पूरी की जानी आवश्यक थी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

क. सहायक कंपनी के साथ समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने में विलंब

छ: चयनित सीपीएसई में से दो सीपीएसई (एचएएल एवं एनएलसी) ने समय के भीतर अपनी सहायक कंपनियों के साथ समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए, दो सीपीएसई (एनएमडीसी एवं एससीआई) ने अपनी सहायक कंपनियों को समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने से छूट दी थी और एक सीपीएसई (नाल्को) की कोई सहायक कंपनी नहीं थी। हालांकि, एक सीपीएसई (ईआईएल) के मामले में, वर्ष 2023-24 के लिए इसकी सहायक कंपनी सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौता जापन पर 2 फरवरी 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे, अर्थात्, आखिरी तिमाही में और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लगभग अंत में। इस प्रकार, सीईआईएल के पास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत कम समय बचा था।

ईआईएल ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि 2023-24 के लिए समझौता जापन पर 27 सितंबर 2023 को हस्ताक्षर किए गए थे और वित्तीय मापदंडों में सीईआईएल के योगदान को सम्मिलित करते हुए समेकित आधार पर 04 अक्टूबर 2023 को ई-हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, सीईआईएल को इसके बारे में अवगत कराया गया और ईआईएल तथा सीईआईएल के बीच समझौता जापन की तैयारी शुरू की गई। इसे तैयार करने और हस्ताक्षर करने में विलंब हुआ और 2 फरवरी 2024 को हस्ताक्षर किए गए। हालांकि, यह आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में सहायक कंपनी के साथ समझौता जापन पर समय पर हस्ताक्षर करने के प्रयास किए जाएंगे।

एमओपी एंड एनजी ने (अक्टूबर 2025) लेखापरीक्षा अवलोकन को नोट किया।

ख. सहायक कंपनियों को समझौता ज़ापन पर हस्ताक्षर करने के लिए छूट देने में विलंब

छ: चयनित सीपीएसई में से, दो सीपीएसई अर्थात् एससीआई और एनएमडीसी के मामले में, वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए सहायक कंपनी को समझौता ज़ापन से छूट देने में विलंब हुआ। एससीआई ने अपनी सहायक कंपनी इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड (आईसीएसएल) को वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए समझौता ज़ापन पर हस्ताक्षर करने से क्रमशः 21 दिसंबर 2022 और 31 मई 2023 को छूट दी अर्थात्, क्रमशः नौ माह और दो माह की विलंब के साथ

इसके अलावा, एनएमडीसी के मामले में, उसने वर्ष 2023-24 के लिए न तो अपनी सहायक सीपीएसई (जेएंडके मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड और एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन) के साथ समझौता ज़ापन पर हस्ताक्षर किए और न ही अपनी सहायक कंपनियों को समझौता ज़ापन पर हस्ताक्षर करने से छूट दी।

एससीआई (जून 2025) और एमओपीएसडब्लू (जुलाई 2025) ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और भविष्य में डीपीई द्वारा प्रदान की गई समय सीमा के भीतर सहायक कंपनियों को छूट का पत्र जारी करने का आश्वासन दिया।

एनएमडीसी ने उत्तर दिया (जून 2025) कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के साथ समझौता ज़ापन में प्रवेश न करने का निर्णय लिया था क्योंकि वे 'वैधानिक स्वीकृति /खानों के आवंटन की प्रतीक्षा/स्थायी कर्मचारियों का न होना' के चरण में थीं और छूट प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं थी।

एमओएस ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, होल्डिंग कंपनी अपनी सहायक कंपनियों के लिए समझौता ज़ापन से छूट के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

एनएमडीसी के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के लिए, एनएमडीसी ने सहायक कंपनियों के लिए समझौता ज़ापनों से छूट के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया था (29 मार्च 2022) और मंत्रालय ने डीपीई को सूचित किया था (13 मई 2022) कि वर्ष 2022-23 के लिए एनएमडीसी के साथ सहायक कंपनियों द्वारा कोई समझौता ज़ापन प्रस्तावित नहीं था। वर्ष 2023-24 के लिए सहायक कंपनियों के लिए समझौता ज़ापनों से छूट की समान प्रक्रिया एनएमडीसी द्वारा शुरू नहीं की गई थी।

6.5.1.5 डीपीई द्वारा भौतिक उत्पादन मापदंड के लिए निर्धारित अवास्तविक लक्ष्य

वर्ष 2023-24 के लिए नालको के लिए डीपीई द्वारा अंतिम रूप दिए गए समझौता ज़ापन में, 20 अंक वाले भौतिक उत्पादन मापदंड के मुकाबले, लक्ष्य कंपनी की स्थापित और मानक क्षमताओं से अधिक निर्धारित किए गए थे, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- (i) एल्युमिनियम कास्ट मेटल उत्पादन के लिए नालको की स्थापित क्षमता 4.60 लाख टन प्रति वर्ष थी। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए समझौता ज़ापन का लक्ष्य डीपीई द्वारा 5.52 लाख टन

निर्धारित किया गया था, जो लगभग 20 प्रतिशत के अधिक आकलन को दर्शाता है। यह लक्ष्य मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधार पर अधिकतम प्राप्य उत्पादन से अधिक था, जिससे यह परिचालन रूप से अवास्तविक हो गया।

- (ii) एलुमिना हाइड्रेट के लिए मानक क्षमता 21.00 लाख टन प्रति वर्ष थी, फिर भी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डीपीई द्वारा निर्धारित समझौता ज्ञापन का लक्ष्य 25.93 लाख टन तय किया गया था, जो मानक और स्थापित दोनों क्षमताओं से अधिक था, जिससे यह स्पष्ट रूप से अप्राप्य हो गया।

वर्ष 2023-24 की निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार, कंपनी दोनों उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि वह एल्युमिनियम कास्ट मेटल उत्पादन के लिए 5.52 लाख टन के समझौता ज्ञापन लक्ष्य के मुकाबले 4.63 लाख टन और एलुमिना हाइड्रेट उत्पादन के लिए 25.93 लाख टन के समझौता ज्ञापन लक्ष्य के मुकाबले 21.24 लाख टन ही प्राप्त कर सकी।

इस प्रकार, डीपीई को वास्तविक परिचालन क्षमताओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य-निर्धारण तंत्र की समीक्षा करनी चाहिए थी।

नालको (जून 2025) ने लेखापरीक्षा अवलोकन से सहमति व्यक्त की और कहा कि इसकी स्थापित क्षमता से परे उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने से वे अवास्तविक और अप्राप्य हो गए।

खनन मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2025) कि भौतिक लक्ष्यों को कम करने के लिए इसे डीपीई के साथ उठाया गया था। डीपीई को मसौदा चरण में संचार भेजे गए थे लेकिन डीपीई ने इस पर विचार नहीं किया।

डीपीई ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि पिछले वर्षों की तुलना में उत्पादन के लक्ष्य में कोई गिरावट की समीक्षा नहीं की गई थी, लेकिन सीपीएसई को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसे धीरे-धीरे बढ़ाया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि इस मापदंड के लक्ष्य पर विचार-विमर्श करते समय, आईएमसी ने, यह नोट करने के बावजूद कि उत्पादन क्षमता ऐतिहासिक निष्पादन के अनुरूप थी, उच्च लक्ष्य को प्रकृति में महत्वाकांक्षी मानते हुए बनाए रखा। उत्पादन मापदंडों की वास्तविक उपलब्धि भी इस बात की पुष्टि करती है कि नालको और मंत्रालय के अनुरोधों के बावजूद डीपीई द्वारा वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

6.5.1.6 भौतिक निष्पादन से संबंधित मापदंडों की अनुपस्थिति

वर्ष 2022-23 और उसके बाद के समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया था कि भौतिक उत्पादन (उत्पादन/उत्पादन/पारेषण/उत्पादन का मूल्य/ कुल आय) को मापने के लिए, पेट्रोलियम, विद्युत, खनन, इस्पात आदि में सीपीएसई से वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार स्थापित क्षमता, क्षमता उपयोग और उत्पादन के बारे में जानकारी देने की अपेक्षा की जाती है। यह मापदंड पूर्ण मात्रा में या क्षमता के प्रतिशत उपयोग में या ₹ करोड़ में दिया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने, हालांकि, पाया कि एनएमडीसी, नालको और एनएलसी के समझौता ज्ञापन में उत्पादन/विद्युत उत्पादन का केवल एक मापदंड था, जिसका भारांक 20 अंक था; अन्य दो मापदंड अर्थात् स्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग समझौता ज्ञापन में सम्मिलित नहीं थे। तदनुसार, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इन दो मापदंडों को सम्मिलित न करने के कारण सीपीएसई का उनकी स्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग से संबंधित जानकारी पर मूल्यांकन नहीं किया जा सका:

तालिका 6.3: 2022-23 के लिए उत्पादन/विद्युत उत्पादन के मापदंड के संबंध में निष्पादन

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	उत्पादन/ विद्युत उत्पादन			
		संस्थापित क्षमता	क्षमता उपयोग	समझौता ज्ञापन के अनुसार लक्ष्य	समझौता ज्ञापन मूल्यांकन के अनुसार उपलब्धि
1.	एनएलसी	-	-	33,943 मिलियन यूनिट	30,082.80 मिलियन यूनिट
2.	नाल्को	-	-	26.21 लाख टन	25.83 लाख टन
3.	एनएमडीसी	-	-	490 लाख टन	408.17 लाख टन

तालिका 6.4: 2023-24 के लिए उत्पादन/विद्युत उत्पादन के मापदंड के संबंध में निष्पादन

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	उत्पादन/ विद्युत उत्पादन			
		संस्थापित क्षमता	क्षमता उपयोग	समझौता ज्ञापन के अनुसार लक्ष्य	समझौता ज्ञापन मूल्यांकन के अनुसार उपलब्धि
1.	एनएलसी	-	-	35,000 मिलियन यूनिट	27,106.21 मिलियन यूनिट
2.	नाल्को	-	-	31.45 लाख टन	25.87 लाख टन
3.	एनएमडीसी	-	-	544.00 लाख टन	450.22 लाख टन

समझौता ज्ञापन में स्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग से संबंधित मापदंडों की अनुपस्थिति में, विनिर्माण/उत्पादन में सम्मिलित कंपनियों के दृष्टिकोण से निष्पादन का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण मापदंड होने के बावजूद समझौता ज्ञापन निष्पादन के मूल्यांकन के लिए संबंधित सीपीएसई की क्षमता के उपयोग की सीमा का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। इसके अलावा, समझौता ज्ञापन पोर्टल की समीक्षा से पता चला कि ये सीपीएसई स्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग के लिए डेटा दिखा रहे थे। वर्ष 2022-23 के लिए पीई सर्वेक्षण रिपोर्टों की समीक्षा से पता चला कि नालको ने स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग किया था और एनएलसी लिमिटेड विद्युत (नवीकरणीय) और विद्युत (थर्मल) के उत्पादन के लिए अपनी स्थापित क्षमता का क्रमशः केवल 17.63 प्रतिशत और 68.86 प्रतिशत उपयोग कर रहा था।

इस प्रकार, अंतिम समझौता ज्ञापन में इन मापदंडों को न सौंपने से सीपीएसई का त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन हुआ और साथ ही समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों का अननुपालन भी हुआ।

डीपीई ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि समझौता ज्ञापन दिशानिर्देश निष्पादन संकेतकों के चयन में लचीलापन प्रदान करते हैं, जिससे स्थापित क्षमता या क्षमता उपयोग, या वैकल्पिक मापदंडों को सम्मिलित करने की अनुमति मिलती है। यह आवश्यकता के आधार पर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्षमता विस्तार को चलाने के लिए इस तरह से समझौता ज्ञापन मापदंडों के निर्माण को सक्षम बनाता है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि समझौता ज़ापन दिशानिर्देशों के अनुसार सीपीएसई को वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार स्थापित क्षमता, क्षमता उपयोग और उत्पादन के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। यद्यपि उत्पादन लक्ष्य विभिन्न कारकों के आधार पर आईएमसी द्वारा अंतिम रूप दिए जाते हैं, स्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग से संबंधित मापदंडों को सम्मिलित करने से न केवल डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन होता बल्कि सीपीएसई का मूल्यांकन भी अधिक व्यापक हो जाता।

6.5.2 समझौता ज़ापन मापदंडों के अननुपालन के बावजूद अंकों की कटौती न करना

6.5.2.1 कंपनी अधिनियम और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 पर अनुपालन मापदंड

वर्ष 2022-23 और उसके बाद के लिए डीपीई द्वारा जारी समझौता ज़ापन दिशानिर्देशों के अनुसार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 या सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए सीपीएसई द्वारा प्राप्त कुल समझौता ज़ापन स्कोर से तीन अंक काट लिए जाएंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी (एलओडीआर) विनियमों के प्रावधानों के अननुपालन के बावजूद, प्रशासनिक मंत्रालयों और डीपीई ने समझौता ज़ापन दिशानिर्देशों के अनुसार सीपीएसई के समझौता ज़ापन स्कोर से तीन अंक नहीं काटे, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

क. स्वतंत्र निदेशक

कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति कंपनी के सामान्य हित में बोर्ड प्रक्रिया में निष्पक्षता का तत्व लाने के लिए और इस तरह अल्पसंख्यक हितों और छोटे शेयरधारकों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण है जो अन्यथा अपनी आवाज नहीं उठा सकते।

सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) के अनुसार, "जहां सूचीबद्ध इकाई के पास एक नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, वहां निदेशक मंडल के कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित होंगे"।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान एनएमडीसी, एससीआई, ईआईएल, एचएएल और एनएलसी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं था, जैसा कि नीचे विवरण में दिया गया है:

सीपीएसई का नाम	वर्ष	वह समय जिसके लिए निदेशक मंडल में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार ज़रूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।
एनएमडीसी	2022-23	01.04.2022 से 31.03.2023 (पूरा समझौता ज़ापन वर्ष)
	2023-24	01.04.2023 से 31.03.2024 (पूरा समझौता ज़ापन वर्ष)
एससीआई	2022-23	19.05.2022 से 31.05.2022 और 13.06.2022 से 31.03.2023
	2023-24	01.04.2023 से 31.03.2024 (पूरा समझौता ज़ापन वर्ष)

सीपीएसई का नाम	वर्ष	वह समय जिसके लिए निदेशक मंडल में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार ज़रूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।
ईआईएल	2022-23	16.08.2022 से 11.12.2022 और 28.12.2022 से 31.03.2023
	2023-24	01.04.2023 से 30.09.2023
एचएएल	2022-23	01.04.2022 से 31.03.2023 (पूरा समझौता ज़ापन वर्ष)
	2023-24	01.04.2023 से 31.03.2024 (पूरा समझौता ज़ापन वर्ष)
एनएलसी	2022-23	01.04.2022 से 05.04.2022 और 11.05.2022 से 31.03.2023
	2023-24	01.04.2023 से 31.03.2024 (पूरा समझौता ज़ापन वर्ष)

ख. स्वतंत्र महिला निदेशक

निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) के अनुसार, "निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक के साथ कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का एक इष्टतम संयोजन होगा। इसके अलावा, शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होगी।"

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएमडीसी को छोड़कर सभी चयनित सीपीएसई के बोर्ड में 2022-23 और 2023-24 के दौरान स्वतंत्र महिला निदेशक थीं।

इस प्रकार, स्वतंत्र/स्वतंत्र महिला निदेशकों के संबंध में सेबी के प्रावधानों का गैर अनुपालन था, लेकिन इस तरह के गैर अनुपालन के लिए डीपीई द्वारा कोई अंक नहीं काटा गया।

एनएमडीसी ने उत्तर दिया (जून 2025) कि कंपनी ने अंकों का दावा किया था क्योंकि बोर्ड की संरचना सीपीएसई के दायरे में नहीं थी।

इस्पात मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में अनुपालन मापदंड का मूल्यांकन मंत्रालय में किया गया था। हालांकि, चूंकि निदेशकों की नियुक्ति सीपीएसई के दायरे में नहीं है, इसलिए इस मापदंड को लागू नहीं माना गया।

एससीआई ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि उसने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से एससीआई बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए कई बार अनुरोध किया था, जिसमें दोनों स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाए गए जुर्माने और अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों का उल्लेख किया गया था जो उनके द्वारा जुर्माना पत्रों में शुरू करने के लिए बताए गए हैं।

एमओपीएसडब्लू ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि एससीआई और एमओपीएसडब्लू ने कई अवसरों पर नामांकन का अनुरोध करते हुए डीपीई से संपर्क किया था, किया था। एमओपीएसडब्लू ने आगे कहा कि अंतिम समझौता ज़ापन रेटिंग आईएमसी द्वारा निर्धारित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सचिव डीपीई, एससीआई, एमओपीएसडब्लू और अन्य प्रासंगिक मंत्रालयों के प्रतिनिधि कर रहे थे। अंतिम समझौता ज़ापन स्कोर प्रदान किए जाने से पहले इन बैठकों के दौरान सभी समझौता ज़ापन मापदंडों पर गहन विचार-विमर्श किया जाता है।

ईआईएल ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि गैर अनुपालन केवल स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण है जो ईआईएल के नियंत्रण से बाहर हैं, क्योंकि नियुक्ति प्राधिकारी भारत सरकार है।

एमओपीएंडएनजी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2025) कि सीपीएसई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति बहुस्तरीय और निरंतर प्रक्रिया है। मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है कि डीपीई/सेबी दिशानिर्देशों का पालन किया जाए। ऐसे प्रयासों के कारण, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से मई 2025 में ईआईएल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई है।

एचएएल ने उत्तर दिया (अगस्त 2025) कि रक्षा मंत्रालय ने डीपीई से दोनों वर्षों 2022-23 और 2023-24 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस मापदंड को माफ करने की अनुशंसा की है। इस अनुशंसा पर डीपीई द्वारा विचार किया गया था और 2022-23 और 2023-24 वर्षों के लिए एचएएल के समझौता जापन मूल्यांकन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित अनुपालन मापदंड के लिए अंक नहीं काटे गए थे। हालांकि, डीपीई ने इस संबंध में अलग से छूट पत्र जारी नहीं किया है।

रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि एचएएल के अनुरोध पर, एमओडी ने डीपीई को पत्र भेजकर वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए समझौता जापन के कॉर्पोरेट गवर्नेंस मापदंडों में नकारात्मक अंकन के साथ दंडित न करने का अनुरोध किया था और तदनुसार, समझौता जापन मूल्यांकन में अंक नहीं काटे गए।

एनएलसी ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए मामला कोयला मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

एमओसी ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि मंत्रालय ने स्वतंत्र निदेशक के पैनल की जांच के लिए एक शॉर्टलिस्टिंग समिति का गठन किया था। समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद, मार्च 2025 में एनएलसी के बोर्ड में दो नए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई है।

उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि 2022-23 और 2023-24 के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, सीपीएसई कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर सके।

संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में भी देखा जा सकता है कि मंत्रालय स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सुनिश्चित नहीं कर सके और यह पहलू निष्पादन के मूल्यांकन में भी परिलक्षित नहीं हुआ। लेखापरीक्षा ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि एनएलसी और ईआईएल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति क्रमशः मार्च 2025 और मई 2025 में जो कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में की गई है।

6.5.2.2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मापदंड के अनुपालन से छूट

समझौता जापन दिशानिर्देशों के अनुसार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी अधिनियम, 2013 {या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (एलओडीआर) विनियम} के अनुपालन के संबंध में समझौता जापन में

मापदंडों का एक समूह सम्मिलित किया गया है। डीपीई दिशानिर्देश सीपीएसई द्वारा इन अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा न करने पर नकारात्मक अंकन निर्धारित करते हैं। सीपीएसई द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित अनुपालन के लिए कुल पांच उप-मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें गैर अनुपालन के लिए कुल 3 अंकों का नकारात्मक अंकन (प्रत्येक अनुपालन मापदंड का भारांक 0.60 अंक) निर्धारित है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि एमओडी ने डीपीई से दोनों वर्षों 2022-23 और 2023-24 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस मापदंड को माफ करने की अनुशंसा की थी। इस अनुशंसा पर डीपीई द्वारा विचार किया गया था और वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए एचएएल के समझौता ज्ञापन मूल्यांकन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित अनुपालन मापदंडों के लिए अंक नहीं काटे गए थे। हालांकि, डीपीई ने इस संबंध में अलग से छूट पत्र जारी नहीं किया है।

साथ ही, एचएएल एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुपालन से ऐसी किसी भी छूट को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, डीपीई को वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए एचएएल के समझौता ज्ञापन स्कोर से 3 अंक काटने चाहिए थे। हालांकि, एचएएल ने क्रमशः 91.50 और 92.50 के स्कोर के साथ 2022-23 और 2023-24 के लिए "उत्कृष्ट" रेटिंग हासिल की।

डीपीई ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मापदंडों के अनुपालन के संबंध में सीपीएसई की कोई गलती नहीं थी, हालांकि डीपीई द्वारा इसके लिए कोई छूट नहीं दी गई थी।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि समझौता ज्ञापन में एक अनुपालन मापदंड के रूप में ऐसे पहलुओं को सम्मिलित करना, जो सीपीएसई के नियंत्रण में नहीं हैं, उस हद तक समझौता ज्ञापन प्रक्रिया की भावना के खिलाफ था।

6.5.2.3 'सीपीएसई में मानव संसाधनों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार' पर अनुपालन मापदंड

समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुपालन मापदंड सीपीएसई में मानव संसाधनों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार' के संबंध में लक्ष्य प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक था और इस अनुपालन मापदंड के अननुपालन पर एक अंक की कटौती की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो सीपीएसई (ईआईएल और एससीआई) के संबंध में, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा 2022-23 और 2023-24 के समझौता ज्ञापन के लिए सीपीएसई में मानव संसाधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार' मापदंड के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य तय नहीं किया गया था। हालांकि, डीपीई ने इस मापदंड के अनुपालन का उल्लेख किया और वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए समझौता ज्ञापन की मूल्यांकन प्रतिवेदन में कोई अंक नहीं काटा।

एमओपीएंडएनजी ने (अक्टूबर 2025) उत्तर दिया कि एचएसई लक्ष्यों को निर्धारित करना एक सामान्य डीपीई दिशानिर्देश था और ईआईएल, एक परामर्शदाता सीपीएसई होने के नाते, अपनी एचएसई नीति का पालन करता था।

एमओपीएसडब्लू ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि एससीआई सभी जहाजों और तट प्रतिष्ठानों पर आईएसओ 45001:2018 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) के अनुपालन में था और एमओपीएसडब्लू ने मानव संसाधनों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के सुधार के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने की प्रथा शुरू की है।

उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार मानव संसाधनों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था।

6.5.2.4 अनुपालन मापदंड - 'परिसंपत्ति मुद्रीकरण मील का पत्थर पर नीति आयोग द्वारा दिए गए लक्ष्य' को सम्मिलित न करना

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2023-24 के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ सभी चयनित सीपीएसई के हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में एक अनुपालन मापदंड "परिसंपत्ति मुद्रीकरण मील का पत्थर पर नीति आयोग द्वारा दिया गया लक्ष्य" सम्मिलित था।

हालांकि, यह देखा गया कि वर्ष 2023-24 के लिए इन सीपीएसई के निष्पादन के मूल्यांकन के दौरान, इस अनुपालन मापदंड को डीपीई पोर्टल/डैशबोर्ड से हटा दिया गया था, हालांकि यह अनुपालन मापदंड ई-हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का हिस्सा था।

इसके अलावा, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, समझौता ज्ञापन अनुपालन मापदंड 'परिसंपत्ति मुद्रीकरण मील के पत्थर' के लिए लक्ष्य नीति आयोग द्वारा दिए गए लक्ष्य के आधार पर तय किया जाना था और सीपीएसई द्वारा इस लक्ष्य की उपलब्धि का सत्यापन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नीति आयोग से पुष्टि के आधार पर किया जाना था। हालांकि, वर्ष 2022-23 के लिए, ईआईएल के संबंध में एमओपीएंडएनजी द्वारा उनके बोर्ड संकल्प के आधार पर इस अनुपालन मापदंड का सत्यापन किया गया था और नीति आयोग से पुष्टि प्राप्त नहीं की गई थी। इस मापदंड के गैर अनुपालन के लिए, ई-हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में एक अंक की कटौती निर्धारित थी।

ईआईएल/एमओपीएंडएनजी ने उत्तर दिया (जुलाई 2025/अक्टूबर 2025) कि उपरोक्त अनुपालन मापदंड बोर्ड द्वारा अनुमोदित इसकी मूल्यांकन प्रतिवेदन का हिस्सा था और बाद में डीपीई को प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, डीपीई के समझौता ज्ञापन पोर्टल पर उपलब्ध सिस्टम जनरेटेड मूल्यांकन प्रतिवेदन इसे प्रतिबिंबित नहीं कर रही थी।

उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में उल्लिखित इस अनुपालन मापदंड को समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के खिलाफ सीपीएसई की वास्तविक निष्पादन उपलब्धि को प्रतिबिंबित करने के लिए उक्त मापदंड के अननुपालन को समायोजित करने के लिए मूल्यांकन के समय डीपीई द्वारा पोर्टल पर बनाए रखा जाना चाहिए था।

इस प्रकार, हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में उल्लिखित अनुपालन मापदंडों को मूल्यांकन के समय पोर्टल पर बनाए न रखने के कारण, उस सीमा तक अंतिम रूप दिए गए समझौता ज्ञापन लक्ष्यों के खिलाफ सीपीएसई का वास्तविक निष्पादन परिलक्षित नहीं हो सका।

इस संबंध में डीपीई के उत्तर की प्रतीक्षा थी।

6.5.2.5 समझौता ज़ापन मूल्यांकन पर सीएजी की अभ्युक्तियाँ/अनुशंसाओं का प्रभाव

समझौता ज़ापन दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष की उपलब्धि का निर्धारण करते समय, राजस्व/लाभ/अधिशेष के अधिक आकलन या हानि/घाटे के कम आकलन के मामले में सीएजी/वैधानिक लेखा परीक्षक की मात्रात्मक अभ्युक्ति को समायोजित किया जाएगा।

एनएमडीसी के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2023-24 के लिए एनएमडीसी के वार्षिक खातों पर सीएजी द्वारा दो टिप्पणियाँ⁸⁰ जारी की गई थीं। हालांकि, कंपनी ने (i) राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए और (ii) नियोजित पूंजी पर रिटर्न के संदर्भ में स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत करते समय सीएजी की टिप्पणियों के प्रभाव पर विचार नहीं किया।

एनएमडीसी ने उत्तर दिया (जून 2025) कि डीपीई ने समझौता ज़ापन दिशानिर्देशों 2023-24 के अनुपालन में वित्तीय स्थिति पर सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर 2023-24 के लिए ₹12.39 करोड़ से लाभ को समायोजित किया है और अंतिम अंक दिए हैं।

यह उत्तर पुष्टि करता है कि कंपनी ने स्व-मूल्यांकन के दौरान लाभ के समायोजन पर विचार नहीं किया था। इसके अलावा, प्रबंधन ने सीएजी की टिप्पणियों के आधार पर लाभ में डीपीई द्वारा किए गए समायोजन को सत्यापित करने के लिए सहायक दस्तावेज प्रदान नहीं किए।

एमओएस ने इस अवलोकन पर कोई टिप्पणी नहीं दी।

6.5.3 समझौता ज़ापन के मूल्यांकन से संबंधित मुद्दे

6.5.3.1 डीपीई डैशबोर्ड पर समझौता ज़ापन मापदंडों के अनुमानित आंकड़े अपलोड करने में विलंब

समझौता ज़ापन दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को समझौता ज़ापन वित्तीय वर्ष से पिछले वित्तीय वर्ष (अर्थात्, आधार वर्ष) के 31 दिसंबर तक डैशबोर्ड पर कुछ वित्तीय और भौतिक विशेषताओं के अनुमानित आंकड़े अपलोड करने की आवश्यकता थी। तदनुसार, समझौता ज़ापन वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए इन्हें क्रमशः 31 दिसंबर 2021 और 31 दिसंबर 2022 तक अपलोड किया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छः चयनित सीपीएसई द्वारा अनुमानित आंकड़े 2022-23 के लिए 87 से 104 दिनों की विलंब से और 2023-24 के लिए 55 से 76 दिनों की विलंब से अपलोड किए गए थे, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

⁸⁰ (i) बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल) को रेलवे को सौंपने की जानकारी न देना और बीआरपीएल से जुड़ी एफआईआर और अदालती मामले, और (ii) बोर्ड से (बट्टे खाते में डालने) की मंजूरी मिलने के बावजूद आंध्र प्रदेश सरकार को दी गई परफॉर्मेंस गारंटी के लिए प्रावधान न करने के कारण 'प्रोविज़न' और 'अन्य खर्चों' को ₹12.39 करोड़ से कम दिखाना, जिससे मुनाफ़ा ज़्यादा दिखाया गया।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम का नाम	2022-23 के लिए अनुमानित आंकड़े अपलोड करने की तारीख	विलंब (दिनों में)	2023-24 के लिए अनुमानित आंकड़े अपलोड करने की तारीख	विलंब (दिनों में)
1	एनएमडीसी	12.04.2022	102	17.03.2023	76
2	नाल्को	12.04.2022	102	24.02.2023	55
3	एनएलसी	14.04.2022	104	11.03.2023	70
4	एससीआई	28.03.2022	87	24.02.2023	55
5	एचएएल	28.03.2022	87	27.02.2023	58
6	ईआईएल	12.04.2022	102	26.02.2023	57

इस विलंब का मुख्य कारण डीपीई की ओर से अनुमानित आंकड़ों को अपलोड करने के लिए पोर्टल उपलब्ध कराने में विलंब था क्योंकि यह डीपीई द्वारा 2022-23 और 2023-24 के लिए क्रमशः 74 दिन और 47 दिन के विलंब के साथ 15 मार्च 2022 और 16 फरवरी 2023 को उपलब्ध कराया गया था।

डीपीई से उत्तर की प्रतीक्षा थी।

6.5.3.2 डीपीई द्वारा समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन/अंकन में लिया गया समय

समझौता ज्ञापन लक्ष्यों के खिलाफ सीपीएसई का वास्तविक निष्पादन प्रत्येक मापदंड के लिए कच्चे स्कोर और व्यक्तिगत मापदंडों के भारित स्कोर को जोड़कर गणना किए गए एक समग्र स्कोर में परिलक्षित होता है। जैसे ही सीपीएसई का वास्तविक निष्पादन सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा डीपीई को प्रस्तुत किया जाता है, डीपीई में वास्तविक निष्पादन के अंकन/समीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने, हालांकि, पाया कि डीपीई द्वारा संबंधित सीपीएसई को समझौता ज्ञापन के अंकन/रैंकिंग को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के लिए समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों में कोई समयसीमा तय नहीं की गई थी।

समझौता ज्ञापन डैशबोर्ड/पोर्टल की समीक्षा से पता चला कि डीपीई ने छः चयनित सीपीएसई के संबंध में वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए अंतिम रैंकिंग/स्कोर प्रदान करने में क्रमशः 55 से 100 दिन और 68 से 92 दिन का काफी समय लिया था, जैसा कि नीचे तालिका में विस्तृत है:

तालिका 6.5: वर्ष 2022-23 के लिए डीपीई द्वारा समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम का नाम	समझौता ज्ञापन पोर्टल पर सीपीएसई द्वारा समझौता ज्ञापन लक्ष्यों पर निष्पादन मूल्यांकन अपलोड करने की तिथि	मंत्रालय द्वारा निष्पादन मूल्यांकन अपलोड करने की तिथि	निष्पादन मूल्यांकन अपलोड करने की तिथि	मंत्रालय द्वारा अपलोड करने से निष्पादन मूल्यांकन के लिए डीपीई द्वारा लिया गया समय
1.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	26.10.2023	31.10.2023	07.02.2024	99 दिन

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम का नाम	समझौता जापन पोर्टल पर सीपीएसई द्वारा समझौता जापन लक्ष्यों पर निष्पादन मूल्यांकन अपलोड करने की तिथि	मंत्रालय द्वारा निष्पादन मूल्यांकन अपलोड करने की तिथि	निष्पादन मूल्यांकन अपलोड करने की तिथि	मंत्रालय द्वारा अपलोड करने से निष्पादन मूल्यांकन के लिए डीपीई द्वारा लिया गया समय
2.	एनएमडीसी लिमिटेड	10.11.2023	15.11.2023	07.02.2024	84 दिन
3.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	27.10.2023	31.10.2023	07.02.2024	99 दिन
4.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	31.10.2023	31.10.2023	08.02.2024	100 दिन
5.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	30.10.2023	09.11.2023	07.02.2024	90 दिन
6.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	30.10.2023	01.11.2023	26.12.2023	55 दिन

तालिका 6.5: वर्ष 2023-24 के लिए डीपीई द्वारा समझौता जापन का मूल्यांकन

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम का नाम	समझौता जापन पोर्टल सीपीएसई द्वारा समझौता जापन लक्ष्यों पर निष्पादन मूल्यांकन अपलोड करने की तिथि	मंत्रालय द्वारा निष्पादन मूल्यांकन अपलोड करने की तिथि	डीपीई द्वारा निष्पादन मूल्यांकन अपलोड करने की तिथि	मंत्रालय द्वारा अपलोड करने से निष्पादन मूल्यांकन के लिए डीपीई द्वारा लिया गया समय
1.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	07.10.2024	09.10.2024	09.01.2025	92 दिन
2.	एनएमडीसी लिमिटेड	14.10.2024	16.10.2024	09.01.2025	85 दिन
3.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	14.10.2024	15.10.2024	06.01.2025	83 दिन
4.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	09.10.2024	24.10.2024	10.01.2025	78 दिन
5.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	15.10.2024	24.10.2024	09.01.2025	77 दिन
6.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	08.10.2024	30.10.2024	06.01.2025	68 दिन

सीपीएसई की रैंकिंग/अंकन को अंतिम रूप देने में लिया गया काफी समय न केवल समझौता जापन तंत्र की भावना के खिलाफ था बल्कि सीपीएसई के पास पिछले वर्ष की तुलना में अपने निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए बहुत कम समय बचा था।

डीपीई ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि समझौता जापन तंत्र सीपीएसई के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करने या पाठ्यक्रम सुधार की सुविधा के लिए लक्षित उपकरण नहीं है। मूल्यांकन में लगने वाला समय सीपीएसई के निष्पादन को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है क्योंकि सीपीएसई के साथ-साथ प्रशासनिक मंत्रालयों को भी अपने निष्पादन के बारे में पहले से अच्छी तरह पता होता है। डीपीई द्वारा समझौता जापन का मूल्यांकन सीपीएसई की समझौता जापन रेटिंग को सत्यापित करने और घोषित करने तक सीमित है।

डीपीई के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि समझौता जापन दिशानिर्देशों के अनुसार, समझौता जापन मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य सीपीएसई के मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में उनकी प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए उनका नियमित निष्पादन मूल्यांकन करना है। इसलिए, सीपीएसई की रैंकिंग उचित समय में की जानी चाहिए ताकि अन्य हितधारक भी सीपीएसई के निष्पादन से अवगत हों और सीपीएसई द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

6.5.3.3 समझौता जापन के ई-हस्ताक्षर के बाद पूंजीगत व्यय लक्ष्य का संशोधन/कमी

वर्ष 2022-23 के लिए एमओपीएंडएनजी और ईआईएल के बीच समझौता जापन पर 21 दिसंबर 2022 को ई-हस्ताक्षर किए गए थे अर्थात्, 2022-23 की तीसरी तिमाही के अंत में। समझौता जापन में, पूंजीगत व्यय मापदंडों में से एक था और इस मापदंड के लिए लक्ष्य ₹160 करोड़ था। समझौता जापन के ई-हस्ताक्षर के बाद, पूंजीगत व्यय मापदंड के खिलाफ लक्ष्य को फरवरी 2023 में ₹160 करोड़ से घटाकर ₹70 करोड़ कर दिया गया था अर्थात्, 56.25 प्रतिशत की कमी की गई थी। डीपीई ने संशोधित/कम किए गए समझौता जापन लक्ष्य के आधार पर पूंजीगत व्यय मापदंड का भी मूल्यांकन किया।

ईआईएल/एमओपीएंडएनजी ने उत्तर दिया (जुलाई 2025/अक्टूबर 2025) कि हमारे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर संशोधित अनुमानों की तैयारी के समय पूंजीगत व्यय को संशोधित कर ₹70 करोड़ कर दिया गया था और इसे अनुमोदन के लिए मंत्रालय के समक्ष रखा गया था। उक्त संशोधन को बजट परिपत्र का हिस्सा बनाया गया था और संशोधित पूंजीगत व्यय ₹70 करोड़ केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज के विवरण 26 में परिलक्षित हुआ था जो वर्ष 2022-23 के लिए समझौता जापन को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने के बाद फरवरी 2023 में प्रकाशित हुआ था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि पूंजीगत व्यय मापदंड के लिए लक्ष्य को समझौता जापन के ई-हस्ताक्षर के बाद संशोधित किया गया था, जो स्वयं 2022-23 की तीसरी तिमाही के अंत में हस्ताक्षरित किया गया था। इस प्रकार, सीपीएसई के पास आंतरिक मूल्यांकन करने और समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने से पहले एमओपीएंडएनजी से अनुरोध करने के लिए पर्याप्त समय था।

6.5.4 सीपीएसई और प्रशासनिक मंत्रालय की वेबसाइट पर समझौता जापन को प्रदर्शित न करना

उनके प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ एनएमडीसी (23 सितंबर 2022) और ईआईएल (09 सितंबर 2022) को पोर्टल जनरेटेड समझौता जापन अग्रेषित करते समय, डीपीई ने निर्धारित समय अवधि के भीतर समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने और उन्हें अपनी वेबसाइटों पर पोस्ट करने का अनुरोध किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएमडीसी/एमओएस और ईआईएल/एमओपीएंडएनजी ने क्रमशः वर्ष 2022-

23 और 2023-24 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज़ापन को अपनी सार्वजनिक वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया।

एनएमडीसी ने उत्तर दिया (जून 2025) कि उसने सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट (इंट्रानेट) में समझौता ज़ापन पोस्ट किया है।

एमओएस ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि एनएमडीसी को हस्ताक्षरित समझौता ज़ापन की प्रति अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने की सलाह दी गई है और मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज़ापन को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। मंत्रालय ने आगे उत्तर दिया कि भविष्य में, सभी हस्ताक्षरित समझौता ज़ापनों को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

ईआईएल (जुलाई 2025) ने उत्तर दिया कि संबंधित लक्ष्यों पर जानकारी का प्रसार करने के लिए सभी ईआईएल कर्मचारियों के लिए सुलभ इसके इंट्रानेट पर समझौता ज़ापन प्रकाशित किया गया था।

एमओपीएंडएनजी ने, ईआईएल के उत्तर की पुष्टि करते हुए कहा (अक्टूबर 2025) कि कंपनी की वेबसाइट पर समझौता ज़ापन को प्रदर्शित करना डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।

एनएमडीसी और ईआईएल के उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि डीपीई के निर्देशों के बावजूद, समझौता ज़ापनों को केवल इंट्रानेट पर होस्ट किया गया था जिसे कर्मचारियों द्वारा एक्सेस किया जा सकता था और सार्वजनिक वेबसाइट पर होस्ट नहीं किया गया था।

अध्याय VII

विनिवेश प्रक्रिया

अध्याय VII

विनिवेश प्रक्रिया

7.1 भारत सरकार की विनिवेश नीति

वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक परि संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में इक्विटी के विनिवेश सहित इक्विटी में केंद्र सरकार के निवेश के प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों को देखता है। इसके कार्य के प्रमुख क्षेत्र रणनीतिक विनिवेश से जुड़े हैं, जिसमें निजीकरण और अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री शामिल हैं।

भारत सरकार की वर्तमान विनिवेश नीति में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री और सीपीएसई का रणनीतिक विनिवेश सम्मिलित है। व्यावसायिक उद्यमों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को पुनर्गठित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, 4 फरवरी 2021 को 'आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति' अधिसूचित की गई थी। इस नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की उपस्थिति को न्यूनतम करना है और यह रणनीतिक विनिवेश पर समग्र मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, वित्तीय सेवाओं के प्रावधान और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता के मानदंडों के आधार पर चार⁸¹ रणनीतिक क्षेत्रों को रेखांकित करती है। रणनीतिक क्षेत्रों में, होल्डिंग कंपनी स्तर पर मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक उद्यमों की न्यूनतम उपस्थिति को सरकारी नियंत्रण में बनाए रखा जाएगा। शेष उद्यमों पर निजीकरण या विलय या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ सहायक कंपनी बनाने या बंद करने पर विचार किया जाएगा।
- गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर, जहाँ भी व्यवहार्य हो, निजीकरण के लिए विचार किया जाएगा, अन्यथा ऐसे उद्यमों को बंद करने पर विचार किया जाएगा।

यह नीति सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ श्रेणियों की संस्थाओं पर लागू नहीं होती है, जैसे कि गैर-लाभकारी कंपनियां, या कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या विकासात्मक/प्रवर्धनात्मक भूमिका निभाने वाले उद्यम आदि।

⁸¹ (i) परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा; (ii) परिवहन और दूरसंचार; (iii) विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज और (iv) बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं।

भारत सरकार ने निर्णय लिया (19 अप्रैल 2022) कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (केंद्रीय/राज्य/संयुक्त)/राज्य सरकारों/सरकार द्वारा नियंत्रित सहकारी समितियों (यानी जहाँ 51 प्रतिशत या अधिक स्वामित्व केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संयुक्त रूप से केंद्र और/या राज्य सरकारों के पास है) को अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश/निजीकरण में बोलीदाता के रूप में भाग लेने की अनुमति नहीं है, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा जनहित में विशेष रूप से इसकी स्वीकृति न दी गई हो।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीआई) ने नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे (13 दिसंबर 2021), जो अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों, नीति आयोग, व्यय विभाग और दीपम के परामर्श से गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सीपीएसई को बंद करने या निजीकरण के लिए उनकी पहचान करने का प्रावधान करता है।

भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडल को अपनी किसी भी सहायक कंपनी या इकाइयों के विनिवेश (रणनीतिक विनिवेश और अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री दोनों) या उन्हें बंद करने या संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी बेचने के लिए अनुशंसा करने और लेनदेन करने के लिए सशक्त किया (1 जून 2022)। यह भी स्वीकृति दी गई कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के बोर्ड और प्रशासनिक मंत्रालय के प्रस्ताव के आधार पर, दीपम वैकल्पिक तंत्र⁸² की 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्राप्त करेगा। इसके बाद, सीपीएसई के बोर्ड दीपम या डीपीई के दिशानिर्देशों के आधार पर सहायक कंपनियों/इकाइयों/संयुक्त उद्यमों के विनिवेश या उन्हें बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

दीपम ने रणनीतिक विनिवेश सहायक कंपनियों/इकाइयों में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री/होलडिंग/मूल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी की बिक्री के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए (14 सितंबर 2022), जबकि डीपीई ने होलडिंग/मूल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उनकी सहायक कंपनियों/इकाइयों को बंद करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए (31 अक्टूबर 2022)।

7.2 विनिवेश के तरीके

सरकार विनिवेश के विभिन्न तरीके अपनाती है, जो इस प्रकार हैं:

- (i) रणनीतिक विनिवेश: इसका तात्पर्य प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की सरकारी शेयरधारिता की पूर्ण या महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की बिक्री से है। निजीकरण के मामले में, जो रणनीतिक विनिवेश का ही एक हिस्सा है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में सरकारी इक्विटी और उसका प्रबंधन नियंत्रण एक निजी रणनीतिक खरीदार (या खरीदारों) को हस्तांतरित कर दिया जाता है और रणनीतिक विनिवेश के अन्य मामलों में, सरकारी इक्विटी नियंत्रण के साथ किसी अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को हस्तांतरित कर दी जाती है।

⁸² वैकल्पिक तंत्र में वित्त मंत्री, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री और संबंधित सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय के मंत्री शामिल होते हैं।

(ii) अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री: कुछ सीपीएसई में, प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के बिना, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अनुमोदित विभिन्न तरीकों से अल्पसंख्यक हिस्सेदारी की बिक्री की जाती है ताकि मूल्य को अनलॉक किया जा सके, सार्वजनिक स्वामित्व को बढ़ावा दिया जा सके, सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों को पूरा किया जा सके और निम्नलिखित माध्यमों से उच्च स्तर की उत्तरदेही सुनिश्चित की जा सके:

- प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ): जब एक असूचीबद्ध कंपनी पहली बार जनता के लिए शेयरों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का नया अंक जारी करती है या अपने मौजूदा शेयरों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए प्रस्तुत करती है या दोनों करती है, तो इसे आईपीओ कहा जाता है।
- फर्दर पब्लिक ऑफर (एफपीओ): जब एक पहले से सूचीबद्ध कंपनी जनता के लिए शेयरों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का नया अंक जारी करती है या जनता के लिए बिक्री का प्रस्ताव लाती है, तो इसे एफपीओ कहा जाता है।
- बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस): यह सूचीबद्ध कंपनियों के लिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयरों की बिक्री का एक सरल तरीका है। इस पद्धति को मुख्य रूप से सूचीबद्ध कंपनियों, सरकारी और निजी दोनों द्वारा, न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के सेबी मानदंडों का पालन करने के लिए अपनाया गया था। सरकार ने अक्सर सीपीएसई में अपनी शेयरधारिता बेचने के लिए इस मार्ग का उपयोग किया है।
- शेयरों का बायबैक: यह किसी कंपनी द्वारा अपने मौजूदा शेयरधारकों से अपने ही शेयरों की पुनर्खरीद है, जिससे खुले बाजार में उसके शेयरों की संख्या कम हो जाती है।
- एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ): इस पद्धति के तहत, सीपीएसई के शेयरों के एक बास्केट का उपयोग सरकार द्वारा विनिवेश के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में किया जाता है। हालांकि, मौजूदा ईटीएफ विंडो के माध्यम से विनिवेश के सीमित दायरे के कारण, सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री के उपकरण के रूप में इक्विटी ईटीएफ का उपयोग करने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

7.3 विनिवेश की प्रक्रिया

7.3.1 सीपीएसई का रणनीतिक विनिवेश:

(i) रणनीतिक क्षेत्रों के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम:

- नीति आयोग उन सीपीएसई की अनुशंसा करता है जिन्हें सरकारी नियंत्रण में रखा जाना है या जिन्हें निजीकरण या विलय या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ सहायक कंपनी बनाने या बंद करने के लिए विचार किया जाना है।

- नीति आयोग की अनुशंसाएँ विनिवेश पर सचिवों के कोर समूह⁸³ (सीजीडी) को सौंपी जाती हैं।
- सीजीडी की अनुशंसाएँ वैकल्पिक तंत्र (एएम) के समक्ष रखी जाती हैं।
- एएम उन सीपीएसई को स्वीकृति देता है जिन्हें सरकारी नियंत्रण में बनाए रखा जाना है या निजीकरण या विलय या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ सहायक कंपनी बनाने या बंद करने के लिए विचार किया जाना है।
- दीपम, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रणनीतिक विनिवेश के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करता है।
- दीपम, अंतर-मंत्रालयी समूह के अनुमोदन से टेंडरिंग के माध्यम से लेनदेन सलाहकारों/कानूनी सलाहकारों /परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति करता है।
- इसके अलावा, दो-चरणीय बोली प्रक्रिया (आरएफपी/ईओआई) का पालन किया जाता है। प्रत्येक चरण में, प्रक्रिया स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार बहु-स्तरीय निर्णय लेने के तंत्र से गुजरती है।

(ii) गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम:

- डीपीई संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों, नीति आयोग, व्यय विभाग और दीपम के परामर्श से बंद करने या निजीकरण के लिए सीपीएसई की पहचान करता है।
- डीपीई बंद करने और/या विनिवेश के लिए पहचाने गए सीपीएसई के संबंध में सीसीईए की सैद्धांतिक स्वीकृति लेता है।
- डीपीई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के निजीकरण/विनिवेश के लिए सीसीईए की सैद्धांतिक स्वीकृति से दीपम को अवगत कराता है। हालांकि, बंद करने के मामले में प्रक्रिया प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा शुरू की जाती है।
- दीपम वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई करता है।

7.3.2 अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री के मामले में विनिवेश प्रक्रिया:

(i) आईपीओ/ एफपीओ के माध्यम से अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री:

- संबंधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के प्रशासनिक मंत्रालय की सैद्धांतिक सहमति ली जाती है।
- सीसीईए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी के विनिवेश को स्वीकृति देता है।

⁸³ विनिवेश पर सचिवों के कोर समूह की अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिव द्वारा की जाती है तथा इसमें आर्थिक कार्य विभाग के सचिव, राजस्व सचिव, व्यय सचिव, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव, कॉर्पोरेट कार्य सचिव, विधि कार्य सचिव तथा संबंधित प्रशासनिक विभाग के सचिव शामिल होते हैं।

- विनिवेश प्रक्रिया के मार्गदर्शन और देखरेख के लिए एक उच्च स्तरीय समिति⁸⁴ का गठन किया जाता है।
- दीपम अंतर-मंत्रालयी समूह⁸⁵ का गठन करता है। प्रस्तावित लेनदेन के लिए सलाहकारों (मर्चेन्ट बैंकर्स/बुक रनिंग लीड मैनेजर्स और कानूनी सलाहकारों) की नियुक्ति अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा की जाती है।
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के समक्ष ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रस्तुत किया जाता है।
- उच्च स्तरीय समिति बुक रनिंग लीड मैनेजर की सलाह पर विचार करने के बाद वैकल्पिक तंत्र को प्राइस बैंड/फ्लोर प्राइस की अनुशंसा करती है।
- दीपम, प्रशासनिक मंत्रालय और सीपीएसई के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू नॉन-डील रोड शो आयोजित करता है।
- सेबी के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दायर किया जाता है।
- वैकल्पिक तंत्र प्राइस बैंड/फ्लोर प्राइस, विनिवेश की विधि और खुदरा निवेशकों एवं कर्मचारियों के लिए मूल्य छूट पर निर्णय लेता है।

(ii) ओएफएस के माध्यम से अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री:

- दीपम अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन करता है। इस प्रक्रिया में सहायता के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह मर्चेन्ट बैंकर्स-सह-बिक्री ब्रोकर्स (एमबीएसबी) और कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति करता है।
- मर्चेन्ट बैंकर्स समय, शेयरों की संख्या और दी जाने वाली छूट की अनुशंसा करते हैं। संबंधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, प्रशासनिक मंत्रालय और दीपम के साथ मिलकर नॉन-डील रोड शो करते हैं।
- कानूनी सलाहकार मौजूदा वैधानिक शासनादेशों के अनुरूप कानूनी दस्तावेज तैयार करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- दीपम, अपने और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों को मिलाकर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन करता है।
- एचएलसी, एमबीएसबी की अनुशंसाओं पर विचार करती है और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में भारत सरकार की शेयरधारिता में से चुकता इक्विटी के आगे के विनिवेश के लिए मात्रा, मोड और विनिवेश की सीमा, आरक्षण का प्रतिशत, खुदरा निवेशकों को छूट और फ्लोर प्राइस तय करने आदि पर एएम को अनुशंसाएँ करती है।

⁸⁴ उच्च स्तरीय समिति में दीपम के सचिव, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार शामिल होते हैं।

⁸⁵ अंतर-मंत्रालयी समूह में दीपम, प्रशासनिक मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), व्यय विभाग (डीओई) और विधि मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

- वैकल्पिक तंत्र एचएलसी की अनुशंसा पर विचार करता है और अपनी स्वीकृति देता है।

7.3.3 एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सरकारी शेयरधारिता का बायबैक:

- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और दीपम द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी नेटवर्थ और कैश बैलेंस के आधार पर बायबैक पर विचार करता है, जब तक कि अंतर-मंत्रालयी समिति यानी 'सीपीएसई में पूंजी प्रबंधन और लाभांश की निगरानी के लिए समिति' द्वारा छूट न दी गई हो। उच्च स्तरीय समिति केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के बायबैक के प्रस्ताव में सरकार की भागीदारी पर वैकल्पिक तंत्र को अनुशंसा करती है।
- वैकल्पिक तंत्र द्वारा बायबैक (शेयरों की पुनर्खरीद) में सरकार की भागीदारी और उक्त बायबैक में सरकारी इक्विटी की पेशकश को स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7.4 सीपीएसई के विनिवेश के लिए लक्ष्य और उपलब्धि

वर्ष 2023-24 के लिए विनिवेश के माध्यम से प्राप्तियों का बजट अनुमान आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ₹51,000 करोड़ निर्धारित किया गया था। हालांकि, संशोधित अनुमान के चरण में, "विविध पूंजी प्राप्तियां - प्राप्तियां" ₹30,000 करोड़ अनुमानित की गई थीं, जिसमें विनिवेश की तत्कालीन श्रेणियों और संपत्ति मुद्रीकरण जैसी अन्य पूंजी प्राप्तियों के तहत प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाना था। वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों के साथ-साथ वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों में विनिवेश के लिए कोई विशिष्ट अनुमान नहीं लगाया गया था।

वर्ष 2023-24 के दौरान वास्तविक विनिवेश प्राप्तियां ₹16,507.29 करोड़ थीं, यानी विविध पूंजी प्राप्तियों के संशोधित अनुमान से 45 प्रतिशत कम।

लक्ष्य-आधारित विनिवेश दृष्टिकोण को बंद करने पर वित्त संबंधी स्थायी समिति (अठारहवीं लोकसभा) (अनुदान की मांगें 2024-25) द्वारा भी विचार-विमर्श किया गया था। समिति ने विनिवेश के लिए लक्ष्य-उन्मुख और राजस्व-केंद्रित दृष्टिकोण को बंद करने के सरकार के निर्णय को टिप्पण किया। समिति ने मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि विनिवेश की प्राथमिकता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और इसे परिचालन दक्षता बढ़ाने तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए दीर्घकालिक मूल्य को अधिकतम करने एवं सरकार के लिए रिटर्न को अनुकूलित करने के उद्देश्य से सही भावना के साथ किया जाना चाहिए।

दीपम ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि सरकार लक्ष्य-उन्मुख दृष्टिकोण से दूर हट गई है और 2023-24 (संशोधित अनुमान चरण) से, सीपीएसई से विनिवेश प्राप्तियों के लिए कोई अलग विशिष्ट अनुमान नहीं दिया गया था।

7.5 विनिवेश से माध्यम-वार प्राप्तियां

भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न माध्यमों/मार्गों से 15 मामलों में अपने शेयरों का विनिवेश किया, जिसका विवरण नीचे तालिका 7.1 में दिया गया है:

तालिका 7.1: 2023-24 के दौरान माध्यम-वार विनिवेश प्राप्तियां

क्र. सं.	विनिवेश का तरीका	लेनदेन की संख्या	प्राप्तियां (₹ करोड़ में)
1.	रणनीतिक विनिवेश	0	0
2.	बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस)	12	13,770.13
3.	शेयरों का बायबैक	0	0
4.	भारतीय यूनिट ट्रस्ट के निर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई ⁸⁶) से प्रेषण	1	1,810.33
5.	शत्रु शेयरों की बिक्री	0	0
6.	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव	1	858.36
7.	खुला बाजार बिक्री	1	68.47
	योग	15	16,507.29

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, दीपम ने वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न माध्यमों से विनिवेश से ₹16,507.29 करोड़ प्राप्त किए, जिनकी चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

7.6 अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री - प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव और बिक्री के लिए प्रस्ताव

7.6.1 प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से विनिवेश से प्राप्ति

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, जिसमें बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) सम्मिलित था, 21-23 नवंबर 2023 की अवधि के दौरान लॉन्च किया गया था। कुल चुकता इक्विटी का 25 प्रतिशत (15 प्रतिशत आईपीओ द्वारा और 10 प्रतिशत ओएफएस द्वारा) बेचा गया, जिससे ₹858.36 करोड़ की प्राप्ति हुई। आईपीओ/ओएफएस के पूरा होने के बाद इरेडा में भारत सरकार की शेयरधारिता घटकर 75 प्रतिशत रह गई।

7.6.2 बिक्री के लिए प्रस्ताव

7.6.2.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, दीपम ने निम्नलिखित बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) लेनदेन पूरे किए, जिससे कुल ₹13,770.13 करोड़ की विनिवेश प्राप्तियां हुईं:

⁸⁶ इसमें एक्सिस बैंक में एसयूयूटीआई की रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री से मिली ₹40.33 करोड़ की आय शामिल है।

तालिका 7.2: 2023-24 के दौरान ओएफएस के माध्यम से विनिवेश से प्राप्ति

क्र. सं.	सीपीएसई के नाम	विनिवेश की विधि	विनिवेश किए गए भारत सरकार के शेयरों का %	विनिवेश के बाद भारत सरकार की शेयरधारिता	प्राप्तियां (₹ करोड़ में)
1.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	कर्मचारी ओएफएस	0.01	71.64	9.30
2.	कोल इंडिया लिमिटेड	ओएफएस	3	63.13	4,185.31
3.	कोल इंडिया लिमिटेड	कर्मचारी ओएफएस	0*	63.13	0.38
4.	रेल विकास निगम लिमिटेड	ओएफएस	5.36	72.84	1,365.61
5.	एसजेवीएन लिमिटेड	ओएफएस	4.92	55	1,348.47
6.	एसजेवीएन लिमिटेड	कर्मचारी ओएफएस	0*	55	0.80
7.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ओएफएस	6.64	75.17	1,049.95
8.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	ओएफएस	8	65.18	1,191.13
9.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	कर्मचारी ओएफएस	0.01	65.17	2.09
10.	एनएचपीसी लिमिटेड	ओएफएस	3.5	67.45	2,452.59
11.	एनएचपीसी लिमिटेड	कर्मचारी ओएफएस	0*	67.45	35.86
12.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	ओएफएस	7	72.2	2,128.64
	योग				13,770.13

* विनिवेश किए गए शेयरों का प्रतिशत 0.01 से कम था

एसजेवीएन लिमिटेड और एनएचपीसी लिमिटेड के विनिवेश लेनदेन से संबंधित रिकॉर्ड दीपम द्वारा लेखापरीक्षा के साथ साझा नहीं किए गए, और यह कहा गया (मई 2025) कि चूंकि लेनदेन पूरे नहीं हुए थे, इसलिए लेनदेन की मूल्य-संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए फाइलों को साझा नहीं किया जा सकता था। शेष ओएफएस लेनदेन में से, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

(i) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

वैकल्पिक तंत्र ने उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं पर, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की चुकता इक्विटी के 1.75 प्रतिशत के विनिवेश को 'बिक्री के लिए प्रस्ताव' (ओएफएस) के माध्यम

से स्वीकृति दी (22 मार्च 2023), जिसमें ओवर-सब्सक्रिप्शन के मामले में चुकता इक्विटी के 1.75 प्रतिशत तक अतिरिक्त शेयर बेचने का विकल्प सम्मिलित था।

एचएएल का ओएफएस 23 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया था और एचएएल की कुल चुकता इक्विटी का 3.50 प्रतिशत बेचा गया था, जिससे ₹2,901.09 करोड़ की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा, अप्रैल 2023 में एचएएल का कर्मचारी ओएफएस (0.0113 प्रतिशत) पूरा हुआ। ओएफएस पूरा होने के बाद एचएएल में भारत सरकार की शेयरधारिता घटकर 71.64 प्रतिशत रह गई।

सेबी के नियमों (जनवरी 2023) के खंड नंबर 4.1 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से बिक्री के प्रस्ताव के बारे में विज्ञापन तब जारी किया जाना होता है जब शेयरों की बिक्री के प्रस्ताव की घोषणा/सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को उपलब्ध करा दी गई हो। दीपम ने अपने पत्रों दिनांक 22 मार्च और 23 मार्च 2023 के माध्यम से एचएएल से आवश्यक कार्रवाई करने और कंपनी की एक विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती डीएवीपी) की दरों पर 23 मार्च 2023 और 24 मार्च 2023 को विज्ञापन जारी करना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। खर्च पहले कंपनी द्वारा वहन किया जाना था और बाद में दीपम द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दीपम ने गैर-डीएवीपी दरों पर किए गए विज्ञापन व्यय के लिए ₹21.11 लाख की राशि (डीएवीपी दरों से ज्यादा) का भुगतान किया था। गैर-डीएवीपी दरों पर विज्ञापन देने के लिए एचएएल द्वारा उद्धृत कारण यह था कि कुछ समाचार पत्रों ने उन्हें डीएवीपी दरें नहीं दीं क्योंकि वे एचएएल को एक व्यावसायिक संगठन मानते थे। लेखापरीक्षा में, हालांकि, यह देखा गया कि समाचार पत्रों में जो विज्ञापन छपा था वह 'रक्षा मंत्रालय' के नाम पर था और एचएएल के इक्विटी शेयरों की बिक्री के प्रस्ताव के संबंध में भारत के राष्ट्रपति की ओर से था।

दीपम ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि चूंकि विज्ञापन के लिए खरीद आदेश एचएएल द्वारा दिया गया था और चालान एचएएल के नाम पर जारी किया जाना था, इसलिए कुछ समाचार पत्र डीएवीपी दरों के लिए सहमत नहीं हुए। इसके अलावा, ओएफएस लेनदेन के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने सहित सभी औपचारिकताओं को लेनदेन के दिन के पिछले दिन के दोपहर के बाद से देर शाम तक बहुत कम समय में एक क्रमवार तरीके से पूरा किया जाना आवश्यक था। चूंकि समाचार पत्रों से आम तौर पर टी-1 दिन की देर शाम को संपर्क किया जाता है, इसलिए संबंधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा ऑर्डर देने के लिए बहुत सीमित समय उपलब्ध था। प्रतिपूर्ति के समय, एचएएल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर दीपम द्वारा उचित विचार किया गया था और आईएफयू की सहमति तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, दीपम द्वारा प्रतिपूर्ति की गई थी।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि चूंकि ओएफएस लेनदेन भारत सरकार द्वारा किए जा रहे थे और विज्ञापन भारत सरकार के नाम पर दिए गए थे, इसलिए डीएवीपी दरों का विस्तार न करना न्यायसंगत नहीं था। दीपम लेनदेन पूरा होने के बाद, भारत सरकार या उसके विभागों की ओर से प्रकाशित विज्ञापन के लिए कुछ समाचार पत्रों द्वारा गैर-डीएवीपी दरें वसूलने के बारे में केंद्रीय संचार ब्यूरो के समक्ष मामला उठा सकता था, क्योंकि समाचार पत्र एजेंसियां भारत सरकार से संबंधित विज्ञापनों के लिए डीएवीपी दरों का विस्तार करने के लिए संविदात्मक रूप से बाध्य थीं।

(ii) रेल विकास निगम लिमिटेड

वैकल्पिक तंत्र ने, एचएलसी की अनुशंसा के आधार पर, रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) में 3.4 प्रतिशत चुकता इक्विटी शेयरों के विनिवेश को स्वीकृति दी (26 जुलाई 2023), जिसमें सरकार की वर्तमान 78.20 प्रतिशत शेयरधारिता में से ओवर-सब्सक्रिप्शन के मामले में चुकता इक्विटी के 1.96 प्रतिशत तक अतिरिक्त शेयर बेचने का विकल्प था। गैर-खुदरा श्रेणी के तहत 27 जुलाई 2023 को बोली लगाई गई और इसमें 273.46 प्रतिशत का ओवर-सब्सक्रिप्शन हुआ। ओवर-सब्सक्रिप्शन को देखते हुए, दीपम ने चुकता इक्विटी पूंजी के 1.96 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त शेयर बेचने के विकल्प का उपयोग किया। तदनुसार, दीपम ने विनिवेश के माध्यम से कुल ₹1365.61 करोड़ प्राप्त किए और सरकार की शेयरधारिता घटकर 72.84 प्रतिशत रह गई।

दीपम ने आरवीएनएल से ओएफएस (पहली किश्त) के उद्देश्य से विभिन्न समाचार पत्रों में डीएवीपी दरों पर विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए कहा था (23 मार्च 2021), जिसकी लागत दीपम द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी थी। तदनुसार, आरवीएनएल ने एक निजी एजेंसी के माध्यम से 24 मार्च 2021 और 25 मार्च 2021 को विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाए। प्रकाशन के बाद, एजेंसी ने आरवीएनएल पर ₹36.99 लाख का चालान दिनांक 25 मार्च 2021 जारी किया, जिसमें ₹1.76 लाख का जीएसटी सम्मिलित था, जिसका आरवीएनएल द्वारा विधिवत भुगतान किया गया था। इसके बाद, आरवीएनएल ने दीपम से विज्ञापन की लागत ₹36.99 लाख की प्रतिपूर्ति करने के लिए कहा, जिसे दीपम द्वारा प्रतिपूर्ति कर दिया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चूंकि जीएसटी चालान आरवीएनएल पर जारी किया गया था और उसका विधिवत भुगतान आरवीएनएल द्वारा किया गया था, इसलिए जीएसटी इनपुट क्रेडिट आरवीएनएल के पास उपलब्ध था और इस तरह जीएसटी की राशि की प्रतिपूर्ति दीपम द्वारा आरवीएनएल को नहीं की जानी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप दीपम द्वारा आरवीएनएल को ₹1.76 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

दीपम ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (सितंबर 2025) और नियमों के अनुसार परिणामी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

(iii) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

वैकल्पिक तंत्र ने उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की अनुशंसाओं पर विचार किया और ₹225 प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर सरकार की 66.13 प्रतिशत शेयरधारिता में से ओवर-सब्सक्रिप्शन के मामले में चुकता इक्विटी के 1.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त शेयर बेचने के विकल्प के साथ सीआईएल में 1.5 प्रतिशत चुकता इक्विटी के विनिवेश को स्वीकृति दी (31 मई 2023)। ओएफएस लेनदेन 1-2 जून 2023 को हुआ और भारत सरकार को उक्त लेनदेन से विनिवेश आय के रूप में ₹4,185.31 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। सीआईएल का कर्मचारी ओएफएस 23 जून 2023 को समाप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹226.10 प्रति शेयर के कट ऑफ मूल्य पर कर्मचारियों को 16,767 शेयर हस्तांतरित किए गए। भारत सरकार को 30 जून 2023 को कर्मचारी ओएफएस लेनदेन के माध्यम से ₹37.91 लाख की राशि प्राप्त हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सेबी के नियमों के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से बिक्री के प्रस्ताव के बारे में विज्ञापन स्टॉक एक्सचेंजों को शेयरों की बिक्री के प्रस्ताव की घोषणा/सूचना उपलब्ध कराए जाने के बाद जारी किया जाना होता है। दीपम ने सीआईएल से आवश्यक कार्रवाई करने और केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती डीएवीपी) की दरों पर 1 जून 2023 और 2 जून 2023 को विज्ञापन जारी करना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। विज्ञापन के प्रकाशन पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति दीपम द्वारा सीआईएल को की जानी थी। प्रकाशन के बाद, दीपम ने सीआईएल द्वारा किए गए विज्ञापन व्यय के एवज में ₹33.28 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चूंकि विज्ञापन एजेंसी द्वारा कर चालान सीआईएल पर जारी किया गया था और उसका विधिवत भुगतान सीआईएल द्वारा किया गया था, इसलिए जीएसटी इनपुट क्रेडिट सीआईएल के पास उपलब्ध था और इस तरह जीएसटी की राशि की प्रतिपूर्ति दीपम द्वारा सीआईएल को नहीं की जानी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप दीपम द्वारा सीआईएल को ₹1.58 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

दीपम ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (सितंबर 2025) और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हालांकि, जीएसटी राशि की वसूली अभी की जानी बाकी थी।

7.6.3 शेयरों की पुनर्खरीद

सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों (मई 2016) के अनुसार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के पास उपलब्ध अधिशेष नकदी और बैंक शेष पर बायबैक के माध्यम से पूंजी के पुनर्गठन के लिए विचार किया जाएगा। इसके अलावा, कम से कम ₹2,000 करोड़ की नेटवर्थ और ₹1,000 करोड़ से अधिक की नकदी और बैंक शेष रखने वाले प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को अपने शेयरों को पुनर्खरीद करने के विकल्प का उपयोग करना होगा। ये दिशानिर्देश उन कंपनियों पर लागू नहीं होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत स्थापित की गई हैं या जिन्हें संचित घाटा हुआ है। यदि कोई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में सक्षम नहीं है, तो उसे अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के माध्यम से दीपम से विशिष्ट छूट प्राप्त करनी होगी। इस उद्देश्य के लिए, सीपीएसई के छूट प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए दीपम द्वारा एक अंतर-मंत्रालयी समिति 'सीपीएसई में पूंजी प्रबंधन और लाभांश की निगरानी के लिए समिति' का गठन (सितंबर 2020) किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, दीपम द्वारा शेयरों के पुनर्खरीद के किसी भी लेनदेन की सूचना नहीं दी गई थी।

7.6.4 रणनीतिक विनिवेश

रणनीतिक विनिवेश पहचाने गए सीपीएसई में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ सरकारी शेयरधारिता के पूरे या बड़े हिस्से की बिक्री है। सीसीईए ने 31 मार्च 2024 तक 36 सीपीएसई के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' स्वीकृति दी थी। रणनीतिक विनिवेश लेनदेन की स्थिति, जिसके

लिए सीसीईए ने मार्च 2024 तक 'सैद्धांतिक' स्वीकृति दी थी, नीचे तालिका 7.3 में दी गई है। प्रत्येक चरण के तहत कंपनियों की स्थिति **अनुलग्नक XL** में दी गई है।

तालिका 7.3: रणनीतिक विनिवेश लेनदेन की स्थिति

चरण	संख्या
दीपम द्वारा संसाधित किए जा रहे चालू लेनदेन जिनमें ईओआई जारी किया गया है	8
ऐसे लेनदेन जहां ईओआई जारी नहीं किया गया है या ईओआई/आरएफपी जारी होने के बाद लेनदेन रद्द कर दिए गए हैं	6
संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा संसाधित किए जा रहे लेनदेन	3
मुकदमेबाजी के कारण रुका हुआ लेनदेन	1
लेनदेन रुका हुआ है क्योंकि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को बंद करने के लिए अनुशंसित/ अनुमोदित किया गया है; या कोई अन्य कारण	5
लेनदेन व्यवहार्य नहीं है	2
पूरे हो चुके लेनदेन	10
एनसीएलटी में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	1
31 मार्च 2024 तक विचार किया गया कुल रणनीतिक विनिवेश	36

वर्ष 2023-24 के दौरान रणनीतिक विनिवेश मोड के माध्यम से किसी भी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का विनिवेश नहीं किया गया था।

7.6.5 भारतीय यूनिट ट्रस्ट के निर्दिष्ट उपक्रम से प्रेषण

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का गठन भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के तहत किया गया था और इसे 18 दिसंबर 2002 को भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 (निरसन अधिनियम, 2002) के माध्यम से निरस्त कर दिया गया था तथा दो नई संस्थाओं अर्थात् यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड⁸⁷ और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के निर्दिष्ट उपक्रम (यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का निर्दिष्ट उपक्रम - सूटी) में पुनर्गठित किया गया था। दोनों संस्थाओं को यूटीआई (निरसन) अधिनियम, 2002 के तहत संसद द्वारा आवंटित विभिन्न योजनाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैबिनेट सचिवालय ने 14 अप्रैल 2016 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से दीपम को सूटी से संबंधित विषयों के साथ-साथ भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 से संबंधित कार्य आवंटित किए थे।

⁸⁷ सेबी में रजिस्टर्ड यूटीआई म्यूचुअल फंड के ज़रिए काम करते हुए, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड - इन्वेस्टमेंट मैनेजर के तौर पर।

क. एसयूटीआई द्वारा प्रेषित लाभांश आय

एसयूटीआई ने विभिन्न स्रोतों से आय अर्जित की जिसमें उसके द्वारा बनाए रखे गए शेयरों और जमाओं के रणनीतिक होल्डिंग्स से लाभांश और ब्याज सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एसयूटीआई ने दीपम को ₹1,770 करोड़ की लाभांश आय प्रेषित (मार्च 2024) की थी, जिसे दीपम द्वारा वर्ष 2023-24 की विनिवेश प्राप्तियों (वार्षिक रिपोर्ट) के हिस्से के रूप में रिपोर्ट किया गया था। चूंकि यह आय सरकारी शेयरधारिता की बिक्री से प्राप्त प्रेषण का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे विनिवेश प्राप्तियों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इस राशि को 'विविध पूंजी प्राप्ति- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों का विनिवेश' (खाता शीर्ष: 4000 03 190 170 100) के तहत दर्ज किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023-24 के लिए विनिवेश प्राप्तियों को ₹1,770 करोड़ अधिक दर्शाया गया था।

दीपम ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि प्रेषण एसयूटीआई द्वारा वेतन एवं लेखा कार्यालय, दीपम के नामित बैंक खाते में जमा किया गया था, जिसने इसके बाद उपयुक्त खाता शीर्ष के तहत राशि दर्ज की थी। इस संबंध में पीएओ, दीपम को निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके थे।

हालांकि, यह उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकन के लिए विशिष्ट नहीं है और दीपम को उपयुक्त खाता शीर्ष के तहत प्रेषण की बुकिंग सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

ख. एसयूटीआई द्वारा एक्सिस बैंक लिमिटेड में सरकार की शेयरधारिता का ओएफएस लेनदेन

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, एसयूटीआई ने बिक्री के लिए प्रस्ताव ओएफएस के माध्यम से एक्सिस बैंक लिमिटेड के 4,74,474 इक्विटी शेयर बेचे (31 मार्च 2023) जिससे कुल ₹40.32 करोड़ की प्राप्ति हुई। एक्सिस बैंक लिमिटेड के शेयरों की बिक्री से प्राप्त विनिवेश प्राप्तियां ₹40.32 करोड़, जिन्हें एसयूटीआई द्वारा पीएओ, दीपम को प्रेषित (3 अप्रैल 2023) किया गया था, शीर्ष 4000.01.800 - 'सरकारी खाते में अन्य प्राप्तियां' के तहत दर्ज की गईं। हालांकि, एसयूटीआई द्वारा धारित एक्सिस बैंक लिमिटेड के शेयरों की बिक्री से प्राप्त विनिवेश प्राप्तियों को शीर्ष 4000.03.190 और 4000.04.190 - 'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों का विनिवेश' के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप एक्सिस बैंक लिमिटेड के शेयरों की बिक्री से प्राप्त विनिवेश प्राप्तियों की गलत बुकिंग हुई।

पिछले वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इसी तरह का अवलोकन उठाया गया था और दीपम ने कहा था कि एसयूटीआई (एक्सिस बैंक) द्वारा धारित हिस्सेदारी की बिक्री से प्राप्त विनिवेश प्राप्तियों को 4000.03/04.190 के तहत प्रतिबिंबित किया जाएगा। यह इंगित करता है कि इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की जानी अभी बाकी है।

दीपम ने उत्तर दिया (सितंबर 2025) कि इस संबंध में पीएओ, दीपम को निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

7.7 अन्य विषय

7.7.1 शत्रु शेयरों की बिक्री⁸⁸

कैबिनेट टिप्पण (नवंबर 2018) के अनुसार, भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक की कस्टडी में 20,323 शेयरधारकों की 996 कंपनियों में 6,50,75,877 शेयर थे। 996 कंपनियों में से 588 कंपनियां कार्यरत थीं, 394 कंपनियां निष्क्रिय अवस्था में थीं और शेष 14 कंपनियों के विवरण गृह मंत्रालय द्वारा यथासमय साझा किए जाने थे। इसके अलावा, 588 कार्यरत कंपनियों में से 139 कंपनियां सूचीबद्ध थीं और उनके शेयरों का बाजार मूल्य लगभग ₹2,291 करोड़ था। कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत समय सीमा के अनुसार, बाजार की स्थितियों के आधार पर सीसीईए की स्वीकृति (8 नवंबर 2018) से एक वर्ष के भीतर शत्रु शेयरों का निपटान किए जाने की संभावना थी।

शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 8ए की उप-धारा 1 के अनुसार, संरक्षक केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से शत्रु शेयरों या अन्य का निपटान कर सकता है। सीसीईए ने स्वीकृति दी (8 नवंबर 2018) कि शत्रु शेयरों की बिक्री से प्राप्त आय विनिवेश आय का हिस्सा बनने के लिए पात्र होगी।

लेनदेन सलाहकार (एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड) ने 13 मार्च 2023 को आयोजित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक में सूचित किया कि चार वर्ष की अवधि (फरवरी 2019 से फरवरी 2023) के दौरान, सूचीबद्ध कंपनियों के कुल 750.89 लाख शेयर बेचे गए (बिक्री के लिए सीईपीआई द्वारा स्थानांतरित शेयरों का 99.4 प्रतिशत) जिससे ₹2,709.15 करोड़ की प्राप्ति हुई। शेष 4.30 लाख इक्विटी शेयर निपटान के लिए बचे थे। इन शेयरों में से 3.12 लाख शेयर 90 असूचीबद्ध कंपनियों से संबंधित थे और 1.18 लाख शेयर 34 सूचीबद्ध कंपनियों से संबंधित थे। इसके अलावा, 161 कंपनियों के 2.40 लाख शेयर अभी भी सीईपीआई के पास थे और विभिन्न कारणों से लेनदेन सलाहकार को हस्तांतरित नहीं किए गए थे।

लेनदेन सलाहकार ने सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का निपटान न होने के कारणों के बारे में आगे सूचित किया कि इनमें से कुछ कंपनियां क्षेत्रीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं जो कुछ मामलों में गैर-परिचालन रहे हैं, अननुपालन के कारण ट्रेडिंग निलंबित कर दी गई थी और कुछ कंपनियों के शेयरों में नगण्य या बहुत कम ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया था तथा सुझाव दिया कि इन शेयरों को बेचने के लिए एक अलग कार्यप्रणाली अपनाने की आवश्यकता है।

दीपम ने सेबी से स्पष्टीकरण मांगा (मार्च 2023) और सेबी ने उत्तर दिया कि सूचीबद्ध कंपनियों के शत्रु शेयरों की बिक्री, जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम नगण्य या कम था या जो गैर-परिचालन एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध थीं, एक ऑफ-मार्केट लेनदेन के माध्यम से निष्पादित की जा सकती है। वैकल्पिक तंत्र के अनुमोदन के लिए 15 सितंबर 2023 को एक टिप्पण प्रस्तुत किया गया था जिसमें एचएलसी ने असूचीबद्ध और सूचीबद्ध कंपनियों के शेष शत्रु शेयरों की बिक्री के लिए अपनाई जाने वाली विस्तृत कार्यप्रणाली का

⁸⁸ एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, 1968 के अनुसार, 'एनिमी प्रॉपर्टी' (दुश्मन की संपत्ति) का मतलब ऐसी किसी भी संपत्ति से है जो उस समय किसी दुश्मन, दुश्मन देश के नागरिक या दुश्मन फर्म की हो, या उनके लिए रखी या मैनेज की जा रही हो। दुश्मन के शेयर उन लोगों के हैं जो 1962 और 1965 की लड़ाइयों के बाद भारत छोड़कर चीन या पाकिस्तान में बस गए थे।

प्रस्ताव रखा था। वैकल्पिक तंत्र ने 1 अक्टूबर 2023 को एचएलसी की अनुशंसा को स्वीकृति दे दी। 84 कंपनियों के 2,91,536 शेयरों की बिक्री के लिए समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी किया गया था (11 जनवरी 2024)। हालांकि, दो कंपनियों के 13,158 शेयरों को बाद में वापस ले लिया गया और इसलिए 2,78,378 शेयर बिक्री के लिए बचे।

14 फरवरी 2024 को आयोजित एचएलसी की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, वित्तीय बोलियों को खोलने और सूचीबद्ध करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था। आईएमसी ने 9 फरवरी 2024 को बोलियां खोलीं और उसके बाद आगे के मूल्यांकन के लिए लेनदेन सलाहकार को सौंप दिया। लेनदेन सलाहकार को 1,44,692 शेयरों (2,78,378 शेयरों में से) की बिक्री से ₹31.70 करोड़ की राशि प्राप्त हुई और उसने बोलीदाताओं को शेयर आवंटित किए तथा 9 अप्रैल 2024 को दीपम को इसकी सूचना दी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- (i) बोलीदाताओं से लेनदेन सलाहकार द्वारा राशि प्राप्त होने की तारीख (तारीखें) और वही राशि सीईपीआई को हस्तांतरित किए जाने की तारीख (तारीखें) दीपम द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान की गई फाइलों/रिकॉर्डों में उपलब्ध नहीं थीं। इसके अलावा, दीपम की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दीपम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विनिवेश आय के तहत शत्रु शेयरों की बिक्री से कोई राशि नहीं दिखाई थी।

दीपम ने कहा (सितंबर 2025) कि प्राप्त आय सीधे सीईपीआई के बैंक खाते में जमा की गई थी, जिसे सीईपीआई द्वारा आगे भारत की संचित निधि में जमा किया गया था। यह ध्यान में रखते हुए कि राशि पहले ही सीएफआई में जमा की जा चुकी थी, इसे दीपम द्वारा बनाए रखे गए विनिवेश प्राप्तियों के रिकॉर्ड में (2024-25 में) अपडेट किया गया था।

- (ii) 31 मार्च 2023 तक टीए के पास उपलब्ध शत्रु शेयरों की संख्या 4,29,626 थी। 31 जनवरी 2024 तक टीए के पास उपलब्ध शेयरों की संख्या 4,24,000 थी। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि चूंकि दीपम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शत्रु शेयरों की बिक्री से विनिवेश प्राप्तियों में कोई राशि नहीं दिखाई थी, इसलिए 5,626 शत्रु शेयरों के अंतर के लिए औचित्य/सामंजस्य की आवश्यकता थी।

दीपम ने कहा (सितंबर 2025) कि वित्तीय वर्ष 2024 में, टीए ने स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार 5,757 शेयर बेचे। बिक्री से प्राप्त आय के विवरण के संबंध में, टीए से इसे प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जो अभी प्राप्त होना बाकी था।

दीपम बिक्री आय का समय पर प्रेषण और अपने रिकॉर्ड में बेचे गए शेयरों की संख्या को अपडेट करना सुनिश्चित करने के लिए टीए के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित कर सकता है।

- (iii) सीईपीआई ने दीपम को सूचित किया था (5 अगस्त 2021) कि उसके पास द भारत लाइन लिमिटेड के 50,830 शत्रु शेयर थे और कंपनी ₹35.82 प्रति शेयर की दर से सभी सार्वजनिक

शेयरधारकों से शेयर खरीद रही थी। साथ ही, भारत लाइन लिमिटेड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की डीलिस्टिंग समिति द्वारा तय की गई ₹35.82 प्रति शेयर की दर से सीईपीआई द्वारा धारित कंपनी के 50,230 शेयरों की बिक्री के लिए दीपम से अनुरोध किया (8 सितंबर 2023)। दीपम के निर्देशों के आधार पर, टीए ने कंपनी के प्रमोटरों को ₹35.82 प्रति शेयर की कीमत पर 50,230 शेयरों की पेश की (30 नवंबर 2023)। भारत लाइन लिमिटेड ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया (2 दिसंबर 2023) और कहा कि शेयर हस्तांतरित होने के बाद ₹17.99 लाख की राशि टीए के बैंक खाते में जारी कर दी जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2021 में सीईपीआई द्वारा दीपम को पत्र भेजे जाने के बावजूद, दीपम द्वारा द भारत लाइन लिमिटेड के शेयरों को बेचने के लिए दो से अधिक वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा, भारत लाइन लिमिटेड ने 50,230 शेयरों की पेश के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया (2 दिसंबर 2023)। हालांकि, क्या शेयर बेचे गए थे और क्या टीए द्वारा राशि प्राप्त की गई थी, इसका विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड में नहीं मिला। इसके अलावा, दीपम ने वर्ष 2023-24 के दौरान शत्रु शेयरों की बिक्री के मद में शून्य प्राप्ति दिखाई।

दीपम ने कहा (सितंबर 2025) कि सेबी द्वारा जारी आदेश को ध्यान में रखते हुए भारत लाइन के शेयर ऑफलाइन पद्धति के माध्यम से बेचे गए थे। बिक्री के परिणामस्वरूप, प्राप्त आय 24 अप्रैल 2024 को सीधे सीईपीआई के बैंक खाते में जमा कर दी गई।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सीईपीआई के बैंक खाते में आय जमा करने से पहले/बाद में टीए द्वारा दीपम के साथ कोई संचार नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दीपम की वार्षिक रिपोर्ट में विनिवेश प्राप्तियों के आंकड़े अपडेटेड/सही नहीं थे।

- (iv) जैसा कि एचएलसी को सूचित किया गया था, 161 कंपनियों के 2,40,467 शेयर अभी भी सीईपीआई के पास थे और विभिन्न कारणों से टीए को हस्तांतरित नहीं किए गए थे। हालांकि, उपरोक्त शेयरों को टीए को हस्तांतरित करने में हुई प्रगति के संबंध में विवरण/दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थे।

दीपम ने कहा (सितंबर 2025) कि सीईपीआई से आवश्यक जानकारी मांगी गई है और वह अभी भी लंबित है।

7.7.2 होल्डिंग/मूल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सहायक कंपनियों/इकाइयों को बंद करने की स्थिति

कैबिनेट ने 18 मई 2022 को आयोजित अपनी बैठक में होल्डिंग/मूल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडल को अपनी सहायक कंपनियों/इकाइयों/संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी के विनिवेश (रणनीतिक विनिवेश और अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री दोनों)/उन्हें बंद करने की प्रक्रिया की अनुशंसा करने और शुरू करने के लिए सशक्त किया था। इस संबंध में प्रस्ताव मूल/होल्डिंग सार्वजनिक क्षेत्र के

उद्यम द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से दीपम को प्रस्तुत किया जाएगा। दीपम वैकल्पिक तंत्र से प्रस्ताव की 'सैद्धांतिक' स्वीकृति लेगा। दीपम ने कैबिनेट के उपरोक्त निर्णयों को दिनांक 1 जून 2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अधिसूचित किया था।

दीपम ने होल्डिंग/मूल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सहायक कंपनियों/इकाइयों के रणनीतिक विनिवेश/अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री/संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी की बिक्री के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए (14 सितंबर 2022), जबकि डीपीई ने अपनी होल्डिंग/मूल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सहायक कंपनियों/इकाइयों को बंद करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए (31 अक्टूबर 2022)। मार्गदर्शक सिद्धांतों में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार, सहायक कंपनी/इकाइयों को बंद करने की प्रक्रिया बंद करने की 'सैद्धांतिक स्वीकृति' की तारीख से 8 माह और 15 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।

वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (2023-24) (अध्याय IV) के अनुसार, दीपम ने नई नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की आठ सहायक कंपनियों/इकाइयों (**अनुलग्नक XLI**) को बंद करने/विनिवेश के लिए एएम की स्वीकृति ली, जिनमें से दो सहायक कंपनियों को विनिवेश के लिए और छः को बंद करने के लिए स्वीकृति दी गई थी। बंद करने के लिए स्वीकृत छः सहायक कंपनियों में से केवल दो को बंद किया गया है और चार को आज तक बंद नहीं किया गया है।

अध्याय VIII

सततता की स्थिति की समीक्षा

अध्याय VIII

सततता की स्थिति की समीक्षा

8.1 परिचय

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने सततता रिपोर्टिंग की दिशा में व्यावसायिक सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक उत्तरदायित्वों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश, 2011 जारी किए थे। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने वर्ष 2012 में शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए एनवीजी के अनुरूप 'व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट' दाखिल करना अनिवार्य कर दिया था, जिसे बाद में वर्ष 2016 में शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों तथा वर्ष 2019 में शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों तक विस्तारित किया गया।

वर्ष 2019 में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने एनवीजी में संशोधन करते हुए नौ सिद्धांतों वाले 'जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश' तैयार किए। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य व्यवसायों को नियामक अनुपालन की आवश्यकताओं से परे जाकर जिम्मेदार आचरण के सिद्धांतों को अपनाने में सहायता करना था। सेबी ने मई 2021 में, एनजीआरबीसी के अनुरूप, पूर्ववर्ती बीआरआर के स्थान पर 'व्यावसायिक उत्तरदायित्व और सततता रिपोर्टिंग' (बीआरएसआर) ढांचे के रूप में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन मापदंडों पर रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की शुरुआत की। बीआरएसआर का उद्देश्य कंपनियों, क्षेत्रों और समय के साथ तुलनात्मकता को सक्षम करने के लिए मात्रात्मक और मानकीकृत प्रकटीकरण (डिस्कलोजर) सुनिश्चित करना था।

जुलाई 2023 में, सेबी ने सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए आश्वासन (एश्योरेंस) को मजबूत करने और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए बीआरएसआर ढांचे में संशोधन किया। विनियमों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, 31 मार्च 2024 तक बाजार पूंजीकरण के आधार पर भारत की शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में अद्यतन (अपडेटेड) बीआरएसआर प्रारूप के अनुसार प्रकटीकरण करना होगा। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट को स्टॉक एक्सचेंज में जमा किया जाना है और उनकी वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, शीर्ष 150 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए ऐसे आश्वासन प्रदाता (एश्योरेंस प्रोवाइडर) से 'बीआरएसआर कोर' प्रकटीकरण के लिए अनिवार्य रूप से उचित आश्वासन (रीजनेबल एश्योरेंस) प्राप्त करना आवश्यक है, जिसका उस संस्था के साथ कोई हित-संघर्ष न हो।

8.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

- i. यह मूल्यांकन करना कि क्या सूचीबद्ध सीपीएसई द्वारा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ प्रतिपाद्य (सत्यापन योग्य) तरीके से सभी लागू अनिवार्य बीआरएसआर प्रकटीकरणों का अनुपालन किया गया था, और
- ii. बीआरएसआर रिपोर्टिंग का समर्थन करने के लिए सूचीबद्ध सीपीएसई में आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का आकलन करना।

8.3 लेखापरीक्षा का दायरा और आच्छादन

लेखापरीक्षा ने मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बीआरएसआर प्रकटीकरण की समीक्षा हेतु 30 सूचीबद्ध सीपीएसई (*अनुलग्नक XLII*) का चयन किया। चयनित सीपीएसई में से, 18 सीपीएसई शीर्ष 150 सूचीबद्ध कंपनियों में सम्मिलित हैं, जिन्हें बीआरएसआर कोर प्रकटीकरण पर उचित आश्वासन की आवश्यकता है। शेष 12 सूचीबद्ध सीपीएसई को केवल बीआरएसआर ढांचे के तहत रिपोर्ट करने का अधिदेश है।

लेखापरीक्षा ने बीआरएसआर प्रकटीकरणों की पूर्णता और प्रतिपादनीयता (सत्यापन योग्यता) की जांच की, जिसमें प्रकटीकरणों का सत्यापन सीपीएसई द्वारा प्रदान किए गए सहायक दस्तावेजों की उपलब्धता पर आधारित था। संकेतकों (इंडिकेटर्स) की समीक्षा केवल संकेतकों के लिए रिपोर्ट किए गए तथ्यों के औचित्य की जांच तक ही सीमित थी।

सीपीएसई के नामों को मास्किंग कोड, यानी सीपीएसई_1 से सीपीएसई_30 का उपयोग करके गोपनीय रखा गया है।

8.4 लेखापरीक्षा मानदंड

समीक्षा निम्नलिखित के आधार पर की गई थी:

- i. बीआरएसआर प्रारूप और आश्वासन आवश्यकता से संबंधित सेबी के परिपत्र।
- ii. सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर प्रारूप के लिए मार्गदर्शिका।
- iii. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)।

8.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

बीआरएसआर ढांचा 145 संकेतकों से युक्त निम्नलिखित तीन खंडों में संरचित है:

- i. **खंड क - सामान्य प्रकटीकरण (26 संकेतक):** संस्था के बारे में बुनियादी जानकारी एकत्र करता है।

ii. **खंड ख - प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण (12 संकेतक)।**

iii. **खंड ग - सिद्धांत-वार निष्पादन प्रकटीकरण:** खंड ग को नौ सिद्धांतों में विभाजित किया गया है जो संस्था के निष्पादन पर प्रकटीकरण की मांग करते हैं। नौ सिद्धांतों के तहत रिपोर्टिंग को 68 आवश्यक संकेतकों (एसेंशियल इंडिकेटर्स) और 39 नेतृत्व संकेतकों में विभाजित किया गया है।

बीआरएसआर रिपोर्टिंग को आवश्यक और नेतृत्व संकेतकों में विभाजित किया गया था। आवश्यक संकेतकों पर अनिवार्य आधार पर रिपोर्ट करना आवश्यक था, जबकि नेतृत्व संकेतकों की रिपोर्टिंग स्वैच्छिक थी।

लेखापरीक्षा ने चयनित सीपीएसई में उपरोक्त संकेतकों की समीक्षा की, और खंड/सिद्धांतवार लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

8.5.1 खंड क: सामान्य प्रकटीकरण

खंड क में संस्था के बारे में सामान्य जानकारी पर 26 संकेतक सम्मिलित हैं, जिसमें उसकी व्यावसायिक गतिविधियां, परिचालन स्थान और उसकी सहायक कंपनियों तथा कर्मचारियों के बारे में मुख्य विवरण सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 30 सीपीएसई में से चार सीपीएसई⁸⁹ में कोई विसंगति नहीं पाई गई। शेष 26 सीपीएसई के मामले में, लेखापरीक्षा ने कुछ संकेतकों के लिए अननुपालन/आंशिक प्रकटीकरण देखा, जिसमें ऐसे मामले भी सम्मिलित थे जहां प्रकटीकरण के औचित्य को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा को सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। खंड क के संबंध में जांच के संकेतक-वार परिणाम **अनुलग्नक XLIII** में प्रस्तुत किए गए हैं।

खंड क के संकेतकों के संबंध में पाई गई कमियों के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

- **प्रदत्त पूंजी:** संस्था के लिए अपनी प्रदत्त पूंजी का प्रकटीकरण करना आवश्यक था। एक सीपीएसई (सीपीएसई_16) ने वर्ष 2023-24 के दौरान अपनी प्रदत्त पूंजी में वृद्धि की थी। हालांकि, रिपोर्टिंग करते समय, वर्ष 2023-24 के बजाय वर्ष 2022-23 की प्रदत्त पूंजी का प्रकटीकरण किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इसे ₹11.31 करोड़ कम करके दिखाया गया।

उत्तर में (अगस्त 2025), सीपीएसई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और भविष्य की रिपोर्टों में आवश्यक सुधार का आश्वासन दिया।

- **रिपोर्टिंग सीमा:** संस्था के लिए रिपोर्टिंग सीमा का प्रकटीकरण करना आवश्यक था, अर्थात् बीआरएसआर के तहत रिपोर्टिंग एकल (स्टैंडअलोन) आधार पर की गई है या समेकित (कंसोलिडेटेड) आधार पर। समेकित आधार पर प्रकटीकरण करते समय, उन सभी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों संबद्ध कंपनियों (एसोसिएट्स) आदि के विवरणों पर विचार किया जाना चाहिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं।

⁸⁹ सीपीएसई_2, सीपीएसई_10, सीपीएसई_21 और सीपीएसई_27

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन सीपीएसई⁹⁰ में, यद्यपि रिपोर्टिंग सीमा को "समेकित आधार" के रूप में प्रकट किया गया था, लेकिन इसकी कुछ सहायक कंपनियों, संबद्ध कंपनियों, संयुक्त उद्यमों से संबंधित जानकारी पर विचार नहीं किया गया था।

इसके अलावा, एक सीपीएसई (सीपीएसई_23) में, हालांकि रिपोर्टिंग सीमा को "एकल आधार" के रूप में प्रकट किया गया था, केवल प्रमुख परिचालन इकाइयों से संबंधित जानकारी सम्मिलित की गई थी, और छोटी इकाइयों अर्थात् अनुसंधान एवं विकास केंद्र, क्षेत्रीय कार्यालयों को छोड़ दिया गया था।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), तीन सीपीएसई⁹¹ ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। सीपीएसई_4 और सीपीएसई_28 ने भविष्य की रिपोर्टों में आवश्यक बदलाव करने का आश्वासन भी दिया। सीपीएसई_20 ने उत्तर दिया कि सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के भिन्न व्यावसायिक मॉडलों के कारण, उनके सततता योगदान को महत्वहीन (इमटेरियल) माना गया और इसलिए उस पर विचार नहीं किया गया। हालांकि, सीपीएसई_20 ने नियामक अपेक्षाओं के साथ निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से बीआरएसआर के लिए एकल रिपोर्टिंग अपनाने का आश्वासन दिया।

कोयला मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2026) कि रिपोर्टिंग सीमा सीपीएसई_4 की वार्षिक एकीकृत रिपोर्ट के अनुरूप थी। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सेबी द्वारा अनिवार्य किए गए अनुसार, संस्था के समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप सभी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों, संबद्ध कंपनियों आदि के विवरणों को सम्मिलित करते हुए बीआरएसआर तैयार नहीं किया गया था।

इस्पात मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2026) कि सीपीएसई_23 द्वारा छोटी इकाइयों को बाहर रखने से रिपोर्ट की गई जानकारी की पूर्णता या सटीकता भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होती है। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि बीआरएसआर निर्धारित प्रारूप में इस तरह से बाहर रखने का कोई अधिदेश नहीं देता है।

- **स्थान:** संस्था के लिए सभी स्थानों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थित संयंत्रों (प्लांट्स) और कार्यालयों की संख्या दर्शाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छः सीपीएसई⁹² में, स्थानों के लिए प्रकटीकरण करते समय इन संस्थाओं की सभी इकाइयों पर विचार नहीं किया गया था।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), तीन सीपीएसई⁹³ ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और भविष्य की रिपोर्टों में आवश्यक सुधार करने का आश्वासन दिया। सीपीएसई_23 ने कहा कि बीआरएसआर रिपोर्ट के तहत केवल मुख्य खनन और परिचालन स्थलों को सम्मिलित किया गया था, जो मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण थे। सीपीएसई_8 ने कहा कि एक इकाई के कार्य की प्रकृति के कारण, उसे एक प्रभाग के तहत एक कैप्टिव सुविधा माना गया था और इस प्रकार यह अंतर देखा गया। हालांकि, बीआरएसआर ने संस्था के सभी संयंत्रों/कार्यालयों के प्रकटीकरण का

⁹⁰ सीपीएसई_4, सीपीएसई_20, और सीपीएसई_28

⁹¹ सीपीएसई_4, सीपीएसई_23 और सीपीएसई_28

⁹² सीपीएसई_4, सीपीएसई_8, सीपीएसई_19, सीपीएसई_23, सीपीएसई_20 और सीपीएसई_28

⁹³ सीपीएसई_4, सीपीएसई_19 और सीपीएसई_20

अनुलग्नक किया था और कोई छूट प्रदान नहीं की थी। सीपीएसई_28 ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों को परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां न होने के कारण सम्मिलित नहीं किया गया था। हालांकि, यह जानकारी वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए विवरणों के अनुरूप नहीं थी।

सीपीएसई_4 के लिए कोयला मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026)। विद्युत मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2026) कि बीआरएसआर में सीपीएसई_20 द्वारा किया गया प्रकटीकरण सटीक था। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि बीआरएसआर में प्रकटीकरण असंगत था और संस्था की वार्षिक रिपोर्ट के अनुरूप नहीं था।

इस्पात मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2026) कि स्थान के लिए प्रकटीकरण सीपीएसई_23 द्वारा परिभाषित रिपोर्टिंग सीमा के अनुसार छोटी इकाइयों को छोड़कर किया गया था, जो रिपोर्ट की गई जानकारी की पूर्णता या सटीकता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता है। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि बीआरएसआर निर्धारित प्रारूप में इस तरह से बाहर रखने का कोई अधिदेश नहीं देता है।

सीपीएसई_28 के लिए रेल मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026)।

- **कर्मचारी:** संस्था के लिए अपने कर्मचारियों और श्रमिकों की कुल संख्या का प्रकटीकरण करना आवश्यक था। संस्था को लिंग-वार विभाजन के साथ-साथ स्थायी और गैर-स्थायी के लिए अलगाव और उनका संबंधित प्रतिशत भी प्रदान करना आवश्यक था। इसके अलावा, प्रत्येक श्रेणी में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपरोक्त विवरण प्रकट किए जाने थे।

समीक्षा से पता चला कि सात सीपीएसई⁹⁴ में, कर्मचारियों/श्रमिकों के संबंध में किए गए प्रकटीकरण और वार्षिक रिपोर्ट में समान विवरण या संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मेल नहीं खा रही थी।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), उपरोक्त सभी सीपीएसई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और भविष्य की रिपोर्टों में आवश्यक सुधार करने का आश्वासन दिया।

सीपीएसई_4 के लिए कोयला मंत्रालय और सीपीएसई_20 के लिए विद्युत मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2026) कि बीआरएसआर में प्रकट किए गए कर्मचारियों और श्रमिकों की संख्या संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्टों से मेल खाती थी। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि दिव्यांग कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या उनकी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट की गई समान जानकारी से मेल नहीं खाती थी।

कोयला मंत्रालय ने सीपीएसई_22 के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026)।

- **होल्टिंग, सहायक, संयुक्त उद्यम और संबद्ध कंपनियां:** संस्था के लिए अपनी सहायक कंपनी/संबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में सूचीबद्ध संस्था द्वारा शेयरधारिता का नाम, प्रकृति और विवरण प्रकट करना आवश्यक था। इसके लिए यह दर्शाना भी आवश्यक था कि क्या होल्टिंग, सहायक, संयुक्त उद्यम और संबद्ध कंपनियों ने संस्था की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लिया था।

⁹⁴ सीपीएसई_4, सीपीएसई_13, सीपीएसई_15, सीपीएसई_19, सीपीएसई_22, सीपीएसई_20 और सीपीएसई_26

लेखापरीक्षा ने पाया कि अपनी सहायक, संयुक्त उद्यम और संबद्ध कंपनियों के लिए प्रकटीकरण करते समय, पांच सीपीएसई⁹⁵ ने या तो अपनी सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/संबद्ध कंपनियों का प्रकटीकरण नहीं किया था या अपने संयुक्त उद्यमों को गलत तरीके से संबद्ध कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया था। इसके अलावा, एक सीपीएसई (सीपीएसई_24) ने भागीदारी के संबंध में विवरण प्रदान नहीं किया था जैसा कि बीआरएसआर के तहत आवश्यक था।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), चार सीपीएसई⁹⁶ ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और भविष्य की रिपोर्टों में आवश्यक सुधार करने का आश्वासन दिया। सीपीएसई_1 ने उत्तर दिया कि प्रकटीकरण कंपनी द्वारा रखे गए डेटा के आधार पर किया गया था। सीपीएसई_1 के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि संयुक्त उद्यमों को गलत तरीके से संबद्ध कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सीपीएसई_28 ने कहा कि बीआरएसआर में प्रकटीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था, जबकि वार्षिक रिपोर्ट में विवरण भारतीय लेखा मानकों के अनुसार प्रस्तुत किए गए थे। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि बीआरएसआर प्रारूप में समान रिपोर्टिंग अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट से विचलन का कोई प्रावधान नहीं था।

सीपीएसई_20 के लिए विद्युत मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026)। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2026) कि संयुक्त उद्यम समझौते के आधार पर, संयुक्त उद्यमों/संबद्धों का वर्गीकरण सीपीएसई_11 द्वारा किया गया था। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि ऐसा वर्गीकरण इसकी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट की गई जानकारी के विरोधाभासी था।

- **किसी भी सिद्धांत पर शिकायतें/शिकायत निवारण:** संस्था के लिए बीआरएसआर रिपोर्ट में शेयरधारकों, कर्मचारियों/श्रमिकों, ग्राहकों और मूल्य श्रृंखला भागीदारों (वैल्यू चेन पार्टनर्स) आदि के लिए शिकायत निवारण तंत्र के अस्तित्व का प्रकटीकरण करना आवश्यक था। इसमें शिकायत निवारण नीति का वेब-लिंक प्रदान करना सम्मिलित था। साथ ही, संस्था को वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या के साथ-साथ चालू वर्ष और पिछले वर्ष के लिए वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों का प्रकटीकरण करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- 15 सीपीएसई⁹⁷ में, शिकायत निवारण तंत्र होने के बावजूद, नीति के लिए वेब लिंक या तो प्रदान नहीं किया गया था या गलत लिंक प्रदान किया गया था।
- चार सीपीएसई⁹⁸ में, वर्ष के दौरान दर्ज की गई और वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या के प्रकटीकरण में विसंगति थी। इस प्रकार प्रकट किए गए विवरण बीआरएसआर रिपोर्ट के अन्य खंड या इसकी अपनी वार्षिक रिपोर्ट के समान विवरणों से मेल नहीं खा रहे थे। जहां वर्ष के दौरान सीपीएसई_4 के कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों को खंड क

⁹⁵ सीपीएसई_1, सीपीएसई_11, सीपीएसई_20, सीपीएसई_25 और सीपीएसई_28

⁹⁶ सीपीएसई_11, सीपीएसई_20, सीपीएसई_25 और सीपीएसई_24

⁹⁷ सीपीएसई_4, सीपीएसई_6, सीपीएसई_5, सीपीएसई_9, सीपीएसई_12, सीपीएसई_13, सीपीएसई_14, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_18, सीपीएसई_19, सीपीएसई_30, सीपीएसई_22, सीपीएसई_28, और सीपीएसई_29

⁹⁸ सीपीएसई_4, सीपीएसई_13, सीपीएसई_18, और सीपीएसई_28

के तहत 160 के रूप में प्रकट किया गया था, वहीं कार्य स्थितियों से संबंधित शिकायतों को सिद्धांत 3 के तहत 3072 के रूप में रिपोर्ट किया गया था। सिद्धांत 3 के तहत प्रकटीकरण खंड के तहत किए गए प्रकटीकरण का एक उप-समुच्चय (सब-सेट) है।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), आठ सीपीएसई⁹⁹ ने शिकायत निवारण नीति के वेबलिनक के प्रकटीकरण के संबंध में लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार किया और आवश्यक सुधारों का आश्वासन दिया। सीपीएसई_30 ने उत्तर दिया कि पाद-टिप्पणी (फुटनोट) के तहत यह प्रकट किया गया है कि 'कंपनी के पास अपने सभी हितधारकों के लिए शिकायत निवारण के लिए एक आंतरिक तंत्र है'। सीपीएसई_6 ने कहा कि कंपनी पर लागू विभिन्न नीतियों के वेबलिनक स्पष्ट रूप से प्रकट किए गए हैं। दो सीपीएसई (सीपीएसई_16 और सीपीएसई_29) ने कहा कि शिकायत निवारण के लिए सीपिग्राम्स पोर्टल का वेबलिनक बीआरएसआर रिपोर्ट में प्रकट किया गया था। उत्तर प्रस्तुत करते समय, तीन सीपीएसई (सीपीएसई_13, सीपीएसई_14 और सीपीएसई_28) ने शिकायत निवारण नीतियों के प्रासंगिक वेबलिनक प्रदान किए।

सीपीएसई_16 और सीपीएसई_29 ने सीपिग्राम्स पोर्टल का वेबलिनक दिया है, जिस पर शिकायत दर्ज की जा सकती है, जबकि बीआरएसआर के अनुसार, शिकायत निवारण नीति के वेबलिनक प्रकट किए जाने थे। इसके अलावा, सीपीएसई_6 द्वारा प्रदान किया गया लिंक सुलभ नहीं था और इसे प्रबंधन ने अपने उत्तरों में स्वीकार किया था। तीन सीपीएसई (सीपीएसई_13, सीपीएसई_14 और सीपीएसई_28) ने उत्तर जमा करते समय नीतियों के प्रासंगिक वेबलिनक प्रदान किए हैं, हालांकि, नीति के प्रासंगिक वेबलिनक इन संबंधित सीपीएसई द्वारा बीआरएसआर रिपोर्टों में प्रकट नहीं किए गए थे।

शिकायतों की संख्या के प्रकटीकरण के संबंध में, सभी चार सीपीएसई (सीपीएसई_4, सीपीएसई_13, सीपीएसई_18 और सीपीएसई_28) ने लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार किया। सीपीएसई_4 ने भविष्य की रिपोर्टों में आवश्यक सुधार करने का आश्वासन भी दिया।

सीपीएसई_5 के लिए पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2026) कि बीआरएसआर प्रारूप की शब्दावली असंगत प्रतीत होती है और औपचारिक प्रलेखित शिकायत निवारण नीति का वेबलिनक प्रकट करना आवश्यक नहीं था। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि बीआरएसआर प्रारूप में शब्दावली स्पष्ट रूप से शिकायत निवारण नीति के वेबलिनक को प्रकट करना अधिदेशित करती थी।

सीपीएसई_4 और सीपीएसई_22 के लिए कोयला मंत्रालय तथा सीपीएसई_18 के लिए रक्षा मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026)।

8.5.2 खंड ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

बीआरएसआर प्रकटीकरण के खंड ख में 12 संकेतक सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना था।

⁹⁹ सीपीएसई_4, सीपीएसई_5, सीपीएसई_9, सीपीएसई_12, सीपीएसई_17, सीपीएसई_18, सीपीएसई_19 और सीपीएसई_22

सभी 30 सीपीएसई में, लेखापरीक्षा ने कुछ संकेतकों के लिए अननुपालन/आंशिक प्रकटीकरण देखा, जिसमें ऐसे मामले भी सम्मिलित थे जहां प्रकटीकरण के औचित्य को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा को सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। खंड ख के संबंध में जांच के संकेतक-वार परिणाम अनुलग्नक **XLIV** में प्रस्तुत किए गए हैं।

खंड ख में पाई गई कमियों के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

- **सिद्धांतों के लिए नीतियों का आच्छादन:** संस्था के लिए यह प्रकट करना आवश्यक था कि क्या उसकी नीतियां खंड ग के प्रत्येक नौ सिद्धांतों को सम्मिलित करती हैं, साथ ही प्रत्येक नीति का संबंधित सिद्धांत के साथ मिलान (मैपिंग) भी करना था। इसके लिए नीतियों के वेबलिंग प्रकट करना भी आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- एक सीपीएसई (सीपीएसई_4) ने संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम अपनी नीतियों के रूप में प्रकट किया, जो सही नहीं है क्योंकि बहिर्नियम और अंतर्नियम कंपनी के पंजीकरण के लिए आवश्यक बुनियादी दस्तावेज हैं और यह कोई नीति नहीं है।
- “खदानों में पर्यावरण कर्मियों के लिए दिशानिर्देश” को एक नीति के रूप में प्रकट किया गया था, हालांकि यह दिशानिर्देश कोई नीति नहीं है बल्कि खदानों के संचालन में पर्यावरणीय पहलुओं से निपटने के लिए एक ज्ञान बैंक (नॉलेज बैंक) है।
- साथ ही, समान अवसर नीति को सिद्धांत 4 के तहत एक नीति के रूप में प्रकट किया गया था जो इस बात पर जोर देता है कि व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। हालांकि, उक्त नीति को सिद्धांत 3 के तहत प्रकट किया जाना चाहिए जो सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने से संबंधित है।
- यद्यपि एक सीपीएसई (सीपीएसई_28) ने सभी सिद्धांतों को सम्मिलित करते हुए अपनी नीतियों का प्रकटीकरण किया है, लेकिन नीतियों का संबंधित सिद्धांतों से मिलान नहीं किया गया था।
- सीपीएसई_4 ने वेबलिंग प्रकट नहीं किया है जबकि सीपीएसई_13 और सीपीएसई_29 ने गलत लिंक प्रदान किए हैं।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), उपरोक्त सभी सीपीएसई ने लेखापरीक्षा को स्वीकार किया।

सीपीएसई_4 के लिए कोयला मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026)।

- **राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कोड/मानक:** संस्था के लिए संस्थाओं द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों के नाम और प्रत्येक सिद्धांत के विरुद्ध उनकी मैपिंग प्रकट करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- यद्यपि दो सीपीएसई (सीपीएसई_4 और सीपीएसई_23) ने प्रकट किया है कि उनके द्वारा कोड/मानक आदि अपनाए गए हैं, यह केवल विशिष्ट सहायक कंपनियों या संस्था की इकाइयों से संबंधित था।
- एक सीपीएसई (सीपीएसई_14) ने प्रकट किया था कि कोड/मानकों आदि के लिए प्रमाणन अपनाया गया है। हालांकि, संस्था के पास ऐसे कोई कोड/मानक उपलब्ध नहीं थे। इसके प्रबंधन ने उत्तर प्रस्तुत करते समय इसकी पुष्टि की है।
- यद्यपि पांच सीपीएसई¹⁰⁰ ने संस्थाओं द्वारा अपनाए गए कोड/मानकों आदि के लिए प्रकटीकरण किया था, लेकिन इन कोड/मानकों को संबंधित सिद्धांतों के विरुद्ध मैप¹⁰¹ नहीं किया गया था जैसा कि बीआरएसआर में अनिवार्य किया गया है।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025),

- पांच सीपीएसई (सीपीएसई_1, सीपीएसई_4, सीपीएसई_13, सीपीएसई_18 और सीपीएसई_28) ने लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार किया। सीपीएसई_1, सीपीएसई_4 और सीपीएसई_18 ने भविष्य की रिपोर्टों में आवश्यक सुधार का आश्वासन भी दिया।
- एक सीपीएसई (सीपीएसई_23) ने कहा कि प्रकट किए गए प्रमाणन इसकी प्रमुख परिचालन इकाइयों और सुविधाओं द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को दर्शाते हैं। इसने यह भी कहा कि प्रकटीकरण पूरी संस्था के व्यापक प्रमाणन के बजाय संगठन के महत्वपूर्ण कार्यों के भीतर अनुपालन की सीमा को इंगित करने के लिए किया गया था।

सीपीएसई_23 के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि पूरी संस्था के रूप में कोड/मानकों आदि के लिए प्रमाणन प्राप्त नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण प्रकटीकरण हुआ।

- सीपीएसई_6 ने कहा कि प्रकट किए गए मानक सिद्धांत 2, 3 और 6 के अनुरूप हैं और सेबी के प्रारूप में कोड की मैपिंग की आवश्यकता नहीं है और इसलिए आवश्यकता को प्रकाशित रूप में पूरा किया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि बीआरएसआर के लिए मानकों/कोडों की सिद्धांतवार मैपिंग आवश्यक है, जो सीपीएसई_6 द्वारा नहीं की गई है।

¹⁰⁰ सीपीएसई_1, सीपीएसई_6, सीपीएसई_13, सीपीएसई_18 और सीपीएसई_28

¹⁰¹ उदाहरण: सीपीएसई_6 ने 2023-24 के लिए अपनी बीआरएसआर रिपोर्ट में कहा कि “सीपीएसई_6 के पास आईएसओ 9001:2015 सर्टिफिकेशन जारी है और 31 मार्च 2024 तक, 50 टर्मिनल आईएसओ 9001:2015 सर्टिफाइड थे। इसके अलावा 2 टर्मिनल आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 सर्टिफाइड हैं।” हालांकि, ये कोड/सर्टिफिकेशन बीआरएसआर प्रिंसिपल्स से मैप नहीं किए गए थे।

सीपीएसई_4 के लिए कोयला मंत्रालय और सीपीएसई_18 के लिए रक्षा मंत्रालय ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026)। सीपीएसई_6 के लिए रेल मंत्रालय ने आगामी वर्षों में आवश्यक बदलावों का आश्वासन दिया (जनवरी 2026)।

- **प्रतिबद्धताएं और उपलब्धियां :** संस्था के लिए परिभाषित समय-सीमा के साथ अपनी विशिष्ट प्रतिबद्धता/लक्ष्य और उन प्रतिबद्धताओं/लक्ष्यों के विरुद्ध संबंधित निष्पादन/उपलब्धियां प्रकट करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- आठ सीपीएसई¹⁰² में, या तो लक्ष्यों में मापने योग्यता/परिभाषित समय-सीमा की कमी थी, या रिपोर्ट की गई उपलब्धियां विशिष्ट नहीं थीं और सामान्य प्रकृति¹⁰³ की थीं।
- एक सीपीएसई (सीपीएसई_4) में, लक्ष्य वर्ष 2024-25 से 2029-30 के लिए निर्धारित किए गए थे, हालांकि, उपलब्धियां वर्ष 2023-24 के लिए प्रकट की गई थीं, इस प्रकार लक्ष्यों के वर्षों और उसके विरुद्ध उपलब्धियों में विसंगति थी।
- एक सीपीएसई (सीपीएसई_30) में, उपलब्धियां प्रकट किए गए लक्ष्यों से मेल नहीं खाती थीं।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार करते हुए, छः सीपीएसई (सीपीएसई_4, सीपीएसई_5, सीपीएसई_18, सीपीएसई_19, सीपीएसई_23 और सीपीएसई_28) ने भविष्य की रिपोर्टों में इस पहलू का अनुपालन करने का आश्वासन दिया। अपने उत्तर में, सीपीएसई_30 ने अपनी बीआरएसआर रिपोर्ट में किए गए प्रकटीकरण को दोहराया। सीपीएसई_1 ने कहा कि कंपनी की अलग व्यापक सततता विकास रिपोर्ट में विशिष्ट लक्ष्य/प्रतिबद्धताएं प्रदान की गई हैं। सीपीएसई_14 ने बीआरएसआर रिपोर्ट में प्रकट तथ्य को दोहराया। इसे इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि इन तीन सीपीएसई द्वारा किए गए प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे।

सीपीएसई_4 के लिए कोयला मंत्रालय और सीपीएसई_18 के लिए रक्षा मंत्रालय ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026)। सीपीएसई_5 के लिए पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने आगामी वर्षों में आवश्यक बदलावों का आश्वासन दिया (जनवरी 2026)।

इस्पात मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2026) कि सीपीएसई_23 द्वारा निश्चित वार्षिक मील के पथर के बजाय गुणात्मक और प्रवृत्ति-आधारित सुधारों के माध्यम से रिपोर्ट किए गए निष्पादन के साथ लक्ष्यों को दिशात्मक या प्रगतिशील प्रतिबद्धताओं के रूप में तैयार किया गया था। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि बीआरएसआर प्रारूप में परिभाषित समय-सीमा और संबंधित लक्ष्य के साथ विशिष्ट प्रतिबद्धता का अधिदेश दिया गया था जिसका सीपीएसई_23 द्वारा पालन नहीं किया गया था।

¹⁰² सीपीएसई_1, सीपीएसई_5, सीपीएसई_6, सीपीएसई_14, सीपीएसई_18, सीपीएसई_19, सीपीएसई_23 और सीपीएसई_28

¹⁰³ उदाहरण: सीपीएसई_1 ने 2023-24 के लिए अपनी बीआरएसआर रिपोर्ट में कहा कि “सीपीएसई_1 ने एनजीआरबीसीसि द्वांतों के अनुसार कई लक्ष्य और टारगेट तय किए हैं, जो एनजी, कम्युनिटी डेवलपमेंट और एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करते हैं। कंपनी एसडीजी, पेरिस एग्रीमेंट, यूएनजीसी, वगैरह के तहत नेट ज़ीरो कमिटमेंट हासिल करने के लिए कमिटेड है।”

- **नीतियों का स्वतंत्र मूल्यांकन :** संस्था के लिए यह प्रकट करना आवश्यक था कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा उसकी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/समीक्षा की गई थी। यदि हां, तो एजेंसी का नाम भी प्रकट किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- एक सीपीएसई (सीपीएसई_4) ने प्रकट किया कि स्वतंत्र मूल्यांकन बीआरएसआर रिपोर्ट के आश्वासन प्रदाता द्वारा किया गया था। हालांकि, यह प्रकटीकरण सही नहीं था क्योंकि संकेतक के लिए इसकी नीतियों के कामकाज के स्वतंत्र मूल्यांकन/समीक्षा की आवश्यकता थी, जो न तो बीआरएसआर आश्वासन प्रदाता के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित था और न ही ऐसा किया गया था।
- उत्तर में (अगस्त 2025), लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार करते हुए, सीपीएसई_4 ने भविष्य की रिपोर्टों में आवश्यकताओं का अनुपालन करने का आश्वासन दिया। कोयला मंत्रालय ने भी अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026)।

8.5.3 खंड ग: सिद्धांतवार निष्पादन प्रकटीकरण

खंड ग का उद्देश्य संस्थाओं को मुख्य प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को एकीकृत करने में अपने निष्पादन को प्रदर्शित करने में मदद करना था। खंड ग में नौ सिद्धांत हैं, जिनमें कुल 107 संकेतक सम्मिलित हैं। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" (एसेंशियल) और "नेतृत्व" (लीडरशिप) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जहां आवश्यक संकेतकों को प्रत्येक संस्था द्वारा प्रकट किए जाने की अपेक्षा की जाती है, जिसे यह रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य है, वहीं नेतृत्व संकेतकों को संस्थाओं द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्रकट किया जा सकता है।

8.5.3.1 सिद्धांत 1: व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ अपना संचालन और शासन करना चाहिए, तथा ऐसा आचरण करना चाहिए जो नैतिक, पारदर्शी और उत्तरदायी हो

सिद्धांत 1 में 11 संकेतक (नौ आवश्यक संकेतक और दो नेतृत्व संकेतक) सम्मिलित हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ अपना संचालन और शासन करना चाहिए और इस तरह से आचरण करना चाहिए जो नैतिक, पारदर्शी और उत्तरदायी हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 30 सीपीएसई में से दस सीपीएसई¹⁰⁴ में कोई विसंगति नहीं देखी गई। शेष 20 सीपीएसई के मामले में, लेखापरीक्षा ने कुछ संकेतकों के लिए अननुपालन/आंशिक प्रकटीकरण देखा, जिसमें ऐसे मामले भी सम्मिलित थे जहां प्रकटीकरण के औचित्य को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा को सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। सिद्धांत 1 के संबंध में जांच के संकेतक-वार परिणाम अनुलग्नक XLV में प्रस्तुत किए गए हैं।

¹⁰⁴ सीपीएसई_3, सीपीएसई_1, सीपीएसई_8, सीपीएसई_10, सीपीएसई_14, सीपीएसई_19, सीपीएसई_20, सीपीएसई_24, सीपीएसई_26 और सीपीएसई_27

सिद्धांत 1 में पाई गई कमियों के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

- **प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा आच्छादन:** संस्था के लिए निदेशक मंडल, मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों, कर्मचारियों और संस्था के श्रमिकों के लिए किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत आच्छादन के साथ-साथ सम्मिलित विषयों के विवरण प्रकट करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- तीन सीपीएसई (सीपीएसई_4, सीपीएसई_13 और सीपीएसई_21) में, संबंधित सीपीएसई के निदेशक मंडल के प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के संबंध में बीआरएसआर रिपोर्ट में प्रकट किए गए विवरण सीपीएसई द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित जानकारी के साथ असंगत थे।
- एक सीपीएसई (सीपीएसई_29) ने कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों के प्रतिशत के बजाय मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों और कर्मचारियों के संबंध में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए पूर्ण आंकड़े (एब्सोल्यूट फिगर्स) प्रकट किए। श्रमिकों के मामले में, यद्यपि सीपीएसई_29 ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के विवरण प्रकट किए थे, लेकिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या और प्रशिक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रदान नहीं की गई थी।
- एक सीपीएसई (सीपीएसई_2) ने बीआरएसआर प्रकटीकरण के तहत आवश्यक कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रशिक्षण विवरण अलग से प्रकट नहीं किए।
- एक सीपीएसई (सीपीएसई_6) ने प्रकट किया कि निदेशक मंडल/मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने संबंधित श्रेणियों में 100 प्रतिशत को कवर किया। हालांकि, सीपीएसई इसे सत्यापित करने के लिए ऐसे विवरणों के दस्तावेज प्रदान करने में सक्षम नहीं रहे हैं।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025) प्रबंधन ने कहा कि:

- पांच सीपीएसई (सीपीएसई_2, सीपीएसई_4, सीपीएसई_13, सीपीएसई_21 और सीपीएसई_29) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और भविष्य की रिपोर्टों में आवश्यक सुधार करने का आश्वासन दिया।
- सीपीएसई_6 ने उत्तर दिया कि उपलब्ध डेटा के आधार पर प्रकटीकरण किए गए थे जबकि सीपीएसई_28 ने नियत समय में विवरण प्रदान करने का आश्वासन दिया था; हालांकि, इन सीपीएसई ने अपनी बीआरएसआर रिपोर्टों में किए गए प्रकटीकरणों के औचित्य को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा को आवश्यक दस्तावेज प्रदान नहीं किए।

सीपीएसई_4 के लिए कोयला मंत्रालय और सीपीएसई_13 के लिए रेल मंत्रालय ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026)। रक्षा मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2026) कि सीपीएसई_2 ने बीआरएसआर 2024-25 रिपोर्ट में आवश्यक सुधार किए हैं।

- **जुर्माने/दंड का विवरण:** संस्था के लिए वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ कार्यवाही के लिए भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/समझौता राशि का विवरण प्रकट करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- वर्ष 2023-24 के लिए एक सीपीएसई (सीपीएसई_17) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 के दौरान ऑडिट समिति के गठन के अननुपालन के लिए एनएसई द्वारा ₹0.03 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माने का भुगतान अक्टूबर 2023 के दौरान किया गया था, हालांकि, बीआरएसआर में रिपोर्ट करते समय, इसने ऐसे जुर्माने के भुगतान के लिए जानकारी 'शून्य' के रूप में प्रकट की।
- साथ ही, एनएसई/बीएसई द्वारा जुर्माने लगाने के संबंध में प्रकटीकरण करते समय, एक सीपीएसई (सीपीएसई_4) ने प्रकट किया है कि जुर्माने के लिए ₹0.21 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था, हालांकि उक्त राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया था।

उत्तर में (अगस्त 2025), सीपीएसई_4 ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। सीपीएसई_17 ने कहा कि जुर्माने का भुगतान वर्ष 2023-24 के दौरान नहीं किया गया था। हालांकि, वर्ष 2023-24 के लिए सीपीएसई_17 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, जुर्माने का भुगतान अक्टूबर 2023 के दौरान किया गया था।

सीपीएसई_4 के लिए कोयला मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026)।

- **व्यवसाय का खुलापन:** संस्था के लिए ट्रेडिंग हाउसों, डीलरों और संबंधित पक्षों (रिलेटेड पार्टोज) के साथ खरीद और बिक्री की एकाग्रता का विवरण प्रकट करना आवश्यक था। इसके लिए संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम तथा निवेश के विवरण भी आवश्यक थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- दो सीपीएसई (सीपीएसई_22 और सीपीएसई_9) ने ट्रेडिंग हाउसों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री के संबंध में गलत प्रकटीकरण किए। संबंधित पक्षों के साथ खरीद, बिक्री, ऋण और अग्रिम आदि से जुड़े लेनदेन होने के बावजूद, सीपीएसई_22 द्वारा बीआरएसआर के तहत जानकारी 'शून्य' के रूप में प्रकट की गई है।
- एक सीपीएसई (सीपीएसई_9) ने जीईएम (गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस) और सीपीपी (सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल) को 'ट्रेडिंग हाउस' के रूप में प्रकट किया, हालांकि, जीईएम और सीपीपी खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्लेटफॉर्म/पोर्टल हैं।
- दो सीपीएसई (सीपीएसई_16 और सीपीएसई_30) ने संकेतक के लिए कोई प्रकटीकरण नहीं किया है।
- एक सीपीएसई (सीपीएसई_13) ने बिक्री की एकाग्रता और सम्बद्ध पक्ष के लेनदेन के हिस्से के विवरण प्रकट किए। हालांकि, ऐसे विवरणों के लिए दस्तावेज प्रदान नहीं किए गए थे।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), तीन सीपीएसई (सीपीएसई_16, सीपीएसई_30 और सीपीएसई_22) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और भविष्य की रिपोर्टों में इसे सुधारने का आश्वासन दिया। सीपीएसई_9 ने लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए अभ्युक्तियों पर कोई टिप्पणी नहीं की। सीपीएसई_13 ने कहा कि इसका संचालन आम तौर पर लाइसेंसी आधारित मॉडल पर किया जाता है और डीलरों की कोई सीधी नियुक्ति नहीं होती है। हालांकि, इसने बीआरएसआर रिपोर्ट में किए गए प्रकटीकरण के औचित्य को सत्यापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रदान नहीं किए।

कोयला मंत्रालय ने सीपीएसई_22 के लिए स्वीकार किया (जनवरी 2026) और आगामी वर्षों में आवश्यक बदलाव करने का आश्वासन दिया।

8.5.3.2 सिद्धांत 2: व्यवसायों को ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान करना चाहिए जो सतत और सुरक्षित हों

सिद्धांत 2 में नौ संकेतक (चार आवश्यक संकेतक और पांच नेतृत्व संकेतक) सम्मिलित हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि व्यवसायों को ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान करना चाहिए जो सतत और सुरक्षित हों।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 30 सीपीएसई में से 23 सीपीएसई¹⁰⁵ में कोई विसंगति नहीं देखी गई। शेष सात सीपीएसई के मामले में, लेखापरीक्षा ने कुछ संकेतकों के लिए अननुपालन/आंशिक प्रकटीकरण देखा, जिसमें ऐसे मामले भी सम्मिलित थे जहां प्रकटीकरण के औचित्य को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा को सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। सिद्धांत 2 के संबंध में जांच के संकेतक-वार परिणाम *अनुलग्नक XLVI* में प्रस्तुत किए गए हैं।

सिद्धांत 2 में पाई गई कमियों के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

- **विशिष्ट तकनीकों में किए गए निवेश:** संस्था के लिए कुल अनुसंधान और विकास तथा पूंजीगत व्यय का वह प्रतिशत प्रकट करना आवश्यक था, जो उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को सुधारने के उद्देश्य से तकनीकों में किया गया हो। इसके अलावा, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव में सुधार के विवरण भी प्रकट किए जाने थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- एक सीपीएसई (सीपीएसई_6) ने उन तकनीकों में अपने कुल आरएंडडी और पूंजीगत व्यय निवेश का प्रतिशत प्रकट नहीं किया था जिनका उद्देश्य उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार करना था। सीपीएसई_29 में, कुल पूंजीगत व्यय निवेश के लिए आवश्यक प्रतिशत प्रकट नहीं किया गया था।
- सीपीएसई_4 में, व्यय के प्रतिशत की गणना करते समय पूंजीगत व्यय के गलत आंकड़े माने गए थे।

¹⁰⁵ सीपीएसई_2, सीपीएसई_3, सीपीएसई_5, सीपीएसई_7, सीपीएसई_8, सीपीएसई_10, सीपीएसई_11, सीपीएसई_13, सीपीएसई_15, सीपीएसई_14, सीपीएसई_12, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_18, सीपीएसई_19, सीपीएसई_30, सीपीएसई_22, सीपीएसई_23, सीपीएसई_25, सीपीएसई_24, सीपीएसई_26, सीपीएसई_27, और सीपीएसई_28

- सीपीएसई_1 में, यद्यपि बीआरएसआर रिपोर्ट एकल (स्टैंडअलोन) आधार पर तैयार की गई है, पूंजीगत व्यय के लिए व्यय का प्रतिशत निकालते समय, उसने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों आदि सहित इस प्रकार किए गए कुल व्यय पर विचार किया।
- दो सीपीएसई (सीपीएसई_9 और सीपीएसई_6) में तकनीकों पर व्यय के कारण सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पर सुधार प्रकट नहीं किए गए थे।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), तीन सीपीएसई (सीपीएसई_1, सीपीएसई_4 और सीपीएसई_29) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। सीपीएसई_6 ने उत्तर प्रस्तुत करते समय कहा कि आरएंडडी पर किए गए व्यय के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ हैं। हालांकि, सीपीएसई ने बीआरएसआर के तहत अनिवार्य आवश्यक विवरण प्रकट नहीं किए थे। सीपीएसई_9 उठाए गए अभ्युक्तियों पर मौन रहा।

सीपीएसई_4 के लिए कोयला मंत्रालय ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026)। रेल मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2026) कि सीपीएसई_6 स्पष्ट रूप से परिभाषित पर्यावरणीय/सामाजिक सुधार परियोजनाओं पर व्यय की पहचान करने के लिए एक आंतरिक तंत्र की तलाश कर रहा है।

- **सतत स्रोतकरण:** सतत सोर्सिंग का अर्थ है अपनी खरीद के हर चरण में पर्यावरणीय, सामाजिक और नैतिक विचारों को सम्मिलित करना। संस्था के लिए यह प्रकट करना आवश्यक था कि क्या उसने सतत सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं और यदि हां, तो सतत¹⁰⁶ रूप से सोर्स किए गए इनपुट का प्रतिशत प्रकट किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- तीन सीपीएसई (सीपीएसई_4, सीपीएसई_21 और सीपीएसई_29) में, हालांकि उन्होंने सतत सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं, सीपीएसई ने बीआरएसआर के तहत आवश्यक सतत रूप से सोर्स किए गए इनपुट के प्रतिशत का प्रकटीकरण नहीं किया था।
- एक सीपीएसई (सीपीएसई_6) ने सतत सोर्सिंग के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं और सतत रूप से सोर्स किए गए इनपुट के प्रतिशत के विवरण प्रकट किए। हालांकि, सीपीएसई_6 ऐसे विवरणों के लिए दस्तावेज प्रदान करने में सक्षम नहीं रहा था।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), सीपीएसई_4 ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जबकि सीपीएसई_6 ने उत्तर दिया कि उपलब्ध डेटा के आधार पर प्रकटीकरण किया गया था। इसे इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि कंपनी ने प्रकटीकरण की पुष्टि करने वाले आवश्यक सहायक दस्तावेज प्रदान नहीं किए। सीपीएसई_21 ने भविष्य की रिपोर्टों में इसे प्रकट करने का आश्वासन दिया। अपने उत्तर में, सीपीएसई_29 सतत सोर्सिंग के प्रतिशत के गैर-प्रकटीकरण के बारे में मौन रहा।

सीपीएसई_4 के लिए कोयला मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026)।

¹⁰⁶ ऐसे सप्लायर्स से सामान लिया गया जो या तो कंपनी के सस्टेनेबल सोर्सिंग प्रोग्राम के दायरे में आते हैं और/या एसए 8000, आईएसओ 14001, ओएचएसएस 18001 जैसे सामाजिक और पर्यावरणीय मानकों का पालन करने के लिए सर्टिफाइड हैं।

- **उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाले जोखिम:** संस्था के लिए यह प्रकट करना आवश्यक था कि क्या उनके उत्पादों या सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम उत्पन्न होते हैं।

उक्त प्रकटीकरण एक नेतृत्व संकेतक है, जिसमें प्रकटीकरण करना अनिवार्य नहीं है। 30 सीपीएसई में से, 24 सीपीएसई ने संकेतक के स्वैच्छिक प्रकटीकरण का विकल्प चुना है और छः सीपीएसई¹⁰⁷ ने संकेतक के तहत प्रकटीकरण न करने का विकल्प चुना है। प्रकटीकरण का विकल्प चुनने वाले 24 सीपीएसई की समीक्षा से पता चला कि:

- एक सीपीएसई (सीपीएसई_4) ने प्रकट किया कि यह 'लागू नहीं' था। हालांकि, सीपीएसई_4 खनन गतिविधियों में लगा हुआ है जिसका पर्याप्त पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव पड़ता है।
- एक सीपीएसई (सीपीएसई_29) ने प्रकट किया कि कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं या जोखिम नहीं पाए गए। हालांकि, सीपीएसई_29 धातु उत्पादन में लगा हुआ है, जो एक ऊर्जा-गहन प्रक्रिया है जिसका उत्सर्जन फुटप्रिंट काफी अधिक है।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), सीपीएसई_4 ने लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार किया। सीपीएसई_29 ने कहा कि उसने कई शमन रणनीतियां शुरू की हैं। सीपीएसई_4 के लिए कोयला मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

8.5.3.3 सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में सम्मिलित लोगों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए

सिद्धांत 3 में 21 संकेतक (15 आवश्यक संकेतक और छः नेतृत्व संकेतक) सम्मिलित हैं जो मूल्य श्रृंखला में कर्मचारियों और श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर गैर-भेदभाव आदि सुनिश्चित करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 30 सीपीएसई में से नौ सीपीएसई¹⁰⁸ में कोई विसंगति नहीं देखी गई। शेष 21 सीपीएसई के मामले में, लेखापरीक्षा ने कुछ संकेतकों के लिए अननुपालन/आंशिक प्रकटीकरण देखा, जिसमें ऐसे मामले भी सम्मिलित थे जहां प्रकटीकरण के औचित्य को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा को सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। सिद्धांत 3 के संबंध में जांच के संकेतक-वार परिणाम अनुलग्नक XLVII में प्रस्तुत किए गए हैं।

सिद्धांत 3 में पाई गई कमियों के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

- **कर्मचारियों/श्रमिकों का कल्याण :** संस्था के लिए स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा, मातृत्व/पितृत्व लाभ और डे-केयर सुविधा के आच्छादन के विवरण सहित कर्मचारियों और श्रमिकों के कल्याण के उपायों को प्रकट करना आवश्यक था। जानकारी स्थायी और अन्य श्रमिकों/कर्मचारियों दोनों के लिए अलग

¹⁰⁷ सीपीएसई_5, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_19 और सीपीएसई_27

¹⁰⁸ सीपीएसई_2, सीपीएसई_3, सीपीएसई_9, सीपीएसई_10, सीपीएसई_15, सीपीएसई_17, सीपीएसई_18, सीपीएसई_26 और सीपीएसई_27

से प्रकट की जानी है। साथ ही, संस्था को कर्मचारियों और श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से किए गए उपायों पर इस प्रकार हुए व्यय को प्रकट करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- तीन सीपीएसई (सीपीएसई_1, सीपीएसई_4, और सीपीएसई_22) में, कल्याणकारी उपायों के विस्तार या संस्था की इकाइयों के आच्छादन की दिशा में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या के संबंध में जानकारी आंशिक रूप से/गलत तरीके से प्रकट की गई है।
- ✓ सीपीएसई_1 में, स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य श्रमिकों के लिए आवश्यक विवरण प्रकट नहीं किए गए थे।
- ✓ सीपीएसई_22 में, गणना करते समय, स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य श्रमिकों को उसकी कुछ इकाइयों के श्रमिकों को छोड़कर गलत तरीके से माना गया था।
- ✓ सीपीएसई_4 ने प्रकट किया कि डे-केयर सुविधा कार्यस्थल पर सीधे या व्यवस्था के माध्यम से सभी के लिए सुलभ थी। 325 स्थानों/इकाइयों पर कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या का विवरण प्रदान करते हुए यह कहा गया था कि सभी कर्मचारी/श्रमिक कवर किए गए थे। जबकि इसकी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, सीपीएसई_4 के पास केवल 18 डेकेयर सुविधाएं हैं। इस प्रकार, प्रकटीकरण गलत हो गया।
- सीपीएसई_30 ने कर्मचारियों और श्रमिकों के कल्याण पर खर्च की गई राशि का प्रतिशत प्रकट नहीं किया।

उत्तर (अगस्त/अक्टूबर 2025) प्रस्तुत करते समय, तीन सीपीएसई (सीपीएसई_1, सीपीएसई_30 और सीपीएसई_22) ने लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार किया। सीपीएसई_4 से प्राप्त उत्तर उठाए गए अभ्युक्तियों से संबंधित नहीं था।

कोयला मंत्रालय ने सीपीएसई_4 और सीपीएसई_22 के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

- **सेवानिवृत्ति लाभ:** संस्था के लिए भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, कर्मचारी राज्य बीमा या अन्य जैसे सेवानिवृत्ति लाभों के तहत कवर किए गए कर्मचारियों और श्रमिकों का प्रतिशत प्रकट करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- तीन सीपीएसई (सीपीएसई_1, सीपीएसई_4 और सीपीएसई_16) में, ऐसे सेवानिवृत्ति लाभों की प्रयोज्यता और आच्छादन के संदर्भ में गलत प्रकटीकरण किए गए थे।
- ✓ सीपीएसई_4 में, यद्यपि ग्रेच्युटी योजना स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य श्रमिकों पर लागू नहीं थी, इसे 'लागू' के रूप में प्रकट किया गया था, जबकि सीपीएसई_1 में, यद्यपि ग्रेच्युटी योजना श्रमिकों पर लागू थी, इसे 'लागू नहीं' के रूप में प्रकट किया गया था।

- ✓ सीपीएसई_16 में, सेवानिवृत्ति लाभों के तहत कवर किए गए कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रतिशत को गलत तरीके से उजागर किया गया था।

उत्तर में (अगस्त 2025), उपरोक्त सभी सीपीएसई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

कोयला मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2026) कि ठेकेदार कानूनों के अनुसार 'ठेकेदार के श्रमिकों' के रूप में तैनात अपने श्रमिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। तदनुसार प्रकटीकरण किया गया था। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सीपीएसई_4 के मैनुअल में संविदात्मक श्रमिकों के लिए ग्रेच्युटी की प्रयोज्यता सुनिश्चित करने के लिए कोई खंड नहीं है।

- **समान अवसर नीति:** संस्था के लिए यह प्रकट करना आवश्यक था कि क्या उनके पास दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है। यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेबलिंग प्रकट किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- पांच सीपीएसई (सीपीएसई_5, सीपीएसई_14, सीपीएसई_30, सीपीएसई_22 और सीपीएसई_23) ने समान अवसर नीति के लिए आवश्यक जानकारी विशिष्ट रूप से प्रकट नहीं की।
- दो सीपीएसई (सीपीएसई_11 और सीपीएसई_12) में समान अवसर नीति होने के बावजूद, नीतियों के वेबलिंग प्रकट नहीं किए गए थे।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025) प्रबंधन ने कहा कि:

- सीपीएसई_5 ने एक अलग नीति तैयार करने का आश्वासन दिया।
- सीपीएसई_14 ने कहा कि एक सीपीएसई होने के नाते, यह दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित भारत सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करता है। हालांकि, उत्तर कंपनी में विशिष्ट समान अवसर नीति के अस्तित्व के बारे में मौन था।
- सीपीएसई_22 ने अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत तैयार किए गए अपने दिशानिर्देश का वेबलिंग प्रदान किया। हालांकि, इसकी बीआरएसआर रिपोर्ट में न तो नीति के अस्तित्व और न ही इसके वेबलिंग का प्रकटीकरण किया गया था।
- सीपीएसई_30 ने कहा कि नीति उपलब्ध थी। हालांकि, इसने न तो कोई नीति साझा की थी और न ही किसी वेबलिंग का प्रकटीकरण किया गया था।
- सीपीएसई_23 ने उत्तर दिया कि कंपनी का अनुपालन ढांचा, जिसके तहत समान अवसर के सिद्धांतों को कंपनी के शासन के भीतर सम्मिलित किया गया है। हालांकि, कंपनी द्वारा ऐसी कोई नीति उपलब्ध नहीं कराई गई।
- वेबलिंग की उपलब्धता के संबंध में, सीपीएसई_12 और सीपीएसई_11 ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

सीपीएसई_5 के लिए पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, सीपीएसई_11 के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा सीपीएसई_22 के लिए कोयला मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि सीपीएसई_5 ने अब समान अवसर नीति तैयार कर ली है।

- **कर्मचारियों/श्रमिकों को प्रशिक्षण:** संस्था के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कर्मचारियों और श्रमिकों की संख्या और प्रतिशत प्रकट करना आवश्यक था, जिन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों तथा कौशल उन्नयन (स्किल अपग्रेडेशन) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- पांच सीपीएसई (सीपीएसई_1, सीपीएसई_4, सीपीएसई_13, सीपीएसई_14 और सीपीएसई_21) में, बीआरएसआर रिपोर्ट में किए गए प्रकटीकरणों में प्रकटीकरणों के समर्थन में संबंधित सीपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी/दस्तावेजों के साथ विसंगतियां थीं।
- तीन सीपीएसई (सीपीएसई_7, सीपीएसई_23 और सीपीएसई_29) ने बीआरएसआर के तहत आवश्यक जानकारी का लिंग-वार अलगाव प्रकट नहीं किया।
- इसके अलावा, सीपीएसई_23 ने बीआरएसआर के तहत आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों और श्रमिकों की संख्या के बजाय मानव-दिवसों (मैन-डेज) में विवरण प्रकट किए। दो सीपीएसई (सीपीएसई_6 और सीपीएसई_28) ने उन कर्मचारियों की संख्या और प्रतिशत प्रकट किया जिन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। हालांकि, सीपीएसई ऐसे विवरणों के लिए दस्तावेज प्रदान करने में सक्षम नहीं रहे थे।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), सात सीपीएसई (सीपीएसई_4, सीपीएसई_7, सीपीएसई_13, सीपीएसई_14, सीपीएसई_21, सीपीएसई_23 और सीपीएसई_29) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। सीपीएसई_1 ने कहा कि यह सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को स्वास्थ्य और सुरक्षा पर पुनश्चर्या सत्र/प्रशिक्षण प्रदान करता है इसलिए प्रकटीकरण सही था, हालांकि, प्रदान किए गए दस्तावेजों से इस प्रकार प्रशिक्षित कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या के संबंध में प्रकटीकरण गलत था। सीपीएसई_6 ने उत्तर दिया कि उपलब्ध डेटा के आधार पर प्रकटीकरण किया गया था जबकि सीपीएसई_28 ने नियत समय में विवरण प्रदान करने का आश्वासन दिया था; हालांकि, दोनों सीपीएसई ने अपनी बीआरएसआर रिपोर्टों में किए गए प्रकटीकरणों के औचित्य को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा को आवश्यक दस्तावेज साझा नहीं किए।

सीपीएसई_4 के लिए कोयला मंत्रालय और सीपीएसई_13 तथा सीपीएसई_14 के लिए रेल मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026)।

8.5.3.4 सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए

सिद्धांत 4 में पांच संकेतक (दो आवश्यक संकेतक और तीन नेतृत्व संकेतक) सम्मिलित हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि व्यवसायों को अपने संचालन और प्रथाओं के सकारात्मक प्रभावों को अधिकतम

करके और प्रतिकूल प्रभावों को कम करके सभी हितधारकों, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के हितों का सम्मान और सुरक्षा करनी चाहिए।

समीक्षा से पता चला कि 30 सीपीएसई में से 26 सीपीएसई में कोई विसंगति नहीं देखी गई। शेष चार¹⁰⁹ सीपीएसई के मामले में, लेखापरीक्षा ने कुछ संकेतकों के लिए अननुपालन/आंशिक प्रकटीकरण देखा, जिसमें ऐसे मामले भी सम्मिलित थे जहां प्रकटीकरण के औचित्य को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा को सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। सिद्धांत 4 के संबंध में जांच के संकेतक-वार परिणाम अनुलग्नक **XLVIII** में प्रस्तुत किए गए हैं।

सिद्धांत 4 में पाई गई कमियों के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

- **कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूह** : संस्था के लिए संस्था के मुख्य हितधारक समूहों की सूची प्रकट करना आवश्यक था और यह भी कि क्या किसी हितधारक समूह की पहचान 'कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूह' के रूप में की गई है। सेबी ने उन व्यक्तियों के समूह की पहचान की 'कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूह' के रूप में है, जो प्रतिकूल शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक या स्वास्थ्य परिस्थितियों के कारण अपने अधिकारों को महसूस करने या अवसरों का आनंद लेने में असमर्थ हैं, जैसे कि महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विस्थापित/भूमिहीन छोटे/सीमांत किसान, प्रवासी श्रमिक आदि।
- समीक्षा से पता चला कि चार सीपीएसई (अर्थात सीपीएसई_4, सीपीएसई_13, सीपीएसई_14 और सीपीएसई_20) में किए गए प्रकटीकरण बीआरएसआर ढांचे की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे।
 - ✓ सीपीएसई_4 भूमि अधिग्रहण और उसके बाद पुनर्वास और पुनर्वस्थापन द्वारा खनन गतिविधियों में सम्मिलित है। हालांकि, प्रकटीकरण करते समय, सीपीएसई_4 ने अधिदेश के खिलाफ, हितधारक समूह "लैंड लूजर" (भूमि गंवाने वाले) के तहत विस्थापित/भूमिहीन किसानों को कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूहों के रूप में नहीं माना/प्रकट नहीं किया।
 - ✓ दो सीपीएसई (सीपीएसई_4 और सीपीएसई_20) ने प्रारूप और अपनी संबंधित वार्षिक रिपोर्टों के विपरीत, पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को हाशिए पर/कमजोर समूह के तहत नहीं माना।
 - ✓ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों/एमएसएमई से खरीद करने के बावजूद, तीन सीपीएसई (सीपीएसई_4, सीपीएसई_13 और सीपीएसई_14) ने उन्हें "आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों" श्रेणी में हाशिए पर और कमजोर नहीं माना है।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), तीन सीपीएसई (सीपीएसई_4, सीपीएसई_13 और सीपीएसई_14) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। सीपीएसई_20 ने कहा कि हालांकि ऐसे कमजोर समूहों को सम्मिलित किया गया और उन पर विचार किया गया, वार्षिक रिपोर्ट से प्रस्तुति में अंतर के कारण, बीआरएसआर में ऐसी जानकारी प्रकट नहीं की गई थी। हालांकि, तथ्य यह रहा कि प्रारूप के तहत आवश्यक आवश्यक प्रकटीकरण नहीं किया गया था।

¹⁰⁹ सीपीएसई_4, सीपीएसई_13, सीपीएसई_14 और सीपीएसई_20

सीपीएसई_4 के लिए कोयला मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026)। विद्युत मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2026) कि सीपीएसई_20 एक बड़ा संगठन होने के नाते, पीडब्ल्यूडी जैसे प्रत्येक उप समूह के लिए अलग हितधारक श्रेणियां बनाना व्यावहारिक या वांछनीय नहीं था। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि मंत्रालय का औचित्य सेबी के दिशानिर्देशों के साथ-साथ संस्था की अपनी वार्षिक रिपोर्ट के विरोधाभासी था।

8.5.3.5 सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

सिद्धांत 5 में 16 संकेतक (11 आवश्यक संकेतक और पांच नेतृत्व संकेतक) सम्मिलित हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि व्यवसायों को सभी के लिए मानव अधिकारों का सम्मान और बढ़ावा देना चाहिए। यह कर्मचारियों को मानव अधिकारों के मुद्दों पर प्रशिक्षण प्रदान करता है।

समीक्षा से पता चला कि 30 सीपीएसई में से 16 सीपीएसई¹¹⁰ में कोई विसंगति नहीं देखी गई। शेष 14 सीपीएसई के मामले में, लेखापरीक्षा ने कुछ संकेतकों के लिए अननुपालन/आंशिक प्रकटीकरण देखा, जिसमें ऐसे मामले भी सम्मिलित थे जहां प्रकटीकरण के औचित्य को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा को सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। सिद्धांत 5 के संबंध में जांच के संकेतक-वार परिणाम अनुलग्नक *XLIX* में प्रस्तुत किए गए हैं।

सिद्धांत 5 में पाई गई कमियों के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

- **मानव अधिकारों के मुद्दों पर प्रशिक्षण:** संस्था के लिए मानव अधिकारों के संबंध में प्रशिक्षित कर्मचारियों और श्रमिकों की संख्या और प्रतिशत प्रकट करना आवश्यक था। स्थायी और गैर-स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए अलगाव प्रदान करना भी आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- तीन सीपीएसई (सीपीएसई_4, सीपीएसई_13 और सीपीएसई_27) में, बीआरएसआर रिपोर्ट में प्रकट की गई जानकारी और संबंधित प्रबंधनों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के बीच महत्वपूर्ण अंतर था। बीआरएसआर रिपोर्टों के अनुसार, सीपीएसई_4, सीपीएसई_13 और सीपीएसई_27 के क्रमशः कुल 3011, 468 और 7007 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। हालांकि, सीपीएसई_4, सीपीएसई_13 और सीपीएसई_27 के क्रमशः केवल 1220, 288 और 753 कर्मचारियों के प्रशिक्षण विवरण प्रदान किए गए थे।
- सीपीएसई_23 ने कर्मचारियों और श्रमिकों की संख्या के बजाय मानव-दिवसों के संदर्भ में विवरण प्रकट किए।
- सीपीएसई_6 ने मानव अधिकारों के मुद्दों पर प्रशिक्षण के विवरण प्रकट किए थे। हालांकि, उसने ऐसे विवरणों के लिए दस्तावेज प्रदान नहीं किए।

¹¹⁰ सीपीएसई_2, सीपीएसई_3, सीपीएसई_1, सीपीएसई_5, सीपीएसई_7, सीपीएसई_8, सीपीएसई_9, सीपीएसई_10, सीपीएसई_12, सीपीएसई_15, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_18, सीपीएसई_21, सीपीएसई_25 और सीपीएसई_26

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), तीन सीपीएसई (सीपीएसई_4, सीपीएसई_13 और सीपीएसई_23) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। सीपीएसई_6 ने उत्तर दिया कि उपलब्ध डेटा के आधार पर प्रकटीकरण किया गया था; हालांकि, इसने प्रकटीकरण को सत्यापित करने के लिए कोई दस्तावेज साझा नहीं किए। सीपीएसई_27 ने कहा कि उसने सभी कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए मानव अधिकारों के मुद्दों और नीतियों पर व्यापक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपाय किए हैं। हालांकि, मानव अधिकार प्रशिक्षण में सभी कर्मचारियों के आच्छादन की पुष्टि करने वाले कोई सहायक दस्तावेज प्रदान नहीं किए गए थे।

सीपीएसई_4 के लिए कोयला मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026)।

- **शिकायतें :** संस्था के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, भेदभाव, बाल श्रम, जबरन श्रम आदि पर वर्ष के दौरान कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा दर्ज की गई और वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या प्रकट करना आवश्यक था। इसके अलावा, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत दर्ज शिकायतों का प्रतिशत सहित कुल शिकायतें भी प्रकट की जानी चाहिए। उपरोक्त जानकारी पिछले वित्तीय वर्षों के लिए भी प्रकट की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- दो सीपीएसई (सीपीएसई_20 और सीपीएसई_27) ने पोश के तहत शिकायतों के प्रतिशत की गणना करते समय केवल स्थायी महिला श्रमिकों और कर्मचारियों पर विचार किया, और 'स्थायी महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के अलावा अन्य' को छोड़ दिया।
- एक सीपीएसई (सीपीएसई_30) ने आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की है।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), दो सीपीएसई (सीपीएसई_20 और सीपीएसई_27) ने स्वीकार किया कि गणना में स्थायी महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के अलावा अन्य पर विचार नहीं किया गया था। सीपीएसई_27 ने भविष्य की रिपोर्टों में आवश्यक सुधार करने का आश्वासन भी दिया। सीपीएसई_30 ने कहा कि प्रकटीकरण अन्य संकेतक जोकि संकेतक संख्या 6 में किया गया था और इसलिए यहां नहीं किया गया था।

यह उजागर करना प्रासंगिक है कि संकेतक संख्या 6 के तहत, संस्था को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, भेदभाव, बाल श्रम, जबरन श्रम आदि पर वर्ष के दौरान कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा दर्ज की गई और वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या प्रकट करनी थी, हालांकि संकेतक 7 के तहत संस्था को महिला कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में पोश पर शिकायतों को प्रकट करना आवश्यक था और सही पाई गई शिकायतों की संख्या भी प्रकट करना आवश्यक है। हालांकि, संकेतक के तहत विवरण प्रकट नहीं किए गए हैं।

- **मानव अधिकारों के मुद्दों का मूल्यांकन :** संस्था के लिए अपनी उन इकाइयों का प्रतिशत प्रकट करना आवश्यक था जहां बाल श्रम, जबरन श्रम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, भेदभाव, मजदूरी आदि जैसे मानव अधिकारों के मुद्दों के लिए मूल्यांकन किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- दो सीपीएसई (सीपीएसई_4 और सीपीएसई_27) ने अपनी इकाइयों का आवश्यक प्रतिशत प्रकट नहीं किया है, जहां मूल्यांकन किया गया था।
- सीपीएसई_19 में, हालांकि यह प्रकट किया गया था कि 100 प्रतिशत मूल्यांकन किया गया था, खदानों और क्षेत्रीय कार्यालयों का मूल्यांकन नहीं किया गया था।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), दो सीपीएसई (सीपीएसई_4 और सीपीएसई_19) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। सीपीएसई_27 ने कहा कि SA8000:2014 के तहत प्रमाणन, एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक उत्तरदेही मानक और मानव अधिकारों के मुद्दों के मूल्यांकन के माध्यम से, कंपनी ने समय के साथ सभी स्थानों का उचित और निरंतर आच्छादन सुनिश्चित किया। हालांकि, आच्छादन का प्रतिशत, जैसा कि अनिवार्य रूप से बीआरएसआर के तहत प्रकट किया जाना था, नहीं बताया गया था।

सीपीएसई_4 के लिए कोयला मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

8.5.3.6 सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसकी सुरक्षा तथा जीर्णोद्धार के लिए प्रयास करने चाहिए

सिद्धांत 6 जिसमें 20 संकेतक (13 आवश्यक संकेतक और 7 नेतृत्व संकेतक) सम्मिलित हैं, ऊर्जा खपत/तीव्रता, जल निकासी/खपत और निर्वहन, वायु और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, अपशिष्ट प्रबंधन, परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन आदि के संबंध में विवरण प्रकट करके पर्यावरण के संरक्षण और जीर्णोद्धार पर जोर देता है।

समीक्षा से पता चला कि 30 सीपीएसई में से 12 सीपीएसई¹¹¹ में कोई विसंगति नहीं देखी गई। शेष 18 सीपीएसई के मामले में, लेखापरीक्षा ने कुछ संकेतकों के लिए अननुपालन/आंशिक प्रकटीकरण देखा, जिसमें ऐसे मामले भी सम्मिलित थे जहां प्रकटीकरण के औचित्य को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा को सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। सिद्धांत 6 के संबंध में जांच के संकेतक-वार परिणाम *अनुलग्नक L* में प्रस्तुत किए गए थे।

सिद्धांत 6 में पाई गई कमियों के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

- **ऊर्जा खपत** : संस्था के लिए कुल ऊर्जा खपत (नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय) के विवरण के साथ-साथ टर्नओवर के प्रति रुपये मापी गई ऊर्जा तीव्रता, क्रय शक्ति समता¹¹² के लिए समायोजित तीव्रता और भौतिक आउटपुट के संदर्भ में तीव्रता प्रकट करना आवश्यक था। इसके अलावा, किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन/समीक्षा/आश्वासन, यदि कोई हो, को प्रकट करना आवश्यक था।

¹¹¹ सीपीएसई_1, सीपीएसई_3, सीपीएसई_8, सीपीएसई_9, सीपीएसई_10, सीपीएसई_15, सीपीएसई_17, सीपीएसई_18, सीपीएसई_19, सीपीएसई_21, सीपीएसई_30 और सीपीएसई_27

¹¹² क्रय शक्ति समता उन वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को मापती है जो किसी देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश में खरीद सकती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- **ऊर्जा खपत और ऊर्जा तीव्रता :** एक सीपीएसई (सीपीएसई_11) ने 'लागू नहीं' बताते हुए कोई जानकारी प्रकट नहीं की, हालांकि बीआरएसआर के तहत ऐसी कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। सीपीएसई_14 में, आवश्यक प्रारूप में प्रकटीकरण नहीं किया गया था। दो सीपीएसई (सीपीएसई_16 और सीपीएसई_28) में, प्रकटीकरण विवरणों की गणना कंपनी की कुछ इकाइयों/संयंत्रों पर विचार करके की गई थी।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), सीपीएसई_11 ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए कहा कि आगामी वर्षों में आवश्यक सुधार किया गया है जबकि सीपीएसई_28 ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मुद्दे का समाधान नहीं किया। सीपीएसई_16 ने कहा कि उसने प्रकटीकरण के लिए केवल विनिर्माण इकाइयों (पांच) पर विचार किया। इसे इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि विपणन, सेवा और परियोजना कार्यालयों, कॉर्पोरेट विपणन, नेटवर्क सिस्टम इकाइयों आदि जैसी विनिर्माण इकाइयों के अलावा अन्य इकाइयों को बाहर रखने की छूट बीआरएसआर के तहत प्रदान नहीं की गई थी। सीपीएसई_14 ने कहा कि प्रकटीकरण बीआरएसआर के तहत आवश्यकता के अनुसार किया गया था। इसे इस तथ्य के आलोक में भी देखा जा सकता है कि प्रकटीकरण अनिवार्य प्रारूप के अनुसार नहीं था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2026) कि सीपीएसई_11 ने बीआरएसआर 2024-25 रिपोर्ट में आवश्यक बदलाव किए हैं।

- **टर्नओवर के प्रति रुपये ऊर्जा तीव्रता :** टर्नओवर के प्रति रुपये ऊर्जा तीव्रता परिचालन से राजस्व द्वारा विभाजित कुल ऊर्जा खपत के बराबर होती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- ✓ दो सीपीएसई (सीपीएसई_20 और सीपीएसई_24) में, 'परिचालन से राजस्व' के बजाय 'कुल आय' का उपयोग करके ऊर्जा तीव्रता की गलत गणना की गई थी।
- ✓ सीपीएसई_13 में, गणना में एक अंकगणितीय त्रुटि देखी गई थी।
- ✓ सीपीएसई_7 में, पीपीपी के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपये ऊर्जा तीव्रता और भौतिक आउटपुट के संदर्भ में विवरण प्रकट नहीं किए गए थे।
- ✓ सीपीएसई_5 ने 'लागू नहीं' बताते हुए भौतिक आउटपुट के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता प्रकट नहीं की, हालांकि बीआरएसआर के तहत ऐसी कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।
- ✓ दो सीपीएसई (सीपीएसई_6 और सीपीएसई_28) ने 'लागू नहीं' बताते हुए पीपीपी के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपये ऊर्जा तीव्रता प्रकट नहीं की, हालांकि बीआरएसआर के तहत ऐसी कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। इसके अलावा, इन दोनों सीपीएसई ने भौतिक आउटपुट के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता प्रकट नहीं की है।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), छः सीपीएसई (सीपीएसई_7, सीपीएसई_6, सीपीएसई_5, सीपीएसई_13, सीपीएसई_20 और सीपीएसई_24) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और भविष्य की रिपोर्टों में आवश्यक प्रकटीकरण का आश्वासन दिया जबकि सीपीएसई_28 ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मुद्दे का समाधान नहीं किया।

रेल मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय ने अपने सीपीएसई के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026)।

➤ **मापन इकाइयां :** बीआरएसआर के अनुसार, इस संकेतक के तहत डेटा जूल या गीगा जूल जैसे गुणकों के संदर्भ में रिपोर्ट किया जाएगा।

दो सीपीएसई (सीपीएसई_4 और सीपीएसई_6) में, ऊर्जा खपत या/और ऊर्जा तीव्रता के लिए मापन इकाइयों (जैसे गीगाजूल/मेगाजूल/रु करोड़, आदि) का उल्लेख नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप तुलना में अस्पष्टता थी।

उत्तर में (अगस्त 2025), सीपीएसई_4 ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जबकि सीपीएसई_6 ने उत्तर दिया कि उपलब्ध डेटा के आधार पर प्रकटीकरण किया गया था। इसे इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि आवश्यक जानकारी प्रकट नहीं की गई थी।

कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने अपने सीपीएसई के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026) और आगामी बीआरएसआर रिपोर्टों में आवश्यक प्रकटीकरण करने का आश्वासन दिया।

➤ **स्वतंत्र मूल्यांकन:**

✓ एक सीपीएसई (सीपीएसई_23) ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन/समीक्षा/आश्वासन के संबंध में विवरण प्रकट नहीं किए।

उत्तर में (अगस्त 2025), सीपीएसई_23 ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए भविष्य की रिपोर्टों में आवश्यक प्रकटीकरण करने का आश्वासन दिया।

• **जल निकासी और खपत:** संस्था के लिए कुल जल निकासी और खपत के साथ-साथ टर्नओवर के प्रति रुपये मापी गई जल तीव्रता, पीपीपी के लिए समायोजित तीव्रता और भौतिक आउटपुट के संदर्भ में तीव्रता प्रकट करना आवश्यक था। इसके अलावा, किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन/समीक्षा/आश्वासन, यदि कोई हो, को प्रकट करना आवश्यक था।

अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि:

➤ **जल निकासी और तीव्रता:**

✓ एक सीपीएसई (सीपीएसई_11) ने कोई जानकारी प्रकट नहीं की और 'लागू नहीं' कहा, हालांकि बीआरएसआर के तहत ऐसी कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।

✓ सीपीएसई_14 में, आवश्यक प्रारूप में प्रकटीकरण नहीं किया गया था।

- ✓ सीपीएसई_16 में, प्रकटीकरण विवरणों की गणना कंपनी की कुछ इकाइयों/संयंत्रों पर विचार करके की गई थी।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), सीपीएसई_11 ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए कहा कि आगामी वर्षों में आवश्यक सुधार किया गया है। सीपीएसई_16 ने कहा कि उसने प्रकटीकरण के लिए केवल विनिर्माण इकाइयों (पांच) पर विचार किया। इसे इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि विपणन, सेवा और परियोजना कार्यालयों, कॉर्पोरेट विपणन, नेटवर्क सिस्टम इकाइयों आदि जैसी विनिर्माण इकाइयों के अलावा अन्य इकाइयों को बाहर रखने की छूट बीआरएसआर के तहत प्रदान नहीं की गई है। सीपीएसई_14 ने कहा कि एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी उत्पादों के निर्माण में सम्मिलित नहीं है और इस प्रकार, पानी का उपयोग नगण्य था। इसे इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि बीआरएसआर के तहत इस तरह से बाहर रखने की छूट प्रदान नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2026) कि सीपीएसई_11 ने बीआरएसआर 2024-25 रिपोर्ट में आवश्यक बदलाव किए थे।

- **कुल बिक्री के प्रति रुपये जल की तीव्रता:** टर्नओवर के प्रति रुपये जल तीव्रता परिचालन से राजस्व द्वारा विभाजित कुल जल खपत के बराबर होती है।
 - ✓ तीन सीपीएसई (सीपीएसई_12, सीपीएसई_20 और सीपीएसई_24) ने जल तीव्रता की गणना करते समय 'परिचालन से राजस्व' के बजाय 'कुल आय' पर विचार किया।
 - ✓ एक सीपीएसई (सीपीएसई_13) में, जल तीव्रता की गणना में अंकगणितीय त्रुटि देखी गई थी।
 - ✓ सीपीएसई_25 में, भौतिक आउटपुट के संदर्भ में जल तीव्रता गलत तरीके से प्रकट की गई थी और सीपीएसई_5 में, यह प्रकट नहीं की गई थी।
 - ✓ दो सीपीएसई (सीपीएसई_7 और सीपीएसई_20) में, पीपीपी के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपये जल तीव्रता और भौतिक आउटपुट के संदर्भ में विवरण प्रकट नहीं किए गए थे।
 - ✓ एक सीपीएसई (सीपीएसई_5) ने भौतिक आउटपुट के संदर्भ में जल तीव्रता प्रकट नहीं की और 'लागू नहीं' कहा, हालांकि बीआरएसआर के तहत ऐसी कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।
 - ✓ दो सीपीएसई (सीपीएसई_6 और सीपीएसई_28) ने 'लागू नहीं' बताते हुए पीपीपी के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपये जल तीव्रता प्रकट नहीं की, हालांकि बीआरएसआर के तहत ऐसी कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। इसके अलावा, इन दोनों सीपीएसई ने भौतिक आउटपुट के संदर्भ में जल तीव्रता प्रकट नहीं की है।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), आठ सीपीएसई (सीपीएसई_5, सीपीएसई_6, सीपीएसई_7, सीपीएसई_12, सीपीएसई_13, सीपीएसई_20, सीपीएसई_25 और सीपीएसई_24) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जबकि सीपीएसई_28 ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मुद्दे का समाधान नहीं किया।

विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय (सीपीएसई_6 और सीपीएसई_13 के लिए) और पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए आगामी बीआरएसआर रिपोर्टों में आवश्यक प्रकटीकरण करने का आश्वासन दिया (जनवरी 2026)।

सीपीएसई_28 के संबंध में रेल मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2026) कि पीपीपी-समायोजित तीव्रता के लिए, सीपीएसई_28 द्वारा 2023-24 के लिए बीआरएसआर की तैयारी के समय कोई अनुदेशात्मक कार्यान्वयन विधि उपलब्ध नहीं थी। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि बीआरएसआर पर सेबी का परिपत्र (जुलाई 2023) स्वतः स्पष्ट है और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है।

➤ **जल निकासी, खपत और निर्वहन:** सेबी के परिपत्र के अनुसार, कुल जल खपत की गणना कुल जल निकासी और कुल जल निर्वहन के बीच के अंतर के रूप में की जानी आवश्यक है।

- ✓ छः सीपीएसई (सीपीएसई_2, सीपीएसई_4, सीपीएसई_6, सीपीएसई_13, सीपीएसई_22 और सीपीएसई_28) में, इन संकेतकों के तहत प्रकटीकरण अंकगणितीय रूप से गलत थे।
- ✓ एक सीपीएसई (सीपीएसई_11) ने 'लागू नहीं' बताते हुए कोई जानकारी प्रकट नहीं की, हालांकि बीआरएसआर के तहत ऐसी कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), पांच सीपीएसई (सीपीएसई_2, सीपीएसई_4, सीपीएसई_11, सीपीएसई_13 और सीपीएसई_22) ने लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार किया और भविष्य की रिपोर्टों में आवश्यक प्रकटीकरण का आश्वासन दिया जबकि सीपीएसई_28 ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मुद्दे का समाधान नहीं किया। सीपीएसई_6 ने कहा कि प्रकटीकरण कंपनी के पास उपलब्ध डेटा के आधार पर किया गया था। इसे इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि जानकारी गलत तरीके से प्रकट की गई थी।

कोयला मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026) और आवश्यक बदलाव करने का आश्वासन दिया। रक्षा मंत्रालय ने सीपीएसई_2 के लिए और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2026) कि संबंधित सीपीएसई ने बीआरएसआर 2024-25 रिपोर्ट में आवश्यक बदलाव किए हैं।

➤ **मापन इकाई और स्वतंत्र मूल्यांकन**

- ✓ बीआरएसआर में एक सीपीएसई (सीपीएसई_4) द्वारा प्रकट जल निर्वहन के लिए मापन इकाई कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान किए गए विवरणों से मेल नहीं खाती थी।
- ✓ एक सीपीएसई (सीपीएसई_23) ने जल निकासी, खपत और निर्वहन के लिए किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन/समीक्षा/आश्वासन के संबंध में विवरण प्रकट नहीं किए।

उत्तर में (अगस्त 2025), उपरोक्त दोनों सीपीएसई ने लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार किया और भविष्य की रिपोर्टों में आवश्यक प्रकटीकरण करने का आश्वासन दिया।

- **वायु उत्सर्जन:** संस्था के लिए वायु उत्सर्जन अर्थात् नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हार्डस एयर पॉल्यूटेंट आदि के विवरण प्रकट करना आवश्यक था। इसके अलावा, किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया स्वतंत्र मूल्यांकन/समीक्षा/आश्वासन, यदि कोई हो, तो उसे प्रकट करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- **आंशिक/गलत प्रकटीकरण:** दो सीपीएसई (सीपीएसई_23 और सीपीएसई_24) ने केवल तीन मापदंडों के लिए प्रकटीकरण किया और बीआरएसआर के तहत अनिवार्य अन्य मापदंडों के लिए प्रकटीकरण प्रदान नहीं किया गया।
- **स्वतंत्र मूल्यांकन:** एक सीपीएसई (सीपीएसई_23) ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन/समीक्षा/आश्वासन के संबंध में विवरण प्रकट नहीं किए।
- सीपीएसई_25 में, वार्षिक वायु उत्सर्जन की रिपोर्ट 10 महिनों (अप्रैल 2023 से जनवरी 2024) के डेटा के आधार पर की गई थी जिससे प्रकटीकरण अधूरा रह गया।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), उपरोक्त सभी सीपीएसई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। इस्पात मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2026) कि सीपीएसई_23 द्वारा बीआरएसआर रिपोर्ट की शुरुआत में खंड 'क' में ईएसजी प्रकटीकरणों के स्वतंत्र मूल्यांकन और उचित आश्वासन के संबंध में जानकारी प्रदान की गई थी।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि उल्लिखित आश्वासन बीआरएसआर कोर से संबंधित था जो वायु उत्सर्जन प्रकटीकरण पर कोई आश्वासन प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा, सीपीएसई_23 ने आवश्यकतानुसार बीआरएसआर रिपोर्ट में वायु उत्सर्जन के लिए किए जा रहे स्वतंत्र मूल्यांकन के विवरण प्रकट नहीं किए हैं।

- **ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) - (परिक्षेत्र 1 और परिक्षेत्र 2)¹¹³:** संस्था के लिए जीएचजी तीव्रता के साथ जीएचजी के उत्सर्जन पर विवरण प्रकट करना आवश्यक था, जिसे प्रति रुपये टर्नओवर, पीपीपी के लिए समायोजित तीव्रता और भौतिक आउटपुट के संदर्भ में तीव्रता के रूप में मापा गया हो। इसके अलावा, किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन/समीक्षा/आश्वासन, यदि कोई हो, को प्रकट करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- **कोई प्रकटीकरण नहीं:**
 - ✓ एक सीपीएसई (सीपीएसई_11) ने 'लागू नहीं' बताते हुए कोई जानकारी प्रकट नहीं की, हालांकि बीआरएसआर के तहत ऐसी कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।

¹¹³ स्कोप 1 एमिशन सीधे जीएचजी एमिशन हैं जो एंटीटी के मालिकाना हक या कंट्रोल वाले सोर्स से होते हैं, और स्कोप 2 एमिशन एनर्जी के इनडायरेक्ट एमिशन हैं जो एंटीटी द्वारा खरीदी या हासिल की गई बिजली, हीटिंग, कूलिंग और स्टीम के इस्तेमाल से होते हैं।

- ✓ सीपीएसई_14 में, आवश्यक प्रारूप में प्रकटीकरण नहीं किया गया था।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), सीपीएसई_11 ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए कहा कि आगामी वर्षों में आवश्यक सुधार किया गया है। सीपीएसई_14 ने कहा कि प्रकट की गई जानकारी कंपनी के संचालन की प्रकृति पर आधारित थी। इसे इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि प्रकटीकरण उस प्रारूप में नहीं किया गया था जैसा कि बीआरएसआर में अनिवार्य किया गया है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2026) कि सीपीएसई_11 ने बीआरएसआर 2024-25 प्रतिवेदन में आवश्यक बदलाव किए थे जबकि रेल मंत्रालय इस मुद्दे पर मौन रहा।

➤ **टर्नओवर के प्रति रुपये जीएचजी तीव्रता :** टर्नओवर के प्रति रुपये जीएचजी तीव्रता जीएचजी उत्सर्जन (परिक्षेत्र 1 और 2) को रुपये में परिचालन से राजस्व द्वारा विभाजित करने के बराबर होती है।

- ✓ दो सीपीएसई (सीपीएसई_20 और सीपीएसई_24) में, जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता के लिए प्रकटीकरण अंकगणितीय रूप से गलत थे।
- ✓ सीपीएसई_25 में, भौतिक आउटपुट के संदर्भ में जीएचजी तीव्रता (परिक्षेत्र 1 और 2) के लिए प्रकट आंकड़े गलत थे।
- ✓ सीपीएसई_13 में, जीएचजी तीव्रता के उत्सर्जन की मापन इकाई अंकगणितीय रूप से गलत थी। इसके अलावा, परिक्षेत्र-1 उत्सर्जन के तहत प्रकट मूल्य गलत तरीके से प्रकट किया गया था क्योंकि इसकी गणना पेट्रोल खपत से सीओ₂ उत्सर्जन को छोड़कर की गई थी।
- ✓ दो सीपीएसई (सीपीएसई_6 और सीपीएसई_28) ने 'लागू नहीं' बताते हुए पीपीपी के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपये जीएचजी तीव्रता प्रकट नहीं की। इसके अलावा, इन दोनों सीपीएसई ने भौतिक आउटपुट के संदर्भ में जीएचजी तीव्रता प्रकट नहीं की है।
- ✓ दो सीपीएसई (सीपीएसई_5 और सीपीएसई_29) ने भौतिक आउटपुट के संदर्भ में जीएचजी तीव्रता प्रकट नहीं की।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), सात सीपीएसई (सीपीएसई_6, सीपीएसई_5, सीपीएसई_13, सीपीएसई_20, सीपीएसई_25, सीपीएसई_24 और सीपीएसई_29) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और भविष्य की रिपोर्टों में आवश्यक प्रकटीकरण का आश्वासन भी दिया जबकि सीपीएसई_28 ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मुद्दे का समाधान नहीं किया।

सीपीएसई_5 के लिए पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने आगामी बीआरएसआर रिपोर्टों में आवश्यक प्रकटीकरण करने का आश्वासन दिया (जनवरी 2026)।

सीपीएसई_6 और सीपीएसई_28 के लिए रेल मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2026) कि बीआरएसआर रिपोर्टों की तैयारी के दौरान उपलब्ध तीव्रता संकेतकों के आसपास विस्तृत मार्गदर्शन की कमी के कारण

ऐसा प्रकटीकरण हुआ। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सेबी द्वारा निर्धारित बीआरएसआर प्रारूप स्वतः स्पष्ट और प्रकृति में विस्तृत है।

सीपीएसई_20 के लिए विद्युत मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2026) कि उत्सर्जन की गणना सीईए दिशानिर्देशों के अनुसार की गई थी। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सीपीएसई_20 द्वारा प्रकट जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता अंकगणितीय रूप से गलत थी।

➤ **स्वतंत्र मूल्यांकन:**

- ✓ एक सीपीएसई (सीपीएसई_23) ने यह प्रकट नहीं किया कि किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन/समीक्षा/आश्वासन किया गया था या नहीं।

उत्तर में (अगस्त 2025), सीपीएसई_23 ने स्वतंत्र मूल्यांकन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और भविष्य की रिपोर्टों में आवश्यक प्रकटीकरण का आश्वासन भी दिया।

- **अपशिष्ट प्रबंधन :** संस्था के लिए उत्पन्न कचरे की विस्तृत जानकारी प्रकट करना आवश्यक था, जिसमें प्लास्टिक कचरा, ई-कचरा, बायो-मेडिकल कचरा, बैटरी कचरा आदि जैसी श्रेणियां सम्मिलित थीं, साथ ही टर्नओवर के प्रति रुपये मापी गई अपशिष्ट तीव्रता, पीपीपी के लिए समायोजित तीव्रता और भौतिक आउटपुट के संदर्भ में तीव्रता सम्मिलित थी। इसके अलावा, किसी बाहरी एजेंसी द्वारा किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन/समीक्षा/आश्वासन, यदि कोई हो, को प्रकट करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

➤ **गलत प्रकटीकरण**

- ✓ दो सीपीएसई (सीपीएसई_4 और सीपीएसई_13) में, प्रति रुपये टर्नओवर अपशिष्ट तीव्रता अंकगणितीय रूप से गलत थी।
- ✓ सीपीएसई_24 में, निपटाए गए कचरे की मात्रा अंकगणितीय रूप से गलत थी।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), सीपीएसई_4, सीपीएसई_13 और सीपीएसई_24 ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

कोयला मंत्रालय ने स्वीकार किया और आगामी बीआरएसआर रिपोर्टों में आवश्यक बदलाव करने का आश्वासन दिया। सीपीएसई_13 के लिए रेल मंत्रालय ने भी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

➤ **आंशिक रिपोर्टिंग:**

- ✓ दो सीपीएसई (सीपीएसई_13 और सीपीएसई_16) में, प्रकटीकरण विवरणों की गणना कंपनी की कुछ इकाइयों/संयंत्रों पर विचार करके की गई थी।
- ✓ सीपीएसई_26 ने 'लागू नहीं' बताते हुए इस संकेतक के तहत कोई जानकारी प्रकट नहीं की। हालांकि, बीआरएसआर के तहत ऐसी कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।

- ✓ सीपीएसई_20 में, टर्नओवर के प्रति रुपये अपशिष्ट तीव्रता, पीपीपी के लिए समायोजित तीव्रता और भौतिक आउटपुट के संदर्भ में तीव्रता प्रकट नहीं की गई थी।
- ✓ सीपीएसई_28 में पीपीपी के लिए अपशिष्ट तीव्रता प्रकट नहीं की गई थी, जिसके लिए 'लागू नहीं' कहा गया था। हालांकि बीआरएसआर के तहत ऐसी कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।
- ✓ सीपीएसई_23 ने यह प्रकट नहीं किया कि किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन/समीक्षा/आश्वासन किया गया था या नहीं।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), तीन सीपीएसई (सीपीएसई_13, सीपीएसई_23 और सीपीएसई_20) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और भविष्य की रिपोर्टों में आवश्यक प्रकटीकरण का आश्वासन भी दिया जबकि सीपीएसई_28 ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मुद्दे का समाधान नहीं किया। सीपीएसई_16 ने कहा कि उसने प्रकटीकरण के लिए केवल विनिर्माण इकाइयों (पांच) पर विचार किया। इसे इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि विपणन, सेवा और परियोजना कार्यालयों, कॉर्पोरेट विपणन, नेटवर्क सिस्टम इकाइयों आदि जैसी विनिर्माण इकाइयों के अलावा अन्य इकाइयों को बाहर रखने की छूट बीआरएसआर के तहत प्रदान नहीं की गई है। सीपीएसई_26 ने कहा कि उनके परिसरों में कचरा नगण्य था, इसलिए इसे प्रकट नहीं किया गया। इसे इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि इस तरह से बाहर रखने की छूट बीआरएसआर के तहत प्रदान नहीं की गई है।

सीपीएसई_13 के लिए रेल मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026) जबकि सीपीएसई_28 के लिए मंत्रालय ने कहा कि बीआरएसआर रिपोर्टों की तैयारी के दौरान उपलब्ध तीव्रता संकेतकों के आसपास विस्तृत मार्गदर्शन की कमी के कारण ऐसा प्रकटीकरण हुआ। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सेबी द्वारा निर्धारित बीआरएसआर प्रारूप स्वतः स्पष्ट और प्रकृति में विस्तृत है।

- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए):** संस्था के लिए यह प्रकट करना आवश्यक था कि क्या परियोजनाओं का ईआईए स्वतंत्र बाहरी एजेंसी के माध्यम से आयोजित किया गया था और इस प्रकार प्राप्त परिणाम वेब लिंक के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- एक सीपीएसई (सीपीएसई_4) ने प्रकट किया कि ईआईए एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया था। हालांकि, अभिलेखों की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि यह सीपीएसई_4 की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा आयोजित किया गया था। इस प्रकार, प्रकटीकरण तथ्यात्मक रूप से गलत था।
- एक सीपीएसई (सीपीएसई_20) ने वेबलिंक प्रदान करने के बजाय, संबंधित कॉलम में सीपीसीबी और एमओईएफसीसी का उल्लेख किया।

उत्तरों में (अगस्त/अक्टूबर 2025), सीपीएसई_4 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर मौन रहा। सीपीएसई_20 ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनी संबंधित वेबसाइटों पर और एमओईएफसीसी परिवेश पोर्टल

पर ईआईए प्रदर्शित करते हैं। इसे इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि सीपीएसई_20 की विशिष्ट परियोजनाओं के ईआईए को निर्देशित करने वाले वेबलिंग प्रकट नहीं किए गए थे, हालांकि बीआरएसआर के तहत यह अनिवार्य था।

कोयला मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026)।

8.5.3.7 सिद्धांत 7: व्यवसायों को, सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में सम्मिलित होते समय, जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से ऐसा करना चाहिए

सिद्धांत 7 में तीन संकेतक (दो आवश्यक संकेतक और एक नेतृत्व संकेतक) सम्मिलित हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि व्यवसाय निर्दिष्ट विधायी और नीतिगत ढांचे के भीतर काम करते हैं, सरकारों के साथ जुड़ने के लिए व्यवसाय की वैधता और जनहित के लिए नीति की वकालत करते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 30 सीपीएसई में से 27 सीपीएसई में कोई विसंगति नहीं थी और शेष तीन सीपीएसई¹¹⁴ के मामले में, लेखापरीक्षा ने कुछ संकेतकों के लिए अननुपालन/आंशिक प्रकटीकरण देखा। सिद्धांत 7 के संबंध में जांच के संकेतक-वार परिणाम **अनुलग्नक LI** में प्रस्तुत किए गए थे।

सिद्धांत 7 में पाई गई कमियों के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

- **व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता:** संस्था के लिए व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धताओं की संख्या प्रकट करना आवश्यक था। संस्था को अपनी शीर्ष 10 संबद्धताओं की सूची प्रकट करना भी आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- एक सीपीएसई (सीपीएसई_7) में संबद्धताओं की कुल संख्या प्रकट नहीं की गई थी।
- एक सीपीएसई (सीपीएसई_1) में, ऐसी 10 संबद्धताओं में से पांच संबद्धताएं¹¹⁵ व्यापार संघ के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करती थीं।

उत्तर में (अगस्त 2025), दोनों सीपीएसई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

8.5.3.8 सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

सिद्धांत 8 जिसमें 11 संकेतक (पांच आवश्यक संकेतक और छः नेतृत्व संकेतक) सम्मिलित हैं, नकारात्मक प्रभावों का आकलन और शमन करने के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन आयोजित करने, आकांक्षी जिलों में सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन, समुदाय से प्राप्त शिकायतों और उनके निवारण तंत्र, एमएसएमई/छोटे उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए खरीद नीति, छोटे शहरों में रोजगार सृजन आदि पर जोर देता है।

¹¹⁴ सीपीएसई_1, सीपीएसई_4 और सीपीएसई_7

¹¹⁵ उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित एक विशेष एजेंसी, तेल उद्योग विकास बोर्ड- एक वैधानिक निकाय, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के तहत एक संगठन, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद- एक स्वैच्छिक स्व-नियामक संगठन और विश्व एलपीजी फोरम- एक वैश्विक मंच।

समीक्षा से पता चला कि 30 सीपीएसई में से 17 सीपीएसई में कोई विसंगति नहीं देखी गई। शेष 13 सीपीएसई¹¹⁶ के मामले में, लेखापरीक्षा ने कुछ संकेतकों के लिए अननुपालन/आंशिक प्रकटीकरण देखा, जिसमें ऐसे मामले भी सम्मिलित थे जहां प्रकटीकरण के औचित्य को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा को सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। सिद्धांत 8 के संबंध में जांच के संकेतक-वार परिणाम **अनुलग्नक LII** में प्रस्तुत किए गए थे।

सिद्धांत 8 में पाई गई कमियों के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

- **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री** : संस्था के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों/छोटे उत्पादकों (एमएसएमई) से की गई खरीद का प्रतिशत और भारत के भीतर की गई खरीद का प्रतिशत प्रकट करना आवश्यक था। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान की गई कुल खरीद पर इन प्रतिशतों की गणना की जानी आवश्यक थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- एमएसएमई से खरीद के विरुद्ध प्रकटीकरण के लिए
 - ✓ चार सीपीएसई (सीपीएसई_1, सीपीएसई_4, सीपीएसई_16 और सीपीएसई_20) में, उन उत्पादों की खरीद जो एमएसएमई/छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादित नहीं की गई थीं, प्रतिशत निकालते समय कुल खरीद से बाहर कर दी गई थीं।
- भारत के भीतर खरीद के विरुद्ध प्रकटीकरण के लिए।
 - ✓ यद्यपि सीपीएसई_16 ने प्रकट किया कि यह संकेतक लागू नहीं था, हालांकि यह गलत था क्योंकि सीपीएसई_16 ने भारत के भीतर खरीद की थी।
 - ✓ सीपीएसई_29 ने भारत के भीतर खरीद का प्रतिशत प्रकट नहीं किया।
- एक सीपीएसई (सीपीएसई_6) ने एमएसएमई से की गई खरीद और भारत के भीतर खरीद का प्रतिशत प्रकट किया। हालांकि, ये सीपीएसई ऐसे विवरणों के लिए दस्तावेज प्रदान करने में सक्षम नहीं थे।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025) प्रबंधन ने कहा कि:

- तीन सीपीएसई (सीपीएसई_1, सीपीएसई_16 और सीपीएसई_29) ने लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार किया।
- सीपीएसई_4 ने कहा (अगस्त 2025) कि एमएसएमई मंत्रालय ने उसे उन वस्तुओं को बाहर रखने की छूट दी है जो एमएसई के दायरे या क्षमता से परे हैं, जैसे कि एचईएमएम, लोहा और इस्पात आदि। हालांकि, तथ्य यह है कि संदर्भित परिपत्र केवल एमएसएमई से अनिवार्य खरीद लक्ष्य प्राप्त करने में ढील से संबंधित है न कि बीआरएसआर ढांचे के तहत प्रकटीकरण

¹¹⁶ सीपीएसई_1, सीपीएसई_4, सीपीएसई_6, सीपीएसई_14, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_19, सीपीएसई_30, सीपीएसई_22, सीपीएसई_20, सीपीएसई_27, सीपीएसई_28 और सीपीएसई_29

आवश्यकताओं से संबंधित है; इसलिए, जबकि सीपीएसई_4 का अपवर्जन एमएसएमई खरीद लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से मान्य हो सकता है, इसे बीआरएसआर संकेतकों की गणना या प्रकटीकरण तक स्वचालित रूप से विस्तारित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि ऐसी कार्यप्रणाली और छूट को रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से समझाया और प्रकट न किया गया हो।

- सीपीएसई_6 ने उत्तर दिया कि चूंकि आंकड़े जीईएम और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) के पास दायर सीएसआर फॉर्म से निकाले गए थे, जो सभी प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं और इस प्रकार, कोई और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। हालांकि, बीआरएसआर प्रकटीकरण के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज प्रदान नहीं किए गए थे।

- सीपीएसई_20 ने लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए इस अभ्युक्तियों पर उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

रेल मंत्रालय ने सीपीएसई_6 के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और भविष्य के अनुपालन का आश्वासन दिया।

विद्युत मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2026) कि एमएसएमई मंत्रालय ने सीपीएसई (सीपीएसई_20) को ईंधन, इस्पात, सीमेंट आदि जैसी कुछ खरीद श्रेणियों को बाहर रखने की छूट दी है (अगस्त 2021)। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि छूट एमएसएमई से अनिवार्य खरीद लक्ष्य प्राप्त करने के लिए थी न कि बीआरएसआर ढांचे के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताओं से संबंधित थी।

- **छोटे शहरों में रोजगार सृजन :** संस्था के लिए ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी और महानगरीय की श्रेणी के तहत छोटे शहरों में कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुलग्नक के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिकों सहित) को भुगतान की गई कुल मजदूरी का प्रतिशत प्रकट करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- एक सीपीएसई (सीपीएसई_1) ने प्रकटीकरण करते समय कहा कि "भुगतान की गई मजदूरी की जानकारी केवल प्रबंधन कर्मचारियों के लिए प्रदान की गई है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी श्रमिक की भर्ती नहीं की गई थी", हालांकि, बीआरएसआर रिपोर्ट के सिद्धांत-5 (कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की गई न्यूनतम मजदूरी) के अनुसार, श्रमिकों (स्थायी श्रमिक के अलावा अन्य) की संख्या 24314 से बढ़कर 25847 हो गई। इस प्रकार, प्रकटीकरण गलत था।
- एक सीपीएसई (सीपीएसई_22) ने गलत प्रकटीकरण किया क्योंकि सभी श्रेणियों के तहत कर्मचारियों/श्रमिकों को भुगतान की गई मजदूरी का कुल प्रतिशत 100 प्रतिशत के बजाय 0.177 प्रतिशत प्रकट किया गया था।
- दो सीपीएसई (सीपीएसई_16 और सीपीएसई_30) ने छोटे शहरों में कार्यरत व्यक्तियों को भुगतान की गई कुल मजदूरी लागत का प्रतिशत प्रकट नहीं किया।
- दो सीपीएसई (सीपीएसई_4 और सीपीएसई_6) ने छोटे शहरों में कार्यरत व्यक्तियों को भुगतान की गई कुल मजदूरी लागत का प्रतिशत प्रकट किया। हालांकि, ये सीपीएसई ऐसे विवरणों के लिए दस्तावेज प्रदान करने में सक्षम नहीं थे।

उत्तर में (अगस्त 2025) चार सीपीएसई (सीपीएसई_1, सीपीएसई_16, सीपीएसई_30 और सीपीएसई_22) ने लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार किया। सीपीएसई_4 ने कहा कि ईआरपी विभाग से प्राप्त जानकारी पर प्रकटीकरण किए गए थे। सीपीएसई_6 ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। इसे इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि न तो सीपीएसई_4 और न ही सीपीएसई_6 ने प्रकटीकरण के लिए कोई सहायक दस्तावेज साझा किए।

सीपीएसई_22 के लिए कोयला मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026) जबकि सीपीएसई_4 के लिए उसने कहा कि यद्यपि विवरण/रिपोर्ट वास्तविक समय के आधार पर एसएपी के माध्यम से उत्पन्न होती हैं, कुछ कर्मचारी संबंधित कार्रवाई के कारण भिन्नता मांगी गई अवधि के लिए जानकारी को प्रभावित कर सकती है। मंत्रालय के उत्तर ने प्रकट की गई जानकारी में भिन्नता की पुष्टि की।

सीपीएसई_6 के लिए रेल मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2026) कि प्रकट किए गए प्रतिशतों की गणना स्थान के अनुसार मैप किए गए पेट्रोल डेटा और शहर की श्रेणियों (ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी, मेट्रो) के आंतरिक रूप से परिभाषित वर्गीकरण का उपयोग करके की गई थी। पेट्रोल सिस्टम में आवश्यक जानकारी होती है; हालांकि, ऑडिट के समय एक समेकित बीआरएसआर विशिष्ट रिपोर्ट नहीं बनाई गई थी। हालांकि, मंत्रालय ने भविष्य की रिपोर्टों के लिए शहर श्रेणी टैग और मानक प्रणाली की समीक्षा करने का आश्वासन दिया।

- **आकांक्षी जिलों में सीएसआर परियोजनाएं :** संस्था के लिए सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए निर्दिष्ट आकांक्षी जिलों में संस्था द्वारा शुरू की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं और उस पर खर्च की गई राशि को प्रकट करना आवश्यक था।

उक्त प्रकटीकरण एक नेतृत्व संकेतक है, जिसमें प्रकटीकरण करना अनिवार्य नहीं है। 30 सीपीएसई में से, 27 सीपीएसई ने संकेतक के स्वैच्छिक प्रकटीकरण का विकल्प चुना है और तीन सीपीएसई ¹¹⁷ ने संकेतक के तहत प्रकटीकरण न करने का विकल्प चुना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- सीपीएसई_13 ने सीएसआर परियोजनाओं के लिए प्रकटीकरण करते समय स्वीकृत परियोजना राशि को खर्च के रूप में दिखाया, हालांकि, रिकॉर्ड के अनुसार, राशि पूरी तरह से खर्च नहीं की गई थी जिससे प्रकटीकरण गलत हो गया।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), सीपीएसई_13 ने बताया कि सीएसआर हेतु राशि कंपनी के खाते से समर्पित अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी, इसलिए उसे व्यय के रूप में माना गया और तदनुसार प्रकटीकृत किया गया। तथापि, उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि प्रतिवेदन में सीएसआर परियोजनाओं पर वास्तव में व्यय की गई राशि का ही प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित था।

सीपीएसई_13 के लिए रेल मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026)।

¹¹⁷ सीपीएसई_5, सीपीएसई_16 और सीपीएसई_27

- **अधिमान्य खरीद नीति :** संस्थाओं के लिए यह प्रकट करना आवश्यक था कि क्या उनके पास हाशिए पर/कमजोर समूहों से खरीदने के लिए अधिमान्य (वरीयता) खरीद नीति है और यदि हाँ, तो उस समूह का नाम और उस समूह से खरीद का प्रतिशत प्रकट किया जाना था।

उक्त प्रकटीकरण एक नेतृत्व संकेतक है, जिसमें प्रकटीकरण करना अनिवार्य नहीं है। 30 सीपीएसई में से, 27 सीपीएसई ने स्वैच्छिक प्रकटीकरण का विकल्प चुना है और तीन सीपीएसई ¹¹⁸ने संकेतक के तहत प्रकटीकरण न करने का विकल्प चुना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- एक सीपीएसई (सीपीएसई_4) ने प्रकट किया कि उसने एमएसएमई के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों के स्वामित्व वाले उद्यमों से अधिमान्य खरीद की थी। हालांकि, प्रतिशत निकालते समय उन उत्पादों की खरीद जो एमएसएमई/छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती हैं, कुल खरीद से बाहर कर दी गई हैं।
- एक सीपीएसई (सीपीएसई_22) ने अधिमान्य खरीद नीति के तहत कहा कि उनके पास हाशिए पर/कमजोर समूहों से युक्त आपूर्तिकर्ताओं से अधिमान्य खरीद के लिए कोई नीति नहीं है। हालांकि, प्रकटीकरण गलत था, क्योंकि सीपीएसई_22 के खरीद मैनुअल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों यानी हाशिए पर/कमजोर समूहों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से अनिवार्य खरीद का प्रावधान सम्मिलित था।
- एक सीपीएसई (सीपीएसई_14) ने अधिमान्य खरीद नीति के अस्तित्व और हाशिए पर/कमजोर समूहों से खरीद के प्रतिशत का प्रकटीकरण किया। हालांकि, ये सीपीएसई ऐसे विवरणों के लिए दस्तावेज प्रदान करने में सक्षम नहीं थे।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), सीपीएसई_22 ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। सीपीएसई_4 ने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय ने उसे उन वस्तुओं को बाहर रखने की छूट दी है जो एमएसई के दायरे या क्षमता से परे हैं, जैसे कि भारी अर्थ मूविंग मशीनरी, लोहा और इस्पात आदि। हालांकि, संदर्भित परिपत्र केवल एमएसएमई से अनिवार्य खरीद लक्ष्य प्राप्त करने में ढील से संबंधित है न कि बीआरएसआर ढांचे के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताओं से संबंधित है। इसलिए, जबकि सीपीएसई_4 का अपवर्जन एमएसएमई खरीद लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से मान्य हो सकता है, इसे बीआरएसआर संकेतकों की गणना या प्रकटीकरण तक स्वचालित रूप से विस्तारित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि ऐसी कार्यप्रणाली और छूट को रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से समझाया और प्रकट न किया गया हो। सीपीएसई_14 ने कहा कि वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जानकारी का उल्लेख किया गया था। हालांकि, तथ्य यह रहा कि प्रकट किए गए प्रतिशत तक पहुंचने के लिए विशिष्ट दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रकटीकरण की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए प्रदान नहीं किए गए थे।

कोयला मंत्रालय ने सीपीएसई_22 के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

¹¹⁸ सीपीएसई_5, सीपीएसई_16 और सीपीएसई_27

8.5.3.9 सिद्धांत 9: व्यवसायों को जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।

सिद्धांत 9 में 11 संकेतक (सात आवश्यक संकेतक और चार नेतृत्व संकेतक) सम्मिलित हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि व्यवसायों को उपभोक्ता कल्याण सुनिश्चित करने, सूचित विकल्पों को बढ़ावा देने और अत्यधिक खपत के प्रभावों को संबोधित करते हुए सुरक्षित, मूल्य-संचालित वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान करना चाहिए। सिद्धांत में निहित संकेतकों का अनुपालन बीआरएसआर प्रकटीकरण ढांचे के अनुसार नहीं किया गया है जो इस प्रकार है:

समीक्षा से पता चला कि 30 सीपीएसई में से 22 सीपीएसई में कोई विसंगति नहीं देखी गई। शेष आठ सीपीएसई¹¹⁹ में, कुछ संकेतकों के लिए अननुपालन/आंशिक प्रकटीकरण देखे गए। इनमें वे सीपीएसई सम्मिलित हैं जहाँ संकेतक के संबंध में किए गए प्रकटीकरणों के औचित्य को सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा को सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। सिद्धांत 9 के संबंध में जांच के संकेतक-वार परिणाम *अनुलग्नक LIII* में प्रस्तुत किए गए थे।

सिद्धांत 9 में पाई गई कमियों के मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

- **उपभोक्ता शिकायतें और प्रतिक्रिया :** संस्था के लिए उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका उत्तर देने के लिए स्थापित तंत्र का प्रकटीकरण करना आवश्यक था।

समीक्षा से पता चला कि:

- एक सीपीएसई (सीपीएसई_11) ने बीआरएसआर के तहत आवश्यक तंत्र का वर्णन नहीं किया है।

उत्तर में (अगस्त 2025), सीपीएसई_11 ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सीपीएसई_11 के लिए अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026) और कहा कि बीआरएसआर 2024-25 रिपोर्ट में आवश्यक बदलाव किए गए हैं।

- **साइबर सुरक्षा ढांचा/नीति :** संस्था के लिए यह प्रकट करना आवश्यक था कि क्या उनके पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से जुड़े जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- एक सीपीएसई (सीपीएसई_4) के पास 'आईटी नीति और साइबर सुरक्षा नीति' है और इसे उसकी वेबसाइट पर हाइलाइट किया जा रहा है। नीति होने के बावजूद, बीआरएसआर रिपोर्ट में प्रकटीकरण करते समय, सीपीएसई_4 ने न तो इस नीति के अस्तित्व का प्रकटीकरण किया और न ही आवश्यक वेब-लिंक प्रदान किया।

¹¹⁹ सीपीएसई_4, सीपीएसई_7, सीपीएसई_11, सीपीएसई_16, सीपीएसई_30, सीपीएसई_20, सीपीएसई_26 और सीपीएसई_27

- हालांकि चार सीपीएसई (सीपीएसई_7, सीपीएसई_11, सीपीएसई_16 और सीपीएसई_26) ने नीति के अस्तित्व का प्रकटीकरण किया, लेकिन उनकी नीतियों के वेबलिंग प्रदान नहीं किए गए थे।

उत्तर में (अगस्त/अक्टूबर 2025), तीन सीपीएसई (सीपीएसई_4, सीपीएसई_11 और सीपीएसई_16) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया। सीपीएसई_7 ने अभ्युक्तियों पर टिप्पणी की और प्रकटीकरण में बदलाव की आवश्यकता का मूल्यांकन करने का आश्वासन दिया। सीपीएसई_16 ने उपयुक्त प्रकटीकरण करने का आश्वासन भी दिया। सीपीएसई_26 ने कहा कि आईटी साइबर सुरक्षा नीति एक गोपनीय दस्तावेज है जो कड़ाई से आंतरिक उपयोग के लिए है और इस प्रकार, इसे सार्वजनिक डोमेन में साझा नहीं किया गया था। हालांकि, ये तथ्य कंपनी की बीआरएसआर रिपोर्ट में प्रकट नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2026) कि सीपीएसई_11 ने बीआरएसआर 2024-25 रिपोर्ट में आवश्यक बदलाव किए थे। कोयला मंत्रालय ने सीपीएसई_4 में आईटी नीति के अस्तित्व को बताया और अपने उत्तर में वेबलिंग प्रदान किया। हालांकि, वास्तविकता यह रही कि सीपीएसई_4 ने अपनी बीआरएसआर रिपोर्ट में न तो इस नीति के अस्तित्व का प्रकटीकरण किया और न ही आवश्यक वेब-लिंग प्रदान किया।

8.5.4 आंतरिक नियंत्रण में कमियां

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अर्थ संस्था द्वारा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, विश्वसनीय जानकारी की तैयारी और उसकी रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं से है।

समीक्षा से पता चला कि समीक्षाधीन सीपीएसई के बीच बीआरएसआर रिपोर्टिंग को नियंत्रित करने वाले आंतरिक नियंत्रण परिवेश में प्रलेखन (डॉक्यूमेंटेशन), डेटा सटीकता, आश्वासन तंत्र के क्षेत्रों में प्रणालीगत कमियां पाई गईं जो इस प्रकार हैं:

8.5.4.1 आश्वासन आवश्यकताओं का अननुपालन

सेबी ने अधिदेश दिया (जुलाई 2023) कि शीर्ष 150 सूचीबद्ध संस्थाओं को तीसरे पक्ष के आश्वासन प्रदाता (थर्ड-पार्टी एश्योरेंस प्रोवाइडर) से बीआरएसआर कोर पर उचित आश्वासन प्राप्त करना आवश्यक है। सेबी ने तीसरे पक्ष के आश्वासन प्रदाता द्वारा आश्वासन प्रस्तुत करने के लिए एक प्रारूप निर्धारित किया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- 30 सीपीएसई में से 18 सीपीएसई को उचित आश्वासन प्राप्त करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने 16 सीपीएसई में कोई विसंगति नहीं देखी।
- एक सीपीएसई (सीपीएसई_28) के मामले में सीमित आश्वासन देने के लिए तीसरे पक्ष के आश्वासन प्रदाता को नियुक्त किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सेबी की आवश्यकता का अननुपालन हुआ।

- सीपीएसई_4 में, आश्वासन प्रदाता ने बीआरएसआर कोर के बजाय बीआरएसआर प्रारूप पर आश्वासन विवरण जारी किया।

ये चूक दर्शाती हैं कि आश्वासन प्रक्रिया प्रकटीकरणों की विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा बढ़ाने के इच्छित उद्देश्य को पूरा करने में विफल रही और निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप भी नहीं थी।

सीपीएसई_4 ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर टिप्पणी की जबकि सीपीएसई_28 से उत्तर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने (21 अगस्त 2025) तक प्राप्त नहीं हुआ था।

कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2026) और आगामी रिपोर्टों में आवश्यक बदलाव करने का आश्वासन दिया।

8.5.4.2 नए अद्यतन प्रारूप में बीआरएसआर ढांचे का गैर-पालन

सेबी ने मई 2021 में, बीआरएसआर ढांचे में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन मापदंडों पर रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की शुरुआत की थी। सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए आश्वासन तंत्र को मजबूत करने और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से, जुलाई 2023 में 'बीआरएसआर कोर' ढांचे की शुरुआत के साथ इस रिपोर्टिंग ढांचे को संशोधित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक सीपीएसई (सीपीएसई_16) ने जुलाई 2023 में सेबी द्वारा निर्धारित संशोधित प्रारूप के अनुसार अपनी बीआरएसआर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। शेष सभी सीपीएसई ने आवश्यक प्रारूप में प्रकटीकरण किया है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए, सीपीएसई ने आश्वासन दिया है कि भविष्य की रिपोर्टों में उपयुक्त प्रकटीकरण किया जाएगा।

8.5.4.3 अन्य मुद्दे

- **गलत और आंशिक प्रकटीकरण:** लेखापरीक्षा के सामने ऐसे मामले आए जहां बीआरएसआर रिपोर्ट में सीपीएसई द्वारा किए गए प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट में दी गई जानकारी या संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के साथ असंगत थे अथवा मेल नहीं खा रहे थे। साथ ही, आंशिक प्रकटीकरण/प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अननुपालन के मामले भी हैं, जिन्हें संबंधित संकेतकों के साथ उजागर किया गया है।

उपरोक्त कमियां डेटा संग्रह, सत्यापन और प्रलेखन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की अनुपस्थिति को दर्शाती हैं जिसके परिणामस्वरूप रिपोर्टिंग में अशुद्धताएं हुई हैं।

8.5.5 डेटा संग्रह तंत्र और बीआरएसआर की तैयारी में चुनौतियां

नमूनाकृत सीपीएसई में डेटा संग्रह तंत्र और बीआरएसआर की तैयारी में चुनौतियों की जांच की गई जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

➤ डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग तंत्र:

19 सीपीएसई में, बीआरएसआर रिपोर्ट विभागीय संसाधनों के माध्यम से संकलित और तैयार की गई थीं, जबकि 11 सीपीएसई¹²⁰ ने रिपोर्टों के संकलन और तैयारी के लिए बाहरी एजेंसियों को नियुक्त किया था। इन 11 सीपीएसई में, रिपोर्ट की तैयारी संबंधित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत डेटा पर आधारित थी।

➤ समर्पित प्रणालियों/मॉड्यूलों और नीतियों की अनुपस्थिति:

लेखापरीक्षा ने जांच की कि क्या प्रचलित आईटी परिवेश में समर्पित प्रणाली/मॉड्यूल है। सीपीएसई ने विशेष रूप से बीआरएसआर रिपोर्टिंग के लिए कोई समर्पित डेटा संग्रह मॉड्यूल या उपकरण विकसित नहीं किए थे। इसके अलावा, बीआरएसआर रिपोर्टों की तैयारी और संकलन को नियंत्रित करने के लिए कोई आंतरिक नीतियां या दिशानिर्देश तैयार नहीं किए गए थे।

➤ क्षमता निर्माण के प्रयास:

दो सीपीएसई (सीपीएसई_1 और सीपीएसई_10) ने कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करके बीआरएसआर रिपोर्टिंग को मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण की दिशा में पहल की है।

➤ डेटा समेकन में चुनौतियाँ:

विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों से डेटा को एक मानकीकृत बीआरएसआर प्रारूप में समेकित करना, केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन मंच की अनुपलब्धता, पर्यावरण डेटा का संकलन और मात्रा निर्धारण सीपीएसई द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों के रूप में पहचाना गया, जो रिपोर्टिंग की दक्षता और गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

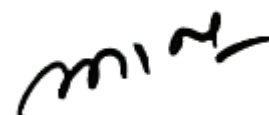
कोयला मंत्रालय, सीपीएसई_2 और सीपीएसई_3 के लिए रक्षा मंत्रालय, सीपीएसई_6 और सीपीएसई_13 के लिए रेल मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, सीपीएसई_20 के लिए विद्युत मंत्रालय और पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2026) कि भविष्य में ईएसजी प्रकटीकरणों के लिए सेबी द्वारा अनिवार्य ढांचे के अनुसार, बीआरएसआर के लिए रिपोर्टिंग प्रक्रिया को परिष्कृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

8.6 निष्कर्ष

संस्थाओं द्वारा पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन मापदंडों के संबंध में प्रकटीकरण आवश्यकताओं को बढ़ाने और आश्वासन को मजबूत करने के लिए सेबी द्वारा बीआरएसआर ढांचा जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने सेबी द्वारा अनिवार्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं के संबंध में चयनित सीपीएसई की बीआरएसआर रिपोर्टों में अननुपालन और विसंगतियों के मामलों को देखा। बीआरएसआर रिपोर्ट

¹²⁰ सीपीएसई_4, सीपीएसई_8, सीपीएसई_9, सीपीएसई_13, सीपीएसई_17, सीपीएसई_19, सीपीएसई_21, सीपीएसई_22, सीपीएसई_23, सीपीएसई_24 और सीपीएसई_28

में प्रकटीकरण करते समय, लेखापरीक्षा ने अनुबंधों के खिलाफ गलत प्रकटीकरण और आंशिक प्रकटीकरण देखे जिन्हें रिपोर्ट में उजागर किया गया है। ऐसे मामले भी थे जहां सीपीएसई द्वारा बीआरएसआर रिपोर्ट में किए गए प्रकटीकरण उनकी अपनी वार्षिक रिपोर्टों में प्रकट की गई जानकारी के साथ असंगत थे।



(आनंद मोहन बजाज)

उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(वाणिज्यिक एवं आरसी) एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली

दिनांक: 04 अगस्त 2026

प्रतिहस्ताक्षरित



(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 04 अगस्त 2026

अनुलग्नक

अनुलग्नक-1 (पैरा संख्या 1.1.3 देखें)
31 मार्च 2024 के अनुसार सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य
कंपनियों/सांविधिक निगमों की सूची

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
	सरकारी कंपनियां
1	एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड
2	एग्नीइनोवेटिव इंडिया लिमिटेड
3	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
4	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड
5	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड
6	एआईसी-आईपीआर प्लाज़्माटेक इनोवेशन फाउंडेशन
7	एआईसी आरआरसीएटी पीआई-हब फाउंडेशन
8	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड
9	अनंतपुरम-कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड
10	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11	अंडमान फिशरीज लिमिटेड
12	एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
13	एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
14	अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड
15	अपोलो डिज़ाइन अपैरल पार्क्स लिमिटेड
16	आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड
17	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
18	औरंगाबाद टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क्स लिमिटेड
19	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
20	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
21	बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
22	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
23	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ लिमिटेड
24	बीईएल-थैल्स सिस्टम्स लिमिटेड
25	बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड
26	बीईएमएल लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
27	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
28	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड
29	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड
30	भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड
31	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
32	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
33	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
34	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
35	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड
36	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
37	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
38	भारत ऑप्टैल्मिक ग्लास लिमिटेड
39	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए लिमिटेड
40	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड
41	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
42	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
43	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड
44	भारत संचार निगम लिमिटेड
45	भारत यंत्र निगम लिमिटेड
46	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड
47	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड
48	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
49	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
50	बिहार इन्फ्रा पावर लिमिटेड
51	बिहार मेगा पावर लिमिटेड
52	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद
53	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
54	बीपीसीएल-केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड
55	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड
56	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
57	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
58	ब्रेथवेट नाकोफ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड
59	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
60	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
61	ब्रशवेयर लिमिटेड
62	बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
63	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
64	कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड
65	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
66	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
67	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
68	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
69	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
70	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटररेस्ट ऑफ इंडिया
71	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
72	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड
73	चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम लिमिटेड
74	चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
75	चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
76	चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड
77	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
78	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड
79	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
80	चेन्नूर इन्फ्रा लिमिटेड
81	छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
82	छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड
83	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
84	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड
85	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड
86	सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड
87	सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड
88	कोल इंडिया लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
89	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
90	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
91	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
92	कॉनकोर एयर लिमिटेड
93	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
94	क्रिएटिव म्यूजियम डिज़ाइनर्स
95	साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
96	दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव एस सी/एस टी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
97	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
98	दिल्ली मेट्रो लास्ट माइल सर्विसेज लिमिटेड
99	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
100	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
101	देवघर इन्फ्रा लिमिटेड
102	देवघर मेगा पावर लिमिटेड
103	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
104	दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड
105	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
106	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
107	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
108	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
109	ईसीजीसी लिमिटेड
110	एडसिल (इंडिया) लिमिटेड
111	एडसिल विद्यांजलि फाउंडेशन
112	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
113	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
114	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
115	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
116	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
117	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड
118	गेल (इंडिया) लिमिटेड
119	गेल गैस लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
120	गेल मेंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
121	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
122	गैस एंड पावर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
123	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
124	घोघरपाली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
125	ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड
126	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
127	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
128	गोला-बी रामगढ़-बी ट्रांसमिशन लिमिटेड
129	गोल्डमोहर डिज़ाइन एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड
130	माल एवं सेवा कर नेटवर्क
131	गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
132	ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड
133	ग्रिड नियंत्रण ऑफ इंडिया लिमिटेड
134	गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड
135	हासन मेंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
136	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
137	हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
138	हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
139	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी
140	एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड
141	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
142	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
143	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड
144	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
145	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
146	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड
147	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
148	हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
149	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
150	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
151	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
152	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
153	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
154	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
155	हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
156	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड
157	एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड
158	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
159	एचएलएल मेडीपार्क लिमिटेड
160	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
161	एचएमटी लिमिटेड
162	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
163	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड
164	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
165	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
166	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
167	एचपीसीएल बायो फ्यूल्स लिमिटेड
168	एचपीसीएल एलएनजी लिमिटेड
169	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड
170	एचपीसीएल रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
171	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
172	आईटीआई लिमिटेड
173	आईडीपीएल तमिलनाडु (प्राइवेट) लिमिटेड
174	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड
175	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
176	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
177	आईएफसीआई लिमिटेड
178	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड
179	आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड
180	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड
181	आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
182	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
183	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
184	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
185	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
186	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड
187	इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
188	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड
189	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
190	इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइज़ेशन
191	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड
192	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
193	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
194	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
195	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
196	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
197	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
198	इंडियन वैक्सीन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
199	इंडो-रशियन हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड
200	इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड
201	इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड
202	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड
203	आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड
204	इरकॉन अकलोली-शिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड
205	इरकॉन भोज-मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड
206	इरकॉन दावणगेरे-हावेरी हाईवे लिमिटेड
207	इरकॉन गुडगांव-रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड
208	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड
209	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
210	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
211	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड
212	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
213	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड
214	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
215	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
216	आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड
217	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड
218	आईआरईएल आईडीसीओएल लिमिटेड
219	आईटीपीओ सर्विसेज़ लिमिटेड
220	जेएंडके मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
221	जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
222	जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
223	जम्मू एवं कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
224	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
225	झारखंड इन्फ्रापावर लिमिटेड
226	झारखंड नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
227	जोडा बारबिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
228	जोगीघोपा लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड
229	कल्लाम ट्रांसको लिमिटेड
230	कंकनी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
231	कर्मयोगी भारत
232	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
233	कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन
234	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड
235	कावारत्ती स्मार्ट सिटी लिमिटेड
236	खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड
237	खावड़ा IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
238	खावड़ा IV ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
239	खावड़ा IV-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड
240	खावड़ा पीएस 1 एंड 3 ट्रांसमिशन लिमिटेड
241	खावड़ा वी ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
242	केआईओसीएल लिमिटेड
243	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
244	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
245	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
246	कोंकण एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड
247	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
248	कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
249	लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
250	लक्षद्वीप टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
251	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड
252	लोकटक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड
253	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
254	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
255	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
256	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
257	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
258	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
259	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
260	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
261	महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
262	एमएएमसी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
263	मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
264	मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड
265	मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
266	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
267	मसाकानी पारादीप रोड विकास लिमिटेड
268	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
269	एमईसीओएन मेकान लिमिटेड
270	मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
271	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड
272	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
273	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
274	मिश्र धातु निगम लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
275	एमजेएसजे कोल लिमिटेड
276	एमएमटीसी लिमिटेड
277	एमएनएच शक्ति लिमिटेड
278	ऑयल लिमिटेड
279	एमपीसीओएन लिमिटेड
280	एमएसटीसी लिमिटेड
281	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
282	मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड
283	म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड
284	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
285	नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड
286	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड
287	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
288	नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
289	नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
290	नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फॉर्मेशन
291	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
292	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
293	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
294	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड
295	राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम
296	नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
297	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
298	नेशनल हाईवेज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
299	नेशनल हाईवेज़ इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
300	नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज आईएनसी
301	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
302	नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड
303	नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
304	राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम लिमिटेड
305	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
306	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
307	नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
308	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
309	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
310	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
311	नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
312	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
313	नेशनल टेक्स्टाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
314	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
315	एनबीसीसी सर्विसेज़ लिमिटेड
316	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांज़िट लिमिटेड
317	नेपा लिमिटेड
318	एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
319	एनईआरजीएस-I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
320	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैनुफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
321	नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल स्मार्ट सिटी लिमिटेड
322	न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड
323	नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड
324	एनएचडीसी लिमिटेड
325	एनएचपीसी लिमिटेड
326	एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड
327	एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड
328	एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड
329	एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
330	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
331	एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड
332	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड
333	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन
334	एनएमडीसी लिमिटेड
335	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड
336	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
337	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
338	नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स क्रिएटिव कॉर्पोरेशन लिमिटेड
339	नॉर्थ ईस्टर्न रिजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
340	नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड
341	एनपीसीआईएल इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
342	एनआरटीयू फाउंडेशन
343	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड
344	एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
345	एनटीपीसी विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड
346	एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
347	एनटीपीसी लिमिटेड
348	एनटीपीसी खनन लिमिटेड
349	एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड
350	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड
351	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
352	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
353	ओडिशा इन्फ्रापावर लिमिटेड
354	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
355	ऑयल इंडिया लिमिटेड
356	दमन, दीव एवं दादरा तथा नगर हवेली का सर्वव्यापी औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
357	ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड
358	ओएनजीसी पेट्रो एडिशनल्स लिमिटेड
359	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
360	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड
361	ओडिशा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड
362	ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड
363	ओवीएल ओवरसीज आईएफएससी लिमिटेड
364	पारादीप संचार लिमिटेड
365	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
366	पवन हंस लिमिटेड
367	पीईसी लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
368	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
369	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
370	पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर
371	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
372	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
373	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड
374	पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
375	पावरग्रिड बाड़मेर I ट्रांसमिशन लिमिटेड
376	पावरग्रिड ब्यावर - मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड
377	पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड
378	पावरग्रिड भड़ला बीकानेर ट्रांसमिशन लिमिटेड
379	पावरग्रिड भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
380	पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड
381	पावरग्रिड भड़ला-III स्टूडियो लिमिटेड
382	पावरग्रिड भीड़ गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड
383	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड
384	पावरग्रिड बीकानेर नीमराना ट्रांसमिशन लिमिटेड
385	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
386	पावरग्रिड धर्मजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
387	पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड
388	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड
389	पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
390	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
391	पावरग्रिड गोमति यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड
392	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड
393	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड
394	पावरग्रिड खवड़ा II-बी ट्रांसमिशन लिमिटेड
395	पावरग्रिड खवड़ा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड
396	पावरग्रिड खावड़ा री ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
397	पावर ग्रिड खेत्री ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
398	पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
399	मित्रगण केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
400	पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड
401	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड
402	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड
403	पावरग्रिड मेवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
404	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड
405	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड
406	पावरग्रिड नीमराना बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड
407	पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
408	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड
409	पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड
410	पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड
411	पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
412	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड
413	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
414	पावरग्रिड सिरोही ट्रांसमिशन लिमिटेड
415	पावरग्रिड सदरन इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
416	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड
417	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड
418	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
419	पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड
420	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड
421	प्राइज़ पेट्रोलियन कंपनी लिमिटेड
422	प्रोजेक्ट्स एंड डिवेलपमेंट इंडिया लिमिटेड
423	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड
424	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
425	रेल विकास निगम लिमिटेड
426	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
427	राजस्थान ड्रग्स एंड फारमास्युटिकल्स लिमिटेड
428	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
429	राजस्थान IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
430	राजस्थान IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
431	राजस्थान IV एच1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
432	राजस्थान पार्ट I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
433	रामकनानी बी-पानागढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
434	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
435	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
436	राष्ट्रीय ईस्पात निगम लिमिटेड
437	रेटल इलेक्ट्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
438	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
439	आरईसी लिमिटेड
440	आरईसी पावर एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड
441	पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड
442	आरईएमसी लिमिटेड
443	रेरोल बर्न लिमिटेड
444	रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड
445	राइट्स लिमिटेड
446	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड
447	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
448	सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड
449	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
450	साभार साल्ट्स लिमिटेड
451	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
452	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
453	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
454	सीएचसीआईएल सर्विसेज़ लिमिटेड
455	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड
456	शॉगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
457	सिडकुल कॉनकोर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड
458	सीकर खेत्री ट्रांसमिशन लिमिटेड
459	सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड
460	सियोट ट्रांसमिशन लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
461	एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
462	एसजेवीएन लिमिटेड
463	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड
464	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
465	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
466	एसटीसीएल लिमिटेड
467	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
468	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
469	स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड
470	स्टॉक होल्डिंग सिन्क्रोरीटीज़ आईएफएससी लिमिटेड
471	सूती टेक ऑप्शंस लिमिटेड
472	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइज़ेशन
473	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड
474	टीसीआईएल लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड
475	टी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
476	टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
477	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
478	टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड
479	द बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड
480	द ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
481	द ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
482	द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
483	द एल्लिगन मिल्स कंपनी लिमिटेड
484	द एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड
485	द फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
486	द हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
487	द इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
488	द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
489	द केरल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
490	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
491	द ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
492	द उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
493	द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
494	द सदरन पेस्टिसाइड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
495	द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
496	ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड
497	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
498	टूप कम्फर्ट्स लिमिटेड
499	तुमकुर-II आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
500	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
501	टुस्को लिमिटेड
502	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
503	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
504	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
505	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
506	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
507	विज्ञान इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
508	विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड
509	वाप्कोस लिमिटेड
510	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
511	यंत्र इंडिया लिमिटेड
512	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
513	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड
514	ज़ेनिथ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
515	पुणे III ट्रांसमिशन लिमिटेड
516	जामनगर ट्रांसमिशन लिमिटेड
517	अंगुल सुंदरगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
518	पीएफसी इन्फ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड
519	भुज II ट्रांसमिशन लिमिटेड
520	ईआरईएस-XXXIX पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
521	पावरग्रिड साउथ ओलपाड ट्रांसमिशन लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
	सांविधिक निगम
1	एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया
2	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन
3	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन
4	फूड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया
5	इनलैंड वॉटरवेज़ अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया
6	नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
7	नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया

क्रम सं.	सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कंपनियाँ
1	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज़ कंपनी लिमिटेड
2	एक्यूमेज़र्स (पंजाब) लिमिटेड
3	एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड
4	एएफसी इंडिया लिमिटेड
5	एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
6	अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे कंपनी लिमिटेड
7	एआईसी-आरआरयू इनक्यूबेशन फ़ाउंडेशन
8	एलाइड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
9	आंध्रा बैंक फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड
10	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड
12	एपिटको फ़ाउंडेशन
13	एपिटको लिमिटेड
14	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
15	एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड
16	अवंतिका गैस लिमिटेड
17	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
18	बैंक ऑफ़ इंडिया ट्रस्टी सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
19	बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज़ लिमिटेड
20	बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड
21	बेंगलुरु एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कंपनियाँ
22	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
23	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
24	भरुच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड
25	भोर सागर पोर्ट लिमिटेड
26	बीको लॉरी लिमिटेड
27	बिहार इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइज़ेशन लिमिटेड
28	बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
29	बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड
30	बीओआई एएक्सए इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
31	बीओआई मर्चेन्ट बैंकर्स लिमिटेड
32	बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड
33	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी (पी) लिमिटेड
34	कलकत्ता हल्दिया पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
35	केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड
36	केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
37	केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
38	कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लिमिटेड
39	कैनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड
40	कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड
41	कैनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड
42	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड
43	सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड
44	सेंट्रल यू.पी गैस लिमिटेड
45	चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
46	चेन्नई एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
47	चेन्नई एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड
48	सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड
49	कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड
50	कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज़ लिमिटेड
51	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
52	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड

क्रम सं.	सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कंपनियाँ
53	सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर प्राइवेट लिमिटेड
54	सीएससी वाई-फाई चौपाल सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
55	डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइज़ेशन
56	दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
57	देवघर एयरपोर्ट लिमिटेड
58	धालभूमगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड
59	धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड
60	डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड
61	डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड
62	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
63	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड
64	ईएसजी रिस्क असेसमेंट्स एंड इनसाइट लिमिटेड
65	एक्सेलसियर प्लांट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
66	एफएसीटी आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड
67	फ्लेवरिट स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड
68	गंगावती शुगर्स लिमिटेड
69	गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
70	ग्रीन गैस लिमिटेड
71	हार्डिकॉन लिमिटेड
72	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड
73	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
74	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
75	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड
76	हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड
77	एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड
78	आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड
79	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लिमिटेड
80	आईडीबीआई इनटेक लिमिटेड
81	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
82	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड
83	आईएचबी प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कंपनियाँ
84	आईआईडीएल रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
85	इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड
86	इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड
87	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
88	इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
89	इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ लिमिटेड
90	इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
91	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
92	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड
93	इंडियनऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
94	इंदौर एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड
95	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड
96	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
97	ऑफ सीसीएस एनआईएम का इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फेडरेशन
98	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
99	आईटीसीओटी लिमिटेड
100	जे एंड के इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइज़ेशन लिमिटेड
101	झाबुआ पावर लिमिटेड
102	कामराजर पोर्ट लिमिटेड
103	कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड
104	कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
105	खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड
106	किटको लिमिटेड
107	कोच्चि सलेम पाइपलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
108	कोलकाता पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
109	कृष्णपट्टनम रेल कंपनी लिमिटेड
110	कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड
111	एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज़ लिमिटेड
112	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
113	लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
114	लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

क्रम सं.	सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कंपनियाँ
115	महाराष्ट्र एग्रीकल्चर एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
116	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
117	मीनाचिल रबरवुड लिमिटेड
118	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड
119	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनंस एजेंसी लिमिटेड
120	मिलेनियम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड
121	मोरमुगाओ पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
122	मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
123	मुंबई जेएनपीटी पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
124	एनएबी फाउंडेशन
125	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
126	एनएबीएफआईएनएस लिमिटेड
127	नबकिसान फाइनेंस लिमिटेड
128	नबसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड
129	नबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड
130	नबवैचर्स लिमिटेड
131	नागपुर एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड
132	नालंदा सिरेमिक्स एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
133	नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
134	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ लिमिटेड
135	नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरीज़ प्राइवेट लिमिटेड
136	नेशनल हाईवेज़ इनविट प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
137	नेशनल हाईवेज़ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड
138	नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
139	नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया
140	नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
141	एनईडीएफआई ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
142	एनईडीएफआई वेंचर कैपिटल लिमिटेड
143	एनईएसएल ई-इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
144	एनईएसएल-एसेट डेटा लिमिटेड
145	न्यू एंड ग्रीन एनर्जी ऑफ़ असम लिमिटेड

क्रम सं.	सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कंपनियाँ
146	न्यू मैंगलोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
147	एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड
148	एनआईसीडीसी पंजाब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
149	एनआईसीडीसी उत्तराखंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड
150	एनआईटीसीओएन सोशल फाउंडेशन
151	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
152	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड
153	नॉर्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइज़ेशन लिमिटेड
154	नॉर्थ इंडिया टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइज़ेशन लिमिटेड
155	एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड
156	एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड
157	एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
158	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
159	एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
160	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड
161	ओडिशा इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइज़ेशन लिमिटेड
162	पाम्बा रबर्स लिमिटेड
163	पारादीप पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
164	पझरसी रबर्स (पी) लिमिटेड
165	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड
166	पेट्रोनेट वीके लिमिटेड
167	पिपावव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
168	पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज़ लिमिटेड
169	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
170	पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड
171	पोनमुडी रबर्स (पी) लिमिटेड
172	पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड
173	रामागुंडम फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
174	रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
175	रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ़ राजस्थान लिमिटेड
176	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ़ केरल लिमिटेड

क्रम सं.	सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कंपनियाँ
177	रिज़र्व बैंक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
178	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड
179	आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटीलिमिटेड
180	रबर पार्क इंडिया (पी) लिमिटेड
181	रबरवुड इंडिया (पी) लिमिटेड
182	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
183	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
184	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड
185	एसबीआई सीडीएमडीएफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड
186	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
187	एसबीआई फाउंडेशन
188	एसबीआई फंड्स इंटरनेशनल (आईएफएमसी) लिमिटेड
189	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
190	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
191	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड
192	एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
193	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
194	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
195	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
196	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
197	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
198	एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड
199	एसबीआईकैप ट्रस्टी लिमिटेड
200	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड
201	सुरक्षा एवं वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान संघ
202	सिडबी ट्रस्टीज कंपनी लिमिटेड
203	सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड
204	स्मेरा ग्रेडिंग्स एंड रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
205	स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
206	स्टेट बैंक ऑपरेशंस सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
207	एसटीसीआई कमोडिटीज लिमिटेड

क्रम सं.	सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कंपनियाँ
208	एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड
209	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर्स लिमिटेड
210	सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट लिमिटेड
211	सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड
212	तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड
213	तमिलनाडु दूरसंचार लिमिटेड
214	टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
215	तूतीकोरिन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
216	यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड
217	उज्ज्वला प्लस फाउंडेशन
218	यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
219	यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
220	यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड
221	यूपी इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंट्स लिमिटेड
222	उर्वरक विदेश लिमिटेड
223	यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड
224	उत्कर्ष एल्युमिनियम धातु निगम लिमिटेड
225	वधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड
226	विशाखापत्तनम पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
227	वैगन इंडिया लिमिटेड
228	वेबकोन कंसल्टिंग (इंडिया) लिमिटेड
229	इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

अनुलग्नक- II (पैरा संख्या 1.1.3 देखें)
सीपीएसई जो 2023-24 के दौरान सीएजी ऑडिट के दायरे में आए/बाहर गए
सरकारी कंपनियाँ सीएजी लेखापरीक्षा के क्षेत्र में आईं

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	एआईसी - आईपीआर प्लाज़्माटेक इनोवेशन फाउंडेशन
2	एआईसी आरआरसीएटी पीआई-हब फाउंडेशन
3	एडसिल विद्यांजलि फाउंडेशन
4	गेल मँगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
5	गोला-बी रामगढ़ बी ट्रांसमिशन लिमिटेड
6	आईओएसआई ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड
7	जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
8	जोडा बारबिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
9	कल्लम ट्रांस्को लिमिटेड
10	कांकाणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
11	खावड़ा IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
12	खावड़ा IV ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
13	खावड़ा IV-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड
14	खावड़ा पीएस1 एवं 3 ट्रांसमिशन लिमिटेड
15	खावड़ा V ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
16	मसकानी पारादीप रोड विकास लिमिटेड
17	एनईआरजीएस-आई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
18	एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
19	एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड
20	ओवीएल ओवरसीज आईएफएससी लिमिटेड
21	पारादीप ट्रांसमिशन लिमिटेड
22	पावरग्रिड बीकानेर नीमराना ट्रांसमिशन लिमिटेड
23	पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड
24	पावरग्रिड मेवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
25	पावरग्रिड नीमराना बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड
26	पावरग्रिड वतामान ट्रांसमिशन लिमिटेड
27	राजस्थान IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
28	राजस्थान IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
29	राजस्थान IV एच1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
30	राजस्थान पार्ट I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
31	रामकनाली बी-पानागढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
32	शौंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
33	टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड
34	तुमकुर-II आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

सीएजी लेखापरीक्षा के क्षेत्र में आने वाले सांविधिक निगम

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कंपनियाँ जो सीएजी की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में आईं

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	एपिटको फाउंडेशन
2	चेन्नई एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड
3	इंडियनऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
4	इंदौर एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड
5	एनआईएएम इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फेडरेशन ऑफ एम
6	नागपुर एमएमएलपी प्राइवेट लिमिटेड
7	एसबीआई सीडीएमडीएफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड

वे सरकारी कंपनियाँ सीएजी ऑडिट के दायरे से बाहर हुईं

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड
2	ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
3	बिजावर विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड
4	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड
5	ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड
6	फतेहगढ़-III ब्यावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
7	फतेहगढ़-III ट्रांसमिशन लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
8	फतेहगढ़-IV ट्रांसमिशन लिमिटेड
9	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड
10	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड
11	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
12	केपीएस I ट्रांसमिशन लिमिटेड
13	एनबीसीसी पर्यावरण इंजीनियरिंग लिमिटेड
14	एनबीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड
15	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड
16	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड
17	स्मिथ स्टैनिसट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
18	वेइबर्ड (इंडिया) लिमिटेड

सरकार के नियंत्रण वाली दूसरी कंपनियाँ जो सीएजी ऑडिट के दायरे से बाहर हुई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड

अनुलग्नक- III क (पैरा संख्या 1.1.3 एवं पैरा संख्या 2.3.2 देखें)
बकाया लेखे, अदेय लेखे अथवा परिसमापनाधीन कंपनियों का विवरण
सरकारी कंपनियाँ

क्रम सं.	क्षेत्र/सीपीएसई का नाम	31 दिसंबर 2024 तक जिन वर्षों के लेखे प्राप्त नहीं हुए
कृषि		
1	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड	2023-24
जैव प्रौद्योगिकी		
2	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2023-24
रसायन एवं उर्वरक		
3**	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड	परिसमापनाधीन
4**	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	2020-21 से 2023-24
5**	आईडीपीएल तमिलनाडु (प्राइवेट) लिमिटेड	2011-12 से 2023-24
6**	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	2019-20 से 2023-24
7	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	2023-24
8	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	2023-24
9**	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
10	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	2023-24
11**	दक्षिणी कीटनाशक निगम लिमिटेड	परिसमापनाधीन
नागरिक उड्डयन		
12	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2023-24
13	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	2023-24
14	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	2023-24
15	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2023-24
16	पवन हंस लिमिटेड	2023-24
17	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड	2023-24
वाणिज्य एवं उद्योग		
18	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्रीबिशन सेंटर लिमिटेड	2023-24
19**	नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इन्फॉर्मेशन	परिसमापनाधीन
20**	टी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
21	द केरल इंडस्ट्रियल कॉरीडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2023-24

क्रम सं.	क्षेत्र/सीपीएसई का नाम	31 दिसंबर 2024 तक जिन वर्षों के लेखे प्राप्त नहीं हुए
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण		
22**	हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22 से 2023-24
वित्त		
23**	इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
24**	पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड	प्रथम लेखे देय नहीं
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
25	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड	2023-24
भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम		
26**	भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
27**	भारत ऑप्टिकल ग्लास लिमिटेड	परिसमापनाधीन
28**	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
29**	भारत यंत्र निगम लिमिटेड	परिसमापनाधीन
30**	साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
31**	हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
32**	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मेनुफेक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड	परिसमापनाधीन
33**	मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
34**	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
35**	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड	परिसमापनाधीन
36**	पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड	परिसमापनाधीन
37**	रेरोल बर्न लिमिटेड	परिसमापनाधीन
38**	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	तरलता के तहत
39**	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
आवास एवं शहरी मामले		
40	चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2023-24
41**	गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड	प्रथम लेखे देय नहीं
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस		
42**	एचपीसीएल रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	प्रथम लेखे देय नहीं
43**	ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड	प्रथम लेखे देय नहीं
विद्युत		
44**	अंगुल सुंदरगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रथम लेखे देय नहीं

क्रम सं.	क्षेत्र/सीपीएसई का नाम	31 दिसंबर 2024 तक जिन वर्षों के लेखे प्राप्त नहीं हुए
45**	भुज II ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रथम लेखे देय नहीं
46**	ईआरईएस-XXXIX पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रथम लेखे देय नहीं
47**	गैस एवं पावर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	2020-21 से 2023-24
48**	जामनगर ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रथम लेखे देय नहीं
49	खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड	2023-24
50**	पावरग्रिड बाड़मेर I ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रथम लेखे देय नहीं
51**	पावरग्रिड ब्यावर - मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रथम लेखे देय नहीं
52**	पावरग्रिड भड़ला बीकानेर ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रथम लेखे देय नहीं
53**	पावरग्रिड सिरोही ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रथम लेखे देय नहीं
54**	पावरग्रिड साउथ ओलपाड ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रथम लेखे देय नहीं
55**	पुणे III ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रथम लेखे देय नहीं
रेलवे		
56**	ब्रेथवेट एनएसीओएफ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड	पहले खाते प्राप्त नहीं हुए
57**	आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड	प्रथम लेखे देय नहीं
वस्त्र		
58	अपोलो डिज़ाइन अपैरल पार्क्स लिमिटेड	2022-23, 2023-24
59	औरंगाबाद टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	2022-23, 2023-24
60**	ब्रशवेयर लिमिटेड	परिसमापनाधीन
61**	कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
62	गोल्डमोहर डिज़ाइन एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	2022-23, 2023-24
63	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	2022-23, 2023-24
64	राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड	2022-23, 2023-24
65	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड	2022-23, 2023-24
66	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23, 2023-24
67**	एल्लिगन मिल्स कंपनी लिमिटेड	परिसमापनाधीन
68	द हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2022-23, 2023-24
पर्यटन		
69**	लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21 से 2023-24
केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन		
70**	चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम लिमिटेड	2020-21 से 2023-24

क्रम सं.	क्षेत्र/सीपीएसई का नाम	31 दिसंबर 2024 तक जिन वर्षों के लेखे प्राप्त नहीं हुए
71	चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2023-24
72**	चंडीगढ़ अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2020-21 से 2023-24
शहरी विकास		
73**	पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड	2020-21 से 2023-24
74**	सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22 से 2023-24
75	कवरत्ती स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23, 2023-24
76	नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2022-23, 2023-24
जल संसाधन		
77	वाप्कोस लिमिटेड	2023-24

**वे सीपीएसई जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि से लंबित थे अथवा जो परिसमापनाधीन थे, या जिनके प्रथम लेखे देय नहीं थे/प्राप्त नहीं हुए थे।"

अनुलग्नक- III ख (पैरा संख्या 1.1.3 एवं पैरा संख्या 2.3.2 देखें)
बकाया लेखाओं अथवा परिसमापनाधीन कंपनियों का विवरण
ख. सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	31 दिसंबर 2024 तक जिन वर्षों के लेखे प्राप्त नहीं हुए
1**	एक्यूमेज़र्स (पंजाब) लिमिटेड	परिसमापनाधीन
2	अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे कंपनी लिमिटेड	2023-24
3	एआईसी-आरआरयू इनक्यूबेशन फाउंडेशन	2023-24
4**	एलाइड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
5**	बिहार इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइज़ेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
6**	एक्सेलसियर प्लांट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
7**	गंगावती शुगर्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
8**	इंडबैंक ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	प्रथम लेखे देय नहीं
9**	इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड	परिसमापनाधीन
10**	लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	2021-22 से 2023-24
11**	मिलेनियम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
12**	नालंदा सिरेमिक्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	परिसमापनाधीन
13**	न्यू एंड ग्रीन एनर्जी ऑफ असम लिमिटेड	प्रथम लेखे देय नहीं
14	एनआईसीडीसी पंजाब इंडस्ट्रियल कॉरीडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2023-24
15**	एनआईसीडीसी उत्तराखंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड	प्रथम लेखे 2022-23 से देय
16**	नॉर्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइज़ेशन लिमिटेड	2012-13 से 2023-24
17**	ओडिशा इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइज़ेशन लिमिटेड	1997-98 से 2023-24
18**	पजहस्सी रबर्स (पी) लिमिटेड	परिसमापनाधीन
19**	पोनमुडी रबर्स (पी) लिमिटेड	2017-18 से 2023-24
20**	रबरवुड इंडिया (पी) लिमिटेड	परिसमापनाधीन
21**	एसबीआई फंड्स इंटरनेशनल (आईएफएससी) लिमिटेड	प्रथम लेखे देय नहीं
22**	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	परिसमापनाधीन
23**	एसटीसीआई कमोडिटीज लिमिटेड	परिसमापनाधीन
24**	सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड	परिसमापनाधीन

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	31 दिसंबर 2024 तक जिन वर्षों के लेखे प्राप्त नहीं हुए
25**	टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
26**	यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड	परिसमापनाधीन
27	यूपी इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंट्स लिमिटेड	2023-24
28**	वैगन इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
29	वेबकोन कंसल्टिंग (इंडिया) लिमिटेड	2022-23, 2023-24

** ऐसे सीपीएसई जिनके तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि से लंबित लेखों वाले, परिसमापनाधीन अथवा जिनके प्रथम लेखे देय नहीं थे/प्रथम लेखों से ही लंबित थे।

अनुलग्नक- IV (पैरा संख्या 1.2.2.2 देखें)
उन सरकारी कंपनियों की सूची जिनकी योग परिसंपत्तियों का मूल्य 31 मार्च, 2024 को बकाया दीर्घकालिक ऋणों से कम था

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	अंडमान फिशरीज लिमिटेड
2	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड
3	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड
4	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
6	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
7	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
8	इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड
9	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
10	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
11	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
12	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
13	नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14	नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स क्रिएटिव कॉर्पोरेशन लिमिटेड
15	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड
16	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
17	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड
18	टीसीआईएल लखनादौन टोल रोड लिमिटेड
19	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अनुलग्नक-V (पैरा संख्या 1.2.4 देखें)
66 सूचीबद्ध सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि एवं कमी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	बाजार पूँजीकरण 2023-24	बाजार पूँजीकरण 2022-23	अंतर
1	एनटीपीसी लिमिटेड	3,25,760	1,69,934	1,55,826
2	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	1,86,096	34,762	1,51,334
3	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	3,36,963	1,89,962	1,47,001
4	कोल इंडिया लिमिटेड	2,67,308	1,31,667	1,35,641
5	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	2,22,518	1,296 9	1,31,222
6	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,36,884	1,10,061	1,26,823
7	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2,57,673	1,57,436	1,00,237
8	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,28,770	40,063	88,707
9	आरईसी लिमिटेड	1,18,706	30,401	88,305
10	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1,47,255	71,307	75,948
11	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	86,077	24,420	61,657
12	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,30,654	74,633	56,021
13	गेल (इंडिया) लिमिटेड	1,19,108	69,203	49,905
14	एनएचपीसी लिमिटेड	90,034	40,381	49,653
15	रेल विकास निगम लिमिटेड	52,741	14,303	38,438
16	ऑयल इंडिया लिमिटेड	65,075	27,289	37,786
17	एसजेवीएन लिमिटेड	47,708	13,067	34,641
18	भारतीय सामान्य बीमा निगम	57,886	23,500	34,386
19	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	67,495	33,591	33,904
20	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	38,329	9,215	29,114
21	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	37,496	8,676	28,820
22	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	74,396	45,840	28,556
23	द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	40,623	13,281	27,342
24	एनएमडीसी लिमिटेड	59,110	32,706	26,404
25	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	37,532	13,379	24,153

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	बाजार पूँजीकरण 2023-24	बाजार पूँजीकरण 2022-23	अंतर
26	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	37,500	15,986	21,514
27	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	55,410	34,275	21,135
28	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	31,622	10,703	20,919
29	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	53,752	35,388	18,364
30	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	26,903	9,519	17,384
31	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	22,934	6,259	16,675
32	आईटीआई लिमिटेड	24,301	8,553	15,748
33	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	20,588	5,267	15,321
34	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	21,429	6,370	15,059
35	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	32,098	18,122	13,976
36	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	27,999	14,410	13,589
37	केआईओसीएल लिमिटेड	23,657	10,247	13,410
38	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13,501	3,543	9,958
39	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	11,673	3,245	8,428
40	बीईएमएल लिमिटेड	13,258	5,233	8,025
41	आईएफसीआई लिमिटेड	9,884	2,159	7,725
42	राइट्स लिमिटेड	15,963	8,522	7,441
43	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	11,350	4,182	7,168
44	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	16,036	9,102	6,934
45	एमटीटीसी लिमिटेड	9,962	4,185	5,777
46	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	9,724	4,379	5,345
47	एमएसटीसी लिमिटेड	5,851	1,780	4,071
48	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	7,377	3,455	3,922
49	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	8,764	5,217	3,547
50	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	5,694	2,349	3,345
51	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	5,417	2,531	2,886
52	मॉयल लिमिटेड	5,662	2,900	2,762
53	एचएमटी लिमिटेड	5,196	2,939	2,257
54	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	4,083	1,895	2,188

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	बाजार पूँजीकरण 2023-24	बाजार पूँजीकरण 2022-23	अंतर
55	उड़ीसा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड	3,548	1,426	2,122
56	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	7,070	5,261	1,809
57	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2,074	1,128	946
58	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	4,298	3,554	744
59	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	1,701	989	712
60	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	1,357	787	570
61	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1,304	929	375
62	भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड	745	410	335
63	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	436	231	205
64	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	264	150	114
65	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	122	96	26
66	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	32	17	15

अनुलग्नक- VI (पैरा संख्या 1.3.1 देखें)

2023-24 के दौरान लाभ कमाने वाली सरकारी कंपनियों एवं निगमों की सूची, जिन्हें 2022-23 में घाटे में रहने वाली कंपनियों की तुलना में लाभ कमाने वाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	क्या वर्ष 2023-24 में लाभ अर्जित करने का कारण परिचालन लाभ था
1	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	नहीं
2	एआईसी आरआरसीएटी पीआई-हब फाउंडेशन	हाँ
3	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	नहीं
4	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	हाँ
5	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	नहीं
6	भारत पेट्रो रिसोर्स जेपीडीए लिमिटेड	नहीं
7	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड	हाँ
8	कॉनकॉर एयर लिमिटेड	नहीं
9	भारतीय कपास निगम लिमिटेड	हाँ
10	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	नहीं
11	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	नहीं
12	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	हाँ
13	गेल मंगलौर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	हाँ
14	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	नहीं
15	एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड	नहीं
16	हसन मैंगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड	हाँ
17	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
18	आईएफसीआई लिमिटेड	हाँ
19	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	हाँ
20	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	हाँ
21	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	नहीं
22	पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ
23	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	नहीं
24	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	नहीं
25	एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	नहीं
26	उड़ीसा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड	नहीं
27	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	नहीं

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	क्या वर्ष 2023-24 में लाभ अर्जित करने का कारण परिचालन लाभ था
28	पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	हाँ
29	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	हाँ
30	पावरग्रिड मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ
31	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	हाँ
32	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	हाँ
33	पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ
34	पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ
35	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	हाँ
36	एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	हाँ
37	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	नहीं
38	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ

* क्रमांक 2 एवं 13 पर स्थित दो कंपनियां नई थीं एवं उन्होंने 2023-24 के दौरान अपने संचालन के पहले वर्ष में लाभ दर्ज किया।

अनुलग्नक-VII (पैरा संख्या 1.3.1 देखें)
2023-24 में लाभ कमाने वाली कंपनियों की सूची से बाहर रखी गई सरकारी कंपनियों की सूची

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या 2023-24 में नुकसान का कारण परिचालन हानि है
1	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	हाँ
2	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	नहीं
3	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	शून्य लाभ
4	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	शून्य लाभ
5	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	हाँ
6	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	शून्य लाभ
7	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	हाँ
8	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	हाँ
9	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
10	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	शून्य लाभ
11	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड	हाँ
12	पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	नहीं
13	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	हाँ
14	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	शून्य लाभ
15	ड्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड	हाँ

अनुलग्नक- VIII (पैरा संख्या 1.3.3.1 देखें)

31 मार्च 2024 तक शून्य या ऋणात्मक निवल संपत्ति वाली सरकारी कंपनियों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	कर के बाद लाभ	निवल मूल्य	प्रदत्त पूंजी
1	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	628.47	-790.02	166.67
2	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	-566.57	-3,664.32	402.25
3	अंडमान मत्स्य पालन लिमिटेड	-8.47	-63.53	1.00
4	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड	-72.02	-2,116.03	51.06
5	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए लिमिटेड	1.51	-55.18	60.00
6	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड	-46.64	-150.63	53.53
7	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.02	-0.08	0.05
8	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	-0.05	0.00	0.05
9	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	-3.83	-155.08	0.39
10	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8.71	-315.83	365.83
11	केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड	-13.67	-95.02	10.85
12	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.01	-0.01	0.05
13	चेय्युर इंफ्रा लिमिटेड	-0.05	0.00	0.05
14	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	0.00	-0.01	0.05
15	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	-0.34	-0.38	0.05
16	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	-0.05	0.00	0.05
17	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.10	-0.01	0.05
18	एडसिल विद्यांजलि फाउंडेशन	-0.18	-0.13	0.05
19	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-11.07	-27.23	25.00
20	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-275.19	-1,361.59	606.08
21	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	-36.13	-713.46	71.72
22	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	1.23	-82.70	19.61
23	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	-10.87	-9.92	134.77
24	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	118.12	-351.27	301.99
25	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	-155.24	-1,972.03	276.60
26	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-70.38	-682.42	137.60
27	अंतर्देशीय एवं तटीय शिपिंग लिमिटेड	-0.97	-1.84	1.05

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	कर के बाद लाभ	निवल मूल्य	प्रदत्त पूंजी
28	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	7.01	-360.41	146.05
29	जम्मू एवं कश्मीर खनिज विकास निगम लिमिटेड	-12.84	-6.25	29.74
30	जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.86	-0.81	0.05
31	झारखंड राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड	-0.01	-0.10	0.01
32	कल्लम ट्रांस्को लिमिटेड	-0.52	-0.47	0.05
33	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	-0.58	-3.18	0.10
34	खावड़ा IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.55	-0.50	0.05
35	खावड़ा IV ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.34	-0.29	0.05
36	खावड़ा IV-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.42	-0.37	0.05
37	खावड़ा V ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.43	-0.38	0.05
38	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.28	-0.01	0.05
39	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.59	-1.05	0.05
40	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	5.55	-189.72	162.14
41	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-0.04	-6.06	0.05
42	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-3,302.19	-23,662.80	630.00
43	महाराष्ट्र एंटीबायोटेक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-122.05	-879.56	1.24
44	एमएमसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-0.10	-1.86	0.05
45	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.88	-0.01	0.05
46	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-42.91	-513.90	0.85
47	मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.56	-0.95	0.05
48	नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड	-3.07	-2.14	65.00
49	भारतीय राष्ट्रीय साइकिल निगम लिमिटेड	-21.63	-714.20	5.65
50	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-186.90	-995.42	9,375.00
51	नेशनल जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड	62.15	-135.31	55.80
52	नेपा लिमिटेड	-126.76	-112.84	724.33
53	एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.92	-0.87	0.05
54	एनईआरजीएस-I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.36	-0.31	0.05
55	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	0.86	-41.38	8.50
56	एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	-0.03	-3.35	0.20

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	कर के बाद लाभ	निवल मूल्य	प्रदत्त पूंजी
57	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	-0.05	0.00	0.05
58	ओएनजीसी पेट्रो एडिंशंस लिमिटेड	-3,456.10	-2,698.11	2,021.93
59	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	0.00	-0.07	0.05
60	पीईसी लिमिटेड	-339.59	-2,835.75	60.00
61	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.31	-1.09	1.60
62	पावरग्रिड भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.27	-0.26	0.01
63	पावरग्रिड मेवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.39	-0.34	0.05
64	पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.18	-0.51	0.05
65	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.01	-19.44	0.05
66	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-1.06	-102.46	4.99
67	राजस्थान IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.41	-0.36	0.05
68	राजस्थान IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.34	-0.29	0.05
69	राजस्थान IV एच1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.52	-0.47	0.05
70	राजस्थान पार्ट I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.67	-0.62	0.05
71	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-1.38	-18.05	4.90
72	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	-4,848.86	-4,538.29	4,889.85
73	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	16.83	-2.41	1.00
74	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-31.14	-22.29	87.27
75	शौंगटोंग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.57	-0.52	0.05
76	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.18	-0.49	0.05
77	एसटीसीएल लिमिटेड	-1.13	-4,559.38	1.50
78	सूटी टेक ऑप्शंस लिमिटेड	-0.01	-0.34	0.50
79	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	-2.79	-45.98	19.57
80	टीसीआईएल लखनादौन टोल रोड लिमिटेड	-0.6 3	-0.88	23.11
81	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	2.29	-129.45	87.29
82	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-79.05	-1,304.44	31.71
83	औद्योगिक ऋण कंपनी लिमिटेड	-0.02	-0.08	0.05
84	उड़ीसा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड	2.82	-10.74	0.60
85	भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड	52.21	-73.88	60.00
86	तुमकुर-II आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.20	-0.15	0.05

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	कर के बाद लाभ	निवल मूल्य	प्रदत्त पूंजी
87	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	45.47	0.00	8.44
88	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-803.71	-1,535.20	3,905.00
89	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-1.09	-29.45	1.30
90	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	-0.01	-0.09	0.05
91	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	-0.01	-0.05	0.05
	योग	-13,706.22	-58,175.15	25,103.08

अनुलग्नक-IX
(पैरा संख्या 1.3.3.2 देखें)

31 मार्च 2024 तक शून्य या ऋणात्मक निवल मूल्य वाली सरकार-नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची।

(₹ लाख में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	कर के बाद लाभ	निवल मूल्य	प्रदत्त पूंजी
1	बिंको लॉरी लिमिटेड	13.32	-11,675.05	7,476.32
2	देवघर एयरपोर्ट लिमिटेड	-1,420.64	-922.39	500
3	एफएसीटी आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-263.24	-14,907.21	7,045.4
4	इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड	-69.06	-12,056.72	1,000
5	सीसीएस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फेडरेशन	-0.55	-0.54	0.01
6	जे एंड के औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	75.16	-48.47	20
7	कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड	-0.75	-26.6	5
8	मीनाचिल रबरवुड लिमिटेड	-6.95	-633.05	182.03
9	एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	-449.19	-22,329.75	10,000
10	पंजा रबर्स लिमिटेड	-24.79	-644.2	118.91
11	पेट्रोनेट वीके लिमिटेड	-1,254.83	-14,236.27	10,000
12	आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी लिमिटेड	-0.52	-138.94	800
13	तमिलनाडु दूरसंचार लिमिटेड	-1,461.88	-16,356.4	4,567.62
	योग	-4,863.92	-93,975.59	41,715.29

अनुलग्नक-X
(पैरा संख्या 1.4.1 देखें)
सरकारी कंपनियों एवं निगमों की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
1	एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड	2,573.47	6.16	0.24	5,290.35	18.59	0.35	7,458.71	29.79	0.40
2	एग्रोनोवेटिव इंडिया लिमिटेड	72.61	2.06	2.84	76.12	4.71	6.19	80.86	6.34	7.84
3	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	361.65	-1.94	-0.54	423.07	96.91	22.91	423.07	96.91	22.91
4	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	8,718.88	1,974.15	22.64	14,915.35	906.21	6.08	16,000.06	1,217.72	7.61
5	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	776.78	575.28	74.06	-790.02	1,036.02	-131.14	-790.02	1,036.02	-131.14
6	एआईसी - आईपीआर प्लाज़्माटेक इनोवेशन फाउंडेशन							0.01	-0.01	-100.00
7	एआईसी आरआरसीएटी पीआई-हब फाउंडेशन							0.08	0.09	112.50
8	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	15,379.24	97.16	0.63	18,147.67	4,060.98	22.38	21,297.90	6,310.06	29.63
9	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	-3,098.55	-262.71	8.48	-3,664.32	-324.28	8.85	-3,664.32	-324.28	8.85
10	अनंतपुरम कुरुनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	79.23	1.28	1.62

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
11	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड	209.14	32.77	15.67	233.55	46.51	19.91	266.86	44.42	16.65
12	अंडमान मत्स्य पालन लिमिटेड	-0.09	-0.02	22.22	-0.11	-0.02	18.18	-0.13	-0.02	15.38
13	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	189.97	17.02	8.96	192.47	16.68	8.67	128.00	-61.91	-48.37
14	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,513.87	36.24	2.39	1,486.72	65.13	4.38	1,475.24	84.49	5.73
15	अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01-	0.00
16	अपोलो डिजाइन अपैरल पार्क्स लिमिटेड	38.73	-80.80	-208.62	38.73	-80.80	-208.62	38.73	-80.80	-208.62
17	आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड	12,302.08	73.65	0.60	13,289.17	383.57	2.89	14,197.58	817.13	5.76
18	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	599.26	64.15	10.70	671.56	72.93	10.86	742.28	71.73	9.66
19	औरंगाबाद टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	12.55	-0.74	-5.90	12.55	-0.74	-5.90	12.55	-0.74	-5.90
20	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	1,319.86	171.98	13.03	1,356.25	211.30	15.58	1,427.22	278.65	19.52
21	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	159.96	67.80	42.39	156.25	75.16	48.10	168.62	87.81	52.08
22	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	34,849.28	-519.32	-1.49	38,503.19	-314.27	-0.82	45,665.25	-110.08	-0.24
23	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	293.71	-1.18	-0.40	292.79	-1.24	-0.42	293.93	1.54	0.52

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
24	बीईएल ऑप्टिकल डिवाइसेज लिमिटेड	244.32	7.91	3.24	271.21	9.14	3.37	286.02	23.36	8.17
25	बीईएल-थल्स सिस्टम्स लिमिटेड	62.85	5.60	8.91	68.29	8.97	13.14	68.93	4.66	6.76
26	बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड	0.00	-0.01	0.00	8.58	-0.59	-6.88	4.86	-3.16	-65.02
27	बीईएमएल लिमिटेड	2,280.73	233.90	10.26	2,394.09	323.91	13.53	2,641.77	420.83	15.93
28	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	76.96	9.24	12.01	163.74	11.17	6.82	181.65	21.43	11.80
29	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड	250.31	-5.78	-2.31	633.92	-15.11	-2.38	871.40	-0.45	-0.05
30	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	84.92	-2.49	-2.93	85.02	0.13	0.15	87.16	2.97	3.41
31	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	3,273.77	191.31	5.84	3,784.13	502.88	13.29	5,321.72	2,091.67	39.30
32	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	3,030.56	709.91	23.43	3,211.50	481.80	15.00	3,636.82	828.24	22.77
33	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	11,984.26	3,157.80	26.35	13,581.99	3,984.88	29.34	16,035.70	5,334.56	33.27
34	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड	-123.04	1.02	-0.83	11.52	8.44	73.26	20.10	4.29	21.34
35	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	26,971.16	484.34	1.80	27,226.98	747.60	2.75	24,815.41	815.38	3.29
36	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	50.18	-4.59	-9.15	47.86	-15.22	-31.80	47.86	-15.22	-31.80
37	भारत पेट्रो रिसोर्सज जेपीडीए लिमिटेड	-1.97	-0.31	15.74	-2.14	-0.16	7.48	-55.18	1.51	-2.74
38	भारत पेट्रो रिसोर्सज लिमिटेड	5,582.33	131.14	2.35	3,794.79	-2,216.93	-58.42	2,599.42	-2,049.53	-78.85

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
39	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	63,837.42	12,176.00	19.07	80,459.90	4,419.38	5.49	86,220.18	37,891.12	43.95
40	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड	-90.42	-46.84	51.80	7.60	27.05	355.92	-39.04	-13.27	33.99
41	भारत संचार निगम लिमिटेड	34,441.88	-4,825.16	-14.01	47,477.65	-5,994.85	-12.63	1,13,609.23	-3,982.17	-3.51
42	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	5,869.04	0.24	0.00	6,064.02	0.10	0.00	6,238.99	3.59	0.06
43	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	7,681.85	820.15	10.68	7,741.27	736.72	9.52	7,668.41	974.88	12.71
44	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.07	-0.01	-14.29	-0.10	-0.11	110.00	-0.08	-0.01	12.50
45	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.06	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
46	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	50.27	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
47	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद	130.13	9.00	6.92	139.17	9.06	6.51	141.82	1.77	1.25
48	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	-12.16	-0.60	4.93	-9.74	1.63	-16.74	-8.01	1.91	-23.85
49	बीपीसीएल- केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड	5.32	-2.90	-54.51	6.32	1.98	31.33	7.95	1.06	13.33
50	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	3,390.03	994.53	29.34	3,386.36	194.36	5.74	3,609.36	-173.79	-4.81
51	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	223.83	-97.64	-43.62	248.21	24.47	9.86	256.92	9.37	3.65
52	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	150.55	46.70	31.02	200.32	64.94	32.42	216.75	23.32	10.76

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
53	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	395.84	62.99	15.91	429.06	67.11	15.64	490.51	107.42	21.90
54	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	111.85	25.86	23.12	114.57	19.08	16.65	95.90	28.83	30.06
55	बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-2.79	-0.01	0.36	-2.60	0.26	-10.00	0.62	4.50	725.81
56	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	155.03	-0.88	-0.57	227.03	5.57	2.45	302.75	8.69	2.87
57	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	162.34	40.20	24.76	258.78	95.29	36.82	352.74	95.05	26.95
58	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	8,411.98	2,094.73	24.90	10,317.49	3,743.61	36.28	13,585.15	4,726.42	34.79
59	केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड	-68.66	-23.96	34.90	-81.06	-12.60	15.54	-95.02	-13.25	13.94
60	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	122.34	36.62	29.93	134.77	26.27	19.49	203.84	79.10	38.80
61	केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड	995.62	366.04	36.77	1,217.65	366.95	30.14	1,591.61	732.84	46.04
62	भारत के प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री	935.51	88.66	9.48	1,154.75	118.01	10.22	1,277.94	167.00	13.07
63	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	40.05	53.49	133.56	26.16	68.49	261.81	54.92	92.18	167.84
64	केंद्रीय भंडारण निगम	3,088.15	589.73	19.10	3,453.10	490.95	14.22	3,342.11	590.36	17.66
65	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	79.30	11.25	14.19	81.44	13.22	16.23	84.47	17.05	20.18

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
66	चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	60.82	0.84	1.38	63.97	9.88	15.44	63.97	9.88	15.44
67	चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	203.44	1.78	0.87	202.49	-26.53	-13.10	202.49	-26.53	-13.10
68	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-2.15	0.00	0.00	-2.55	-0.01	0.39	-0.01	-0.01	100.00
69	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड	19,635.79	-539.73	-2.75	21,260.80	-367.86	-1.73	26,938.60	718.04	2.67
70	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,181.69	2,244.08	43.31	8,588.97	5,138.88	59.83	9,927.57	3,878.46	39.07
71	चेय्युर इंफ्रा लिमिटेड	0.09	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
72	छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
73	छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड	0.05	-0.10	-200.00	0.08	-0.06	-75.00	0.04	-0.03	-75.00
74	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	3,084.81	5.98	0.19	3,292.24	-227.09	-6.90	3,349.72	-250.76	-7.49
75	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	1,500.41	-0.28	-0.02	2,130.15	-0.24	-0.01	3,288.06	-0.22	-0.01
76	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
77	सीआईएल नवकारणीय ऊर्जा लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
78	सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.04	-0.01	-25.00
79	कोल इंडिया लिमिटेड	16,357.95	11,358.34	69.44	16,706.45	15,093.51	90.35	17,325.73	16,042.12	92.59
80	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	-0.01	-0.01	100.00	-0.04	-0.03	75.00	-0.38	-0.34	89.47
81	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	157.58	0.00	0.00	166.66	0.00	0.00	177.51	0.00	0.00

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
82	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	4,462.86	794.39	17.80	4,427.12	459.02	10.37	5,046.26	1,117.95	22.15
83	कॉनकार एयर लिमिटेड	24.24	-9.21	-38.00	23.13	3.19	13.79	26.26	3.13	11.92
84	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10,777.30	1,407.02	13.06	11,244.98	1,553.73	13.82	11,812.34	1,634.48	13.84
85	क्रिएटिव संग्रहालय डिजाइनर	10.19	4.16	40.82	28.64	5.72	19.97	33.74	5.81	17.22
86	दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव एससी/एसटी वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	15.16	4.47	29.49	15.81	0.64	4.05	17.38	1.57	9.03
87	दामोदर घाटी निगम	23,413.91	2,552.13	10.90	23,401.41	2,628.00	11.23	26,098.26	3,068.70	11.76
88	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	48,416.84	1,521.39	3.14	54,323.03	2,263.05	4.17	61,005.03	3,015.00	4.94
89	दिल्ली मेट्रो लास्ट माइल सर्विसेज लिमिटेड	0.07	-0.01	-14.29	0.06	-0.01	-16.67	0.06	0.00	0.00
90	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	67,461.06	-4,288.10	-6.36	67,648.57	-1,734.30	-2.56	56,971.69	-1,359.03	-2.39
91	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12.98	0.22	1.69	13.79	1.08	7.83	17.92	5.56	31.03
92	देवघर इंधन लिमिटेड	0.40	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
93	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	23.85	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
94	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन	33.35	1.43	4.29	45.78	2.13	4.65	82.07	11.76	14.33
95	दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2.02	0.03	1.49	0.54	0.41	75.93	2.95	2.42	82.03
96	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	877.43	118.45	13.50	681.12	64.35	9.45	760.69	109.19	14.35

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
97	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	-2.10	0.00	0.00	-2.48	-0.01	0.40	-0.01	2.10	-21,000
98	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,971.93	-1,437.37	-72.89	2,707.60	806.58	29.79	3,135.63	288.01	9.19
99	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	269.99	0.27	0.10	266.41	-4.81	-1.81	266.43	-0.08	-0.03
100	ईसीजीसी लिमिटेड	15,375.28	1,131.02	7.36	11,386.60	2,761.06	24.25	14,064.91	2,859.27	20.33
101	एडसिल (इंडिया) लिमिटेड	211.79	71.33	33.68	260.12	86.94	33.42	339.79	136.91	40.29
102	एडसिल विद्युतजालि फाउंडेशन							-0.13	-0.18	138.46
103	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,255.73	301.66	24.02	1,433.07	357.91	24.98	1,820.75	709.14	38.95
104	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	83.46	-59.83	-71.69	83.90	5.45	6.50	22.56	-62.66	-277.75
105	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	1,925.05	447.84	23.26	2,105.66	441.48	20.97	2,311.28	470.41	20.35
106	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	212.00	54.18	25.56	218.53	51.35	23.50	257.41	88.21	34.27
107	भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड	666.50	42.97	6.45	712.75	58.78	8.25	750.03	50.90	6.79
108	भारतीय खाद्य निगम	45,004.55	3,715.06	8.25	46,658.86	3,678.23	7.88	46,836.12	3,267.43	6.98
109	फ़ेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	33.29	-3.73	-11.20	38.92	-2.57	6.60	39.55	0.63	1.59
110	गेल (इंडिया) लिमिटेड	60,416.88	13,895.52	23.00	63,213.72	6,895.53	10.91	77,692.48	12,395.68	15.95
111	गेल गैस लिमिटेड	3,065.96	416.42	13.58	3,840.02	423.84	11.04	4,332.29	510.53	11.78
112	गेल मँगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड							2,189.00	355.02	16.22
113	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	1,248.60	257.24	20.60	1,413.82	309.54	21.89	1,673.44	492.41	29.43

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
114	जनरल इश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,39,087.47	3,560.14	2.56	1,50,108.59	7,749.44	5.16	1,72,959.48	8,465.42	4.89
115	घोसरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	15.01	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
116	ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड	529.96	0.96	0.18	651.85	11.39	1.75	653.28	14.21	2.18
117	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-10.06	-5.69	56.56	-16.64	-4.81	28.91	-26.01	-9.85	37.87
118	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	1,148.40	135.43	11.79	1,246.43	205.01	16.45	1,437.46	364.63	25.37
119	गोला-बी रामगढ़ बी ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.01	0.00	0.00
120	गोल्डमोहर डिज़ाइन एंड अपैरल पाकर्स लिमिटेड	27.72	-85.12	-307.07	27.72	-85.12	-307.07	27.72	-85.12	-307.07
121	माल एवं सेवा कर नेटवर्क	81.66	29.08	35.61	13.08	-79.05	-604.36	13.08	0.00	0.00
122	सरकारी ई-मार्केट प्लेस	98.83	140.24	141.90	551.18	384.96	69.84	1,217.99	891.62	73.20
123	ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड				0.12	0.03	25.00	0.14	0.03	21.43
124	ग्रिड नियंत्रण ऑफ इंडिया लिमिटेड	508.19	60.13	11.83	561.83	78.49	13.97	636.41	108.52	17.05
125	हसन मँगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड	307.60	-34.79	-11.31	276.77	-25.89	-9.35	288.39	18.35	6.36
126	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-844.07	-245.31	29.06	-952.34	-188.28	19.77	-1,222.51	-229.50	18.77
127	हेमिस्फेर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	440.25	-12.82	-2.91	430.86	-1.33	-0.31	418.35	-5.87	-1.40

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
128	हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	46.71	2.50	5.35	50.02	4.43	8.86	57.06	9.46	16.58
129	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी	7,861.84	551.06	7.01	6,976.53	397.90	5.70	7,796.35	348.85	4.47
130	एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड	185.02	28.50	15.40	132.74	-42.19	-31.78	457.97	16.67	3.64
131	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	19,264.00	5,289.29	27.46	23,506.17	6,492.94	27.62	29,046.42	10,199.05	35.11
132	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	-91.63	-2.91	3.18	-144.25	-23.57	16.34	-180.38	-7.32	4.06
133	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	57.16	88.39	154.64	354.86	15.74	4.44	348.84	-4.47	-1.28
134	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	998.73	410.70	41.12	869.20	410.47	47.22	2,145.93	425.13	19.81
135	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	150.16	3.20	2.13	160.45	12.62	7.87	179.41	37.23	20.75
136	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	-78.81	-5.49	6.97	-83.92	-4.48	5.34	-82.70	1.23	-1.49
137	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	505.80	27.83	5.50	460.46	-0.23	-0.05	466.62	-5.32	-1.14
138	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	73,028.96	8,991.03	12.31	76,841.39	-9,941.67	-12.94	84,007.75	21,524.27	25.62
139	हिंदुस्तान प्रोफैब लिमिटेड	8.63	-12.25	-141.95	0.94	-7.68	-817.02	-9.92	-10.87	109.58
140	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	52.06	4.14	7.95	64.95	12.89	19.85	62.06	15.45	24.90
141	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	-6.10	68.15	-1117.21	62.27	66.65	107.03	155.91	176.38	113.13
142	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	146.06	37.65	25.78	166.00	31.51	18.98	179.80	35.56	19.78

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
143	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	636.42	671.72	105.55	624.81	24.98	4.00	608.39	-16.10	-2.65
144	एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड	30.70	24.04	78.31	42.55	35.00	82.26	66.72	49.73	74.54
145	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	768.91	572.10	74.40	658.83	84.53	12.83	814.79	255.88	31.40
146	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड	3.19	1.64	51.41	2.97	-0.22	-7.41	2.97	-0.22	-7.41
147	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	36.78	0.28	0.76	37.03	0.31	0.84	37.82	4.81	12.72
148	एचएमटी लिमिटेड	1,068.27	46.82	4.38	1,075.65	15.02	1.40	1,100.50	17.47	1.59
149	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	-1,684.73	-61.49	3.65	-1,816.72	-48.78	2.69	-1,972.03	-71.74	3.64
150	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड	11.50	1.05	9.13	13.00	1.64	12.62	0.00	3,530.65	0.00
151	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	170.82	-3.82	-2.24	196.48	-9.48	-4.82	166.43	-18.25	-10.97
152	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-110.90	-36.53	32.94	-134.19	-22.20	16.54	-134.19	-22.20	16.54
153	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	58,986.01	6,878.47	11.66	66,130.57	6,792.65	10.27	77,227.56	7,801.91	10.10
154	एचपीसीएल बायो फ्यूल्स लिमिटेड	310.18	-44.04	-14.20	393.49	-14.94	-3.80	415.18	0.41	0.10
155	एचपीसीएल एलएनजी लिमिटेड	1,522.53	-14.03	-0.92	2,991.63	-7.20	-0.24	3,650.40	-10.15	-0.28
156	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	15,505.44	514.58	3.32	28,161.83	-299.52	-1.06	43,083.84	1,899.18	4.41

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
157	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	143.61	33.21	23.13	162.22	23.39	14.42	193.25	54.62	28.26
158	आईटीआई लिमिटेड	1,233.52	286.78	23.25	1,356.58	-215.87	-15.91	1,260.89	-393.92	-31.24
159	आईएफसीआई फेक्टर्स लिमिटेड	264.35	6.22	2.35	244.67	14.16	5.79	13.92	0.58	4.17
160	आईएफसीआई वित्तीय सेवाएँ लिमिटेड	69.74	1.08	1.55	65.44	-3.82	-5.84	63.66	-1.91	-3.00
161	आईएफसीआई अवसंरचना विकास लिमिटेड	506.80	10.15	2.00	522.89	16.46	3.15	507.93	13.53	2.66
162	आईएफसीआई लिमिटेड	6,540.74	-862.22	-13.18	6,430.32	445.73	6.93	5,259.73	1,056.54	20.09
163	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	179.79	1.83	1.02	174.43	5.87	3.37	175.65	14.04	7.99
164	आईएफआईएन कमोडिटीज़ लिमिटेड	4.13	-0.66	-15.98	3.43	-0.66	-19.24	3.13	-0.29	-9.27
165	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड	1.98	0.00	0.00	1.99	0.01	0.50	2.01	0.03	1.49
166	आईएफआईएन सिक्योरिटीज़ फाइनेंस लिमिटेड	28.96	0.43	1.48	29.35	0.33	1.12	30.48	1.26	4.13
167	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	27.14	2.89	10.65	29.16	2.73	9.36	26.06	-3.02	-11.59
168	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	22.93	5.14	22.42	24.47	2.06	8.42	25.73	2.62	10.18
169	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	51,537.78	2,935.32	5.70	54,942.61	3,972.56	7.23	63,615.96	5,379.23	8.46

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
170	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड	3,051.17	1.33	0.04	3,800.02	0.44	0.01	3,800.02	0.44	0.01
171	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड	5,778.55	84.80	1.47	6,234.03	315.89	5.07	6,443.57	329.11	5.11
172	इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	10.00	6.51	65.10	10.00	-0.06	-0.60	10.00	-0.04	-0.40
173	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड	473.06	-169.47	-35.82	892.98	25.99	2.91	1,177.21	91.87	7.80
174	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	319.26	10.43	3.27	376.35	86.93	23.10	424.96	109.93	25.87
175	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	2,371.44	-52.83	-2.23	2,863.56	242.84	8.48	2,956.27	213.14	7.21
176	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	174.35	11.70	6.71	174.35	11.70	6.71	174.35	11.70	6.71
177	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	117.85	45.41	38.53	128.12	30.13	23.52	134.56	17.75	13.19
178	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,92,637.33	34,200.93	17.75	1,91,718.89	16,628.41	8.67	2,34,276.20	57,692.18	24.63
179	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	1,883.88	889.51	47.22	2,478.40	1,354.01	54.63	3,229.97	1,496.28	46.32
180	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	4,12,985.23	14,654.16	3.55	4,40,422.10	32,830.74	7.45	4,48,561.63	26,454.78	5.90
181	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	32,374.35	2,360.64	7.29	45,702.47	3,227.69	7.06	57,765.91	4,728.15	8.19

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
182	इंडियन वैक्सीन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4.54	-2.42	-53.30	6.12	0.38	6.21	6.24	0.17	2.72
183	इंडो-रशियन हेल्थेकॉप्टर्स लिमिटेड	7.59	-0.33	-4.35	7.56	-0.03	-0.40	7.37	-0.19	-2.58
184	इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड	0.31	-0.89	-287.10	0.53	-0.68	-128.30	0.63	-0.97	-153.97
185	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	204.43	26.75	13.09	209.29	4.86	2.32	202.76	7.01	3.46
186	आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड							837.51	-3.81	-0.45
187	इरकॉन अक्वोली -शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	82.50	0.44	0.53	218.79	13.49	6.17
188	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड				6.77	0.00	0.00	196.70	16.97	8.63
189	इरकॉन दावणगरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	560.97	35.45	6.32	570.59	63.50	11.13	594.47	62.89	10.58
190	इरकॉन गुडगांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	18.40	0.00	0.00	75.07	4.91	6.54	292.73	11.03	3.77
191	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड				82.99	1.03	1.24	198.86	6.80	3.42
192	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	164.94	13.39	8.12	170.26	7.13	4.19	176.61	14.22	8.05
193	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	4,620.96	610.50	13.21	5,178.48	883.19	17.06	5,771.76	1,155.54	20.02
194	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	256.43	8.22	3.21

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
195	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	410.07	-9.18	-2.24	351.31	1.56	0.44	336.95	8.55	2.54
196	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड				54.71	-0.32	-0.58	497.96	-0.23	-0.05
197	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	554.76	29.46	5.31	536.14	23.06	4.30	524.54	34.75	6.62
198	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	760.44	122.31	16.08	977.85	78.08	7.98	1,025.96	123.70	12.06
199	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	1,548.15	746.63	48.23	2,106.05	1,144.37	54.34	2,853.62	1,344.84	47.13
200	आईआरईएल आईडीसीओएल लिमिटेड	1.87	-0.05	-2.67	3.75	-0.12	-3.20	3.74	-0.01	-0.27
201	आईटीपीओ सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
202	जे एंड के एवं कश्मीर खनिज विकास निगम लिमिटेड	7.83	-0.90	-11.49	6.59	-1.24	-18.82	-6.25	-12.84	205.44
203	जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	281.49	-0.35	-0.12	561.49	0.28	0.05	1,019.87	0.27	0.03
204	जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.81	-0.86	106.17
205	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	165.42	3.81	2.30	170.02	6.70	3.94	173.86	6.73	3.87
206	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	448.77	3.03	0.68	545.05	8.13	1.49	1,030.95	3.48	0.34
207	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	0.06	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
208	झारखंड राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड	-0.08	-0.01	12.50	-0.09	-0.01	11.11	-0.10	-0.01	10.00

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
209	जोडा बारबिल ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.01	0.00	0.00
210	जोगीघोषा लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
211	कल्लम ट्रांस्को लिमिटेड							-0.47	-0.52	110.64
212	कांकाणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.05	-0.01	-20.00
213	कर्मयोगी भारत				31.97	2.89	9.04	43.04	6.08	14.13
214	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	239.84	33.16	13.83	260.69	34.51	13.24	268.91	17.62	6.55
215	कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन	144.46	1.32	0.91	148.29	3.83	2.58	157.56	8.99	5.71
216	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	640.42	-0.70	-0.11	-2.60	-0.68	26.15	-3.18	-0.58	18.24
217	कवरत्ती स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
218	खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.03	-0.02	-66.67	0.03	-0.02	-66.67
219	खावड़ा IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.50	-0.55	110.00
220	खावड़ा IV ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.29	-0.34	117.24
221	खावड़ा IV-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.37	-0.42	113.51

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
222	खावड़ा पीएस1एण्ड3 ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.01	0.00	0.00
223	खावड़ा V ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.38	-0.43	113.16
224	केआईओएसआईएल लिमिटेड	2,152.64	412.75	19.17	2,032.87	-118.16	-5.81	1,949.33	-58.19	-2.99
225	कोचि मेट्रो रेल लिमिटेड	6,701.44	-152.57	-2.28	6,642.66	-113.89	-1.71	6,563.89	-140.10	-2.13
226	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1.92	0.00	0.00	-2.28	-0.01	0.44	-0.01	2.28	-22,800
227	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8,298.10	0.06	0.00	8,612.38	0.75	0.01	8,848.85	-0.01	0.00
228	कॉकण एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड	4,504.19	491.39	10.91	4,386.95	108.09	2.46	4,317.80	24.08	0.56
229	कॉकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4,609.97	102.34	2.22	4,815.76	486.45	10.10	5,628.19	544.11	9.67
230	कुमारकृष्णा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	27.29	5.84	21.40	33.96	10.42	30.68	37.27	11.09	29.76
231	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड	388.64	28.61	7.36	411.43	27.63	6.72	411.43	27.63	6.72
232	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	1,440.50	-0.20	-0.01	2,274.41	-0.22	-0.01	3,309.41	-0.36	-0.01
233	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड	160.21	0.01	0.01	-0.30	-161.28	53760.00	1.01	-0.25	-24.75
234	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड				-0.46	-0.51	110.87	-1.05	-0.59	56.19

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
235	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	816.32	235.12	28.80	1,088.16	314.63	28.91	1,240.09	69.49	5.60
236	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-5.99	-0.02	0.33	-6.02	-0.03	0.50	-6.06	-0.04	0.66
237	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	89.07	-0.02	-0.02	88.64	-0.43	-0.49	379.56	-1.58	-0.42
238	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	8,217.48	11,462.43	139.49	13,312.60	18,493.02	138.91	16,110.21	15,593.10	96.79
239	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-2,090.91	-598.55	28.63	2,656.79	-731.72	-27.54	2,132.16	-841.89	-39.49
240	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-757.51	-523.77	69.14	-879.32	-0.80	0.09	-879.32	-0.80	0.09
241	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	14,502.08	-260.27	-1.79	17,974.62	-201.99	-1.12	18,213.27	-155.29	-0.85
242	महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	614.18	5.69	0.93	559.59	34.60	6.18	1,412.29	33.49	2.37
243	एमएएमसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-1.66	0.09-	5.42	-1.75	-0.09	5.14	-1.86	-0.10	5.38
244	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1.87	0.00	0.00	-2.23	-0.01	0.45	-0.01	1.88	-18,800
245	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	21,411.84	3,573.81	16.69	22,252.62	5,290.19	23.77	23,337.91	6,583.79	28.21
246	मणिपुर स्टेट इग्ज एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-470.99	-172.01	36.52	-513.90	-3.72	0.72	513.90-	-3.72	0.72
247	मसकानी पारादीप रोड विकास लिमिटेड							26.52	-1.14	-4.30
248	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	3,321.31	772.69	23.26	4,177.51	1,429.33	34.21	5,570.68	2,461.38	44.18
249	मेकॉन लिमिटेड	382.93	20.16	5.26	394.44	35.18	8.92	439.97	52.08	11.84

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
250	मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड				-0.39	-0.44	112.82	-0.95	-0.56	58.95
251	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	5.69	0.27	4.75	5.95	0.43	7.23	6.05	0.33	5.45
252	खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	679.06	28.49	4.20	662.77	20.86	3.15	737.17	107.33	14.56
253	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	1,190.72	243.75	20.47	1,373.55	234.00	17.04	1,378.58	157.71	11.44
254	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	74.13	0.09	0.12	74.84	0.71	0.95	75.50	0.90	1.19
255	एमएमटीसी लिमिटेड	193.40	326.43	168.78	1,264.83	1,392.05	110.06	1,354.36	78.66	5.81
256	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	41.55	1.15	2.77	41.73	0.24	0.58	43.00	1.69	3.93
257	मॉयल लिमिटेड	2,141.51	523.29	24.44	2,244.32	334.45	14.90	2,390.18	387.00	16.19
258	एमपीसीओएन लिमिटेड	8.45	1.70	20.12	11.02	6.01	54.54	15.48	8.46	54.65
259	एमएसटीसी लिमिटेड	471.36	222.69	47.24	595.41	313.57	52.66	665.95	284.44	42.71
260	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	17,741.85	24.37	-0.14	19,811.22	30.63	-0.15	21,821.34	462.90	2.12
261	मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड	235.19	7.57	3.22	321.74	87.42	27.17	430.26	133.70	31.07
262	म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड	6,549.75	25.40	0.39	7,575.66	101.89	1.34	9,273.22	750.59	8.09
263	नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड	-8.26	-12.82	155.21	0.88	-6.08	-690.91	-2.14	-3.07	143.46
264	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	12,184.34	3,954.87	32.46	13,238.45	1,954.99	14.77	14,571.66	2,783.57	19.10
265	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2,068.65	30.56	1.48	2,099.28	30.36	1.45	2,145.43	31.07	1.45

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
266	भारतीय राष्ट्रीय साइकिल निगम लिमिटेड	3.52	-0.33	-9.38	3.35	-0.17	-5.07	2.67	-0.68	-25.47
267	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	8,999.05	136.00	1.51	14,000.11	701.51	5.01	19,610.18	876.53	4.47
268	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम				6,585.54	703.31	10.68	6,887.31	740.23	10.75
269	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	24.39	10.00	41.00	34.39	13.49	39.23	53.47	19.19	35.89
270	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	3,013.16	268.48	8.91	3,410.43	886.70	26.00	2,698.58	338.46	12.54
271	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	21.76	-6.74	-30.97	26.77	1.85	6.91	42.03	14.97	35.62
272	नेशनल फार्मेशनल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	1.21	0.03	2.48	1.24	0.03	2.42	1.27	0.05	3.94
273	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	496.22	6.20	1.25	501.28	5.09	1.02	508.52	8.92	1.75
274	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	76.76	-2.64	-3.44	81.63	6.51	7.98	85.20	5.53	6.49
275	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13,351.85	105.14	0.79	14,750.79	68.51	0.46	15,319.09	108.95	0.71
276	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	410.39	152.21	37.09	601.10	304.78	50.70	715.30	240.62	33.64
277	नेशनल हाईवेज़ इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	15.81	8.69	54.97	16.36	1.49	9.11	17.30	1.27	7.34

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
278	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक.	741.86	61.80	8.33	892.24	200.36	22.46	1,089.36	265.92	24.41
279	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,661.32	-1,599.95	-43.70	-54.15	-3,790.67	7000.31	-100.42	-123.91	123.39
280	राष्ट्रीय निवेश एवं अवसरचना निधि ट्रस्टी लिमिटेड	-0.10	0.03	-30.00	-0.01	0.09	-900.00	0.12	0.17	141.67
281	राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड	-9.99	-7.77	77.78	21.08	49.60	235.29	83.22	84.25	101.24
282	राष्ट्रीय भूमि मुद्राकरण निगम लिमिटेड				152.99	4.00	2.61	161.96	11.98	7.40
283	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	3,039.34	67.64	2.23	3,285.48	65.26	1.99	3,410.99	53.13	1.56
284	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	241.48	50.45	20.89	280.26	62.14	22.17	268.94	77.84	28.94
285	भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लिमिटेड	9.50	0.20	2.11	5.78	-3.72	-64.36	4.40	-1.45	-32.95
286	राष्ट्रीय सफाईकर्मचारीवित्त एवं विकास निगम	875.22	15.92	1.82	890.22	14.99	1.68	920.18	19.99	2.17
287	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	2,185.31	48.78	2.23	2,235.33	47.61	2.13	2,294.80	47.71	2.08
288	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	1,128.22	24.45	2.17	1,152.51	24.29	2.11	1,193.07	25.67	2.15
289	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	668.26	17.57	2.63	712.96	54.48	7.64	742.45	87.64	11.80

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
290	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1,180.06	208.03	17.63	1,258.12	239.05	19.00	1,349.52	214.72	15.91
291	राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड	892.21	-263.22	-29.50	892.21	-263.22	-29.50	892.21	-263.22	-29.50
292	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	1,774.75	236.73	13.34	1,914.54	312.28	16.31	2,139.00	456.49	21.34
293	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड	32.97	6.12	18.56	37.70	9.93	26.34	54.40	27.92	51.32
294	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	0.98	0.03	3.06	0.99	0.00	0.00	0.99	0.10	10.10
295	नेपा लिमिटेड	366.52	-16.05	-4.38	260.72	-57.21	-21.94	133.96	-74.22	-55.40
296	एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.87	-0.92	105.75
297	एनईआरजीएस-I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.31	-0.36	116.13
298	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड	60.74	-1.24	-2.04	60.74	-1.24	-2.04	60.74	-1.24	-2.04
299	नई दिल्ली नगर परिषद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	135.96	2.35	1.73	135.96	2.35	1.73	135.96	2.35	1.73
300	न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड	1,441.77	459.15	31.85	6,606.40	625.76	9.47	7,198.47	803.58	11.16
301	नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड	12,450.56	-0.33	0.00	14,014.36	-0.15	0.00	16,611.82	1,111.31	6.69
302	एनएचडीसी लिमिटेड	5,644.67	725.95	12.86	5,693.27	1,168.43	20.52	5,668.68	1,219.53	21.51
303	एनएचपीसी लिमिटेड	56,811.32	3,305.69	5.82	61,470.96	6,087.40	9.90	65,517.89	6,155.19	9.39
304	एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड				18.41	-1.91	-10.37	19.38	1.06	5.47

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
305	एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड				11.87	0.48	4.04	12.22	0.47	3.85
306	एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड				545.13	3.08	0.57	592.24	1.47	0.25
307	एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड							49.84	-0.16	-0.32
308	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	22,632.70	3,390.20	14.98	22,455.77	2,396.20	10.67	23,933.56	3,430.78	14.33
309	एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड							0.04	-0.06	-150.00
310	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	4,063.94	538.58	13.25	3,847.94	614.60	15.97	3,518.45	370.01	10.52
311	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन	6.04	1.02	16.89	4.56	-1.48	-32.46	4.53	-0.03	-0.66
312	एनएमडीसी लिमिटेड	36,512.19	13,013.67	35.64	22,332.31	7,705.82	34.51	25,405.78	8,083.65	31.82
313	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	0.04	-0.01	-25.00	6,748.90	0.00	0.00	20,286.44	-1,870.72	-9.22
314	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड	181.66	-4.03	-2.22	178.54	-4.06	-2.27	174.65	-4.85	-2.78
315	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13,096.80	490.46	3.74	12,780.23	1,283.01	10.04	13,111.22	1,132.96	8.64
316	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	3.85	-28.18	-731.95	3.07	-1.60	-52.12	5.92	0.86	14.53
317	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड	-19.98	-2.38	11.91	14.14	4.44	31.40	20.15	1.73	8.59

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
318	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	7,871.34	6,937.64	88.14	11,176.47	9,357.46	83.72	15,375.54	10,843.63	70.53
319	एनपीसीआई एल इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.45	0.05	3.45	1.50	0.07	4.67	1.57	0.10	6.37
320	एनआरटीयू फाउंडेशन	1.22	0.22	18.03	0.19	-2.43	-1278.95	0.04	-0.15	-375.00
321	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड	7.29	2.31	31.69	9.76	4.06	41.60	12.59	5.01	39.79
322	एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	-2.76	-2.05	74.28	-3.32	-0.56	16.87	-3.35	-0.03	0.90
323	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाइ कंपनी लिमिटेड	55.58	-0.25	-0.45	20.27	0.33	1.63	20.31	0.15	0.74
324	एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड				9,949.05	68.72	0.69	14,427.68	1,170.14	8.11
325	एनटीपीसी लिमिटेड	2,88,738.96	30,489.82	10.56	3,09,800.05	35,630.84	11.50	3,17,516.32	36,982.73	11.65
326	एनटीपीसी खनन लिमिटेड	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	150.66	-3.43	-2.28
327	एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड	767.78	0.17	0.02	1,452.53	9.58	0.66	6,048.76	136.40	2.26
328	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	562.57	201.08	35.74	768.96	257.74	33.52	964.40	239.35	24.82
329	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,08,783.01	11,533.23	10.60	1,26,626.20	10,468.88	8.27	1,47,426.92	15,479.53	10.50
330	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	9,237.72	4,849.68	52.50	14,286.13	4,956.98	34.70	21,779.47	2,944.13	13.52
331	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	0.38	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
332	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	2,43,529.03	41,344.74	16.98	2,64,419.76	50,714.99	19.18	3,09,948.80	53,324.11	17.20
333	ऑयल इंडिया लिमिटेड	40,994.16	5,558.83	13.56	44,994.60	9,441.04	20.98	54,929.62	7,375.80	13.43
334	ओम्निबस औद्योगिक विकास निगम दमन, दीव एवं दादरा एवं नगर हवेली लिमिटेड	232.93	32.92	14.13	277.31	54.65	19.71	324.44	65.13	20.07
335	ओएनजीसी पेट्रो एडिशनल्स लिमिटेड	22,931.37	928.93	4.05	21,819.02	-1,988.19	-9.11	21,760.69	-2,436.50	-11.20
336	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	65,365.11	6,177.21	9.45	68,801.02	5,529.41	8.04	66,293.41	4,907.67	7.40
337	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड	22,067.20	-419.58	-1.90	27,173.29	2,467.34	9.08	26,031.25	-1,817.44	-6.98
338	उड़ीसा इंडीग्रेटेड पावर लिमिटेड	153.17	0.00	0.00	109.13	0.00	0.00	117.08	0.00	0.00
339	ओवीएल ओवरसीज आईएफएससी लिमिटेड							1.58	-0.43	-27.22
340	पारादीप ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.01	0.00	0.00
341	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	5,750.81	278.78	4.85	7,937.57	393.42	4.96	9,956.40	517.60	5.20
342	पवन हंस लिमिटेड	970.01	-3.94	-0.41	902.55	-6.47	-0.72	902.55	-6.47	-0.72
343	पीईसी लिमिटेड	-2,223.98	-5.27	0.24	-2,466.86	-243.93	9.89	-2,835.75	-6.29	0.22
344	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	120.83	51.11	42.30	172.69	87.01	50.39	248.76	212.45	85.40
345	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-1.71	0.16	-9.36	-1.40	0.58	-41.43	-1.09	0.36	-33.03

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
346	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3,91,999.26	34,898.95	8.90	4,34,586.18	36,618.29	8.43	4,98,146.06	44,620.43	8.96
347	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2,08,298.61	27,649.90	13.27	2,11,684.45	25,877.31	12.22	2,07,608.01	26,980.63	13.00
348	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड	582.36	32.96	5.66	579.92	46.20	7.97	558.25	60.10	10.77
349	पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	633.59	-0.02	0.00	876.87	51.23	5.84	1,034.39	68.58	6.63
350	पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.01	0.00	0.00	120.87	2.32	1.92
351	पावरग्रिड भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	451.93	15.78	3.49
352	पावरग्रिड भडला ट्रांसमिशन लिमिटेड	299.47	8.86	2.96	497.17	28.21	5.67	711.82	42.70	6.00
353	पावरग्रिड भडला-III ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.01	0.00	0.00	103.54	2.54	2.45
354	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	456.08	20.86	4.57	545.40	27.60	5.06	550.07	63.75	11.59
355	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	945.72	-0.04	0.00	1,146.59	65.78	5.74	1,128.25	95.01	8.42
356	पावरग्रिड बीकानेर नीमराना ट्रांसमिशन लिमिटेड							19.77	0.40	2.02
357	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	448.82	-0.03	-0.01	1,136.58	52.32	4.60	1,381.54	120.65	8.73

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
358	पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.01	0.00	0.00	34.09	0.83	2.43
359	पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड				0.67	-12.47	-1861.19	115.66	13.27	11.47
360	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.26	-0.31	119.23	14.71	0.18	1.22	54.22	1.49	2.75
361	पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.04	-0.01	-25.00	19.74	0.55	2.79
362	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	660.32	36.85	5.58	661.24	53.68	8.12	637.65	70.17	11.00
363	पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.00	0.00	434.39	7.25	1.67	896.99	63.86	7.12
364	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	537.44	65.94	12.27	494.14	57.77	11.69	421.34	59.51	14.12
365	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	447.26	46.86	10.48	473.80	50.63	10.69	417.54	61.60	14.75
366	पावरग्रिड खावड़ा II-बी ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.05	-0.01	-20.00	376.32	11.49	3.05
367	पावरग्रिड खावड़ा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.05	-0.01	-20.00	911.38	29.02	3.18
368	पावरग्रिड खावड़ा सी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड				0.05	-0.01	-20.00	219.51	5.52	2.51
369	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	994.58	57.40	5.77	968.77	91.01	9.39	941.07	120.79	12.84

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
370	पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड							19.59	0.39	1.99
371	पावरग्रिड कैपीएस 2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड				0.05	-0.01	-20.00	56.98	3.35	5.88
372	पावरग्रिड कैपीएस 3 ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.05	-0.01	-20.00	89.27	3.99	4.47
373	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	3,215.88	430.54	13.39	3,140.24	485.56	15.46	2,997.07	475.19	15.86
374	पावरग्रिड मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	751.45	-0.02	0.00	1,009.36	53.18	5.27	1,082.05	102.94	9.51
375	पावरग्रिड मेवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.34	-0.39	114.71
376	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,181.91	113.62	9.61	1,178.43	122.32	10.38	1,135.59	124.97	11.00
377	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.00	0.00	429.47	7.48	1.74	1,218.22	53.81	4.42
378	पावरग्रिड नीमराना बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड							19.07	0.39	2.05
379	पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड				186.97	-0.29	-0.16	727.09	28.69	3.95
380	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,155.63	80.60	6.97	1,356.01	325.93	24.04	1,100.98	129.24	11.74
381	पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.01	0.00	0.00	15.25	0.58	3.80

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
382	पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड				-0.69	-0.74	107.25	152.63	2.20	1.44
383	पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	92.86	-0.01	-0.01	256.97	12.17	4.74	320.67	24.68	7.70
384	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	551.40	-0.01	0.00	738.94	48.16	6.52	809.17	91.44	11.30
385	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	525.86	16.37	3.11	851.95	43.44	5.10	1,207.73	70.71	5.85
386	पावरग्रिड सदरन इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	3,291.11	141.21	4.29	3,193.98	361.20	11.31	3,078.19	365.54	11.88
387	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	8.67	-0.44	-5.07	8.61	-0.09	-1.05	817.01	353.91	43.32
388	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	59.61	21.34	35.80	61.91	18.37	29.67	60.73	17.67	29.10
389	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	934.60	75.85	8.12	938.27	93.41	9.96	891.13	91.89	10.31
390	पावरग्रिड वतामान ट्रांसमिशन लिमिटेड							68.10	0.42	0.62
391	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-19.42	-0.01	0.05	-19.43	-0.01	0.05	-19.44	-0.01	0.05
392	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	109.53	-5.79	-5.29	73.04	-36.49	-49.96	21.05	-51.98	-246.94
393	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	167.40	14.84	8.86	167.74	4.59	2.74	174.78	14.38	8.23

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
394	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	2.26	-0.01	-0.44	2.25	-0.01	-0.44	2.22	-0.03	-1.35
395	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	221.25	-3.89	-1.76	219.58	3.86	1.76	208.81	3.15	1.51
396	रेल विकास निगम लिमिटेड	11,946.84	1,935.82	16.20	12,509.73	2,173.87	17.38	13,855.05	2,443.35	17.64
397	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,516.02	282.77	18.65	1,636.50	252.58	15.43	1,827.24	328.09	17.96
398	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-27.30	-2.06	7.55	-28.36	1.04	-3.67	-28.36	1.04	-3.67
399	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंसूलैटर्स लिमिटेड	72.94	-7.49	-10.27	62.86	-16.58	-26.38	65.61	4.38	6.68
400	राजस्थान IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.36	-0.41	113.89
401	राजस्थान IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.29	-0.34	117.24
402	राजस्थान IV एच1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.47	-0.52	110.64
403	राजस्थान पार्ट I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.62	-0.67	108.06
404	रामकनानी बी-पानागढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.01	0.00	0.00
405	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-15.63	-0.53	3.39	-16.81	-0.83	4.94	-18.05	-0.54	2.99

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
406	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	5,250.46	1,049.52	19.99	5,730.89	1,443.39	25.19	6,009.65	480.34	7.99
407	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	11,947.06	2,363.94	19.79	11,203.69	-1,741.66	-15.55	4,501.11	-3,406.01	-75.67
408	रेटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	186.27	-0.53	-0.28	375.89	8.59	2.29	674.81	5.56	0.82
409	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	1,057.13	-116.06	-10.98	842.58	-98.16	-11.65	2,170.98	1,802.66	83.03
410	आरईसी लिमिटेड	3,83,528.83	34,477.81	8.99	4,18,834.95	15,527.00	3.71	4,77,537.16	46,250.00	9.69
411	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	328.58	68.87	20.96	440.92	186.35	42.26	567.16	202.70	35.74
412	आरईएमसी लिमिटेड	233.22	66.43	28.48	235.37	84.04	35.71	228.40	113.38	49.64
413	रिचर्डसन एवं कुंजास (1972) लिमिटेड	247.31	25.44	10.29	260.04	16.99	6.53	255.09	23.26	9.12
414	राइट्स लिमिटेड	2,399.26	674.56	28.12	2,503.04	708.54	28.31	2,506.87	596.87	23.81
415	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड	-0.02	-0.01	50.00	29.70	-4.62	-15.56	29.70	-4.62	-15.56
416	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	794.77	9.38	1.18	908.81	18.97	2.09	1,022.17	32.45	3.17
417	सेल रिफ़ैक्टरी कंपनी लिमिटेड	120.38	27.75	23.05	125.12	24.35	19.46	139.19	27.55	19.79
418	सखीगोपाल इंडीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	16.39	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
419	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	5.25	15.15	288.57	16.53	15.87	96.01	33.35	24.46	73.34
420	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	65.08	13.16	20.22	65.85	6.30	9.57	34.71	1.34	3.86

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
421	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4,854.23	923.09	19.02	6,416.14	2,341.21	36.49	6,943.95	1,383.84	19.93
422	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	800.70	-0.10	-0.01	800.28	-0.41	-0.05	800.11	-0.18	-0.02
423	एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड	91.73	28.60	31.18	95.08	19.43	20.44	112.71	27.32	24.24
424	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड	0.01	0.00	0.00	2,886.43	17.58	0.61	2,933.85	55.10	1.88
425	शॉगटॉग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.52	-0.57	109.62
426	सिडयोग कॉन्कॉर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	90.29	0.02	0.02	91.90	2.06	2.24	97.40	6.68	6.86
427	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड				-0.67	-0.72	107.46	-0.49	-0.01	2.04
428	एसआईओटी ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
429	एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड				2,818.95	-2.97	-0.11	6,495.49	9.95	0.15
430	एसजेवीएन लिमिटेड	18,190.97	1,460.96	8.03	20,577.30	1,927.50	9.37	23,528.81	1,583.63	6.73
431	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड	3,689.50	-0.81	-0.02	6,416.65	-1.16	-0.02	8,169.45	-0.91	-0.01
432	भारतीय सौर ऊर्जा निगम	2,060.46	320.00	15.53	2,379.33	427.19	17.95	3,060.00	595.39	19.46

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
433	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	5,442.08	2,137.34	39.27	6,936.01	3,529.95	50.89	14,465.53	9,297.45	64.27
434	एसटीसीएल लिमिटेड	-4,557.11	7.16	-0.16	-4,558.19	-1.10	0.02	-4,559.38	-1.13	0.02
435	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	60,917.09	17,736.60	29.12	59,917.82	4,524.64	7.55	64,664.18	6,161.48	9.53
436	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4,552.99	161.70	3.55	5,956.02	209.79	3.52	6,444.54	301.22	4.67
437	स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	66.33	6.82	10.28	56.58	9.95	17.59	86.32	15.95	18.48
438	स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड	12.93	-2.30	-17.79	14.24	-1.85	-12.99	13.17	-1.25	-9.49
439	सूटी टेक ऑप्शंस लिमिटेड	-0.32	-0.01	3.13	-0.33	-0.01	3.03	-0.34	-0.01	2.94
440	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन	310.20	3.89	1.25	339.54	29.51	8.69	484.89	26.20	5.40
441	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	42.31	8.02	18.96	52.17	6.81	13.05	46.87	10.58	22.57
442	टीसीआईएल लखनादौन टोल रोड लिमिटेड	76.66	0.82	1.07	83.69	5.53	6.61	82.55	6.70	8.12
443	टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	612.79	47.75	7.79	618.56	67.03	10.84	674.39	119.90	17.78
444	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	16,832.13	1,586.44	9.43	21,190.30	1,008.11	4.76	25,527.76	1,631.91	6.39
445	टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड							9.50	-0.64	-6.74

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
446	द बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	-141.10	8.44	-5.98	-116.21	12.91	-11.11	-114.45	3.30	-2.88
447	ब्रेथेड बर्न एंड जेसप कंसट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	211.99	5.12	2.42	219.82	14.00	6.37	238.57	28.65	12.01
448	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-1,234.52	-3.21	0.26	-1,234.52	-3.21	0.26	-1,234.52	-3.21	0.26
449	भारतीय कपास निगम लिमिटेड	363.38	491.37	135.22	288.53	-72.84	-25.25	326.71	191.33	58.56
450	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	250.82	15.57	6.21	248.19	13.46	5.42	256.62	15.38	5.99
451	द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	1,975.16	595.21	30.13	3,049.46	857.77	28.13	3,151.30	287.56	9.13
452	भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड	87.03	-18.05	-20.74	87.03	-18.05	-20.74	87.03	-18.05	-20.74
453	औद्योगिक ऋण कंपनी लिमिटेड	-0.05	0.00	0.00	-0.06	-0.01	16.67	-0.08	-0.02	25.00
454	भारतीय जूट निगम लिमिटेड	133.69	-13.78	-10.31	143.70	12.75	8.87	182.63	71.96	39.40
455	केरल औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड	4.90	-0.10	-2.04	4.99	0.10	2.00	4.99	0.10	2.00
456	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	38,191.19	159.91	0.42	37,957.33	1,245.22	3.28	44,704.21	1,445.48	3.23
457	ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7,533.32	-3,146.87	-41.77	3,765.12	-4,890.23	-129.88	5,040.90	117.98	2.34

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
458	उड़ीसा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड	131.47	16.42	12.49	-12.80	-2.86	22.34	-10.74	-5.31	49.44
459	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10,966.77	899.90	8.21	8,699.51	850.05	9.77	9,436.06	730.66	7.74
460	भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड	-197.57	-48.60	24.60	-144.07	37.11	-25.76	-73.88	52.46	-71.01
461	ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड							3.98	-1.34	-33.67
462	हूप कम्फर्ट्स लिमिटेड	4,573.67	23.04	0.50	4,852.84	34.63	0.71	4,664.48	-406.49	-8.71
463	तुमकुर-II आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.15	-0.20	133.33
464	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-44.89	-0.18	0.40	-44.69	0.20	-0.45	0.00	54.09	0.00
465	टस्को लिमिटेड	18.71	-1.46	-7.80	37.17	-0.38	-1.02	67.30	-0.74	-1.10
466	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	139.32	-17.52	-12.58	155.66	-10.57	-6.79	176.83	4.13	2.34
467	यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	6,047.69	-2,061.30	-34.08	-732.05	-2,829.33	386.49	-1,535.20	-803.71	52.35
468	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3,944.70	777.48	19.71	3,702.73	97.17	2.62	3,900.06	322.13	8.26
469	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-23.81	-0.18	0.76	-24.85	-0.12	0.48	-25.95	-0.13	0.50
470	विज्ञान इंस्टीट्यूट लिमिटेड	53.85	-4.95	-9.19	30.28	0.09	0.30	29.14	-0.09	-0.31
471	विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड	180.24	-0.49	-0.27	162.27	-2.20	-1.36	144.74	-1.48	-1.02

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में
472	वेपकोस लिमिटेड	659.28	65.36	9.91	702.29	16.24	2.31	702.29	16.24	2.31
473	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,505.82	1,259.73	83.66	2,090.93	626.19	29.95	6,452.34	4,181.67	64.81
474	यंत्र इंडिया लिमिटेड	2,577.89	-123.12	-4.78	3,760.21	51.34	1.37	4,023.55	425.58	10.58
475	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	-0.08	-0.01	12.50	-0.08	0.00	0.00	-0.09	-0.01	11.11
476	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	-0.04	-0.01	25.00	-0.04	-0.01	25.00	-0.05	-0.01	20.00
477	जेनिथ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	22.65	43.70	192.94	37.40	78.45	209.76	49.34	13.61	27.58
	योग	39,98,159.88	4,15,288.49	10.39	43,72,330.10	3,98,114.54	9.11	49,45,867.86	5,98,037.13	12.09

अनुलग्नक-XI (पैरा संख्या 1.4.2 देखें)
सरकारी कंपनियों एवं निगमों की इक्विटी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
1	एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड	4.71	2,573.47	0.18	12.17	5,290.35	0.23	20.24	7,458.71	0.27
2	एगीनोवेटिव इंडिया लिमिटेड	1.54	72.61	2.12	3.51	76.12	4.61	4.74	80.86	5.86
3	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	15.33	361.65	4.24	77.92	423.07	18.42	77.92	423.07	18.42
4	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	-1,057.47	-6,266.13	16.88	-551.22	-69.65	791.41	484.71	1,015.06	47.75
5	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	837.12	-1,381.51	-60.59	628.47	-790.02	-79.55	628.47	-790.02	-79.55
6	एआईसी - आईपीआर प्लाज्माटेक इन्वैशन फाउंडेशन							-0.01	0.01	-100.00
7	एआईसी आरआरसीएटी पीआई-हब फाउंडेशन							0.07	0.08	87.50
8	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	8.76	12,227.30	0.07	2,972.05	15,762.38	18.86	4,651.31	18,899.84	24.61
9	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	-447.76	-3,098.55	14.45	-566.57	-3,664.32	15.46	-566.57	-3,664.32	15.46
10	अनंतपुरम कुरुनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00
11	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड	23.93	209.14	11.44	34.87	233.55	14.93	33.32	266.86	12.49
12	अंडमान मत्स्य पालन लिमिटेड	-7.22	-47.78	15.11	-7.27	-55.05	13.21	-8.47	-63.53	13.33

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
13	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	-0.90	183.14	-0.49	1.17	186.61	0.63	-64.22	124.24	-51.69
14	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24.96	1,513.87	1.65	48.54	1,486.72	3.26	62.86	1,475.24	4.26
15	अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00
16	अपोलो डिज़ाइन अपैरल पार्कर्स लिमिटेड	-80.74	38.73	-208.47	-80.74	38.73	-208.47	-80.74	38.73	-208.47
17	आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड	54.19	12,302.08	0.44	271.17	13,289.17	2.04	605.07	14,197.58	4.26
18	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	64.15	599.26	10.70	72.93	671.56	10.86	71.73	742.28	9.66
19	औरंगाबाद टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्कर्स लिमिटेड	-0.75	12.55	-5.98	-0.75	12.55	-5.98	-0.75	12.55	-5.98
20	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	122.81	1,319.86	9.30	153.86	1,356.25	11.34	203.47	1,427.22	14.26
21	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	66.62	159.96	41.65	73.42	156.25	46.99	85.62	168.62	50.78
22	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-476.92	11,147.71	-4.28	-467.12	12,498.42	-3.74	-341.57	30,655.84	-1.11
23	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	-0.89	293.71	-0.30	-0.93	292.79	-0.32	1.14	293.93	0.39
24	बीईएल ऑप्टिकल डिवाइसेज लिमिटेड	5.16	244.32	2.11	6.76	271.21	2.49	16.59	286.02	5.80
25	बीईएल-थैल्स सिस्टम्स लिमिटेड	5.21	62.85	8.29	7.00	68.29	10.25	2.77	68.93	4.02
26	बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड	-0.01	0.00	-	-0.63	8.58	-7.34	-3.72	4.86	-76.54
27	बीईएमएल लिमिटेड	134.59	2,280.73	5.90	158.78	2,394.09	6.63	283.02	2,641.77	10.71

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
28	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	7.47	76.96	9.71	10.16	163.74	6.20	18.08	181.65	9.95
29	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड	-3.82	250.31	-1.53	-10.89	478.05	-2.28	-10.67	715.54	-1.49
30	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	-2.49	84.92	-2.93	0.10	85.02	0.12	2.14	87.16	2.46
31	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	111.62	3,273.77	3.41	589.32	3,784.13	15.57	1,564.46	5,321.72	29.40
32	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	499.92	3,030.56	16.50	352.17	3,211.50	10.97	612.72	3,636.82	16.85
33	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	2,348.93	11,984.26	19.60	3,006.67	13,581.99	22.14	4,020.00	16,035.70	25.07
34	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड	-68.88	-1,982.54	3.47	-61.46	-2,044.01	3.01	-72.02	-2,116.03	3.40
35	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	410.24	26,971.16	1.52	447.55	27,226.98	1.64	259.89	24,815.41	1.05
36	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-8.75	43.18	-20.26	-16.64	43.18	-38.54	-16.64	43.18	-38.54
37	भारत पेट्रो रिसोर्स जेपीडीए लिमिटेड	-0.31	-56.52	0.55	-0.16	-56.68	0.28	1.51	-55.18	-2.74
38	भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड	-22.81	3,392.33	-0.67	-2,252.55	3,339.79	-67.45	-2,065.40	2,599.42	-79.46
39	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8,788.73	48,355.45	18.18	1,870.10	51,767.10	3.61	26,673.50	74,695.56	35.71
40	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड	-53.69	-90.42	59.38	-13.43	-103.99	12.91	-46.64	-150.63	30.96
41	भारत संचार निगम लिमिटेड	-6,981.62	5,000.00	-139.63	-8,161.56	31,386.44	-26.00	-5,370.73	90,389.48	-5.94
42	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	0.19	4,806.58	0.00	0.08	4,806.66	0.00	2.67	4,809.32	0.06

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
43	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	328.70	2,921.98	11.25	243.99	2,877.99	8.48	517.00	3,022.83	17.10
44	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.01	0.07	-14.29	-0.11	-0.10	110.00	0.02	-0.08	-25.00
45	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
46	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
47	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद	9.00	130.13	6.92	9.06	139.17	6.51	1.77	141.82	1.25
48	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	-5.40	-147.36	3.66	-3.89	-151.25	2.57	-3.83	-155.08	2.47
49	बीपीसीएल- केआईएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड	-3.85	-4.65	82.80	0.99	-3.65	-27.12	3.82	0.17	2,247.06
50	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	690.53	3,280.79	21.05	134.23	3,201.64	4.19	-160.22	3,001.37	-5.34
51	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-97.64	-348.92	27.98	24.38	-324.54	-7.51	8.71	-315.83	-2.76
52	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	42.42	150.55	28.18	49.73	200.32	24.83	16.47	216.75	7.60
53	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	21.28	395.84	5.38	40.90	429.06	9.53	74.92	490.51	15.27
54	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	11.09	21.14	52.46	4.06	23.53	17.25	13.85	36.73	37.71
55	बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	-2.79	0.00	0.20	-2.60	-7.69	3.21	0.62	517.74
56	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	-0.70	95.03	-0.74	-3.00	94.03	-3.19	-3.69	95.95	-3.85

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
57	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	40.20	11.44	351.40	95.29	107.88	88.33	95.05	201.84	47.09
58	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,696.92	8,411.98	20.17	2,751.67	10,317.49	26.67	3,658.53	13,585.15	26.93
59	केंद्रीय कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	-24.38	-68.66	35.51	-13.01	-81.06	16.05	-13.67	-95.02	14.39
60	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	23.78	122.34	19.44	17.49	134.77	12.98	58.87	203.84	28.88
61	केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड	282.12	995.62	28.34	296.66	1,217.65	24.36	503.23	1,591.61	31.62
62	भारत के प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री	65.57	935.51	7.01	118.25	1,154.75	10.24	122.09	1,277.94	9.55
63	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	40.03	40.05	99.95	51.11	26.16	195.37	68.78	54.92	125.24
64	केंद्रीय भंडारण निगम	450.56	3,088.15	14.59	369.58	3,453.10	10.70	459.69	3,342.11	13.75
65	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	8.11	79.30	10.23	9.82	81.44	12.06	12.44	84.47	14.73
66	चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	4.61	60.82	7.58	6.28	63.97	9.82	6.28	63.97	9.82
67	चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1.29	203.44	0.63	-0.95	202.49	-0.47	-0.95	202.49	-0.47
68	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	-2.15	0.00	-0.01	-2.55	0.39	-0.01	-0.01	100.00
69	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड	-722.98	5,967.43	-12.12	-566.73	5,731.59	-9.89	427.60	9,558.36	4.47
70	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,342.42	2,790.14	48.11	3,533.81	6,280.87	56.26	2,711.25	8,592.87	31.55

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
71	चेय्युर इंफ्रा लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
72	छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
73	छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड	-0.10	0.05	-200.00	-0.06	0.08	-75.00	-0.03	0.05	-60.00
74	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	62.33	819.62	7.60	-118.59	751.05	-15.79	-94.88	694.63	-13.66
75	छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड	-0.28	592.81	-0.05	-0.24	720.03	-0.03	-0.22	721.51	-0.03
76	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	-0.01	0.00	-	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
77	सीआईएल नविकर्णीय ऊर्जा लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00
78	सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	-0.01	0.04	-25.00
79	कोल इंडिया लिमिटेड	11,201.57	16,357.95	68.48	14,802.31	16,706.45	88.60	15,766.83	17,325.73	91.00
80	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	-0.01	-0.01	100.00	-0.03	-0.04	75.00	-0.34	-0.38	89.47
81	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00
82	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	586.57	4,339.86	13.52	334.49	4,404.10	7.59	813.10	5,023.24	16.19
83	कॉनकॉर एयर लिमिटेड	-9.65	24.24	-39.81	-1.10	23.13	-4.76	3.13	26.26	11.92
84	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,062.34	10,777.30	9.86	1,169.08	11,244.98	10.40	1,230.79	11,812.34	10.42
85	क्रिएटिव संग्रहालय डिजाइनर	4.16	10.19	40.82	3.58	28.64	12.50	5.10	33.74	15.12
86	दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव एससी/एसटी वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	4.47	15.16	29.49	0.64	15.81	4.05	1.57	17.38	9.03

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
87	दामोदर घाटी निगम	634.89	6,738.82	9.42	704.24	7,684.66	9.16	811.44	8,795.08	9.23
88	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-16.15	15,994.76	-0.10	-19.70	15,975.94	-0.12	-29.59	15,945.76	-0.19
89	दिल्ली मेट्रो लास्ट माइल सर्विसेज लिमिटेड	-0.01	0.07	-14.29	-0.01	0.06	-16.67	0.00	0.06	0.00
90	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-3,815.11	24,130.39	-15.81	-1,569.95	23,359.97	-6.72	-4,913.21	9,952.73	-49.37
91	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.17	12.98	1.31	0.81	13.79	5.87	4.13	17.92	23.05
92	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
93	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
94	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन	1.43	33.35	4.29	2.13	45.78	4.65	11.76	82.07	14.33
95	दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.03	2.02	1.49	0.41	0.54	75.93	2.42	2.95	82.03
96	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	105.84	877.43	12.06	40.61	681.12	5.96	79.56	760.69	10.46
97	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	-2.10	0.00	-0.01	-2.48	0.40	2.10	-0.01	-21,000.00
98	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	-1,060.66	1,813.71	-58.48	616.42	2,543.87	24.23	251.59	2,977.64	8.45
99	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	-0.44	269.99	-0.16	-3.58	266.41	-1.34	0.02	266.43	0.01
100	ईसीजीसी लिमिटेड	875.16	15,375.28	5.69	2,164.25	11,386.60	19.01	2,159.05	14,064.91	15.35
101	एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड	50.41	211.79	23.80	64.55	260.12	24.82	101.95	339.79	30.00
102	एडसिल विद्युत निगम लिमिटेड							-0.18	-0.13	138.46

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
103	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	220.78	1,255.73	17.58	269.70	1,433.07	18.82	525.04	1,820.75	28.84
104	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	-65.06	83.46	-77.95	0.44	83.90	0.52	-61.36	22.56	-271.99
105	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	344.41	1,925.05	17.89	342.15	2,105.66	16.25	356.99	2,311.28	15.45
106	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	40.36	212.00	19.04	38.38	218.53	17.56	64.92	257.41	25.22
107	भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड	35.74	666.50	5.36	46.82	712.75	6.57	37.85	750.03	5.05
108	भारतीय खाद्य निगम	0.00	8,004.55	0.00	0.00	9,958.86	0.00	0.00	10,136.12	0.00
109	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	-3.73	33.29	-11.20	-2.57	38.92	-6.60	0.63	39.55	1.59
110	गेल (इंडिया) लिमिटेड	10,363.97	55,586.79	18.64	5,301.51	55,376.64	9.57	8,836.48	64,179.40	13.77
111	गेल गैस लिमिटेड	283.36	2,430.75	11.66	297.04	2,953.41	10.06	323.17	3,142.82	10.28
112	गेल मँगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड							319.30	713.00	44.78
113	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	189.53	1,248.60	15.18	228.12	1,413.82	16.14	357.27	1,673.44	21.35
114	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2,005.74	1,39,087.47	1.44	6,312.50	1,50,108.59	4.21	6,497.30	1,72,959.48	3.76
115	घोसरपल्ली इंडीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
116	ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड	0.71	529.96	0.13	6.87	651.85	1.05	10.77	653.28	1.65

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
117	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-6.67	-11.38	58.61	-4.75	-18.13	26.20	-11.07	-27.23	40.65
118	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	101.09	1,148.40	8.80	154.54	1,246.43	12.40	271.32	1,437.46	18.87
119	गोला-बी रामगढ़ बी ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.00	0.01	0.00
120	गोल्डमोहर डिज़ाइन एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	-85.07	27.72	-306.89	-85.07	27.72	-306.89	-85.07	27.72	-306.89
121	माल एवं सेवा कर नेटवर्क	20.49	81.66	25.09	-68.26	13.08	-521.87	0.00	13.08	0.00
122	सरकारी ई-मार्केट प्लेस	104.07	98.83	105.30	279.94	551.18	50.79	666.89	1,217.99	54.75
123	ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड				0.02	0.12	16.67	0.02	0.14	14.29
124	ग्रिड नियंत्रण ऑफ इंडिया लिमिटेड	44.39	508.19	8.73	58.18	561.83	10.36	81.21	636.41	12.76
125	हसन मँगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड	-40.00	307.60	-13.00	-30.83	276.77	-11.14	11.65	288.39	4.04
126	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-256.07	-844.07	30.34	-230.85	-1,080.66	21.36	-275.19	-1,361.59	20.21
127	हेमिस्फेर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	-14.86	372.33	-3.99	-6.47	365.87	-1.77	-9.82	356.05	-2.76
128	हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.91	46.71	4.09	3.30	50.02	6.60	7.07	57.06	12.39
129	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी	447.52	6,579.27	6.80	397.26	6,976.53	5.69	344.82	7,321.35	4.71

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
130	एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड	2.21	107.80	2.05	-68.70	54.29	-126.54	4.50	58.79	7.65
131	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	5,086.50	19,264.00	26.40	5,811.17	23,506.17	24.72	7,595.04	29,046.42	26.15
132	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	-16.21	-623.45	2.60	-53.88	-677.33	7.95	-36.13	-713.46	5.06
133	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	88.39	57.16	154.64	15.74	354.86	4.44	-4.47	348.84	-1.28
134	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	373.78	805.61	46.40	295.31	851.99	34.66	295.41	2,073.43	14.25
135	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2.52	138.40	1.82	10.29	148.69	6.92	30.72	179.41	17.12
136	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	-6.13	-78.81	7.78	-5.11	-83.92	6.09	1.23	-82.70	-1.49
137	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-23.24	53.23	-43.66	-50.22	7.89	-636.50	-55.32	11.19	-494.37
138	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6,382.63	38,052.04	16.77	-8,974.03	27,088.43	-33.13	14,693.83	40,404.77	36.37
139	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	-12.25	8.63	-141.95	-7.68	0.94	-817.02	-10.87	-9.92	109.58
140	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	1.52	52.06	2.92	8.21	52.54	15.63	9.52	62.06	15.34
141	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	50.78	-547.31	-9.28	65.24	-478.94	-13.62	118.82	-351.27	-33.83
142	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	27.77	146.06	19.01	23.15	166.00	13.95	26.16	179.80	14.55
143	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	547.34	636.42	86.00	-10.23	624.81	-1.64	-16.23	608.39	-2.67
144	एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड	17.60	30.70	57.33	25.01	42.55	58.78	37.07	66.72	55.56
145	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	408.23	768.91	53.09	39.77	658.83	6.04	172.82	814.79	21.21

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
146	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड	1.37	3.19	42.95	-0.22	2.97	-7.41	-0.22	2.97	-7.41
147	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	0.21	36.78	0.57	0.20	37.03	0.54	0.80	37.82	2.12
148	एचएमटी लिमिटेड	38.36	426.66	8.99	7.06	433.93	1.63	24.42	458.78	5.32
149	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	-145.73	-1,684.73	8.65	-131.65	-1,816.72	7.25	-155.24	-1,972.03	7.87
150	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड	1.05	-2,682.28	-0.04	1.50	-2,680.79	-0.06	2,680.79	0.00	0.00
151	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	-2.84	39.82	-7.13	-20.34	65.48	-31.06	-30.05	79.43	-37.83
152	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-84.81	-613.86	13.82	-70.38	-682.42	10.31	-70.38	-682.42	10.31
153	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	1,716.60	11,343.13	15.13	1,701.62	12,548.29	13.56	2,116.74	13,888.19	15.24
154	एचपीसीएल बायो फ्यूल्स लिमिटेड	-66.95	206.92	-32.36	-41.41	393.49	-10.52	-8.00	415.18	-1.93
155	एचपीसीएल एलएनजी लिमिटेड	-14.09	1,230.54	-1.15	-7.48	1,223.15	-0.61	-10.35	1,212.80	-0.85
156	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	-22.37	5,646.75	-0.40	-299.57	9,347.18	-3.20	-34.12	13,913.06	-0.25
157	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	25.18	143.61	17.53	22.67	162.22	13.97	39.56	193.25	20.47
158	आईटीआई लिमिटेड	121.06	933.52	12.97	-360.10	1,056.58	-34.08	-569.06	960.89	-59.22
159	आईएफसीआई फेक्टर्स लिमिटेड	-9.67	106.44	-9.08	-4.22	103.59	-4.07	-87.94	13.92	-631.75
160	आईएफसीआई वित्तीय सेवाएँ लिमिटेड	1.07	69.74	1.53	-3.82	65.44	-5.84	-1.91	63.66	-3.00
161	आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	8.32	506.80	1.64	16.13	522.89	3.08	9.99	507.93	1.97

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
162	आईएफसीआई लिमिटेड	-1,991.33	445.45	-447.04	-287.58	626.10	-45.93	128.25	1,214.20	10.56
163	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड	-2.97	166.74	-1.78	5.42	172.23	3.15	1.03	173.45	0.59
164	आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड	-0.66	4.13	-15.98	-0.66	3.43	-19.24	-0.29	3.13	-9.27
165	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड	0.00	1.98	0.00	0.01	1.99	0.50	0.03	2.01	1.49
166	आईएफ एनसीई सिक्क्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड	0.31	28.96	1.07	0.39	29.35	1.33	1.15	30.48	3.77
167	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	2.16	27.14	7.96	2.04	29.16	7.00	-2.98	26.06	-11.44
168	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	3.74	22.93	16.31	1.56	24.47	6.38	1.91	25.73	7.42
169	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	514.26	10,731.19	4.79	1,075.60	11,891.35	9.05	1,551.61	13,714.71	11.31
170	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीक्यूटिव सेंटर लिमिटेड	0.94	2,453.86	0.04	0.30	2,454.17	0.01	0.30	2,454.17	0.01
171	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड	60.11	5,778.55	1.04	236.39	6,234.03	3.79	233.03	6,443.57	3.62
172	इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	6.38	10.00	63.80	-0.02	10.00	-0.20	-0.02	10.00	-0.20
173	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड	-159.62	473.06	-33.74	20.16	892.98	2.26	34.24	1,177.21	2.91
174	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	6.86	319.26	2.15	60.33	376.35	16.03	71.86	424.96	16.91

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
175	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	-52.83	1,971.87	-2.68	232.22	2,236.72	10.38	168.69	2,404.38	7.02
176	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	8.42	174.35	4.83	8.42	174.35	4.83	8.42	174.35	4.83
177	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	33.76	117.85	28.65	20.81	128.12	16.24	12.81	134.56	9.52
178	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24,184.10	1,29,321.49	18.70	8,241.82	1,33,561.26	6.17	39,618.84	1,76,531.90	22.44
179	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	663.69	1,883.88	35.23	1,005.88	2,478.40	40.59	1,111.26	3,229.97	34.40
180	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	6,089.84	40,996.34	14.85	6,337.01	45,470.32	13.94	6,412.10	49,178.57	13.04
181	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	633.53	4,962.72	12.77	864.63	5,537.19	15.61	1,252.23	8,161.68	15.34
182	इंडियन वैक्सीन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-3.70	4.54	-81.50	1.57	6.12	25.65	0.12	6.24	1.92
183	इंडो-रशियन हेलिकोप्टर्स लिमिटेड	-0.33	7.59	-4.35	-0.03	7.56	-0.40	-0.19	7.37	-2.58
184	अंतर्देशीय एवं तटीय शिपिंग लिमिटेड	-0.89	-0.19	468.42	-0.68	-0.87	78.16	-0.97	-1.84	52.72
185	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	22.26	-367.63	-6.06	4.86	-362.77	-1.34	7.01	-360.41	-1.95
186	आईओसी ग्लोबल कैपिटल मैनेजमेंट आईएफएससी लिमिटेड							-2.85	3.41	-83.58
187	इरकॉन अकालोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.31	51.80	0.60	7.06	63.09	11.19

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
188	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड				0.00	6.77	0.00	10.91	67.33	16.20
189	इरकॉन दावणगरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	5.87	196.92	2.98	26.37	223.29	11.81	23.88	247.17	9.66
190	इरकॉन गुडगांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	-0.01	18.40	-0.05	3.67	75.07	4.89	4.14	96.21	4.30
191	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड				0.77	82.99	0.93	2.71	85.90	3.15
192	इरकॉन इंप्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	5.30	164.94	3.21	5.33	170.26	3.13	8.86	176.61	5.02
193	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	544.32	4,620.96	11.78	776.83	5,178.48	15.00	862.90	5,771.76	14.95
194	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.94	0.00	1.53	59.43	2.57
195	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	-24.62	169.41	-14.53	-17.17	152.07	-11.29	-7.76	139.44	-5.57
196	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड				-0.29	54.71	-0.53	-0.31	126.75	-0.24
197	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	-12.05	61.70	-19.53	-14.34	47.36	-30.28	-6.39	40.97	-15.60
198	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	60.16	239.90	25.08	21.74	288.21	7.54	48.12	336.32	14.31
199	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	555.51	1,548.15	35.88	808.13	2,106.05	38.37	1,012.22	2,853.62	35.47
200	आईआरईएल आईडीसीओएल लिमिटेड	-0.05	1.87	-2.67	-0.12	3.75	-3.20	-0.01	3.74	-0.27
201	आईटीपीओ सर्विसेज लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
202	जे एंड के खनिज विकास निगम लिमिटेड	-0.90	7.83	-11.49	-1.24	6.59	-18.82	-12.84	-6.25	205.44
203	जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.48	281.49	-0.17	0.28	281.49	0.10	0.22	362.87	0.06
204	जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.86	-0.81	106.17
205	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	2.31	165.42	1.40	4.60	170.02	2.71	3.85	173.86	2.21
206	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	2.02	92.87	2.18	5.40	111.53	4.84	2.52	552.56	0.46
207	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
208	झारखंड राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड	-0.01	-0.08	12.50	-0.01	-0.09	11.11	-0.01	-0.10	10.00
209	जोडा बारबिल ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.00	0.01	0.00
210	जोगीघोपा लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
211	कल्लम ट्रांस्को लिमिटेड							-0.52	-0.47	110.64
212	कांकाणी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.00	0.05	0.00
213	कर्मयोगी भारत				1.97	31.97	6.16	6.08	43.04	14.13
214	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	24.66	239.09	10.31	24.89	259.93	9.58	11.32	268.91	4.21
215	कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन	1.32	144.46	0.91	3.83	148.29	2.58	8.99	157.56	5.71

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
216	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	-0.70	-1.91	36.65	-0.68	-2.60	26.15	-0.58	-3.18	18.24
217	कावारत्ती स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00
218	खावड़ा II-डी ट्रांसमिशन लिमिटेड				-0.02	0.03	-66.67	-0.02	0.03	-66.67
219	खावड़ा IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.55	-0.50	110.00
220	खावड़ा IV ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.34	-0.29	117.24
221	खावड़ा IV-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.42	-0.37	113.51
222	खावड़ा पीसी1 एण्ड3 ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.00	0.01	0.00
223	खावड़ा V ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.43	-0.38	113.16
224	केआईओसीएल लिमिटेड	313.41	2,143.64	14.62	-97.67	2,002.04	-4.88	-83.31	1,918.50	-4.34
225	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	-339.73	2,551.88	-13.31	-334.59	2,409.84	-13.88	-432.95	2,160.69	-20.04
226	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	-1.92	0.00	-0.01	-2.28	0.44	2.28	-0.01	-22,800.00
227	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.06	3,758.62	0.00	0.75	3,759.35	0.02	-0.01	3,759.34	0.00
228	कौकण एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड	384.70	691.12	55.66	-448.26	573.88	-78.11	-246.57	324.73	-75.93
229	कौकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-135.08	1,458.68	-9.26	278.93	1,792.43	15.56	301.74	2,021.81	14.92

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
230	कुमारकृष्णा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	4.16	27.29	15.24	7.64	33.96	22.50	8.18	37.27	21.95
231	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड	23.56	388.64	6.06	22.80	411.43	5.54	22.80	411.43	5.54
232	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	-0.20	1,440.50	-0.01	-0.22	1,724.41	-0.01	-0.36	1,724.41	-0.02
233	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.01	160.21	0.01	-161.28	-0.30	53,760.00	-0.25	1.01	-24.75
234	लुहरी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड				-0.51	-0.46	110.87	-0.59	-1.05	56.19
235	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	162.05	-505.39	-32.06	185.33	-287.07	-64.56	5.55	-189.72	-2.93
236	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-0.02	-5.99	0.33	-0.03	-6.02	0.50	-0.04	-6.06	0.66
237	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	-0.02	89.07	-0.02	-0.43	88.64	-0.49	-1.58	379.56	-0.42
238	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	8,480.51	8,212.55	103.26	13,475.21	13,308.02	101.26	11,845.40	16,106.26	73.55
239	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-2,602.59	-18,656.46	13.95	-2,910.74	-20,842.90	13.97	-3,302.19	-23,662.80	13.96
240	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-625.87	-757.51	82.62	-122.05	-879.56	13.88	-122.05	-879.56	13.88
241	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-237.42	4,868.78	-4.88	-166.22	4,156.16	-4.00	-353.39	4,441.59	-7.96
242	महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	3.41	514.13	0.66	25.89	359.59	7.20	24.97	722.27	3.46
243	एमएएमसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-0.09	-1.66	5.42	-0.09	-1.75	5.14	-0.10	-1.86	5.38
244	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	-1.87	0.00	-0.01	-2.23	0.45	1.88	-0.01	-18,800.00

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
245	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	2,955.27	7,196.34	41.07	2,638.39	9,834.66	26.83	3,595.94	13,251.49	27.14
246	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-250.31	-470.99	53.15	-42.91	-513.90	8.35	-42.91	-513.90	8.35
247	मसकानी पारादीप रोड विकास लिमिटेड							-1.14	26.52	-4.30
248	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	586.47	3,321.31	17.66	1,072.72	4,177.51	25.68	1,845.43	5,570.68	33.13
249	मेकॉन लिमिटेड	13.70	382.93	3.58	31.01	394.44	7.86	24.52	439.97	5.57
250	मेरठ शामली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड				-0.44	-0.39	112.82	-0.56	-0.95	58.95
251	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	0.20	5.69	3.51	0.32	5.95	5.38	0.25	6.05	4.13
252	खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	20.21	679.06	2.98	13.94	662.77	2.10	80.41	737.17	10.91
253	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	176.31	1,190.72	14.81	155.88	1,286.19	12.12	91.26	1,319.44	6.92
254	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	0.09	74.13	0.12	0.71	74.84	0.95	0.66	75.50	0.87
255	एमएमटीसी लिमिटेड	-241.93	193.40	-125.09	1,076.07	1,264.83	85.08	68.21	1,354.36	5.04
256	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	0.86	41.55	2.07	0.18	41.73	0.43	1.26	43.00	2.93
257	मॉयल लिमिटेड	376.98	2,141.51	17.60	250.59	2,244.32	11.17	293.34	2,390.18	12.27
258	एमपीसीओएन लिमिटेड	1.20	8.45	14.20	4.41	11.02	40.02	5.90	15.48	38.11
259	एमएसटीसी लिमिटेड	200.09	465.48	42.99	239.23	594.03	40.27	171.91	664.57	25.87
260	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-19.49	4,313.71	-0.45	-28.14	4,679.08	-0.60	-35.40	8,433.14	-0.42
261	मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड	7.57	235.19	3.22	87.42	321.74	27.17	133.70	430.26	31.07

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
262	म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड	18.10	6,549.75	0.28	73.35	7,575.66	0.97	558.78	9,273.22	6.03
263	नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड	-12.82	-8.26	155.21	-6.08	0.88	-690.91	-3.07	-2.14	143.46
264	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	2,951.97	12,184.34	24.23	1,544.49	13,238.45	11.67	2,059.95	14,571.66	14.14
265	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	30.56	2,068.65	1.48	30.36	2,099.28	1.45	30.82	2,145.43	1.44
266	भारतीय राष्ट्रीय साइकिल निगम लिमिटेड	-21.26	-671.48	3.17	-21.09	-692.57	3.05	-21.63	-714.20	3.03
267	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	47.04	1,829.50	2.57	79.91	2,260.27	3.54	138.83	2,949.66	4.71
268	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम				527.34	5,392.32	9.78	573.93	5,849.62	9.81
269	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	7.49	24.39	30.71	10.00	34.39	29.08	19.09	53.47	35.70
270	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	108.20	2,279.03	4.75	456.10	2,771.32	16.46	64.74	2,698.58	2.40
271	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	-6.74	21.76	-30.97	5.01	26.77	18.71	10.91	42.03	25.96
272	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	0.02	1.21	1.65	0.02	1.24	1.61	0.04	1.27	3.15
273	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	6.20	496.22	1.25	5.09	501.28	1.02	8.92	508.52	1.75
274	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	-1.57	76.76	-2.05	5.21	81.63	6.38	5.47	85.20	6.42

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
275	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	83.93	13,351.85	0.63	53.79	14,750.79	0.36	80.16	15,319.09	0.52
276	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	113.29	410.39	27.61	224.70	601.10	37.38	181.66	715.30	25.40
277	नेशनल हाईवेज इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	7.04	15.81	44.53	0.55	16.36	3.36	0.92	17.30	5.32
278	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक.	46.17	741.86	6.22	149.77	892.24	16.79	196.82	1,089.36	18.07
279	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-1,674.72	2,766.32	-60.54	-3,865.40	-949.15	407.25	-186.90	-995.42	18.78
280	राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि ट्रस्टी लिमिटेड	0.03	-0.10	-30.00	0.09	-0.01	-900.00	0.13	0.12	108.33
281	राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड	-8.13	-228.52	3.56	31.06	-197.45	-15.73	62.15	-135.31	-45.93
282	राष्ट्रीय भूमि मुद्राकरण निगम लिमिटेड				2.99	152.99	1.95	8.97	161.96	5.54
283	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	67.64	3,039.34	2.23	65.26	3,285.48	1.99	53.13	3,410.99	1.56
284	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	35.10	241.48	14.54	45.25	280.26	16.15	74.79	268.94	27.81
285	भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लिमिटेड	0.05	9.50	0.53	-3.72	5.78	-64.36	-1.38	4.40	-31.36
286	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	15.92	875.22	1.82	14.99	890.22	1.68	19.99	920.18	2.17

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
287	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	48.78	2,185.31	2.23	47.61	2,235.33	2.13	47.09	2,294.80	2.05
288	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	24.45	1,128.22	2.17	24.29	1,152.51	2.11	25.67	1,193.07	2.15
289	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	10.76	668.26	1.61	53.30	712.96	7.48	73.64	742.45	9.92
290	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	108.23	1,131.70	9.56	110.48	1,210.03	9.13	126.56	1,304.16	9.70
291	राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड	-310.06	892.21	-34.75	-310.06	892.21	-34.75	-310.06	892.21	-34.75
292	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	182.86	1,774.75	10.30	231.13	1,914.54	12.07	344.36	2,139.00	16.10
293	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड	4.26	32.97	12.92	7.24	37.70	19.20	20.70	54.40	38.05
294	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	0.02	0.98	2.04	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00
295	नेपा लिमिटेड	-59.90	119.72	-50.03	-105.80	13.92	-760.06	-126.76	-112.84	112.34
296	एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.92	-0.87	105.75
297	एनईआरजीएस-I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.36	-0.31	116.13
298	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड	-1.21	60.74	-1.99	-1.21	60.74	-1.99	-1.21	60.74	-1.99
299	नई दिल्ली नगर परिषद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2.36	135.96	1.74	2.36	135.96	1.74	2.36	135.96	1.74
300	न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड	342.99	1,441.77	23.79	467.03	6,606.40	7.07	599.12	7,198.47	8.32

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
301	नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड	-0.33	3,870.14	-0.01	-0.47	4,386.63	-0.01	-1.48	5,156.84	-0.03
302	एनएचडीसी लिमिटेड	512.96	5,644.67	9.09	774.43	5,693.27	13.60	812.24	5,668.68	14.33
303	एनएचपीसी लिमिटेड	3,537.71	32,119.85	11.01	3,833.79	34,278.66	11.18	3,743.94	36,318.00	10.31
304	एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड				-1.59	18.41	-8.64	0.97	19.38	5.01
305	एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड				0.36	11.87	3.03	0.35	12.22	2.86
306	एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड				2.26	438.76	0.52	1.00	446.91	0.22
307	एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड							-0.16	49.84	-0.32
308	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	1,236.78	13,806.64	8.96	1,248.24	14,638.86	8.53	1,846.58	15,993.91	11.55
309	एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड							-0.06	0.04	-150.00
310	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	211.28	2,625.16	8.05	278.65	2,794.40	9.97	129.16	2,802.98	4.61
311	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन	1.02	6.04	16.89	-1.48	4.56	-32.46	-0.03	4.53	-0.66
312	एनएमडीसी लिमिटेड	9,398.48	34,843.97	26.97	5,529.31	22,332.31	24.76	5,631.89	25,405.78	22.17
313	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	-0.01	0.04	-25.00	0.00	2,930.61	0.00	-1,560.32	15,488.26	-10.07
314	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड	-2.52	181.66	-1.39	-3.12	178.54	-1.75	-3.89	174.65	-2.23

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
315	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	148.89	5,908.70	2.52	396.90	5,935.30	6.69	548.12	6,217.35	8.82
316	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	-28.33	-40.77	69.49	-1.60	-42.24	3.79	0.86	-41.38	-2.08
317	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड	-4.63	-21.98	21.06	4.28	14.14	30.27	1.28	20.15	6.35
318	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	4,857.05	7,871.34	61.71	6,973.99	11,176.47	62.40	8,318.13	15,375.54	54.10
319	एनपीसीआई एल इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.04	1.45	2.76	0.05	1.50	3.33	0.07	1.57	4.46
320	एनआरटीयू फाउंडेशन	0.22	1.22	18.03	-2.46	0.19	-1,294.74	-0.15	0.04	-375.00
321	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड	1.90	7.29	26.06	3.04	9.76	31.15	3.75	12.59	29.79
322	एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	-2.05	-2.76	74.28	-0.56	-3.32	16.87	-0.03	-3.35	0.90
323	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाइ कंपनी लिमिटेड	0.29	55.58	0.52	0.25	20.27	1.23	0.04	20.31	0.20
324	एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड				173.08	4,894.05	3.54	370.47	6,264.52	5.91
325	एनटीपीसी लिमिटेड	16,111.42	1,22,357.81	13.17	17,196.73	1,33,825.19	12.85	18,079.39	1,46,615.56	12.33
326	एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	-3.43	150.66	-2.28
327	एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	0.11	727.78	0.02	-1.37	1,089.69	-0.13	-25.16	1,414.53	-1.78

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
328	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	150.26	562.57	26.71	175.90	718.96	24.47	160.94	854.40	18.84
329	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6,394.78	46,147.08	13.86	5,146.01	50,058.89	10.28	6,522.66	56,776.56	11.49
330	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	3,561.56	8,288.08	42.97	3,702.79	11,326.94	32.69	2,160.11	13,826.00	15.62
331	ओडिशा इंफ्रापावर लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00
332	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	40,305.74	2,37,132.13	17.00	38,828.87	2,57,829.88	15.06	40,525.97	3,05,960.55	13.25
333	ऑयल इंडिया लिमिटेड	3,887.31	29,358.52	13.24	6,810.40	33,833.27	20.13	5,551.85	43,590.46	12.74
334	ओम्निबस औद्योगिक विकास निगम दमन, दीव एवं दादरा एवं नगर हवेली लिमिटेड	24.50	232.93	10.52	44.46	277.31	16.03	48.25	324.44	14.87
335	ओएनजीसी पेट्रो एडिंशंस लिमिटेड	-534.66	4,583.72	-11.66	-4,155.49	620.80	-669.38	-3,456.10	-2,698.11	128.09
336	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	3,247.53	35,681.78	9.10	3,062.02	40,713.06	7.52	1,796.06	44,211.75	4.06
337	ओएनजीसी विदेश रोबुमा लिमिटेड	-610.63	5,402.20	-11.30	2,465.82	9,100.29	27.10	-2,581.20	7,692.05	-33.56
338	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	0.00	-0.07	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.00	-0.07	0.00
339	ओवीएल ओवरसीज आईएफएससी लिमिटेड							-0.43	1.58	-27.22
340	पारादीप ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.00	0.01	0.00
341	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	-0.03	1,670.39	0.00	-0.51	2,345.55	-0.02	-0.01	2,922.47	0.00

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
342	पवन हंस लिमिटेड	-13.13	970.01	-1.35	-23.56	902.55	-2.61	-23.56	902.55	-2.61
343	पीईसी लिमिटेड	-314.29	-2,223.98	14.13	-243.93	-2,466.86	9.89	-339.59	-2,835.75	11.98
344	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	37.68	111.31	33.85	63.81	162.99	39.15	158.67	239.39	66.28
345	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.16	-1.71	-9.36	0.34	-1.40	-24.29	0.31	-1.09	-28.44
346	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10,021.90	59,350.28	16.89	11,605.47	68,202.23	17.02	14,367.02	79,203.49	18.14
347	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	17,093.76	76,151.57	22.45	15,333.02	82,832.96	18.51	15,474.61	83,946.03	18.43
348	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड	0.91	115.57	0.79	10.25	118.57	8.64	20.69	124.02	16.68
349	पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.01	62.34	-0.02	0.01	77.94	0.01	-0.04	99.90	-0.04
350	पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
351	पावरग्रिड भइला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.27	-0.26	103.85
352	पावरग्रिड भइला ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.15	19.75	0.76	-0.09	31.56	-0.29	-0.29	72.27	-0.40
353	पावरग्रिड भइला-III ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00
354	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.07	89.43	-0.08	9.18	118.31	7.76	23.22	114.08	20.35

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
355	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.03	179.97	-0.02	2.31	234.28	0.99	18.57	235.92	7.87
356	पावरग्रिड बीकानेर नीमराना ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.01	0.00	0.00
357	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-0.02	22.19	-0.09	-0.30	99.67	-0.30	22.02	151.18	14.57
358	पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
359	पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड				-9.33	0.67	-1,392.54	8.08	96.49	8.37
360	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.31	-0.26	119.23	-0.12	-0.38	31.58	-0.27	9.35	-2.89
361	पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड				-0.01	0.04	-25.00	-0.01	0.04	-25.00
362	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.26	143.26	1.58	12.86	145.69	8.83	24.62	147.04	16.74
363	पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.01	0.00	-0.77	-0.77	100.00	10.68	105.90	10.08
364	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	51.29	422.30	12.15	49.69	427.00	11.64	53.20	402.20	13.23
365	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	17.12	101.60	16.85	18.97	120.57	15.73	26.68	99.94	26.70
366	पावरग्रिड खावड़ा II-बी ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.00	0.05	0.00	-0.19	25.86	-0.73

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
367	पावरग्रिड खावड़ा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.00	0.05	0.00	-0.01	0.04	-25.00
368	पावरग्रिड खावड़ा री ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड				0.00	0.05	0.00	-1.12	11.64	-9.62
369	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	5.96	203.84	2.92	26.84	206.88	12.97	48.41	213.47	22.68
370	पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.00	0.01	0.00
371	पावरग्रिड केपीएस 2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड				0.00	0.05	0.00	-0.07	1.23	-5.69
372	पावरग्रिड केपीएस 3 ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.00	0.05	0.00	-0.06	6.23	-0.96
373	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	191.62	692.24	27.68	223.55	706.53	31.64	213.00	672.42	31.68
374	पावरग्रिड मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.02	129.69	-0.02	-0.17	194.95	-0.09	28.62	234.41	12.21
375	पावरग्रिड मेवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.39	-0.34	114.71
376	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	38.09	254.51	14.97	41.11	245.01	16.78	39.86	239.16	16.67
377	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.01	0.00	-0.38	-0.37	102.70	-0.79	98.83	-0.80

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
378	पावरग्रिड नीमराना बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.00	0.01	0.00
379	पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड				-0.22	-0.17	129.41	-1.29	124.30	-1.04
380	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	7.50	264.27	2.84	222.39	488.66	45.51	54.63	497.14	10.99
381	पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00
382	पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड				-0.74	-0.69	107.25	0.18	-0.51	-35.29
383	पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.01	0.58	-1.72	-0.01	24.47	-0.04	2.84	34.32	8.28
384	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.06	108.06	-0.06	6.79	147.95	4.59	32.50	189.65	17.14
385	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.12	46.88	0.26	-0.13	79.40	-0.16	-0.38	141.02	-0.27
386	पावरग्रिड सदरन इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-37.51	639.79	-5.86	129.91	751.27	17.29	128.93	730.60	17.65
387	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	-0.33	8.67	-3.81	-0.06	8.61	-0.70	313.66	779.78	40.22
388	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	16.76	25.02	66.99	14.83	28.57	51.91	14.39	28.64	50.24
389	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	20.16	195.00	10.34	29.16	195.83	14.89	26.24	191.31	13.72

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
390	पावरग्रिड वतमान ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.00	0.01	0.00
391	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.01	-19.42	0.05	-0.01	-19.43	0.05	-0.01	-19.44	0.05
392	प्राइज़ पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	-5.79	109.53	-5.29	-36.49	73.04	-49.96	-51.98	21.05	-246.94
393	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	10.81	167.40	6.46	3.58	167.74	2.13	10.62	174.78	6.08
394	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	-0.01	2.26	-0.44	-0.01	2.25	-0.44	-0.03	2.22	-1.35
395	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	-5.93	160.69	-3.69	-0.91	158.98	-0.57	0.14	159.09	0.09
396	रेल विकास निगम लिमिटेड	1,087.21	5,631.41	19.31	1,267.97	6,479.15	19.57	1,462.95	7,867.28	18.60
397	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	208.34	1,516.02	13.74	187.38	1,636.50	11.45	246.21	1,827.24	13.47
398	राजस्थान इग्नेस एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-2.13	-101.40	2.10	-1.06	-102.46	1.03	-1.06	-102.46	1.03
399	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	-8.46	72.94	-11.60	-10.06	62.86	-16.00	3.16	65.61	4.82
400	राजस्थान IV ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.41	-0.36	113.89
401	राजस्थान IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.34	-0.29	117.24

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
402	राजस्थान IV एच1 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.52	-0.47	110.64
403	राजस्थान पाट I पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.67	-0.62	108.06
404	रामकनानी बी-पानागढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.00	0.01	0.00
405	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.75	-15.63	4.80	-1.13	-16.81	6.72	-1.38	-18.05	7.65
406	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	704.36	3,889.23	18.11	967.15	4,598.32	21.03	227.74	4,616.40	4.93
407	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	913.19	3,174.55	28.77	-2,858.74	391.24	-730.69	-4,848.86	-4,538.29	106.84
408	रेटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.43	186.27	-0.23	6.32	375.89	1.68	4.04	674.81	0.60
409	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	-201.23	-278.58	72.23	-179.60	-69.53	258.31	1,708.37	1,638.84	104.24
410	आरईसी लिमिटेड	10,045.92	50,427.20	19.92	11,054.64	57,121.27	19.35	14,019.21	68,224.75	20.55
411	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	53.03	328.58	16.14	139.79	440.92	31.70	149.64	567.16	26.38
412	आरईएमसी लिमिटेड	45.32	216.24	20.96	59.04	235.37	25.08	81.22	228.40	35.56
413	रिचर्डसन एवं कूडास (1972) लिमिटेड	19.35	247.31	7.82	12.72	260.04	4.89	18.31	255.09	7.18
414	राइट्स लिमिटेड	497.10	2,399.26	20.72	530.54	2,503.04	21.20	454.11	2,506.87	18.11

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
415	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड	0.00	-0.02	0.00	6.72	29.70	22.63	6.72	29.70	22.63
416	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	6.98	794.77	0.88	14.08	908.81	1.55	23.51	1,022.17	2.30
417	सेल रिफ़ैक्टरी कंपनी लिमिटेड	19.66	120.38	16.33	17.75	125.12	14.19	20.17	139.19	14.49
418	सखीगोपाल इंडीगैटेड पावर कंपनी लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
419	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	10.85	-30.52	-35.55	11.30	-19.23	-58.76	16.83	-2.41	-698.34
420	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	7.58	8.08	93.81	0.76	8.85	8.59	-31.14	-22.29	139.70
421	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	689.19	4,854.23	14.20	1,779.25	6,416.14	27.73	911.04	6,943.95	13.12
422	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.10	800.70	-0.01	-0.41	800.28	-0.05	-0.18	800.11	-0.02
423	एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड	21.35	91.73	23.27	13.89	95.08	14.61	20.07	112.71	17.81
424	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड	0.00	0.01	0.00	35.58	2,886.43	1.23	47.49	2,933.85	1.62
425	शॉगटॉग पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.57	-0.52	109.62
426	सिडयोग कॉन्कॉर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	0.21	90.28	0.23	1.61	91.90	1.75	5.51	97.40	5.66
427	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड				-0.72	-0.67	107.46	0.18	-0.49	-36.73
428	सियोट ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
429	एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड				-10.56	1,289.04	-0.82	2.13	3,291.13	0.06

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
430	एसजेवीएन लिमिटेड	977.52	13,128.61	7.45	1,363.45	13,821.97	9.86	908.40	14,030.28	6.47
431	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड	-1.14	2,511.29	-0.05	-1.16	2,510.13	-0.05	-0.91	2,509.23	-0.04
432	भारतीय सौर ऊर्जा निगम	240.32	2,060.46	11.66	315.65	2,376.31	13.28	436.03	2,811.76	15.51
433	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,544.87	5,442.08	28.39	2,498.19	6,936.01	36.02	6,971.06	14,465.53	48.19
434	एसटीसीएल लिमिटेड	7.12	-4,557.11	-0.16	-1.10	-4,558.19	0.02	-1.13	-4,559.38	0.02
435	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	12,015.04	51,484.42	23.34	1,903.07	51,763.72	3.68	2,733.11	54,005.01	5.06
436	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	136.55	4,552.99	3.00	178.11	5,956.02	2.99	264.27	6,444.54	4.10
437	स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	1.57	36.63	4.29	4.95	41.49	11.93	8.12	49.48	16.41
438	स्टॉक होल्डिंग सिक्स्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड	-2.30	12.93	-17.79	-1.86	14.24	-13.06	-1.26	13.17	-9.57
439	सूटी टेक ऑल्लेंस लिमिटेड	-0.01	-0.32	3.13	-0.01	-0.33	3.03	-0.01	-0.34	2.94
440	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन	3.89	310.20	1.25	28.85	339.54	8.50	26.20	364.37	7.19
441	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	0.08	-40.65	-0.20	-2.55	-43.19	5.90	-2.79	-45.98	6.07
442	टीसीआईएल लखनौ टोल रोड लिमिटेड	-5.20	0.82	-634.15	-1.07	-0.25	428.00	-0.63	-0.88	71.59
443	टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	30.33	612.79	4.95	35.49	618.56	5.74	73.37	674.39	10.88

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
444	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	894.78	10,178.15	8.79	673.09	10,242.28	6.57	599.08	10,282.26	5.83
445	टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड							-0.50	9.50	-5.26
446	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	7.81	-141.10	-5.54	11.74	-131.21	-8.95	2.29	-129.45	-1.77
447	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	3.15	209.37	1.50	8.86	217.41	4.08	20.63	236.39	8.73
448	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-79.05	-1,304.44	6.06	-79.05	-1,304.44	6.06	-79.05	-1,304.44	6.06
449	भारतीय कपास निगम लिमिटेड	13.29	363.38	3.66	-55.54	288.53	-19.25	38.91	326.71	11.91
450	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनेरल्स इंडिया लिमिटेड	11.59	250.82	4.62	9.74	248.19	3.92	11.18	256.62	4.36
451	द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	353.28	189.37	186.56	612.99	1,273.87	48.12	146.17	1,375.71	10.63
452	भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड	-19.37	13.82	-140.16	-19.37	13.82	-140.16	-19.37	13.82	-140.16
453	औद्योगिक ऋण कंपनी लिमिटेड	0.00	-0.05	0.00	-0.01	-0.06	16.67	-0.02	-0.08	25.00
454	भारतीय जूट निगम लिमिटेड	-13.78	133.69	-10.31	10.01	143.70	6.97	46.12	182.63	25.25
455	केरल औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड	-0.10	4.90	-2.04	0.09	4.99	1.80	0.09	4.99	1.80
456	न्यू इंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड	164.27	38,191.19	0.43	1,055.39	37,957.33	2.78	1,129.33	44,704.21	2.53
457	ओरिएंटल इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड	-3,115.16	6,783.32	-45.92	-4,968.11	3,015.12	-164.77	18.61	5,040.90	0.37

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
458	उड़ीसा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड	-14.49	3.53	-410.48	-16.54	-12.80	129.22	2.82	-10.74	-26.26
459	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	794.79	8,820.58	9.01	800.12	6,371.44	12.56	612.15	6,811.57	8.99
460	भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड	-93.97	-197.57	47.56	32.89	-144.07	-22.83	52.21	-73.88	-70.67
461	ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड							-1.02	3.98	-25.63
462	हूप कम्पर्ट्स लिमिटेड	16.38	4,573.67	0.36	18.95	4,852.84	0.39	-303.07	4,664.48	-6.50
463	तुमकुर-II आरईजेड पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.20	-0.15	133.33
464	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	9.57	-98.81	-9.69	0.20	-98.61	-0.20	45.47	0.00	0.00
465	टस्को लिमिटेड	-1.03	18.71	-5.51	-0.25	37.17	-0.67	-0.58	37.88	-1.53
466	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	-12.94	124.32	-10.41	-8.67	140.66	-6.16	1.11	161.83	0.69
467	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-2,135.55	5,147.69	-41.49	-2,829.33	-732.05	386.49	-803.71	-1,535.20	52.35
468	यूरोनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	576.72	3,944.70	14.62	65.70	3,702.73	1.77	238.63	3,900.06	6.12
469	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.88	-27.31	3.22	-1.04	-28.35	3.67	-1.09	-29.45	3.70
470	विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-6.00	53.85	-11.14	-0.79	30.28	-2.61	-1.14	29.14	-3.91
471	विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड	-8.21	89.62	-9.16	-10.54	78.15	-13.49	-10.39	67.77	-15.33

क्रम सं.	सीपीएसई	2021-22			2022-23			2023-24		
		कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)	कर एवं वरीयता लाभों के बाद शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
472	वेपकोस लिमिटेड	40.85	619.45	6.59	-26.80	559.46	-4.79	-26.80	559.46	-4.79
473	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	942.41	1,505.82	62.58	466.46	2,090.93	22.31	3,245.43	6,452.34	50.30
474	यंत्र इंडिया लिमिटेड	-123.12	2,577.89	-4.78	42.36	3,760.21	1.13	425.58	4,023.55	10.58
475	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	-0.01	-0.08	12.50	0.00	-0.08	0.00	-0.01	-0.09	11.11
476	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	-0.01	-0.04	25.00	-0.01	-0.04	25.00	-0.01	-0.05	20.00
477	जेनिथ सिक्क्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	41.20	22.65	181.90	74.75	37.40	199.87	11.94	49.34	24.20
	योग	2,35,905.34	18,20,279.61	12.96	2,05,100.15	19,93,973.94	10.29	3,23,477.46	23,96,439.40	13.50

अनुलग्नक-XII
(पैरा संख्या 2.5.1 देखें)
उन सीपीएसई की सूची, जिन पर सीएजी द्वारा टिप्पणियाँ जारी की गईं।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
1	एडवांस्ड वेपन्स इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड	जीसी
2	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसीओसी
3	एपीआईटीसीओ फाउंडेशन	जीसीओसी
4	अपोलो डिज़ाइन अपैरल पार्क्स लिमिटेड (वित्त वर्ष 22-2021)	जीसी
5	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
6	आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड	जीसी
7	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
8	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	जीसी
9	बीईएमएल लिमिटेड	जीसी
10	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड	जीसी
11	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	जीसीओसी
12	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	जीसी
13	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	जीसी
14	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड	जीसी
15	भारत संचार निगम लिमिटेड	जीसी
16	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
17	भोर सागर पोर्ट लिमिटेड	जीसीओसी
18	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	जीसी
19	ब्रेथवेट एनएसीओएफ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड	जीसी
20	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड	जीसीओसी
21	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
22	चेन्नई एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
23	कोल इंडिया लिमिटेड	जीसी
24	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	जीसी
25	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	जीसीओसी
26	सीएससी वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
27	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसीओसी

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
28	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
29	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	जीसी
30	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
31	गोल्डमोहर डिज़ाइन एंड अपैरल पाकर्स लिमिटेड (वित्त वर्ष 22-2021)	जीसी
32	सरकारी ई-मार्केट प्लेस	जीसी
33	ग्रीन गैस लिमिटेड	जीसीओसी
34	हसन मँगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड	जीसी
35	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	जीसीओसी
36	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	जीसी
37	हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड	जीसीओसी
38	एचएमटी लिमिटेड	जीसी
39	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	जीसी
40	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	जीसी
41	एचपी ऑयल गैस प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
42	आईएफसीआई एफएसीटीएस लिमिटेड	जीसी
43	आईएफसीआई वित्तीय सेवाएँ लिमिटेड	जीसी
44	आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	जीसी
45	आईएफसीआई लिमिटेड	जीसी
46	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड	जीसी
47	आईएचबी प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
48	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी
49	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड	जीसी
50	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
51	आईटीआई लिमिटेड	जीसी
52	झाबुआ पावर लिमिटेड	जीसीओसी
53	कामराजार पोर्ट लिमिटेड	जीसीओसी
54	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	जीसी
55	कोच्चि सलेम पाइपलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
56	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
57	कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
58	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	जीसी
59	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
60	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	जीसी
61	महाराष्ट्र प्राकृतिक गैस लिमिटेड	जीसीओसी
62	महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	जीसी
63	मसकानी पारादीप रोड विकास लिमिटेड	जीसी
64	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	जीसी
65	मेकॉन लिमिटेड	जीसी
66	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	जीसी
67	खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	जीसी
68	एमपीसीओएन लिमिटेड	जीसी
69	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
70	मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड	जीसी
71	म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड	जीसी
72	एनबी समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड	जीसीओसी
73	नेशनल हाईवेज़ इनवाइट प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड (2022-23)	जीसीओसी
74	राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड	जीसीओसी
75	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक.	जीसी
76	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी
77	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2021-22)	जीसी
78	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	जीसी
79	नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड	जीसी
80	एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड	जीसी
81	एनआईसीडीसी पंजाब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2022-23)	जीसीओसी
82	एनएमडीसी लिमिटेड	जीसी
83	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	जीसी
84	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
85	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
86	एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	जीसी
87	एनटीपीसी लिमिटेड	जीसी
88	पवन हंस लिमिटेड (2022-23)	जीसी
89	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	जीसीओसी
90	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	जीसी
91	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	जीसी
92	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	जीसी
93	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड (2022-23)	जीसी
94	सेल रिफ़ैक्टरी कंपनी लिमिटेड	जीसी
95	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जीसीओसी
96	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड	जीसीओसी
97	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
98	एसजेवीएन लिमिटेड	जीसी
99	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
100	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
101	टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	जीसी
102	न्यू इंडिया एंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी
103	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी
104	तूतीकोरिन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
105	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी
106	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
107	यंत्र इंडिया लिमिटेड	जीसी

अनुलग्नक-XIII
(पैरा संख्या 2.6 देखें)

**उन सीपीएसई का विवरण, जिनमें सांविधिक लेखापरीक्षकों ने
लेखांकन मानकों/इंड एस के अनुपालन न होने की रिपोर्ट दी।**

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	कैटेगरी (सूचीबद्ध/ असूचीबद्ध)	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	लेखा मानक (एस) / इंड एस की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एस 16
2	आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसीओसी	एस 29
3	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एस 3
4	भारत संचार निगम लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एस 8, इंड एस 16, इंड एस 18, इंड एस 36, इंड एस 37, इंड एस 109 एवं इंड एस 116
5	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसीओसी	इंड एस 1, इंड एस 8 एवं इंड एस 109
6	एचएमटी लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण)	सूचीबद्ध	जीसी	इंड एस 2, इंड एस 19, इंड एस 40, इंड एस 109, इंड एस 115 एवं इंड एस 116
7	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एस 2, इंड एस 19, इंड एस 24, इंड एस 36, इंड एस 40 एवं इंड एस 116
8	आईटीआई लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंड एस 2, इंड एस 19, इंड एस 40, इंड एस 36, इंड एस 109, इंड एस 115 एवं इंड एस 116
9	कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन	असूचीबद्ध	जीसी	एस 22
10	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एस 7, इंड एस 12, इंड एस 16, इंड एस 24 एवं इंड एस 109
11	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एस 22
12	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (22-2021)	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एस 116
13	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एस 1
14	एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसीओसी	इंड एस 12 एवं इंड एस 109

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	कैटेगरी (सूचीबद्ध/ असूचीबद्ध)	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	लेखा मानक (एएस) / इंड एस की संख्या
15	पवन हंस लिमिटेड (23-2022)	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एस 7
16	पीईसी लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एस 105
17	एसबीआई फाउंडेशन	असूचीबद्ध	जीसीओसी	एएस 3, एएस 12 एवं एएस 15
18	एसटीसीएल लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	भारतीय लेखा मानक 24 एवं भारतीय लेखा मानक 105
19	तमिलनाडु दूरसंचार लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसीओसी	इंड एस 109
20	टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एस 109
21	भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	भारतीय मानक ब्यूरो 21, भारतीय मानक ब्यूरो 36 एवं भारतीय मानक ब्यूरो 116

अनुलग्नक XIV
(पैरा संख्या 2.7 देखें)

उन सीपीएसई का विवरण जहां सीएजी द्वारा प्रबंधन पत्र जारी किए गए

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड
2	एक्यूइटेरेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड
3	एएफसी इंडिया लिमिटेड
4	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड
5	एग्रीनोवेटिव इंडिया लिमिटेड
6	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड
7	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड
8	अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड
9	आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
10	आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड
11	एपीआईटीसीओ लिमिटेड
12	अपोलो डिज़ाइन अपैरल पार्क्स लिमिटेड
13	आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड
14	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
15	एसएसआईसी (इंडिया) लिमिटेड
16	औरंगाबाद टेक्स्टाइल एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड
17	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
18	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
19	बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड
20	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
21	बीईएमएल लिमिटेड
22	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड
23	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
24	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
25	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
26	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
27	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड
28	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
29	भारत संचार निगम लिमिटेड
30	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
31	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड
32	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड
33	भरुच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड
34	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
35	बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड
36	बीओआई मर्चेन्ट बैंकर्स लिमिटेड
37	बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड
38	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी (पी) लिमिटेड
39	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड
40	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
41	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
42	ब्रेथवेट एनएसीओएफ सोलर प्रोजेक्ट लिमिटेड
43	कलकत्ता हल्दिया पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
44	केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
45	कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
46	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
47	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड
48	सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
49	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
50	केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड
51	भारत के प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री
52	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
53	चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड
54	चेन्नई एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
55	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड
56	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
57	कोल इंडिया लिमिटेड
58	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
59	कॉनकॉर एयर लिमिटेड

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
60	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
61	क्रिएटिव संग्रहालय डिजाइनर
62	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड
63	सीएससी वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
64	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
65	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
66	डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड
67	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
68	ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
69	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
70	ईसीजीसी लिमिटेड
71	एडसिल (इंडिया) लिमिटेड
72	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
73	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
74	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
75	ईएसजी रिस्क असेसमेंट्स एंड इनसाइट्स लिमिटेड
76	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड
77	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
78	भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड
79	फ्लेवरिट स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड
80	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड
81	गेल (इंडिया) लिमिटेड
82	गेल मँगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
83	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
84	ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड
85	गोल्डमोहर डिज़ाइन एंड अपैरल पाक्स लिमिटेड
86	सरकारी ई-मार्केट प्लेस
87	ग्रीन गैस लिमिटेड
88	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड
89	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
90	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
91	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
92	एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड
93	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड
94	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
95	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
96	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
97	हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड
98	एचएमटी लिमिटेड
99	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
100	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड
101	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
102	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
103	एचपीसीएल बायो फ्यूल्स लिमिटेड
104	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड
105	हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
106	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सेवाएँ लिमिटेड
107	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड
108	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
109	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवाएँ लिमिटेड
110	आईएफसीआई फेक्टरस लिमिटेड
111	आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
112	आईएफसीआई लिमिटेड
113	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड
114	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
115	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
116	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
117	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड
118	भारत एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
119	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
120	भारत व्यापार संवर्धन संगठन
121	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
122	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
123	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
124	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड
125	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड
126	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड
127	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड
128	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड
129	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड
130	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
131	सीसीएस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फेडरेशन
132	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
133	इरकॉन अकलोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड
134	इरकॉन गुडगांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड
135	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
136	आईटीआई लिमिटेड
137	जम्मू एवं कश्मीर खनिज विकास निगम लिमिटेड
138	झाबुआ पावर लिमिटेड
139	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
140	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड
141	केआईओसीएल लिमिटेड
142	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड
143	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
144	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
145	कृष्णपटनम रेल कंपनी लिमिटेड
146	कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड
147	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड
148	एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड
149	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
150	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
151	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
152	महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
153	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
154	महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
155	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
156	मसकानी पारादीप रोड विकास लिमिटेड
157	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड
158	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनंस एजेंसी लिमिटेड
159	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड
160	मोरमुगाओ पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
161	एमपीसीओएन लिमिटेड
162	एमएसटीसी लिमिटेड
163	मुंबई जेएनपीटी पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
164	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
165	मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड
166	म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड
167	एनबी एआरडी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
168	एनबी समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड
169	एनबीबी वेंचर्स लिमिटेड
170	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
171	राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड
172	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
173	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
174	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा लिमिटेड
175	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड
176	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड
177	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
178	राष्ट्रीय उच्च शक्ति परीक्षण प्रयोगशाला प्राइवेट लिमिटेड
179	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
180	नेशनल हाईवेज़ इनवाइट प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
181	राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड
182	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक.
183	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
184	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
185	भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लिमिटेड
186	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
187	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
188	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
189	राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड
190	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
191	एनईपीए लिमिटेड
192	एनईएसएल एसेट डेटा लिमिटेड
193	एनआईएसएल ई-इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
194	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैनुफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
195	न्यू मैंगलोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
196	न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड
197	नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड
198	एनएचपीसी लिमिटेड
199	एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड
200	एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड
201	उत्तर भारत तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड
202	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
203	एनएमडीसी लिमिटेड
204	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड
205	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
206	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
207	एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड
208	एनपीसीआई अंतर्राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड
209	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड
210	एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
211	एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
212	एनटीपीसी लिमिटेड
213	एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड
214	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
215	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड
216	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
217	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
218	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड
219	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
220	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड
221	ओवीएल ओवरसीज आईएफएससी लिमिटेड
222	पारादीप पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
223	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
224	पिपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
225	पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड
226	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
227	पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड
228	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
229	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
230	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
231	पावरग्रिड भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
232	पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड
233	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड
234	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड
235	पावरग्रिड सदरन इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
236	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
237	पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड
238	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
239	रेल विकास निगम लिमिटेड
240	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
241	रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
242	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
243	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
244	रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
245	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
246	आरईसी लिमिटेड
247	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड
248	रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड
249	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड
250	राइट्स लिमिटेड
251	रबर पार्क इंडिया (पी) लिमिटेड
252	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
253	सेल रिफ़ैक्टरी कंपनी लिमिटेड
254	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
255	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
256	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड
257	एसबीआई सीडीएमडीएफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड
258	एसबीआई फाउंडेशन
259	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
260	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
261	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
262	एसबीआई पेमेंट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
263	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
264	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
265	एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड
266	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड
267	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
268	भारतीय शिपिंग निगम
269	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड
270	एस आईडीबीआई ट्रस्टीज़ कंपनी लिमिटेड
271	एस आईडीबीआई वेंचर कैपिटल लिमिटेड
272	सिडयोग कोकोर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड
273	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड
274	एसएमई आरए रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
275	भारतीय सौर ऊर्जा निगम
276	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
277	स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
278	स्टेट बैंक ऑपरेशंस सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
279	एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड
280	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लिमिटेड
281	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
282	स्टॉकहोल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड
283	सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट लिमिटेड
284	तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड
285	टीसीआईएल लखनादौन टोल रोड लिमिटेड
286	टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
287	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
288	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड
289	भारतीय कपास निगम लिमिटेड
290	द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
291	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
292	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
293	तूतीकोरिन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
294	यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड
295	यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
296	यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
297	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
298	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
299	उर्वरक विदेश लिमिटेड
300	यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड
301	वधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड
302	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
303	यंत्र इंडिया लिमिटेड
304	जेनिथ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

अनुलग्नक XV
(पैरा संख्या 2.7 देखें)
उन सीपीएसई का विवरण सीएजी द्वारा जारी प्रबंधन पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण सुधार किए गए

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामी	सुधार किया गया
1	आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड	जीसीओसी	यह सुनिश्चित करना कि संबंधित पक्ष प्रकटीकरण इंड एस 24 के अनुसार किया जाए।	2023-24 में आवश्यक अनुपालन पूरा किया गया।
2	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड.	जीसी	- देय राशि तीन साल से अधिक पुरानी है, इसलिए प्रत्येक पक्ष के साथ आवश्यक मिलान यथाशीघ्र किया जाना चाहिए। - कंपनी का विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड (वीपीएलपीएल) में ₹81.04 करोड़ का इक्विटी निवेश है, हालांकि, कंपनी ने हानिपरीक्षण नहीं किया, जबकि मार्च 2023 तक वीपीएलपीएल की वित्तीय स्थिति एवं प्रदर्शन असंतोषजनक बना रहा।	- सभी संबंधित पक्षों के साथ बकाया राशि के मिलान के लिए एक केंद्रित अभ्यास शुरू किया गया एवं भविष्य में असमायोजित राशियों के संचय को रोकने के लिए 31 मार्च 2024 तक प्रक्रिया पूरी होने का आश्वासन दिया गया। - प्रबंधन ने वीपीएलपीएल में अपने निवेश के उचित मूल्य का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता को नियुक्त किया है एवं 31 मार्च 2024 तक आवश्यक लेखांकन समायोजन के साथ हानि परीक्षण पूरा करने का आश्वासन दिया है, यदि आवश्यक हो।
3	भारत संचार निगम लिमिटेड	जीसी	- मांगा किए गए एवं बकाया होलिंग टैक्स के भुगतान से संबंधित मुद्दे के लिए कड़ी निगरानी एवं उसके बाद उचित प्रावधान की आवश्यकता है। - अप्रचलित पीपीई का उचित लेखा-जोखा सुनिश्चित किया जाए। - बंद की गई संपत्तियों के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य का पता लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। - पट्टे पर दी गई भूमि का उचित वर्गीकरण एवं उसके बाद उसका उचित लेखा-जोखा सुनिश्चित किया जाए। - बीएसएनएल की संपत्तियों पर अतिक्रमण के संबंध में उचित खुलासा किया जाना आवश्यक है।	- आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया - आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया - आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया - आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया - आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामी	सुधार किया गया
4	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	जीसी	- परिसर में आपातकालीन सहायता केंद्र के निर्माण की लागत के लिए देय राशि का खुलासा लेखा टिप्पणियों में करना आवश्यक है। - आगामी वर्ष के लेखाओं में इंड एस 24 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरण।	2023-24 में आवश्यक अनुपालन पूरा किया गया 2023-24 में आवश्यक अनुपालन पूरा किया गया
5	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी	आयकर वापसी योग्य राशि का उचित मिलान एवं लेखा-जोखा सुनिश्चित किया जाए।	आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया
6	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	जीसी	कंपनी अपने वित्तीय विवरणों में अप्रयुक्त सीएसआर निधि को अलग से आवंटित करने की आवश्यकता की समीक्षा करें।	वित्तीय विवरणों में अप्रयुक्त सीएसआर निधियों को अलग से चिन्हित करने की समीक्षा की गई है एवं लेखा बही में आवश्यक सुधार प्रविष्टियाँ दर्ज करके इसे चिन्हित बैंक शेष के रूप में लेखांकित किया गया है।
7	बीपीसीएल	जीसी	मंथली एक्स-ग्रेडिआ स्कीम एमईजीएस) एवं आयु संबंधी अभिनंदन लाभ (अभिनंदन पुरस्कार योजना के अंतर्गत) उन कर्मचारियों को नहीं दिए गए जिन्होंने एनडीआर से पहले इस्तीफा दे दिया था या बर्खास्तगी के बाद बीपीसीएल से कार्यभार संभाला था। एमईजीएस एवं अभिनंदन पुरस्कार योजना से संबंधित बीमांकिक मूल्यांकन में इन बातों पर विचार नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप देयता का कम आकलन हुआ। एथेनॉल की खरीद लागत में काफी भिन्नता थी। एथेनॉल के भंडार का समापन शेष उच्च दर पर था। इसके परिणामस्वरूप एथेनॉल के भंडार का अधिक मूल्यांकन हुआ।	- एमईजीएस एवं एज माइलस्टोन से संबंधित एफईएलआईसी लाभ को 2023-24 के दौरान एकचुरियल देनदारी में शामिल किया गया। - सितंबर 2023 से, भारत औसत मूल्य की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक अथवा कम प्रदर्शित होने वाले चल औसत मूल्य (एमएपी) को भारत औसत मूल्य के अनुरूप समायोजित कर दिया गया।
8	बीपीसीएल केआईएल	जीसी	कंपनी द्वारा दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में हवाईअड्डे आर्थिक नियामक प्राधिकरण के दिनांक 15.03.2022 के आदेश के विरुद्ध दायर अपील के संक्षिप्त तथ्यों को पाठकों की बेहतर समझ के लिए “वित्तीय विवरणों के टिप्पणी” में प्रकट करना आवश्यक है।	2023-24 में आवश्यक अनुपालन पूरा किया गया

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामी	सुधार किया गया
9	ब्रह्मपुत्र वैली फटिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी	- अनुदान सहायता के लेखांकन से संबंधित महत्वपूर्ण लेखांकन नीति का अनुपालन करना आवश्यक है। - बीवीएफसीएल में तैनात सीआईएसएफ कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ता, एनपीएस एवं वेतन से संबंधित देनदारी का लेखा-जोखा किया जाना आवश्यक है।	2023-24 में आवश्यक अनुपालन पूरा किया गया 2023-24 में आवश्यक अनुपालन पूरा किया गया
10	चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड	जीसीओसी	इंड एस 20 के अनुसार, गैर-चालू परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सरकारी अनुदान को या तो गैर-चालू देनदारियों के तहत आस्थगित आय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए या पूंजीकरण के समय परिसंपत्ति के सकल ब्लॉक से घटाया जाना चाहिए। हालांकि, प्रबंधन ने अनुदान को आस्थगित आय के रूप में दिखाते हुए इसे चालू देनदारी के रूप में वर्गीकृत करके दोनों तरीकों को मिला दिया है, जो मानक के विपरीत है क्योंकि अनुदान गैर-चालू परिसंपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप गलत वर्गीकरण हुआ है।	2023-24 में आवश्यक अनुपालन पूरा किया गया
11	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	तटस्थक	कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के साथ अंतर को उचित ठहराने वाले विशिष्ट खुलासों के साथ कोयला हैंडलिंग संयंत्रों के जीवन का तकनीकी मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।	कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) की लाइफ के टेक्निकल मूल्यांकन का सीआईएल की टेक्निकल कमिटी ने रिव्यू किया है एवं सिफारिश की है कि मौजूदा सीएचपीएस, जिन्हें टर्नकी बेसिस पर कैपिटलाइज किया गया है, उनकी लाइफ बिना शिफ्ट के मूल्यहास के 15 वर्ष तक जारी रहेगी।
12	फागमिल	जीसी	समय सीमा समाप्त हो चुके व्यापारिक देय एवं व्यापारिक प्राप्त राशियों की वापसी एवं प्रावधान संबंधी लेखांकन नीति की समीक्षा की जाए। एवं 2023-24 में आवश्यक कार्रवाई की जाए।	प्रबंधन ने वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की मान्यता रद्द करने की नीति को विस्तार से बताया है।
13	गेल गैस लिमिटेड	जीसी	संयुक्त उद्यम कंपनी गोवाने चारल गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हुए नुकसान का कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित मिलान एवं लेखांकन सुनिश्चित किया जाए।	आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामी	सुधार किया गया
14	गेल (इंडिया) लिमिटेड	जीसी	- कंपनी द्वारा इंड एस 106 के प्रावधानों के अनुपालन में नॉर्थ अथारामुरा कुएं में किए गए व्यय पर परिसंपत्तियों के मूल्यहास के लिए प्रावधान बनाया जाए। - कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर) के प्रति दायित्व को इंड एस 16 के प्रावधानों के अनुपालन में सीडब्ल्यूआईपी शीर्षक के तहत मान्यता दी जाए एवं दर्ज किया जाए। - मध्यस्थ द्वारा आरआईएल के पक्ष में दिए गए निर्णय के कारण उत्पन्न होने वाली देनदारी के लिए प्रावधान बनाया जाए।	- आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया - आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया - आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया
15	एचएल	जीसी	- प्रबंधन यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्राप्य राशि संदिग्ध होने पर प्रावधान बनाने एवं उसके बाद राजस्व को प्रभावित किए बिना उसे बड़े खाते में डालने का उचित क्रम निर्धारित किया जाए। - प्रबंधन विदेशी विक्रेताओं से प्राप्त माल की समीक्षा करे एवं यह सुनिश्चित करे कि पारगमन में माल का उचित लेखा-जोखा एवं संबंधित देयता सुनिश्चित हो।	- दावों के उचित लेखांकन के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए गए थे। - माल-इन-ट्रांजिट (जीआईटी) के लेखांकन एवं विदेशी विक्रेताओं द्वारा भेजे गए लेकिन बैलेंस शीट की तिथि तक डिवीजन में प्राप्त नहीं हुए शिपमेंट के संबंध में संबंधित विक्रेताओं की देयता के निर्माण के अनुपालन को दोहराते हुए आवश्यक लेखांकन निर्देश जारी किए गए थे।
16	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी	कंपनी की "परिचालन राजस्व" संबंधी लेखा नीति में प्रदर्शन दायित्वों या उन्हें आवंटित लेनदेन मूल्य के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इंड एस 115 का अनुपालन नहीं होता है एवं नीति में खामी आ जाती है।	आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया
17	एचएफसीएल	जीसी	कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की समीक्षा की जाए एवं उसमें निहित टिप्पणियों का सुधार किया जाए।	महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में, एचएफसीएल द्वारा उपलब्ध निधियों का तरल निधियों/नकदी समकक्षों एवं अन्य बैंक शेष के आधार पर आवश्यक वर्गीकरण किया गया है।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामी	सुधार किया गया
18	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	जीसी	कंपनी को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत एमएसएमई को देय ब्याज का अलग से खुलासा करना आवश्यक है, धारा 22(i) के अनुसार। हालांकि, लेखाओं की टिप्पणी में अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं की गई है।	आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया
19	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	तटरक्षक	- हडको ने वर्ष 1995 एवं 1997 के वित्तपोषण समझौतों (ट्रेंच-V एवं VI) के अंतर्गत कैपेडब्ल्यू-जर्मन बैंक से प्राप्त ₹97.55 करोड़ तथा उस पर अर्जित ₹9.87 करोड़ ब्याज को, समझौतों की अवधि समाप्त हो जाने, सभी शर्तों की पूर्ति हो जाने तथा उक्त राशि के अप्रतिदेय हो जाने के बावजूद, अन्य वित्तीय देयताओं के अंतर्गत दर्शाना जारी रखा। अतः 31 मार्च 2023 की स्थिति में यह देयता अस्तित्व में नहीं थी एवं इसे लेखों से हटा दिया जाना चाहिए था। - सरकारी क्षेत्र के दूसरे चरण के ऋणों के लिए जीवनकाल में डिफॉल्ट की संभावना निर्धारित करने की विधि का खुलासा खातों के टिप्पणी में नहीं किया गया था।	- इस रकम को दूसरी वित्तीय देनदारियों फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ से हटा दिया गया है। 2023-24 के अकाउंट्स में जरूरी जानकारी दे दी गई है।
20	एचपीसीएल	जीसी	- संदिग्ध पीएमयूवाई ऋण प्राप्तियों के विरुद्ध प्रावधान बनाने के लिए अपनाई गई पद्धति की उद्योगव्यापी समीक्षा की जाए। एवं वर्ष 2023-24 के दौरान उचित उपचार किया जाए। - वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 'विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियों' से संबंधित लेखांकन नीति को शामिल करने की आवश्यकता की गहन जांच की जाए। एवं आवश्यक कार्रवाई की जाए।	- कंपनी द्वारा पीएमयूवाई ऋण प्राप्तियों के लिए प्रावधान पद्धति की उद्योग भर में समीक्षा की गई एवं 70 प्रतिशत प्रावधान के साथ 6-12 महीने की निष्क्रिय अवधि का एक नया समूह शामिल करने का निर्णय लिया गया। इसे 2023-24 के दौरान लागू किया गया। 'विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियों' से संबंधित लेखांकन नीति को 2023-24 के दौरान 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना' में शामिल किया गया है।
21	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड	जीसी	अवकाश वेतन अंशदान के विलंबित भुगतान पर देय ब्याज के लिए प्रावधान सुनिश्चित किया जा सकता है।	आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामी	सुधार किया गया
22	आईओएसआई एल	जीसी	• कंपनी अपने वित्तीय विवरणों में पीएम केयर फंड से संबंधित दावों के लिए भारत सरकार से वसूली योग्य राशि के संबंध में उचित खुलासा कर सकती है ताकि हितधारकों को निष्पक्ष जानकारी मिल सके। • कंपनी अपने वित्तीय विवरणों में हरियाणा सरकार को आंतरिक खपत पर देय बिजली शुल्क की राशि का उचित निपटान सुनिश्चित कर सकती है।	• आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया • आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया
23	इस्कॉन	जीसी	• कंपनी ने अपनी प्रमुख एवं सहायक उद्देश्यों में से एक, अर्थात् संपत्तियों को किराये पर देकर अर्जित आय के संबंध में अपनाई गई लेखांकन नीति का खुलासा नहीं किया है।	• आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड.	जीसी	• मूल्यहास की गणना के लिए अपनाई गई परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु, कंपनी अधिनियम, 2013 की संबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपयोगी आयु से भिन्न है। इस विचलन का खुलासा कंपनी की लेखांकन नीति में किया जाना चाहिए।	• आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया
25	केआईओसीएल लिमिटेड	जीसी	• महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में पांच साल से अधिक समय तक रखे गए अचल भंडार एवं अतिरिक्त सामान के लिए मान्यता प्राप्त हानि के प्रतिशत को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।	• आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया
26	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	जीसी	• कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत अपेक्षित व्यापार देय एवं व्यापार प्राप्य की आयु-वार अनुसूची प्रदान नहीं की।	• 2023-24 के दौरान आवश्यक अनुपालन पूरा किया गया
27	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी	• पूंजी प्रतिबद्धताओं (टिप्पण 33) को ₹160.87 करोड़ से कम करके बताया गया है, क्योंकि कंपनी ने खुलासा नहीं किया है: (ए) कार्यालय स्थान के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को देय ₹130.87 करोड़, एवं (बी) अंजुर अर्थ इलेक्ट्रोड स्टेशन को मालेगांव में स्थानांतरित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड को देय ₹30 करोड़।	• 2023-24 के दौरान आवश्यक अनुपालन पूरा किया गया
28	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	जीसी	• कंपनी ने दिनांक 24.03.2021 के परिपत्र के अनुसार इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तैयार करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप का पालन नहीं किया है।	• 2023-24 के दौरान आवश्यक अनुपालन पूरा किया गया

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामी	सुधार किया गया
29	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी	कोल इंडिया लिमिटेड ने (सितंबर 2020 में) ओवरबर्डन रिमूवल (ओबीआर) संबंधी लेखांकन निर्देश जारी करते हुए निर्देश दिया था कि ओबीआर गतिविधि से सीधे के रूप में संबंधित न होने वाली लागतों को अग्रिम स्ट्रिपिंग एवं अनुपात विचरण रिजर्व के मूल्यांकन के लिए ओबीआर लागत निर्धारित करने से बाहर रखा जाएगा। इसके विपरीत, एनसीएल की निगाही एवं जयंत परियोजनाओं ने अनुपात विचरण समायोजन के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन की गणना करते समय प्रशासनिक एवं लेखापरीक्षा व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, डाक व्यय, छपाई एवं स्टेशनरी आदि को शामिल किया, जिन्हें इन इकाइयों के लाभ-हानि विवरण में प्रभावित किया जाना था। चूंकि ये लागतें सीधे के रूप में ओबीआर से संबंधित नहीं थीं, इसलिए इन्हें ओबीआर गतिविधि के अंतर्गत आवंटित नहीं किया जाना चाहिए था, जिसके परिणामस्वरूप स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन में कमी एवं लाभ में अधिकता हुई। ओबीआर गतिविधि से सीधे के रूप में संबंधित न होने वाली लागतों की प्रकृति एवं मदों को कोयला एवं ओबीआर के बीच लागतों के सटीक आवंटन के लिए अन्य लागतों से अलग करके विवेकपूर्ण ढंग से पहचाना एवं सीमांकित किया जाना आवश्यक है, एवं सभी क्षेत्रों/खानों में इस प्रकार के लेखांकन व्यवहार में एकरूपता सुनिश्चित की जानी चाहिए।	कोयले एवं ऊपरी परत के बीच लागत आवंटन में एकरूपता बनाए रखने के लिए सभी इकाइयों में एक समान प्रारूप प्रसारित एवं लागू किया गया। यह जून 2023 से प्रभावी हुआ।
30	एनएससी	जीसी	रबी की खड़ी फसलों के मूल्यांकन एवं नर्सरी की सूची के संबंध में लेखांकन नीति की समीक्षा इंड एस 41 के पैरा 30 के अनुसार की जाए।	आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया
31	एनटीपीसी	जीसी	कंपनी को ईईएसएल तथा टेलक में किए गए निवेश के हास विश्लेषण की पुनर्समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि दोनों संस्थाओं ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में हानि अर्जित की है तथा उनकी निवल संपत्ति में कमी आई है। इसके आधार पर कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों में आवश्यक समायोजन करना चाहिए।	जरूरी इंतजाम किए गए।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामी	सुधार किया गया
32	ओएनजीसी लिमिटेड.	जीसी	- नॉर्थ कादी पॉलिमर इंजेक्शन प्लांट का पार्ट प्रोजेक्ट, यानी पॉलिमर इंजेक्शन प्लांट, जो 31.03.2023 तक पूरा हो गया था, उसे वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीकृत किया जाए। - तकनीकी रूप से पूर्ण कुओं के पूंजीकरण की समीक्षा वर्ष के दौरान की जाए। कृत्रिम लिफ्ट की स्थापना के बाद कुएं में की गई गतिविधियों को भी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखा-बही में राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाए।	- नॉर्थ कादी पॉलिमर इंजेक्शन प्लांट के पॉलिमर इंजेक्शन संयंत्र वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लेखा बही में ₹26.04 करोड़ मूल्य की पूंजी दर्ज की गई है। - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखा-बही में सभी पांच कुओं का पूंजीकरण ₹31.55 करोड़ के मूल्य पर किया गया है।
33	पीएफसी लिमिटेड	जीसी	नियमों का पालन न करने पर नियामक निकायों द्वारा लगाए गए दंडों की लेखा-बही में उचित लेखांकन के लिए समीक्षा की जाए।	आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया
34	पीजीसीआईएल	जीसी	ईईएसएल के संयुक्त उद्यम में किए गए निवेश के लिए परिसंपत्तियों के मूल्यहास का प्रावधान बनाया जाए।	आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया
35	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	जीसी	आरसीएफ को ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों के लेखांकन के लिए अपनाई गई लेखांकन नीति का खुलासा करना होगा (i) विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एवं इन्वेंट्री के रूप में रखे गए प्रमाणपत्र एवं (ii) पावर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदे गए एवं वर्ष के दौरान व्यय के रूप में दर्ज किए गए प्रमाणपत्र।	आवश्यक अनुपालन पूरा हो गया

अनुलग्नक - XVI
(पैरा संख्या 3.1.2 देखें)
चुनिंदा सीपीएसई की सूची, जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे

क्रमांक	सीपीएसई का नाम
1.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3.	ऑइल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन
4.	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)
5.	ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)
6.	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीआईबीकोल)
7.	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरडीडीए)
8.	एमएसटीसी लिमिटेड
9.	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
10.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
11.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
12.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
13.	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
14.	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसीएल)
15.	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)
16.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (रेलटेल)
17.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
18.	राइट्स लिमिटेड
19.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
20.	भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी)
21.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)
22.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
23.	भारतीय सामान्य बीमा निगम
24.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल)
25.	एनएमडीसी लिमिटेड.
26.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड.

क्रमांक	सीपीएसई का नाम
27.	ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल)
28.	एचएमटी लिमिटेड
29.	केआईओसीएल लिमिटेड
30.	आईएफसीआई लिमिटेड
31.	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईसीपीएसएल)
32.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आईटीडीसी)
33.	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
34.	एमएमटीसी लिमिटेड
35.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको)
36.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (एचपीआईएल)
37.	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
38.	भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बीईएल)
39.	बीईएमएल लिमिटेड
40.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल)
41.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी)
42.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)
43.	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)
44.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)
45.	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटीएल)
46.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफएल)
47.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)
48.	आईटीआई लिमिटेड
49.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)
50.	एनटीपीसी लिमिटेड
51.	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)
52.	एसजेवीएन लिमिटेड
53.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)
54.	एनएचपीसी लिमिटेड
55.	आरईसी लिमिटेड

क्रमांक	सीपीएसई का नाम
56.	एमओआईएल लिमिटेड नागपुर
57.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
58.	गेल (इंडिया) लिमिटेड
59.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
60.	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
61.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
62.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
63.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
64.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
65.	इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड
66.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड.

अनुलग्नक - XVII
(पैरा संख्या 3.1.2 देखें)
चुने हुए सीपीएसई/ संविधिक निगमों की सूची, जिनके बांड/डिबेंचर/गैर-परिवर्तनीय
ऋण प्रतिभूतियां स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थीं।

क्रमांक	सीपीएसई का नाम
1.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3.	ऑइल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन
4.	ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड
5.	नेशनल इंडियन कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल)
6.	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरडीडी)
7.	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआई एल)
8.	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसीएल)
9.	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
10.	ओरिएंटल इंडियन कंपनी लिमिटेड
11.	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईसीपीएसएल)
12.	आईएफसीआई लिमिटेड.
13.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको)
14.	डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड
15.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई)
16.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड
17.	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
18.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड.
19.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)
20.	भारत संचार निगम लिमिटेड
21.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफएल)
22.	भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)
23.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)
24.	एनटीपीसी लिमिटेड
25.	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)

क्रमांक	सीपीएसई का नाम
26.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
27.	एसजेवीएन लिमिटेड
28.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)
29.	एनएचपीसी लिमिटेड
30.	आरईसी लिमिटेड
31.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीआई)
32.	गेल इंडिया लिमिटेड
33.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
34.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
35.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
36.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड.

अनुलग्नक - XVIII
(पैरा संख्या 3.1.2 देखें)

सीपीएसई की सूची, जिनके शेयर एवं डिबेंचर दोनों स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे

क्रमांक	सीपीएसई का नाम
1.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3.	ऑइल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन
4.	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए)
5.	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसीएल)
6.	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईसीपीएसएल)
7.	आईएफसीआई लिमिटेड.
8.	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड हुडको
9.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड.
10.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफएल)
11.	एनटीपीसी लिमिटेड
12.	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)
13.	एसजेवीएन लिमिटेड
14.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)
15.	एनएचपीसी लिमिटेड
16.	आरईसी लिमिटेड
17.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीआई)
18.	गेल इंडिया लिमिटेड
19.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
21.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
22.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

अनुलग्नक XIX
(पैरा संख्या 3.2.2 देखें)
वे सीपीएसई के जहां अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष का पद	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रति-शत में)	वर्ष 2023-24 के दौरान कमी की अवधि
1.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	5	1(17)	अप्रैल से अगस्त एवं जनवरी से मार्च
2.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9	गैर कार्यकारी	6	3	3(50)	अप्रैल से मार्च
3.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	3	3(50)	अप्रैल से जुलाई
		5		5	3	2(40)	अगस्त से मार्च
4.	एमएसटीसी लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	2	3(60)	अप्रैल से मार्च
5.	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	2	5(71)	अप्रैल से मई
		6		6	2	4(67)	जून से मार्च
6.	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	3	गैर कार्यकारी	2	0	2(100)	अप्रैल से मार्च
7.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	4	2(33)	अप्रैल
		7		7	4	3(43)	मई से दिसंबर
		8		8	4	4(50)	जनवरी से मार्च
8.	केआईओसीएल लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	2	2(50)	अप्रैल
		5		5	2	3(60)	मई
		6		6	2	4(67)	जून से जनवरी
		5		5	2	3(60)	फरवरी से मार्च

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष का पद	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2023-24 के दौरान कमी की अवधि
9.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	5 6	कार्यकारी	5 6	0 0	100 100	अप्रैल से मई एवं फरवरी से मार्च जून से जनवरी
10.	एचएमटी लिमिटेड	3 4	कार्यकारी	3 4	0 0	100 100	अप्रैल से अगस्त एवं दिसंबर सितंबर से नवंबर एवं जनवरी से मार्च
11.	एनएमडीसी लिमिटेड	5 6	कार्यकारी	5 6	4 4	20 33	अप्रैल से मई एवं फरवरी से मार्च जून से जनवरी
12.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	5 4 6	कार्यकारी	5 4 6	3 3 3	2(40) 1(25) 3(50)	अप्रैल से अगस्त, दिसंबर एवं मार्च सितंबर से नवंबर जनवरी से फरवरी
13.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	7	कार्यकारी	7	6	1(14)	मई से मार्च

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष का पद	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रति-शत में)	वर्ष 2023-24 के दौरान कमी की अवधि
14.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी)	7	कार्यकारी	7	6	1(14)	मई से जनवरी
15.	हेमिस्फेर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	2	3(60)	अप्रैल से मार्च
16.	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	4	1(20)	अप्रैल से फरवरी
		5		5	3	2(40)	मार्च
17.	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	3	2(40)	अप्रैल से मार्च
18.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	6	1(14)	मई से मार्च
19.	ऑयल इंडिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	3	4(71)	अप्रैल एवं मई
		6		6	3	3(50)	जून से जनवरी
		6		6	2	4(67)	फरवरी एवं मार्च
20.	आईएफसीआई लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	0	7(100)	अप्रैल
		7		7	1	6(86)	मई से नवंबर
		8		8	1	7(88)	दिसंबर से मार्च

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष का पद	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2023-24 के दौरान कमी की अवधि
21.	एमएमटीसी लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	1	5(83)	अप्रैल एवं मई
		6		6	3	3(50)	जून, जुलाई एवं मार्च
		6		6	4	2(33)	अगस्त से फरवरी
22.	रेल विकास निगम लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	2	4(67)	अप्रैल से सितंबर, नवंबर एवं फरवरी से मार्च
		7		7	2	5(71)	दिसंबर से जनवरी
23.	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	3	कार्यकारी	3	2	1(33)	अप्रैल से मार्च
24.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	2	3(60)	अप्रैल से जून एवं नवंबर
		6		6	2	4(67)	जुलाई से अक्टूबर एवं दिसंबर से मार्च
25.	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	2	3(60)	अप्रैल से मई
		6		6	3	3(50)	जून से मार्च
26.	इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	4	1(20)	अप्रैल से मार्च
27.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3	कार्यकारी	3	0	3(100)	अप्रैल से मई
		3		3	1	2(67)	जून, सितंबर एवं अक्टूबर
		2		2	1	1(50)	जुलाई एवं अगस्त
		4		4	1	3(75)	नवंबर से मार्च

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष का पद	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रति-शत में)	वर्ष 2023-24 के दौरान कमी की अवधि
28.	राइट्स लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	4	2(33)	अप्रैल से मार्च
29.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	11	कार्यकारी	11	6	5(45)	अप्रैल
		10		10	6	4(40)	मई से मार्च
30.	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	5	1(17)	मई से जून एवं अक्टूबर से जनवरी
		7		7	5	2(28)	जुलाई से सितंबर
31.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	3	2(40)	अप्रैल से जून
		5		5	2	3(60)	जुलाई से सितंबर
		4		4	2	2(50)	अक्टूबर
		4		4	1	3(75)	नवंबर से जनवरी
		5		5	1	4(80)	फरवरी से मार्च
32.	एमओआईएल लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	3	4(57)	अप्रैल से अगस्त एवं जनवरी से फरवरी
		6		6	3	3(50)	सितंबर से दिसंबर एवं मार्च
33.	आईटीआई लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	3	4(57)	अप्रैल से मई
		6		6	3	3(50)	जून से सितंबर, नवंबर एवं फरवरी से मार्च
		5		5	3	2(40)	अक्टूबर, दिसंबर से जनवरी

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष का पद	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रति-शत में)	वर्ष 2023-24 के दौरान कमी की अवधि
34.	एसजेवीएन लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	4	3(43)	अप्रैल से अक्टूबर
		6		6	4	2(33)	नवंबर से जनवरी
35.	आरईसी लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	4	1(20)	अप्रैल से जनवरी
36.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	3	2(40)	अप्रैल से मई
		4		4	3	1(25)	जून से मार्च
37.	एनएचपीसी लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	5	1(17)	अक्टूबर से दिसंबर
38.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	8	कार्यकारी	8	6	2(25)	जून से अक्टूबर एवं दिसंबर से मार्च
		7		7	6	1(14)	नवंबर
39.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	2	5(71)	अप्रैल
		6		6	2	4(67)	मई
		6		6	3	3(50)	जून
		7		7	3	4(57)	जुलाई से अगस्त एवं अक्टूबर से मार्च
		5		5	3	2(40)	सितम्बर
40	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8	कार्यकारी	8	7	1(13)	फरवरी
		9		9	7	2(22)	मार्च

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष का पद	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रति-शत में)	वर्ष 2023-24 के दौरान कमी की अवधि
41	एनटीपीसी लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	4	3(43)	अप्रैल, जनवरी एवं मार्च
		6		6	4	2(33)	फरवरी
		8		8	4	4(50)	मई से दिसंबर
42.	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8	कार्यकारी	8	3	5(63)	अप्रैल एवं मई
		6		6	3	3(50)	जून से अगस्त
		7		7	3	4(57)	सितंबर-नवंबर
		7		7	2	5(71)	दिसंबर
		6		6	2	4(67)	जनवरी - मार्च
43.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	6	1(14)	अप्रैल से सितंबर
44.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	8	कार्यकारी	8	7	1(13)	जुलाई
45.	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	3	2(40)	अप्रैल से फरवरी
		5		5	4	1(20)	मार्च
46.	बीईएमएल लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	4	2(33)	अप्रैल से जून
		5		5	4	1(20)	जुलाई
47.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	2	2(50)	अप्रैल से फरवरी
		3		3	2	1(33)	मार्च

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष का पद	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2023-24 के दौरान कमी की अवधि
48.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	5 4 6	कार्यकारी	5 4 6	2 2 2	3(60) 2(50) 4(67)	अप्रैल मई से जुलाई अगस्त से मार्च
49.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	4 5	कार्यकारी	4 5	2 2	2(50) 3(60)	अप्रैल से जून जुलाई से मार्च

अनुलग्नक XX
(पैरा संख्या 4.2 देखें)
चयनित सीपीएसई के नाम

क्रम संख्या	सीपीएसई के नाम	संक्षिप्त नाम
	महारत्न	
1	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	बीएचईएल
2	कोल इंडिया लिमिटेड	कोल इंडिया
3	गेल इंडिया लिमिटेड	गेल
4	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एचपीसीएल
5	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आईओएसआई एल
6	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड	एनटीपीसी
7	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	ओएनजीसी
8	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	सेल
9	ऑयल इंडिया लिमिटेड	ओआईएल
10	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	एचएएल
	नवरत्न	
1	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	बीईएल
2	केंद्रीय भंडारण निगम	सीडब्ल्यूसी
3	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	इरेडा
4	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	एमडीएसएल
5	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	नालको
6	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड	एनएमडीसी
7	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम विदेश लिमिटेड	ओवीएल
	मिनीरत्न I	
1	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लिमिटेड	एएआई
2	भारत कुकिंग कोल लिमिटेड	बीसीसीएल
3	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	बीडीएल
4	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	बीईएमएल
5	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	एमडीएनएल
6	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

क्रम संख्या	सीपीएसई के नाम	संक्षिप्त नाम
7	टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	टी सी आई एल
	मिनीरत्न II	
1	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड	एलिम्को
2	मेकॉन लिमिटेड	मेकॉन

अनुलग्नक-XXIक
(पैरा संख्या 5.2 देखें)
सीपीएसई की सूची

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ कमाने वाली सीपीएसई (समान समूह के अनुसार) का शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब के अनुसार लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब में सीपीएसई की संख्या	स्लैब से चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का प्रतिशत
1	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-8974.03	5 करोड़ से कम	46 सीपीएसई	3 सीपीएसई	6.52%
2	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	-179.6				
3	एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड	-68.7				
4	द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-55.54				
5	डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड	-26.8				
6	ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	-16.54				
7	एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड	-12.79				
8	एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	-10.56				
9	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	-10.06				
10	पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज़ लिमिटेड	-9.34				
11	उडुपी कोचीन शिपयार्ड्स लिमिटेड	-8.67				
12	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	-3.58				

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ कमाने वाली सीपीएसई (समान समूह के अनुसार) का शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब के अनुसार लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब में सीपीएसई की संख्या	स्लैब से चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का प्रतिशत
13	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	-2.57				
14	नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	-1.47				
15	कॉनकोर एयर लिमिटेड	-1.1				
16	पंजाब लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	-0.91				
17	पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.77				
18	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-0.3				
19	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.16				
20	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	-0.07				
21	पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.01				
22	इरकॉन भोज मोर्बे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	0				
23	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइज़ेशन	0				
24	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	0				
25	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	0.1				
26	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	0.2				

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ कमाने वाली सीपीएसई (समान समूह के अनुसार) का शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब के अनुसार लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब में सीपीएसई की संख्या	स्लैब से चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का प्रतिशत
27	इरकॉन अकलोकी-सिरसाड एक्सप्रेसवे लिमिटेड	0.31				
28	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	0.32				
29	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.34				
30	इरकॉनहरिद्वारबाईपास लिमिटेड	0.77				
31	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.81				
32	बीपीसीएल-केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड	0.99				
33	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	1.56				
34	एसआईडीसीयूएल सीओएनसीओआर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	1.61				
35	कर्मयोगी भारत	1.97				
36	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.31				
37	नेशनल लैंड मॉनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2.99				
38	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड	3.04				
39	एचएसआरसी इंफ्रा सर्विसेज़ लिमिटेड	3.3				
40	एग्रीइनोवेट इंडिया लिमिटेड	3.51				

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ कमाने वाली सीपीएसई (समान समूह के अनुसार) का शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब के अनुसार लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब में सीपीएसई की संख्या	स्लैब से चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का प्रतिशत
41	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	3.58				
42	इरकॉन गुड़गांव-रेवाड़ी हाईवे सर्विसेज़	3.67				
43	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	4.06				
44	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4.27				
45	जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4.59				
46	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	4.86				
47	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.01	5 करोड़ - 10 करोड़ के बीच	18 सीपीएसई	2 सीपीएसई	11.11%
48	नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	5.09				
49	नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.21				
50	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड	5.33				
51	बीईएल ऑप्ट्रोनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	6.76				
52	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.79				
53	ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड	6.86				

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ कमाने वाली सीपीएसई (समान समूह के अनुसार) का शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब के अनुसार लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब में सीपीएसई की संख्या	स्लैब से चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का प्रतिशत
54	बीईएल -थैल्स सिस्टम्स लिमिटेड	7				
55	एचएमटी लिमिटेड	7.06				
56	एनबीसीसी सर्विसेज़ लिमिटेड	7.24				
57	कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	7.64				
58	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	8.21				
59	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	8.86				
60	बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल	9.06				
61	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	9.17				
62	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लिमिटेड	9.74				
63	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	9.74				
64	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	9.82	10 करोड़ - 50 करोड़ के बीच	40 सीपीएसई	4 सीपीएसई	10%
65	द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10.01				
66	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	10.19				

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ कमाने वाली सीपीएसई (समान समूह के अनुसार) का शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब के अनुसार लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब में सीपीएसई की संख्या	स्लैब से चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का प्रतिशत
67	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	10.25				
68	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	11.3				
69	द बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	11.74				
70	रिचर्डसन एंड क्रूडस (1972) लिमिटेड	12.72				
71	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	12.87				
72	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13.94				
73	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	14.08				
74	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	14.83				
75	नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	14.99				
76	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	17.49				
77	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	17.75				
78	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	18.97				
79	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	20.81				
80	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	21.74				

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ कमाने वाली सीपीएसई (समान समूह के अनुसार) का शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब के अनुसार लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब में सीपीएसई की संख्या	स्लैब से चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का प्रतिशत
81	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	22.67				
82	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	23.15				
83	नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	24.29				
84	ब्रह्मपुत्रवैलीफर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24.38				
85	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	24.88				
86	HLL इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड	25.01				
87	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	26.37				
88	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	26.84				
89	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन	29.12				
90	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन लिमिटेड	29.16				
91	नेशनल बैंकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	30.35				
92	मेकॉन लिमिटेड	31.01				
93	टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड	35.49				
94	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड	35.55				

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ कमाने वाली सीपीएसई (समान समूह के अनुसार) का शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब के अनुसार लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब में सीपीएसई की संख्या	स्लैब से चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का प्रतिशत
95	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	38.38				
96	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	39.77				
97	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	40.9				
98	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	41.1				
99	यंत्र इंडिया लिमिटेड	42.36				
100	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	45.24				
101	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	47.62				
102	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	48.54				
103	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	49.69				
104	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	49.73				
105	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	51.11	50 करोड़ - 100 करोड़ के बीच	18 सीपीएसई	4 सीपीएसई	22.22%
106	नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	53.3				
107	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	56.28				
108	ग्रिड नियंत्रण ऑफ इंडिया लिमिटेड	58.18				

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ कमाने वाली सीपीएसई (समान समूह के अनुसार) का शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब के अनुसार लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब में सीपीएसई की संख्या	स्लैब से चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का प्रतिशत
109	रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	59.04				
110	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	63.81				
111	नेशनल माइनोंरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन	65.17				
112	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	65.24				
113	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	65.71				
114	ईडीसीआइएल (इंडिया) लिमिटेड	65.95				
115	आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	72.93				
116	म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड	73.35				
117	बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	73.42				
118	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड	78.31				
119	मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	86.27				
120	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज़ कंपनी लिमिटेड	87.55				
121	चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	88.69				
122	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	95.29				

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ कमाने वाली सीपीएसई (समान समूह के अनुसार) का शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब के अनुसार लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब में सीपीएसई की संख्या	स्लैब से चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का प्रतिशत
123	नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	110.48	100 करोड़ - 500 करोड़ के बीच	38 सीपीएसई	8 सीपीएसई	21.05%
124	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सिक्युरिटाइज़ेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्युरिटी इंटररेस्ट ऑफ़ इंडिया	117.62				
125	पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	129.9				
126	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	139.79				
127	नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इनकॉर्पोरेटेड	149.77				
128	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	153.86				
129	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	154.55				
130	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	155.88				
131	बीईएमएल लिमिटेड	158.78				
132	एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	174.44				
133	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	175.89				
134	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	185.33				
135	रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	188.25				
136	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड	206.91				

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ कमाने वाली सीपीएसई (समान समूह के अनुसार) का शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब के अनुसार लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब में सीपीएसई की संख्या	स्लैब से चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का प्रतिशत
137	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	222.39				
138	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	223.65				
139	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	224.7				
140	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	228.12				
141	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	231.14				
142	इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइज़ेशन	232.22				
143	एमएसटीसी लिमिटेड	239.23				
144	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	243.99				
145	एमओआईएल लिमिटेड	250.59				
146	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	269.7				
147	आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड	271.17				
148	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	278.65				
149	कॉकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	278.93				
150	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	295.31				

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ कमाने वाली सीपीएसई (समान समूह के अनुसार) का शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब के अनुसार लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब में सीपीएसई की संख्या	स्लैब से चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का प्रतिशत
151	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड	296.66				
152	गेल गैस लिमिटेड	297.04				
153	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया	315.65				
154	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	334.49				
155	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	342.15				
156	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	352.17				
157	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन	369.58				
158	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	396.9				
159	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	456.1				
160	न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड	459.98				
161	राइट्स लिमिटेड	530.54	500 करोड़ - 10,500 करोड़ के बीच	45 सीपीएसई	31 सीपीएसई	68.89%
162	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड	612.83				
163	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	624.28				
164	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	628.47				
165	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	664.78				

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ कमाने वाली सीपीएसई (समान समूह के अनुसार) का शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब के अनुसार लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब में सीपीएसई की संख्या	स्लैब से चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का प्रतिशत
166	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	673.09				
167	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	776.83				
168	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	800.12				
169	एनएचडीसी लिमिटेड	800.52				
170	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	808.61				
171	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव. एजेंसी लिमिटेड	864.63				
172	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	892.8				
173	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	967.15				
174	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,005.88				
175	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	1,072.72				
176	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	1,075.6				
177	एमएमटीसी लिमिटेड	1,076.07				
178	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	1,169.08				
179	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	1,248.24				
180	रेल विकास निगम लिमिटेड	1,267.97				

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ कमाने वाली सीपीएसई (समान समूह के अनुसार) का शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब के अनुसार लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब में सीपीएसई की संख्या	स्लैब से चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का प्रतिशत
181	एसजेवीएन लिमिटेड	1,363.45				
182	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	1,544.49				
183	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,615.25				
184	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	1,701.62				
185	सिक्क्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	1,779.25				
186	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,870.10				
187	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,903.07				
188	ईसीजीसी लिमिटेड	2,164.25				
189	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	2,638.39				
190	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	2,972.05				
191	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	3,006.67				
192	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	3,062.02				
193	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	3,393.30				
194	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3,533.81				
195	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	3,702.79				
196	एनएचपीसी लिमिटेड	3,833.79				

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ कमाने वाली सीपीएसई (समान समूह के अनुसार) का शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब के अनुसार लाभ (₹ करोड़ में)	स्लैब में सीपीएसई की संख्या	स्लैब से चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का प्रतिशत
197	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	3,865.31				
198	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5,146.01				
199	गेल (इंडिया) लिमिटेड	5,301.51				
200	एनएमडीसी लिमिटेड	5,528.63				
201	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	5,811.17				
202	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	6,167.16				
203	ऑयल इंडिया लिमिटेड	6,810.40				
204	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	7,123.39				
205	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8,241.82				
206	आरईसी लिमिटेड	11,054.64	10,500 करोड़ से ज्यादा	7 सीपीएसई	7 सीपीएसई	100%
207	पावर फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11,605.47				
208	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	13,470.16				
209	कोल इंडिया लिमिटेड	14,802.31				
210	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	15,335.54				
211	एनटीपीसी लिमिटेड	17,196.73				
212	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	40,096.50				

अनुलग्नक-XXI ख
(पैरा संख्या 5.2 देखें)
चयनित सीपीएसई की सूची

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ कमाने वाली सीपीएसई (समान समूह के अनुसार) का शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का %
1	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	40,096.50	₹10,500 करोड़ से ज्यादा के स्लैब में 7 सीपीएसई को चुना गया।	100%
2	एनटीपीसी लिमिटेड	17,196.73		
3	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	15,335.54		
4	कोल इंडिया लिमिटेड	14,802.31		
5	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	13,470.16		
6	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11,605.47		
7	आरईसी लिमिटेड	11,054.64		
8	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8,241.82	₹500 करोड़ से ₹10,500 करोड़ के स्लैब में 45 सीपीएसई में से 31 सीपीएसई को चुना गया।	68.89%
9	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	7,123.39		
10	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6,167.16		
11	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	3,865.31		
12	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	3,702.79		
13	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3,533.81		
14	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	3,062.02		
15	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	2,638.39		
16	ईसीजीसी लिमिटेड	2,164.25		

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ कमाने वाली सीपीएसई (समान समूह के अनुसार) का शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का %
17	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,903.07		
18	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,870.10		
19	सिक्क्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	1,779.25		
20	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,615.25		
21	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	1,544.49		
22	एसजेवीएन लिमिटेड	1,363.45		
23	रेल विकास निगम लिमिटेड	1,267.97		
24	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	1,248.24		
25	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,169.08		
26	एमएमटीसी लिमिटेड	1,076.07		
27	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	1,075.60		
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	1,072.72		
29	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,005.88		
30	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	967.15		
31	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	892.80		
32	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	864.63		

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ कमाने वाली सीपीएसई (समान समूह के अनुसार) का शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का %
33	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	808.61		
34	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	800.12		
35	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	628.47		
36	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	624.28		
37	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	612.83		
38	राइट्स लिमिटेड	530.54		
39	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	295.31	₹100 करोड़ - ₹500 करोड़ के स्लैब में 38 सीपीएसई में से 8 सीपीएसई को चुना गया।	21.05%
40	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	269.7		
41	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	228.12		
42	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	224.7		
43	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	222.39		
44	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड	206.91		
45	मिश्रा धातु निगम लिमिटेड	155.88		
46	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्युरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्युरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया	117.62		

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभ कमाने वाली सीपीएसई (समान समूह के अनुसार) का शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का %
47	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	65.71	₹50 करोड़ - ₹100 करोड़ के स्लैब में 18 सीपीएसई में से 4 सीपीएसई चयनित	22.22%
48	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	65.17		
49	ग्रिड नियंत्रण ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	58.18		
50	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	51.11		
51	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	24.29	₹10 करोड़ - ₹50 करोड़ के स्लैब में 40 सीपीएसई में से 4 सीपीएसई चयनित	10%
52	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	20.81		
53	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	14.08		
54	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	10.19		
55	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड	5.33	₹5 करोड़ - ₹10 करोड़ के स्लैब में 18 सीपीएसई में से 2 सीपीएसई चयनित।	11.11%
56	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.01		
57	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	4.86	₹5 करोड़ से कम लाभ कमाने वाली 46 सीपीएसई में से 3 सीपीएसई को चुना गया।	6.52%
58	जम्मू-कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4.59		
59	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4.27		

अनुलग्नक-XXII
(पैरा संख्या 5.3.2 देखें)
सीएसआर नीति तैयार करना

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर समिति ने सीएसआर नीति तैयार करके बोर्ड को उसकी सिफारिश की थी?	क्या कंपनी के बोर्ड ने सीएसआर पॉलिसी को मंजूरी दी थी?
1	नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	कंपनी में सीएसआर कमिटी नहीं है।	हाँ
2	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	हाँ	हाँ
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	हाँ	हाँ
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	नहीं	हाँ
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	हाँ	हाँ
6	नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसटीएफडीसी)	हाँ	हाँ
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	हाँ	हाँ
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	हाँ	हाँ
9	नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन (एनएमडीएफसी)	हाँ	हाँ
10	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
11	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सिक्युरिटाइज़ेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरैस्ट ऑफ़ इंडिया (सीएसआरएसएआई)	नहीं	हाँ
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (एमआईडीएचएनआई)	हाँ	हाँ
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	नहीं	नहीं
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	हाँ	हाँ
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	हाँ	हाँ
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	हाँ	हाँ
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	हाँ	हाँ

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर समिति ने सीएसआर नीति तैयार करके बोर्ड को उसकी सिफारिश की थी?	क्या कंपनी के बोर्ड ने सीएसआर पॉलिसी को मंजूरी दी थी?
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	हाँ	हाँ
19	आरआईटीएस लिमिटेड	हाँ	हाँ
20	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड (एफएसीटी)	हाँ	हाँ
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल)	हाँ	हाँ
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	हाँ	हाँ
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ	हाँ
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (आईआरईडीए)	हाँ	हाँ
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (आरसीएफ)	हाँ	हाँ
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	हाँ	हाँ
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	हाँ	हाँ
29	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	हाँ	हाँ
30	एमएमटीसी लिमिटेड	नहीं	हाँ
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीओएनसीओआर)	हाँ	हाँ
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	हाँ	हाँ
34	एसजेवीएन लिमिटेड	नहीं	हाँ
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (एनएलसीओ)	हाँ	हाँ
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	हाँ	हाँ
37	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	हाँ	हाँ
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	हाँ	हाँ
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल)	हाँ	हाँ
40	ईसीजीसी लिमिटेड	हाँ	हाँ

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर समिति ने सीएसआर नीति तैयार करके बोर्ड को उसकी सिफारिश की थी?	क्या कंपनी के बोर्ड ने सीएसआर पॉलिसी को मंजूरी दी थी?
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	हाँ	हाँ
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	हाँ	हाँ
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	हाँ	हाँ
44	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	हाँ	हाँ
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	हाँ	हाँ
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	हाँ	हाँ
47	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	हाँ	हाँ
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ
49	आरईसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	हाँ	हाँ
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	हाँ	हाँ
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	हाँ	हाँ
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	हाँ	हाँ
54	एनटीपीसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी)	हाँ	हाँ
56	जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	हाँ	हाँ
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	लागू नहीं	लागू नहीं
58	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	हाँ	नहीं

अनुलग्नक-XXIII
(पैरा संख्या 5.4.1 देखें)
कुल सीएसआर व्यय

(₹ लाख में)

क. सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत लाभ	ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2%	उपलब्ध सेट-ऑफ़	पिछले वर्ष का अधिशेष	सीएसआर दायित्व	चालू वर्ष के फंड से कुल सीएसआर व्यय
1	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	335.32	6.7	0	0	0	0
2	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	1,185.00	24	0	0	24	24
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	938.45	18.77	0	0	18.78	18.78
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	986.00	19.71	0	0	19.71	19.71
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	3,019.61	60.39	0	0	60.39	60.39
6	नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसटीएफडीसी)	2,506.49	50.13	1.73	1.31	49.71	63.88
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	4,064.79	81.3	0	0	81.3	81.3
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	5,542.54	110.85	0	0	110.85	110.85
9	नेशनल माइनोंरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन (एनएमडीएफसी)	6,612.37	132.25	0	0	132.25	0

क. सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत लाभ	ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2%	उपलब्ध सेट-ऑफ़	पिछले वर्ष का अधिशेष	सीएसआर दायित्व	चालू वर्ष के फंड से कुल सीएसआर व्यय
10	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	49,928.56	998.56	88.63	0	909.93	909.93
11	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सिक्युरिटाइज़ेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटररेस्ट ऑफ़ इंडिया (सीएसआरएसएआई)	8,976.44	179.53	179.53	0	0	0
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (एमआइडीएचएनआई)	22,733.80	454.68	0	0	454.68	455.02
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	20,034.62	400.69	0	0	400.69	400.69
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	9,074.89	181.5	0	0	181.5	181.5
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	19,017.46	380.35	0	0	380.35	393.03
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	25,544.02	510.88	0	0	511	511
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	27,066.75	541.33	0	2.83	544.16	541.33
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	28,809.33	576.19	254.6	0	321.59	265.28
19	आरआईटीएस आरआईटीईएस लिमिटेड	66,408.00	1330	0	0	1330	1331
20	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी)	43,661.02	873.22	263	0	610.22	1662.46
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	-940.77	-18.82	0	0	0	0

क. सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत लाभ	ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2%	उपलब्ध सेट-ऑफ़	पिछले वर्ष का अधिशेष	सीएसआर दायित्व	चालू वर्ष के फंड से कुल सीएसआर व्यय
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल)	45,500.17	910	0	0	910	910.03
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	73,507.00	1470.13	0	0	1470.13	544.62
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	76,810.96	1536.22	0	0	1536.22	1602.02
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (आईआरईडीए)	84,675.83	1693.52	28.93	0	1664.59	551.68
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (आरसीएफ)	88,398.00	1768	50	0	1718	2008
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	83,240.10	1664.8	0	0	1664.8	1664.8
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	91,860.63	1837.21	0	0	1837.21	2230
29	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	72,469.24	1449.38	0	0	1449.38	45.51
30	एमएमटीसी लिमिटेड	-39,464.00	-789	0	0	0	0
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीओएनसीओआर)	1,31,964.00	2745	0	0	2745	614
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	2,01,356.00	4027	0	0	4027	4736.25
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	1,40,205.00	2804.1	280	0	2524.1	2971
34	एसजेवीएन लिमिटेड	1,73,038.00	3460.76	0	0	3460.76	4595.78
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (एनएलसीओ)	46,735.00	4815.03	0	0	4815.03	5053.82

क. सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत लाभ	ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2%	उपलब्ध सेट-ऑफ़	पिछले वर्ष का अधिशेष	सीएसआर दायित्व	चालू वर्ष के फंड से कुल सीएसआर व्यय
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	74,616.00	1,492.32	317.00	0	1,175.32	1,397.07
37	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	133,702.00	2,674.05	276.54	0	2,397.51	285.09
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	1,031,447.98	20,628.95	0.00	47	20,675.95	15,818.90
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	816,289.33	16,325.79	451.00	0	15,874.79	16,193.00
40	ईसीजीसी लिमिटेड	150,303.87	3,006.08	0.00	0	3,010.00	2,908.80
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	201,804.00	4,036.08	500.00	0	3,536.08	2,048.00
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	329,897.67	6,597.95	0.00	0	6,597.95	2,755.72
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	152,374.33	3,047.49	1,774.00	0	1,273.49	2,011.51
44	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	461,328.00	9,227.00	820.00	0	8,407.00	8,598.00
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	257,060.00	5,141.00	0.00	0	5,141.00	5,307.00
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	561,373.00	11,227.00	0.00	0	11,227.00	3,133.22
47	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	752,096.00	15,041.92	150.00	0	14,891.92	15,787.44
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,144,478.00	42,890.00	648.00	0	42,242.00	45,771.00
49	आरईसी लिमिटेड	1,249,309.00	24,986.00	770.00	0	24,216.00	24,731.00
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	1,076,971.92	21,539.44	0.00	0	21,539.44	9,937.00

क. सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत लाभ	ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2%	उपलब्ध सेट-ऑफ़	पिछले वर्ष का अधिशेष	सीएसआर दायित्व	चालू वर्ष के फंड से कुल सीएसआर व्यय
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	13,08,128.00	26,162.56	11,899.90	98.57	14,361.23	16,289.02
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	56,519.33	1,130.39	0.00	0	1,130.39	9,855.59
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	17,13,407.00	34,269.00	3,045.00	0	31,224.00	33,048.00
54	एनटीपीसी लिमिटेड	16,89,880.00	33,798.00	22,519.00	0	11,279.00	20,057.00
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी)	32,51,671.67	65,033.43	4,613.50	0	60,419.93	63,457.45
56	जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	640.30	12.80	0.00	0	12.80	14.00
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	-229.73	-4.59	0.00	0	0.00	0.00
58	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	1,171.72	23.43	0.00	0	23.43	19.52
	योग	1,90,30,040.03	3,84,590.45	48,930.36	149.71	3,36,619.56	3,33,980.99

अनुलग्नक-XXIII क
(पैरा संख्या 5.4.1 देखें)
कुल सीएसआर व्यय (दायित्व से अधिक)

(₹ लाख में)

क. सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत लाभ	ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2%	उपलब्ध सेट-ऑफ़	पिछले वर्ष का अधिशेष	सीएसआर दायित्व	चालू वर्ष के निधि से कुल सीएसआर व्यय	दायित्व एवं वास्तविकता में अंतर	ज़रूरी दायित्व से अधिक (%) में
1	नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएसटीएफडीसी)	2,506.49	50.13	1.73	1.31	49.71	63.88	14.17	28.51
2	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी)	22,733.80	454.68	0.00	0	454.68	455.02	0.34	0.07
3	नेशनल हाईवेज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	19,017.46	380.35	0.00	0	380.35	393.03	12.68	3.33
4	आरआईटीईएस लिमिटेड	66,408.00	1,330.00	0.00	0	1,330.00	1,331.00	1	0.08
5	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड (एफएसीटी)	43,661.02	873.22	263.00	0	610.22	1,662.46	1052.24	172.44
6	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईएसएल)	45,500.17	910.00	0.00	0	910.00	910.03	0.03	0.00329
7	आईआरएल (इंडिया) लिमिटेड	76,810.96	1,536.22	0.00	0	1,536.22	1,602.02	65.8	4.28

क. सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत लाभ	ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2%	उपलब्ध सेट-ऑफ़	पिछले वर्ष का अधिशेष	सीएसआर दायित्व	चालू वर्ष के निधि से कुल सीएसआर व्यय	दायित्व एवं वास्तविकता में अंतर	ज़रूरी दायित्व से अधिक (%) में
8	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (आरसीएफ)	88,398.00	1,768.00	50.00	0	1,718.00	2,008.00	290	16.88
9	मज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	91,860.63	1,837.21	0.00	0	1,837.21	2,230.00	392.79	21.38
10	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	2,01,356.00	4,027.00	0.00	0	4,027.00	4,736.25	709.25	17.61
11	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	1,40,205.00	2,804.10	280.00	0	2,524.10	2,971.00	446.9	17.71
12	एसजेवीएन लिमिटेड	1,73,038.00	3,460.76	0.00	0	3,460.76	4,595.78	1,135.02	32.8
13	नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	46,735.00	4,815.03	0.00	0	4,815.03	5,053.82	238.79	4.96
14	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	74,616.00	1,492.32	317.00	0	1,175.32	1,397.07	221.75	18.87
15	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएआईएल)	8,16,289.30	16,325.79	451.00	0	15,874.79	16,193.00	318.21	2
16	चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	1,52,374.30	3,047.49	1,774.00	0	1,273.49	2,011.51	738.02	57.95
17	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	4,61,328.00	9,227.00	820.00	0	8,407.00	8,598.00	191	2.27
18	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	2,57,060.00	5,141.00	0.00	0	5,141.00	5,307.00	166	3.23

क. सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत लाभ	ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2%	उपलब्ध सेट-ऑफ़	पिछले वर्ष का अधिशेष	सीएसआर दायित्व	चालू वर्ष के निधि से कुल सीएसआर व्यय	दायित्व एवं वास्तविकता में अंतर	ज़रूरी दायित्व से अधिक (%) में
19	नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	7,52,096.00	15,041.92	150.00	0	14,891.92	15,787.44	895.52	6.01
20	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	21,44,478.00	42,890.00	648.00	0	42,242.00	45,771.00	3,529.00	8.35
21	आरईसी लिमिटेड	12,49,309.00	24,986.00	770.00	0	24,216.00	24,731.00	515.00	2.13
22	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	13,08,128.00	26,162.56	11,899.90	98.57	14,361.23	16,289.02	1,927.79	13.42
23	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	56,519.33	1,130.39	0.00	0	1,130.39	9,855.59	8,725.20	771.88
24	पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	17,13,407.00	34,269.00	3,045.00	0	31,224.00	33,048.00	1,824.00	5.84
25	एनटीपीसी लिमिटेड	16,89,880.00	33,798.00	22,519.00	0	11,279.00	20,057.00	8,778.00	77.83
26	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी)	32,51,672.00	65,033.43	4,613.50	0	60,419.93	63,457.45	3,037.52	5.03
27	जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	640.30	12.80	0.00	0	12.80	14.00	1.20	9.37
	योग	1,49,46,027.00	3,02,804.40	47,602.13	99.88	2,55,302.15	2,90,529.37	35,227.22	

अनुलग्नक-XXIIIख
(पैरा संख्या 5.4.1 देखें)
2023-24 के लिए कोई दायित्व नहीं

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत लाभ	ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2%	उपलब्ध सेट-ऑफ़	पिछले वर्ष का अधिशेष	सीएसआर दायित्व	चालू वर्ष के फंड से कुल सीएसआर व्यय
1	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	335.32	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सिक्युरिटाइज़ेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्युरिटी इंटररेस्ट ऑफ़ इंडिया (सीएसआरएसएआई)	8976.44	179.53	179.53	0.00	0.00	0.00
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	-940.77	-18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
4	एमएमटीसी लिमिटेड	-39,464.00	-789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	229.73	-4.59	0.00	0.00	0.00	0.00

अनुलग्नक-XXIII ग
(पैरा संख्या 5.4.1 देखें)
कुल सीएसआर व्यय, दायित्व से कम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत लाभ	ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2%	उपलब्ध सेट-ऑफ़	पिछले वर्ष का अधिशेष	सीएसआर दायित्व	चालू वर्ष के फंड से कुल सीएसआर व्यय	दायित्व एवं वास्तविकता में अंतर	कमी का प्रतिशत
1	नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनैस कॉरपोरेशन (एनएमडीएफसी)	6,612.37	132.25	0.00	0	132.25	0.00	-132.25	-100
2	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	27,066.75	541.33	0.00	2.83	544.16	541.33	-2.83	-0.52
3	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	28,809.33	576.19	254.60	0	321.59	265.28	-56.31	-17.51
4	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	73,507.00	1,470.13	0.00	0	1,470.13	544.62	-925.51	-62.95
5	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (आईआरईडीए)	84,675.83	1,693.52	28.93	0	1,664.59	551.68	-1,112.91	-66.86
6	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	72,469.24	1,449.38	0.00	0	1,449.38	45.51	-1,403.87	-96.86
7	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	1,31,964.00	2,745.00	0.00	0	2,745.00	614.00	-2,131.00	-77.63
8	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	1,33,702.00	2,674.05	276.54	0	2,397.51	285.09	-2,112.42	-88.11
9	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	10,31,447.98	20,628.95	0.00	47	20,675.95	15,818.90	-4,857.05	-23.49
10	ईसीजीसी लिमिटेड	1,50,303.87	3,006.08	0.00	0	3,010.00	2,908.80	-101.20	-3.36

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत लाभ	ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2%	उपलब्ध सेट-ऑफ़	पिछले वर्ष का अधिशेष	सीएसआर दायित्व	चालू वर्ष के फंड से कुल सीएसआर व्यय	दायित्व एवं वास्तविकता में अंतर	कमी का प्रतिशत
11	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	2,01,804.00	4,036.08	500.00	0	3,536.08	2,048.00	-1,488.08	-42.08
12	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	3,29,897.67	6,597.95	0.00	0	6,597.95	2,755.72	-3,842.23	-58.23
13	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	5,61,373.00	11,227.00	0.00	0	11,227.00	3,133.22	-8,093.78	-72.09
14	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	10,76,971.92	21,539.44	0.00	0	21,539.44	9,937.00	-11,602.44	-53.87
15	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	1,171.72	23.43	0.00	0	23.43	19.52	-3.91	-16.69
	योग					77,334.46	39,468.67	37,865.79	

अनुलग्नक-XXIII घ
(पैरा संख्या 5.4.1 देखें)
कुल सीएसआर व्यय दायित्व के बराबर

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत लाभ	ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2%	उपलब्ध सेट-ऑफ़	पिछले वर्ष का अधिशेष	सीएसआर दायित्व	चालू वर्ष के फंड से कुल सीएसआर व्यय
1	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	1,185.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00
2	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	938.45	18.77	0.00	0.00	18.78	18.78
3	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	986.00	19.71	0.00	0.00	19.71	19.71
4	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	3,019.61	60.39	0.00	0.00	60.39	60.39
5	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	4,064.79	81.30	0.00	0.00	81.30	81.30
6	ग्रिड नियंत्रण ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	5,542.54	110.85	0.00	0.00	110.85	110.85
7	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	49,928.56	998.56	88.63	0	909.93	909.93
8	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	20,034.62	400.69	0.00	0.00	400.69	400.69
9	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	9,074.89	181.50	0.00	0.00	181.50	181.50

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत लाभ	ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के औसत लाभ का 2%	उपलब्ध सेट-ऑफ़	पिछले वर्ष का अधिशेष	सीएसआर दायित्व	चालू वर्ष के फंड से कुल सीएसआर व्यय
10	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	25,544.02	510.88	0.00	0.00	511.00	511.00
11	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीएस)	83,240.10	1,664.80	0.00	0.00	1,664.80	1,664.80

अनुलग्नक-XXIV
(पैरा संख्या 5.4.2 देखें)
रत्न श्रेणी-वार सीएसआर व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	मंत्रालय का नाम	सीपीएसई की स्थिति	सीएसआर व्यय	योग व्यय का प्रतिशत
महारत्न सीपीएसई (10)					
1	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई)	महारत्न	0.00	0.00%
2	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	कोयला मंत्रालय	महारत्न	9,855.59	2.95%
3	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	विद्युत मंत्रालय	महारत्न	33,048.00	9.89%
4	एनटीपीसी लिमिटेड	विद्युत मंत्रालय	महारत्न	20,057.00	6.01%
5	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	महारत्न	63,457.45	19.00%
6	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	महारत्न	15,818.90	4.74%
7	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल)	इस्पात मंत्रालय	महारत्न	16,193.00	4.85%
8	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	महारत्न	45,771.00	13.70%
9	आरईसी लिमिटेड	विद्युत मंत्रालय	महारत्न	24,731.00	7.40%
10	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	विद्युत मंत्रालय	महारत्न	9,937.00	2.98%
क]	महारत्न सीपीएसई का सीएसआर व्यय			2,38,869.00	71.52%
नवरत्न सीपीएसई (12)					
11	राइट्स लिमिटेड	रेल मंत्रालय	नवरत्न	1,331.00	0.40%
12	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	नवरत्न	544.62	0.16%

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	मंत्रालय का नाम	सीपीएसई की स्थिति	सीएसआर व्यय	योग व्यय का प्रतिशत
13	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	रक्षा मंत्रालय	नवरत्न	2,755.72	0.83%
14	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (आईआरईडीए)	नवीन एवं नवीकरणीय विद्युत मंत्रालय	नवरत्न	551.68	0.16%
15	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	नवरत्न	2,008.00	0.60%
16	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	रेल मंत्रालय	नवरत्न	1,664.80	0.50%
17	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	रक्षा मंत्रालय	नवरत्न	2,230.00	0.67%
18	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	रेल मंत्रालय	नवरत्न	614.00	0.18%
19	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	कोयला मंत्रालय	नवरत्न	4,736.25	1.42%
20	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	रेल मंत्रालय	नवरत्न	2,971.00	0.89%
21	एसजेवीएन लिमिटेड	विद्युत मंत्रालय	नवरत्न	4,595.78	1.38%
22	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	खान मंत्रालय	नवरत्न	5,053.82	1.51%
ख]	नवरत्न सीपीएसई का सीएसआर व्यय			29,056.00	8.70%
मिनीरत्न सीपीएसई (18)					
23	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	लघु रत्न	0.00	0.00%

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	मंत्रालय का नाम	सीपीएसई की स्थिति	सीएसआर व्यय	योग व्यय का प्रतिशत
24	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	लघु रत्न	19.71	0.01%
25	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	आयुष मंत्रालय	लघु रत्न	60.39	0.02%
26	ग्रिड नियंत्रण ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	विद्युत मंत्रालय	लघु रत्न	110.85	0.03%
27	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	कोयला मंत्रालय	लघु रत्न	1,397.07	0.42%
28	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	वित्त मंत्रालय	लघु रत्न	285.09	0.09%
29	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	रक्षा मंत्रालय	लघु रत्न	455.02	0.14%
30	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	रक्षा मंत्रालय	लघु रत्न	511.00	0.15%
31	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	परमाणु ऊर्जा विभाग	लघु रत्न	541.16	0.16%
32	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	खान मंत्रालय	लघु रत्न	265.28	0.08%
33	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	लघु रत्न	2,011.51	0.60%
34	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	लघु रत्न	8,598.00	2.57%

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	मंत्रालय का नाम	सीपीएसई की स्थिति	सीएसआर व्यय	योग व्यय का प्रतिशत
35	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	कोयला मंत्रालय	लघु रत्न	5,307.00	1.59%
36	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	रेल मंत्रालय	लघु रत्न	3,133.00	0.94%
37	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	कोयला मंत्रालय	लघु रत्न	15,787.44	4.73%
38	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	परमाणु ऊर्जा विभाग	लघु रत्न	1,602.02	0.48%
39	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	लघु रत्न	2,048.00	0.61%
40	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	कोयला मंत्रालय	लघु रत्न	16,289.02	4.88%
ग]	मिनीरत्न सीपीएसई सीएसआर व्यय			58,422.00	17.49%
अन्य सीपीएसई (18)					
41	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	रेल मंत्रालय	अन्य (नहीं)	24.00	0.01%
42	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	अन्य (कोई नहीं)	18.78	0.01%
43	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	जनजातीय कार्य मंत्रालय	नहीं	63.88	0.02%
44	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	विद्युत मंत्रालय	लागू नहीं	81.30	0.02%

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	मंत्रालय का नाम	सीपीएसई की स्थिति	सीएसआर व्यय	योग व्यय का प्रतिशत
45	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	नहीं	0.00	0.00%
46	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परमाणु ऊर्जा विभाग	अन्य (अनुसूची ख)	909.93	0.27%
47	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	वित्त मंत्रालय	शून्य	0.00	0.00%
48	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	रक्षा मंत्रालय	अनुसूची-'ख'	400.69	0.12%
49	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	विद्युत मंत्रालय	अन्य	181.50	0.05%
50	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	सड़क एवं परिवहन मंत्रालय	कोई नहीं	393.03	0.12%
51	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीआई)	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	नहीं	1,662.46	0.50%
52	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल)	नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए)	नहीं	910.03	0.27%
53	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	लागू नहीं	45.51	0.01%
54	एमएमटीसी लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग	नहीं	0.00	0.00%

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	मंत्रालय का नाम	सीपीएसई की स्थिति	सीएसआर व्यय	योग व्यय का प्रतिशत
55	ईसीजीसी लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	अन्य (लागू नहीं)	2,908.80	0.87%
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	नहीं	14.00	0.00%
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय	नहीं	0.00	0.00%
58	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई)	नहीं	19.52	0.01%
घ]	अन्य सीपीएसई का सीएसआर व्यय			7633	2.29%
	योग (क+ख+ग+घ)			3,33,980.6	100.00

अनुलग्नक-XXV
(पैरा संख्या 5.4.2 देखें)
मंत्रालय-वार / विभाग-वार सीएसआर व्यय

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	मंत्रालय का नाम	सीपीएसई की स्थिति	सीएसआर व्यय	योग व्यय का प्रतिशत
क] पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (6)					
01	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	महारत्न	15,818.90	4.74%
02	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	लघु रत्न	2,048.00	0.61%
03	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	लघु रत्न	2,011.51	0.60%
04	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	लघु रत्न	8,598.00	2.57%
05	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	महारत्न	45,771.00	13.70%
06	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	महारत्न	63,457.45	19.00%
क] एमओपीएनजी सीपीएसई का सीएसआर व्यय				1,37,704.86	41.23%
ख] विद्युत मंत्रालय (8)					
07	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	विद्युत मंत्रालय	लागू नहीं	81.30	0.02%
08	ग्रिड नियंत्रण ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	विद्युत मंत्रालय	लघु रत्न	110.85	0.03%
09	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	विद्युत मंत्रालय	अन्य	181.50	0.05%
10	एसजेवीएन लिमिटेड	विद्युत मंत्रालय	नवरत्न	4,595.78	1.38%
11	आरईसी लिमिटेड	विद्युत मंत्रालय	महारत्न	24,731.00	7.40%
12	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	विद्युत मंत्रालय	महारत्न	9,937.00	2.98%
13	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	विद्युत मंत्रालय	महारत्न	33,048.00	9.90%

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	मंत्रालय का नाम	सीपीएसई की स्थिति	सीएसआर व्यय	योग व्यय का प्रतिशत
14	एनटीपीसी लिमिटेड	विद्युत मंत्रालय	महारत्न	20,057.00	6.01%
ख] बिजली मंत्रालय के सीपीएसई का सीएसआर व्यय				92,742.43	27.77%
ग] कोयला मंत्रालय (6)					
15	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	कोयला मंत्रालय	नवरत्न	4,736.25	1.42%
16	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	कोयला मंत्रालय	लघु रत्न	1,397.07	0.42%
17	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	कोयला मंत्रालय	लघु रत्न	5,307.00	1.59%
18	नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	कोयला मंत्रालय	लघु रत्न	15,787.44	4.73%
19	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	कोयला मंत्रालय	लघु रत्न	16,289.02	4.88%
20	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	कोयला मंत्रालय	महारत्न	9,855.59	2.95%
ग] कोयला मंत्रालय की सीपीएसई का सीएसआर व्यय				53,372.37	15.98%
घ] इस्पात मंत्रालय (1)					
21	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	इस्पात मंत्रालय	महारत्न	16,193.00	4.85%
घ] इस्पात मंत्रालय के सीपीएसई का सीएसआर व्यय				16,193.00	4.85%
ड] रेल मंत्रालय (6)					
22	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	रेल मंत्रालय	अन्य (नहीं)	24.00	0.01%
23	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	रेल मंत्रालय	नवरत्न	1,664.80	0.50%
24	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	रेल मंत्रालय	नवरत्न	2,971.00	0.89%
25	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	रेल मंत्रालय	लघु रत्न	3,133.00	0.94%
26	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	रेल मंत्रालय	नवरत्न	614.00	0.18%
27	राइट्स लिमिटेड	रेल मंत्रालय	नवरत्न	1,331.00	0.40%

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	मंत्रालय का नाम	सीपीएसई की स्थिति	सीएसआर व्यय	योग व्यय का प्रतिशत
ड] रेल मंत्रालय के सीपीएसई का सीएसआर व्यय				9,737.80	2.92%
च] रक्षा मंत्रालय (5)					
28	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	रक्षा मंत्रालय	लघु रत्न	455.02	0.14%
29	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	रक्षा मंत्रालय	अनुसूची- 'ख'	400.69	0.12%
30	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	रक्षा मंत्रालय	लघु रत्न	511.00	0.15%
31	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	रक्षा मंत्रालय	नवरत्न	2,755.72	0.83%
32	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	रक्षा मंत्रालय	नवरत्न	2,230.00	0.67%
च] रक्षा मंत्रालय के सीपीएसई का सीएसआर व्यय				6,352.43	1.90%
छ] खान मंत्रालय (2)					
33	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	खान मंत्रालय	लघु रत्न	265.28	0.08%
34	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	खान मंत्रालय	नवरत्न	5,053.82	1.51%
छ] खान मंत्रालय सीपीएसई सीएसआर व्यय				5,319.10	1.59%
ज] वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (3)					
35	ईसीजीसी लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	अन्य (लागू नहीं)	2,908.80	0.87%
36	एमएमटीसी लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग	नहीं	0.00	0.00%
37	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	नहीं	14.00	0.00%
ज] वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सीपीएसई सीएसआर व्यय				2,922.80	0.88%

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	मंत्रालय का नाम	सीपीएसई की स्थिति	सीएसआर व्यय	योग व्यय का प्रतिशत
झ] रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (3)					
38	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीपीसीएल)	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	अन्य (लागू नहीं)	18.78	0.01%
39	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीओ)	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	नहीं	1,662.46	0.50%
40	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	नवरत्न	2,008.00	0.60%
झ] रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का सीएसआर व्यय				3,689.24	1.10%
ञ] परमाणु ऊर्जा विभाग (3)					
41	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परमाणु ऊर्जा विभाग	अन्य (अनुसूची ख)	909.93	0.27%
42	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	परमाणु ऊर्जा विभाग	लघु रत्न	1,602.02	0.48%
43	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	परमाणु ऊर्जा विभाग	लघु रत्न	541.16	0.16%
ञ] परमाणु ऊर्जा विभाग की सीपीएसई का सीएसआर व्यय				3,053.11	0.91%
ट] अन्य मंत्रालय / विभाग					
44	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	लघु रत्न	0.00	0.00%
45	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	लघु रत्न	19.71	0.01%
46	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	आयुष मंत्रालय।	लघु रत्न	60.39	0.02%
47	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	जनजातीय कार्य मंत्रालय	नहीं	63.88	0.02%
48	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	जनजातीय कार्य मंत्रालय	नहीं	0.00	0.00%

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	मंत्रालय का नाम	सीपीएसई की स्थिति	सीएसआर व्यय	योग व्यय का प्रतिशत
49	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय	शून्य	0.00	0.00%
50	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	सड़क एवं परिवहन मंत्रालय	कोई नहीं	393.03	0.12%
51	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	भारी उद्योग मंत्रालय	महारत्न	0.00	0.00%
52	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल)	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	नहीं	910.03	0.27%
53	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	नवरत्न	544.62	0.16%
54	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (आईआरडीडीए)	नवीन एवं नवीकरणीय विद्युत मंत्रालय	नवरत्न	551.68	0.17%
55	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय	लागू नहीं	45.51	0.01%
56	सिक्क्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	वित्त मंत्रालय	लघु रत्न	285.09	0.09%
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय	नहीं	0.00	0.00%
58	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	भारी उद्योग मंत्रालय	नहीं	19.52	0.01%
ट] अन्य मंत्रालय / विभाग सीपीएसई सीएसआर व्यय				2,893.51	0.87%
58 सीपीएसई (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज+झ+ञ+ट) द्वारा कुल सीएसआर व्यय				3,33,980.60	100.00

अनुलग्नक-XXVI
(पैरा संख्या 5.4.3 देखें)
श्रेणी-वार सीएसआर व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	सीएसआर व्यय (₹ लाख में)	सीएसआर व्यय का प्रतिशत
1	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	63,457.45	19.00%
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	45,771.00	13.70%
3	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	33,048.00	9.90%
4	आरईसी लिमिटेड	24,731.00	7.40%
5	एनटीपीसी लिमिटेड	20,057.00	6.01%
6	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	16,289.02	4.88%
7	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	16,193.00	4.85%
8	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	15,818.90	4.74%
9	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	15,787.44	4.73%
10	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	9,937.00	2.98%
11	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	9,855.59	2.95%
12	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	8,598.00	2.57%
13	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	5,307.00	1.59%
14	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	5,053.82	1.51%
15	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	4,736.25	1.42%
16	एसजेवीएन लिमिटेड	4,595.78	1.38%
17	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	3,133.00	0.94%
18	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	2,971.00	0.89%
19	ईसीजीसी लिमिटेड	2,908.80	0.87%
20	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	2,755.72	0.83%
21	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	2,230.00	0.67%
22	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	2,048.00	0.61%
23	चेन्नई पेट्रोलीयम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	2,011.51	0.60%
24	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	2,008.00	0.60%

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	सीएसआर व्यय (₹ लाख में)	सीएसआर व्यय का प्रतिशत
25	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	1,664.80	0.50%
26	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीआई)	1,662.46	0.50%
27	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	1,602.02	0.48%
28	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	1,397.07	0.42%
29	राइट्स लिमिटेड	1,331.00	0.40%
30	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल)	910.03	0.27%
31	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	909.93	0.27%
32	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	614.00	0.18%
33	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	551.68	0.17%
34	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	544.62	0.16%
35	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	541.16	0.16%
36	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	511.00	0.15%
37	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	455.02	0.14%
38	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	400.69	0.12%
39	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	393.03	0.12%
40	सिक्क्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	285.09	0.09%
41	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	265.28	0.08%
42	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	181.50	0.05%
43	ग्रिड नियंत्रण ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	110.85	0.03%
44	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	81.30	0.02%
45	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	63.88	0.02%
46	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	60.39	0.02%
47	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	45.51	0.01%
48	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	24.00	0.01%
49	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	19.71	0.01%

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	सीएसआर व्यय (₹ लाख में)	सीएसआर व्यय का प्रतिशत
50	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	19.52	0.01%
51	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	18.78	0.01%
52	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	14.00	0.00%
53	नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	0.00	0.00%
54	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	0.00	0.00%
55	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	0.00	0.00%
56	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00%
57	एमएमटीसी लिमिटेड	0.00	0.00%
58	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	0.00	0.00%
	योग	3,33,980.60	100.00%

अनुलग्नक-XXVII
(पैरा संख्या 5.4.4 देखें)
अव्ययित राशि

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	बिना व्यय हुए खाते में अंतरण	अंतरण की तिथि	अनुसूची VII के तहत बताए गए फंड में अंतरण	अंतरण की तिथि
1	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	132		शून्य	शून्य
10	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	बिना व्यय हुए खाते में अंतरण	अंतरण की तिथि	अनुसूची VII के तहत बताए गए फंड में अंतरण	अंतरण की तिथि
11	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	176	19.04.2024	59	25.04.2024
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	22	30.04.2024	शून्य	शून्य
19	राइट्स लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीओ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	925	25.04.2025	0.14	18.07.2024

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	बिना व्यय हुए खाते में अंतरण	अंतरण की तिथि	अनुसूची VII के तहत बताए गए फंड में अंतरण	अंतरण की तिथि
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	1,112	24.04.2024	शून्य	शून्य
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	280	29.04.2024	171	27.03.2024
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	1,403	30.04.2024	शून्य	शून्य
30	एमएमटीसी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	2,131		शून्य	
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	0	शून्य	0	शून्य
34	एसजेवीएन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
37	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	2,684	30.04.2024	शून्य	शून्य
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	8,758	30.04.2024	लागू नहीं	लागू नहीं

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	बिना व्यय हुए खाते में अंतरण	अंतरण की तिथि	अनुसूची VII के तहत बताए गए फंड में अंतरण	अंतरण की तिथि
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	7,826	29.04.2024	शून्य	शून्य
40	ईसीजीसी लिमिटेड	254	26.04.2024	1.8	26.04.2024
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	2,258	29.04.2024	शून्य	शून्य
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	3,842	29.04.2024	शून्य	शून्य
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
44	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	8,093	30.04.2024	शून्य	शून्य
47	नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	शून्य		शून्य	शून्य
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
49	आरईसी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	11,602	30.04.2024	शून्य	शून्य
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
54	एनटीपीसी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	बिना व्यय हुए खाते में अंतरण	अंतरण की तिथि	अनुसूची VII के तहत बताए गए फंड में अंतरण	अंतरण की तिथि
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	4.8	15.04.2024	शून्य	लागू नहीं
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
58	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	13		शून्य	शून्य
		51,515.8		231.94	
	योग अप्रयुक्त राशि	51,747.74			

अनुलग्नक-XXVIII
(पैरा संख्या 5.4.5 देखें)
सीएसआर पर प्रशासनिक उपरिव्यय एवं प्रभाव आकलन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	प्रशासनिक व्यय	प्रभाव आकलन पर व्यय	योग व्यय (प्रशासनिक व्यय सहित)
1	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	0	0	0
2	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	0	0	0
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	0	0	0
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	0	0	0
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	0	0	0
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	0	0	0
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	0	0	0
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	2.52	0	2.52
10	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	0	0	0
11	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	0	0	0
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	17.44	0	17.44
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	प्रशासनिक व्यय	प्रभाव आकलन पर व्यय	योग व्यय (प्रशासनिक व्यय सहित)
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	0	0	0
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	0.88	0	0.88
19	राइट्स लिमिटेड	62.89	10.27	73.16
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीआई)	0	0	0
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	19.11	0	19.11
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल)	0	0	0
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	1.04	0	1.04
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	76.26	0	76.26
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	2.76	0	2.76
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	0	3.05	3.05
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	0	0	0
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	105.64	6.71	112.35
29	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	0	0	0
30	एमएमटीसी लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	0	7.08	7.08
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	201.35	0	201.35

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	प्रशासनिक व्यय	प्रभाव आकलन पर व्यय	योग व्यय (प्रशासनिक व्यय सहित)
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	26.03	13.55	39.58
34	एसजेवीएन लिमिटेड	15.3	15.1	30.4
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	38.17	0	38.17
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	0	0	0
37	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	12.54	5.69	18.23
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	1,246.21	498	1,744.21
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	190	0	190
40	ईसीजीसी लिमिटेड	10.3	12.9	23.2
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	0	8.97	8.97
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	314.19	7.99	322.18
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	95.73	1	96.73
44	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	269.02	24.84	293.86
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	257.05	0	257.05
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
47	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	744	1.88	745.88
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,178.51	22.67	2,201.18
49	आरईसी लिमिटेड	796	13	809
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	651	0	651
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	358.64	8.68	367.32
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	33.19	13.23	46.42
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	1,307	27	1,334

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	प्रशासनिक व्यय	प्रभाव आकलन पर व्यय	योग व्यय (प्रशासनिक व्यय सहित)
54	एनटीपीसी लिमिटेड	0	0	0
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	2,170.75	45	2,215.75
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	0	0	0
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	0	0	0
58	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	0	0	0
	योग	11,203.52	746.61	11,950.13

अनुलग्नक-XXIX
(पैरा संख्या 5.4.6 देखें)
सामान्य विषय पर व्यय

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या 10 दिसंबर 2018 के डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर पर योग वार्षिक व्यय का लगभग 60 प्रतिशत व्यय किया गया था	2023-24 के दौरान व्यय का वास्तविक प्रतिशत
1	नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	लागू नहीं	लागू नहीं
2	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	नहीं	42%
3	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	नहीं	6.64%
4	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	नहीं	24.41%
5	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	नहीं	30.49%
6	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	नहीं	36.35%
7	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	नहीं	43.10%
8	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	नहीं	44%
9	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल)	नहीं	48.29%
10	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	नहीं	54%
11	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	हाँ	60%
12	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	हाँ	61.19%
13	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	हाँ	61.63%
14	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	हाँ	62.32%
15	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	हाँ	62.90%
16	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	हाँ	63.53%
17	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	हाँ	65.87%
18	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	हाँ	66.53%

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या 10 दिसंबर 2018 के डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर पर योग वार्षिक व्यय का लगभग 60 प्रतिशत व्यय किया गया था	2023-24 के दौरान व्यय का वास्तविक प्रतिशत
19	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	हाँ	67.27%
20	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	हाँ	70%
21	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	हाँ	74.60%
22	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	हाँ	75.60%
23	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	हाँ	100%
24	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएएमटीएल)	हाँ	100%
25	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीओ)	नहीं	13
26	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	हाँ	61.08
27	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	हाँ	100
28	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	हाँ	60.08%
29	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	नहीं	36.36%
30	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	नहीं	19.17 %.
31	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	नहीं	32.69%
32	ईसीजीसी लिमिटेड	नहीं	40%
33	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	नहीं	उल्लेख नहीं
34	एमएमटीसी लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं
35	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या 10 दिसंबर 2018 के डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर पर योग वार्षिक व्यय का लगभग 60 प्रतिशत व्यय किया गया था	2023-24 के दौरान व्यय का वास्तविक प्रतिशत
36	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	लागू नहीं	लागू नहीं
37	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	उल्लेख नहीं
38	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	नहीं	उल्लेख नहीं
39	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	हाँ	उल्लेख नहीं
40	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	हाँ	उल्लेख नहीं
41	राइट्स लिमिटेड	हाँ	उल्लेख नहीं
42	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	हाँ	उल्लेख नहीं
43	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)*	पूरी राशि पीएम केयर फंड में स्थानांतरित कर दी गई।	पूरी राशि पीएम केयर फंड में स्थानांतरित कर दी गई।
44	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)*	नहीं	0%
45	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	हाँ	उल्लेख नहीं
46	सिक्थोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	हाँ	65.60%
47	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	नहीं	34.81%
48	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	हाँ	60%
49	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमएसएल)	हाँ	74%
50	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल)*	नहीं	0%
51	ग्रिड नियंत्रण ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	हाँ	उल्लेख नहीं
52	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	हाँ	उल्लेख नहीं
53	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या 10 दिसंबर 2018 के डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर पर योग वार्षिक व्यय का लगभग 60 प्रतिशत व्यय किया गया था	2023-24 के दौरान व्यय का वास्तविक प्रतिशत
54	एसजेवीएन लिमिटेड	हाँ	60.58%
55	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	63.36
56	आरईसी लिमिटेड	हाँ	62.94%
57	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	नहीं	40.98%
58	एनटीपीसी लिमिटेड	हाँ	60.72%

सामान्य विषय पर व्यय (आठ सीपीएसई ने प्रतिशत का उल्लेख नहीं किया)

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	क्या 10 दिसंबर 2018 के डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर पर योग वार्षिक व्यय का लगभग 60 प्रतिशत व्यय किया गया था	2023-24 के दौरान व्यय का वास्तविक प्रतिशत।
1	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	हाँ	उल्लेख नहीं
2	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	हाँ	उल्लेख नहीं
3	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	हाँ	उल्लेख नहीं
4	राइट्स लिमिटेड	हाँ	उल्लेख नहीं
5	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	हाँ	उल्लेख नहीं
6	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	हाँ	उल्लेख नहीं
7	ग्रिड नियंत्रण ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	हाँ	उल्लेख नहीं
8	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	हाँ	उल्लेख नहीं

कॉमन थीम पर व्यय (दो सीपीएसई ने प्रतिशत लागू नहीं किया)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या 10 दिसंबर 2018 के डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान सीएसआर पर योग वार्षिक व्यय का लगभग 60 प्रतिशत व्यय किया गया था	2023-24 के दौरान व्यय का वास्तविक प्रतिशत।
1.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	नहीं	उल्लेख नहीं
2.	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	नहीं	उल्लेख नहीं

अनुलग्नक-XXIX क
(पैरा संख्या 5.4.6 देखें)
आकांक्षी जिला-वार सीएसआर व्यय (ए अक्षर से शुरू होने वाले राज्य)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आंध्र प्रदेश			अरुणाचल प्रदेश	असम						
		विशाखापत्तनम	विजयनगरम	वाईएसआर कडप्पा		नामसाई	बक्सा	उदलगुड़ी	दरांग	धुबरी	हैलाकांडी	बारपेटा/ गोलपाड़ा
1	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आंध्र प्रदेश			अरुणाचल प्रदेश	असम					
		विशाखापत्तनम	विजयनगरम	वाईएसआर कडप्पा		बक्सा	उदलगुड़ी	दरांग	धुबरी	हैलाकांडी	बारपेटा/गोलपाड़ा
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आंध्र प्रदेश			अरुणाचल प्रदेश	असम					
		विशाखापत्तनम	विजयनगरम	वाईएसआर कडप्पा		बक्सा	उदलगुड़ी	दरांग	धुबरी	हैलाकांडी	बारपेटा/गोलपाड़ा
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	राइट्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आंध्र प्रदेश			अरुणाचल प्रदेश	असम					
		विशाखापत्तनम	विजयनगरम	वाईएसआर कडप्पा		बक्सा	उदलगुड़ी	दरांग	धुबरी	हैलाकांडी	बारपेटा/गोलपाड़ा
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीओ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईएसएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	आईआरएल (इंडिया) लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आंध्र प्रदेश			अरुणाचल प्रदेश	असम					
		विशाखापत्तनम	विजयनगरम	वाईएसआर कडप्पा		बक्स	उदलगुड़ी	दरांग	धुबरी	हैलाकांडी	बारपेटा/गोलपाड़ा
27	इंडियन रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	एमएमटीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आंध्र प्रदेश			अरुणाचल प्रदेश	असम					
		विशाखापत्तनम	विजयनगरम	वाईएसआर कडप्पा		बक्सा	उदलगुड़ी	दरांग	धुबरी	हैलाकांडी	बारपेटा/गोलपाड़ा
34	एसजेवीएन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंगिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ईसीजीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आंध्र प्रदेश			अरुणाचल प्रदेश	असम					
		विशाखापत्तनम	विजयनगरम	वाईएसआर कडप्पा		बक्सा	उदलगुड़ी	दरांग	धुबरी	हैलाकांडी	बारपेटा/गोलपाड़ा
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	0	4.28	0	0	0	0	0	0	0	0
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	नमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	0	0	0	0	0	0	28.94	0	0	0
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
47	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	563.04	59.70	15.64	7.36	23.28	0	46.56	0	0	221.68
49	आरईसी लिमिटेड	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आंध्र प्रदेश			अरुणाचल प्रदेश	असम					
		विशाखापत्तनम	विजयनगरम	वाईएसआर कडप्पा		बक्सा	उदलगुड़ी	दरांग	धुबरी	हैलाकांडी	बारपेटा/गोलपाड़ा
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	38.68	0
54	एनटीपीसी लिमिटेड	2.4	95.51	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	2.10	0	0	0	0	262.00	0	0	528.00	0
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

अनुलग्नक-XXIXक
(पैरा संख्या 5.4.6 देखें)
आकांक्षी जिला-वार सीएसआर व्यय (राज्य वर्णमाला बी)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	बिहार									
		कटिहार	नवादा	शेखपुरा	औरंगाबाद	बांका	बेगूसराय	गया	पूर्णिया	खगरिया	मुजफ्फरपुर
1	नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	बिहार									
		कटिहार	नवादा	शेखपुरा	औरंगाबाद	बांका	बेगूसराय	गया	पूर्णिया	खगरिया	मुजफ्फरपुर
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	भारतीय प्रतिभूतिरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	बिहार									
		कटिहार	नवादा	शेखपुरा	औरंगाबाद	बांका	बेगूसराय	गया	पूर्णिया	खगरिया	मुजफ्फरपुर
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	राइट्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	बिहार									
		कटिहार	नवादा	शेखपुरा	औरंगाबाद	बांका	बेगूसराय	गया	पूर्णिया	खगरिया	मुजफ्फरपुर
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	एमएमटीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	एसजेवीएन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	बिहार									
		कटिहार	नवादा	शेखपुरा	औरंगाबाद	बांका	बेगूसराय	गया	पूर्णिया	खगरिया	मुजफ्फरपुर
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	0	0	0	29.38	0	5.23	0	89.16	0	0
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ईसीजीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	बिहार									
		कटिहार	नवादा	शेखपुरा	औरंगाबाद	बांका	बेगूसराय	गया	पूर्णिया	खगरिया	मुजफ्फरपुर
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	37.59558	0	0	43.90	0	260.91	0	36.31	42.23	1055.63
49	आरईसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	एनटीपीसी लिमिटेड	0	0	0	238.3	0	0	0	0	0	21.89
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	0	272.80	34.60	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	बिहार									
		कटिहार	नवादा	शेखपुरा	औरंगाबाद	बांका	बेगूसराय	गया	पूर्णिया	खगरिया	मुजफ्फरपुर
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

अनुलग्नक-XXIXक
(पैरा संख्या 5.4.6 देखें)
आकांक्षी जिला-वार सीएसआर व्यय (राज्य वर्णमाला सी एवं जी)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	छत्तीसगढ़								गुजरात	
		महासमुंद्र	बस्तर	बीजापुर	दंतेवाड़ा	कांकेर/ राजनांदगांव	नारायणपुर	सुकमा	कोरबा	दाहोद	नर्मदा
1	नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	छत्तीसगढ़								गुजरात	
		महासमुंद	बस्तर	बीजापुर	दंतेवाड़ा	कांकेर/ राजनांदगांव	नारायणपुर	सुकमा	कोरबा	दाहोद	नर्मदा
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	यूरेनियम कॉपरिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	छत्तीसगढ़								गुजरात	
		महासमुंद	बस्तर	बीजापुर	दंतेवाड़ा	कांकेर/ राजनांदगांव	नारायणपुर	सुकमा	कोरबा	दाहोद	नर्मदा
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	राइट्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीओ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईएसएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	छत्तीसगढ़								गुजरात	
		महासमुंद्र	बस्तर	बीजापुर	दंतवाड़ा	कांकेर/ राजनांदगांव	नारायणपुर	सुकमा	कोरबा	दाहोद	नर्मदा
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	एमएमटीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	छत्तीसगढ़								गुजरात	
		महासमुंद	बस्तर	बीजापुर	दंतेवाड़ा	कांकेर/ राजनांदगांव	नारायणपुर	सुकमा	कोरबा	दाहोद	नर्मदा
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
34	एसजेवीएन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	0	0	0	0	845.05	1,003.74	0	0	0	0
40	ईसीजीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	छत्तीसगढ़								गुजरात	
		महासमुंद	बस्तर	बीजापुर	दंतवाड़ा	कांकेर/ राजनांदगांव	नारायणपुर	सुकमा	कोरबा	दाहोद	नर्मदा
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	92.1	0	0
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	52.88	0	0	0	0	7.71	0	43.18	88.02	169.23
49	आरईसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	छत्तीसगढ़								गुजरात	
		महासमुंद	बस्तर	बीजापुर	दंतवाड़ा	कांकेर/ राजनांदगांव	नारायणपुर	सुकमा	कोरबा	दाहोद	नर्मदा
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0
54	एनटीपीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	518.53	0	0
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	0	0	0	0	0	0	0	0	513.20	90.90
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एगीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

अनुलग्नक-XXIXक
(पैरा संख्या 5.4.6 देखें)
आकांक्षी जिला-वार सीएसआर व्यय (राज्य वर्णमाला एच एवं जे)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	हरियाणा		हिमाचल प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर	झारखंड						
		नूह 27	मेवात 28			चंबा 29	बारामूला/ कुपवाड़ा 30/31	साहिबगंज 45	गोड्डा 44	गुमला	गिरिडीह 32	बोकारो 33
1	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	इस्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	हरियाणा		हिमाचल प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर	झारखंड					
		नूह 27	मेवात 28			साहिबगंज 45	गोड्डा 44	गुमला	गिरिडीह 32	बोकारो 33	हजारीबाग 34
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	यूनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	हरियाणा		हिमाचल प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर	झारखंड					
		नूह 27	मेवात 28			साहिबगंज 45	गोड्डा 44	गुमला	गिरिडीह 32	बोकारो 33	हजारीबाग 34
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएएमटीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	राइट्स लिमिटेड	112.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएससीआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	हरियाणा		हिमाचल प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर	झारखंड					
		नूह 27	मेवात 28			साहिबगंज 45	गोड्डा 44	गुमला	गिरिडीह 32	बोकारो 33	हजारीबाग 34
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	एमएमटीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	हरियाणा		हिमाचल प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर	झारखंड					
		नूह 27	मेवात 28			साहिबगंज 45	गोड्डा 44	गुमला	गिरिडीह 32	बोकारो 33	हजारीबाग 34
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	13.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	एसजेवीएन लिमिटेड	0	0	95.52	0	0	0	0	0	0	0
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड म्रिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	13.24	0
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	0	0	0	0	0	0	0	0	607.89	0
40	ईसीजीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	हरियाणा		हिमाचल प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर	झारखंड					
		नूह 27	मेवात 28			साहिबगंज 45	गोड्डा 44	गुमला	गिरिडीह 32	बोकारो 33	हजारीबाग 34
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	166.05	0	0	0	0	0	6.23	0	0	0
49	आरईसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	हरियाणा		हिमाचल प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर	झारखंड					
		नूह 27	मेवात 28			साहिबगंज 45	गोड्डा 44	गुमला	गिरिडीह 32	बोकारो 33	हजारीबाग 34
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	एनटीपीसी लिमिटेड	0	0	0	0	42.33	6.27	0	0	0	15.01
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	0	0	0	0	0	0	291.60	0	942.00	112.30
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

अनुलग्नक-XXIX क
(पैरा संख्या 5.4.6 देखें)
आकांक्षी जिला-वार सीएसआर व्यय (राज्य: जे एवं के)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	झारखंड								कर्नाटक	
		पलामू 35	रामगढ़/ नारायणपुर 36/37	लातेहार/ लोहरदगा 38/39	खूंटी 40	रांची 41	गढ़वा 42	पूर्वी सिंहभूम/ सिमडेगा 43/44	चाईबासा/ चतरा 45/46	यादगीर 47	रायचूर 48
1	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	झारखंड								कर्नाटक	
		पलामू 35	रामगढ़/ नारायणपुर 36/37	लातेहार/ लोहरदगा 38/39	खूंटी 40	रांची 41	गढ़वा 42	पूर्वी सिंहभूम/ सिमडेगा 43/44	चाईबासा/ चतरा 45/46	यादगीर 47	रायचूर 48
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन युटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	झारखंड								कर्नाटक	
		पलामू 35	रामगढ़/ नारायणपुर 36/37	लातेहार/ लोहरदगा 38/39	खूंटी 40	रांची 41	गढ़वा 42	पूर्वी सिंहभूम/ सिमडेगा 43/44	चाईबासा/ चतरा 45/46	यादगीर 47	रायचूर 48
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	0	0	0	0	0	0	48.86	0	0	0
19	राइट्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	63.08	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	झारखंड								कर्नाटक	
		पलामू 35	रामगढ़/ नारायणपुर 36/37	लातेहार/ लोहरदगा 38/39	खूंटी 40	रांची 41	गढ़वा 42	पूर्वी सिंहभूम/ सिमडेगा 43/44	चाईबासा/ चतरा 45/46	यादगीर 47	रायचूर 48
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	झारखंड								कर्नाटक	
		पलामू 35	रामगढ़/ नारायणपुर 36/37	लातेहार/ लोहरदगा 38/39	खूंटी 40	रांची 41	गढ़वा 42	पूर्वी सिंहभूम/ सिमडेगा 43/44	चाईबासा/ चतरा 45/46	यादगीर 47	रायचूर 48
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	0	14.8	0	45.8	0	0	38.64	0	0	0
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	एमएमटीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	0	0	0	0	100	0	200	0	0	0
34	एसजेवीएन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	झारखंड								कर्नाटक	
		पलामू 35	रामगढ़/ नारायणपुर 36/37	लातेहार/ लोहरदगा 38/39	खूंटी 40	रांची 41	गढ़वा 42	पूर्वी सिंहभूम/ सिमडेगा 43/44	चाईबासा/ चतरा 45/46	यादगौर 47	रायचूर 48
35	नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	0	0	0	0	105.05	0	531	0	0	0
40	ईसीजीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	214.28	0	0	0
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	21.45	29.65
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	90.72	513.62

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	झारखंड								कर्नाटक	
		पलामू 35	रामगढ़/ नारायणपुर 36/37	लातेहार/ लोहरदगा 38/39	खूंटी 40	रांची 41	गढ़वा 42	पूर्वी सिंहभूम/ सिमडेगा 43/44	चाईबासा/ चतरा 45/46	यादगीर 47	रायचूर 48
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	नमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	0	0	377.64	92.71	0	28.04	0	0	0
49	आरईसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	झारखंड								कर्नाटक	
		पलामू 35	रामगढ़/ नारायणपुर 36/37	लातेहार/ लोहरदगा 38/39	खूंटी 40	रांची 41	गढ़वा 42	पूर्वी सिंहभूम/ सिमडेगा 43/44	चाईबासा/ चतरा 45/46	यादगीर 47	रायचूर 48
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	0	0	0	0	0	0	27.36	0	0	0
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	0	0	0	0	87.23	0	0	0	0	0
54	एनटीपीसी लिमिटेड	0	0	0	0	27.53	0	0	7.83	0	0
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	0	110.00	0	41.50	0	0	0	0	0	0
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

अनुलग्नक-XXIXक
(पैरा संख्या 5.4.6 देखें)
आकांक्षी जिला-वार सीएसआर व्यय (राज्य वर्णमाला के एवं एम)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	केरल	मध्य प्रदेश								महाराष्ट्र	
			वायनाड 49	दमोह	बड़वानी	छतरपुर 50	राजगढ़ 51	खंडवा 52	विदिशा 94	सिंगरौली/ गुना 53/54	धाराशिव/ उस्मानाबाद	नंदुरबार 55
1	नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	केरल	मध्य प्रदेश								महाराष्ट्र	
			वायनाड 49	दमोह	बड़वानी	छतरपुर 50	राजगढ़ 51	खंडवा 52	विदिशा 94	सिंगरौली/ गुना 53/54	धाराशिव/ उस्मानाबाद	नंदुरबार 55
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	केरल	मध्य प्रदेश								महाराष्ट्र	
			वायनाड 49	दमोह	बड़वानी	छतरपुर 50	राजगढ़ 51	खंडवा 52	विदिशा 94	सिंगरौली/ गुना 53/54	धाराशिव/ उस्मानाबाद	नंदुरबार 55
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	पावरग्रिड एनएएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएएमटीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	राइट्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	केरल	मध्य प्रदेश								महाराष्ट्र	
			वायनाड 49	दमोह	बड़वानी	छतरपुर 50	राजगढ़ 51	खंडवा 52	विदिशा 94	सिंगरौली/ गुना 53/54	धाराशिव/ उस्मानाबाद	नंदुरबार 55
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	7.2	0	0	0	0	8.31	8.31	8.31	8.31	0	0
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	केरल	मध्य प्रदेश								महाराष्ट्र	
			वायनाड 49	दमोह	बड़वानी	छतरपुर 50	राजगढ़ 51	खंडवा 52	विदिशा 94	सिंगरौली/ गुना 53/54	धाराशिव/ उस्मानाबाद	नंदुरबार 55
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.49
29	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	एमएमटीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	एसजेवीएन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	केरल	मध्य प्रदेश							महाराष्ट्र	
			वायनाड 49	दमोह	बड़वानी	छतरपुर 50	राजगढ़ 51	खंडवा 52	विदिशा 94	सिंगरौली/ गुना 53/54	धाराशिव/ उस्मानाबाद
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	99.03	0	0	0
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ईसीजीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	केरल	मध्य प्रदेश								महाराष्ट्र	
			वायनाड 49	दमोह	बड़वानी	छतरपुर 50	राजगढ़ 51	खंडवा 52	विदिशा 94	सिंगरौली/ गुना 53/54	धाराशिव/ उस्मानाबाद	नंदुरबार 55
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	नमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
47	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	571.05	0	0
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	35.10	48.02	0	21.09
49	आरईसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	केरल	मध्य प्रदेश							महाराष्ट्र	
			वायनाड 49	दमोह	बड़वानी	छतरपुर 50	राजगढ़ 51	खंडवा 52	विदिशा 94	सिंगरौली/ गुना 53/54	धाराशिव/ उस्मानाबाद
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	0	-2.41	0	0	0	0	0	0	0	0
54	एनटीपीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	408.41	0	0
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	0	0	0	0	0	0	0	0	506.80	0
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

अनुलग्नक-XXIXक
(पैरा संख्या 5.4.6 देखें)
आकांक्षी जिला-वार सीएसआर व्यय (राज्य वर्णमाला एम, एन एवं ओ)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	महाराष्ट्र		मेघालय	मिज़ोरम	नगालैंड	ओडिशा						
		वाशिम	गडचिरोली				री भोई	ममित 59	किफायर 60	कंधमाल	धेनकनाल 61	नुआपाड़ा 62	बलांगीर 63
1	नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	0	0	0	0	0		0	0			0	0
2	इस्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	0	0	0	0	0		0	0			0	0
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	0	0	0	0	0		0	0			0	0
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	0	0	0	0	0		0	0			0	0
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	0	0	0	0	0		0	0			0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	महाराष्ट्र		मेघालय	मिज़ोरम	नगालैंड	ओडिशा				
		वाशिम	गडचिरोली				कंधमाल	धेनकनाल	नुआपाड़ा	बलांगीर	गजपति
				री भोई	ममित	किफायर	60	61	62	63	64
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	यूरोनियम कॉपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	महाराष्ट्र		मेघालय	मिज़ोरम	नगालैंड	ओडिशा				
		वाशिम	गडचिरोली				कंधमाल	धेनकनाल	नुआपाड़ा	बलांगीर	गजपति
				री भोई	ममित 59	किफायर 60		61	62	63	64
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	राइट्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएससीआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	महाराष्ट्र		मेघालय	मिज़ोरम	नगालैंड	ओडिशा				
		वाशिम	गडचिरोली				कंधमाल	धेनकनाल	नुआपाड़ा	बलांगीर	गजपति
				री भोई	ममित	किफायर		61	62	63	64
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	0	0	0	0	0	40.01	0	0	0	21.67
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	महाराष्ट्र		मेघालय	मिज़ोरम	नगालैंड	ओडिशा				
		वाशिम	गडचिरोली				कंधमाल	धेनकनाल	नुआपाड़ा	बलांगीर	गजपति
				री भोई	ममित 59	किफायर 60		61	62	63	64
29	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	एमएमटीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	0	0	0	0	0	12.98	0	0	0	0
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	एसजेवीएन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	महाराष्ट्र		मेघालय	मिज़ोरम	नगालैंड	ओडिशा				
		वाशिम	गडचिरोली				कंधमाल	धेनकनाल	नुआपाड़ा	बलांगीर	गजपति
				री भोई	ममित	किफायर		61	62	63	64
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	0	0	11.97	0	0	0	79.65	0	0	0
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ईसीजीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	महाराष्ट्र		मेघालय	मिज़ोरम	नगालैंड	ओडिशा				
		वाशिम	गडचिरोली				कंधमाल	धेनकनाल	नुआपाड़ा	बलांगीर	गजपति
				री भोई	ममित 59	किफायर 60		61	62	63	64
47	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	63.71	0	38.77	0	0	27.67	100.41	0	0	0
49	आरईसी लिमिटेड	0	26	0	152	215	0	0	0	0	0
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	0	0	0	0	0	406.95	0	123.21	113.42	0
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	एनटीपीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	0	0	0	0	0	0	23.50	423.30	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	महाराष्ट्र		मेघालय	मिज़ोरम	नगालैंड	ओडिशा				
		वाशिम	गडचिरोली				कंधमाल	धेनकनाल	नुआपाड़ा	बलांगीर	गजपति
				री भोई	ममित 59	किफायर 60		61	62	63	64
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

अनुलग्नक-XXIXक
(पैरा संख्या 5.4.6 देखें)
आकांक्षी जिला-वार सीएसआर व्यय (राज्य वर्णमाला ओ, पी एवं आर)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	ओडिशा					पंजाब		राजस्थान		
		कालाहांडी	कोरापुट	नबरंगपुर	मल्कानगिरी	रायगढ़	मोगा	फिरोजपुर	बारां	करौली	जैसलमेर
1	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	ओडिशा					पंजाब		राजस्थान		
		कालाहांडी	कोरापुट	नबरंगपुर	मल्कानगिरी	रायगढ़	मोगा	फिरोजपुर	बारां	करौली	जैसलमेर
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	यूरोनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	ओडिशा					पंजाब		राजस्थान		
		कालाहांडी	कोरापुट	नबरंगपुर	मल्कानगिरी	रायगढ़	मोगा	फिरोजपुर	बारां	करौली	जैसलमेर
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	राइट्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	16.75	0	0
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	ओडिशा						पंजाब		राजस्थान		
		कालाहांडी	कोरापुट	नबरंगपुर	मल्कानगिरी	रायगढ़		मोगा	फिरोजपुर	बारां	करौली	जैसलमेर
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	0	0	0	0	0		8.47	8.47	0	0	0
24	आईआरएल (इंडिया) लिमिटेड	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
29	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	ओडिशा					पंजाब		राजस्थान		
		कालाहांडी	कोरापुट	नबरंगपुर	मल्कानगिरी	रायगढ़	मोगा	फिरोजपुर	बारां	करौली	जैसलमेर
30	एमएमटीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	0	0	0	78.3	0	0	0	0	0	50.38
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	0	0	0	51.76	50	0	0	0	0	0
34	एसजेवीएन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	0	1307.41	28.92	0	0	0	0	0	0	0
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	24.5	0
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	ओडिशा						पंजाब		राजस्थान		
		कालाहांडी	कोरापुट	नबरंगपुर	मल्कानगिरी	रायगढ़	मोगा	फिरोजपुर	बारां	करौली	जैसलमेर	
40	ईसीजीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	
47	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	75.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	आरईसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	ओडिशा						पंजाब		राजस्थान		
		कालाहांडी	कोरापुट	नबरंगपुर	मल्कानगिरी	रायगढ़	मोगा	फिरोजपुर	बारां	करौली	जैसलमेर	
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	59.94	0	0	0	0	0	0	23.68	0	0	
54	एनटीपीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	12.99	0	0	
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136.40	
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

अनुलग्नक-XXIXक
(पैरा संख्या 5.4.6 देखें)
आकांक्षी जिला-वार सीएसआर व्यय (राज्य वर्णमाला आर, एस, टी एवं यू)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु		तेलंगाना			त्रिपुरा	उत्तराखंड	
				रामनाथपुरम 77	विरुधुनगर 78	खम्मम/ भूपालपल्ली 79/80	आसिफाबाद 81	भद्राद्रि कोठागुडेम 82		हरिद्वार 84	ऊधम सिंह नगर 85
1	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	इस्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु		तेलंगाना			त्रिपुरा	उत्तराखंड	
				रामनाथपुरम 77	विरुधुनगर 78	खम्मम/ भूपालपल्ली 79/80	आसिफाबाद 81	भद्राद्रि कोठागुडम 82		हरिद्वार 84	ऊधम सिंह नगर 85
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	यूरनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु		तेलंगाना			त्रिपुरा	उत्तराखंड	
				रामनाथपुरम 77	विरुधुनगर 78	खम्मम/ भूपालपल्ली 79/80	आसिफाबाद 81	भद्राद्रि कोठागुडेम 82		हरिद्वार 84	ऊधम सिंह नगर 85
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	0	0	0	0	0	31.13	0	0	0	0
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएएमटीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	0	0	0	0	0	39.41	0	0	0	0
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु		तेलंगाना			त्रिपुरा	उत्तराखंड	
				रामनाथपुरम 77	विरुधुनगर 78	खम्मम/ भूपालपल्ली 79/80	आसिफाबाद 81	भद्राद्रि कोठागुडम 82		हरिद्वार 84	ऊधम सिंह नगर 85
19	राइट्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीओ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	108.31	0
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु		तेलंगाना			त्रिपुरा	उत्तराखंड	
				रामनाथपुरम 77	विरुधुनगर 78	खम्मम/ भूपालपल्ली 79/80	आसिफाबाद 81	भद्राद्रि कोठागुडेम 82		हरिद्वार 84	ऊधम सिंह नगर 85
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	एमएमटीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
34	एसजेवीएन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु		तेलंगाना			त्रिपुरा	उत्तराखंड	
				रामनाथपुरम 77	विरुधुनगर 78	खम्मम/ भूपालपल्ली 79/80	आसिफाबाद 81	भद्राद्रि कोठागुडम 82		हरिद्वार 84	ऊधम सिंह नगर 85
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)			189.84	0	0	0	0	0	0	0
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ईसीजीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु		तेलंगाना			त्रिपुरा	उत्तराखंड	
				रामनाथपुरम 77	विरुधुनगर 78	खम्मम/ भूपालपल्ली 79/80	आसिफाबाद 81	भद्राद्रि कोठागुडेम 82		हरिद्वार 84	ऊधम सिंह नगर 85
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	0	0	0	0	0	290.37	0	0	0	0
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	0	0	30.4	19.58	0	0	0	0	0	0
44	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
47	नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	466.58	0	43.68	87.36	0	0	0	0	87.43	0
49	आरईसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु		तेलंगाना			त्रिपुरा	उत्तराखंड	
				रामनाथपुरम 77	विरुधुनगर 78	खम्मम/ भूपालपल्ली 79/80	आसिफाबाद 81	भद्राद्रि कोठागुडेम 82		हरिद्वार 84	ऊधम सिंह नगर 85
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	एनटीपीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	0	0	913.10	718.90	0	0	0	819.50	353.70	0
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

अनुलग्नक-XXIXक
(पैरा संख्या 5.4.6 देखें)
आकांक्षी जिला-वार सीएसआर व्यय (राज्य वर्णमाला यू, डब्ल्यू, पूरे भारत में संचालित परियोजनाएँ)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	उत्तर प्रदेश								पश्चिम बंगाल	पूरे भारत में संचालित परियोजनाएँ (यदि कोई हों) एवं अन्य
		बहराइच	चंदौली 86	बलरामपुर 87	फतेहपुर 88	चित्रकूट 89	श्रावस्ती 90	सोनभद्र	सिद्धार्थनगर/ सोनभद्र 91/92		
1	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.78
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	उत्तर प्रदेश								पश्चिम बंगाल	पूरे भारत में संचालित परियोजनाएँ (यदि कोई हों) एवं अन्य
		बहराइच	चंदौली 86	बलरामपुर 87	फ़तेहपुर 88	चित्रकूट 89	श्रावस्ती 90	सोनभद्र	सिद्धार्थनगर/ सोनभद्र 91/92		
5	इंडियन मोडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	उत्तर प्रदेश								पश्चिम बंगाल	पूरे भारत में संचालित परियोजनाएँ (यदि कोई हों) एवं अन्य
		बहराइच	चंदौली 86	बलरामपुर 87	फ़तेहपुर 88	चित्रकूट 89	श्रावस्ती 90	सोनभद्र	सिद्धार्थनगर/ सोनभद्र 91/92		
10	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएएमटीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	उत्तर प्रदेश									पश्चिम बंगाल	पूरे भारत में संचालित परियोजनाएँ (यदि कोई हों) एवं अन्य
		बहराइच	चंदौली 86	बलरामपुर 87	फ़तेहपुर 88	चित्रकूट 89	श्रावस्ती 90	सोनभद्र	सिद्धार्थनगर/ सोनभद्र 91/92	मुर्शिदाबाद 93		
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	राइट्स लिमिटेड	0	0	13.2	0	0	0	0	0	0	0	9.1
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	उत्तर प्रदेश									पश्चिम बंगाल	पूरे भारत में संचालित परियोजनाएँ (यदि कोई हों) एवं अन्य
		बहराइच	चंदौली 86	बलरामपुर 87	फ़तेहपुर 88	चित्रकूट 89	श्रावस्ती 90	सोनभद्र	सिद्धार्थनगर/ सोनभद्र 91/92	मुर्शिदाबाद 93		
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	51.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	0	427.87	155.7	0	0	0	0	12.04	0	220.28	
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	उत्तर प्रदेश									पश्चिम बंगाल	पूरे भारत में संचालित परियोजनाएँ (यदि कोई हों) एवं अन्य
		बहराइच	चंदौली 86	बलरामपुर 87	फ़तेहपुर 88	चित्रकूट 89	श्रावस्ती 90	सोनभद्र	सिद्धार्थनगर/ सोनभद्र 91/92	मुर्शिदाबाद 93		
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	0	0	0	28.4	0	0	0	0	0	0	0
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	एमएमटीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	0	155	0	0	15	0	0	0	0	0	0
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	उत्तर प्रदेश									पश्चिम बंगाल	पूरे भारत में संचालित परियोजनाएँ (यदि कोई हों) एवं अन्य
		बहराइच	चंदौली 86	बलरामपुर 87	फतेहपुर 88	चित्रकूट 89	श्रावस्ती 90	सोनभद्र	सिद्धार्थनगर/ सोनभद्र 91/92	मुर्शिदाबाद 93		
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	एसजेवीएन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	0	0	0	0	9.74	49.47	0	12.44	0	0	1.1

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	उत्तर प्रदेश								पश्चिम बंगाल	पूरे भारत में संचालित परियोजनाएँ (यदि कोई हों) एवं अन्य
		बहराइच	चंदौली 86	बलरामपुर 87	फ़तेहपुर 88	चित्रकूट 89	श्रावस्ती 90	सोनभद्र	सिद्धार्थनगर/ सोनभद्र 91/92		
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)										
40	ईसीजीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	उत्तर प्रदेश								पश्चिम बंगाल	पूरे भारत में संचालित परियोजनाएँ (यदि कोई हों) एवं अन्य
		बहराइच	चंदौली 86	बलरामपुर 87	फ़तेहपुर 88	चित्रकूट 89	श्रावस्ती 90	सोनभद्र	सिद्धार्थनगर/ सोनभद्र 91/92		
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	नॉर्डर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	377.78	0	0
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	20.50	0	43.26	85.16	0	0	36.48	0	0
49	आरईसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	0	0	0	0	0	87.37	0	0	0	0
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	उत्तर प्रदेश								पश्चिम बंगाल	पूरे भारत में संचालित परियोजनाएँ (यदि कोई हों) एवं अन्य
		बहराइच	चंदौली 86	बलरामपुर 87	फ़तेहपुर 88	चित्रकूट 89	श्रावस्ती 90	सोनभद्र	सिद्धार्थनगर/ सोनभद्र 91/92		
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	एनटीपीसी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	368.64	26.46	0	0
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

अनुलग्नक-XXIXक
(पैरा संख्या 5.4.6 देखें)
आकांक्षी जिला-वार सीएसआर व्यय (योग एवं प्रतिशत)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	योग	प्रतिशत
1	नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	0.00	0.00
2	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	0.00	0.00
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	18.78	0.07
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	0.00	0.00
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	0.00	0.00
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	0.00	0.00
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	0.00	0.00
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	20.00	0.07
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	4.00	0.01
10	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	0.00	0.00
11	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	0.00	0.00
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	31.13	0.11
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	0.00	0.00
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	0.00	0.00
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	0.00	0.00
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	0.00	0.00
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	39.41	0.14
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	48.86	0.18

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	योग	प्रतिशत
19	राइट्स लिमिटेड	214.98	0.78
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीआई)	0.00	0.00
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल)	0.00	0.00
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	224.37	0.81
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	61.68	0.22
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	815.89	2.94
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	5.00	0.02
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	127.64	0.46
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	294.49	1.06
29	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	0.00	0.00
30	एमएमटीसी लिमिटेड	0.00	0.00
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	182.98	0.66
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	128.68	0.46
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	725.43	2.62
34	एसजेवीएन लिमिटेड	95.52	0.34
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	1,336.33	4.82
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	0.00	0.00
37	सिक्थोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	79.80	0.30
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	623.90	2.25
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल)	3,092.73	11.16
40	ईसीजीसी लिमिटेड	374.28	1.35
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	51.10	0.18
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	898.99	3.24
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	49.98	0.18

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	योग	प्रतिशत
44	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	28.94	0.10
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	92.10	0.33
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	30.00	0.11
47	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	948.83	3.42
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4,726.38	17.05
49	आरईसी लिमिटेड	1,494.00	5.40
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	87.37	0.32
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	643.58	2.32
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	27.36	0.10
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	207.27	0.75
54	एनटीपीसी लिमिटेड	1,792.10	6.46
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	8,096.20	29.21
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	0.00	0.00
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	0.00	0.00
58	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	0.00	0.00
	योग (₹ लाख में)	27,720.0766	100.00

अनुलग्नक-XXX
(पैरा संख्या 5.5.1 देखें)

आवश्यकता आकलन के आधार पर सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों का चयन

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2023-24 में शुरू की गई नई परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या जिनके लिए आधारभूत/आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण आयोजित किया गया था	वर्ष 2023-24 में शुरू की गई उन नई परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या जिनके लिए आधारभूत/आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया था।
1	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	लागू नहीं	लागू नहीं
2	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	लागू नहीं	लागू नहीं
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	0	2
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	0	0
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	0	0
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	0	2
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	0	0
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	0	10
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	0	22
10	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	0	0
11	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	0	0
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	0	0
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	लागू नहीं	लागू नहीं
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	2	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2023-24 में शुरू की गई नई परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या जिनके लिए आधारभूत/आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण आयोजित किया गया था	वर्ष 2023-24 में शुरू की गई उन नई परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या जिनके लिए आधारभूत/आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया था।
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	लागू नहीं	लागू नहीं
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	लागू नहीं	लागू नहीं
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	12	2
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	42	0
19	राइट्स लिमिटेड	39	0
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीआई)	0	11
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल)	0	0
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	20	15
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	93	0
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	16	0
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	40	1
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	0	59
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	22	0
29	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए	डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया
30	एमएमटीसी लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	58	0
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	54	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2023-24 में शुरू की गई नई परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या जिनके लिए आधारभूत/ आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण आयोजित किया गया था	वर्ष 2023-24 में शुरू की गई उन नई परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या जिनके लिए आधारभूत/ आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया था।
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	4	20
34	एसजेवीएन लिमिटेड	1	23
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	0	0
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	134	0
37	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	22	0
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	7	240
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	सेल की नीति के अनुसार	सेल की नीति के अनुसार
40	ईसीजीसी लिमिटेड	0	27
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	0	0
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	28	0
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	0	65
44	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	42	1
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	61	0
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	लागू नहीं	लागू नहीं
47	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	78	0
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	397	4
49	आरईसी लिमिटेड	34	0
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	39	1

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2023-24 में शुरू की गई नई परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या जिनके लिए आधारभूत/आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण आयोजित किया गया था	वर्ष 2023-24 में शुरू की गई उन नई परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या जिनके लिए आधारभूत/आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया था।
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	221	0
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	34	0
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	97	0
54	एनटीपीसी लिमिटेड	885	0
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	1288	0
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	लागू नहीं	लागू नहीं
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	लागू नहीं	लागू नहीं
58	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	0	0
	योग	3770	505

अनुलग्नक-XXXI
(पैरा संख्या 5.5.2 देखें)
सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आंतरिक रूप से कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या	परियोजनाओं की योग संख्या
1	नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	0	0	0
2	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	0	0	0
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	0	0	0
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	1	0	1
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	0	2	2
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	0	0	0
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	10	1	11
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	3	19	22
10	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	0	0	0
11	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आंतरिक रूप से कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या	परियोजनाओं की योग संख्या
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	8	12	20
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएएमटीएल)	0	0	0
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	20	0	20
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	6	12	18
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	12	2	14
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	8	37	45
19	राइट्स लिमिटेड	0	55	55
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीआई)	6	5	11
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल)	0	0	0
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	1	34	35
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	92	1	93

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आंतरिक रूप से कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या	परियोजनाओं की योग संख्या
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	1	15	16
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	14	27	41
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	5	54	59
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	3	28	31
29	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	0	10	10
30	एमएमटीसी लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	2	103	105
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	79	13	92
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	5	32	37
34	एसजेवीएन लिमिटेड	3	52	55
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	18	14	32
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	116	36	152
37	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	17	5	22
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	21	339	360

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आंतरिक रूप से कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या	परियोजनाओं की योग संख्या
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	कोई डेटा नहीं दिया गया एवं सेल की नीति के अनुसार जानकारी दी गई।	कोई डेटा नहीं दिया गया एवं सेल की नीति के अनुसार जानकारी दी गई।	कोई डेटा नहीं दिया गया एवं सेल की नीति के अनुसार जानकारी दी गई।
40	ईसीजीसी लिमिटेड	0	27	27
41	मेंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	156	0	156
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	27	1	28
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	65	0	65
44	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	56	40	96
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	45	63	108
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	0	16	16
47	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	106	40	146
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	267	283	550
49	आरईसी लिमिटेड	6	59	65
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	37	21	58
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	311	81	392
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	5	66	71
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	132	126	258

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आंतरिक रूप से कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या	परियोजनाओं की योग संख्या
54	एनटीपीसी लिमिटेड	0	926	926
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	142	1406	1548
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
58	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	0	0	0
	योग	1,806	4,063	5,869

अनुलग्नक-XXXI क
(पैरा संख्या 5.5.2 देखें)
सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आंतरिक रूप से कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	परियोजनाओं की योग संख्या
1	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	1	0	1
2	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	20	0	20
3	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	156	0	156
4	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	65	0	65

अनुलग्नक-XXXI ख
(पैरा संख्या 5.5.2 देखें)
सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आंतरिक रूप से कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	परियोजनाओं की योग संख्या
1	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	0	2	2
2	राइट्स लिमिटेड	0	55	55
3	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	0	10	10
4	ईसीजीसी लिमिटेड	0	27	27
5	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	0	16	16
6	एनटीपीसी लिमिटेड	0	926	926

अनुलग्नक-XXXI ग
(पैरा संख्या 5.5.2 देखें)
सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	आंतरिक रूप से कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या	परियोजनाओं की योग संख्या
1	ग्रिड नियंत्रण ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	10	1	11
2	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	3	19	22
3	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	8	12	20
4	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	6	12	18
5	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	12	2	14
6	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	8	37	45
7	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीओ)	6	5	11
8	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	1	34	35
9	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	92	1	93
10	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	1	15	16
11	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	14	27	41
12	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	5	54	59
13	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	3	28	31
14	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	2	103	105

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	आंतरिक रूप से कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या	परियोजनाओं की योग संख्या
15	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	79	13	92
16	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	5	32	37
17	एसजेवीएन लिमिटेड	3	52	55
18	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	18	14	32
19	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	116	36	152
20	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	17	5	22
21	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	21	339	360
22	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	27	1	28
23	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	56	40	96
24	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	45	63	108
25	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	106	40	146
26	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	267	283	550
27	आरईसी लिमिटेड	6	59	65
28	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	37	21	58
29	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	311	81	392
30	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	5	66	71
31	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	132	126	258
32	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	142	1,406	1,548

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	आंतरिक रूप से कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/गतिविधियों की संख्या	परियोजनाओं की योग संख्या
28	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	37	21	58
29	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	311	81	392
30	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	5	66	71
31	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	132	126	258
32	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	142	1,406	1,548

अनुलग्नक-XXXI घ
(पैरा संख्या 5.5.2 देखें)
सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	आंतरिक रूप से कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	परियोजनाओं की योग संख्या
1	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	0	0	0
2	इस्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	0	0	0
3	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	0	0	0
4	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	0	0	0
5	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	0	0	0
6	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	0	0	0
7	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	0	0	0
8	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल)	0	0	0
9	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	0	0	0

अनुलग्नक-XXXI इ
(पैरा संख्या 5.5.2 देखें)
सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आंतरिक रूप से कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	बाहरी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाओं/ गतिविधियों की संख्या	परियोजनाओं की योग संख्या
1	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	एमएमटीसी लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	सेल की नीति के अनुसार	सेल की नीति के अनुसार	सेल की नीति के अनुसार
6	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

अनुलग्नक-XXXII
(पैरा संख्या 5.5.3 देखें)
अनुसूची VII के अनुसार प्रमुख क्षेत्र

क्र. सं.	सीपीएसई	स्वास्थ्य	शिक्षा	लैंगिक समानता	पर्यावरण	राष्ट्रीय धरोहर	सशस्त्र बल	खेल	(₹ लाख में)	
									स्वच्छ भारत	कोष
1	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0		
2	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	0	0	0	0	0	0	0		
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	9.39	0	0	9.39	0	0	0		
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	0	0	0	0	0	0	0		
5	इंडियन मोडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	60.39	0	0	0	0	0	0		

क्र. सं.	सीपीएसई	स्वास्थ्य	शिक्षा	लैंगिक समानता	पर्यावरण	राष्ट्रीय धरोहर	सशस्त्र बल	खेल	स्वच्छ भारत कोष
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	30.86	33.02	0	0	0	0	0	
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	0	0	0	0	0	0	0	
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	66.84	31.22	0	0	0	0	0	12.83
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	14.27	2.18	0	0.29	0	0	1.2	
10	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	681	82	1	0	0	10	27	
11	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	0	0	0	0	0	0	0	
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	251	186	20.01	0	3	0	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई	स्वास्थ्य	शिक्षा	लैंगिक समानता	पर्यावरण	राष्ट्रीय धरोहर	सशस्त्र बल	खेल	स्वच्छ भारत कोष
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)								
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	103.68	0	0	0	0	0	0	
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	165	78	0	37	0	0	0	
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	400	108.63	0	2	0	0	0	
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	234.56	205.99	0	0	0	10	0	
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	162.96	59.07	0	13.09	4.08	0	9.29	
19	राइट्स लिमिटेड	972.76	238.56	0	46.43	0	0	0	
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएससीओ)	223.9	25.79	0	0	0	0	0	
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	155.66	5	122.59					

क्र. सं.	सीपीएसई	स्वास्थ्य	शिक्षा	लैंगिक समानता	पर्यावरण	राष्ट्रीय धरोहर	सशस्त्र बल	खेल	स्वच्छ भारत कोष
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल)								
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	305.86	99.42	0	113.295	0	0	25	
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	866.1	403.5	50.69	16.46	37.22	0	0	
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेजा)	815.898	10.33	0	100.33	0	0	0	
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	1,429.32	102.32	346.28	15	0	0	0	
27	इंडियन रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	1,073.2	146.6	129.8	147	0	61.1	46.5	
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	1,667.03	336.89	0	0	0	0	0	

क्र. सं.	सीपीएसई	स्वास्थ्य	शिक्षा	लैंगिक समानता	पर्यावरण	राष्ट्रीय धरोहर	सशस्त्र बल	खेल	स्वच्छ भारत कोष
29	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	143.63	4.86	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
30	एमएमटीसी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	1,094.14	438.88	0.00	144.54	40.00	0.00	33.46	
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	3,044.30	1,062.52	119.99	13.62	154.19	0.05	46.39	
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	671.74	1,486.72	179.00	269.75	253.22	0.00	55.00	
34	एसजेवीएन लिमिटेड	2,054.00	493.37	114.98	283.21	1,141.40	10.77	34.10	
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	1,577.63	3,159.23	3.00	46	202.77	0.00	21.02	
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	508.14	628.62	30.40	28.34	0.00	0.00	49.89	
37	सिंक्रोमिटी प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	812.66	230.04	0.00	0	0.00	100.00	0.00	

क्र. सं.	सीपीएसई	स्वास्थ्य	शिक्षा	लैंगिक समानता	पर्यावरण	राष्ट्रीय धरोहर	सशस्त्र बल	खेल	स्वच्छ भारत कोष
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	9,963.00	1,887.00	235.00	310	1,141.00	1.00	29.00	
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	4,333.00	6,036.00	461.00	965	252.00	0.00	3,267.00	
40	ईसीजीसी लिमिटेड	972.54	1,747.82	0.00	0	0.00	173.94	0.00	
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	406.86	994.78	113.00	119.73	13.62	0.00	19.47	
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	1,659.69	3,482.52	5.00	30.91	0.00	0.00	0.00	
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	1,028.28	703.45	0.00	30.7	0.00	1.00	0.00	
44	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	5,384.25	1,435.44	37.96	44.12	78.55	0.00	444.59	
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	3,247.33	1,082.76	0.00	24.08	6.83	28.16	6.36	
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	5,618.99	1,674.09	1,326.89	759.92	0.00	441.48	1,190.98	

क्र. सं.	सीपीएसई	स्वास्थ्य	शिक्षा	लैंगिक समानता	पर्यावरण	राष्ट्रीय धरोहर	सशस्त्र बल	खेल	स्वच्छ भारत कोष
47	नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	1,048.47	4,555.71	0.00	1,089.00	0.00	0.00	256.37	
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	29,001.14	6,798.10	108.08	3,933.08	2,692.50	0.00	721.27	0
49	आरईसी लिमिटेड	6,741.21	1,009.76	0.00	2,117.52	0.00	1,350.00	2,182.51	0
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	9,191.42	31.23	0.00	186.87	0.00	0.00	0.00	
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	6,398.23	4,388.50	37.96	877.12	200.74	0.00	1,557.35	
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	6,557.16	2,529.91	463.25	165.17	29.10	0.00	0.00	
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	16,743.41	4,531.13	9.95	272.03	38.85	0.00	152.28	0
54	एनटीपीसी लिमिटेड	6,360.15	4,504.97	232.84	5,986.27	202.73	0.00	1,047.35	0
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	20,743.84	25,310.14	2,095.82	6,016.19	278.42	36.65	1,471.38	
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	14.00	-	-	-	-	-	-	

क्र. सं.	सीपीएसई	स्वास्थ्य	शिक्षा	लैंगिक समानता	पर्यावरण	राष्ट्रीय धरोहर	सशस्त्र बल	खेल	स्वच्छ भारत कोष
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	-	-	-	-	-	-	-	
58	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड		1.52	5.41		0.34		9.45	
	प्रतिशतता	44.42	23.60	1.79	6.94	1.94	0.64	3.64	0.00
	योग	155,009.24	82,363.19	6,249.90	24,213.65	6,770.55	2,224.15	12,704.21	12.83

अनुलग्नक-XXXIII
(पैरा संख्या 5.5.4 देखें)
स्थानीय क्षेत्र

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी द्वारा स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित किया गया है?	क्या स्थानीय क्षेत्र की परिभाषा कंपनी की सीएसआर नीति का हिस्सा है?	क्या कंपनी ने सीएसआर फंड खर्च करने के लिए अपने परिचालन के आसपास के स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी थी?
1	नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	नहीं	नहीं	लागू नहीं
2	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	हाँ	हाँ	लागू नहीं
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	नहीं	नहीं	नहीं
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	हाँ	हाँ	लागू नहीं
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	नहीं	नहीं	नहीं
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	हाँ	हाँ	हाँ
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	हाँ	हाँ	नहीं
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	हाँ	हाँ	हाँ
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	हाँ	हाँ	हाँ
10	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	हाँ	नहीं	हाँ
11	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	नहीं	नहीं	लागू नहीं
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	हाँ	नहीं	हाँ
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी द्वारा स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित किया गया है?	क्या स्थानीय क्षेत्र की परिभाषा कंपनी की सीएसआर नीति का हिस्सा है?	क्या कंपनी ने सीएसआर फंड खर्च करने के लिए अपने परिचालन के आसपास के स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी थी?
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएएमटीएल)	हाँ	हाँ	हाँ
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	हाँ	हाँ	हाँ
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	हाँ	हाँ	हाँ
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	हाँ	हाँ	हाँ
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	हाँ	हाँ	हाँ
19	राइट्स लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीआई)	हाँ	हाँ	हाँ
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	हाँ	हाँ	नहीं
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल)	नहीं	नहीं	नहीं
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	हाँ	हाँ	हाँ
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	हाँ	हाँ	हाँ
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	हाँ	हाँ	हाँ
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	हाँ	हाँ	हाँ
29	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	हाँ	हाँ	नहीं
30	एमएमटीसी लिमिटेड	नहीं	नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी द्वारा स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित किया गया है?	क्या स्थानीय क्षेत्र की परिभाषा कंपनी की सीएसआर नीति का हिस्सा है?	क्या कंपनी ने सीएसआर फंड खर्च करने के लिए अपने परिचालन के आसपास के स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी थी?
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	हाँ	हाँ	हाँ
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	हाँ	हाँ	हाँ
34	एसजेवीएन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	हाँ	हाँ	हाँ
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	हाँ	हाँ	हाँ
37	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	हाँ	हाँ	हाँ
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	नहीं	हाँ	हाँ
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल)	हाँ	हाँ	हाँ
40	ईसीजीसी लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	हाँ	हाँ	हाँ
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	नहीं	नहीं	हाँ
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	नहीं	नहीं	हाँ
44	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	हाँ	हाँ	नहीं
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	हाँ	हाँ	हाँ
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
47	नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	हाँ	हाँ	हाँ
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ
49	आरईसी लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	नहीं	नहीं	नहीं

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी द्वारा स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित किया गया है?	क्या स्थानीय क्षेत्र की परिभाषा कंपनी की सीएसआर नीति का हिस्सा है?	क्या कंपनी ने सीएसआर फंड खर्च करने के लिए अपने परिचालन के आसपास के स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी थी?
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	हाँ	हाँ	हाँ
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	हाँ	हाँ	हाँ
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	हाँ	हाँ	हाँ
54	एनटीपीसी लिमिटेड	हाँ	हाँ	हाँ
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	नहीं	नहीं	हाँ
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	नहीं	नहीं	हाँ
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
58	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	हाँ	नहीं	हाँ

अनुलग्नक-XXXIV
(पैरा संख्या 5.7.1 देखें)
वेबसाइट पर सीएसआर आँकड़ों का प्रकटीकरण

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर समिति की संरचना, एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं को (यदि कोई हो) उनकी वेबसाइट पर सार्वजनिक पहुंच के लिए प्रकाशित किया गया है?
1	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	हाँ
2	इस्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	हाँ
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	हाँ
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	हाँ
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	नहीं
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	हाँ
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	हाँ
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	हाँ
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	हाँ
10	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	हाँ
11	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	हाँ
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	हाँ
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	नहीं
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	नहीं
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	हाँ
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	हाँ
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	हाँ
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	हाँ
19	राइट्स लिमिटेड	हाँ
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीओ)	नहीं
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	हाँ

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर समिति की संरचना, एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं को (यदि कोई हो) उनकी वेबसाइट पर सार्वजनिक पहुंच के लिए प्रकाशित किया गया है?
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल)	बोर्ड की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	हाँ
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	हाँ
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	हाँ
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	हाँ
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	हाँ
29	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	हाँ
30	एमएमटीसी लिमिटेड	हाँ
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	हाँ
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	हाँ
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	हाँ
34	एसजेवीएन लिमिटेड	हाँ
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	हाँ
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	हाँ
37	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	हाँ
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	हाँ
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल)	हाँ
40	ईसीजीसी लिमिटेड	हाँ
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	हाँ
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	हाँ
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	हाँ
44	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	हाँ
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	हाँ

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर समिति की संरचना, एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं को (यदि कोई हो) उनकी वेबसाइट पर सार्वजनिक पहुंच के लिए प्रकाशित किया गया है?
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	हाँ
47	नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	हाँ
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
49	आरईसी लिमिटेड	हाँ
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	हाँ
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	हाँ
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	हाँ
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	हाँ
54	एनटीपीसी लिमिटेड	हाँ
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	हाँ
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	हाँ
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	लागू नहीं
58	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	नहीं

अनुलग्नक-XXXV
(पैरा संख्या 5.7.2 देखें)
सीएसआर रिपोर्टिंग प्रारूप

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या 'सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट' सीएसआर नीति नियम 2022 द्वारा प्रदान किए गए टेम्पलेट/प्रारूप के अनुसार है?
1	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	हाँ
2	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	हाँ
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	नहीं
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	नहीं
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	नहीं
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	हाँ
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	हाँ
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	हाँ
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	हाँ
10	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	हाँ
11	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसआई)	हाँ
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	हाँ
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	नहीं
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	हाँ
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	हाँ
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	हाँ
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	हाँ
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	हाँ
19	राइट्स लिमिटेड	हाँ
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीओ)	हाँ
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	हाँ
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल)	अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या 'सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट' सीएसआर नीति नियम 2022 द्वारा प्रदान किए गए टेम्पलेट/प्रारूप के अनुसार है?
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	हाँ
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	हाँ
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	हाँ
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	हाँ
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	हाँ
29	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	हाँ
30	एमएमटीसी लिमिटेड	हाँ
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	हाँ
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	हाँ
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	हाँ
34	एसजेवीएन लिमिटेड	हाँ.
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	हाँ
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	हाँ
37	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	हाँ
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	हाँ
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	हाँ
40	ईसीजीसी लिमिटेड	हाँ
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	हाँ
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	नहीं
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	हाँ
44	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	हाँ
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	हाँ
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	हाँ
47	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	नहीं
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या 'सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट' सीएसआर नीति नियम 2022 द्वारा प्रदान किए गए टेम्पलेट/प्रारूप के अनुसार है?
49	आरईसी लिमिटेड	हाँ
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	हाँ
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	हाँ
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	हाँ
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	हाँ
54	एनटीपीसी लिमिटेड	हाँ
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	हाँ
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	हाँ
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	लागू नहीं
58	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	नहीं

अनुलग्नक-XXXVI
(पैरा संख्या 5.7.3 देखें)
सृजित/अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्तियाँ

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति सृजित/अधिग्रहित की गई थी?
1	नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	लागू नहीं
2	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	नहीं
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	नहीं
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	लागू नहीं
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	हाँ
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	हाँ
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	नहीं
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	नहीं
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	नहीं
10	यूरैनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	नहीं
11	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	नहीं
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	नहीं
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	नहीं
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	नहीं
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	हाँ
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	नहीं
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	नहीं
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	नहीं
19	राइट्स लिमिटेड	हाँ
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीसी)	नहीं
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	लागू नहीं
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल)	नहीं
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	हाँ

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति सृजित/अधिग्रहित की गई थी?
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	नहीं
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	हाँ
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	लागू नहीं
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	नहीं
29	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	नहीं
30	एमएमटीसी लिमिटेड	लागू नहीं
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	नहीं
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	हाँ
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	हाँ
34	एसजेवीएन लिमिटेड	नहीं
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	नहीं
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	हाँ
37	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	हाँ
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	हाँ
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	नहीं
40	ईसीजीसी लिमिटेड	नहीं
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	नहीं
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	नहीं
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	नहीं
44	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	नहीं
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	हाँ
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	नहीं
47	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	हाँ
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं
49	आरईसी लिमिटेड	नहीं
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	हाँ

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति सृजित/अधिग्रहित की गई थी?
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	हाँ
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	हाँ
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	नहीं
54	एनटीपीसी लिमिटेड	नहीं
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	हाँ
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	नहीं
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	लागू नहीं
58	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	नहीं

अनुलग्नक-XXXVII
(पैरा संख्या 5.7.5 देखें)
प्रभाव का आकलन

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी ने एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के व्यय वाली अपनी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कराया है, एवं ये परियोजनाएं प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी हों?
1	नेशनल फ़िल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएफडीसीएल)	लागू नहीं
2	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड (आईआईएसएल)	लागू नहीं
3	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल)	नहीं
4	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल)	लागू नहीं
5	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	लागू नहीं
6	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)	लागू नहीं
7	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)	लागू नहीं
8	ग्रिड नियंत्रण ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (जीसीआई)	लागू नहीं
9	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	लागू नहीं
10	यूरैनियम कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	लागू नहीं
11	भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री (सीएसआरएसएआई)	लागू नहीं
12	मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	लागू नहीं
13	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)	नहीं
14	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)	लागू नहीं
15	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)	लागू नहीं
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)	लागू नहीं
17	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)	लागू नहीं
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	नहीं
19	राइट्स लिमिटेड	हाँ

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी ने एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के व्यय वाली अपनी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कराया है, एवं ये परियोजनाएं प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी हों?
20	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीआई)	लागू नहीं
21	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	लागू नहीं
22	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल)	लागू नहीं
23	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	लागू नहीं
24	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	लागू नहीं
25	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा)	लागू नहीं
26	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	हाँ
27	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)	लागू नहीं
28	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल)	हाँ
29	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	नहीं
30	एमएमटीसी लिमिटेड	लागू नहीं
31	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर)	हाँ
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	हाँ
33	रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल)	हाँ
34	एसजेवीएन लिमिटेड	हाँ
35	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	नहीं
36	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)	लागू नहीं
37	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	हाँ
38	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	हाँ
39	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल)	लागू नहीं
40	ईसीजीसी लिमिटेड	नहीं
41	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	हाँ
42	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)	हाँ
43	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल)	हाँ

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	क्या कंपनी ने एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के व्यय वाली अपनी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कराया है, एवं ये परियोजनाएं प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी हों?
44	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल)	हाँ
45	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	हाँ
46	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी)	नहीं
47	नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	हाँ
48	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
49	आरईसी लिमिटेड	हाँ
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	हाँ
51	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)	हाँ
52	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	हाँ
53	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	हाँ
54	एनटीपीसी लिमिटेड	शून्य
55	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी	हाँ
56	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी)	लागू नहीं
57	नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेरामैक)	लागू नहीं
58	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	लागू नहीं

अनुलग्नक-XXXVIII
(पैरा संख्या 6.2.4 देखें)

वर्ष 2022-23 एवं उसके बाद के लिए समझौता ज्ञापन के मापदंड एवं उनका संबंधित भारांक

क्रम सं.	मानदंड	अंक
क. राजस्व, भौतिक उत्पादन, पूंजीगत व्यय एवं विदेशी मुद्रा आय/बचत:		
1	परिचालन से राजस्व (₹ करोड़ में)	5
2	भौतिक उत्पादन: उत्पादन/उत्पादन/संचरण/उत्पादन का मूल्य/सेवाएँ/योग आय	20
3	पूंजीगत व्यय (₹ करोड़)	10
4	(i) परिचालन से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत के रूप में निर्यात	4
	(ii) परिचालन से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत के रूप में आयात	4
ख. लाभप्रदता		
5	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए (%)	10
6	निवल संपत्ति पर प्रतिफल (%) या नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (%)	15
7	एसेट टर्नओवर अनुपात (%)	5
ग. क्रय, व्यापारिक प्राप्तियां एवं अनुसंधान एवं विकास		
8	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार निर्धारित समय के भीतर टीआरईडीएस पोर्टल के ज़रिए सीपीएसई द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति (%)	5
9	योग खरीद में जीईएम पोर्टल से खरीद का प्रतिशत (%)	2
10	परिचालन से प्राप्त राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में व्यक्त व्यापारिक प्राप्त राशि को किया जाता है।	3
11	अनुसंधान एवं विकास/नवाचारों पर व्यय, सार्वजनिक व्यय प्रबंधन (पीबीटी) के प्रतिशत के रूप में (%)	2
घ. शेयरधारकों के लिए मूल्य निर्माण		
12	प्रति शेयर आय (असूचीबद्ध कंपनियों के लिए) (₹) या शेयरधारकों को योग प्रतिफल (सूचीबद्ध कंपनियों के लिए) (%)	15

इसके अतिरिक्त, कुछ अनुपालन मापदंड भी थे, जैसे कि सीएसआर व्यय पर डीपीई दिशानिर्देश, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी अधिनियम, 2013 (या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में एसईबीआई एलओडीआर विनियम), कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर नीति आयोग द्वारा दिए गए परिसंपत्ति मुद्रीकरण मील के पत्थर पर दिये गए लक्ष्य, एमएसई को खरीद एवं समय पर भुगतान, सीपीएसई में मानव संसाधनों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम एवं पहल।

इन मापदंडों का पालन न करने पर अंकों में कटौती की जाएगी।

अनुलग्नक-XXXIX
(पैरा संख्या 6.4 देखें)
वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए समझौता ज्ञापन
मापदंडों के संबंध में निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क) एनएलसी लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

क्रम सं.	मापदंड	इकाई	लक्ष्य 2022-23	उपलब्धि 2022-23	लक्ष्य 2023-24	उपलब्धि 2023-24
1.	परिचालन से राजस्व	₹ करोड़	13,939.00	16,165.24	15,000.00	12,999.03
2.	विद्युत उत्पादन	एमयू	33,943.00	30,082.80	35,000.00	27,106.21
3.	कोयले का उत्पादन	एमटी	-	-	14.44	12.64
4.	पूंजीगत व्यय	₹ करोड़	2,920.00	3,307.79	2,880.00	4,270.18
5.	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए	%	40.70	26.98	40.70	39.84
6.	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	11.39	7.96	11.39	9.67
7.	एसेट टर्नओवर अनुपात	%	29.95	32.76	29.95	25.38
8.	टीआरईडीएस पोर्टल के जरिए सामान एवं सेवाओं के बीजक को स्वीकार/अस्वीकार करना	%	100.00	60.00	100.00	100.00
9.	योग खरीद में से जीईएम से की गई खरीद का प्रतिशत	%	25.00	59.08	100.00	156.84
10.	परिचालन से प्राप्त राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में व्यापारिक प्राप्य राशियाँ	दिनों की संख्या	90.00	106.80	45.00	113.62
11.	सार्वजनिक व्यय प्रबंधन (पीबीटी) के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास/ नवाचार पहलों पर व्यय	%	2.00	1.45	2.00	1.51
12.	शेयरधारकों को योग प्रतिफल (बीएसई 500 सूचकांक से अधिक)	%	0.00	28.20	100.00	199.97

ख) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

क्रम सं.	मापदंड	इकाई	लक्ष्य 2022-23	उपलब्धि 2022-23	लक्ष्य 2023-24	उपलब्धि 2023-24
1.	परिचालन से राजस्व	₹ करोड़	3,720	3,330.14	3,885	3,280.86
2.	पूँजीगत व्यय	₹ करोड़	70	73.30	98	70.84
3.	निर्यात/विदेश से आय	₹ करोड़	300	236.74	270	281.11
4.	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए	%	21.10	13.53	17.55	14.75
5.	शुद्ध संपत्ति पर प्रतिफल	%	20.00	18.41	14.10	21.54
6.	परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	81.00	79.64	70.54	73.81
7.	टीआरईडीएस पोर्टल के ज़रिए वस्तुओं एवं सेवाओं के बीजक की स्वीकृति/अस्वीकृति	%	100	100	100	100.00
8.	योग खरीद में से जीईएम से की गई खरीद का प्रतिशत	%	25	76.17	100	137.95
9.	व्यापारिक प्राप्य राशि, परिचालन से प्राप्त राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में	दिनों की संख्या	48	40.30	45	37.34
10.	पीबीटी के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास/नवाचार पहलों पर व्यय	%	10.77	6.76	-	-
11.	अनुसंधान एवं विकास/नवाचार पहलों पर व्यय	₹ करोड़	-	-	30	29.12
12.	शेयरधारकों को योग प्रतिफल (बीएसई 500 सूचकांक से अधिक)	%	0.00	20.94	100	175.47
13.	सौर ऊर्जा प्रणाली का चालू होना	किलो-वाट-घंटा	400	400	-	-
14.	ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में नए व्यवसाय से प्राप्त राजस्व	₹ करोड़	30	63.86	-	-

ग) एनएमडीसी लिमिटेड

क्रम सं.	मापदंड का नाम	इकाई	लक्ष्य 2022-23	उपलब्धि 2022-23	लक्ष्य 2023-24	उपलब्धि 2023-24
1.	परिचालन से राजस्व	₹ करोड़	30,060	17,620.46	28,790	21,307.85
2.	लौह अयस्क का उत्पादन	लाख टन	490	408.17	544	450.22
3.	पूंजीगत व्यय	₹ करोड़	3512	4,265.06	1,769	1,879.07
4.	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए	%	44.32	37.09	44.18	38.20
5.	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	22.38	18.89	35.50	31.28
6.	परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	60.06	35.86	65.21	63.60
7.	टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं के बिलों की स्वीकृति/ अस्वीकृति	%	100	60	100	100.00
8.	योग खरीद के प्रतिशत के रूप में जीईएम से खरीद	%	25	84.97	100	132.97
9.	व्यापारिक प्राप्य राशियाँ, परिचालन से प्राप्त राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में	दिनों की संख्या	42	54.06	45	33.31
10.	पीबीटी के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास/ नवाचार पहलों पर व्यय	%	2.00	2.15	2	2.08
11.	शेयरधारकों को योग प्रतिफल (बीएसई 500 सूचकांक से अधिक)	%	0.00	-9.90	100	88.44

घ) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

क्रम सं.	मापदंड का नाम	इकाई	लक्ष्य 2022-23	उपलब्धि 2022-23	लक्ष्य 2023-24	उपलब्धि 2023-24
1.	परिचालन से होने वाली आय	₹ करोड़	5,445	5,806.36	6,534	5,046.53
2.	योग जहाजों के प्रतिशत के रूप में जहाजों की उपलब्धता	%	100	92.35	100	94.29
3.	पूँजीगत व्यय	₹ करोड़	466	509.95	615	517.39
4.	परिचालन से होने वाले राजस्व के प्रतिशत के रूप में निर्यात	%	30.39	29.59	30.39	30.61
5.	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए	%	38.21	29.46	38.21	32.42
6.	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	%	9.48	8.56	9.48	8.97
7.	परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	46.66	40.15	49.61	43.49
8.	टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं के बिलों की स्वीकृति/अस्वीकृति	%	100	100	100	100.00
9.	योग खरीद में से जीईएम से की गई खरीद का प्रतिशत	%	25	18.95	100	106.75
10.	परिचालन से होने वाली आय के दिनों की संख्या के रूप में व्यापारिक प्राप्य राशियाँ	दिनों की संख्या	47	64	45	102.05
11.	शेयरधारकों को योग प्रतिफल (बीएसई 500 सूचकांक से अधिक)	%	0.00	4.98	100	122.54

ड) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड

क्रम सं.	मापदंड का नाम	इकाई	लक्ष्य 2022-23	उपलब्धि 2022-23	लक्ष्य 2023-24	उपलब्धि 2023-24
1.	परिचालन से होने वाली आय	₹ करोड़	14,181	14,254.86	17,017	13,149.15
2.	एल्युमिनियम ढलाई धातु का उत्पादन	लाख टन	4.60	4.60	5.52	4.63
3.	एल्युमिना हाइड्रेट का प्रोडक्शन	लाख टन	21.61	21.23	25.93	21.24
4.	पूंजीगत व्यय	₹ करोड़	1,800	1,834.77	2,200	1,988.22
5.	परिचालन से होने वाले राजस्व के प्रतिशत के रूप में निर्यात	%	36.49	29.58	-	-
6.	विदेश से निर्यात/इनकम	₹ करोड़	-	-	4,813	4,275.73
7.	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए	%	33.25	17.76	33.25	22.78
8.	शुद्ध संपत्ति पर प्रतिफल	%	25.93	11.17	25.93	14.45
9.	परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	83.81	82.21	83.81	69.66
10.	टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं के बिलों की स्वीकृति/अस्वीकृति	%	100	60	100	100.00
11.	योग खरीद में से जीईएम से की गई खरीद का प्रतिशत	%	25	53.90	100	102.27
12.	व्यापारिक प्राप्य राशियाँ, परिचालन से प्राप्त राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में	दिनों की संख्या	2	2.34	-	-
13.	पीबीटी के % के रूप में अनुसंधान एवं विकास/ नवाचार पहलों पर व्यय	%	2.00	8.76	2.15	3.92
14.	शेयरधारकों को योग प्रतिफल (बीएसई 500 सूचकांक से अधिक)	%	0.00	-31.45	100	99.40

च) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

क्रम सं.	मापदंड का नाम	इकाई	लक्ष्य 2022-23	उपलब्धि 2022-23	लक्ष्य 2023-24	उपलब्धि 2023-24
1.	उत्पादन का मूल्य	₹ करोड़	26,400	27,053.68	31,680	30,117.82
2.	पूँजीगत व्यय	₹ करोड़	1,800	1,831.27	1,550	2,060.81
3.	विदेशों से निर्यात/आय	₹ करोड़	511	293.71	537	415.48
4.	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए	%	26.08	29.21	26.79	32.84
5.	निवल संपत्ति पर प्रतिफल	%	29.25	27.17	29.25	24.44
6.	परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	56.14	42.55	47.63	39.30
7.	टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं के बिलों की स्वीकृति/ अस्वीकृति	%	100	60	100	100.00
8.	योग खरीद में से जीईएम से की गई खरीद का प्रतिशत	%	25	42.35	100	148.87
9.	व्यापारिक प्राप्य राशियाँ, परिचालन से प्राप्त राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में	दिनों की संख्या	69	63.97	60	58.52
10.	पीबीटी के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास/नवाचार पहलों पर व्यय	%	37.65	38.32	37.65	32.70
11.	शेयरधारकों को योग प्रतिफल (बीएसई 500 सूचकांक से अधिक)	%	0.00	86.95	100	145.89

अनुलग्नक-XL
(पैरा संख्या 7.6.4 देखें)
रणनीतिक विनिवेश की स्थिति

रणनीतिक विनिवेश की स्थिति	क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
दीपम द्वारा प्रक्रियाधीन उन लेन-देनों की सूची जिनमें ईओआई जारी किया जा चुका है।	1	बीईएमएल लिमिटेड
	2	द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
	3	एसएलएल लाइफ़केयर लिमिटेड
	4	प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
	5	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (सहायक कंपनी)
	6	इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
	7	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल)
	8	आईडीबीआई बैंक
ऐसे लेन-देन जिनके लिए ईओआई जारी नहीं किया गया है, या ईओआई/आरएफपी जारी होने के बाद रद्द कर दिए गए लेन-देन।	9	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को छोड़कर)
	10	पवन हंस लिमिटेड
	11	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल)
	12	दुर्गापुर मिश्र धातु इस्पात संयंत्र; सलेम इस्पात संयंत्र; भद्रावती इस्पात संयंत्र - भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की इकाइयाँ
	13	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
	14	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा संसाधित किए जा रहे लेन-देन	15	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विभिन्न इकाइयाँ
	16	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
	17	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
सीपीएसई द्वारा बंद करने की सिफारिश/मंजूरी के कारण लेन-देन रोक दिए गए; या किसी अन्य कारण से	18	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) *
	19	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड *
	20	भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड *
	21	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड**
	22	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की इकाइयाँ (नयागाँव इकाई) #
कानूनी विवाद के कारण लेन-देन रुके हुए हैं।	23	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

रणनीतिक विनिवेश की स्थिति	क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
एनसीएलटी में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अधीन	24	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (सहायक कंपनी)@
लेन-देन संभव नहीं है।	25	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड
	26	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
लेन-देन पूरे हुए	27	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)
	28	रूरल इलेक्ट्रिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी)
	29	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
	30	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी)
	31	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल)
	32	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसी)
	33	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनईईपीसीओ)
	34	कामराजार पोर्ट लिमिटेड
	35	एयर इंडिया ^^
	36	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)

* सरकार ने कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी।

** सीपीएसई बंद होने की प्रक्रिया में है।

लेन-देन संभव नहीं है एवं खदानें राज्य सरकारों को वापस की जा रही हैं।

@ केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) की संकल्प योजना को कोच्चि एनसीएलटी के दिनांक 29.01.2021 के आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन है।

^^ एआईएचएल के स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का विनिवेश अभी बाकी है।

अनुलग्नक-XLI
(पैरा संख्या 7.7.2 देखें)
पीएसई की सहायक कंपनी/इकाइयों को बंद करने/विनिवेश का विवरण

क्रम सं.	पीएसई की सहायक कंपनी/इकाइयाँ	प्रस्ताव	एएम अनुमोदन की तिथि	बंद होने की तिथि	एएम की मंजूरी की तिथि से 31 मार्च 2025 / बंद होने की वास्तविक तिथि तक के दिन
1	कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड (सीआईएएल), कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	समापन	14-03-24	बंद नहीं	382
2	सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड (सीएसपीएल), कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	समापन	14-03-24	बंद नहीं	382
3	टीसीआईएल ओमान एलएलसी (टीसीआईएल ओमान का जेवी)	समापन	11-04-23	मई 2023	20
4	टीसीआईएल यूएसए इंक. (यूएसए में टीसीआईएल की 100% सहायक कंपनी)	समापन	08-05-23	अगस्त 2024	451
5	टीसीआईएल लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड (टीएलटीआरएल), टीसीआईएल की एसपीवी/सहायक कंपनी	समापन	10-07-23	बंद नहीं	630
6	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड (टीबीटीआरएल) (टीसीआईएल की एसपीवी/सहायक कंपनी)	समापन	17-08-23	बंद नहीं	592

क्रम सं.	पीएसई की सहायक कंपनियाँ/इकाइयाँ	प्रस्ताव	एएम अनुमोदन की तिथि	बंद होने की तिथि	एएम की मंजूरी की तिथि से 31 मार्च 2025 / बंद होने की वास्तविक तिथि तक के दिन
7	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)	25% तक इक्विटी का विनिवेश	14-03-24	पूरा नहीं हुआ	382
8	भारती हेक्साकॉम लिमिटेड (बीएचएल) में टीसीआईएल की 30% इक्विटी	टीसीआईएल की 30% इक्विटी का विनिवेश	17-08-23	पूरा नहीं हुआ	592

अनुलग्नक-XLII
(पैरा संख्या 8.3 देखें)
समीक्षा के लिए चयनित सीपीएसई की सूची

क्रम सं.	चयनित सीपीएसई (नाम गुप्त रखे गए)
1	सीपीएसई_1
2	सीपीएसई_2
3	सीपीएसई_3
4	सीपीएसई_4
5	सीपीएसई_5
6	सीपीएसई_6
7	सीपीएसई_7
8	सीपीएसई_8
9	सीपीएसई_9
10	सीपीएसई_10
11	सीपीएसई_11
12	सीपीएसई_12
13	सीपीएसई_13
14	सीपीएसई_14
15	सीपीएसई_15
16	सीपीएसई_16
17	सीपीएसई_17
18	सीपीएसई_18
19	सीपीएसई_19
20	सीपीएसई_20
21	सीपीएसई_21
22	सीपीएसई_22

क्रम सं.	चयनित सीपीएसई (नाम गुप्त रखे गए)
23	सीपीएसई_23
24	सीपीएसई_24
25	सीपीएसई_25
26	सीपीएसई_26
27	सीपीएसई_27
28	सीपीएसई_28
29	सीपीएसई_29
30	सीपीएसई_30

अनुलग्नक-XLIII
(पैरा संख्या 8.5.1 देखें)

खंड 'क' के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण

क्र. सं.	सूचकों के नाम	अनुपालन करने वाले सीपीएसई की संख्या	सीपीएसई का नाम
1	सूचीबद्ध कंपनी का (सीआईएन)	शून्य	लागू नहीं
2	सूचीबद्ध कंपनी का नाम	शून्य	लागू नहीं
3	निगमन वर्ष	शून्य	लागू नहीं
4	पंजीकृत कार्यालय पता	शून्य	लागू नहीं
5	कॉर्पोरेट पता	शून्य	लागू नहीं
6	ई-मेल	शून्य	लागू नहीं
7	टेलीफोन	शून्य	लागू नहीं
8	वेबसाइट	शून्य	लागू नहीं
9	रिपोर्टिंग के लिए वित्तीय वर्ष	शून्य	लागू नहीं
10	स्टॉक एक्सचेंज जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं	शून्य	लागू नहीं
11	प्रदत्त पूंजी	1	सीपीएसई_16
12	बीआरएसआर रिपोर्ट से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम एवं संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता)	शून्य	लागू नहीं
13	रिपोर्टिंग का दायरा	4	सीपीएसई_4, सीपीएसई_23, सीपीएसई_20, सीपीएसई_28
14	बीमा प्रदाता का नाम	2	सीपीएसई_16, सीपीएसई_30
15	बीमा का प्रकार	2	सीपीएसई_16, सीपीएसई_30
16	व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण	3	सीपीएसई_7, सीपीएसई_19, सीपीएसई_20
17	बेचे गए उत्पाद/सेवाएँ	3	सीपीएसई_3, सीपीएसई_7, सीपीएसई_14
18	उन स्थानों की संख्या जहाँ संयंत्र एवं कार्यालय स्थित हैं	6	सीपीएसई_4, सीपीएसई_8, सीपीएसई_19, सीपीएसई_23, सीपीएसई_20, सीपीएसई_28
19	जिन बाजारों में कंपनी कार्यरत है	3	सीपीएसई_4, सीपीएसई_18, सीपीएसई_24
20	कर्मचारियों एवं श्रमिकों की संख्या	7	सीपीएसई_4, सीपीएसई_13, सीपीएसई_15, सीपीएसई_19, सीपीएसई_22, सीपीएसई_20, सीपीएसई_26

क्र. सं.	सूचकों के नाम	अननुपालन करने वाले सीपीएसई की संख्या	सीपीएसई का नाम
21	महिलाओं की भागीदारी	1	सीपीएसई_4
22	कर्मचारियों एवं श्रमिकों का टर्नओवर रेट	3	सीपीएसई_7, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16
23	होल्डिंग, सहायक एवं सहयोगी कंपनियां जिनमें संयुक्त उद्यम भी शामिल हैं	6	सीपीएसई_1, सीपीएसई_11, सीपीएसई_20, सीपीएसई_25, सीपीएसई_24, सीपीएसई_28
24	सीएसआर का विवरण	1	सीपीएसई_1
25	प्राप्त शिकायतें/आपत्तियाँ	15	सीपीएसई_4, सीपीएसई_6, सीपीएसई_5, सीपीएसई_9, सीपीएसई_12, सीपीएसई_13, सीपीएसई_14, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_18, सीपीएसई_19, सीपीएसई_30, सीपीएसई_22, सीपीएसई_28, सीपीएसई_29
26	चिन्हित जोखिम / अवसर	2	सीपीएसई_4, सीपीएसई_29

उन सीपीएसई की संख्या जिनमें कुछ संकेतकों के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए थे: 2 (सीपीएसई_6, सीपीएसई_28)

अनुलग्नक-XLIV
(पैरा संख्या 8.5.2 देखें)

खंड ख के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण

क्र. सं.	सूचकों के नाम	अननुपालन करने वाले सीपीएसई की संख्या	सीपीएसई का नाम
1	प्रत्येक सिद्धांत एवं उसके वेब लिंक से संबंधित नीति/नीतियाँ	4	सीपीएसई_4, सीपीएसई_13, सीपीएसई_28, सीपीएसई_29
2	नीति को प्रक्रियाओं में रूपांतरित किया गया	शून्य	लागू नहीं
3	वीसीपी तक विस्तारित नीतियां	1	सीपीएसई_4
4	अपनाए गए कोड/प्रमाणीकरण/मानक एवं उनका मानचित्रण	8	सीपीएसई_1, सीपीएसई_4, सीपीएसई_6, सीपीएसई_14, सीपीएसई_13, सीपीएसई_18, सीपीएसई_23, सीपीएसई_28
5	निर्धारित समयसीमा के साथ प्रतिबद्धताएं/ लक्ष्य	10	सीपीएसई_1, सीपीएसई_4, सीपीएसई_6, सीपीएसई_5, सीपीएसई_14, सीपीएसई_18, सीपीएसई_19, सीपीएसई_30, सीपीएसई_23, सीपीएसई_28
6	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध प्रदर्शन	9	सीपीएसई_1, सीपीएसई_4, सीपीएसई_5, सीपीएसई_14, सीपीएसई_18, सीपीएसई_19, सीपीएसई_30, सीपीएसई_23, सीपीएसई_28
7	व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का बयान	3	सीपीएसई_11, सीपीएसई_19, सीपीएसई_22
8	व्यवसायिक उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण	22	सीपीएसई_2, सीपीएसई_3, सीपीएसई_1, सीपीएसई_4, सीपीएसई_6, सीपीएसई_7, सीपीएसई_8, सीपीएसई_9, सीपीएसई_10, सीपीएसई_12, सीपीएसई_15, सीपीएसई_11, सीपीएसई_13, सीपीएसई_17, सीपीएसई_18, सीपीएसई_21, सीपीएसई_23, सीपीएसई_22, सीपीएसई_25, सीपीएसई_24, सीपीएसई_27, सीपीएसई_28

क्र. सं.	सूचकों के नाम	अननुपालन करने वाले सीपीएसई की संख्या	सीपीएसई का नाम
9	सतत विकास संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए निर्दिष्ट समिति	21	सीपीएसई_4, सीपीएसई_6, सीपीएसई_10, सीपीएसई_12, सीपीएसई_8, सीपीएसई_11, सीपीएसई_13, सीपीएसई_15, सीपीएसई_14, सीपीएसई_17, सीपीएसई_18, सीपीएसई_19, सीपीएसई_21, सीपीएसई_23, सीपीएसई_22, सीपीएसई_20, सीपीएसई_25, सीपीएसई_24, सीपीएसई_26, सीपीएसई_27, सीपीएसई_28
10	नीतियों के अनुरूप प्रदर्शन की समीक्षा का विवरण	1	सीपीएसई_10
11	नीतियों का स्वतंत्र मूल्यांकन	1	सीपीएसई_4
12	सिद्धांतों को शामिल न करने के कारण	शून्य	लागू नहीं

उन सीपीएसई की संख्या जिन्होंने कुछ संकेतकों के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए थे: 3 (सीपीएसई_13, सीपीएसई_20, सीपीएसई_28)

अनुलग्नक-XLV
(पैरा संख्या 8.5.3 देखें)

खंड ग के सिद्धांत 1 के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण
आवश्यक संकेतक

क्र. सं.	सूचकों के नाम	अनुपालन करने वाले सीपीएसई की संख्या	सीपीएसई का नाम
1	किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता	5	सीपीएसई_2, सीपीएसई_4, सीपीएसई_13, सीपीएसई_21, सीपीएसई_29
2	भुगतान किए गए जुर्माने/दंड का विवरण	2	सीपीएसई_4, सीपीएसई_17
3	क्रमांक 2 के लिए अपील/पुनरीक्षण	शून्य	लागू नहीं
4	भ्रष्टाचार-विरोधी/रिश्वत-विरोधी नीति एवं वेब-लिंग का अस्तित्व	2	सीपीएसई_12, सीपीएसई_22
5	निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई	1	सीपीएसई_29
6	हितों के टकराव से संबंधित शिकायतें	शून्य	लागू नहीं
7	क्रमांक 7 से संबंधित सुधारात्मक कार्रवाई	शून्य	लागू नहीं
8	देय खातों के दिनों की संख्या	3	सीपीएसई_11, सीपीएसई_15, सीपीएसई_30
9	व्यापार की पारदर्शिता - खरीद/बिक्री/संबंधित पक्षों का संकेंद्रण	4	सीपीएसई_9, सीपीएसई_16, सीपीएसई_30, सीपीएसई_22

उन सीपीएसई की संख्या जिनमें कुछ संकेतकों के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए थे: 3 (सीपीएसई_6, सीपीएसई_13, सीपीएसई_28)

नेतृत्व संकेतक

क्र. सं.	सूचकों के नाम	अननुपालन वाले सी.पी.एस. की संख्या	नियमों का पालन न करने वाली सीपीएसई के नाम	खुलासे का विकल्प न चुनने वाली सीपीएसई की संख्या	उन सीपीएसई के नाम जिन्होंने जानकारी का खुलासा न करने का विकल्प चुना।
1	वीसीपी के लिए जागरूकता कार्यक्रम	3	सीपीएसई_4, सीपीएसई_13, सीपीएसई_25	5	सीपीएसई_5, सीपीएसई_9, सीपीएसई_16, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27
2	हितों के टकराव से बचने/उसे संभालने की प्रक्रियाएँ	शून्य	लागू नहीं	3	सीपीएसई_5, सीपीएसई_16, सीपीएसई_27

उन सीपीएसई की संख्या जिनमें कुछ संकेतकों के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए: 1 (सीपीएसई_20)

अनुलग्नक-XLVI
(पैरा संख्या 8.5.3 देखें)

खंड ग के सिद्धांत 2 के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण
आवश्यक संकेतक

क्र. सं.	सूचकों के नाम	अननुपालन वाले सी.पी.एस. की संख्या	सीपीएसई का नाम
1	पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास तथा पूंजीगत व्यय निवेश।	5	सीपीएसई_1, सीपीएसई_4, सीपीएसई_6, सीपीएसई_9, सीपीएसई_29
2	सतत क्रय का प्रतिशत	3	सीपीएसई_4, सीपीएसई_21, सीपीएसई_29
3	उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया	शून्य	लागू नहीं
4	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की प्रयोज्यता	1	सीपीएसई_20

सीपीएससी की संख्या जिसमें कुछ संकेतकों के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे: 1 (सीपीएससी_6)

नेतृत्व संकेतक

क्र. सं.	सूचकों के नाम	अननुपालन वाले सी.पी.एस. की संख्या	नियमों का पालन करने वाली सीपीएसई के नाम	खुलासे का विकल्प न चुनने वाली सीपीएसई की संख्या	उन सीपीएसई के नाम जिन्होंने जानकारी का खुलासा न करने का विकल्प चुना।
1	जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/ मूल्यांकन का संचालन	1	सीपीएसई_1	4	सीपीएसई_5, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_27
2	उत्पादों के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाले जोखिम	2	सीपीएसई_4, सीपीएसई_29	6	सीपीएसई_5, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27
3	उत्पादन में उपयोग की गई पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत	शून्य	लागू नहीं	4	सीपीएसई_5, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_27
4	उत्पादों के जीवनकाल के अंत में पुनः प्राप्त उत्पाद एवं उनकी मात्रा	शून्य	लागू नहीं	6	सीपीएसई_5, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27
5	पुनः प्राप्त उत्पाद एवं उनकी पैकेजिंग सामग्री	शून्य	लागू नहीं	6	सीपीएसई_5, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27

उन सीपीएसई की संख्या जिनमें कुछ संकेतकों के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए: 1 (सीपीएसई_20)

अनुलग्नक-XLVII
(पैरा संख्या 8.5.3 देखें)
उन सीपीएसई का विवरण जो खंड ग के सिद्धांत 3 के संकेतक का
पालन नहीं कर रहे हैं आवश्यक संकेतक:

क्र. सं.	सूचकों के नाम	अननुपालन वाले सी.पी.एस. की संख्या	सीपीएसई का नाम
1	कर्मचारियों/श्रमिकों के कल्याण के लिए किए गए उपाय एवं उन पर खर्च की गई राशि	4	सीपीएसई_1, सीपीएसई_4, सीपीएसई_30, सीपीएसई_22
2	कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण	3	सीपीएसई_1, सीपीएसई_4, सीपीएसई_16
3	दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कार्यस्थलों की सुलभता	2	सीपीएसई_19, सीपीएसई_23
4	समान अवसर नीति का अस्तित्व एवं उसका वेब-लिंक	7	सीपीएसई_5, सीपीएसई_11, सीपीएसई_12, सीपीएसई_14, सीपीएसई_30, सीपीएसई_22, सीपीएसई_23
5	कर्मचारियों/श्रमिकों की कार्य पर वापसी एवं प्रतिधारण दरें	शून्य	लागू नहीं
6	कर्मचारियों/श्रमिकों की शिकायतों को प्राप्त करने एवं उनका निवारण करने की व्यवस्था	1	सीपीएसई_11
7	संघों या यूनियनों में कर्मचारियों/श्रमिकों की सदस्यता	शून्य	लागू नहीं
8	कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिया गया प्रशिक्षण	8	सीपीएसई_1, सीपीएसई_4, सीपीएसई_7, सीपीएसई_13, सीपीएसई_14, सीपीएसई_21, सीपीएसई_23, सीपीएसई_29
9	कर्मचारियों/श्रमिकों के प्रदर्शन एवं कैरियर विकास की समीक्षा	1	सीपीएसई_7
10	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन की मौजूदगी	1	सीपीएसई_7
11	सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण	3	सीपीएसई_13, सीपीएसई_22, सीपीएसई_24

क्र. सं.	सूचकों के नाम	अननुपालन वाले सी.पी.एस. की संख्या	सीपीएसई का नाम
12	कार्यस्थल की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए उपाय	शून्य	लागू नहीं
13	कार्य परिस्थितियों/स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कर्मचारियों/श्रमिकों की शिकायतें	1	सीपीएसई_4
14	कार्य स्थितियों/स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए कारखानों एवं कार्यालयों का मूल्यांकन	2	सीपीएसई_4, सीपीएसई_19
15	सुरक्षा संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई	1	सीपीएसई_5

उन सीपीएसई की संख्या जिनमें कुछ संकेतकों के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए थे: 3 (सीपीएसई_6, सीपीएसई_28, सीपीएसई_29)

नेतृत्व संकेतक

क्र. सं.	सूचकों के नाम	अननुपालन करने वाले सीपीएसई की संख्या	नियमों का पालन न करने वाली सीपीएसई के नाम	खुलासा करने का विकल्प न चुनने वाली सीपीएसई की संख्या	उन सीपीएसई के नाम जिन्होंने जानकारी का खुलासा न करने का विकल्प चुना।
1	कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए जीवन बीमा या कोई भी मुआवजा पैकेज	शून्य	लागू नहीं	5	सीपीएसई_5, सीपीएसई_7, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_27
2	यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि वीसीपी द्वारा सांविधिक देय राशि काट ली गई है एवं जमा कर दी गई है।	2	सीपीएसई_4, सीपीएसई_22	7	सीपीएसई_5, सीपीएसई_7, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_19, सीपीएसई_17, सीपीएसई_27
3	जिन कर्मचारियों/श्रमिकों को कार्यस्थल से संबंधित गंभीर चोट/मृत्यु का सामना करना पड़ा है	1	सीपीएसई_4	5	सीपीएसई_5, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27
4	रोजगार क्षमता को सुगम बनाने के लिए संक्रमणकालीन सहायता कार्यक्रम	3	सीपीएसई_4, सीपीएसई_6, सीपीएसई_14	5	सीपीएसई_5, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27
5	कार्य स्थितियों/स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए वीसीपी का मूल्यांकन	1	सीपीएसई_22	6	सीपीएसई_5, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27
6	क्रमांक 5 से उत्पन्न जोखिम को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की गई।	1	सीपीएसई_1	7	सीपीएसई_5, सीपीएसई_9, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27

उन सीपीएसई की संख्या जिनमें कुछ संकेतकों के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए थे: 3 (सीपीएसई_14, सीपीएसई_20, सीपीएसई_28)

अनुलग्नक-XLVIII
(पैरा संख्या 8.5.3 देखें)

खंड ग के सिद्धांत 4 के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण
आवश्यक संकेतक

क्र. सं.	सूचकों के नाम	अननुपालन करने वाले सीपीएसई की संख्या	सीपीएसई का नाम
1	मुख्य हितधारकों की पहचान करना	शून्य	लागू नहीं
2	संवेदनशील एवं वंचित समूहों की पहचान	4	सीपीएसई_4, सीपीएसई_13, सीपीएसई_14, सीपीएसई_20

उन सीपीएसई की संख्या जिनमें कुछ संकेतकों के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए: शून्य

नेतृत्व संकेतक

क्रम संख्या	सूचकों के नाम	अननुपालन करने वाले सीपीएसई की संख्या	नियमों का पालन न करने वाली सीपीएसई के नाम	जानकारी का खुलासा न करने का विकल्प चुनने वाली सीपीएसई की संख्या	जानकारी का खुलासा न करने का विकल्प चुनने वाली सीपीएसई के नाम
1	हितधारकों एवं बोर्ड के बीच परामर्श की प्रक्रियाएँ	1	सीपीएसई_20	7	सीपीएसई_5, सीपीएसई_9, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27
2	पर्यावरण एवं सामाजिक विषयों की पहचान एवं प्रबंधन में सहयोग हेतु हितधारकों से परामर्श।	शून्य	लागू नहीं	8	सीपीएसई_5, सीपीएसई_7, सीपीएसई_9, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27
3	कमजोर/वंचित हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदम	1	सीपीएसई_4	5	सीपीएसई_5, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27

उन सीपीएसई की संख्या जिनमें कुछ संकेतकों के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए थे: 2 (सीपीएसई_20, सीपीएसई_28)

अनुलग्नक-XLIX
(पैरा संख्या 8.5.3 देखें)

खंड ग के सिद्धांत 5 के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण
आवश्यक संकेतक

क्रम संख्या	सूचकों के नाम	अननुपालन करने वाले सीपीएसई की संख्या	सीपीएसई का नाम
1	कर्मचारियों/श्रमिकों को मानवाधिकारों पर प्रशिक्षण देना	4	सीपीएसई_4, सीपीएसई_13, सीपीएसई_23, सीपीएसई_27
2	कर्मचारियों/श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी	1	सीपीएसई_11
3	महिला कर्मचारियों को मिलने वाला औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी एवं मजदूरी	4	सीपीएसई_14, सीपीएसई_30, सीपीएसई_24, सीपीएसई_29
4	मानवाधिकार मुद्दों के समाधान का केंद्र बिंदु	शून्य	लागू नहीं
5	मानवाधिकार संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र	शून्य	लागू नहीं
6	कर्मचारियों/श्रमिकों द्वारा मानवाधिकारों पर शिकायतें	शून्य	लागू नहीं
7	पीओएसएच के तहत दर्ज शिकायतें	3	सीपीएसई_30, सीपीएसई_20, सीपीएसई_27
8	भेदभाव एवं उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र	शून्य	लागू नहीं
9	मानवाधिकार संबंधी आवश्यकताएं व्यावसायिक समझौतों एवं अनुबंधों का अभिन्न अंग हैं।	शून्य	लागू नहीं
10	मानवाधिकारों के लिए संयंत्रों एवं कार्यालयों का मूल्यांकन	3	सीपीएसई_4, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27
11	क्रमांक 10 के आकलन से उत्पन्न जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की गई।	शून्य	लागू नहीं

उन सीपीएसई की संख्या जिनमें कुछ संकेतकों के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए थे: 6 (सीपीएसई_6, सीपीएसई_13, सीपीएसई_19, सीपीएसई_20, सीपीएसई_25, सीपीएसई_28)

नेतृत्व संकेतक

क्रम संख्या	सूचकों के नाम	अननुपालन करने वाले सीपीएसई की संख्या	सीपीएसई के नाम	जानकारी का खुलासा न करने का विकल्प चुनने वाली सीपीएसई की संख्या	जानकारी का खुलासा न करने का विकल्प चुनने वाली सीपीएसई के नाम
1	मानवाधिकार संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु व्यावसायिक प्रक्रिया के विवरण में संशोधन किया गया है।	शून्य	लागू नहीं	8	सीपीएसई_5, सीपीएसई_8, सीपीएसई_9, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27
2	मानवाधिकार संबंधी किसी भी उचित जांच-पड़ताल का दायरा एवं कवरेज	शून्य	लागू नहीं	9	सीपीएसई_5, सीपीएसई_7, सीपीएसई_8, सीपीएसई_9, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27
3	संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है।	शून्य	लागू नहीं	6	सीपीएसई_5, सीपीएसई_8, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27
4	मानवाधिकार मुद्दों के लिए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का मूल्यांकन	2	सीपीएसई_4, सीपीएसई_22	5	सीपीएसई_5, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_27

क्रम संख्या	सूचकों के नाम	अननुपालन करने वाले सीपीएसई की संख्या	सीपीएसई के नाम	जानकारी का खुलासा न करने का विकल्प चुनने वाली सीपीएसई की संख्या	जानकारी का खुलासा न करने का विकल्प चुनने वाली सीपीएसई के नाम
5	क्रमांक 5 के आकलन से उत्पन्न जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की गई।	शून्य	लागू नहीं	6	सीपीएसई_5, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27

उन सीपीएसई की संख्या जिनमें कुछ संकेतकों के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे: 1 (सीपीएसई_20)

अनुलग्नक-L
(पैरा संख्या 8.5.3 देखें)

खंड ग के सिद्धांत 6 के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण
आवश्यक संकेतक

क्रम संख्या	सूचकों के नाम	अनुपालन करने वाले सीपीएसई की संख्या	सीपीएसई का नाम
1	योग ऊर्जा खपत का विवरण	12	सीपीएसई_4, सीपीएसई_6, सीपीएसई_5, सीपीएसई_7, सीपीएसई_11, सीपीएसई_13, सीपीएसई_14, सीपीएसई_16, सीपीएसई_23, सीपीएसई_20, सीपीएसई_24, सीपीएसई_28
2	पीएटी योजना	शून्य	लागू नहीं
3	जल निकासी संबंधी जानकारी का खुलासा	14	सीपीएसई_4, सीपीएसई_5, सीपीएसई_6, सीपीएसई_7, सीपीएसई_11, सीपीएसई_12, सीपीएसई_13, सीपीएसई_14, सीपीएसई_16, सीपीएसई_23, सीपीएसई_20, सीपीएसई_25, सीपीएसई_24, सीपीएसई_28
4	जल निकासी से संबंधित विवरण	4	सीपीएसई_2, सीपीएसई_4, सीपीएसई_22, सीपीएसई_23
5	शून्य द्रव निर्वहन	1	सीपीएसई_20
6	योग वायु उत्सर्जन का विवरण	3	सीपीएसई_23, सीपीएसई_25, सीपीएसई_24
7	ग्रीनहाउस गैस (1 एवं 2) उत्सर्जन का विवरण	11	सीपीएसई_6, सीपीएसई_5, सीपीएसई_11, सीपीएसई_13, सीपीएसई_14, सीपीएसई_23, सीपीएसई_20, सीपीएसई_25, सीपीएसई_24, सीपीएसई_28, सीपीएसई_29
8	ग्रीनहाउस गैसों को कम करने से संबंधित परियोजना	शून्य	लागू नहीं
9	अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण	8	सीपीएसई_4, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_23, सीपीएसई_20, सीपीएसई_24, सीपीएसई_26, सीपीएसई_28
10	अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का विवरण	1	सीपीएसई_16
11	पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अस्तित्व	1	सीपीएसई_20

क्रम संख्या	सूचकों के नाम	अननुपालन करने वाले सीपीएसई की संख्या	सीपीएसई का नाम
12	पर्यावरण प्रभाव आकलन के विवरण	2	सीपीएसई_4, सीपीएसई_20
13	लागू पर्यावरण कानून/नियमों के अनुपालन न करने का विवरण	शून्य	लागू नहीं

उन सीपीएसई की संख्या जिनमें कुछ संकेतकों के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए थे: 3 (सीपीएसई_4, सीपीएसई_6, सीपीएसई_28)

नेतृत्व संकेतक

क्रम संख्या	सूचकों के नाम	अननुपालन करने वाले सीपीएसई की संख्या	सीपीएसई के नाम	जानकारी का खुलासा न करने का विकल्प चुनने वाली सीपीएसई की संख्या	जानकारी का खुलासा न करने का विकल्प चुनने वाली सीपीएसई के नाम
1	जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, उपभोग एवं निर्वहन	शून्य	लागू नहीं	6	सीपीएसई_5, सीपीएसई_8, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27
2	ग्रीनहाउस गैसों के दायरे 3 में आने वाले उत्सर्जन का विवरण	2	सीपीएसई_4, सीपीएसई_25	8	सीपीएसई_5, सीपीएसई_8, सीपीएसई_9, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27
3	जैव विविधता पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव	1	सीपीएसई_22	7	सीपीएसई_5, सीपीएसई_7, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27
4	उत्सर्जन/अपशिष्ट निर्वहन/उत्पन्न अपशिष्ट को कम करने की पहल	शून्य	लागू नहीं	6	सीपीएसई_5, सीपीएसई_7, सीपीएसई_8, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_27
5	व्यवसाय निरंतरता एवं आपदा प्रबंधन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी	शून्य	लागू नहीं	5	सीपीएसई_5, सीपीएसई_7, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_27
6	मूल्य श्रृंखला भागीदारों से उत्पन्न पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव	शून्य	लागू नहीं	7	सीपीएसई_5, सीपीएसई_7, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27
7	पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकित मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत	शून्य	लागू नहीं	7	सीपीएसई_5, सीपीएसई_7, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27

उन सीपीएसई की संख्या जिनमें कुछ संकेतकों के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए: 1 (सीपीएसई_20)

अनुलग्नक-LI
(पैरा संख्या 8.5.3 देखें)

खंड ग के सिद्धांत 7 के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण
आवश्यक संकेतक

क्रम संख्या	सूचकों के नाम	अनुपालन करने वाले सीपीएसई की संख्या	सीपीएसई का नाम
1	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों से संबद्धताओं की संख्या एवं सूची	2	सीपीएसई_1, सीपीएसई_7
2	प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित मुद्दों पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण	1	सीपीएसई_4

उन सीपीएसई की संख्या जिनमें कुछ संकेतकों के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए: शून्य

नेतृत्व संकेतक

क्रम संख्या	संकेतकों के नाम	अनुपालन न करने वाले सीपीएसई की संख्या	सीपीएसई का नाम	खुलासा न करने वाले सीपीएसई की संख्या	खुलासा न करने वाले सीपीएसई के नाम
1	समर्थन की गई सार्वजनिक नीति संबंधी स्थितियों का विवरण	शून्य	लागू नहीं	6	सीपीएसई_5, सीपीएसई_9, सीपीएसई_13, सीपीएसई_17, सीपीएसई_19, सीपीएसई_27

उन सीपीएसई की संख्या जिनमें कुछ संकेतकों के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए: शून्य

अनुलग्नक-LII
(पैरा संख्या 8.5.3 देखें)
खंड ग के सिद्धांत 8 के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण
आवश्यक संकेतक

क्रम संख्या	सूचकों के नाम	अननुपालन करने वाले सीपीएसई की संख्या	सीपीएसई का नाम
1	परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन	1	सीपीएसई_27
2	उन परियोजनाओं की जानकारी जिनके लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कार्य चल रहा है	शून्य	लागू नहीं
3	समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने एवं उनका निवारण करने का तंत्र	शून्य	लागू नहीं
4	भारत के भीतर/मध्यम आकार के उद्यमों से प्राप्त इनपुट का प्रतिशत	5	सीपीएसई_1, सीपीएसई_4, सीपीएसई_16, सीपीएसई_20, सीपीएसई_29
5	छोटे शहरों में रोजगार सृजन	4	सीपीएसई_1, सीपीएसई_16, सीपीएसई_30, सीपीएसई_22

उन सीपीएसई की संख्या जिनमें कुछ संकेतकों के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए थे: 2 (सीपीएसई_4, सीपीएसई_6)

नेतृत्व संकेतक

क्रम संख्या	सूचकों के नाम	अननुपालन करने वाले सीपीएसई की संख्या	सीपीएसई का नाम	जानकारी देने से बाहर रहने वाली कोई सीपीएसई नहीं	जानकारी देने से बाहर रहने वाली सीपीएसई के नाम
	सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए उठाए गए कदम	शून्य	लागू नहीं	3	सीपीएसई_5, सीपीएसई_16, सीपीएसई_27
	आकांक्षी जिलों में सीएसआर परियोजनाएं चलाई जा रही हैं	1	सीपीएसई_13	3	सीपीएसई_5, सीपीएसई_16, सीपीएसई_27
	वंचित/संवेदनशील समूहों के लिए अधिमान्य क्रय नीति	2	सीपीएसई_4, सीपीएसई_22	3	सीपीएसई_5, सीपीएसई_16, सीपीएसई_27
	स्वामित्व वाली/अधिग्रहित बौद्धिकसंपत्तियों से प्राप्त लाभ	शून्य	लागू नहीं	4	सीपीएसई_5, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_27
	बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों में प्रतिकूल आदेश पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई	शून्य	लागू नहीं	5	सीपीएसई_5, सीपीएसई_9, सीपीएसई_16, सीपीएसई_17, सीपीएसई_27
	सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण	2	सीपीएसई_4, सीपीएसई_19	3	सीपीएसई_5, सीपीएसई_16, सीपीएसई_27

उन सीपीएसई की संख्या जिनमें कुछ संकेतकों के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए थे: 5 (सीपीएसई_6, सीपीएसई_13, सीपीएसई_14, सीपीएसई_20, सीपीएसई_28)

अनुलग्नक LIII
(पैरा संख्या 8.5.3 देखें)
खंड ग के सिद्धांत 9 के संकेतक का अनुपालन न करने वाले सीपीएसई का विवरण
आवश्यक संकेतक

क्रम संख्या	सूचकों के नाम	अननुपालन करने वाले सीपीएसई की संख्या	सीपीएसई का नाम
1	उपभोक्ता शिकायतों को प्राप्त करने एवं उन पर प्रतिक्रिया देने की व्यवस्था	2	सीपीएसई_4, सीपीएसई_11
2	ऐसे उत्पादों एवं/या सेवाओं का कारोबार जिनमें पर्यावरणीय एवं सामाजिक मापदंडों, सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग, सुरक्षित निपटान से संबंधित जानकारी प्रकट की जाती है।	शून्य	लागू नहीं
3	आंकड़ों की गोपनीयता, विज्ञापन, प्रतिबंधित व्यापार प्रथाओं एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त हुईं।	1	सीपीएसई_30
4	सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर उत्पाद वापस मंगाने के उदाहरण	शून्य	लागू नहीं
5	साइबर सुरक्षा संबंधी नीति का अस्तित्व	5	सीपीएसई_4, सीपीएसई_7, सीपीएसई_11, सीपीएसई_16, सीपीएसई_26
6	क्रमांक 3 से संबंधित मुद्दों पर की गई कार्रवाई का विवरण	2	सीपीएसई_30, सीपीएसई_27
7	डेटा उल्लंघनों के बारे में विवरण	2	सीपीएसई_16, सीपीएसई_27

उन सीपीएसई की संख्या जिनमें कुछ संकेतकों के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए: शून्य

नेतृत्व संकेतक

क्रम संख्या	सूचकों के नाम	अननुपालन करने वाले सीपीएसई की संख्या	सीपीएसई का नाम	खुलासा करने का विकल्प न चुनने वाली सीपीएसई की संख्या	उन सीपीएसई के नाम जिन्होंने जानकारी का खुलासा न करने का विकल्प चुना।
1	वे चैनल/ मंच जहां संस्था के उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए।	शून्य	लागू नहीं	5	सीपीएसई_5, सीपीएसई_7, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_27
2	उत्पादों एवं/या सेवाओं के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग के लिए उपभोक्ताओं को सूचित करने हेतु उठाए गए कदम।	शून्य	लागू नहीं	5	सीपीएसई_5, सीपीएसई_7, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_27
3	आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/ बंद होने से उत्पन्न जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने का तंत्र।	शून्य	लागू नहीं	5	सीपीएसई_5, सीपीएसई_7, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_27
4	उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में सर्वेक्षण	1	सीपीएसई_4	5	सीपीएसई_5, सीपीएसई_7, सीपीएसई_13, सीपीएसई_16, सीपीएसई_27

उन सीपीएसई की संख्या जिनमें कुछ संकेतकों के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे: 1 (सीपीएसई_20)

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/hi/page-21-of-2026>

